राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] चौदहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का अट्ठाईसवां दिवस [संख्या: 16

बुधवार,
22 मार्च 2017

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

बधाई एवं आभार

कैलाश चन्द्र मेघवाल, श्री, अध्यक्ष को जन्म दिवस पर बधाई

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो।

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की ओर से आपको जन्म दिवस पर बधाई देना चाहूंगा। कहने को तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आप 83 बसंत पार कर गए पर आपके चेहरे पर जो लावण्य है, जिस प्रकार से आपकी आदर्श जीवन शैली रही है, मैं समझता हूं कि आज अगर कोई देखे तो आप 48 वर्ष से भी कम नजर आते हैं। आपका यह लावण्य, आपका यह हसीन चेहरा इसी तरह से मुस्कुराता रहे और आप इसी प्रकार सदन की गरिमा और परम्पराओं को बढ़ाते रहें। बहुत-बहुत शुभकामनाएं अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष की तरफ से और पूरे सदन की तरफ से मैं आपको जन्म दिन पर बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। परमपिता परमेश्वर से यह कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें। भगवान आपकी लम्बी उम्र करे और इसी तरीके से एक अच्छे और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सदन को चलाते रहें, इसी शुभकामना के साथ आपको फिर बधाई।

जन्म दिन की बधाई पर माननीय अध्यक्ष का आभार

श्री अध्यक्ष: सभी माननीय सदस्यों का मैं आभार प्रदर्शित करता हूं, आपने मुझे जन्म दिन की शुभकामनाएं दीं और दीर्घ जीवन की कामना की। अब कितना दीर्घ जीवन जीएं, यह बड़ा सवाल है, कंट्रोवर्शियल इसलिए आपका सबका आदर करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द।

श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सम्माननीय प्रदेश अध्यक्षजी के चरणों में नमन, आज आपका जन्म दिन है। ...(व्यवधान)... विधान सभा अध्यक्षजी का ...(व्यवधान)... आपकी कृपा हम पर ऐसी ही बनी रहे, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं।

श्री हीरालाल (निवाई): आप जीएं हजारों साल, साल के दिन हों पचास हजार। बधाई हो, अध्यक्ष महोदय।

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश के सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की कार्य योजना

268. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ने राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ दिलवाने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश के दो लाख कर्मचारियों के वेतनमान में कमी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या?

(4) क्या यह सही है कि शासन सचिवालय और राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक कैडर के कर्मचारियों के वेतनमान और पदोन्नति के अवसरों में काफी असमानता है? यदि हां, तो क्यों व क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संदीप शर्मा)

(5) क्या सरकार कर्मचारियों के हित में कैडर्स की असमानता को दूर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बधाई अपने आप ही आप तक पहुंचती है। आप हमेशा हमको ऐसे ही डांटते रहें और मुझे रजनी गंधा खाने दें आप। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: पोल क्यों खोल रहे हो सबके सामने?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री) (वित्त मंत्री के स्थान पर): (1) राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्र के अनुरूप सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ दिये जाने के संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा सं. प. 6(5) प्रसु/अनु.3/2017 दिनांक 23.02.2017 के द्वारा समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार द्वारा समुचित निर्णय लिया जावेगा।

(2) राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्र के अनुरूप सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ दिये जाने के संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा सं. प. 6(5) प्रसु/अनु.3/2017 दिनांक 23.02.2017 के द्वारा समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार द्वारा समुचित निर्णय लिया जावेगा।

(3) जी नहीं।

(4) शासन सचिवालय एवं अधीनस्थ विभागों के मंत्रालयिक सेवा संवर्ग के कर्मचारियों के प्रारम्भिक दो पद, क्लर्क ग्रेड II एवं क्लर्क ग्रेड I को छोड़कर शेष पदों के वेतनमान एवं पदोन्नति के अवसर भिन्न-भिन्न हैं। शासन सचिवालय एवं अधीनस्थ विभागों के मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों की कार्यात्मक आवश्यकता, कार्य की प्रकृति एवं उत्तरदायित्व में भिन्नता होने के कारण दोनों संवर्ग परस्पर तुलनीय नहीं हैं। शासन सचिवालय एवं अधीनस्थ विभागों के कर्मचारियों के वेतनमान एवं पदोन्नति अवसरों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(5) शासन सचिवालय एवं अधीनस्थ विभागों के मंत्रालयिक संवर्ग के

(उद्योग मंत्री)

कर्मचारियों की कार्यात्मक आवश्यकता, कार्य की प्रकृति एवं उत्तरदायित्व में भिन्नता होने के कारण दोनों संवर्ग परस्पर तुलनीय नहीं हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रदेश में लागू करने पर राज्य सरकार पर कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा तथा राज्य सरकार इसकी व्यवस्था कैसे करेगी और कब तक इसे लागू कर देगी? आपने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्तावित कर दिया है परन्तु राज्य सरकार के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके लिए अभी तक कोई सिफारिश नहीं की गई है। इस मामले को क्यों लंबित किया जा रहा है? वित्त विभाग ने बजट में कोई प्रस्ताव नही किया है, प्रावधान नहीं रहा है। जो सामन्त कमेटी आपने गठित की है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है जबकि पूर्व में भी बिना किसी कमेटी के निर्णय आप स्वयं ने लिए हैं। अन्य कई प्रदेशों में भी स्वत: इसे लागू कर दिया गया है तो हमारे यहां इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा कि गए बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन में घोषणा की थी कि केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतनमान का रिवीजन किए जाने हेतु गठित सातवें वेतन आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। इस आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा आदेश जारी किए जाने के पश्चात् राज्य कर्मचारियों का रिवाइज वेतनमान निर्धारण करने हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घोषणा गए बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन में की थी। इसी के आधार पर जिस कमेटी की आपने चर्चा की इस कमेटी कि जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में पहले वेतन आयोगों के आधार पर वेतनमान का निर्धारण नहीं हुआ। केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जरिये और बाद में जस्टिस राणावत के कमीशन और जस्टिस बेरी के कमीशन की सिफारिशों के आधार पर यहां पे-रिवीजन हुआ। हमने पहली बार 1986 में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप कर्मचारियों को वेतनमान दिया। लेकिन शुरू से लेकर छठे वेतन आयोग तक वेतनों का निर्धारण पे-स्केल के आधार पर होता था। छठे वेतन आयोग के अंदर यह पे-स्केल के आधार पर होना बंद हो गया और पे-मेट्रिक्स के अंदर पे-बैंड, रनिंग पे-बैंड और ग्रेड-पे, इन तीन चीजों के आधार पर वेतनमान तय होने लगे और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब-जब हम पे-स्केल का रिवीजन, पे-कमीशन के आधार पर राजस्थान में करते हैं तो उसके बाद में एनॉमोलीज पैदा होती है और उन एनॉमोलीज के निराकरण के लिए वेरियस कमेटीज बनती हैं। चौथे वेतन आयोग के टाइम, पांचवें वेतन आयोग के टाइम, एवं छठे वेतन आयोग के टाइम, सबके वेतन आयोगों को लागू करने के बाद जितनी भी एनॉमोलीज पैदा हुईं उन एनॉमोलीज की पूर्ति करने के लिए हमने विभिन्न समितियां बनाईं और कई बार तो माननीय अध्यक्ष महोदय, अगले वेतन आयोग तक उन एनॉमोलीज का सही रूप से निस्तारण नहीं होता। ऐसी स्थिति बार-बार नहीं बने, उसके लिए जिस प्रकार का काम होना चाहिए, वह काम कर पाएं, इसके आधार पर तीन बिन्दुओं को लेकर इस समिति का गठन हुआ, जिसकी घोषणा गए बजट में हुई थी। तीन बिन्दु है माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा कि बजट में प्रोविजन नहीं किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन बिन्दु हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, पहला, राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम, 2008 में राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित रनिंग पे-बैंड एवं ग्रेड-पे के दृष्टिगत केन्द्रीय कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए वेतनमान, पे लेवल, नई बात, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, के संदर्भ में वेतन लेवल निर्धारित किए जाने के लिए सिफारिश, नम्बर एक। नम्बर दो, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में राज्य कर्मचारियों को वेतनमान, पे- लेवल का लाभ दिए जाने से राज्य सरकार पर आने वाले वित्तीय भार का आकलन करते हुए राज्य कर्मियों के वेतनमान के सम्बन्ध में समुचित सिफारिश। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरा बिन्दु है टर्म्स ऑफ रेफरेंस का, वह है राज्य कर्मचारियों को देय भत्तों, विशेष भत्तों एवं विशेष वेतन की देयता एवं

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

दरों का परीक्षण कर रिपोर्ट और सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने कहा कि बजट में प्रोविजन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा और सुराना साहब जैसे वरिष्ठ सदस्यों को पता है, हमने पे-कमीशन की बाकी रिकमंडेशन के आधार पर पे रिवीजन किए हैं, वहां कहीं भी बजट में पहले से प्रोविजन नहीं किया गया। हमेशा इनकी रिकमंडेशन के आधार पर जो भी रिवीजन होते हैं, उन रिवीजन के लिए हम हमेशा सप्लीमेंट्री डिमांड के साथ में लेकर आते हैं। पिछली कोई परम्परा नहीं रही है, कोई कारण नहीं रहा है। आज तक कभी भी बजट में इस प्रकार के प्रोविजन नहीं किए जाते रहे हैं, इस प्रकार के प्रोविजन, रिवीजन होने के बाद सप्लीमेंट्री डिमांड के साथ लिए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह सकता हूं, आपने यह भी कहा कि केन्द्रीय सेवाओं के लोगों के लिए हमने किया है। देश के अंदर, कई प्रदेशों के अंदर सातवां वेतन आयोग लागू नहीं किया गया है राज्य कर्मचारियों के लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सिफारिश की है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): हां, लागू नहीं किया गया लेकिन सेंटर सर्विस के लोगों को दे दिया गया। पच्चीस राज्यों में ऐसा किया गया, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं किया गया। मैं आपको इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार कर्मचारियों के हितों के बारे में सजग है और वह कर्मचारियों के हितों के प्रति सजग होने के दरमियान, केन्द्र और राज्य के कर्मचारियों के बीच कोई विभेद नहीं करना चाहती है और यही कारण है कि 25 राज्यों के अंदर इस प्रकार की पे-स्केल सेंट्रल एम्पलोईज को देने के बावजूद राजस्थान में इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया। इसलिए यह कहना कि इसके लिए कमेटी बनाने की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत तो एक साल पहले ही पड़ गई, एक साल पहले ही डिग्रेडेशन हो गया। कमेटी के टर्म्स एण्ड रेफरेंस बड़े स्पष्ट हैं जिनके आधार पर मैं इतना कह सकता हूं कि कमेटी की रिकमण्डेशन आने के बाद उसका परीक्षण करके निश्चित रूप से सरकार सातवें वेतन आयोग को किस रूप में राजस्थान में लागू करना होगा, इसका निर्णय करेगी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे?

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): जी, साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पढ़े-लिखे युवा ऐसे कई बेरोजगार हैं जिनके लिए आवश्यक है कि सरकारी भर्तियां हों। इस हिसाब में अभी तक सरकारी भर्तियों के लिए इतनी उत्तरोत्तर हमने प्रगति नहीं की है। क्या वित्त विभाग के पास नई भर्तियों की स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव लम्बित है? आगे आने वाले दिनों में राज्य सरकार किन-किन विभागों में सरकारी भर्तियां खोलने का विचार करती है? प्रदेश में नवनियुक्त जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें दो वर्ष तक फिक्स वेतन दिया जाता है, दो वर्ष उनका परिवीक्षा काल होता है। क्या सरकार उनके इस परिवीक्षा काल को दो वर्ष से एक वर्ष करने का विचार करती है तथा नियुक्ति के दिन से उन्हें पूर्ण वेतन और भत्ते देने का विचार करती है?

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए। यह तो सिफारिश आने के बाद की बात है। मंत्री महोदय, जो आपको .... (व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक नये पदों पर नियुक्ति का ताल्लुक है, इसका सातवें वेतन आयोग से कोई संबंध नहीं है।

श्री अध्यक्ष: कोई संबंध नहीं है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार शुरू कर चुकी। कोर्ट की कुछ तकलीफें हैं, उन तकलीफों को दूर करते हुए उन भर्ती की प्रक्रिया को शामिल करेंगे, लेकिन सरकार से इसका संबंध नहीं है।

आपने कहा कि प्रोबेशन पर दो साल तक रखा जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा कि पांचवे वेतन आयोग ने यह सवाल बहुत जोर-जोर से उठाया था कि राज्यों का एस्टेब्लिशमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। इसको कम करने के लिए उन्होंने रिकमण्ड किया था पाँचवाँ वेतन आयोग, उसी का आपको ध्यान होगा, 1998 से लेकर 2006 तक लगभग भर्तियां नहीं हुईं। 1998 से लेकर 2006 के बीच में सरकार के अंदर मोटे तौर पर कोई भर्तियां नहीं हुईं। भर्तियां न हों, एस्टेब्लिशमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा न बढ़े, क्योंकि पांचवें वेतन आयोग का यह कहना था

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

और उसके बीच लोगों को एम्प्लायमेंट कैसे दिया जाए, इसलिए इनको एम्प्लायमेंट दिया जाए और साथ में एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे को बढ़ने से कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके लिए रास्ता निकाला गया कि दो साल तक प्रोबेशन पीरियड पर लोगों को रखा जाए। मैं समझता हूं यह राजस्थान के अनएम्प्लायमेंट और यूथ के अनएम्प्लायमेंट को पूरा करने की दिशा में काम है। उस दो साल के परिवीक्षा काल को कम करने का कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो 1990 में चुनाव जीतकर आया था, पर आज 2017 में मुझे लगता है कि मैं यहां प्रोबेशनर एमएलए ही हूं। दो साल का पीरियड किसी के प्रोबेशन के लिए कोई ज्यादा पड़ता हो, मुझे नहीं लगता। मैं समझता हूं प्रोबेशन पूरा होने के बाद उनको रैगुलर पे-स्केल के ऊपर भर्ती करते हैं, उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक, द्रोपती। द्रोपती पहले आ चुकी है। तीन नाम।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि यही प्रश्न पिछली बार विधान सभा में लगा था और इसका जवाब माननीय गृह मंत्रीजी ने दिया था और उन्होंने यह कहा कि मंत्रालयिक कर्मचारियों के वेतन निर्धारण करने के लिए एक कमेटी बनायी गयी है। उस कमेटी की अध्यक्षता माननीय राठौड़ साहब कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में यह कमेटी बनायी गयी थी। उस कमेटी ने क्या मंत्रालयिक कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है? यदि कर दी है तो आप सदन पटल पर रखें। क्या सरकार मंत्रालयिक कर्मचारियों की ग्रेड-पे 2400 से बढ़ाकर 3600 करने का विचार रखती हैं? मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय, यह रिलेवेंट नहीं है। आप दे दीजिए जवाब।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इस समस्या के समाधान के लिए, इस समस्या पर ध्यान देने के लिए कैबिनेट सब-कमेटी बनी थी। इस कैबिनेट सब-कमेटी की

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

रिकमण्डेशन अभी तक नहीं आयी। (व्यवधान) आप हैं क्या? इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सवाल लम्बे समय से उठता रहता है, लेकिन हम सबको मालूम है कि यह अंतर इस कारण से है कि सैक्रेटेरियट की सर्विसेज और बाकी अधीनस्थ सेवाओं के बीच में काम की प्रकृति में मोटे तौर पर अंतर है। यहां पॉलिसी फार्मुलेशन का काम होता है। बाकी अधीनस्थ सेवाओं के लोग काम करते हैं, वे सारा का सारा काम इंप्लिमेंटेशन का करते हैं। पांचवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के चैप्टर में भी कैटेगरिकली इस बात को स्वीकार किया है। यह एनोमोली यहां पर ही नहीं है, दिल्ली में भी है। "Historically various services in the Secretariat have been given an edge over analogous posts in the field offices. This was done on the ground that office staff in the Secretariat perform complex duties and are involved in analysing issues with policy implications whereas their counterparts in the field offices perform routine work relating to routine matters concerning personnel and general administration." साथ में, सैक्रेटेरियट के कर्मचारियों का काम चाहे राजस्थान के सैक्रेटेरियट का हो, चाहे दिल्ली के सैक्रेटेरियट का हो, उस सैक्रेटेरियट के कर्मचारियों का काम और बाकी अधीनस्थ सेवा के मंत्रालयिक कर्मचारियों के काम के अंदर, काम के नैचर में अंतर है, उसके करैक्टर में अंतर है। इसीलिए इसी के आधार पर इनके प्रमोशनल एवेन्यूज और इनकी स्केल के अंदर वेरिएशन है। मैं समझता हूं इसमें कोई कॉंट्राडिक्शन नहीं है। फिर भी सरकार ने इस बात को री-एग्जामिन करने के लिए वेरियस अदर लाइट्स के अंदर एग्जामिन करने के लिए कैबिनेट की सब-कमेटी बनायी है, जिसकी रिकमण्डेशन आएगी उसके आधार पर सरकार आगे काम करेगी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। श्री हीरालाल नागर।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश के सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में संविदाकर्मी लम्बे अर्से से कार्यरत है। क्या राज्य सरकार इन संविदाकर्मियों को भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने का

(श्री हीरालाल नागर)

विचार रखती है? यदि नहीं तो संविदा कर्मचारियों को, जो मामूली वेतन पर कार्य कर रहे हैं, इनको आर्थिक लाभ देने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है तथा सचिवालय व अन्य विभागों में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों के वेतन, ग्रेड व भत्तों में भी भेदभाव किया जा रहा है जबकि योग्यता समान है? सचिवालय का बाबू उप शासन सचिव तक की पदोन्नति भी प्राप्त कर लेता है जबकि अन्य विभाग में कार्यालय अधीक्षक भी नहीं बन पाता है। यह भेदभाव क्यों है? क्या सरकार इसे दूर करने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा संविदा कर्मियों पर पे-स्केल लागू नहीं है, पे-कमीशन की रिकमण्डेशन लागू नहीं होती। संविदाकर्मी, जैसा कि नाम बताता है संविदा, कांट्रेक्ट। मेरा आपसे आज शाम तक काम करने का वादा है, 6 महीने काम करने का वादा, इतने रुपये पर काम करने का वादा। यह कांट्रेक्ट है। इसलिए पे-कमीशन की रिकमण्डेशन संविदाकर्मियों पर लागू नहीं होती।

दूसरा सवाल आपने उठाया था मंत्रालयिक सैक्रेटेरियट कर्मचारियों के बारे में और अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों के बारे में। इसका जवाब मैंने आपके सवाल पूछने से पहले बड़े विस्तृत रूप से दिया है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों कामों की प्रकृति अलग है। योग्यता का जहां तक ताल्लुक है, अध्यक्ष महोदय, मेरे जैसा घूमने वाला सड़कछाप आदमी भी बी.ए. है और एक आईएएस भी बी.ए. है। योग्यता के आधार पर इस प्रकार तय नहीं किया जा सकता। काम का करैक्टर क्या है, काम की प्रकृति क्या है, काम किस तरह का है, उस काम के आधार पर तनख्वाह दी जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सैक्रेटेरियट सर्विसेज के कर्मचारियों के काम की प्रकृति और अधीनस्थ सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले मंत्रालयिक कर्मचारियों के कार्य की प्रकृति में मौलिक अंतर है, जिसका मैंने आपसे निवेदन किया, जिसकी मैंने चर्चा की है। इसके कारण दोनों के पे-स्केल, ग्रेड-पे और प्रमोशन एवेन्यूज के बारे में कंपेरिजन करना न्यायसंगत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न श्री रणधीर सिंह भीण्डर।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी की बातों से लग रहा है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार सातवां वेतन आयोग लागू करने के लिए सिद्धांतत: सहमत हो गई है, लागू कर देंगे। लेकिन 2006 में एम.एस.स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित किसान आयोग, जिसकी रिपोर्ट 2009 से लागू करनी थी उसको अभी तक सरकार ने लागू नहीं किया। यह असमानता क्यों? एक तरफ कर्मचारियों के वेतन बढ़ते जा रहे हैं, इधर किसानों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उसको कब लागू करेंगे, यह भी मुझे बताएं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, This question pertains to the Pay Commission. स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट हालांकि मैंने पढ़ी है, पढ़ने की कोशिश की है, पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पे-कमीशन की रिपोर्ट के साथ इक्वलाइज करने की कोशिश का कारण समझ में नहीं आता। जहां तक किसानों की समस्याओं का ताल्लुक है राजस्थान की सरकार किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए जागृत है, स्वामीनाथन कमीशन और नो-स्वामीनाथन कमीशन। अभी हाथों-हाथ बिजली के अंदर जिस प्रकार उन पर पड़ने वाले भार को सरकार ने अपने माथे पर लिया है, यह इस बात का सबूत है कि किसानों के हितों के बारे में सरकार कितनी जागरूक है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री हमीरसिंह भायल।

सिवाना में खरीफ फसल खराबे का अनुदान

269. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि खरीफ फसल 2015 के खराबे पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को अनुदान दिया गया है? यदि हां, तो बाड़मेर जिले के सिवाना विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना के तहत किसानों को कितना अनुदान दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना से वंचित किसानों को अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हमीरसिंह भायल)

(3) क्या यह सही है कि उक्त अनुदान राशि किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से दी गई है? यदि हां, तो सिवाना विधान सभा क्षेत्र की सहकारी समिति वार राशि वितरण का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त अनुदान योजना से कई गांवों के किसान वंचित रह गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त किसानों के नाम पुनः जुड़वाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): (1) जी हां। बाड़मेर जिले के सिवाना विधान सभा क्षेत्र में खरीफ फसल 2015 के प्रभावित काश्तकारो को कृषि आदान अनुदान के भुगतान हेतु राशि 48.60 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं।

(2) अभाव सम्वत् 2072 (खरीफ फसल 2015) में विधान सभा क्षेत्र सिवाना में 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराबा वाले प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान के भुगतान हेतु राशि 48.26 करोड़ रुपये बाड़मेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को हस्तान्तरित कर दी गई है। विधान सभा क्षेत्र सिवाना में 33 से 50 प्रतिशत तक फसल खराबा वाले दो हैक्टेयर तक भूमि धारिता वाले प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान वितरित करने हेतु 34.04 लाख रुपये बाड़मेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को हस्तान्तरित कर दी गयी है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ग्राम सेवा सहकारी समितियों के द्वारा किये गये भुगतान की सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) अभाव सम्वत् 2072 खरीफ फसल 2015 के दौरान जिला बाड़मेर के विधान सभा क्षेत्र सिवाना में बिन्दु संख्या 02 के उल्लेखानुसार पात्र एवं स्वीकृत श्रेणी में आपदा प्रभावित किसान वंचित नहीं रहे है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, खरीफ

(श्री हमीरसिंह भायल)

सम्वत् 2072 की गिरदावरी के दौरान अनेक राजस्व गांवों जैसे गोलिया, पिपलून इत्यादि गांवों की सम्बन्धित पटवारियों ने सही निरीक्षण व गिरदावरी नहीं की तो क्या सरकार इन राजस्व गांवों का पुन: निरीक्षण कर पीड़ित काश्तकारों को सहायता दिलाने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो गिरदावरी हमने की है और जिसकी डिटेल हमारे पास है उसमें 75 से 100 प्रतिशत जहां खराबा हुआ था दो हैक्टेयर भूमि धारकों को, उनमें हमने 27772 किसानों को 10 करोड़ रुपये वितरित करने के लिए भेज दिये। उसके बाद दो हैक्टेयर से अधिक के बड़े किसान हैं जिनका 75 से 100 प्रतिशत खराबा हुआ था, उन 19237 किसानों के खाते में 23 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिये। उसके बाद फिर हम नीचे आये और 50 से 75 प्रतिशत खराबा वाले दो हैक्टेयर भूमि धारक 7752 किसानों को 2 करोड़ 91 लाख रुपये उनके खाते में ट्रांसफर किये। फिर जो 50 से 75 प्रतिशत खराबा है दो हैक्टेयर से अधिक भूमिधारकों, अर्थात् बड़े किसानों को भी 9615 किसानों को 11 करोड़ 52 लाख रुपये उनके खाते में ट्रांसफर कर दिये। 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक ही जिनका खराबा है, उनको भी केवल दो हैक्टेयर के भूमिधारक, लघु और सीमांत कृषक का पैसा तो उनके खाते में, जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया कि 34 लाख 4 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिये हैं लेकिन 33 से लेकर 50 प्रतिशत के बीच में जिनका खराबा है और बड़े किसान हैं उनके खाते में भी पैसा उपलब्ध होने के बाद ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से केवल इनके विधान सभा क्षेत्र में 65879 किसानों को 48 करोड़ 60 लाख रुपये खातों में ट्रांसफर कर दिये हैं। जो सूची गिरदावरी की हमारे पास आई है उसी के आधार पर हमने पेमेंट किया और सारा पेमेंट ऑनलाइन किया है। अगर राजस्थान का कोई भी व्यक्ति चाहे तो, हमारी वेबसाइट पर प्रत्येक किसान का नाम और उसको दिये गये पैसे हैं, वो देख सकता है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे?

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्वत् 2074 की रबी में 18 तारीख को तेज बारिश और ओले गिरने से ईसबगोल,

(श्री हमीरसिंह भायल)

जीरा व गेहूं का नुकसान हो गया है तो इसका सर्वे जल्दी कराकर सहायता दिलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह अभी इसी मार्च की 9 तारीख को, 18 और 19 तारीख को हुई है। उसमें हमने कल 21 तारीख को ही उसकी गिरदावरी के लिए आदेश जारी कर दिये हैं और गिरदावरी 20 दिन में हो जाएगी और 15 अप्रैल तक उनका भी पेमेंट करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि खरीफ की फसल के बारे में सिवाना के माननीय विधायक ने मुद्दा उठाया कि जो सर्वे हुआ, वहां वास्तव में जिनको अकाल के अन्दर लाभ मिलना चाहिए उनके सर्वे में नाम छोड़ दिये गये हैं और वो गांव अकालग्रस्त घोषित हैं वहां सीमांत और बड़े किसान को पैसे मिल गये, पर गरीब हैं उनके नाम छूट गये तो क्या उन किसानों का सर्वे कराकर उनको मुआवजा दिलाने का कार्य करेंगे? उनको मुआवजा मिलेगा? मंत्री महोदय, भरूटिया, सांसा, खुडास ऐसी कई पंचायतें हैं जहां उन गांवों में पटवारियों ने जान-बूझकर नाम छोड़ दिये हैं तो क्या उनका सर्वे कराकर मुआवजा दिलाएंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप और हम सब लोग जानते हैं कि गिरदावरी रिपोर्ट में जो कलेक्टर के द्वारा अधिकृत सूची भेजी जाती है वहां तक ही आदान-अनुदान देना हमारी सीमा में आता है। अब आप इतने लम्बे समय बाद उन गांवों के बारे में कहो कि वहां खराबा हो गया। खराबा हुआ या नहीं हुआ, यह तो गिरदावरी के समय अगर कहीं चूक थी तो उसी समय उसको करेक्ट किया जा सकता था। अब एक साल के बाद उस पुरानी गिरदावरी को खेत में जाकर क्या देखूंगा।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): पूरे के पूरे गांव में अकाल है और उसमें छोड़ दिया है। पूरे गांव में अकाल है, एक-आधा हो तो बतायें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपके आधार पर सदन के माध्यम से राजस्थान के किसानों को यह बात बताना चाह रहा हूं कि यह पहली बार है 2072 में कि हमने 46 लाख किसानों को ऑनलाइन पेमेंट किया है और एक शिकायत राजस्थान के किसी भी कोने से इस बारे में दर्ज नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा प्रश्न, श्री शंकर सिंह। सिवाना का है, यह ध्यान रखना और इधर-उधर मत जाना।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): बरसात, ओलावृष्टि की ही बात करूंगा साहब।

श्री अध्यक्ष: सिवाना का है और रिलेवेंट पूरक प्रश्न कीजिये आप।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मेरा तो इतना ही निवेदन है कि जो ओलावृष्टि अभी हुई है उसमें बड़े किसानों को ले लिया और छोटे किसान जैसे एक बीघा, दो बीघा, पांच बीघा वाले हैं उनको नहीं मिला तो उनके लिए भी थोड़ा क्लियर करवा दें और उनको भी मिले ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: हां, विराजिये। जवाब दिलवा देता हूं। ध्यानाकर्षण किया है उन्होंने।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार है कि जैसे-जैसे हमारी पैसों की उपलब्धता रही तो सबसे पहले तो जिनको 75 से लेकर 100 प्रतिशत का नुकसान हुआ उनकी भरपाई की। उसके बाद जब हमारी पैसे की उपलब्धता हुई तो 50 से लेकर 75 तक की और उसके बाद हमारे पास और पैसा था तो हमने 33 से लेकर 50 तक जो छोटे किसान, दो हैक्टेयर वाले लघु और सीमांत किसान हैं, उनका पेमेंट कर दिया और जो बाकी बचे हुए बड़े किसान हैं जिनका नुकसान 33 से लेकर 50 प्रतिशत के बीच में हुआ है, पैसा उपलब्ध होते ही उनको भी पेमेंट करेंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, श्री गोरधन। रिलेवेंट सवाल करना।

श्री गोरधन (धोद): बिलकुल, माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपदा प्रबन्धन मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जब ओलावृष्टि या अति बारिश से फसल का नुकसान होता है तो उसमें क्या खराबे को 33 प्रतिशत माना गया है और इकाई खेत को माना गया है या पूरी पंचायत समिति या तहसील को माना गया है? यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): बहुत पहले ही मेरे सवाल का आ गया कि हम किसान को इकाई मानते हैं और किसान के खराबे की ही गिरदावरी होती है और प्रत्येक किसान के खाते में ही हमने पैसे ट्रांसफर किये हैं इस खराबे के, न गांव को किया न किसी दूसरे को किया, इंडिविजुअल किसान को किया है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्री मानिक चन्द सुराना। माननीय विधायक, विराजिये। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

लूणकरणसर में मनरेगा के तहत जल कुण्डों का निर्माण

270. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गांरटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर तहसील लूणकरणसर की 38 व बीकानेर की 18 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2015-16 व 2016-17 के 31 दिसम्बर, 2016 तक किस-किस पंचायत में ग्रामीण परिवारों को कितने-कितने दिन मनरेगा में काम दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मनरेगा कार्यक्रम में वर्ष 2015-16 व 2016-17 के 31 दिसम्बर, 2016 तक के मनरेगा कार्यक्रम में क्षेत्र की किस-किस पंचायत में अनुसूचित जाति, बी.पी.एल., सीमान्त कृषक व छोटे किसान परिवारों के खेतों में कितने जलकुण्ड बनाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस वर्ष भारत सरकार के मनरेगा बजट में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 100 दिन का रोजगार दिये जाने के कार्यक्रम को सुनिश्चित करने का नीतिगत निर्देश ग्राम पंचायतों को देकर बारानी क्षेत्रों में अधिक से अधिक जलकुण्ड बनाने का विचार रखती है?

(4) क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2016-17 व आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 में मनरेगा में वर्ष 2008-09 से अधिक मनरेगा परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र की बीकानेर एवं लूणकरणसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में ग्रामीण परिवारों को

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

उपलब्ध कराए गए रोजगार का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में व्यक्तिगत लाभार्थी कार्यों के तहत् पात्र परिवारों के खेतों में निर्मित किये गये जलकुण्डों का ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत रोजगार, संबन्धित परिवार की मांग पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस प्रति परिवार उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। 100 दिवस के रोजगार की मांग किये जाने पर नियमानुसार संबंधित परिवार को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान अधिनियम में निर्दिष्ठ है।

योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ही तैयार किये जाते है, जिसमें जलकुण्डों के निर्माण के प्रस्ताव जो कि श्रेणी 'बी' में अनुमत्त हैं, आवश्यकतानुसार कार्य सम्मिलित कराये जाकर कराये जा सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राकृतिक संसाधन से संबंधित कार्य कराये जाने पर विशेष फोकस है एवं जलकुण्डों का कार्य इस श्रेणी में सम्मिलित है। इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी किये जा चुके है।

(4) महात्मा गांधी नरेगा योजना मांग आधारित योजना है जिसमें रोजगार की मांग किये जाने पर महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 14 के प्रावधानानुसार रोजगार की मांग किये जाने के 15 दिवस में संबंधित ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। मांग के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो सूची दी है, परिशिष्ट-2 को कृपया देख लें। परिशिष्ट-2 में आपने कतरियासर का नाम दिया है और उसमें आपने 77 जलकुण्ड

(श्री मानिक चन्द सुराना)

बनाने दिखाये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदयजी के माध्यम से मैं इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि मैंने सुबह ही सरपंच से बात की। उन्होंने कहा कि 77 में से एक भी नहीं बना है। 77 की स्वीकृतियां जारी हैं, एक भी नहीं बना है। यह सैम्पल के तौर पर मैंने आपसे निवेदन किया है। अब इस पन्ने को पलटें। लूणकरणसर की तरफ लें, इसका सैकण्ड पेज लें। क्रमांक-11 पर जैतपुर देखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कितने नम्बर पर?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्रमांक-11 जैतपुर में आपने 59 कुण्ड दिखाये हैं। मैंने सरपंच से बात की। उन्होंने कहा, भाई साहब, 33 की स्वीकृति है, 30 बने हैं, 14 का पैसा मिला है, 16 का पैसा नहीं मिला है। अनेक सरपंचों से बात करने के पश्चात् निरन्तर उनके बीच में रहने के कारण, मैं मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि जलकुण्ड बनाने में आप अपने विभाग से पूछें कि यह जलकुण्डों की स्वीकृतियां दिखाई हैं, इनमें किस वर्ष में कितनों के पेमेंट किये हैं? आज सिस्टम यह बन गया माननीय मंत्रीजी, कि मार्च में पेमेंट किया जाये और कुण्ड बनेगा उसके पहले ही, तो यह जो फंडिंग पैटर्न है आपका, एक सरपंच से हम यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दो-दो लाख तीन-तीन लाख का कुण्ड 30-30 की संख्या में यानी जिसमें करीब 90 लाख रुपयों का इन्वेस्टमेंट हो जाये कि वह बिना आपके एडवांस पेमेंट के कैसे करेगा? मैं एक तो ध्यान आकर्षित करता हूं कि आपने यह जो सूची दी है, मैं चाहता हूं कि इसको आप दुबारा करेक्ट करें और एक्चुअल में जो कुण्ड बने हैं, स्वीकृतियां अलग चीज हैं और कुण्ड बनने अलग हैं, नम्बर वन।

नम्बर टू, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग नम्बर तीन और चार में आपने जो जवाब दिया है माननीय मंत्री महोदय, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने तो आपको ध्यान में रखकर यह सवाल किया था तीन और चार, कि "क्या राज्य सरकार निर्देश देगी कि 100 दिन का रोजगार दिये जाने के कार्यक्रम को सुनिश्चित करने का नीतिगत निर्देश ग्राम पंचायतों को देकर बारानी क्षेत्रों में अधिक से अधिक जलकुण्ड बनाने का विचार रखती है?"

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मुख्य मंत्रीजी जल स्वावलम्बन कार्यक्रम चला रही हैं। नरेगा में भी जलकुण्ड बनाने के प्रावधान हैं। मैं निवेदन यह करता हूं कि जल स्वावलम्बन और जलकुण्ड एक ही बात है और उस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए नरेगा में भारत सरकार ने 48,000 करोड़ रुपये का बजट कर दिया है माननीय मंत्री महोदय और वसुन्धरा सरकार के 2008-09 के कार्यकाल में 6,175 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और वर्तमान में सिर्फ 4,400 करोड़ रुपये इस साल खर्च हो रहे हैं। मेरे पूछने का मतलब यह था कि आप ऊपर से नीति बनाते हो। यह जो आपने बताया है, यह तो सब जानकारी है कि यह डिमांड आधारित है और इसको ग्राम सभा बनाती है। मेरा निवेदन यह है कि 100 दिन का रोजगार नहीं मिल पा रहा है और आपके खुद के आंकड़ों के अनुसार 50 दिन का मिल रहा है। इसके संबंध में आप कोई नीति-निर्देश देकर, जो भी नरेगा का मजदूर है, उसको अधिक से अधिक 100 दिन तक रोजगार देने की व्यवस्था करेंगे? और दूसरा प्रश्न यह है कि 2008-09 में...

श्री अध्यक्ष: एक का जवाब आ जाने दीजिये। जवाब आ जाने दीजिये, फिर दूसरा पूरक प्रश्न कर लेना।

श्री राजेन्द्र राठौड (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की अनुसूची-2 के अंदर यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि पात्रताधारी परिवार को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय, आजकल जिस प्रकार की स्थिति-परिस्थितियां हैं, आज नरेगा के अंदर जो हमारा श्रमिक हैं, उसको 183 रुपये के लगभग प्रतिदिन के मिलते हैं और बाजार के अंदर मजदूर आज 300 रुपये में मिलता है। अध्यक्ष महोदय, जो 2008 की बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, 2008 के अंदर, बाजार के अंदर मार्केट में जो मजदूर को मजदूरी मिलती थी 100 रुपये और 100 रुपये ही मजदूरी नरेगा में अनुमत्त थी। दोनों में अंतर नहीं था इसलिए उस समय 2008 के अंदर ज्यादा काम हुए थे। 100 दिन का रोजगार मिले, यह सुनिश्चित करने का काम विभाग कर रहा है क्योंकि यह एक्ट है और एक्ट के अंदर अध्यक्ष महोदय, अनुसूची-2 के पैरा-6 में यह प्रावधान है कि 100 दिन का रोजगार मांगने पर मिले। परन्तु रोजगार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मांगने के लिए, मजदूर रोजगार मांगे, इसके लिए यह भी आवश्यकता है क्योंकि यह मांगपरक सारा कार्यक्रम है।

आपने फार्म पौंड और जलकुण्ड की बात कही। आपने यह कहा। दो जगह दो नाम आपने उद्धृत किये और यह कहा, कतरियासर और दूसरा आपने जैतपुर कहा। इन दोनों के अंदर परिशिष्ट-ब के अंदर 77 कुण्ड की बात कही गई है और 59 कुण्ड की बात कही गई है। निश्चित तौर पर अगर आप कहते हो कि इनकी स्वीकृतियां कम जारी हुई हैं या ये बने नहीं हैं या इनका पेमेंट बाकी है...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): बने नहीं हैं, बने ही नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अगर इनकी स्वीकृति जारी हो गई है। चूंकि यह आपको मालूम है कि यह व्यक्तिगत लाभकारी योजना जो परिशिष्ट-2 में है, यह केटेगरी-2 का काम है। पहले इनकी केटेगरी-4 हुआ करती थी पर अब इनको संशोधन करके केटेगरी-2 में डाला है। यह मजदूर को मस्टररोल जारी होते हैं और इस काम को, व्यक्तिगत लाभकारी काम को मजदूर को करना पड़ता है। अगर मस्टररोल जारी करने के बाद उन्होंने काम चालू नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि वह मजदूर काम करने में अनिच्छा प्रकट करता है और मस्टररोल जारी करने के बाद उन्होंने काम किया और पेमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब निश्चित तौर पर विभाग को पेमेंट करना चाहिए। 15 दिन के अंदर श्रम का पेमेंट करना, यह मेंडेटरी है और 15 दिन में अगर पेमेंट नहीं हो तो 0.05 परसेंट प्रतिदिन का मुआवजा देने का भी प्रावधान इसके अंदर है।

जहां तक सामग्री मद का मामला है अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर भारत सरकार से रिलीजेज कुछ समय विलम्ब से मिली। 400 करोड़ रुपये का सामग्री मद के अंदर बकाया था। राज्य सरकार ने अपने खुद के उससे 269 करोड़ रुपये हमें दिया है और अभी कल ही को 163 करोड़ रुपये हमने और दिये हैं और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आने वाले 15 दिन के अंदर सामग्री मद का जो पैसा है, वह सारा का सारा पैसा हम चुकायेंगे और चूंकि यह प्राकृतिक संसाधन से संबंधित कार्य है, इस बार नरेगा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के अंदर जो गाइडलाइन आई हैं, उसमें 65 फीसदी करने हैं। हमने 2015-16 के अंदर भी लगभग 15,105 कुण्ड बनाये थे, 2016-17 में 22,223 बने थे और इस बार हम इनकी संख्या को और बढ़ायेंगे और माननीय सदस्य, आप ही के पत्र पर, आपने एक पत्र लिखा था कि 30,000 लीटर का कुण्ड आपने मेंडेटरी कर रखा है, इसको आप और बढ़ायें। हमने उसको एग्जामिन किया और वह 30,000 लीटर का ही कुण्ड बने, उस प्रतिबंध को हमने हटा दिया है। अब वहां की स्थिति-परिस्थिति को देखकर, कैचमेंट एरिया को देखकर, हम उन कुण्ड का निर्माण करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं में माननीय मंत्री महोदय, तीन लाख रुपये जलकुण्ड बनाने के लिए दिये जाते हैं। व्यक्तिगत लाभ में एक तो जलकुण्ड है, व्यक्तिगत लाभ में कैटल शैड है। अब आप ध्यान करें कि 60,000 रुपये तो आप जलकुण्ड के दे रहे हैं और 60,000 रुपये कैटल शैड के दे रहे हैं। यह सब 1,20,000 रुपये तो ठीक हो गया। अब आप 1,80,000 रुपये उसको भूमि समतलीकरण के दे रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप भारत सरकार से कहें कि यह 60-40 का रेशो, यह सम्पत्ति निर्माण में 60-40 का रेशो बाधक है और 1,80,000 रुपये में, जो अपन उसको समतलीकरण के लिए दे रहे हैं। मेरा ठोस सुझाव है कि आप उसको तारबंदी के लिए दें। आखिर तो यहां रोज रोजड़ों की समस्या आती है सदन में। तारबंदी होगी तो किसान की फसल सुरक्षित रहेगी। बिना तारबंदी के कुछ सुरक्षित ही नहीं है। पचासों पशु रात को आते हैं। अब वह एक किसान उसकी रक्षा करने में असमर्थ रहता है। आप तारबंदी को एक लीगल फ्रिक्शन क्रिएट करिये कि...

श्री अध्यक्ष: आपस में बातचीत नहीं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ....यह समतलीकरण के बराबर ही माना जायेगा और आप उसको कहीं सोलर पैनल दीजिये 1,80,000 रुपये में और कहीं ड्रिप इर्रिगेशन दीजिये। मेरा निवेदन यह है कि 1,80,000 रुपये का भी सदुपयोग करिये। एक बार जिसको तीन लाख रुपये मिलता है, उसको

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अपने आप, अपने पाँव पर खड़े होने का पूरा अवसर है और सरकार यदि इसमें संशोधन कर ले, समतलीकरण, मिट्टी हटाना, मिट्टी को बराबर करना, माननीय मंत्री महोदय, आप स्वयं सब गांवों के बीच में रहते हैं। आपको मालूम है कि इस प्रोविजन का दुरुपयोग होता है, इसलिए इसमें आप तारबंदी, सोलर पैनल, ड्रिप इर्रिगेशन को डालने का काम करें तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को एक किसान बिलकुल अपने पाँव पर खड़ा हो जायेगा। एक बार नरेगा में आने के बाद दुबारा नरेगा में आएगा नहीं। दो मजदूर अपने खेत पर लगाने का काम करेगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि नरेगा एक्ट है। इस एक्ट के शिड्यूल के अंदर वह कार्य जो नरेगा के अंतर्गत हम कर सकते हैं, उनका उल्लेख किया गया है।

माननीय सदस्य ने तारबंदी की बात की। निश्चित तौर पर यह व्यावहारिक बात तो है। अभी केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रीजी आये थे। मैंने व्यक्तिगत तौर पर सिर्फ उनको अनुरोध किया था कि कम से कम हमारे जो चरागाह बचे हुए हैं। चरागाहों के चारों तरफ भी अगर तारबंदी हो जाये तो चरागाह सुरक्षित हो सकते हैं। राज्य रोजगार परिषद है, उसकी बैठक में हम प्रस्ताव लेंगे और केन्द्र सरकार को भेजेंगे कि इस प्रकार अगर तारबंदी होती है तो राजस्थान को फायदा है।

दूसरा, आपने कहा कि रोजगार से संबंधित जितने भी लोग हैं निश्चित तौर पर हम कोशिश करेंगे और मैंने आपको पहले ही निवेदन किया कि सामग्री के मद के अन्दर कुछ बकाया था। सामग्री मद के अन्दर अभी हमारे पास कुछ रिलीजेज आये हैं हम इसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मंत्री महोदय ने जो बात बताई कि रोजगार मांगने पर दिया जाता है। यह

(श्री मनोज कुमार)

मांगने वाला प्रश्न है या आप मुझे यह बता दें एक तो कि राजस्थान में आपने फार्म नं. 6 की पालना कितनी कराई है? अगर फार्म नं. 6 की पालना के बिना भी आपने रोजगार दिया है, और नहीं तो इसको मेंडेटरी करें कि फार्म नं. 6 भरवाया जाए और हर पंचायत में बाध्य करें।

दूसरा, इसमें बीपीएल एससी/एसटी को कुंड बनाने की बात है व्यक्तिगत लाभ की, इसमें पंचायत प्लान में जिनको शामिल करती है उनको तो मिल जाता है, लेकिन यह राजनीतिक द्वेष से या आपस में गांव में विरोध के कारण इनको व्यक्तिगत लोग जो चाहते हैं उनको नहीं मिलता है इसलिए इसमें पारदर्शिता करने का आपका कोई विचार है क्या कि सीधा ऑनलाइन आवेदन करे या बीडीओ को आवेदन करे तो उन लोगों को भी लाभ मिल जाए जो पंचायत के प्लान में शामिल नहीं किये गये?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की अनुसूची-2 के पैरा-6 में प्रावधान है कि जॉब कार्ड द्वारा परिवार सदस्यों की कार्य की मांग किया जाना अनिवार्य है और माननीय सदस्य ने कहा कि फार्म नं. 6 निश्चित तौर पर निर्धारित प्रपत्र नहीं हो, सादे कागज पर भी वो मांग करे तो उसको सौ दिन का रोजगार एक साथ या अलग-अलग टुकड़ों में दिया जा सकता है। आपने कहा कि व्यक्तिगत लाभकारी योजना के अन्तर्गत कैटेगरीज के अन्दर भेदभाव होता है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूं कि जो जॉब कार्ड जिस परिवार का है उसमें वरीयता में सबसे पहले शिड्यूल्ड कास्ट है, उसके बाद शिड्यूल्ड ट्राइब है, उसके बाद बीपीएल परिवार है और महिला मुखिया परिवार यानी जिस परिवार की मुखिया महिला है और उसके बाद दिव्यांग परिवार, जिस परिवार का मुखिया अगर दिव्यांग है तो वो है और फिर इन्दिरा आवास के लाभार्थी हैं और उसके बाद लघु सीमान्त हैं। इस कैटेगरी के एग्जोस्ट होने के पश्चात् सामान्य व्यक्ति अगर इसमें आवेदन करता है तो उनके पश्चात् उनको देने का प्रावधान है और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर अब ये बात चल रही है कि नरेगा में भी ऑनलाइन पूरा का पूरा पेमेंट हो ही रहा है। इसके अन्दर मैं समझता हूं कि किसी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। हां, काम करने के लिए अब नरेगा सोफ्ट के अन्दर अगर वो सौ दिन का रोजगार मांगता है तो नरेगा सोफ्ट के अन्दर वो अपने-आप परिलक्षित होने लग जाता है, उसमें इन्द्राज करना पड़ता है और उसके बाद जब वो अपना रोजगार पूरा कर लेता है तो भी मस्टररोल नरेगा सोफ्ट में जाता है और नरेगा सोफ्ट के अन्दर जाने के बाद, उसके वैरीफिकेशन के बाद पैसा भी उसी के खाते में जाता है इसलिए मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की क्रिया-प्रतिकिया इसमें है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव होने की गुंजाइश माननीय अध्यक्ष महोदय, अब है नहीं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न, श्री दर्शन सिंह।

श्री दर्शन सिंह (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे करौली विधान सभा क्षेत्र में गुढ़ला ग्राम पंचायत क्षेत्र में दो साल से महात्मा गांधी रोजगार योजना के तहत कोई काम नहीं दिया जा रहा है तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां रोजगार लोगों को दिलाया जा सके, धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरा प्रश्न बीकानेर व लूणकरणसर पंचायत समिति से संबंधित था। फिर भी माननीय सदस्य अगर दो साल से लगातार नरेगा के अन्दर मांगने पर काम नहीं दिया जा रहा है तो यह अत्यंत गंभीर बात है आप मुझे लिखकर दें। मैं जांच कराऊंगा और उत्तरदायित्व का निर्धारण करके उस अधिकारी/कर्मचारी पर कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बहुत इम्पोर्टेंट बात है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आपका बाद में बटन दबा है। नहीं, यह नहीं। दूसरे भी तो हैं अब उन्होंने पहले दबाया है। कोई आपके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। विराजो, श्रवण जी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमारा तो आने ही नहीं दे रहे हो। क्या करेंगे बैठ कर। हमारे पास उपाय क्या है। नहीं बैठेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्रवण जी, बैठिये। सबको दे रहा हूं मैं मौका। पक्षपात कर रहा हूं क्या? इधर से दो लिये मैंने, उधर से एक लिया है। आप बटन तो पहले दबाते नहीं, फिर बीच में, अब दबाया है आखिरी में तो आखिरी में नाम है मैं तीन से ज्यादा नहीं दे सकता। बैठिये। हां, श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि नरेगा में फार्म-6 भर कर आवेदन करने पर रोजगार दिया जाता है और अगर रोजगार नहीं दिया जाता है तो उसको कम्पनसैट किया जाता है। माननीय मंत्री महोदय बतायें कि पिछले दो साल में ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने फार्म-6 भरा और उनको समय पर रोजगार नहीं मिलने के कारण कम्पनसैट किया गया? क्या यह जो फार्म-6 की प्रक्रिया है...

श्री अध्यक्ष: यह लूणकरणसर से संबंधित है सवाल।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): लूणकरणसर का मान लें सर, इसको।

श्री अध्यक्ष: नहीं, लूणकरणसर का कैसे मान लें।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): लूणकरणसर में ही कितने लोगों को दिया? लूणकरणसर में बता दें कि क्या इस फार्म-6 की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: नहीं, बैठिये। नहीं यह रिलेवेंट नहीं है। विराजिये। रिलेवेंट सवाल होना चाहिए। आप देंगे क्या जवाब? दे दीजिये जवाब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान इस बार भी नरेगा के अन्दर हर क्षेत्र में पहले नम्बर पर है। हमने देश में सर्वाधिक खर्चा इसमें किया। इस बार पांच हजार चालीस करोड़ रुपये का किया है और सर्वाधिक मेन डेज जनरेट किये हैं हमने। हमारे मेन डेज, अब पैंतालीस लाख परिवारों को दिया है और चौबीस करोड़ से ज्यादा मेन डेज दिये हैं हमने। यह इस बात को सिद्ध कर रहा है कि राजस्थान में नरेगा का काम बेहतरी से चल रहा है और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया कि अब सब चीज ऑनलाइन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है। वो फार्म-6 भरे या सीधे सादा कागज पर वो आवेदन करे, नरेगा सोफ्ट के अन्दर वो इन्द्राज होता है। नरेगा सोफ्ट में उसके जॉब कार्ड के अन्दर ही फिर जब वो काम कर लेता है तो उसका सारा बिल जाता है और ऑनलाइन होकर ही सारी प्रक्रिया निकलती है।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

प्रदेश में पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत भ्रूण लिंग जांच के दर्ज प्रकरण

271. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रदेश में भ्रूण लिंग जांच को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए क्या-क्या ठोस कार्यवाहियां की गई हैं?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत गत तीन वर्षों में विशेष अभियान चला कर भ्रूण लिंग जांच को पूर्णरूप से समाप्त करने व अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करने तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रयास किए हैं? यदि हां, तो कब-कब व क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में गत तीन वर्षों में भ्रूण लिंग जांच के कितने प्रकरण पाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कुंड बनाये हैं इनकी प्रक्रिया क्या है जो आज तक तैयार होने के बाद में पानी नहीं भरता है। तालाब तैयार हो गये उनमें आज तक पानी नहीं भरता है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। इस तरह नहीं। नो-नो। इस तरह नहीं। अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइये। श्रवण जी, आपकी आदत पड़ गयी है। आप बटन दबाते नहीं हो और हर बार बीच में खड़े हो जाते हैं। नहीं, अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: नो-नो। बैठिये आप।

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री अध्यक्ष: हां, नहीं होगा। दादागीरी है। अंकित नहीं हो एक भी शब्द इनका।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: श्रवण जी, जवाब नहीं आएगा। जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। हां, माननीय मंत्री महोदय।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): (1) राज्य सरकार द्वारा भ्रूण लिंग जॉच को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिये समुचित प्राधिकारियों द्वारा राज्य में पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम के तहत गत तीन वर्षों में (दिनांक 01.01.2014 से दिसम्बर 2016 तक) 520 सोनोग्राफी केन्द्रों का पंजीकरण, 4750 सोनोग्राफी केन्द्रों का निरीक्षण, 39 सोनोग्राफी केन्द्रों का निलम्बन, 76 सोनोग्राफी केन्द्रों के पंजीकरण को निरस्त एवं 91 सोनोग्राफी मशीनों को सील किया गया। 63 परिवाद न्यायालय में पेश किये गये, 108 अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया। अधिनियम के उल्लंघन पर दर्ज परिवादों में 21 चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन निलम्बित किया गया। 1 अप्रैल, 2014 से 28 फरवरी, 2017 तक कुल 39 डिकॉय ऑपरेशन किये गये, जिनमें 10 अन्तरराज्यीय डिकॉय ऑपरेशन सम्मिलित है। मुखबिर योजना के तहत 78 व्यक्तियों को 2 लाख रुपये प्रति व्यक्ति इनामी राशि प्रदान की गई। सभी 520 पंजीकृत केन्द्रों पर एक्टिव ट्रेकर उपकरण संबंद्ध किये गये है, जिससे सोनोग्राफी मशीनों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जा सकें।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी हां।

गत तीन वर्षों में भ्रूण लिंग जांच के तहत लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ 39 सफल डिकॉय ऑपरेशन किये गये जिनमें अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करने हेतु 10 डिकॉय ऑपरेशन भी शामिल है। जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में गत तीन वर्षों में लिंग जांच के कुल 39 प्रकरण पाये गये है, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नं. एक।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न राजस्थान प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण इश्यू की तरफ है। यह प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस प्रश्न की गंभीरता इतनी इम्पोर्टेंट है और यह राजस्थान प्रदेश को झकझोर देने वाला है। रोजाना सभी समाचार पत्रों के माध्यम से जिस तरह से खबरें आती हैं डॉक्टर लोग हो, और कोई लोग हो, एजेंट हो, नये-नये तरीके ईजाद करके बच्चियों की संख्या कम करने का प्रयास करते हैं, लिंग-भ्रूण परीक्षण करते हैं और आज के समाचार पत्रों में स्पेशली जोधपुर में खबर छपी है कि एक डॉक्टर साहिबान हैं वह बच्चों के दिल की धड़कन की जांच की जो मशीन होती है उसके साथ जोड़ कर के और ऐसे उपकरण लगाकर लिंग भ्रूण परीक्षण करने का प्रयास किया और विभाग ने पकड़ा, उसके लिये तो मंत्री जी आपका बहुत बहुत आभार है, आपको धन्यवाद भी है। डिकॉय आपरेशन के मार्फत से राजस्थान में जो क्रांति लाये हो, रोकने का प्रयास किया, उसके लिये भी आपका बहुत-बहुत आभार। आपके प्रयासों से ही केन्द्रीय स्तर पर आपको स्काच योग्यता पुरस्कार भी मिला है और नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला है, इसके लिये भी आपको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सीधा सवाल कीजिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा पहला प्रश्न है, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि राजस्थान प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर लिंगानुपात, 1 से 6 वर्ष के बच्चे और उसके ऊपर की जनसंख्या के आंकड़े प्राप्त करने

(श्री जोगाराम पटेल)

के क्या-क्या मापदंड हैं और लिंगानुपात के आंकड़े प्राप्त करने और जारी करने के लिये कौन-कौन अधिकृत हैं? आप यह भी बता दें कि राजस्थान ने इस संबंध में क्या नवाचार किया है? जैसे पीसीपीएनडीटी किया है, उसके आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में बच्चियों का लिंगानुपात क्या है?

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों में लगातार बेटियों की संख्या बढ़ रही है। हमारा प्रेग्नेंसी एवं चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम हर साल होने वाले जन्मों में से लड़के तथा लड़की का अनुपात निकालता है। अगर हम इन अनुपात को 2021 में होने वाली जनगणना तक बनाये रखेंगे तो हमारा बाल लिंगानुपात 930 से 935 के बीच में हो सकता है, जो 2011 में 888 से 42 अंक अधिक होगा। 2012 में 7 लाख 52 हजार लड़के और 6 लाख 80 हजार लड़कियां, यानी प्रति हजार लड़कों पर 904 लड़कियां थीं। 2013 में 7 लाख 65 हजार लड़कों पर 7 लाख 3 हजार लड़कियां, यानी 920 लड़कियां प्रति हजार थीं। इसी प्रकार से 2014 में 7 लाख 27 हजार लड़के और 6 लाख 82 हजार लड़कियां, लिंगानुपात था 927 और 2015 में 7 लाख 31 लड़कों के कम्पेरीजन में 6 लाख 80 हजार लड़कियां, यानी 930 का अनुपात और 2016 में 7 लाख 40 हजार के कम्पेरीजन में 6 लाख 86 हजार, यानी 939 का रेशो। हर वर्ष 14 लाख से ज्यादा जन्म का आंकड़ा जो हमारे पास आता है उसमें हम लिंगानुपात निकालते हैं। जब हमारे द्वारा जवाब दिया गया था तब इस वित्तीय वर्ष में 30 डिकॉय आपरेशन हो गये थे, पर सवाल देने और आज सदन में आने तक तीन डिकॉय आपरेशन और हो गये। इससे कन्या भ्रूण जांच के प्रति हमारी निष्ठा का पता चलता है। एक आपरेशन तो कल सायंकाल ही जोधपुर में किया गया था और आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा, हमारी टीम लगातार काम कर रही है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): ...(व्यवधान)... बेटियां बढ़ गईं उसका जोड़ तो राठौड़ साहब का लगाया हुआ है।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक ही बात है, राठौड साहब में और हमारे में कोई फर्क नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है, जैसा आपने बताया आपके प्रभाव से लिंगानुपात में बहुत सुधार हो गया। आपने राजस्थान में जो नवाचार किया है जिसका आपने अपने जवाब में जिक्र नहीं किया है और इस नवाचार की वजह से ही राजस्थान को स्काच का पुरस्कार मिला है और पीसीटीएस का जो नवाचार है उसकी देश में बहुत प्रशंसा हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि आपके इस पीसीपीएनडीटी एक्ट की प्रभावी कार्यवाही के लिये जो आपने डिकॉय आपरेशन किया है, इससे छह वर्षों में राजस्थान में लिंगानुपात में सुधार हुआ, उसका तो वर्णन आपने कर दिया लेकिन राजस्थान प्रदेश स्तर पर जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय पारित किया, उसके आधार पर आप क्या क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? पुलिस स्तर पर और कोर्ट स्तर पर जो इन्वेस्टीगेशन पेंडिंग है या जो कोर्टों में केस पेंडिंग है, उनमें प्रभावी सज़ा दिलाने, इन्वेस्टीगेशन जल्दी होने, कोर्ट में चालान पेश करने और इसका प्रचार और प्रसार करने का ताकि इसमें सुधार हो सके, इस संबंध में आप क्या-क्या कार्यवाही कर रहे हैं? जनहित याचिका संख्या 3270/2012 में दिनांक 15.04.2015 को जो आदेश पारित किया, एस.के. गुप्ता बनाम यूनियन इंडिया में, उसकी पालना में आप क्या-क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए, माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने कार्यवाही के बारे में पूछा, मैं बताना चाहूंगा कि पीएसपीएनडीटी एक्ट के तहत 145 मुकदमों में कुल 202 व्यक्तियों को सज़ा हुई है। जिसमें 125 चिकित्सक और 77 दलाल और अन्य व्यक्ति हैं। अभी 2017 में ही 3.06.2014 को हमारी टीम द्वारा किये गये डिकॉय कार्यवाही के तीन आरोपियों को माननीय न्यायालय ने कडी सज़ा सुनाई है। अर्जुन लाल, खेताराम और रूबीना को माननीय न्यायालय द्वारा तीन तीन वर्ष कारावास तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सज़ा देकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इससे यह जाहिर होता है कि इस समय हमारे विभाग का न्यायपालिका के साथ इस अभियान में पूरा सहयोग होने के कारण भ्रूण जांच और कन्या भ्रूण हत्या में लिप्त लोगों में कानून का भय उत्पन्न हुआ है।

(श्री कालीचरण सराफ)

आपने पूछा कि आप क्या-क्या नवाचार कर रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने राजश्री योजना प्रारंभ की है। बालिकाओं के जन्म और स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 1 जून, 2016 से मुख्य मंत्री राजश्री योजना को प्रारंभ किया है, जिसमें 6 किश्तों में अधिकतम 50 हजार का परिलाभ उनके माता-पिता को देय है। प्रसव के बाद 2500 रुपये, एक वर्ष की उम्र पर टीकाकरण पूर्ण होने पर 2500 रुपये, पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 4000 रुपये और कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5000 रुपये, कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11000 रुपये और कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर 25000 रुपये। इसी प्रकार से नि:शुल्क साइकिल योजना, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, गार्गी पुरस्कार, बारहवीं क्लास के बाद टॉपर्स को स्कूटी और 6 से 8 कक्षा तक की बच्चियों के लिये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और शारदीय हॉस्टल 9 से 12 कक्षा तक की बच्चियों के लिये और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। इस प्रकार के नवाचार हमने किये हैं। निश्चित रूप से इनका अच्छा प्रभाव पड़ा है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): विभागीय अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिये कोई पुरस्कार देने की योजना रखते हैं या नहीं रखते हैं ताकि विभागीय आदमी इफेक्टिव कार्यवाही करे।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, बिलकुल नहीं। जवाब देने की जरूरत नहीं। मैंने श्री सुखराम जी को बुला लिया, इसके बाद श्री घनश्याम तिवाडी। यह तीसरा पूरक प्रश्न है।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने यह कहा कि जो काम कर रहे हैं और जो अच्छे अधिकारी हैं उनके लिये सरकार क्या योजना बना रही है। निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों को पुरस्कृत करने का विचार हमारा है और हम करेंगे।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से जानना चाहूंगा 39 सोनोग्राफी केन्द्रों का निलंबन किया, 80 सोनोग्राफी केन्द्रों का पंजीयन निरस्त किया, 91 सोनोग्राफी मशीनों को सील किया। यह कुल 206 मशीने/केन्द्र हुए, उनमें से चालान सिर्फ 39 केन्द्रों का ही किया, 167 केन्द्र बचते हैं, उनको ले देकर छोड़ दिया, उनको चार्जशीट

(श्री सुखराम विश्नोई)
क्यों नहीं किया? 167 केन्द्रों के संचालकों के खिलाफ कोर्ट में कार्यवाही क्यों नहीं पेश की आपने?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): न्यायालय की अपनी एक प्रक्रिया होती है और न्यायालय में हमारी जो टीम है वह बिलकुल संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है और उसी का परिणाम है कि अभी तक 125 चिकित्सक ...(व्यवधान)...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कौनसा संकल्प, संकल्प क्या है? काहे का संकल्प है। कुल 167 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र क्यों नहीं पेश किया? किस बात का संकल्प है? कोई लेने देने का संकल्प है, संकल्प की परिभाषा तो होगी, कौनसा संकल्प है? 167 लोग क्यों छोड़े गये?

श्री अध्यक्ष: सुखराम जी विराजिए। श्री घनश्याम तिवाडी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी आंकडे दिये हैं और 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण का बजट के साथ आंकड़ा दिया है, उसमें फर्क है। उसमें प्रति 1000 बच्चों पर 888 बच्चियां 6 वर्ष के लिंगानुपात में आपने बताई है। अब जो 112 बच्चे बचे हैं उनमें से कितने लोगों को आप +++ बनाएंगे, यह बता दो आप।

श्री अध्यक्ष: मेरे बारे में जो इन्होंने बोला है, इसको एक्सपंज किया जाये।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह मैंने जो आंकडे बताये हैं यह 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का जो बाल लिंगानुपात है, वह बताया है। हमारी यह एक्सपैक्टेशन है कि 2021 में जब जनगणना होगी तो वह 888 से 939 तक पहुंच जाएगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(12.00 बजे)

अनुपस्थिति अनुमति

कल्याण सिंह चौहान, श्री, सदस्य को 22 मार्च, 2017 से सत्रांत तक

(श्री अध्यक्ष)

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री कल्याण सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 22 मार्च, 2017 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थिति रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से प्रदेश में शराबबंदी लागू करने के संबंध में।
2. श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के ग्राम बबाई में स्थित डेयरी संयंत्र के भवन निर्माण में हो रहे विलंब से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
3. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांचौर में नर्स श्रेणी द्वितीय के पद समाप्त किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
4. श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से जिला भरतपुर के थाना सेवर के पंछी का नगला क्षेत्र में पुलिस द्वारा दबिश के दौरान पोखर में छलांग लगाने से दो युवतियों की मृत्यु होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
5. श्री रमेश, सदस्य की ओर से प्रदेश में सिलिकोसिस बीमारी के मरीजों के प्रमाण-पत्र नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

6. श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र

(श्री अध्यक्ष)

कोटपूतली में स्वीकृतशुदा अंडरपास एवं फ्लाईओवर को निरस्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में आवासरत छात्र-छात्राओं को निम्न स्तर की खाद्य सामग्री दिए जाने के संबंध में।

8. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से जिला नागौर के जायल क्षेत्र में मात सुख पेयजल परियोजना में बरती जा रही लापरवाही व अनियमितता के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह यादव, श्री घनश्याम एवं श्री हनुमान बेनीवाल को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनिट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ की ग्राम पंचायत सिंघाना को नगरपालिका बनाने के संबंध में।

2. श्रीमती सूर्यकांता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में।

3. श्रीमती गोलमा, सदस्य की ओर से पंचायत समिति सपोटरा के कालीसिंध बाँध के बहाव क्षेत्र में बनाये गये मॉडल तालाब के निर्माण कार्यों की जांच कराने के संबंध में।

4. श्री नाना लाल अहारी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के उपखण्ड मुख्यालय ऋषभदेव के रेफरल चिकित्सालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खैरवाड़ा में शैय्याओं की संख्या बढ़ाने के संबंध में।

5. श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा के अरिहंत नगर, हलेड़ में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित किए जाने से

उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

6. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में मोबाइल टॉवर लगाये जाने के संबंध में।
7. श्रीमती सोनादेवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में दिनांक 9 अक्टूबर, 2016 को आये चक्रवाती तूफान से प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि दिए जाने के संबंध में।
8. श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से उपखण्ड मुख्यालय निवाई में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता का खण्ड कार्यालय खोले जाने के संबंध में।
9. राजकुमारी दियाकुमारी, सदस्य की ओर से मलारना डूंगर, (सवाई माधोपुर) में स्वीकृत मॉडल महाविद्यालय हेतु शीघ्र भूमि आवंटन कर इसे प्रारंभ करने के संबंध में।
10. श्री जगदीश नारायण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ में वन अभयारण्य क्षेत्र में आने वाले गांव की जमीनों की रजिस्ट्री पर लगी रोक हटाने के संबंध में।
11. श्रीमती कामिनी जिन्दल, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स लिमिटेड बंद होने के कारण शेष श्रमिकों के अन्य विभागों में समायोजन के संबंध में।
12. श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से घरेलू विद्युत कनेक्शनों की राशि डीएलसी रेट से लिए जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 22 मार्च, 2017 को शून्यकाल में बोलने हेतु 47 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

1. श्री सुरेश धाकड़, भैसरोडगढ़ व रावडदा में पेयजल योजना स्वीकृत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

2. श्री शंकर सिंह, यातायात विभाग के अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरते जाने के संबंध में।
3. श्री फूल सिंह मीणा, उदयपुर के कलड़वास रीको एरिया व पानेरियों की मादड़ी में किसानों को पट्टा दिए जाने के संबंध में।
4. श्रीमती अनीता, नगर विधान सभा क्षेत्र में सेवल मंदिर पर हो रहे खनन कार्य को रोके जाने के संबंध है।

श्री राजेंद्र सिंह यादव। श्री राजेंद्र सिंह यादव अनुपस्थित है क्या?

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी लड़कियों की चर्चा चल रही थी। अनुपात की बात भी चल रही है। सेवर थाना में जो घटना घटी है, वह बड़ा गंभीर इश्यू है। दो बच्चियों की पोखर में डूबने से मौत हो गई और एक बच्ची को हमारे वहां के प्रशिक्षु आई.पी.एस. ऑफिसर श्री सुधीर चौधरी ने हिम्मत करके, खुद तालाब में कूदकर जान बचाई। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर इश्यू है।

श्री अध्यक्ष: नो, नो। कई तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। सब इम्पोर्टेंट हैं। आनी भी चाहिए, पर यह व्यवस्था के अनुरूप होगा। आप बैठिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था तो आपके हाथ में है। आज आपका जन्मदिन है। आज तो आप कृपा कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, जन्मदिन के बहाने दुहाई मत दो। श्री घनश्याम।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में निम्न स्तर की खाद्य सामग्री का वितरण

श्री घनश्याम (टोडाभीम): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम-50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संचालित छात्रावासों में आवासरत छात्र-छात्राओं को खाद्य सामग्री एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति सहकारिता विभाग के कांट्रेक्ट द्वारा जुलाई, 2016 एवं जुलाई, 2017 में एक निजी फ़र्म के माध्यम से की जा रही है,

(श्री घनश्याम)

जिसमें खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की कमी व अन्य वस्तुओं की आपूर्ति की मात्रा में कमी व निर्धारित ब्राण्ड बदलकर निम्न स्तर के ब्राण्ड की सामग्री की आपूर्ति की जा रही है। जो सामग्री की आपूर्ति की जा रही है, वह एक्ट के अनुसार नहीं है।

श्री अध्यक्ष: कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठें। आपस में बातचीत नहीं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): निम्न स्तर की सामग्री सप्लाई की जा रही है, जिसकी पुष्टि श्रीमान् जिला कलेक्टर, चूरू के निर्देश अनुसार की गई। कार्यवाही भी हो गई है। परंतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चूरू द्वारा इस संबंध में आधी-अधूरी कार्यवाही की गई है। इस प्रकार उक्त सामग्री की सप्लाई समयावधि में नहीं हो रही है। चालानों में भी अनेक प्रकार की हेराफेरी की गई है। फर्जी तरीके से चालन पेश किए गए हैं। इसका भुगतान भी उठा लिया गया है। जिसकी शिकायत खुद सहकारिता विभाग के प्रबंध महानिदेशक द्वारा की जा रही है। कांट्रेक्ट को भी इसको दिया गया। परंतु उक्त प्रकरण की सरकार द्वारा जांच न करवाकर, आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आपूर्ति निजी फर्म द्वारा कांट्रेक्ट के माध्यम से कराकर आवासरत छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाले में गरीब छात्र-छात्राओं के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है, इस तरह का भेदभाव हो रहा है। सरकार इस मामले की अनदेखी कर रही है। इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। कंपनी को बहुत सारा फायदा इसमें हो रहा है। इस मामले के पूरे तथ्य मेरे पास हैं और इन तथ्यों की जांच के लिए मैं इस पूरे प्रकरण को आपके माध्यम से टेबल कराना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी को दे दीजिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): इसकी जांच कराई जाए, अन्यथा इन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो रहा है। गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: गंभीर है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): जो भी सामग्री आई है, एक बार जांच कमेटी बैठाकर उन सामग्रियों की आप जांच कराएं, मेरा आपसे यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: जवाब भी दे दीजिए और कागज भी ले लीजिए, इनके पास जो भी हैं। पहले आप जवाब दे दीजिए।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नियंत्रण में 750 के लगभग छात्रावास संचालित होते हैं। 2015-16 से पहले इन सब छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक को अधिकार था। उनका दिन भर का एक चार्ट बना उस हिसाब से सामग्री का स्वयं प्रोक्योरमेंट करके बच्चों को दे। 2015-16 से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने तय किया कि इन सबको, एक लिस्ट क्या-क्या, 1040 रुपये का एक कोम्बो पैक बनाया और 1040 रुपये के कोम्बो पैक में उनका सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, चाय के साथ बिस्कुट वगैरह और रात का खाना, इसके सब आइटम तय किए। आइटम में उनके ब्रांड भी तय किए कि किस ब्रांड का मैटेरियल उनको सप्लाई किया जाएगा। जून 2016 में एक आदेश इसी बात का निकाला और हमने कानफेड को इसका आदेश दिया कि इस-इस तरह के इन-इन आइटम को लेंगे। किस ब्रांड का आइटम होगा यह भी उसमें देने की बात की। पूरी गाइड लाइन जारी की कि किस ब्रांड का दिया जाएगा, किस समय तक दिया जाएगा, कितनी मात्रा में होगा, कब सप्लाई होगा, पूरा। अगर इसमें कोई भी डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है तो उस कमी के लिए भी क्या-क्या पैनल्टी इम्पोज की जाएगी, वह भी रखी गई।

माननीय सदस्य ने बताया चूरू का एक विषय जुलाई या अगस्त महीने में आया था। वहां बच्चियों ने कहा कि वहां के आटे की गलत क्वालिटी थी। कलेक्टर को इसकी जानकारी हुई। उस आटे के बारे में कानफेड को 11.08.2016 को एक पत्र हमारे डायरेक्टर के द्‌वारा लिखा गया। उनको कहा कि इस तरह की जांच की मांग आई है, इस तरह की शिकायत आई

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

है। कलेक्टर ने खुद जाकर की। उसकी जांच के लिए हमने मेडिकल हैल्थ डिपार्टमेंट को सैम्पल भेजा। कानफैड को भी भेजा कि इस तरह की चीज को आप तुरंत चेंज करें। उसको पैनल्टी इम्पोज करने की बात की। आगे इसमें किसी प्रकार की नहीं हो। उसमें हमारा नियम है कि एक बार या दो बार, किसी तरह की क्वालिटी में गोता या क्वांटिटी में कमी होती है तो दो बार तक तो उसमें दण्ड का प्रावधान है। तीसरी बार उसी प्रकार का, अगर सप्लायर कानफैड किसी तरह की कमी करेगा तो उसको रद्द करने का भी या किसी और को देने का भी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने इसको रखा हुआ है। तुरंत काग्नीजेंस देकर उनको सावचेत किया गया कि आप इसके ऊपर बदले, उसको करने का। माननीय सदस्य ने बताया, अगर आपके पास इसमें से कोई शिकायत हो, जो आपने बताई है तो मुझे दें।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): इसमें जांच हो गई। जांच हो जाने के बाद भी आपने पेमेंट नहीं रोका, कम्पनी को पेमेंट करते रहे। कम्पनी ने घटिया सामग्री पेश की है। छोटे बच्चे छात्रावासों में रह रहे हैं, उनके साथ इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना संवेदनशील है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। नोट कर लिया, विराजिए।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपने स्थगन में अगर पेमेंट वाला विषय भी रखा होता तो मैं आपको उसका जवाब भी दे देता कि कितना हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, सारी चीज। फिर भी जो भी आपके पास है इस विषय पर पूरी सरकार और विभाग संवदेनशील है। हम बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किसी तरह का कोई कम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। एजेंसी उसके साथ कोई भी गड़बड़ करेगी और आपके पास कोई सूचना है तो दें, निष्पक्ष जांच कराएंगे। अगर पेमेंट उसके बाद भी हुआ है तो उसकी भी जांच कराएंगे। कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई अधिकारी जिम्मेदार है तो उस पर कार्यवाही भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री बेनीवाल।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): पेमेंट नहीं रोका।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब आप बैठिए। मिस्टर घनश्याम बैठिए। श्री बेनीवाल को पुकार लिया मैंने।

जायल की मातासुख पेयजल परियोजना में अनियमितता

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि मातासुख माइंस है जहां लिग्नाइट भारी मात्रा में निकलता है। इस माइंस की खुदाई के दौरान खारा पानी बहुतायत मात्रा में निकलता है। 2010 में सरकार ने निर्देश दिया था कि आरएसएमएमएल और पीएचईडी के मध्य में इस परियोजना के अन्तर्गत एक एमओयू हुआ। उस एमओयू की सतह यह थी कि कम्पनी को 20 एमएलडी क्षमता का आर ओ प्लांट वहां लगाना था। उसके बाद जायल क्षेत्र के 120 गांवों को 13 मिलियन लीटर शुद्ध पानी उपलब्ध कराना था मगर अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से पिछले तीन-चार साल, पांच साल के अंदर जब से ये कम्पनियां भुगतान उठा रही हैं, आज तक मात्र एक मिलियन पानी, वह भी तीन दिनों के अंदर जायल क्षेत्र की जनता को पिलाया जा रहा है। इस पेयजल से वहां के पशुधन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। कई लोग बीमार हो गए। और तो और जब सरकारी लेब के अंदर उस पानी की जांच कराई तो पानी शुद्ध नहीं था। गुजरात की डोसी कम्पनी है, वहां डोसी कम्पनी के द्वारा वाटर को शुद्ध किया जा रहा है। राम की कम्पनी पीएचईडी के माध्यम से, वह 120 गांवों के अंदर पानी पहुंचाती है।

(12.14 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, जब इसकी जांच सरकारी लैब से कराई गई तो इसका टीडीएस 1100 पीपीएम था जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत घातक है। इस मामले को लेकर वहां पर बहुत बड़े आंदोलन हुए। 120 गांव के लोगों को आज तक, 3-4 साल के अंदर शुद्ध पानी नहीं मिला। अनुबंध की तुलना में बहुत कम पानी उन गांवों के अंदर गया। अब गर्मी का मौसम आ गया। वहां पर लोग फिर आंदोलित है। यहां दो-तीन बार, 2014 से लेकर तीन कलक्टर, तीन बार उसकी जांच करने गए। दो कलक्टर ने कम्पनी के खिलाफ रिपोर्ट भेजी लेकिन एक कलेक्टर डा. वीना प्रधान 31.05.2014 में

(श्री हनुमान बेनीवाल)

वहां थी, उसने रिपोर्ट भेजी, प्लांट से पानी का किसी भी तरह का अवैध हस्तान्तरण नहीं हो रहा है व पानी पीने योग्य है। उक्त समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभागों के मध्य उच्च स्तर पर निर्णय लिया जाकर इस समस्या का त्वरित निराकरण करवाया जाना अति आवश्यक है। उस कलेक्टर के ट्रान्सफर होने के बाद जो दोनों कलेक्टर नागौर में आए, उनकी रिपोर्ट भिन्न है। दोनों कलेक्टर ने मौके पर जाकर माना कि कम्पनी गलत तरीके से, जो शर्तें, एमओयू था, और तो और इसके अंदर पहले जो पानी यहां लिया जा रहा था, उस पानी की रेट भी अलग-अलग तरीके से भिन्न आई। पहले 42 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से भुगतान किया और फिर 52 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से भुगतान किया गया। प्रतिमाह डेढ़ करोड़ रुपये का नुकसान है, राजस्थान की सरकार को राजस्व घाटा हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह वह बांकापट्टी है जिसका नाम निश्चित रूप से आपने भी सुना होगा। पूरा राजस्थान जानता है, देश जानता है कि इस इलाके का पानी पीकर लोग बाँके-टेढ़े हो जाया करते थे। बहुत ज्यादा फ्लोराइड इस इलाके के अंदर था। आज लोगों को पीने के पानी के लिए टैंकर मंगाने पड़ते हैं। टैंकर 1500 से लेकर 3000 रुपये तक आता है, पर लोग उसके अंदर पानी पीने को मजबूर है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि 2013 में सुराज संकल्प यात्रा के दौरान आपके मुख्य मंत्रीजी वहां गए थे, उनके सामने जब यह शिकायत आई तो उन्होंनेयह कहा कि अगर मेरी सरकार बनी तो इसकी मैं जांच करवाऊंगी। सरकार बने हुए साढ़े तीन साल हो गए, कम से कम एक जांच तो इस पूरे प्रकरण की करा देते राठौड़ साहब। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आपकी सरकार से डोसी और राम नामक कम्पनियां मिलकर करोड़ों रुपये का भुगतान उठा रही हैं। वहां लोग बीमार पड़ रहे हैं। देखिए साहब, आपकी विधायक का बयान भी मैंने पढ़ा वहां पर। विधायक ने कहा कि यह पानी पीने लायक नहीं है। हमारी जनता यह पानी नहीं पी सकती। यह पानी बदबूदार है और कलेक्टर ने मौके पर जाकर यह बात कही कि इस पानी को पीकर लोग कैसे जिंदा रहते हैं, कैसे यह पानी पीते हैं। साहब, कम से कम

(श्री हनुमान बेनीवाल)

यह संदेश तो मत दो। जो बात आपके सामने आ गई, उस बात पर आपको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। आपकी सरकार को गंभीर होना चाहिए। आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना। गोगडाव के अंदर नागौर लिफ्ट का पानी आ रहा है, नागौर खींवसर क अंदर वहां 74 एमएलडी पानी उपलब्ध है। तो आप गोगोलाव से सीधा जो फड़ोद पड़ता है जायल के अंदर उसकी, दूरी 35 किलोमीटर, आप तो सिर्फ 35 किलोमीटर पाइप लाइन बिछा दें। वहां से 120 गांव के अंदर टंकियां वगैरह, मातासुख परियोजना की बनी है उसके अंदर पानी डाल दें तो 120 गांवों को पानी भी मिल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी, से निवेदन है, मंत्रीजी बैठे ही नहीं है, आज यहां है ही नहीं। मैं सिर्फ आपसे यही मांग करताहूं कि आप इसकी एक कमेटी बनाकर या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से इसकी जांच कराए। एक कलेक्टर तो यह रिपोर्ट देती है कि पानी सही है, मैंने जाकर देख लिया। उसके बाद, एक-दो महीने बाद जो कलेक्टर आते हैं, फिर छह महीने बाद दूसरी रिपोर्ट जाती है, कलेक्टर मौके पर जाते हैं वे यह कहते हैं कि कम्पनी पानी सही नहीं दे रही है, पानी ठीक नहीं है, पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी इस मामले में संरक्षण चाहूंगा क्योंकि जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। हमारा पशुधन वहां पर मर रहा है। लोग गंदा व बदबूदार पानी पीने को मजबूर है। नागौर लिफ्ट कैनाल का पानी या तो इन गांवों के अंदर पिलाया जाए और कम्पनी को करोड़ों रुपये का भुगतान गलत तरीके से, आपस में पीएचईडी, राम की और डोसी कम्पनी ने मिलकर करोड़ों रुपये का भुगतान गलत तरीके से उठाया है, इसकी जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से इसकी जांच होनी चाहिए। उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर इसकी जांच कराएं। और तो और, उपाध्यक्ष महोदय, जब भी कोई वहां जांच करने जाता और मैं कहता कि आपका पानी ठीक नहीं है तो कम्पनी वालों की दादागीरी देखिये, उपाध्यक्ष महोदय, पानी बंद कर देते और पी.एच.ई.डी. वाले हाथ खड़े कर देते कि हमारे पास तो पानी पहुंचाने का दूसरा साधन नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, 07 मार्च से इन्होंने प्लाण्ट को बंद कर दिया। इससे बड़ी इन लोगों की और क्या

(श्री हनुमान बेनीवाल)

दादागीरी होगी? बताओ, हम पैसा दे रहे हैं, दुगुनी-तिगुनी कीमत के अन्दर, वे आपको पानी दे रहे हैं और 52 रुपये प्रति लीटर का पैसा भी राजस्थान सरकार से ले रहे हैं। फिर भी गुण्डागर्दी कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस कम्पनी के अन्दर जितना भी, मातासुख लिग्नाइट परियोजना से पीने का पानी इन 120 गांवों को पहुंचाने के अन्दर जो भी घोटाला हुआ है, जो भी गलत तरीके से भुगतान राजस्थान की सरकार ने, पी.एच.ई.डी. ने और आर.एस.एम.एम.एल. ने किया है, इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर, इस मामले की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जांच करायें और वहां लोगों को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध करायें। यह मेरा निवेदन आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार से है।

अब आप कह रहे हैं कि हम बहुत संवेदनशील हैं। जब हमारे पास शिकायत आती है तो हम तुरन्त कार्यवाही करते हैं। इससे बड़ी बात तो आ नहीं सकती कि जायल के अन्दर आपके विधायक ने भी वहां बयान दिया था। मुख्य मंत्री से भी आपके विधायक मिले थे कि गलत हो रहा है, यह हो रहा है, वह हो रहा है। यहां तो जांच की बात की जाती है लेकिन मौके पर जांच करने के लिये कोई कमेटी नहीं गई। कलेक्टर दो बार गये, तीन कलेक्टर गये। एक कलेक्टर ने तो इनके फेवर में रिपोर्ट दी कि पानी शुद्ध है, अच्छा है। उन्होंने शायद अपनी सैटिंग कर ली होगी। लेकिन दूसरे जो दोनों कलेक्टर थे उन्होंने कहा पानी ठीक नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस मामले में कलेक्टर ने गलत रिपोर्ट दी है तो कलेक्टर के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिये। जनता की जान के साथ, जनता की जान जोखिम में डाल-कर इस तरह जो लोग त्रस्त हैं, आजादी के 70 साल बाद भी अगर पीने के पानी के मामले में भी भ्रष्टाचार होगा और इस तरह वित्तीय अनियमितताएं होंगी तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा गलत बात नहीं हो सकती। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय कमेटी से, ए.सी.बी. से जांच करा कर वहां के लोगों को राहत दिलायें और नागौर लिफ्ट का पानी 120 गांवों के अन्दर पहुंचे। 35 किलोमीटर गोगोलाव से फड़ोद के अन्दर आप पाइप लाइन लगाकर इसको जल्दी से चालू करें और इस पूरे मामले की आप जांच करायें। ऐसा मैं निवेदन आपके

(श्री हनुमान बेनीवाल)

माध्यम से सरकार से करूंगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जायल विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 120 गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के सन्दर्भ में विषय यहां पर उठाया कि मातासुख से पानी जाना है। मैं आपके माध्यम से उनको जानकारी देना चाहती हूं कि ये 120 गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आर.एस.एम.एम.एल. और एक कम्पनी मैसर्स नागौर वाटर सप्लाई कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, जो डि-बूट के आधार पर इनके साथ में एक एग्रीमेंट हुआ। वह एग्रीमेंट था कि खारे पानी को मीठे पानी के अन्दर बदल कर 13 एम.एल.डी. पानी इन 120 गांवों को उपलब्ध कराना था। यह समय-समय पर जो पानी कम उपलब्ध कराया गया, उसके लिये जायल की माननीय विधायक महोदय के साथ में मीटिंग्स भी होती रहीं। आर.एस.एम.एम.एल. द्वारा 13 एम.एल.डी. के अगेंस्ट में 6-7 एम.एल.डी. ही पानी उपलब्ध कराया गया। यह जो एग्रीमेंट हुआ था वह 22.02.2010, पिछली सरकार के समय में यह एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन मात्र 6-7 एम.एल.डी. ही पानी उपलब्ध कराया जाता था। लास्ट एक साल के अन्दर सिर्फ 03 एम.एल.डी. पानी उपलब्ध कराया गया और पिछले तीन महीने में, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी के अन्दर यह मात्र एक-डेढ़ एम.एल.डी. तक ही पानी हमें उपलब्ध हुआ। इसके पश्चात अभी 07 फरवरी से तो यह पानी उपलब्ध कराना बिलकुल ही बंद है। जो आर.एस.एम.एम.एल. द्वारा उपलब्ध कराना है, वह प्लाण्ट बिलकुल ही बंद पड़ा है। इसलिये जो पानी उपलब्ध होगा उसमें स्काडा सिस्टम लगा है। जितना पानी उपलब्ध होगा उस हिसाब से ही पी.एच.ई.डी. पेमेण्ट कर रही है। पहली बात, जो एग्रीमेंट है वह एग्रीमेंट आर.एस.एम.एम.एल और कम्पनी के बीच में है। पी.एच.ई.डी. का इसमें कोई रोल नहीं है। पी.एच.ई.डी. तो पानी लेगी। जो शुद्ध पानी वे सप्लाई करेंगे और जितना पानी सप्लाई करेंगे, अकोर्डिंगली पेमेण्ट करना है और स्काडा सिस्टम के माध्यम से इसका पेमेण्ट होगा। तो जो पहले पानी कम आया है तो उसके आधार पर कोई पेमेण्ट ही नहीं हुआ।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

दूसरी बात चूँकि 120 गांवो के अन्दर शुद्ध पेयजल नहीं मिलने की वजह से वहां पर परेशानी आ रही है, इस वजह से 30.11.2016 को एक मीटिंग मुख्य सचिव ने आयोजित की। उनकी अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उसमें पी.एच.ई.डी. को यह निर्देशित किया गया कि आप अपने स्तर पर आर.ओ. प्लाण्ट लगायें, कुछ ट्यूबवेल्स नये दें और जो पुराने ट्यूबवेल्स हैं उनको रिपेयर करें। इस आधार पर पी.एच.ई.डी. ने काम करना शुरू कर दिया। 21 नलकूपों की नई स्वीकृति जारी कर दी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो 258.53 लाख रुपये की है। पुराने जो नलकूप हैं उनको ठीक करने के लिये लगभग 50 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की है पेयजल परिवहन हेतु टैंकर्स से पानी सप्लाई करने के लिये 225 लाख रुपये की स्वीकृति जारी कर दी है। जिसमें काम भी शुरू हो गया है। लगभग 21 में से 10 नलकूप खोदे जा चुके हैं। 15-20 दिन के अन्दर 21 में से बचे हुए 11 नलकूपों का भी काम पूरा हो जायेगा। माननीय सदस्य ने जायल के सन्दर्भ में जो चिंता जाहिर की, मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहूंगी कि पूरी तरीके से पी.एच.ई.डी. इसके अन्दर अपनी सक्रियता के माध्यम से ये सारे जो नलकूप खराब हैं, उनको ठीक कराकर, नये नलकूप लगाकर और ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से सारा करेंगे।

इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फेज-2 के अन्दर हमारी नागौर लिफ्ट योजना है, उसके तहत लगभग तीन हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं, जिससे कि प्रत्येक गांव और ढाणी तक शुद्ध पेयजल पहुंचे, उसकी व्यवस्था करने का कार्य चल रहा है। बिफोर टाइम, मार्च, 2018 तक कम्पलीट होना है लेकिन दिसम्बर, 2017 तक उस काम को पूरा कर लिया जायेगा और नागौर की सम्पूर्ण गांव और ढाणियां, जिसको हम बांका पट्टी कहते हैं, उसमें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये यह सरकार दृढ़ संकल्पित है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड।

मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं, आप कह रहे हो कि हमने ट्यूबवेल स्वीकृत करा दिये। लेकिन वहां पानी मीठा नहीं है तो ट्यूबवैल का क्या करेंगे, साहब। इन 120 गांवों के अन्दर पीने का पानी मीठा नहीं है

(श्री हनुमान बेनीवाल)

मंत्रीजी। मैं तो यह कह रहा हूं कि जिन शर्तों के आधार पर कम्पनी ने पानी मीठा करके, फिर रामकी पानी आगे पहुंचा रही थी, आप यह बताओ कि जितना पानी दिया, उससे ज्यादा भुगतान हो गया और पानी सही नहीं था। लोग आंदोलित हैं। पशु मर रहे हैं। लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब गर्मी का महीना आ गया। रोज आंदोलन हो रहे हैं। हमें तो वहां जाना पड़ता है। मैं ही चिंता नहीं कर रहा हूं। ये जायल विधान सभा क्षेत्र के विधायक बैठे हैं, इनसे भी आपकी बात हुई थी। इनका भी बयान मैंने अख़बार के अन्दर पढ़ा था। इन्होंने कहा कि जायलवासियों को ऐसे पानी की आवश्यकता नहीं है। पानी बदबूदार है, खारा है, बेकार है। हम जो चाहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर इतना ही संरक्षण चाहते हैं कि पूरे प्रकरण के अन्दर अगर आप कह रहे हो कि वित्तीय अनियमितता नहीं है तो ठीक है, आप इस पूरे प्रकरण की जांच करा लें। आपका एक कलेक्टर तो रिपोर्ट देता है कि पानी सही है, पानी के अन्दर कोई गलत नहीं हुआ, पानी शुद्ध है और पानी का भुगतान सही हुआ। दूसरा कलेक्टर कहता है कि वित्तीय अनियमितता हुई है। पानी बदबूदार है, पानी गंदा है। अब किसकी रिपोर्ट मानोगे? दोनों रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। जिस मात्रा के अन्दर टी.डी.एस. होना चाहिये, उससे कितनी ज्यादा मात्रा के अन्दर है। आप लोगों को मारोगे क्या? उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपने यही तय कर लिया कि 2018 के अन्दर अब यही काम करके सत्ता में आना है तो वह आप जानो। लेकिन मंत्रीजी, कम से कम लोगों को गुमराह मत करो। मैं तो आपके माध्यम से इतना ही चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करा लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। यह मैं थोड़े ही कह रहा हूं, आपके आंकड़े बोल रहे हैं। वहां की जनता आंदोलित है। उनको पानी नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हो, वहां से यह कर देंगे, वह कर देंगे। वह तो पाँच साल बाद करोगे। अभी पीने का पानी कहां से लाओगे, यह बताओ ना आप। ट्यूबवैल स्वीकृत कर दिये, पानी मीठा नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाओ। यह तो पेयजल की डिबेट हो गई। मेरे ख्याल से वैसे भी पेयजल की डिमाण्ड है, उस दिन आप बोल लेना, जो भी आपका शेष रह गया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोगों को तीन-तीन हजार रुपये में टैंकर से पानी लाना पड़ रहा है। ...(व्यवधान)... इसका मंत्रीजी बता दें।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें। ...(व्यवधान)... आसन आपको बाध्य नहीं कर सकता। In case you want to react, you can react.

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): Simply I want to say, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एग्रीमेंट पी.एच.ई.डी. के साथ में नहीं है। यह एग्रीमेंट कम्पनी और आर.एस.एम.एम.एल. का है। जब ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, पी.एच.ई.डी. पानी ले ही नहीं रहा है तो भुगतान क्यों। जब पी.एच.ई.डी. को पानी उपलब्ध ही नहीं हो रहा है तो पेमेण्ट किस बात का होगा। जो पूर्व में पेमेण्ट्स हुए हैं और पूर्व में जो सारी जांचें हुई हैं, वे सारी जांचें डिपार्टमेंट में जाकर देख लें, क्या जांच हुई।

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत, श्री श्रवण कुमार।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक परमिशन चाही थी, अगर आपकी इजाजत हो।

श्री उपाध्यक्ष: हां, कोई पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन की है।

सूचना

भरतपुर के सेवर में पुलिस दबिश के दौरान दो बालिकाओं की मौत

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन यहां पर बैठा हुआ है और राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। भरतपुर के सेवर थाने में पंछी का नगला में कल जो घटना हुई, मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार अपनी ओर से उसका वक्तव्य दे। ताकि सारी स्थिति क्लीयर हो सके। दो प्रकार की धारणाएं हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि 20-25 गाड़ियां पुलिस की गयीं, गोली चलाई और डरते हुए बच्चियां कूद पड़ीं। पुलिस का कहना है कि वे फिसल गयीं, गिर गयीं और दो बच्चियों की मौत हो गयी। गम्भीर घटना है। 20-25 गाड़ियों को दिन में चार बजे जाने का और इन बच्चियों को पकड़ने के लिये इतना बड़ा चारों तरफ से घेरने का क्या कारण रहा होगा? यह सारे कारण अगर सरकार

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बतायेगी तो मैं समझता हूं कि स्थिति साफ होगी और सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है, यह भी साथ-साथ आ जाये तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। इसलिये मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री श्रवण कुमार।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा भी आसन से समय निश्चिए हो, उस समय मैं अपनी तरफ से स्टेटमैंट देने को तैयार हूं।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सिंघाना (सूरजगढ़) में नगरपालिका का गठन

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में सिंघाना बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, जिसमें 12 हजार मतदाता मत का प्रयोग करते हैं।

अत: श्रीमान् जी से निवेदन है कि यह सरकार का संकल्प है कि स्वस्थ भारत स्वस्थ राजस्थान का संकल्प ले रखा है लेकिन बड़ी पंचायतों में एक भाग सिंघाना बड़ी पंचायत है। उसको तत्काल नगरपालिका बनाने की घोषणा करें और जनता में 10 वर्षों से यह तमन्ना थी कि कब हमारी ग्राम नगरपालिका बने। यह तमन्ना 2017 में पूरी करने और सिंघाना को नगरपालिका घोषित करने का श्रम करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

सूरसागर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों की क्रमोन्नति

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के अभाव को दूर करने की अविलंब आवश्यकता के क्रम में निवेदन है।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के 25 सैक्टर, पूर्वी-पश्चिमी पाल रोड योजना, सूंथला, चांदणा भाखर, कमला नेहरू नगर, राजीव गांधी कॉलोनी, देवनगर, मसूरिया, प्रताप नगर के आश्रित डेढ़ लाख से ज्यादा की जनसंख्या क्षेत्र के लिए कोई भी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयय नहीं है। इस कारण यहां के निर्धन और कमजोर वर्ग की बालिकाओं को मजबूरी में या तो महंगे निजी विद्यालयों में जाना पड़ता है अथवा वे पढ़ाई छोड़ देती हैं। हालात यह है कि चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के दूसरा पुलिया पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवांची गेट में लगभग 500 बालिकाएं लड़कों के साथ पढ़ने को मजबूर हैं। इस क्रम में अनेक प्रस्ताव विभागीय उदासीनता और लापरवाही के चलते क्रियान्वित नहीं हो पाए हैं। हालत यह है कि शहर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जालौरी गेट, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवांची गेट के बीच दूरी केवल 200 मीटर है और इनके पास ही 200 मीटर से कम दूरी पर एक और राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय खाण्डा फलसा, जोधपुर भी स्थित है। इसमें राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवांची गेट को चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के दूसरा पुलिया स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंवांची गेट के विशाल भवन में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव उच्च स्तर पर लंबे समय से लंबित है।

यह उल्लेखनीय है कि नगरीय विस्तार और जनसंख्या के अनुरूप पूर्व में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवांची गेट भी सिंवांची गेट से चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थानांतरित हुआ था। यहां वर्तमान में लगभग 500 बालिकाएं पढ़ रही हैं। यदि यहां एक अलग पारी में बालिका विद्यालय संचालित होता है तो यहां बालिकाओं की संख्या में और अधिक वृद्धि हो सकती है। उक्त प्रकरण में विद्यालय संचालन का भवन परिसर बदलने से वर्तमान संचालित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवांची गेट की बालिकाओं के लिए 100 मीटर से 200 मीटर की दूरी पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जालौरी गेट और राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय खाण्डा फलसा उपलब्ध है।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

इसी प्रकार क्षेत्र के अन्य विद्यालयों को क्रमोन्नत करके भी बालिका शिक्षा के अवसरों को क्षेत्र में बढ़ाया जा सकता है जैसे- राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय 14 सैक्टर, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर को माध्यमिक स्तर पर, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, प्रताप नगर को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया जा सकता है।

अत: मेरी मांग है कि विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में बालिका माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की सरकारी शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिवांची गेट को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवांची गेट दूसरा पुलिया, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में स्थानांतरित किया जाए। राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय प्रताप नगर को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया जाए। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय 14 सैक्टर, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती गोलमा देवी।

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): गोलमा देवी का पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: पढ़ा हुआ मान लिया। अब आप विराज जाएं।

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप पढ़ा हुआ मान लेना मेरा। देखो, आप यह और मेरा वह विकास का काम है। कर लेना, मंत्रीजी। यह देखो कोई लापरवाही मत करना। क्षेत्र में कोई विरोध का वह मत करना और पढ़े हुए मान लेना। ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): बिलकुल भाभी। बिलकुल नहीं करेंगे, भाभी, बिलकुल नहीं करेंगे।

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): भाभीजी से पार नहीं पड़ेगी। देखो, आप भाभीजी कह कर राज़ी कर देते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): तो भाभी नहीं हों, आप मेरी?

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): भाभीजी तो है तो है ही। यह

(श्रीमती गोलमा)

भाभीजी तो देखो यह है न, पर भाभीजी कह कर राज़ी करते हो आप और काम करते नहीं हो। आप तो मंत्री बनकर बैठे हैं। क्षेत्र में विकास होना चाहिए और काम भी होना चाहिए। दो करोड़ के बजट से होता क्या है, आप बताओ क्षेत्र में? मंत्री के पास में तो सब कुछ है। विकास का काम होना चाहिए और पढ़ा हुआ मान लेना चाहिए। यह लो।

(श्रीमती गोलमा देवी की नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचना पढ़ी हुई मानी गयी)

सपोटरा के कालीसिंध बाँध के मॉडल तालाब के निर्माण कार्यों की जांच

नियमों के नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

जिला करौली के अंतर्गत पंचायत समिति सपोटरा द्वारा पेयजल एवं संरक्षण हेतु सार्वजनिक तालाब की पाल निर्माण व पिचिंग कार्य बसोड़ी वाले बालाजी के पास ग्राम बाजना में वर्ष 2015-16 में विभिन्न योजनाओं में लगभग 90 लाख रुपये की राशि टुकड़ों में स्वीकृत की गयी थी जिसकी कार्यकारी एजेंसी पंचायत समिति सपोटरा थी। इस कार्य के लिए टुकड़ों में स्वीकृति इसलिए की गयी ताकि ग्रामीण कार्य निर्देशिका के पैरा नम्बर 7.3.2 के अनुसार वित्तीय स्वीकृति पंचायत समिति स्तर से ही की जा सके एवं कार्यकारी संस्था द्वारा किये गये घोटाले से उच्च अधिकारी अनभिज्ञ रहे। इस कार्य की सी.ई.ओ., जिला परिषद द्वारा स्वीकृति देने के लिए सिंचाई विभाग से एन.ओ.सी. लेना अति आवश्यक था। यह तालाब सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित कालीसिंध बाँध के केचमेंट एरिया के बहाव क्षेत्र में आता है लेकिन कार्यकारी संस्था द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए निर्माण में गंभीर अनियमितताएं एवं घटिया किस्म का निर्माण करवा कर लाखों रुपये की राशि का गबन किया, जो वसूली योग्य है। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 4(9)पराविं/पी.सी./वर्षा जल संरक्षण/2011-12, दिनांक 30.07.2012 एवं माननीय न्यायालय द्वारा सभी कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि किसी भी बाँध के केचमेंट एरिया में चैक डैम/वाटर हार्वेस्टिंग/एनिकट बिना एन.ओ.सी. के बनाये जाते हैं एवं पानी में बहाव को अवरुद्ध करते हैं तो उन्हें तुरंत हटवाकर कार्यकारी संस्था से राशि भी वसूली की जाए।

(श्रीमती गोलमा)

अत: आपसे निवेदन है कि उक्त कार्य में की गयी गंभीर अनियमितताओं की जांच करवाकर बहाव क्षेत्र में बनाये गये तालाब को ध्वस्त कराते हुए कार्यकारी संस्था से राशि वसूलने की कार्यवाही करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नानालाल अहारी।

ऋषभदेव, रैफरल चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैरवाड़ा में शय्याओं की संख्या में वृद्धि

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि खैरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत उपखंड मुख्यालय ऋषभदेव प्राचीन तीर्थ-स्थली केशरियाजी में राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर स्थित रैफरल चिकित्सालय विगत 38 वर्षों से सत्र् 1978-79 से संचालित होकर, 25 बैड की उक्त चिकित्सालय में वर्तमान में व्यवस्था है।

उपखंड मुख्यालय ऋषभदेव में धार्मिक नगरी के साथ-साथ पगल्याजी मठ, पुलिस उप अधीक्षक, मयूर धागा मिल, पंचायत समिति, देवस्थान एवं खनन विभाग के कार्यालय भी स्थित हैं। उपखंड मुख्यालय के अधीनस्थ 28 ग्राम पंचायतें हैं। समस्त ग्राम पंचायतों में उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से आम जन को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। ग्रामीण जनजाति बाहुल्य पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र के आर्थिक स्थिति से कमजोर एवं सामान्य वर्ग के साथ सभी जाति-बिरादरी के लोग निवास करने वाले आमजन को उपचार के लिए उदयपुर, डूंगरपुर जिला मुख्यालयों तक लगभग 120-150 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। एन.एच.-8 पर स्थित होने के कारण दुर्घटना, प्रसूति प्रबंधन एवं अन्य चिकित्सा सुविधा की विकराल समस्या का समाधान किया जाना अपेक्षित है।

उपखंड मुख्यालय रैफरल चिकित्साल्य में 25 बैड की व्यवस्था है। जिन्हें क्षेत्र की आम जनता की बेहद मांग के अनुसार 25 बैड से 50 बैड किया जाकर उक्त चिकित्सालय को क्रमोन्नत किया जाना अपेक्षित है। साथ

(श्री नाना लाल अहारी)

ही, खैरवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भी 30 बेड है, जिनकी वृद्धि कर 50 बेड का चिकित्सालय क्रमोन्नत किया जाने से क्षेत्र की गरीब जनता को राहत मिल सकेगी। साथ ही यह हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री एवं सरकार के लिए ऐतिहासिक कदम साबित होगा।

अत: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि रैफरल चिकित्सालय ऋषभदेव में 25 बैड से 50 बैड एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैरवाड़ा में 30 से 50 बैड कर चिकित्सालय क्रमोन्नत करा क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान कराएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी।

भीलवाड़ा में डा. अम्बेडकर की प्रतिमा खंडित होने से आक्रोश

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत अनुरोध है कि अखिल भारतीय डाक्टर अम्बेडकर क्रांति मंच (भारत) द्वारा गाम पंचायत हलेड, जिला भीलवाड़ा में सरकारी भूमि आराजी संख्या-625/04 पर डाक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करने हेतु ग्राम पंचायत हलेड में आवेदन किया गया था।

सचिव, ग्राम पंचायत हलेड एवं सरपंच द्वारा उक्त भूमि को सरकारी बताते हुए बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित करने हेतु अनुशंसा की थी तथा वर्तमान सरपंच ने भी अनुमोदन किया।

उक्त अनुशंसा के आधार पर अखिल भारतीय डाक्टर अम्बेडकर क्रांति मंच (भारत) ने समस्त ग्रामवासियों के साथ मिलकर डाक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया लेकिन नाथू सिंह, हरिसिंह एवं बालू आचार्य द्वारा सरकारी भूमि आराजी संख्या 625/04 को फर्जी पट्टों के आधार पर अपनी बताते हुए डाक्टर बाबा साहेब की प्रतिमा को खंडित कर दिया तथा साथ ही अखिल भारतीय डाक्टर अम्बेडकर क्रांति मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री कल्पना रेनू चन्नाल पर अतिक्रमण करने बाबत् थाना सदर, जिला भीलवाड़ा पर एफ.आई.आर. दर्ज करा दी जो कि पुलिस जांच अनुसंधान में फर्जी पाई गयी तथा पंचायत में उक्त भूमि का पट्टा जारी होने का कोई रिकार्ड नहीं पाया गया तथा एफ.आर. पेश की गयी।

(श्री पूरणमल सैनी)

उक्त प्रकरण पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संज्ञान लेते हुए सी.बी.आई. जांच के लिये मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को पत्र लिखा गया था, किन्तु आज दिनांक तक सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जबकि सुश्री कल्पना रेणु चन्नाल को श्री नाथू सिंह, हरिसिंह द्वारा डराया-धमकाया जा रहा है तथा उनके दोनों बड़े भाई की दुर्घटना करवा दी, जिसमें एक भाई राजेश चन्नाल की हत्या हो गयी तथा दूसरा भाई अशोक चन्नाल गंभीर रूप से घायल हो गया है तथा अशोक चन्नाल, जोकि राजकीय सेवा में है, उसे भी परेशान किया जा रहा है तथा सी.एम.एच.ओ. भीलवाड़ा द्वारा मनगढ़ंत आरोप लगाकर अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन जयपुर ए.पी.ओ. कर दिया है तथा राजकीय सेवा से बर्खास्त करने एवं हत्या की साजिश बना रखी है।

अत: आपसे मांग है कि उक्त प्रकरण की जांच करवाकर आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाये तथा बाबा साहेब की मूर्ति उक्त स्थान पर पुन: राजकीय खर्च पर स्थापित करायी जाये एवं परिवार को सुरक्षा उपलब्ध करायी जाये।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

बानसूर में मोबाइल टावर की स्थापना

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत् विशेष उल्लेख के अन्तर्गत निवेदन है कि आज देश को आजाद हुए इतने वर्ष हो गये, फिर भी बानसूर क्षेत्र की पंचायत एवं कई गांवों में लोग मोबाइल पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि उन गांवों में मोबाइल टावर ही नहीं है। जैसे ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा छीड़ है। इसमें अनेक गांव हैं अधिरा, मेडा, धोली की ढाणी आदि एवं पंचायत हाजीपुर का गांव, धामला का बास एवं ग्राम पंचायत रामपुर के खारी का बास, नाथूसर लोज, गुडा, भाकरवाल, पंचायत सबलपुरा के कल्याणपुरा, पंचायत बामनवास कांकड के गांव नांगलहेडी, बेरावास, बणजारा की ढाणी ऐसे अनेक गांवों का सर्वे करवाकर यहां पर टावर लगवायें ताकि ये गांव मोबाइल व नेट से जुड़ सके। वैसे तो सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

अत: माननीय मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन है कि ऐसे गांवों एवं ग्राम पंचायतों का सर्वे करवाकर, भारत सरकार से राजस्थान सरकार मांग करके जहां पर मोबाइल टावर से वंचित रही सभी ग्राम पंचायतों में किसी भी कम्पनी का टावर लगवाने का कष्ट करें ताकि ये गांव भी मोबाइल व नेट से जुड़ सकें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सोना देवी।

रायसिंहनगर में चक्रवाती तूफान से प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में 9 अक्टूबर, 2016 को आये चक्रवाती तूफान से प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान किये जाने हेतु प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत् निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मुख्यालय 3 एम.के., 5 टी.के., उड़सर, 16 पीएस, डाबला, 2 एल.सी., 33 एम एल, मुकलावा, जगतसिंह वाला, 12 एन आर डी, 14 पी एस बी, ठण्डी, 11 टी के, 28 एन पी के लगभग 58 ग्रामों में दिनांक 9 अक्टूबर, 2016 को भारी चक्रवाती तूफान आया, जिससे इस क्षेत्र के ग्रामवासियों एवं किसानों को अपनी फसलों का भारी नुकसान हुआ और किसानों को अपनी अगली फसल के लिये खाद-बीज हेतु पैसे का इन्तजाम करना भी दूभर हो गया है।

मान्यवर, दिनांक 3 फरवरी, 2017 को उप तहसील कार्यालय, मुकलावा में प्रभावित किसानों व उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर तथा उपस्थित बीमा कम्पनी के अधिकारियों के मध्य फसल खराबे का मुआवजा भुगतान किये जाने हेतु समझौता हुआ कि दो माह के भीतर प्रभावित किसानों को भुगतान कर दिया जायेगा, परन्तु अभी तक मुआवजा राशि नहीं मिली है। क्षेत्र के गरीब किसान मुआवजा राशि हेतु दर-दर की ठोकरें खाने के लिये मजबूर हैं तथा वर्तमान में आन्दोलनरत हैं।

अत: प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के माध्यम से माननीय आपदा राहत मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि

(श्रीमती सोनादेवी)

प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा राशि का भुगतान किये जाने हेतु आदेश प्रदान कर राहत प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हीरालाल जी।

निवाई में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के खण्ड कार्यालय की स्थापना

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई में उपखण्ड निवाई एवं पीपलू का जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का खण्ड कार्यालय निवाई में खोलने का अनुरोध करता हूं।

विधान सभा क्षेत्र निवाई, तहसील निवाई की 41 एवं तहसील पीपलू की 25 ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए बनाया गया है। तहसील निवाई का जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का खण्ड कार्यालय (अधिशासी अभियन्ता) मालपुरा में तथा तहसील पीपलू का खण्ड कार्यालय टोंक में आता है। मालपुरा निवाई से लगभग 80 किलोमीटर दूर है तथा टोंक की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। इसके कारण से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में अनेक बार निवाई व पीपलू का टोंक एवं मालपुरा से सम्पर्क कट जाता है जिसके कारण आम जनता मालपुरा या टोंक नहीं जा पाती है।

निवाई उपखण्ड मुख्यालय पर जयपुर विद्युत वितरण निगम का अधिशासी अभियन्ता कार्यालय स्थित है, जबकि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का अधिशासी कार्यालय अभी तक नहीं खोला गया है। टोंक जिले के विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह- मालपुरा के उपखण्ड टोडारायसिंह एवं मालपुरा दोनों ही मुख्यालयों पर खण्ड कार्यालय स्थापित है, जबकि विधान सभा क्षेत्र निवाई के किसी भी उपखण्ड मुख्यालय पर खण्ड कार्यालय नहीं है। अत: विधान सभा क्षेत्र मालपुरा-टोडारायसिंह के दोनों खण्ड कार्यालयों में से किसी एक जगह के खण्ड कार्यालय को समाप्त करते हुए विधान सभा क्षेत्र निवाई के उपखण्ड निवाई एवं पीपलू का खण्ड कार्यालय निवाई में स्थापित किये जाने से सरकार पर स्टाफ आदि का अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा

(श्री हीरालाल)

तथा उपखण्ड निवाई एवं पीपलू के सरकारी अधिकारियों सहित आम जनता एवं जन प्रतिनिधियों को भी सुविधा हो जाएगी।

अत: इस प्रस्ताव के माध्यम से मेरा निवेदन है कि उपखण्ड निवाई एवं उपखण्ड पीपलू को मिलाकर उपखण्ड मुख्यालय निवाई पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का खण्ड कार्यालय (अधिशासी अभियन्ता) स्थापित करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष: राजकुमारी दिया कुमारी।

मलारना डूंगर (सवाई माधोपुर) में स्वीकृत मॉडल महाविद्यालय हेतु भूमि आबंटन

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में मलारना डूंगर उपखण्ड मुख्यालय है तथा यहां पर उच्च शिक्षा के लिये कोई भी कॉलेज नहीं है जिससे कि आस-पास के लगभग 1000 विद्यार्थियों को कॉलेज शिक्षा के लिये सवाई माधोपुर जाना पड़ता है। सवाई माधोपुर से इस क्षेत्र की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है, जिस वजह से विशेषकर बालिकाओं को उच्च शिक्षा पाने में दूरी होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। मलारना डूंगर के आस-पास लगभग 11 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हैं जिनमें लगभग 800 विद्यार्थी कक्षा बारहवीं में पढ़ाई कर रहे हैं, जो आगे की पढ़ाई के लिये कॉलेज में जायेंगे। सरकार ने ऐसे क्षेत्रों में जहां उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारा और प्रोत्साहन दिया जाना अत्यनत आवश्यक है, वहां भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के अधीनस्थ चल रहे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम के तहत मॉडल महाविद्यालय स्वीकृत करने का निर्णय लिया, जिसके तहत् 14 सितम्बर, 2016 को राज्य सरकार द्वारा उपखण्ड मुख्यालय मलारना डूंगर (सवाई माधोपुर) में मॉडल महाविद्यालय स्वीकृत किया गया। किन्तु इस संबंध में भूमि आबंटन व अन्य शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यवाही नहीं की गयी है, जिससे यह मॉडल महाविद्यालय स्वीकृत होने के बाद भी क्रियाशील नहीं हो पा रहा है।

(राजकुमारी दियाकुमारी)

मलारना डूंगर के आस-पास का क्षेत्र डांग क्षेत्र में आता है। ऐसे में यहां पर यह मॉडल महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान करेगा। वहीं यहां रह रहे विद्यार्थियों के लिये, विशेषकर बालिकाओं के उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार लायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे में मलारना डूंगर (सवाई माधोपुर) में स्वीकृत मॉडल महाविद्यालय को अतिशीघ्र प्रारम्भ किये जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जगदीश नारायण जी।

जमवारामगढ़ में वन अभयारण्य क्षेत्र के गांवों की जमीनों पर रजिस्ट्री पर रोक हटाना

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वन अभयारण्य क्षेत्र में आने वाले गांवों की जमीनों की रजिस्ट्री पर लगी रोक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए निवेदन करना चाहता हूं एवं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सर्वविदित है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के विठलपुर, सुरेटी, बिशनपुरा, केलनवास, गोपालगढ़, नवपुरा, भिवास, घाटी घनश्यामपुरा, साहू, साहू शीरा, जमवाघाट, रासावाला, बस्सी, काली बरकड़ी, डगोता, काणीखोर, दांतली, पावटा, महंगी, गुढा-हरूका, बामनवाटी, महंगौर, नांगल तेजसिह, रायसर, रामजीपुरा, कुशलपुरा, डारोलाई, चैनपुरा, नीम्बी, रायपुर, घोरठ, खरहड़ व लोठीपुरा पावटा इत्यादि गांव वन्य अभयारण्य क्षेत्र में आते हैं। इस कारण सरकार द्वारा इन गांवों की जमीनों पर रजिस्ट्री पर पूर्णतया रोक लगा दी गयी है। इनके अलावा क्षेत्र के लगभग 50 गांवों को भी आंशिक रूप से वन्य अभयारण्य क्षेत्र में मानते हुए उन गांवों की जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगायी गयी है। इस कारण से उक्त सभी गांवों की जनता में भारी रोष व्याप्त हो गया है। रजिस्ट्री पर लगी रोक को हटाने के लिए आये दिन धरने-प्रदर्शन हो रहे हैं तथा भविष्य में जन आन्दोलन और तेज होने की संभावना है।

(श्री जगदीश नारायण)

इस सम्बन्ध में सरकार से मेरी मांग है कि जन हित में मेरे क्षेत्र के वन अभयारण्य क्षेत्र में आने वाले गांवों की जमीनों की रजिस्ट्री पर लगी रोक को तुरन्त प्रभाव से हटाया जाए ताकि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता में आक्रोश नहीं फैल सके एवं उनको राहत मिल सके।

अत: इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जन हित के मुद्दे पर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जन हित में उक्त समस्या को ध्यान में रखते हुए इसका शीघ्र निस्तारण किये जाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती कामिनी जिन्दल।

श्रीगंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स लिमिटेड बंद होने के बाद शेष श्रमिकों का अन्य विभागों में समायोजन

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत् विशेष उल्लेख प्रस्ताव- श्रीगंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स लिमिटेड के बंद होने के पश्चात् कर्मचारियों/श्रमिकों के समायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय, श्रीगंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स लिमिटेड को अपरिहार्य कारणों से जनवरी, 2014 में बंद करने का फैसला लिया गया था। तत्कालीन लिक्विडेटर द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करते हुए पिक एण्ड चूज के आधार पर कर्मचारियों/श्रमिकों का समायोजन अन्य विभागों में किया गया। कॉटन कॉम्प्लेक्स के 205 कर्मियों का समायोजन तो कर दिया गया परन्तु 200 स्थायी श्रमिकों एवं 94 बदलिक श्रमिकों को अधरझूल में छोड़ दिया गया।

महोदय, श्रीगंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स लिमिटेड को बंद हुए एक दशक से ऊपर हो गया है परन्तु उक्त 294 श्रमिकों का ना तो समायोजन अन्य विभागों में किया गया ना ही उनके पी.एफ. तथा मेडिकल इत्यादि बकाया का भुगतान किया गया। फलस्वरूप सभी 294 श्रमिक श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष 90 दिनों से अधिक समय से धरने पर बैठे हैं। तत्कालीन लिक्विडेटर एवं श्रीगंगानगर सहकारी बैंक लिमिटेड के वर्तमान एम.डी. द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आन्दोलनरत श्रमिक कई

(श्रीमती कामिनी जिन्दल)

बार क्रमिक अनशन भी कर चुके हैं। अभी हाल ही में तो एक अनशनकारी की न्याय की आस में मौत भी हो गयी है। ये श्रमिक समायोजन और बकाया भुगतान की मांग को लेकर स्थानीय प्रशासन से लेकर जयपुर उच्चाधिकारियों एवं सरकार तक गुहार लगा चुके हैं। दूसरी तरफ हनुमानगढ़ स्पिनिंग मिल को अभी बंद करने का फैसला लिया गया और सभी कार्मिकों/श्रमिकों को बकाया भुगतान के साथ-साथ यथायोग्य समायोजन भी कर दिया गया है।

श्रीगंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स लिमिटेड के कई श्रमिक तो समायोजन की आस में ओवर-एज भी हो गये हैं। बकाया भुगतान की आस लगाये वे लगातार शांतिपूर्ण तरीके से आन्दोलन कर रहे हैं परन्तु इनके बकाया भुगतान सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, इसके क्या कारण हैं?

अत: श्रीगंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स लिमिटेड के समायोजन से वंचित रहे श्रमिकों के बकाया भुगतान एवं नियमानुसार समायोजन हेतु मैं विशेष उल्लेख प्रस्तुत करती हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

घरेलू विद्युत कनेक्शनों की राशि की डी.एल.सी. रेट से वसूली

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत आवासीय कॉलोनियों में घरेलू कनेक्शन की राशि, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एक समान राशि होने के कारण ग्रामीणों पर अधिक भार पड़ने के संदर्भ में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि विद्युत विभाग के द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय कॉलोनियां विकसित होती हैं तो जयपुर शहर में जहां जमीन की दर 50 हजार रुपये प्रति गज है वहां पर भी 200 रुपये प्रति गज के हिसाब से घरेलू कनेक्शन की राशि वसूल की जाती है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जहां जमीन की दर 500 रुपये प्रति गज है वहां पर भी 200 रुपये प्रति गज की रेट से वसूल की जाती है। शहरवासी तो उपरोक्त राशि को वहन कर सकते हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जितनी राशि की जमीन खरीदते हैं उतनी ही राशि का मांग-पत्र

(श्री रामलाल शर्मा)

बिजली विभाग वाले जारी करते हैं अत: गरीब आदमी उतनी राशि जमा कराने में असमर्थ रहते हैं।

अत: आपके माध्यम से निवेदन है कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में एक समान जो राशि ली जाती है उसको भूमि की डी.एल.सी. रेट पर करने का श्रम करें ताकि ग्रामवासियों को राहत मिल सके। 000

श्री उपाध्यक्ष: 295 में जितना मामला गम्भीर था, उतना आपने पढ़ लिया। अब आप विराज जाओ।

पर्ची के माध्यम से, श्री सुरेश धाकड़।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

भैंसरोड़गढ़ रावड़दा में पेयजल योजना की स्वीकृति

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्मय से मुझे मेरे क्षेत्र की भैंसरोड़गढ़ रावड़दा पेयजल परियोजना पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं भैंसरोड़गढ़-रावड़दा पेयजल परियोजना की समस्या वहां से खड़ी हुई कि पूर्ववर्ती सरकार में एक योजना बनी कि भीलवाड़ा जिले को पानी पिलाया जायेगा। उसके लिए 2500 करोड़ रुपये की इन्होंने योजना बना दी लेकिन जहां से पानी उठाना था, ऑन-रूट विलेज का ध्यान नहीं रखा और मेरे क्षेत्र में कम से कम 25-30 किलोमीटर एरिया में वहां पानी होकर जाता है और वो सोर्स भैंसरोड़गढ़ में है। पूरा काम चल रहा है लेकिन बाद में जब इनको फोरेस्ट की एन.ओ.सी. की जरूरत पड़ी तो इन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में यह था कि इनको एन.ओ.सी. की जरूरत थी, कलेक्टर से एक सर्टिफिकेट चाहिए था लेकिन कलेक्टर तब तक सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकता जब तक कि ग्राम पंचायतों की एन.ओ.सी. नहीं मिल जाए। तब मीटिंग में एक समझौता हुआ जिसमें मैं स्वयं था। तत्कालीन माननीय मंत्री महोदय सांवर लाल जी जाट थे, इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सब अधिकारी थे। उसमें दो-तीन चीजों पर समझौता हुआ। वह मैं बताता हूं कि "To solve the drinking water problem of 77 villages. i.e.

(श्री सुरेश धाकड़)

Bhainsroadgarh, Bhoraw, Dhangalmowkala, Gopalpura, Sepra and Tambolia Panchayat." इसमें यह भी लिखा हुआ है कि "Existing intake well of Bhainsroadgarh, infrastructure to deliver drinking water to 77 villages of Bhainsroadgarh Panchayat Samiti will be prepared and sanctioned at an early date."

इसका सैकिण्ड पाईंट है "A separate detail proposal for solving the drinking water problem of 9 villages of Rawarda Panchayat of Panchayat Samiti of Begun will be prepared and sanctioned."

इसका थर्ड पाईंट है "The required certificate from the District Collector, Chittorgarh, regarding diversion to forest land for Chambal-Bhilwara Water Supply Project will be issued immediately." केवल इसमें इमिडिएटली लिखा हुआ है बाकी इन्होंने इनकी मर्जी से लिख दिया।

इसमें मेरा यह है कि जो 2500 करोड़ रुपये की योजना बनायी, उस योजना के लिए जो समझौता हुआ, उस समझौते में इन्होंने खुद ने लिखकर दिया और यह समझौता 17 जुलाई, 2014 का है। जब विपक्ष में थे तब हमने आन्दोलन किया, कुछ काम किया लेकिन अब हम सत्ता पक्ष में है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। मैं मंत्रीजी से यही कहना चाहूंगा कि जो 2500 करोड़ रुपये की पेयजल योजना है उसमें तीन-चार महीने एन.ओ.सी. देने में लग गये। हमने कहा हमें पानी पिलाओ, तब जाकर यह मैटर इस स्तर पर पहुंचा। फिर एक समझौता हुआ। उस योजना को डिले होने में करीब 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। फिर इन्होंने एक 52 करोड़, एक 7 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर एन.ओ.सी. नहीं मिलती तो अभी तक भीलवाड़ा को पानी पीने से वंचित रहना पड़ता। अभी भी पूरी एन.ओ.सी. नहीं मिली है। जो ऑन-रूट विलेज हैं उनको पानी मिलना चाहिए। यह एक बहाना बना देते हैं भैसरोड़गढ़ के लिए कि फोरेस्ट है 30 परसेंट में, उसको एन.ओ.सी. नहीं दे सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, चलो भैसरोड़गढ़ में फोरेस्ट का थोड़ा-बहुत इश्यू है तो इसको बात कर कि क्या हो

(श्री सुरेश धाकड़)

सकता है लेकिन रावड़दा में क्या प्रॉब्लम है?

इसके साथ मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि रावड़दा पेयजल परियोजना में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसकी पी.पी.सी. मीटिंग में भी आ गया, उसको तो सेंक्शन कर देना चाहिए, टैण्डर कर देना चाहिए लेकिन उसमें भी देरी की जा रही है।

दूसरा यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने अब तक ऐसी कितनी परियोजना हैं जिनकी एन.ओ.सी. लिये बिना टैण्डर कर दिये? अगर कर दिये हैं, बहुत सारी योजना के किये हैं तो फिर इसमें क्यों, इसको जान बूझकर क्यों नहीं किया जा रहा है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें 70 परसेंट सिम्पल जमीन है और 30 परसेंट फोरेस्ट है। अगर यह टैण्डर कर देते तो थोड़ा प्रोसेस में चल कर, उसकी एन.ओ.सी. आयेगी तब तक 70 परसेंट काम कम्प्लीट हो जायेगा और सोर्स से जोड़ने का काम बाकी रहेगा तो पेयजल में सोर्स का काम कोई दो-चार महीने का रहता है, ज्यादा लम्बा प्रोसेस नहीं होता है तो वह कर सकते हैं।

लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि मन थोड़ा ठीक नहीं है। अगर पूरे मन से बात की जाए तो यह हो सकता है और भीलवाड़ा को पानी पिलाना है तो सोर्स को पानी देना वहां के बसे हुए लोगों को, क्योंकि झालावाड़ पानी जा रहा है, रामगंजमंडी पानी जा रहा है, वो भीलवाड़ा जाने लग गया। अभी थोड़े दिनों पहले एक डी.पी.आर. बनाने की घोषणा की कि ब्राहमणी पर बांध बनेगा और जयपुर को पानी पिलाया जायेगा। पानी सबका है। राजस्थान के लोगों को पानी मिलना चाहिए। कहीं और भी जरूरत हो वहां भी पानी मिलना चाहिए। लेकिन मानवता के नाते और नियम से भी ऑन रूट विलेजेज को पानी मिलना चाहिए। इसमें मेरे 2-3 समाधान हैं।

(13.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, पहला यह है कि भीलवाड़ा को 256 एमएलडी पानी चाहिए। मेरे क्षेत्र की जो पेयजल परियोजना है उसको सिर्फ 2.25 एमएलडी

(श्री सुरेश धाकड़)

पानी चाहिए, जोकि लगभग एक परसेंट पानी है। उसी योजना से अगर यह पानी दे दें तो इनको इतना खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा और पानी भी आराम से मिल जाएगा। एनओसी का झंझट भी नहीं रहेगा। सब काम ठीक से हो सकता है। इसमें ये लोग कह सकते हैं कि सब लोग ऐसे तो पानी मांगने लग जाएंगे। लेकिन सब लोगों को पानी मांगने का हक इसलिए नहीं है कि जहां सोर्स है और जिन गांवों से होकर के लाइन निकल रही है, उन लोगों को पानी देना ठीक है। लेकिन कोई जैसलमेर का आदमी थोड़े ही वहां पानी मांगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा यह है कि इस योजना का नाम बदल दें। इस योजना का नाम भैसरोड़गढ़ पेयजल परियोजना नहीं रखकर, भीलवाड़ा पेयजल विस्तार योजना रख दें और इसके टेंडर लगा दें। इससे इसकी एनओसी तीन महीने में मिल जाएगी। फोरेस्ट एक्ट यह कहता है कि हमने फोरेस्ट लैंड का डाइवर्जन पीएचईडी को कर दिया है। इससे पांच मीटर के अंदर पीएचईडी चाहे जिस तरह का काम करे। इन दोनों की नेचर एक तरह की है। पाइप लाइन डालनी है। पानी पिलाना है। सारे काम सेम नेचर के हैं तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा इसमें यह है कि एक राइजिंग पाइप लाइन है, जोकि करीब 10-11 किलोमीटर है। उसी का इश्यू ज्यादा है। वह फोरेस्ट में पड़ती है। जो 2500 करोड़ रुपये की योजना है तो उसमें 10 परसेंट एक्सट्रा, एक्सेस काम कर सकते हैं। मेरी जो पाइप लाइन डालनी है उसका केवल 5-6 करोड़ रुपए में काम हो जाता है। आप उस पाइप लाइन के लिए उसी ठेकेदार को विशेष परिस्थिति में अनुमति दे दें। वैसे ही नियम, कानून, एक्ट में लिखा हुआ है कि कर सकते हैं। अगर वह कर दें और भैंसरोड़गढ़ का ही टेंडर कर दें, तब भी इन लोगों को पानी मिल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, माना कि यह नहीं कर सकते हैं। यह कहें कि हम यह काम नहीं कर सकते हैं तो फिर इनको यह समझौता नहीं करना चाहिए था। जब समझौता कर दिया और वहां के लोगों को पानी पिलाना है तो एक समाधान और है। कुल छह पंचायतों के 77 गावों को पानी मिल रहा है और उसके पैसे लग रहे हैं 52 करोड़। मेरी जो दो ग्राम पंचायतें फोरेस्ट में आती

(श्री सुरेश धाकड़)

हैं, उनके सारे विलेजेज को छोड़कर के दूसरी दो ग्राम पंचायतों को उसमें एड कर लिया जाए। जो सोर्स है बिना फोरेस्ट का, वहां से मैं बता दूं और उसी 52 करोड़ में यह योजना इनक्लूड कर ली जाए ताकि वहां के लोगों को पानी मिल सके।

रावड़दा के लिए मैं पहले भी बोल चुका हूं कि उसमें कोई प्रोब्लम नहीं है। मंत्री महोदय जब जवाब देंगे और उसमें इसकी घोषणा कर देंगे तो भीलवाड़ा के लिए भी और हम सब लोगों के लिए भी ठीक रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अंतिम समाधान। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सिर्फ इसका टेंडर करा दो। हम हमारे स्तर पर ही वहां पाइप लाइन बना देंगे और वहां पर काम होकर, वहां के लोगों को पानी मिल जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा, अगर आप पूरी ईमानदारी से और पूरे मन से सोचेंगे तो जो ऑनरूट विलेजेज हैं उनको पानी मिलना चाहिए। यह कोई बड़ा इश्यू नहीं है। भीलवाड़ा जो पानी जा रहा है, उसकी एनओसी पूरी कंपलीट नहीं है। फोरेस्ट एक्ट में यह लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो पाइप लाइन के अंदर एनओसी एप्लाई कर दें। आप सारा काम कर दें लेकिन फाइनल एनओसी नहीं आती है, तब तक आप उस चीज को उपयोग में नहीं ले सकते हैं। अभी जो भीलवाड़ा पानी जा रहा है और उसका उपयोग ले रहे हैं तो यह कानूनन ठीक नहीं है।

दूसरा, वहां जो 33 केवी की लाइन है, वह नगरपालिका क्षेत्र में से होकर निकल रही है। हमारी बिना एनओसी के ले रखी है। आने वाले समय में 33 केवी के तार वहां से हटाने पड़ेंगे। गर्मी का समय है और आप लोगों को भी परेशानी नहीं हो और मेरे क्षेत्र के लोगों को भी परेशानी नहीं हो, तो मैं मंत्री महोदय से यही कहूंगा कि इसकी आप घोषणा कर दें। यह सभी के हित में ठीक रहेगा। छोटा सा ही काम है। केवल टेंडर करना है। थैंक्यू। किरण जी देंगी जवाब?

श्री उपाध्यक्ष: बड़ा संवेदनशील विषय है इनका।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

बेगूं से आने वाले माननीय सदस्य ने विकल्प भी बहुत दिए हैं। इनकी प्रोब्लम वास्तव में बहुत ही जेन्युइन है क्योंकि भीलवाड़ा चंबल परियोजना के ऑनरूट विलेजेज में यह भैसरोड़गढ़ आता है।

भैसरोड़गढ़ के लगभग 65 गांव और ढाणियां हैं जिनकी योजना बनाई गई थी। जिसकी स्वीकृति भी दिनांक 9.12.2014 को मिली है। लगभग 51 करोड़ रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पीपीसी की मीटिंग में जारी हो चुकी थी। इसके पश्चात् 2.11.2015 को यह टैक्निकल कमेटी से भी निकली है। लेकिन इस परियोजना के लिए जो मैन समस्या आ रही है, वह यह है कि इसका 35 परसेंट भाग जवाहर सागर अभयारण्य, भैंसरोड़गढ़ अभयारण्य और वन मंडल चित्तौड़गढ़ की बुराव रेंज में आता है। फोरेस्ट की परमिशन के बिना हम इसकी स्वीकृति जारी नहीं कर पा रहे हैं। यह इसकी मैन टैक्निकल प्रोब्लम आ रही है जिसकी क्लियरेंस नहीं होने से योजना स्वीकृत होने के बावजूद भी टेंडर्स नहीं कर पा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाह रही हूं कि क्लियरेंस के लिए 28.01.2016 और 02.02.2016 को वन विभाग की वेबसाइट पर इसकी एप्लीकेशन अपलोड कर दी गई है। इसकी क्लियरेंस के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि हम लोग परमिशन लेते रहें और एक बार टेंडर कॉल कर दें तो मैं आपके माध्यम से उनको यह बताना चाहती हूं कि पूर्व में भी ऐसे ही 2004-05 में हमने सवाई माधोपुर-नादौती योजना को जब स्वीकृत किया था तो उसमें यह अनुमान था कि फोरेस्ट की क्लियरेंस हो ही जाएगी। लेकिन फोरेस्ट की क्लियरेंस नहीं मिलने पर आपने देखा कि बहुत लंबे समय तक जब टेंडर्स हो जाते हैं, वर्क ऑर्डर हो जाते हैं तो उसकी जो रेट्स हैं तो उनको रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पुरानी रेट्स पर ठेकेदार काम करते नहीं हैं। इसके कारण से बाद में जाकर बहुत सारी परेशानियां आईं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह भी है कि जो फोरेस्ट एरिया है उसमें जो मैन इनटेक फिल्टर प्लांट हैं, पंप हाउस हैं, मैन ट्रांसमिशन हैं, ये सारे आ रहे हैं। आज अगर हम पाइप लाइन डाल देंगे और अगर इनटेक नहीं होगा,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

मैन ट्रांसमिशन की लाइन हम नहीं डाल पाएंगे तो वह सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम खड़ा करेंगे, वह बेकार होगा। इस वजह से इसकी स्वीकृति फोरेस्ट से आने के पश्चात् इस काम को हम हाथ में ले लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने रावड़दा के संदर्भ कहा, जो योजना इन्होंने बनवाई है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से उनको आश्वस्त कर सकती हूं कि आने वाली जो पीपीसी की मीटिंग होगी, उसमें उस पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। उसके अंदर 5 गांव और 3 ढाणियों को जोड़ने की योजना बनाई गई है, उस पर हम लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करके स्वीकृत करने की कोशिश करेंगे।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): उपाध्यक्ष महोदय, जब मेरा भैंसरोडगढ़ पेयजल योजना के बारे में पूछने का नम्बर आता है, तब भी मंत्रीजी जवाब नहीं देते हैं। दो-तीन मंत्री और सब लोग समझाकर बैठा देते हैं। मैं यहां आपका संरक्षण चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि एग्रीमेंट किया तो फिर एग्रीमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी? जब इनको भीलवाड़ा को पानी पिलाना था तो इन्होंने इमिजिएटली शब्द भी लिख दिया। मैंने उस समय भी ऑब्जेक्शन किया था। लेकिन तत्कालीन मंत्री महोदय ने कहा कि मैं बैठा हूं यार, हो जायेगा। लेकिन हो नहीं पाया। उसके बाद दूसरी मंत्री किरणजी आ गईं। तीसरे मंत्री सुरेन्द्रजी गोयल आए और आज मुझे चौथे मंत्री के रूप में किरण जी माहेश्वरी से वापस जवाब मिल रहा है।

मेरा कहना यह है कि आप कम से कम रावड़दा के लिए तो घोषणा कर दो। आश्वासन में जाएगा तो आश्वासन कमेटी में तो मैं हूं। वहां तो मैं कागज मंगवा ही लूंगा। लेकिन यहां मैं आपसे चाहूंगा कि पीपीसी की मीटिंग में इसकी घोषणा हो जाए।

श्री उपाध्यक्ष: इसके लिए तो मंत्री जी सहमत हैं ना।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): उपाध्यक्ष महोदय, सहमत हैं तो मैं धन्यवाद दे देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अंकित और हो गया। अब इससे ज्यादा गारंटी आपको और क्या चाहिए।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तो यह है कि पीपीसी की मीटिंग होती है, बहुत बार आपके यहां से भी और माननीय सदस्य भी बोलते हैं कि यह सदन परंपराओं से चलता है। मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट भी परंपराओं से चलता है। इनकी पुरानी परंपरा चली आ रही है कि बिना एनओसी के टेंडर करना तो इसमें एक परंपरा और निभा दें और बिना एनओसी के टेंडर कर दें।

किरणजी माहेश्वरी घोसुण्डा से हैं और हमारे चित्तौड़ की बहू भी हैं। प्राचीन काल से एक परंपरा रही है कि समाज में, अपने घर-परिवार वालों को पानी पिलाने का काम बहू, बेटी का रहता है। आज इनको एक मौका मिला है तो यह घोषणा कर दें कि मैं इसके टेंडर करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही यह जब कपासन पधारे थे, तो मंत्रीजी ने एक घोषणा की थी, वहां कपासन तालाब के पानी का इश्यू है। उसके लिए दो मंत्रियों का आपस में मिलन नहीं हो पा रहा है। जलदाय मंत्री और सिंचाई मंत्री कब मिलने वाले हैं, उसकी भी तारीख बता दें तो थोड़ा मेरे लिए ठीक हो जाएगा। उसमें आपकी तरफ से भी स्नेह, आशीर्वाद रहे। मैं माननीय किरण जी माहेश्वरी से निवेदन करूंगा कि उसकी घोषणा करें और इसमें भी कह दें कि बहुत जल्दी करेंगे। पीपीसी की मीटिंग कब होगी, उसकी तारीख जरूर बता दें। वह आता है ना कि तारीख पर तारीख, कौनसी फिल्म है उसमें? ऐसे ही इनकी मीटिंगों के बारे में मैं जब भी पूछता हूं तो यह तारीख पर तारीख दिए जाते हैं। भीलवाड़ा में कोई प्रोब्लम पैदा नहीं हो और पानी को लेकर के वहां कोई इश्यू खड़ा नहीं हो, इससे बचने के लिए इनको कुछ करना चाहिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, किरणजी हमारी भाभी जरूर हैं, लेकिन भाभीजी घर पर नहीं रहती हैं। यह राजसमंद रहने लग गई हैं। हमसे थोड़ी नाराज हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो बेगूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, पीपीसी की मीटिंग तो अतिशीघ्र

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

करवा देंगे। माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी से हम कह देंगे कि वह मीटिंग जल्दी करें।

लेकिन इसके अलावा इन्होंने जो कपासन शहरी योजना के संदर्भ में बात कही, उसमें दोनों ही मिनिस्टर्स को बैठना है। जल संसाधन मंत्रीजी भी यहां पर विराजमान हैं। पीएचईडी मिनिस्टर और इनकी जल्दी ही मीटिंग करवाकर इसमें पानी के आरक्षण का मुद्दा है, वह हो जाए। अगर रिजर्व वाटर होगा तो कपासन शहरी योजना की पेयजल की स्कीम हमारी बन सकेगी। उसको जल्दी से जल्दी करवायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकर सिंहजी।

ब्यावर में यातायात विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही लापरवाही

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर में डीटीओ कार्यालय खुले हुए काफी वर्ष हो गए हैं, वाहनों की फिटनैस और पास कराने का सारा काम ब्यावर में ही होता है। पिछले तीन वर्ष से यह काम अजमेर के अंडर में दे दिया। वहां के जो अधिकारी, डीटीओ आए हुए हैं, उन्होंने अजमेर वालों से बात करके, सैटिंग करके ब्यावर में पास कराने की जगह हर वाहन मालिक को परेशान करने की नीति से यह काम अजमेर में शुरू करवा दिया। सबको अजमेर जाकर गाड़ियों की फिटनैस करवानी पड़ती है। इससे उनका डीजल भी खर्च होता है, दो जगह टोल भी देना पड़ता है और इस वजह से परेशानी खड़ी हो रखी है तो मेरा मंत्री महोदय के माध्यम से निवेदन है कि उसको वापस ब्यावर में ही करना शुरू करवा दिया जाए, इस तरह से डीटीओ को पाबंद करवा दिया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितने छोटे ट्रैक्टर, टैक्सियां, डम्पर वहां से निकलते हैं उन सबके ऊपर तो वह चालान काट देते हैं। जिसके एक डम्पर है, गरीब आदमी है, एक ट्रेलर है उन सबके चालान काट रहे हैं। कोई भी वाहन बिना चालान के नहीं निकल पा रहा है जबकी श्री सीमेंट से और राजसमंद से हर ट्रेलर ओवरलोड निकलता है। पाँच सौ ट्रेलर राजसमंद से आते हैं और पाँच सौ ट्रेलर श्री सीमेंट से निकलते हैं। सारे ओवरलोड निकल रहे हैं। तीन साल से कभी किसी का चालान नहीं काटा गया। ऊपर से

(श्री शंकर सिंह)

सरकार को करोड़ों रुपयों की हानि पहुंचा रहा है। ऐसे अधिकारी के खिलाफ मैं तो कह रहा हूं कि कार्यवाही होनी ही चाहिए। हमने जांच की। पहले शिकायत की है, उस शिकायत में, जिसकी पुष्टि में अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), डॉक्टर मनीषा अरोड़ा के पत्र क्रमांक 14801 दिनांक 29.07.2016 को, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि वास्तव में सही है यह आरोप। इन पर आरोप लगे थे, उन पर भी आपने कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसे अधिकारी के खिलाफ मैं कह रहा हूं। अभी पिछले दो महीने से वह चालान काट रहे हैं। जब से हमने शिकायत की है, तब से चालान काटना चालू कर दिया है लेकिन करोड़ों रुपयों का उसने चूना लगाया है। हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए कोशिश की। इस प्रकार के अधिकारी को तुरंत निलम्बित करना चाहिए और दूसरा, उससे वसूली भी करनी चाहिए और दो महीने के अंदर जो चालान काट रहे हैं उसकी औसतन जांच करवाकर इसको मिलान करवाया जाए कि जितने इन दो महीनों में चालान कटे हैं, उतने पिछले तीन सालों में क्यों नहीं काटे गए? वह पैसे कहां गए? ऐसे अधिकारी के खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप बहुत ही जागरूक और बहुत संवेदनशील हैं, हर मामले को आपने गंभीरता से लिया है। हमारी सरकार जो बहुत ही सुशासन की सरकार चल रही है, उस सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ अधिकारी ऐसे आ जाते हैं। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसी मछली को उठाकर बाहर फेंके। उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उससे वसूली भी हो और वह निलम्बित भी हो। धन्यवाद।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी पर्ची के माध्यम से बात कही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा माननीय सदस्य को कि आपकी इस विषय में तीन शिकायतें हमारे कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट को प्राप्त हुई हैं। उनको भी मैंने देखा है और हमारी डीटीओ को शो कॉज नोटिस दिया है। आपकी शिकायत पर, उसका जवाब भी आया है। जहां तक चालान का सवाल

(श्री युनुस खान)

है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो बातें कहीं। एक बात तो यह कही कि राजस्व का नुकसान हो रहा है। दूसरी बात यह कही कि चालान ज्यादा काट दिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ज्यादा नहीं काटा है। चालान काट ही नहीं रहा, पूरी की पूरी राशि जेब में यूं ही हजम कर रहा है। यह कह रहा हूं, यह कहना है मेरा सीधा।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा, अभी तक 3000 चालान काटे गए हैं। जिस जगह की बात कही है, श्री सीमेंट कम्पनी की, उन्हीं की कम्पनी के 3000 चालान काटे हैं तो यह राजस्व सरकार के खाते में ही आया है। आपकी तीनों शिकायतों में एक ही बात आई है कि इसका स्थानांतरण कर दिया जाए तो निश्चित रूप से अगले वर्ष में जब हम स्थानांतरण करेंगे तो रूटीन में उसका स्थानांतरण भी कर देंगे। यदि उसके खिलाफ कोई अनियमितता की बात है तो उसकी भी जांच करवा लेंगे और यदि वह दोषी होगा तो वह भी कार्यवाही कर देंगे। ...(व्यवधान)...

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय मंत्रीजी, उसे निलम्बित भी कर सकते हो, आज ही निलम्बित करना चाहिए ऐसे अधिकारी को।

श्री उपाध्यक्ष: श्री फूलसिंह मीणा।

उदयपुर के कलड़वास रीको एरिया व पानेरियों की मादड़ी में किसानों को पट्टा वितरण

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे किसानों की समस्या है और भारी समस्या है, मंत्री महोदय, जरा इनके ऊपर दया करेंगे और किसानों को उनका अधिकार दिलाएंगे। कलड़वास, तितरड़ी व डाकन कोटड़ा राजस्व गांव में रीको द्वारा कृषि भूमि अवाप्त की गई थी। 2005 में अवार्ड जारी किया गया। उसमें किसानों को कृषि भूमि की एवज में 20 प्रतिशत आवासीय व पाँच

(श्री फूलसिंह मीणा)

प्रतिशत व्यावसायिक भूमि देना तय किया गया। जो नकद मुआवजा लेना चाहते थे उनके लिए नकद मुआवजा देने का प्रावधान रखा था। करीब दस वर्ष हो चुके है और नकद मुआवजा भी मिल चुका है, परन्तु जिन किसानों ने जमीन के बदले में जमीन लेने के लिए रिकार्ड में समर्पण कर दिया, आज दिनांक तक इनको अपनी जमीन के पट्टे रीको द्वारा नहीं दिए गए हैं। किसानों के रहने के मकान भी नहीं हैं, किराये के मकानों में वह रह रहे हैं। उनको फसल का भी दस वर्षों से नुकसान हो रहा है। सरकार द्वारा आवास योजना भी आई है। उनके प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री आवास योजना में नाम आ गए हैं, पर वे आवास कहां पर बनाएं। इन किसानों को जल्दी पट्टा दिलाने की कृपा कराएं। वर्षों पहले सरकार ने इनकी जमीन भी ले ली और पट्टे भी नहीं दे रहे हैं। उद्योग लगाने के लिए आवंटन भी कर दिया, उद्योग लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया। किसानों ने विरोध किया कि जब तक हमें पट्टा नहीं देंगे तब तक हम हमारी जमीन में उद्योग नहीं लगाने देंगे। तब जिला कलेक्टर महोदय ने मुझे बुलाया और यह कहा कि उद्योग का काम चलने दो, सरकार का काम है, रुकेगा तो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी से जल्दी इन किसानों को पट्टा दिलाने का काम कर देंगे मगर अभी तक किसानों को पट्टे नहीं दिए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि किसान उग्र आंदोलन करे, इससे पहले उनको पट्टा दिलाने की कृपा करावें ताकि उद्योग भी लगे और इन किसानों को रोजगार भी उपलब्ध हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि जिन किसानों के बिला नाम पर वर्षों से मकान बने हुए थे उनको भी रीको द्वारा ले लिया गया। जिनका कोई मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इन किसानों को पट्टा आवंटित किया जाए और किसानों को राहत प्रदान कराई जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में पानेरियों की मादड़ी के किसानों की दो सौ बीघा जमीन राजस्थान आवासन मंडल ने वर्ष 1983 में अवाप्त की थी और वर्ष 2000 में तीस हजार रुपए

(श्री फूलसिंह मीणा)

प्रति बीघा की दर से अवार्ड पास किया गया। किसानों ने लेने से मना करने पर मुआवजा राशि को कोर्ट में जमा कराकर बोले कि किसानों की खातेदारी खत्म कर समस्त भूमि आवासन मंडल के नाम दर्ज कर दी गई है। इस पर किसानों ने विरोध करते हुए भूमि समर्पण के एवज में उनके ही पास के गांव भुवाणा में उनके समान स्थिति वाली जमीन की मांग की, जिसको स्वयं आवासन मंडल ने मानते हुए, आवासन मंडल के तत्कालीन अध्यक्षजी ने भुवाणा की तर्ज पर पानेरियों की मादड़ी के किसानों को नि:शुल्क समर्पण के बदले पच्चीस प्रतिशत विकसित भूमि दिलाने की राज्य सरकार से सिफारिश की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाद में आवासन मण्डल इससे मुकर गया जिस पर किसानों ने 22 से 28 अगस्त, 2008 तक धरना, प्रदर्शन, आमरण अनशन किया। जिसे माननीय गुलाबचंदजी कटारिया एवं श्रीमती किरणजी माहेश्वरी की मध्यस्थता पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भुवाणा की तर्ज पर 25 प्रतिशत दिलाये जाने के आश्वासन पर आंदोलन समाप्त करवाया। ऐसी परिस्थिति में 2009 के बाद किसान बराबर आवासन मण्डल के अधिकारियों से उदयपुर में कैम्प लगाकर पट्टे देने की मांग करते रहे, लेकिन समझौते के अनुसार पट्टे नहीं दिये जाये और कुछ छोटे किसानों को पकड़कर अपने पक्ष में लेकर 6-7 बीघा की एवज में 16 पट्टे जारी किये। उसमें से भी 8 ने पट्टे लिये और बाकी पट्टे नहीं ले रहे थे। जब मैंने मंत्री महोदय से मुलाकात की, तब माननीय मंत्रीजी ने यह कहा कि कुछ आदमियों ने सरकार की बात मानकर पट्टे ले लिये इसलिए हम बाकी को अतिरिक्त फायदा नहीं दे सकते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मुझे कहा कि लेना है तो उसी नियम के तहत हम पट्टे देने को तैयार हैं। उसके बाद माननीय गृह मंत्रीजी व मैंने मिलकर प्रयास किया और उन किसानों को समझाया। बड़ी मुश्किल से वे राज़ी हुए। उसके बाद में कुछ अधिकारियों के साथ एवं किसानों के साथ एक बैठक की गयी जिसमें पट्टे देने का आश्वासन मिला। आज दिन तक पट्टे नहीं दिये गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन व सचिव दोनों ही इस काम को करना नहीं चाहते, क्योंकि जो 16 पट्टे दिये थे उनमें भी

(श्री फूलसिंह मीणा)

नाम उल्टे-सीधे लेकर भेज दिये। वे नहीं ले पाये और समय निकल गया। उसके बाद भी 8 पट्टे अभी भी अटके हुए हैं। उनको भी नहीं दिया। कई बार माननीय मंत्री महोदय से मिले, लेकिन इन अधिकारियों के कोई असर नहीं पड़ा जबकि गृह मंत्री महोदय ने भी इनको कहा कि इन किसानों का क्या दोष है। जैसे हम दे रहे हैं, वैसे ही ये लेने को तैयार हो गये हैं, फिर आपको क्या तकलीफ है। उसके बाद भी चेयरमैन व सचिव ने एक मजाक के तौर पर ले रखा है। इन्होंने मंत्री महोदय को गुमराह करते हुए किसानों के हित पर कुठाराघात किया। 34 वर्षों से किसान इस विश्वास के साथ बैठे हैं कि सरकार हमारे साथ न्याय करेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छह महीने पहले विश्वास पर तलवार तब चली जब यहां के चेयरमैन व सचिव ने कलेक्टर साहब को आदेश दिया कि पुलिस फोर्स लेकर बेदखल किया जाए और कब्जा हाउसिंग बोर्ड को दिया जाए। वह नोटिस हमारे पास आया तब गृह मंत्रीजी से मिले। मैं माननीय गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं, कलेक्टर साहब को तुरन्त फोन कर इस कार्यवाई को रुकवाया और जो खून-खराबा होने वाला था, उसको रुकवाकर किसानों को समझाया कि आपके साथ न्याय किया जाएगा, अन्याय नहीं होने देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारियों को तुरन्त प्रभाव से इन पदों से हटाया जाए क्योंकि गृह मंत्रीजी और वहां के सैकड़ों किसान एवं जन-प्रतिनिधि उनका अधिकार मांग रहे हैं। ऐसा मेरे साथ हो रहा है तो जनता के साथ क्या होता होगा? इसलिए वहां ऐसे अधिकारियों को लगाया जाए जो जनता के हित को प्राथमिकता दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में वर्तमान में मंत्री महोदय श्रीचन्द जी कृपलानीजी से भी काश्तकारों ने जयपुर में मुलाकात की तो माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी शिविर लगाकर पट्टे दे दिये जाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ये कितने मंत्रियों को रेफर कर रहे हैं? एक-एक चीज को कहां रेफर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कर रहे हैं? हरेक मंत्री का नाम रिकॉर्ड पर ले रहे हैं कि उसने यह कहा, उसने यह कहा।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, एक मिनट आप विराजो। मैं संसदीय कार्य मंत्री आपको और मुख्य सचेतक महोदय, आपको भी यह निवेदन कर रहा हूं। या तो आप सदस्यों को कोई ओरिएंटेशन प्रोग्राम के माध्यम से कि किस प्रकार से, किस नियम से कैसे बोलना है, इसकी शिक्षा प्रदान करा दें। अन्यथा आसन को सख्त होकर इस पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। 10 मिनट से सम्माननीय सदस्य, आदरणीय सदस्य अपना लिखा हुआ वक्तव्य पढ़ रहे हैं। अगर लिखा हुआ वक्तव्य उनको पढ़ना था तो 295 में दे देते, जवाब तो उसका भी आता। पर्ची के माध्यम से आपको एक ऐसा अवसर मिलता है कि कोई भी आपका ऐसा सीरियस इश्यू है जिसको आप मंत्री के ध्यान में लाएं और मंत्री उसका जवाब देता है। अब कुछ रह गया है तो वह भी पढ़ दें।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 34 वर्षों से इस समस्या से किसान जूझ रहे हैं। मैंने पूरा इसलिए बताया कि कम से कम उन किसानों को उनका अधिकार मिल जाए और हमारे वर्तमान में जो माननीय मंत्री हैं उनसे मुझे पूर्ण विश्वास हैं। ये भी मेवाड़ से आते हैं। ये इन किसानों को राहत दिलाकर पट्टे दिलाने की कार्यवाही करेंगे, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: बात तो मेवाड़ की है, आप तो ढूंढाड़ से हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मेवाड़ वालों ने तो अभी तक किया नहीं, अब ढूंढाड़ वाले कर दें तो ठीक है। मेवाड़ वालों ने तो किया नहीं अभी तक।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से दो मुद्दे उठाये गये। उदयपुर के कलडवास रीको इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है। वहां 225 हैक्टेयर निजी भूमि का एक्वीजिशन किया गया। माननीय सदस्य ने कहा कि 2005 में उसका अवार्ड जारी किया गया जबकि अवार्ड 2005 में नहीं, अवार्ड 2009 में जारी किया गया है। अवार्ड जारी करने के बाद खातेदारों को अवार्ड का 9 करोड़ 20 लाख से ज्यादा राशि का भुगतान भी किया जा चुका है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जब उनसे ऑप्शन मांगा गया कि वे कैश अवार्ड लेंगे या जमीन के बदले जमीन लेंगे तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियत तिथि तक 724 खातेदारों ने कहा कि हमें जमीन के बदले जमीन दी जाए। नियत तिथि के बाद 170 खातेदारों ने और कहा। इस प्रकार कुल 894 खातेदारों ने कहा कि हमें जमीन के बदले जमीन दे दी जाए। इनमें से 92 खातेदार ऐसे थे जो इस एक्वीजिशन के खिलाफ कोर्ट में चले गये और जोधपुर हाईकोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया। इस इंडस्ट्रियल एरिया का जो प्लान बनाया गया, उस प्लान के अंदर जो आवासीय हिस्सा बताया गया, वह आवासीय हिस्सा उन 92 खातेदारों की जमीन में है जिनकी जमीन पर स्टे है। इस कारण से उनको जमीन के बदले जमीन नहीं दी गयी है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहता हूं, हालांकि 894 में से 375 को आरक्षण-पत्र दे दिया है, बाकी को आरक्षण-पत्र देने की प्रक्रिया जारी है। इसके बावजूद मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिन 92 खातेदारों ने जोधपुर हाईकोर्ट के माध्यम से स्टे ले रखा है और जिनकी जमीन में प्लान में रेजिडेंशियल एरिया है, इस प्लान को हम रिवाइज करेंगे, री-ऑर्गेनाइज करेंगे और री-ऑर्गेनाइज करने के बाद आवासीय इलाके की जमीन को उन 92 खातेदारों की जमीन से अलग कर देंगे और अलग करने के बाद न केवल आरक्षण-पत्र देंगे, बल्कि आरक्षण-पत्र के साथ-साथ आवंटन-पत्र देकर इस समस्या का समाधान कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनीता। (व्यवधान) अच्छा, आप भी रिएक्ट करना चाहेंगे?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पानेरियों की मादड़ी जिला उदयपुर में किसानों की अवाप्त भूमि के बदले 15 प्रतिशत विकसित भूमि, आप 25 प्रतिशत कह रहे थे, लेकिन इसमें 15 प्रतिशत का ही प्रावधान है। भू-खण्डों के आवंटन-पत्र दिलाने के विषय में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संदर्भ में जो निवेदन किया है, यह सही है कि जो अधिसूचना जारी हुई, उस समय 27.6.1983 से यह समस्या चल रही है। इसको काफी लम्बा समय हो गया है। माननीय सदस्य ने जो समस्या रखी है, वह वाजिब है। लेकिन बीच में

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गयीं कि कई किसान, जिनको जमीन के बदले मुआवजा देना था, उन्होंने मुआवजा नहीं लिया और जिनको भू-खण्ड देना था, उन्होंने भू-खण्ड लेने से मना कर दिया। कई किसानों से जब भू-खण्ड देने के लिए बात की गयी तो उनके उसमें नाम ही चेंज हो गये। और कई विसंगतियां उसमें हो गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई जगह कुछ काश्तकारों की मृत्यु हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, अब कुल मिलाकर स्थिति यह है कि काश्तकार यह चाहते हैं और मैं खुद भी मानता हूं यह इनकी जैन्युइन समस्या है और इसका समाधान करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर 15 वादों में 17 हिस्सेदारों को आवंटन पत्र जारी किए गए थे जिनमें से आठ वादों के खातेदारों के द्वारा आबंटन पत्र समयावधि में पंजीयन नहीं कराये जाने पर पुन: मण्डल को प्राप्त हो चुके हैं, जोकि सक्षम स्वीकृति उपरांत जारी किये जाने हैं। पांच वादों में खातेदारों के द्वारा नामित व्यक्तियों को आबंटन पत्र जारी करने हेतु सहमति प्रस्तुत की गई। 222वीं बोर्ड बैठक के बिन्दु संख्या 29 के निर्णयानुसार राज्य सरकार की स्वीकृति चाही गई है जो प्रक्रियाधीन है।

नम्बर तीन, तीन वादों में पांच हिस्सेदारों द्वारा हक त्याग के अनुसार आबंटन पत्र चाहे गये हैं। खातेदारों द्वारा रजिस्टर्ड हक त्याग प्रस्तुत नहीं करने पर खातेदारों को सूचित किया गया है। सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और वो प्राप्त हो जाएगी तब उस पर कार्यवाही की जाएगी। सात वादों में जारी अवार्ड में संशोधन अपेक्षित है जिनका विधिक परीक्षण कर निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन वादों में आबंटन पत्र जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है जिसके लिए भी शीघ्र निस्तारण के निर्देश हम दे चुके हैं। 13 वादों में जो अवार्डी थे उनकी मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित होना है, उसके उपरांत आबंटन पत्र जारी किया जाना है। मृत्योपरांत वारिसान को विधिक बिन्दु का परीक्षण कर निर्देश जारी किए जा रहे हैं और दो वादों में मूल अवार्डी के स्थान पर क्रेता द्वारा आबंटन पत्र चाहा गया है। उनके स्थान पर दूसरे, जिनको इन्होंने बेच दी वो उसके बदले मांग रहे हैं तो मण्डल स्तर पर वो सम्भव नहीं है। 17

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

वादों के खातेदारों के द्वारा आबंटन पत्र जारी करने हेतु आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं अत: खातेदारों के स्तर पर वो लम्बित है। अवार्ड में समस्त वादों की नकद मुआवजा राशि न्यायालय में 2004 से जमा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यही कहूंगा कि माननीय सदस्य की समस्या बहुत गम्भीर है और इन प्रकरणों के निस्तारण हेतु तीन माह के अन्दर पानेरियों की मादड़ी में विशेष शिविर लगाकर इनका हम निस्तारण करेंगे।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनीता।

नगर में सेवल मंदिर के आसपास हो रहे खनन कार्य पर रोक

श्रीमती अनीता (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मैं मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सीकरी उप तहसील है वहां पर एक पौराणिक मन्दिर है जिसको सेवल मन्दिर के नाम से जानते हैं। यहां पर जो राम-सीता की मूर्ति रखी है वो भी 100-150 साल पहले की है। यह पूरा मन्दिर बहुत आस्था का केन्द्र है। इसके आस-पास जो पहाड़ हैं, उन पहाड़ों पर हजारों कदम्ब के और अन्य महत्वपूर्ण वृक्ष वहां लगे हुए हैं जो इस मन्दिर का भी सौन्दर्य बढ़ाते हैं और हमारे यहां पर प्राकृतिक रूप से अगर पर्यावरण के रूप से समझते हैं तो हमारे क्षेत्र में ऐसा यह एक क्षेत्र है।

मैं यह कहना चाहती हूं कि इस मन्दिर के पास में ही, इस मन्दिर के अन्तर्गत ही एक गौशाला का संचालन होता है जिसमें मेरे ख्याल से कम से कम 1000 गायें, बछड़े, नन्दी हैं और सरकार के द्वारा जो बनी हुई कमेटी है, वो इनकी देखभाल करती है। इस समय परेशानी यह आ गई है कि इस मन्दिर और इस गौशाला के आस-पास जो पहाड़ थे उन पहाड़ों पर सरकार के द्वारा 15 जुलाई, 2010 को लीज सैंक्शन कर दी गई। वो लीज सैंक्शन करने के बाद जो पिछला मई गया है, उस मई तक भी इसमें यह पता नहीं लग पाया कि यहां लीज है या क्या है, क्या नहीं है। वह आस्था का केन्द्र है, लोग वहां पर पूजा-अर्चना करने भी जाते हैं। जब मई में इसकी लीज

(श्रीमती अनीता)

आई और उसके बाद रास्ता बन्द करना और माइंस का काम करना इन्होंने शुरू किया तो वहां के आस-पास के गांवों में आंदोलन के रूप में यह बात सामने आई। क्योंकि सारे गांवों के लोग यह चाहते थे कि यह हमारी आस्था का केन्द्र है, यहां पर माइनिंग का काम नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि माइनिंग डिपार्टमेंट से भी हमने कागज निकलवाये थे। माइनिंग डिपार्टमेंट से यह आया कि यह अकबरपुर गांव और टेसकी गांव के बीच में यह माइंस सैंक्शन की है। अकबरपुर गांव में 14 लीज सैंक्शन की हैं जिनके खसरा नम्बर 196, 201, 306, 195 और 322 है और जो टेसकी गांव है उसमें इसकी दो लीज सैंक्शन की है। ऐसे करके 16 लीज इस मंदिर के आस-पास की है। यह जो मंदिर है इस मंदिर की मूर्ति के नाम 23.7 हैक्टेयर की कृषि भूमि है जिसमें चारा और फसल उगाते हैं, उससे गौशाला भी चलती है और मंदिर का काम-धाम भी उसी के अनुसार चलता है। माइनिंग डिपार्टमेंट का जो उत्तर हमें मिला था, हमारी बात हुई, तब तो वो ये कह रहे थे कि इसकी जो दूरी है वो माइनिंग एक्ट के हिसाब से सही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि जो पहाड़ है, उसके एक तरफ तो माइनिंग की लीज अलॉट कर दी और पहाड़ का जो दूसरा हिस्सा है, वहां पर हमारी मंदिर की जमीन और मंदिर है। जब माइनिंग के द्वारा उस पहाड़ के पत्थर निकालेंगे तो नेचुरली वो पहाड़ पूरा ही उससे नष्ट होने वाला है और जब पूरा ही पहाड़ नष्ट होगा तो आप जो नपाई का हिसाब कर रहे हैं तो पहाड़ को इस तरह से ट्राएंगल के हिसाब से देख लिये तो लम्बाई तो ज्यादा आ गई पर असलियत में आप अगर देखेंगे तो उसकी दूरी इतनी नहीं आती। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि इस मन्दिर के आस-पास ये लीज सैंक्शन हुई है और इन लीज के सैंक्शन होने से, ये जो 16 लीज एक साथ हुई हैं इनसे पर्यावरण पर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा लेकिन जो आस्था का केन्द्र है सेवल मंदिर, उस पर भी पड़ेगा क्योंकि यह 100-150 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर के अस्तित्व पर संकट आया है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से चाहती हूं कि हमारे इस मंदिर की रक्षा हो। इसमें जो गौशाला चलती है, वो भी अच्छी तरह से संचालित होती रहे, इसलिए इसके लिए भी आप ध्यान करें। मेरा तो आपसे

(श्रीमती अनीता)

यह कहना है कि ये जो लीज हैं ये कैन्सिल होनी चाहिए जिससे हमारे मंदिर का संकट दूर हो सके।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्या ने पर्ची के माध्यम से सेवल मंदिर के पास माइनिंग का मुद्दा उठाया है। नगर के अन्दर कुल 66 खनन पट्टे हैं लेकिन यह सेवल मंदिर टेसकी तहसील के अन्दर आता है। जैसा आपने बताया कि वहां 14 माइंस हैं लेकिन इसके इर्द-गिर्द, जो नियम है वो तो यह है कि 45 मीटर के पैरीफेरी एरिया में कोई खनन स्वीकृत नहीं की जा सकती लेकिन यहां खनन पट्टा संख्या 139 और 140 जो हैं ये 2010 में स्वीकृत हुए हैं, जिला कलेक्टर से एनवायर्नमेंटल क्लियरेंस भी इनको मिला है और वर्तमान में ये चल रहे हैं। इनकी दूरी 1600 मीटर है। एक और खान जो ग्राम बास-बुर्जा में 233/8 है, यह 650 मीटर की दूरी पर है। इसकी ई.सी. जारी नहीं होने के कारण यह अभी बन्द पड़ी है और इसमें माइनिंग नहीं हो रही है। मैं माननीय सदस्या से कहना चाहूंगा कि जो भी वर्तमान में खनन हो रहा है, उसमें नियमानुसार तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जहां तक भावनाओं का सवाल है या धार्मिक आधार पर मामला है तो जिला कलेक्टर के पास ये पावर्स हैं। इससे पूर्व में भी ब्रज चौरासी में एक कमेटी कलेक्टर ने बनाई थी और ब्रज चौरासी के इर्द-गिर्द 500 मीटर में प्रतिबन्ध लगा दिया था। इसके बाद भी 08.02.2008 को डीग और कामां में 138 हैक्टेयर का एक गैर मुमकिन पहाड़ था उसको भी वन भूमि डिक्लेयर कर दिया था। अगर जिला कलेक्टर के माध्यम से कोई रिपोर्ट आती है कि धार्मिक भावनाओं के कारण यहां पर कलेक्टर प्रतिबंधित करता है तो निश्चित तौर पर खान विभाग उसमें कार्यवाही करेगा। अगर कोई इल्लीगल माइनिंग इस मंदिर और 1600 मीटर के बीच में हो रही है तो उसकी निश्चित तौर पर हम जांच करायेंगे और इल्लीगल माइनिंग कोई कर रहा है तो वो तो नहीं होने देंगे लेकिन वर्तमान में दो खान के पट्टे जारी हुए हैं और खनन हो रहा है वो नियमानुसार हो रहा है। जिला कलेक्टर इसके अन्दर अधिकृत हैं। जिला कलेक्टर अगर रिपोर्ट भेजेगा तो पूर्व में भी हमने 202 खान पट्टे बन्द करके स्थानान्तरित किये हैं और उस पर कार्यवाही हम निश्चित तौर पर करवायेंगे।

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो टेसकी में दो लीज हैं उनकी और अकबरपुर में 14 हैं उनकी, और ये मेरी बात को अवश्य रूप से समझें, जो आप लम्बाई बता रहे हैं, मैं उससे आपको मना नहीं कर रही हूं क्योंकि आपका नापने का जो तरीका है और मेरा जो सोचने का तरीका है, उसमें आप अगर उसको अण्डरस्टैंड करेंगे तो आप समझ जायेंगे कि पहाड़ को आप नाप किस तरीके से रहे हैं? जो आपकी नाप है, उसमें सही बैठ रहा है लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहाड़ ऐसा है, एक तरफ लीज दे दी और एक तरफ मंदिर है। आपका नापने का तरीका ऐसा है, वह लम्बाई तो सही बैठ रही है लेकिन वह पहाड़ वही हैं जिस पहाड़ के लिए मैं कह रही हूं, जो सेवल मंदिर से लगता हुआ है तो एक तो मेरी इस बात को आप नोट करें।

दूसरा, आपने मुझसे कहा है कि कलक्टर की उसमें कमेटी बन सके। यह हो सकता है तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि आज मैंने आपका ध्यानाकर्षण किया है तो इसमें कलेक्टर साहब की कोई कमेटी बनाकर, एसडीएम साहब या जैसा भी आप उचित समझें, उनकी कमेटी बनाकर इसकी जांच करा दें। एक तो इसकी लम्बाई की बात है। अगर एक ही पहाड़ है लेकिन लम्बाई है तो उसकी भी जांच हो जाये और जो धार्मिक आधार पर मैंने आपको निवेदन किया है, उसकी भी जांच हो जाये, और दोनों जांचों की रिपोर्ट आ जाये और ये लीज यहां कैंसिल हो, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को मैं आश्वस्त करता हूं कि नापने के नियम बने हुए हैं। उसकी जो नाप है, वह हम पुन: करा देंगे। अगर माननीय सदस्या किसी भी प्रतिनिधि को उस नाप के अंदर शामिल कराना चाहेंगी तो उनको भी उसमें शामिल कर देंगे और जिला कलेक्टर को हम फारवर्ड कर देंगे और जो जिला कलेक्टर की रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर हम आगे कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती अनीता (नगर): धन्यवाद जी।

श्री उपाध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्रीमती कामिनी जिन्दल, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

आदर्श ग्राम पंचायत होने के बावजूद ग्राम पंचायत 9 एमएल लट्ठावाली में निर्धारित मापदण्डानुसार काम नहीं होना

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर की आदर्श पंचायत 9 एमएल लट्ठावाली में निर्धारित मापदण्ड अनुसार कार्य नहीं होने के संबंध में माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करती हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने गंगानगर निर्वाचन क्षेत्र में 9 एमएल लट्ठावाली चयन आदर्श ग्राम पंचायत योजना में निर्धारित मापदण्ड से काम नहीं होने के लिए ध्यान आकर्षित किया है नियम 131 में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत में आदर्श ग्राम पंचायत बने, माडल ग्राम पंचायत बने, इस उद्देश्य को लेकर यह योजना प्रारम्भ की गई थी जिसमें बुनियादी सुविधाएं हों, मानव संसाधन का पूरा विकास हो और सारी सार्वजनिक सेवाएं सुदृढ़ हों। माननीय सदस्या ने 22.04.2015 को गांव 9 एमएल लट्ठावाली को मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में चयनित किया और इसमें विभिन्न योजनाओं के अंदर, मैं निवेदन करूं, यह जो मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान है, इसके तहत इस 9 एमएल लट्ठावाली के अंदर 14 कार्य स्वीकृत किये गये और उसमें 12 कार्यों की स्वीकृति जारी हो चुकी है, बाकी की डीपीआर बनी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परिसम्पत्ति निर्माण निधि के अन्तर्गत 12.01.2016 को तीन इंटरलॉक की सड़कें मंजूर की गई थीं और वहां रिकार्ड के अंदर मुझे बताया गया कि वे तीनों कार्य प्रगति पर हैं। मैं सोच रहा हूं कि निश्चित तौर पर सवा साल से नरेगा का काम प्रगति पर हो, किन्तु यह चिंताजनक बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नरेगा के अंदर 2015-16 में 18 कार्य स्वीकृत हुए, पाँच कार्य पूर्ण हुए, 13 कार्य अब भी प्रगतिरत हैं। 2016-17 में 9 कार्य स्वीकृत हुए और मुझे जो रिपोर्ट दी गई है, उसके अनुसार एक भी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

काम अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। प्रधान मंत्री आवास योजना के अंदर 9 एमएल लट्ठावाली में 14 लाभार्थी थे, 10 का जियो टेकिंग किया गया पर एफटीओ एक का भी जारी नहीं किया गया और विधायक विकास कोष से जो काम स्वीकृत किये गये हैं, उनमें से सात कार्य माननीया विधायक ने अनुशंसित किये और सातों की स्वीकृति निकलीं। दो काम प्रगतिरत है, दो काम प्रारम्भ नहीं हुए और तीन काम पूर्ण हो गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा तो माननीया विधायक ने जो अनुशंसा की थी, एक काम था इनका, डिग्गी से ओमप्रकाश के घर होते हुए लाभसिंह के घर तक एक सड़क इन्होंने स्वीकृत की। 20.06.2016 को जिला परिषद, गंगानगर ने इसकी तकनीकी स्वीकृति जारी की और 20.01.2017 यानी छह महीने बाद विधायिका महोदया की अनुशंसा के विरुद्ध, जो कार्य की स्वीकृति इन्होंने की थी, उसकी जगह बदलकर पंचायत समिति ने स्वीकृति जारी की। ये सारी बात जब संज्ञान में आई तो निश्चित रूप में इसमें हमको कमी-खामी लगी। हमने ग्राम सेवक को निलम्बित किया है और बीडीओ को हमने 16 सीसीए का नोटिस दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को आश्वस्त करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी चिंता हुई। मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत जिसका चयन आपने किया, अगर उसके काम के अंदर इतनी शिथिलता है तो निश्चित तौर पर इसमें गुणावगुण के आधार पर हम उत्तरदायित्व का निर्धारण करेंगे और सख्त से सख्त आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो जवाब विभाग द्वारा मंत्रीजी को उपलब्ध कराया गया है और मंत्रीजी ने जो इसे प्रस्तुत किया है, उससे मैं असंतुष्ट तो हूं ही, और मंत्रीजी ने जैसा अपने वक्तव्य में कहा कि वह भी इसके लिए विचार कर रहे हैं और वास्तव में आप सजग जन प्रतिनिधि हैं और मुझे खुशी है कि आपने इस बात को गम्भीरता से लिया है।

मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना अपने आपमें ग्रामीण विकास के लिए ऐतिहासिक कदम है लेकिन आदर्श पंचायतों का अगर यह हाल है,

(श्रीमती कामिनी जिन्दल)

अधिकारियों ने अगर इस पंचायत के साथ यह किया है तो मुझे लगता है कि जितनी भी योजनाएं हैं, उनके ऊपर हमें पुन: मोनेटरिंग करने की जरूरत है और आज सारे प्रयास इस पंचायत के अंदर सब मिट्टी हो चुके हैं। केवल अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, चाहे वह एमएलए लेड के काम हों, चाहे तीन इंटरलाकिंग सड़कों के काम हों। आप देखें, डेढ़ साल से वे नहीं बनी हैं। डेढ़ साल में तो फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाते हैं। 700-800 फीट की सड़कें तैयार नहीं हुई हैं। अगर हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन की, तो उसके अंदर भी मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगने के बाद लाभार्थियों को उसका पैसा उपलब्ध हुआ है। इस तरह के काम इसमें हो रहे हैं। मैं तो यह कहूंगी कि इसके अंदर अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही करने की जरूरत है। आज अधिकारियों के लिए कहना तो नहीं चाहूंगी, पर आराम का और भ्रष्टाचार का सांप काट चुका है और उनका यह जहर हमें भी खतम कर रहा है और आज जनता को भी उसका लाभ नहीं मिल रहा है, वह भी खतम हो रहे हैं।

इस पंचायत के अंदर जो फाइलें हैं, वह फुटबाल की तरह जिला परिषद से लेकर पंचायत समिति में घुमाई जाती है और जब भी जवाब मांगा जाता है, सिर्फ एक ही रटा-रटाया जवाब है कि कार्य प्रगति पर है। अभी मंत्रीजी ने भी बताया, उनके जवाब में यह आया है कि डेढ़ साल से कार्य प्रगति पर है तो ऐसी कौनसी बीरबल की खिचड़ी हो गई तो पूरी ही नहीं हो रही है। जरूरत है इसकी जांच करने की। जब हम इस तरह की मोनेटरिंग कर रहे हैं या इतनी कल्याणकारी आदर्श ग्राम योजना है, अगर इसमें काम नहीं हो रहे हैं तो इसकी मोनेटरिंग करें और इसमें जो दोषी पाया जाये, उसके ऊपर कार्यवाही की जाये और, इसकी जांच भी करेंगे, यही मैं मांग करती हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने मेरे उत्तर में कहा, निश्चित तौर पर जब इस प्रकार के प्रस्ताव आते हैं और सारी तथ्यात्मक जानकारी मिलती है तो जहां कहीं भी गलती-कमी होगी, उसमें कार्यवाही करते हैं। मैं सदन में घोषणा कर रहा हूं कि मैं इस विकास अधिकारी को एपीओ भी कर रहा हूं और एपीओ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के साथ-साथ 16 सीसीए का आरोप-पत्र भी उनको जारी कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्रीमती अनिता कटारा।

याचिका

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्न दो याचिकाओं का उपस्थापन करती हूं:-

धरियावाद पाटिया मोड़ से वाया गलिया कोट मोड़ एवं चीखली स्टेट हाइवे सड़क का निर्माण

(1) विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के धरियावाद पाटिया मोड़ से वाया गलिया कोट मोड़ एवं चीखली पीठ स्टेट हाइवे सड़क का निर्माण करवाये जाने बाबत।

सिलोही गलियाकोट एवं नीलकंठ महादेव मंदिर पर पुलिया निर्माण

(2) विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा की ग्राम पंचायत सिलोही गलियाकोट एवं पंचायत समिति नीलकंठ महादेव मंदिर पर पुलिया निर्माण करवाये जाने बाबत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नरेन्द्र कुमार। श्री नरेन्द्र कुमार (अनुपस्थित) श्री शंकर लाल शर्मा।

लवाण (दौसा) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार लवाण पंचायत समिति मुख्यालय (जिला दौसा) पर राजकीय महाविद्यालय खुलवाये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-18, अनुदान की मांग संख्या-24, श्री वासुदेव देवनानी।

अनुदान की मांग

शिक्षा, कला एवं संस्कृति - मांग संख्या 24 की प्रस्तुति

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 232,72,20,77,000/- (रुपये दौ सौ बत्तीस अरब बहत्तर करोड़ बीस लाख सत्तहतर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 24 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

व्यवस्था

माननीय सदस्य जो चर्चा में भाग लेते हैं, उत्तर के समय उनका उपस्थित रहना आवश्यक

श्री उपाध्यक्ष: मुझे सदन को यह सूचित करना है, जैसे पहले भी आसन से निर्देश दिया जा चुका है, जो सदस्य आज की इस मांग पर अपना विवेचन प्रस्तुत करेंगे, मंत्री के उत्तर के समय अगर वो अनुपस्थित रहे तो आसन दुबारा इस प्रकार की किसी भी गतिविधियों में आपको इजाजत नहीं देगा। कल सत्ता पक्ष के पाँच सदस्य नहीं थे। कुछ सदस्य थे तो बहुत लेट आये और प्रतिपक्ष के भी दो सदस्य नहीं थे। नाम अंकित कर लिये गये हैं। अगर इस पर सुधार नहीं हुआ तो आसन बाध्य होगा कठोर रवैया अपनाने को।

मंत्रीगण के अतिरिक्त अन्य सदस्य अधिकारी दीर्घा में जाकर बात नहीं कर सकते

आसन यह भी निवेदन करता है कि समय-समय पर यह देखा गया है, अफसरों की गैलरी पर सिर्फ मंत्रिमंडल के सदस्य अफसर से वार्तालाप कर सकते हैं, अन्य सदस्यों को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह नियम के विरुद्ध है। कई बार देखा गया है कि माननीय सदस्य भी अफसरों की गैलरी में जाकर वार्तालाप करते हैं। कृपया इसको ध्यान में रखें और ऐसा न करें।

(श्री उपाध्यक्ष)

अब तक सत्ता पक्ष के सदस्य शुरू कर रहे थे। शिक्षा का मामला है प्रशिक्षित हो जाएं इसलिए प्रतिपक्ष को निवेदन करते हैं। श्री गोविन्द सिंह जी।

अनुदान की मांग

शिक्षा, कला एवं संस्कृति - मांग संख्या 24 पर विचार

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर मैं अपनी बात रख रहा हूं। आपने अनुमति दी, धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस सदन में 22 जुलाई, 2014 को शिक्षा मंत्री के रूप में कालीचरण जी सराफ साहब का, माननीय सदस्य का भाषण सुना। हमने 20.03.2015 को माननीय शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव जी देवनानी साहब का भी उद्‌बोधन सुना। हमें 17 मार्च, 2016 को भी माननीय राज्य मंत्री वासुदेव जी देवनानी साहब का उद्‌बोधन सुनने को मिला। इन दोनों मंत्रियों के तीनों जो भाषण हुए हैं, यहां पर मांग के ऊपर जो जवाब हुआ है अपने विषय के ऊपर उसको मैंने ध्यान से पढ़ा। इतनी शानदार स्पीच। एकदम धारा प्रवाह और ऐसा लगा था हमें कि हो सकता है कि हमसे कहीं चूक हुई थी और अच्छा है प्रदेश के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनको अच्छी शिक्षा मिलने का काम होगा और सवा तीन साल से हम उम्मीद लगाये बैठे थे, टकटकी लगाये बैठे थे कि हमारे वो विद्‌यार्थी जो अध्यापकों के अभाव में अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे, उनको आप भर्ती करके और समुचित व्यापक अध्यापकों की संख्या आप उपलब्ध करायेंगे। हम उम्मीद करते थे कि आदर्श विद्‌यालय आप जो बनाने जा रहे हैं, उनमें समस्त स्टाफ और भौतिक सुविधाएं और संसाधन आप जुटा करके राजस्थान के जो विद्‌यार्थी, गरीब का बच्चा पढ़ने आता है उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी। हम उम्मीद करते थे कि हमारी जो बच्चियां स्कूल में जाती हैं उनके लिए शौचालयों की व्यवस्था नहीं होती थी। हमारे बच्चों को बैठने के लिए कक्षा-कक्ष नहीं होते थे। आप उन पर और ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करके, इस शिक्षा के ढांचे में सुधार करने का काम करेंगे। आप आरटीई के माध्यम से, जो हमारी अनिवार्य शिक्षा का कानून हमारी भारत सरकार ने

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

लागू किया था, उसमें भी कई तब्दीलियां करने की आपने बात की थी, लेकिन हम पर आरोप पर आरोप उस वक्त लगाये गये थे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आपने अध्यापकों की भर्ती नहीं की, आपने कोर्टों में अटका दिया। आपने विद्यार्थी मित्रों को बहकाने का काम किया। इनको नहीं लिया। आपने शिक्षा सहायक, विद्यालय सहायक पता नहीं क्या-क्या पदनाम दे दिये। और जो उन कांट्रेक्ट वालों को 10,15,20 बोनस अंक मिलने चाहिए थे, उसमें भी आपने गड़बड़ियां की। मैं पूछना चाह रहा हूं आपके माध्यम से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जब अपना जवाब दें तो बताने का कष्ट करें कि आपने कितने थर्ड ग्रेड के अध्यापक आज तक भर्ती कर दिये? आपने विद्यालय सहायक या शिक्षा सहायक जो 34-35 हजार का था, वो कितने भर्ती करने का काम कर दिया? मैं पूछना चाहता हूं आपने 26 हजार विद्यार्थी मित्रों को कहां एडजस्ट किया? आपने पहले भाषण में कहा था कि अस्सी हजार पद टीचर ग्रेड थर्ड के खाली हैं हम भरने का काम करेंगे। जब दूसरा वर्ष आया तो आपने कहा कि 55 हजार टीचरों के पद खाली हैं, हम एकीकरण कर रहे हैं, हम इन अध्यापकों की भर्ती करेंगे और जब तीसरी बार आये 2016 में तो आपने कहा कि पैंतीस हजार ग्रेड थर्ड के टीचर भरने का काम करेंगे। 2012 में जो टीचर्स हमने भर्ती किये थे वो मुद्दा भी आप निपटा नहीं पाये, उनमें से साठ हजार टीचर्स जो योग्य हैं, जो क्वालिफाई कर गये, आदेश हो गये, उनको भी आप नियुक्ति नहीं दे रहे हो। 2013 का प्रकरण आप निपटा नहीं पाये। विद्यार्थी मित्रों का प्रकरण आप निपटा नहीं पाये। एक काम जरूर किया कि प्रारंभिक-मिडिल स्कूल तक आपने विषय जरूर बांट दिये। अच्छी बात है, बांटने चाहिए। एकीकरण किया उसमें एक बात ठीक की कि मंत्री जी की भी नहीं चलेगी, विधायक की भी नहीं चलेगी। जो काउन्सिलिंग होगी, वह मैरिट के आधार पर होगी। हम मानते हैं यह अच्छी बात है। हमारा भी पिण्ड छूटा और किसी के साथ अन्याय भी नहीं हुआ। राजनीतिक भेदभाव भी नहीं हुआ, यह अच्छी बात है, लेकिन क्या वह कर पाये आप? जो आदर्श विद्यालय बना करके आप जिस तरीके की व्यवस्थाएं करना चाह रहे थे। जब सर्वशिक्षा अभियान आया, 60:40 का रेशो केन्द्र सरकार ने कर दिया उसके बाद में एक नयी योजना ले आये। आप

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जन सहभागिता की ले आये कि चालीस परसेंट जन सहभागिता होगी तो साठ परसेंट राज्य सरकार आपको पैसा देगी वो पैसा जो शायद केन्द्र सरकार का है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने एक कैडर नया बनाने का काम किया कि जिस पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय होगा, आदर्श विद्यालय होगा, उसका प्रिंसिपल होगा, वो ही उनको पेमेंट देने का काम करेगा, वो ही मोनिटरिंग करेगा। मैं समझता हूं कि उसको जो पढ़ाना होता है वह कब पढ़ायेगा? यह व्यवस्था कैसे बैठेगी? वो मोनिटरिंग किस प्रकार से करेगा? अपने विद्यालय की मोनिटरिंग करेगा या पंचायत में जो 5-7 विद्यालय हैं उनकी मॉनिटरिंग करेगा? उनके टीचर्स की मॉनिटरिंग करेगा? आपने कहा कि 30 की संख्या से कम हैं, उन विद्यालयों का हम एकीकरण करने जा रहे हैं। अच्छी बात है आपने किया होगा, लेकिन आपने उसके साथ-साथ में इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा कि हमारा जो केन्द्र का कानून है, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो हमें देता है उसके अनुसार आज ऐसे-ऐसे भी गांव हैं जहां 5-5 किलोमीटर तक बच्चों को पढ़ने की सुविधा नहीं मिल रही है। मेरे यहां मैं एक एग्जाम्पल दूंगा कि ग्राम पंचायत मुख्यालय कुमासजाटान, उसमें सैकण्डरी विद्यालय चल रहा था, आपने बंद कर दिया। आज वहां प्राइमरी विद्यालय भी नहीं है। ठीक है, आप एकीकरण कीजिये, कुछ भी कीजिये, लेकिन आप बीस हजार स्कूलें बंद कर चुके। उन स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं है, वो भवन कोई काम में नहीं आ रहे हैं। जिनका एकीकरण करके जो सरप्लस हुए थे अध्यापक, उनको एडजस्ट करने का तो काम किया, लेकिन इसके साथ-साथ एक गलती आपने की है। एक त्रुटि हमारे बेरोजगारों के साथ में हुई है, आपने धोखा किया है, वो पद समाप्त हो जाएंगे, माननीय मंत्री महोदय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी इन्होंने एक आदेश निकाला है कि शिक्षा विभाग में 6120 पद समाप्त किये जाते हैं। भर्ती तो कुछ करते नहीं, समाप्त करने की बातें कर रहे हैं। समाप्त करने के आदेश निकाल रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आरटीई के माध्यम से ढ़ाई लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को, गरीब के बच्चों को पढ़ाने का जो अधिकार हमारी सरकार के

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

समय था। आपने यहां खड़े होकर कहा था कि केवल हम बीपीएल को पढ़ायेंगे। हम सबको नहीं पढ़ा सकते। पहले ढाई लाख तक ओबीसी का विद्यार्थी, एससी/एसटी, जिसकी ढाई लाख वार्षिक इन्कम थी, उसको हमने अधिकार आरटीई के माध्यम से, केन्द्र के कानून के माध्यम से दे रखा था। आपने उस कानून का गलत इन्टरप्रिटेशन किया और गलत इन्टरप्रिटेशन करके सदन को गुमराह करने का काम किया। वो हाईकोर्ट में चेलेंज हुआ और हाईकोर्ट में जाकर आपको मुंह की खानी पड़ी। आपने वहां भी गरीब के बच्चे के साथ इन्साफ करने की नहीं ठानी। आप फिर सुप्रीम कोर्ट में गये। मैं समझता हूं कि शायद सुप्रीम कोर्ट में भी, मैं जहां तक सही हूं, आपको मुंह की खानी पड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ कर कहा कि इस वर्ष तो हमारे साथ लिहाज कर दो इस वर्ष हम नहीं कर पाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आज केवल पैंतीस हजार विद्यार्थी रह गये। कहां ढ़ाई-तीन लाख बच्चों को जो अनिवार्य शिक्षा कानून आरटीई के माध्यम से, जो प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा, गरीब का बच्चा भी पढ़े, इस बात को लेकर के केन्द्र सरकार ने कानून बनाया, हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। वह आपने कहीं भी नहीं किया है। केवल स्कूलें बंद करने से कुछ नहीं होगा। आप कहां भर्ती कर रहे हो? कहां है आपके टीचर? रीट, टेट, नाम बदल देंगे, बदल दिया, कुछ भी बदल दो लेकिन आप हमारे बेरोजगारों को नौकरी तो दो। आप उन विद्यार्थी मित्रों को रोजाना लट्ठ पड़वा रहे हो, उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हो। अब एक नया फार्मूला ला रहे हैं कि ग्राम पंचायत सहायक के रूप में उनको ग्राम सेवक नियुक्ति देगा। क्या लीगल सैंक्टिटी है, कहां आरक्षण है, कहां उसको बोनस अंक का प्रावधान है? संविदा के कर्मचारियों को जो बोनस अंक हमारी सरकार ने दिये थे सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को वैध ठहरा दिया तो आप किस तरह की व्यवस्था करने जा रहे हो? क्यों उनके साथ छल करने का काम कर रहे हो? यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

(14.00 बजे)

पैराटीचर और शिक्षा सहायकों के 600 रुपये बढाये, अच्छी बात है लेकिन क्या तीन साल बाद में 600 रुपये ही बढने चाहिये थे? 200 रुपये के

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)
हिसाब से साल के 10 परसेंट बढ़ाने की बात थी, आपने वह भी बढाने का काम नहीं किया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं विज्ञान विषय खोलने की बात थी, नहीं खोल रहे हैं। उर्दू के आपने पद ही समाप्त कर दिये। हमारा 36 कौमों का प्रदेश है, साम्प्रदायिक सौहार्द की मिसाल है हमारा प्रदेश। वहां पर हमारा हिन्दू भाई भी पढे, मुस्लिम भी पढे, पंजाबी भी पढे, सिख भी पढ़े, सबको पढ़ने का अधिकार है। आपने तो उर्दू के पद ही समाप्त कर दिये। मदरसा बोर्ड के माध्यम से, शिक्षा सहायक जो बार्डों में थे, उनकी 10 हजार के लगभग भर्तियों के लिए हमने मई-जून, जुलाई, 2013 में वेकेंसी निकाली थी। एक भी पद पर नियुक्ति देने का काम नहीं किया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं निजी विद्यालयों में फीस का कानून हम लेकर आये थे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले बजट में हमने पारित किया था। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि निजी विद्यालयों की फीस पर नियंत्रण का जो कानून हमने पारित किया था, क्या वह लागू हो गया? दूसरा बजट सत्र आ गया है। पहले में आपने पारित किया, आज तक लागू नहीं हुआ। अभी दस-बीस दिन पहले लगाया, अब यह कमेटियां बनेंगी नहीं, अगले साल से यह नियम लागू होगा, प्रभावी होगा, इस वर्ष तक नहीं हो पाया। आपकी मंशा ठीक नहीं थी।

आज आप एकीकरण के नाम से विद्यालयों को बंद तो कर रहे हो लेकिन जिस बालिका शिक्षा पर सबका जोर रहता है, हमारी बच्ची पढ़कर शिक्षित बने, क्योंकि बेटा एक घर को शिक्षित करता है, बेटी दो घरों को शिक्षित करती है। आप एकीकरण के माध्यम से, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो बालिका विद्यालय पहले से संचालित हो रही थीं, उनको भी मर्ज करके, एकीकरण करके बंद करने की शुरूआत कर दी है, इससे बड़ा अन्याय मैं समझता हूं कोई हो नहीं सकता। बालिका विद्यालय में ढ़ाई सौ, तीन सौ के लगभग हमारी बेटियां पढ़ने का काम कर रही हैं, उन विद्यालयों को भी आप एकीकरण के नाम से बंद करने जा रहे हो।

दूसरा, कंप्यूटर शिक्षा देंगे, अच्छी बात है दीजिए। आपने विभिन्न एजेंसियों से, विभिन्न प्राइवेट लोगों से एमओयू किये। कर लीजिए, हम कब

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)
मना कर रहे हैं लेकिन उस एमओयू के बाद में कंप्यूटर सिखाने के लिये आरकेसीएल से आपने जो एमओयू किया उसके तहत् कक्षा 1 से लेकर 6 तक 960 रुपये बच्चों से लेंगे। उससे आगे 1300 रुपये के लगभग लेंगे। जिस बच्चे के पास पढ़ने के लिये फीस नहीं है उस बच्चे से आप कंप्यूटर के नाम से पैसे ले रहे हो। आप करने क्या जा रहे हो?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काउंसलिंग के माध्यम से दिखवाना पडेगा। मंत्री महोदय, आप इस बात को एंश्योर कीजिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, देवयानी जी कहूं या देवनानी जी कहूं। ...(व्यवधान)... बोल रहा हूं, लेकिन इनको पता नहीं, फिर जवाब क्या देंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। कई ऐसे विद्यालय हो गये जिसमें आपने मर्जी आये जहां अंग्रेजी का विषय रख दिया, मनमर्जी आये वहां गणित का विषय रख दिया। कोई एकरूपता तो रखते कम से कम। जिसको जहां रखना था, वह रखने के लिये उस विषय के पद को ही समाप्त कर दिया। जहां नहीं रखना था, चाहे जैसा कर दिया। कई लोग तो वहीं एडजस्ट हो गये, कइयों को दूसरे ब्लाकों में जाने का आपने अधिकार दे दिया। जो आपकी व्यवस्था रही, उसमें जो खामियां थी उस पर भी आपको गौर करना चाहिये। क्योंकि आपने सबको शिक्षित करने का संकल्प लेकर यहां पर उद्बोधन दिया था। मैं समझता हूं कि आप उसमें ठीक करने का काम करेंगे।

माननीय मंत्री महोदय, प्रिंसिपलों को आप अधिकार दे रहे हैं। 5-5, 7-7 डीईओ कार्यालय को समाप्त कर रहे हैं, मैं समझता हूं इससे व्यवस्थाएं और ज्यादा बिगडेंगी, व्यवस्थाएं सुधरने की बात नहीं होगी।

तीसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपने यहां खडे होकर कहा था, कालीचरण जी सराफ साहब ने भी कहा था, आपने कहा था कि मिड डे मील को और ज्यादा और सुदृढ बनायेंगे। गरीब के बच्चे को जो भोजन हम देते हैं, जो पैसा हमारी सरकारों का लगता है, हमारी जनता का पैसा लगता है, अच्छा भोजन मिलना चाहिये। क्या हुआ कल परसों सवाई माधोपुर में? हमारे विद्यालय में हमारे गरीब बच्चे जो पढने आते थे उनके साथ कुत्ते भोजन

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

कर रहे थे। यह व्यवस्था आपकी बन रही है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। यह सवाई माधोपुर जिले की घटना है। सब पेपर्स में भी आया था, आपको भी ध्यान होगा। क्या किया आपने, कहीं कोई जांच कराई हो तो आप बता दीजिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, स्वच्छ भारत बनाइए, बहुत अच्छी बात है, हमारा भारत स्वच्छ होना चाहिये। लेकिन इन विद्यालयों को किस प्रकार से आप स्वच्छ रखना चाह रहे हैं। आपके पास चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं वे 10 परसेंट विद्यालयों में नहीं है। शौचालय नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। पीने का पानी नहीं है तो शौचालय में काम में आने वाला पानी कहां से होगा। बच्चे बाहर पेडों के नीचे बैठते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास अगर कोई सबसे ज्यादा आते हैं तो वे कहते हैं साहब कमरा बना दो। सवा दो लाख में 56 लाख में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जल स्वावलंबन में चेप दिया। 20 परसेंट हमारी मजबूरी है कि हमें कानून के हिसाब से एससी, एसटी को देना पडेगा। उनका अधिकार है, संविधान में प्राप्त अधिकार है, वह हमें देना पडेगा। अब जनरल का कोटा हमारे पास बचा कितना और कमरे में जनरल का लगता है। आप रोजाना चिट्ठियां दे रहे हो, कमरे बना दो, कमरे में सहयोग कीजिए। तीन साल से आप क्या कर रहे हो, यह तो बताओ। कहां गये आपके कमरे, कहां गये आपके शौचालय, कहां गई आपकी अध्यापकों की भर्ती? कुछ भी नहीं। आपने किस-किससे एमओयू किये, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिये अगर आपने एमओयू किया तो कहां किया, उस बात को देखना पडेगा।

मैं एक बात और निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय, बीएलओ के रूप में आपका शिक्षक कार्य कर रहा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। उस बीएलओ को अभी एक टार्गेट दिया गया युवा पंजीयन महोत्सव के नाम से, उनका नाम जोड़िये। 6 परसेंट का टार्गेट दिया गया। टीचर्स को यह कहा जा रहा है कि आप 6 परसेंट युवाओं के नाम जोड़िए। आपको कोई आधार कार्ड देखने की जरूरत नहीं, कोई मार्कशीट देखने की जरूरत नहीं। एक षड्यंत्र मैं समझ रहा हूं, राजनीतिक दुराग्रह से उनको टार्गेट दिया जा रहा है कि 6 परसेंट नाम चाहे आप फर्जी जोड़िये। अगर कोई टीचर नहीं जोड़ेगा उसको

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

नोटिस देकर उनकी तनख्वाह रोकी जायेगी, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। मैं नोटिस लेकर आया हूं। मेरे यहां कल-परसों टीचर्स को दिया गया है कि आपने 6 परसेंट का लक्ष्य पूरा नहीं किया। युवा पंजीयन महोत्सव, 2017 में लापरवाही बरतने के लिये आपको नोटिस दिया जाता है और उसमें यह लिखा है कि आपको जो लक्ष्य आवंटित किया गया था, वह लक्ष्य पूरा नहीं किया। इसलिए क्यों नहीं आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये? मैं निवेदन करना चाहता हूं उस टीचर का क्या दोष है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फर्जी नाम कहां से जोड़ देगा वह? किसी गांव में मान लीजिए 1000 वोट हैं तो वह 6 परसेंट के हिसाब से उसको 60 नाम जोडने पडेंगे। आप बताइए, कहां से जोड़ देगा वह 60 नाम? जब है नहीं तो कहां से जोड़ देगा? उसको आप नोटिस देने का काम करवा रहे हो। मैं समझता हूं यह आपका एक राजनीतिक दुराग्रह है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं बहुत चीजें जो आपने अपने भाषणों में कही थीं, वह एक भी पूरा होने का नाम नहीं ले रही है। अनुदानित शिक्षकों का कोर्ट से फैसला हो गया फिर भी आप उनको पैसा नहीं दे रहे हो। जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद भी सरकार वेरिफिकेशन ऑफ डाक्यूमेंट ऑफ एम्प्लोईज का बहाना बनाकर समय निकाल रही है। वेरिफिकेशन तीन-चार बार हो गया, उसके बावजूद भी सरकार 15 दिसम्बर, 2016 को कर्मचारियों के पेमेंट करके इसका एफिडेविट कोर्ट में पेश करना था। एक दिन पहले 14 दिसम्बर, 2016 को सभी अनुदानित कर्मचारियों को वार्निंग लैटर जारी कर दिए गए। आप बताइये, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कह दे, उसके बाद में अगर आप उनको वार्निंग लैटर दो, और उनका पैसा नहीं दो तो कहां से होगा?

तीसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उच्च शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि 2012 में हमने विश्वविद्यालय खोले। उन विश्वविद्यालयों में तकरीबन 53-53 पद, चाहे सीकर का दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय हो, चाहे भरतपुर का विश्वविद्यालय हो। उन सबमें हमने 2012 में पद स्वीकृत किये। आप बिल लेकर आए और केवल नाम

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

चेंज किया। लेकिन आज की तारीख में, सवा तीन साल बाद में भी उन विश्वविद्‌यालयों में एक भी कर्मचारी, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर को आपने नियुक्त करने का काम नहीं किया है।

अभी नियामक आयोग की बात थी। प्राइवेज निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए नियामक आयोग के लिए यहां पर कहा था। क्या आपने नियामक आयोग का गठन कर दिया? आपने कहा कि जल्दी ही कर देंगे। लॉ डिपार्टमेंट में गया हुआ है। जब काली चरण जी सराफ, उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब की बात है। आज तक कुछ नहीं हुआ। जिन निजी विश्वविद्‌यालयों के खिलाफ आपके पास शिकायतें आईं। पहले जब सराफ साहब थे तो कोठारी कमेटी बनाई। उसका क्या हुआ? वह कमेटी कहां गई? उसकी क्या रिपोर्ट आई, आज तक यह पता नहीं। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने घोषणा की है कि हम जांच करवा रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगी, आपकी रिपोर्ट इस सदन में आए और हमारे प्रदेश के युवाओं एवं विद्‌यार्थियों के साथ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के मालिक शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन हो। यह हम चाहते हैं। क्योंकि यह हम सब का दायित्व है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के जो बच्चे हैं, चाहे वे माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, चाहे उच्च शिक्षा में पढ़ रहे हों, उनको ज्यादा से ज्यादा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। केंद्र से आपके पास पैसा आ रहा है। आपसे लग नहीं रहा है। आपने यहां पर घोषणा की थी कि 248 उपखंड हैं जहां पर सरकारी महाविद्‌यालय नहीं है। आपने खोले नहीं। हमने जो महाविद्‌यालय खोले थे, उनको भी आपने समीक्षा के नाम पर बंद कर दिया। पत्रकारिता विश्वविद्‌यालय को भी आपने बंद कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि इस शिक्षा को कहां ले जाना चाहते हैं? केवल मात्र वहां बैठने से, उसी विषय के ऊपर दूसरे व्याख्यान होते हैं और इधर बैठने के बाद दूसरे व्याख्यान होते हैं। इससे हमारी सबकी प्रतिष्ठा को धक्का लगता है।

चूंकि हम सत्ता पक्ष में हैं, इसलिए हमें यह बोलना पड़ेगा। हम विपक्ष में हैं, इसलिए हमें विरोध करना पड़ेगा। विरोध करने वाली चीज का विरोध होना चाहिए। जो चीज अच्छी हो सकती है, उसको अच्छा करना चाहिए और अच्छा बताना चाहिए, तभी जाकर जनता का विश्वास हम सब पर टिकेगा।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

इसलिए आप जो भर्ती नहीं कर पाए, उन भर्तियों को जल्दी करने का काम करें। आपने वादे किए थे कि आदर्श विद्यालय ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर खोल देंगे। आप अभी तक नहीं खोल पाए।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपकी सरकार के पास डेढ़ साल का समय है। उसमें आपको करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 163 का बहुमत है और उसके बाद छोटा-सा विपक्ष है। जब थोड़ा बहुत मौका मिलता है। यह बात आपके कान में नहीं डलती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इन सब चीजों को देखना पड़ेगा।

एक और आपने किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक या दो मिनट लूंगा। स्थानान्तरण के लिए आपने अपने विधायकों से डिजायर ले ली। कोई बात नहीं। ले ली, यह अच्छी बात है। आपको करना चाहिए था। आप जब सुराज संकल्प यात्रा में गए थे, उस वक्त मुख्य मंत्रीजी ने जगह-जगह यह कहा था कि हमारी बहन, बेटी और बेटे, जो कि प्रतिबंधित जिलों में रहते हैं, उनका हम स्थानान्तरण करेंगे। आपने डिजायर ले ली और यह एक धंधा चल गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन वे डिजायर चली गईं। ट्रांसफर खुले नहीं। अब उनमें क्या हो रहा है? कहां घालमेल हो रही है? सारे लड़के जो कि टीचर्स हैं, बोलते हैं कि साहब को सैटिंग है तो बता दो। किस बात की सैटिंग? सैटिंग से ट्रांसफर थोड़े ही होते हैं। साहब हमें डिजायर दिए छह महीने हो गए हैं, फिर हमारा ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है? आपको मेरा यह निवेदन है कि आप जैसे ईमानदार आदमी पर यदि अंगुली उठेगी तो मैं समझता हूं कि हम सबकी बदनामी होगी, पूरे सदन की बदनामी होगी। इसलिए ऐसे नाम लेकर उसके बाद आप घालमेल का अवसर प्रदान कर रहे हो। यह हमारे सब के लिए अच्छा नहीं है और न ही उन टीचर्स के लिए अच्छा है।

इसलिए अंत में, उच्च शिक्षा मंत्रीजी मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा, कॉलेजों में व्याख्याताओं की लगभग 1180 भर्ती की बात कालीचरण जी सर्राफ किया करते थे, आज तक नहीं हुई है। यू.जी.सी. द्वारा सलेक्शन हो गया। जो मापदंड है, वह क्वालीफाई कर रहा है। एक राइडर लगा दिया कि उसका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा करके ग्रामीण परिवेश के

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

बच्चे को, किसान के बच्चे को दूर करने का काम कर रहे हैं। यह आज बर्दाश्त होगा, न कल। आप किसान की जय-जयकार करके कि किसान के लिए यह कर देंगे, उसको मालामाल कर देंगे, उनके बेटों की नौकरियां लगा देंगे, यह कहकर सत्ता में आ गए और आज जब मौका मिला तो अंग्रेजी माध्यम के शहर के बच्चे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हैं, उनको एडजस्ट करने के लिए यह किया है। उन ग्रामीण परिवेश के बच्चों के ऊपर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, आप यह पहले ही लगा देते कि साहब यह व्यवस्था रहेगी। अगर सलेक्शन हो गया। आर.पी.एस.सी. ने एग्जाम ले ली और वह सलेक्ट हो गया। उसके बाद किस प्रकार का गुड एकेडमिक रिकॉर्ड? यह आप क्या रहे हो? यह तब हुआ करता था जब प्राइवेट पढ़ाते थे, तो उनका एकेडमिक रिकॉर्ड देखते थे कि ठीक है, इनका अच्छा है। आज यू.जी.सी. जो क्वालिफिकेशन निर्धारित करती है, उसके मापदंड के हिसाब से जो व्यक्ति आर.पी.एस.सी. में सलेक्ट हुआ है, उसके ऊपर राइडर नहीं लगाने का काम करें।

अनिवार्य शिक्षा कानून हैं, उसके मुताबिक, यह वाउचर वाली सब नकली बातें हैं। न तो कोई वाउचर देता है और न बच्चे आते हैं। आप यह बात कहोगे कि हमारा नामांकन बढ़ गया। आपने बगैर टी.सी. के ही एडमिशन देने का प्रावधान कर दिया। बेचारे प्राइवेट वाले हैं। वे कह रहे हैं कि साहब बिना टी.सी. ले रहे हैं। हमारी तो फीस बर्बाद हो गई है। सब सिस्टम खतम हो गया, तो दोनों को देखना पड़ेगा। निजी विद्यालयों का भी सहयोग प्रदेश में शिक्षा के विकास में कम नहीं है। उनको भी कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि सरकार के सीमित संसाधन हैं। उसके द्वारा सारी व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती। माननीय मंत्री महोदय, आज अगर निजी विद्यालय बंद हो जाए तो त्राहिमाम - त्राहिमाम हो जाए। महाप्रलय हो जाए, इसलिए उनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और सरकार की सुविधाओं को भी आपको ठीक करना पड़ेगा।

इसलिए मैं अंत में इतना ही निवेदन करूंगा और उपाध्यक्ष महोदय से आज्ञा चाहूंगा। आपकी आज्ञा को टाल नहीं सकता। मैं आपसे पहले भी इजाजत ले चुका। मुझे शाम को मंत्री महोदय का उद्बोधन सुनने को नहीं

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मिलेगा, क्योंकि आपकी अनुमति और हमारे नेता जी की अनुमति से मेरे को दिल्ली जाना पड़ेगा। मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। आप इस मामले में मुझे माफ करेंगे।

आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): रुको भई।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो आक्षेप लगाए हैं, उनका जवाब तो इनको....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मुझे पता है, वही उत्तर दोगे। तीन साल से ढाक के तीन पात, कुछ भी उत्तर नहीं आएगा। कोई भर्ती की घोषणा करो तो जल्दी से बता दो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समानता के व्यवहार के लिए आप तो पूरे हाउस में मशहूर हैं। जब आप हम पर कार्यवाही के निर्देश जारी कर सकते हैं, तो समान व्यवहार होना चाहिए। डोटासराजी ने जितने भी प्रवचन दिए हैं, उनको विलोपित करने के निर्देश कृपया प्रदान कर दीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अनुमति का प्रावधान है। अनुमति ले रहा हूं। अनुमति देंगे तो ही जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आसन ने व्यवस्था दे रखी है कि कोई भी माननीय सदस्य अपना वक्तव्य देने के बाद..

श्री उपाध्यक्ष: विशेष परिस्थितियों में किसी भी सदस्य को आसन की अनुमति से जाने की इजाजत मिल सकती है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आप हमारे खिलाफ कार्यवाही करते हैं तो कम-से-कम आज यह भी ऐतिहासिक निर्णय करके दिखा दो, आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: डॉ. फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्षजी, शिक्षा, कला और संस्कृति की मांग संख्या - 24 पर विचार-विमर्श चल रहा है। अभी विपक्ष के माननीय सदस्य ने कुछ आरोप-प्रत्यारोप किए हैं। मैं उनके जाने से

(डा. फूलचन्द भिण्डा)
पहले यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान में शिक्षा के लिए अगर किसी ने ईमानदारी से काम किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चाहे भैरोसिंहजी सरकार थी, चाहे यह वर्तमान माननीय वसुन्धराजी की सरकार है और उसके बारे में मैं व्यक्तिगत तौर पर भी बता दूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, शिक्षा एक ऐसा चर है जो समाज द्वारा व्यक्ति को दिया जाता है और वह ट्रांसफरेबल नहीं है। शिक्षा व्यक्ति को ही प्राप्त होती है, देता समाज है। चाहे वह सरकार दे, चाहे प्राइवेट दे, चाहे गवर्नमेंट दे, लेकिन समाज देता है। इस कारण से हमारी व्यवस्था में गुरु ऋण की व्यवस्था की गई थी। पितृ ऋण, मातृ ऋण के बाद गुरु ऋण की व्यवस्था की गई थी। ऐसे विषय पर आज हम डिबेट कर रहे है।

हमारे विवेकानन्द जी ने शिक्षा पर बोलते हुए एक बार कहा कि मनुष्य के अंदर जो अंतर्निहित गुण है, उनको प्रकट करने का अगर कोई काम करता है तो वह शिक्षा है।

(14.20 बजे)

(श्री ज्ञानचंद पारख, सभापति, पदासीन)

शिक्षा इस हेतु दी जाती है कि व्यक्ति में जो अंतर्निहित गुण हैं उनको प्रकट किया जाए, समाज के लिए उपयोगी बनाया जाए, राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाया जाए, परिवार उपयोगी बनाया जाए। इसका दूसरा अर्थ है कि जीवन का निर्माण, मानव निर्माण, चरित्र निर्माण और विचारों के सामंजस्य का निर्माण व्यवस्था में हो। इसके लिए शिक्षा की बात की जाती है।

विवेकानन्द जी ने आगे यह भी कहा कि बालक को शिक्षा तब प्राप्त होगी, जब उसके दिमाग में संकेन्द्रन होगा। संकेन्द्रन का दूसरा अर्थ होता, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और आस्था होगी, तब शिक्षा ग्रहण करने में उसको आसानी होगी। आगे भी कहा है, बालक का संकेन्द्रन शिक्षक में तब होगा, जब शिक्षक गुणवान होगा। इस आधार पर हमें वर्तमान युग में शिक्षा का मूल्यांकरण करने की आवश्यकता है।

हमारे विपक्षी और बीजेपी के खिलाफ जितने दल देश में है, शिक्षा में जब हम कोई चीज, भारतीय पद्धति के अनुसार, सांस्कारिक शिक्षा एक शब्द है

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

जिसको जोड़ते हैं तब शिक्षा परिपूर्ण होती है, उस पर बवेला मचा देते हैं, तुरंत कह देते हैं भगवाकरण हो गया। इसलिए मैं मजबूर होकर आज यह भगवा कुर्ता पहन कर आया हूं कि उनको दर्शन हो जाए कि भगवाकरण क्या है।

शिक्षा में संस्कार हो, सदाचार हो, यह हमारी पुरानी ख्याति है। यही कारण था कि सामाजिक संस्कार ग्रहण करने के लिए भगवान कृष्ण को भी सांदीपनि आश्रम में जाना पडा था। हमारे गरीब थे उनके साथ उनको लकड़ी बीननी पड़ती थी। सांदीपनि आश्रम में वह रहते थे। शिक्षा में आज गुणवत्ता नहीं है, संस्कार नहीं है, संस्कार शिक्षा नहीं है तो वह कोरी है। वह मनुष्य के लायक नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें कि शिक्षा में नैतिकता होना आवश्यक है। नैतिकता शिक्षा में संयोजित करने के लिए पाठ्यक्रमों का निर्माण, विद्यालय का वातावरण, समाज का वातावरण आवश्यक है। उसी अनुरूप जब हम विचार करते हैं दो शब्दों पर कि इस देश में अगर मानव निर्माण करना है, समाज को व्यवस्थित चलाना है, राष्ट्र को व्यवस्थित चलाना है, राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव पैदा करने वाला मनुष्य निर्माण करना है तो निश्चित तौर पर नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। नैतिक शिक्षा बिना आध्यात्मिकता के नहीं आ सकती है। कोई सोचे कि हम आध्यात्मिक तो रहेंगे तो नहीं, किसी को रहने नहीं देंगे, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शास्त्र पंथ निरपेक्ष को भी धर्मनिरपेक्ष करके हम कह देते हैं लेकिन बिना आध्यात्मिकता के नैतिकता नहीं हो सकती।

उस अदृश्य शक्ति को हमारे पूर्वजों ने पहचाना। इसी कारण कहा, व्यक्ति, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टी, यह चार अवयव मानकर हमने विचार किया। इस कारण से हमें जगदगुरू कहा गया। वरना जगदगुरु, आज पाश्चात्य में तो केवल कहते हैं मैं और ग्रुप या समूह, ऐसा अमेरिका के लोग मानते हैं। इस कारण से उनके यहां संस्कार का विषय नहीं है। परिवार पद्धति का विषय नहीं है। परिवार संगठन का विषय नहीं है।

दूसरे शब्दों में, सदाचार और संस्कार क्यों चाहिए, तो ध्यान आता है व्यक्ति श्रेष्ठ चाहिए। व्यक्ति श्रेष्ठ क्यों चाहिए, परिवार की श्रेष्ठता के लिए व्यक्ति श्रेष्ठ चाहिए। परिवार श्रेष्ठ क्यों चाहिए, समाज व्यवस्थित रहे इसलिए परिवार श्रेष्ठ चाहिए। राष्ट्र समृद्ध हो, राष्ट्र व्यवस्थित हो, तो राष्ट्र

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

भक्ति चाहिए। इस कारण से जब विचार करते हैं तो व्यक्ति और परिवार की श्रेष्ठता के लिए सद्‌चरित्र आवश्यक है। सद्‌चरित्र शिक्षा से ही प्राप्त हो सकता है, परिवार के संस्कारों से ही प्राप्त हो सकता है। वह कहीं बाजार में नहीं मिलता है, ना ही उद्‌योग में पैदा होता है, ना ही खेत में पैदा होता है। यह शिक्षा परिवार से, क्योंकि परिवार को पहली पाठशाला कहा गया है, मां को पहला शिक्षक कहा गया है, इस कारण से परिवार और समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए सद्‌चरित्र व्यक्ति का होना आवश्यक है। जब ये तीनों चीजों हो जाती हैं, समाज, परिवार और व्यक्ति संस्कारित हो जाता है तो राष्ट्र अपने आप संस्कारित हो जाता है। माननीय सभापति जी, इस देश में होने वाले लोगों को 33 करोड़ देवी-देवता इसलिए ही कहा जाता था। धन के ताले नहीं लगते थे। सद्‌चरित्र के कारण से दुनिया हमारा लोहा मानती थी, इस कारण से यह आवश्यक है।

इन सब बातों के लिए राष्ट्र व्यक्तित्व या राष्ट्रभाव, इसकी स्थापना करना आवश्यक है। यह सतत प्रक्रिया है। कि केवल एक दिन भाषण करवा दें, टेलीविजन पर दे दें, इसके कारण से नहीं। बच्चा जन्म लेता है तब उसको मां सबसे पहले मामा, काका, पापा बोलना सिखाती है। वह उसे पहचानना सिखाती है कि किसके साथ क्या संबंध है। इस सतत प्रक्रिया में एक चीज आती है स्कूल में क्या पढ़ाया जाए, स्कूल में क्या किया जाए, कैसा वातावरण हो। हमारे विपक्ष के लोग यही तो प्रचार करते हैं कि पाठ्‌यक्रम बिगाड़ दिया, भगवाकरण कर दिया, यह कर दिया, वह कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, राष्ट्र भाव, समाज भाव पैदा करने के लिए क्या महापुरुष नहीं पढ़ाए जा सकते। भगवान राम को वनवास भेजने के लिए कैकेयी ने 100 परसेंट आरक्षण मांगा था लेकिन उस पद के जब ठोकर मारी, भरजी द्‌वाज, भरजी को हम पूजते है, ऐसे लोगों का चरित्र जब नहीं पढ़ाएंगे तो त्याग भावना कहां से आएगी, परिवार भावना कहां से आएगी, सहजता कहां से आएगी। पूर्वजों के स्वाभिमान को अगर नहीं करेंगे, कैसे-कैसे पूर्वज हमारे हुए हैं। राम कृष्ण से लेकर आज तक जितने महापुरुष हुए हैं उनके जीवन को नहीं पढ़ाएंगे तो प्रेरणा कहां से मिलेगी। महापुरुषों के चरित्र की प्रेरणा कहां से मिलेगी, संस्कार कहां से मिलेगे।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

कई बार कहते हैं कि सामाजिक समरसता होनी चाहिए। सामाजिक समरसता के लिए हमारे ज्योतिराव जी फूले हैं, डाक्टर अम्बेडकर हैं, वीर तेजाजी हैं। वीर तेजाजी एक प्राणी को वचन देकर गए और अपने जीव को बाहर निकालकर उसका पूरा किया, किसके लिए गए वह। हनुमान जी, किसकी पत्नी कौन ले गया, समुद्र में डूब सकते थे, सुरसा खा सकती थी, मत पढ़ाओ हनुमान जी को। मत पढ़ाओ, फिर कैसे स्वाभिमान पैदा होंगे।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब बातों के लिए महापुरुषों की जीवनी पढ़ाना आवश्यक है। राष्ट्र गौरव, राष्ट्र पर स्वाभिमान हो, इस पीढ़ी को स्वाभिमान हो। महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ाए, महाराजा सूरजमल को नहीं पढ़ाए, कीचल पुंजा को नहीं पढ़ाए, वीर सावरकर जी को नहीं पढ़ाए, पृथ्वीराज चौहान को नहीं पढ़ाए, सरदार भगत सिंह, सुखदेव को नहीं पढ़ाए, नेहरूजी को नहीं पढ़ाए, डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नहीं पढ़ाए, अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं पढ़ाए, सरदार पटेल को नहीं पढ़ाए, डा. अब्दुल कलाम को नहीं पढ़ाए, त्याग के लिए भर्तृहरि जी को नहीं पढ़ाए? आज तो हम कुर्सी के लिए सब कुछ हथकंडे अपनाते हैं, मैं इस सदन में कह रहा हूं। भर्तृहरि ने तो अपने गुरु से कहा उस गुरु गति का भी, दो दिन पहले ही मुख्य मंत्री बना है। गुरु गोरखनाथ जी को कहा कि मेरा मन नहीं मानता, गोरखनाथ जी ने क्या कहा, जाओ अपनी पत्नी को मां कहो, जो नहीं कहना चाहिए था, जो नहीं करना चाहिए वह किया तो त्याग भावना उत्पन्न हो गई। आज भर्तृहरि के त्याग की पराकाष्ठा हो गई। लेकिन भृतहरि की नीति शतक नही पढ़ा सकते आप, क्योंकि साम्प्रदायिक है, हिन्दुओं का राजा था। भगवान बुद्ध राजपाट छोड़कर गए, भगवान महावीर राजपाट छोड़कर गए, उनको नहीं पढ़ाए। पन्ना धाय को नहीं पढ़ाए, फिर क्या पढ़ाए? मीराबाई को नहीं पढ़ाए। चाणक्य को नहीं पढ़ाए, चन्द्रगुप्त को नहीं पढ़ाए, मोहम्मद शाह, ईसा मसीह को नहीं पढाए?

आज पूरी दुनिया बीमारियों से ग्रसित है। फिर हिन्दुत्व का पुनर्जागरण हो गया योग के नाम से। फिर योग गुरु रामदेव आएंगे ही, दीनदयाल जी आएंगे ही, वीर सावरकर आएंगे। जब भक्ति की बात करेंगे तो मीराबाई भी आएंगी। भगिनी निवेदिता भी आएगी। जब महिला वीरता की बात करेंगे तो

(डा. फूलचन्द भिण्डा)
लक्ष्मी बाई भी आएगी, महादेवी वर्मा भी आएगी। वैज्ञानिकों की बात करेंगे तो बाणभट्ट भी आएगा, महर्षि दधीचि भी आएगा।

मैं इस सरकार को धन्यवाद दूंगा, एकलव्य, क्या श्रेष्ठता प्राप्त की आस्था के आधार पर, श्रद्धा के आधार पर मूर्ति बनाकर भी श्रेष्ठ बन गया? अर्जुन से भी श्रेष्ठ बन गया, धुरुंधर, लेकिन यह कहा था, गुरु में गुण होना चाहिए। गुरु तो कलंकित हो गया अंगूठा कटवा लिया इसलिए। लेकिन एकलव्य के आधार पर आज हम पुरस्कार दे रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात मानता हूं। उनसे ही प्रेरणा मिलेगी।

महिलाओं को अधिकार नहीं, सारी दुनिया में अधिकार मिले हैं, 19वीं शताब्दी में वोटिंग राइट ही नहीं था। हमारे तो गार्गी जीको शासन करने का अधिकार मिला इसलिए गार्गी पुरस्कार देते हैं, हम मीरा पुरस्कार देते हैं। शिक्षा केवल आदर्श से नहीं चलेगी, उसकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी।

मैं वर्तमान सरकार को, माननीय मुख्य मंत्रीजी को, शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि शाला दर्पण और शाला दर्शन, सारी सूचनाएं एक साथ। समुदाय का उपयोग हो, समुदाय की अवधारणा और सहभागिता हो, अध्यापक-अभिभावक परिषद बन गई। एस.एम.सी., एस.डी.एम.सी. बन गई। फिर प्रेरणा के लिये पुरस्कार, प्रतिभा खोज के लिये पुरस्कार, विज्ञान खोज के लिये पुरस्कार। शिक्षक सम्मान और व्यवस्था के लिये, बच्चे कैसे जायें, साइकिल वितरण, बालिका छात्रावास, कस्तूरबा छात्रावास, शारदा विद्यालय, मॉडल स्कूल, ये व्यवस्था किये बिना व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती।

अब मैं आपके माध्यम से, कुछ आंकड़ों के माध्यम से प्रमाणित करने की कोशिश करूंगा। वे माननीय सदस्य चले गये। 1951 में हम पढ़े-लिखे लोग, साक्षर 24 प्रतिशत थे। लेकिन राजस्थान का औसत 14 प्रतिशत, यानी 10 प्रतिशत का अंतर था। आज सारे देश का औसत 80.89 है और हम 79.14 पर आ गये। दस प्रतिशत का अंतर था, डेढ प्रतिशत पर ले आये। लेकिन इस उपलब्धि में भी दो बार सत्ता का परिवर्तन हुआ। इस जनता का सौभाग्य जागा। कांग्रेस का परिवर्तन हो गया, 1977 में केवल ढाई साल रहे थे, लेकिन जो विकास दर थी, 33 प्रतिशत से सीधे 44 प्रतिशत पर राजस्थान में शिक्षा की दर चली गई, केवल ढाई साल में। क्योंकि तत्कालीन

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

शिक्षा मंत्री और मुख्य मंत्रीजी ने यह आर्डर निकाला, जिस गांव की आबादी तीन हजार है 1971 की जनगणना के अनुसार, उन सब में दसवीं के स्कूल खोले जाते हैं। अपने आप नामांकन बढ़ गया, अपने आप शिक्षा का स्तर बढ़ गया।

फिर उसके बाद में फिर 1990 में सरकार परिवर्तित हो गई। 1998 तक, आठ साल तक बी.जे.पी. की सरकार रही, माननीय भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री रहे। वर्तमान गृह मंत्रीजी उस समय शिक्षा मंत्री रहे। उस कार्यकाल में बिना भेदभाव के, क्योंकि भेदभाव का तो कांग्रेस का जिम्मा रहा है इस देश में। किसी को आवश्यकता ही नहीं थी औरों से भेदभाव करने की। पहली बार एक आदेश से सभी ग्राम पंचायतों में मिडिल स्कूल कर दी गई। उसमें भी जो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है बांसवाड़ा, उसको दोहरा लाभ हो गया। जब 1977 में सरकार बदली, तो विकास खण्डों की वृद्धि कर दी माननीय भैरोंसिंहजी ने। चार विकास खण्ड भारत सरकार से बढ़वा लिये। माननीय गुलाबजी ने क्या किया कि, हर पंचायत समिति में बारहवीं का एक स्कूल होगा। एक लड़कियों का होगा और एक लड़कों का होगा। इस कारण से वहां पाँच विधान सभाओं की जगह आठ थे, इसलिये 08 और 08, सोलह स्कूल खुल गये। पाँच साल तक खुल गये। आज बांसवाड़ा औसत के बराबर है। उसके नीचे तो 15-17 जिले और हैं, जिनका औसत कम है, एक निर्णय के कारण से। एक आदेश से सबको कहा कि सब जगह मिडिल स्कूल होगी। आठवीं तक आ गये हम।

जब वसुन्धराजी आ गयीं तो उन्होंने निर्णय किया 2007 में, प्रत्येक पंचायत में सीनियर सैकण्डरी स्कूल होगा। पहले मिडिल पहुंचाई प्रत्येक पंचायत में, फिर सैकण्डरी पहुंचाई। 3105 स्कूल एक साथ एक-एक स्कूल के लिये गिड़गिड़ाते हैं।

उसके बाद में थोड़े से बच गये थे, मजबूरी हो गई। इसके लिये मैं अशोकजी गहलोत को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 1900 स्कूल खोलकर उस कमी को पूरा किया।

सत्ता परिवर्तन के कारण से, आज फिर आ करके माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक साथ पाँच हजार स्कूल खोलकर, आजादी से लेकर, पहले

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

ग्यारहवीं के स्कूल होते थे, 1988 में 10+2 हो गये। तो पहले 4200 स्कूल थे, 2014 के पहले केवल 4200, जिसमें कोई तो आजादी के समय का था, कोई कब का था, कोई कब का था। एक साथ पाँच हजार स्कूल और बाद में 65, इसलिये 5065 स्कूल एक साथ खोल करके राजस्थान को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया। व्यवस्था के नाम पर, बच्चा कहां जाये, दूर-दूर गांव हैं, दूर-दूर ढाणियां हैं। लेकिन राजस्थान में शिक्षा को, यह गैप जो 10 प्रतिशत का था, उसको डेढ प्रतिशत पर ले आये। उसका कारण यही है कि हमने सामूहिक रूप से आवश्यकतानुसार ये निर्णय किये हैं। इन निर्णयों के कारण से ऐसी स्थिति बनी है। माध्यमिक विद्यालय, ऐसा नहीं है, माध्यमिक विद्यालय भी 241 हमने पिछले तीन साल में खोले हैं।

जहां तक नामांकन की स्थिति है, 2013-14 में 22 लाख बालक पढ़ते थे और 15 लाख बालिकाएं पढ़ती थीं। लेकिन हमारे अच्छे निर्णयों से बालकों का नामांकन 23.50 लाख हो गया, बालिकाओं का 17.44 हो गया। दो लाख 37 हजार बालिकाएं तीन साल में ज्यादा पढ़ने लग गयीं और सवा लाख के लगभग बालक बढ़ गये। जो बालिकाओं का रेशो बालकों के अनुपात में 40 प्रतिशत था, उसको हम 43 प्रतिशत तक ले आये। इनके गैप को भी हमने पाटा है।

अब मैं थोड़ा सा उच्च शिक्षा पर आता हूं। उच्च शिक्षा मेरा विषय भी रहा है। उच्च शिक्षा के बारे में भी आजादी के पहले से लेकर, भैरोंसिंहजी 1993 में जब तीसरी बार मुख्य मंत्री बने थे, तब उन्होंने एक निर्णय किया कि बालिका शिक्षा को, क्योंकि हमारा अंतिम स्थान था, उस समय भारत में 35वां स्थान था। तब उन्होंने निर्णय किया, चरणबद्ध तरीके से पाँच साल में हम प्रत्येक जिला हैड-क्वार्टर पर लड़कियों का कॉलेज खोलेंगे और उन्होंने दो को छोड़कर के खोले। क्योंकि वहां प्राइवेट कॉलेज थे सीकर और हनुमानगढ़ में बाकी सब जगह लड़कियों के कॉलेज खुले। उसकी स्थिति देखिये आप, सौ लड़कों पर 1990 से 1998 के बीच में सौ से कम लड़कियां पढ़ती थीं। आज हम इस स्थिति में आ गये उन कॉलेजों के कारण से, आज अगर सौ लड़के पढ़ते हैं तो सामान्य वर्ग की 120 लड़कियां पढ़ती हैं। लड़कों से लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं। एस.सी. वर्ग में 2005 में, जब हमारा शासन था, उस

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

समय हमने फिर इसमें चेंज किया, सौ लड़कों पर 33 लड़कियां पढ़ती थीं। अब 2016-17 में 85 हो गयीं। इतनी वृद्धि हमने की है। एस.टी. वर्ग में सौ पर 30 लड़कियां ही पढ़ती थीं, अब 97 लड़कियां पढ़ रही हैं। ओ.बी.सी. और एस.बी.सी. में सौ पर 49 लड़कियां पढ़ती थीं, अब सौ पर 98 लड़कियां पढ़ती हैं। ओवरऑल कहें तो पहले सौ पर 63 थीं, अब 106 हो गयी हैं। यह मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं।

पिछले पाँच वर्षों में कॉलेज में छात्र संख्या 2009 से 2013 तक, जब माननीय गहलोत साहब मुख्य मंत्री थे, केवल 60 हजार की वृद्धि हुई थी। अब तीन साल में ही ढाई गुना, डेढ लाख विद्यार्थी कॉलेजों में बढ़े हैं। लड़कियों की स्थिति भी यही है। उन पाँच सालों में 1.18 लाख, इन्होंने कॉलेज नहीं खोला, हमने खोले थे, उसका प्रभाव आ गया, इस कारण से 1.18 लाख लड़कियां पढ़ती थीं। अब इन तीन सालों में 1.18 लाख लड़कियों की संख्या बढ़ी है, नामांकन बढ़ा है।

लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में संस्थाओं के मामले में असंतुलन है। राजस्थान में भारत की तुलना में तो औसत से ज्यादा संस्थाएं हैं, अभी 49 हजार पर एक कॉलेज है, लेकिन हमारे 39,110 पर एक कॉलेज है। यह दिसम्बर, 2016 के आंकड़े हैं। लेकिन जयपुर में 23 हजार पर है, बीकानेर में 30 हजार पर है, भरतपुर में 40 हजार पर है। लेकिन जोधपुर, जहां से बार-बार कांग्रेस के मुख्य मंत्री रह रहे हैं, वहां 79 हजार पर एक कॉलेज है। उदयपुर फिर भी उससे 20 हजार कम है, 57 हजार पर एक कॉलेज है। कोटा, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, इस पर थोड़ा विशेष, हालांकि कॉलेज तीन-चार खोले हैं, अब एक साथ तीन-चार कॉलेज बढ़ाये हैं। कोटा 74 हजार पर है और अजमेर 54 हजार पर है। इस संतुलन को ठीक करने के लिए कुछ कॉलेज बढ़ाने की आवश्यकता है जो आठ कॉलेज खोले भी हैं, लगातार खोल रहे हैं। पहले आठ खोले, फिर आठ खोले, फिर बारह खोले, फिर आठ खोले हैं। तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि अभी बजट का अंतिम उत्तर देना है, उस समय तक और हमें मैडम का आशीर्वाद मिले।

उच्च शिक्षा के बारे में दो बातें जरूर मैं कहूंगा कि एक तो हमारा

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

बाड़मेर, जालौर, राजसमंद, माननीया मंत्रीजी कहां चली गईं? बूंदी, झालावाड़ और करौली, ये ऐसे जिले हैं जो हमारे प्रदेश के औसत जो 40 हजार है, उससे दुगने से भी ज्यादा का अंतर है, इस कारण से शिक्षा मंत्री और मुख्य मंत्रीजी, दोनों से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह करें।

इसके अलावा मैं मेरी विराटनगर की कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं। एक तो राजस्थान में पांडवों का अज्ञातवास मेरे यहां पर था और मत्स्य राज्य के जो राजा थे, राजा विराट, उनकी राजधानी विराटनगर थी। इस कारण राजस्थान धरोहर और संरक्षण प्रोन्नति प्राधिकरण के माध्यम से पौराणिक स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाए, एक तो यह निवेदन है।

मेरे यहां पर संस्कृत के चार वरिष्ठ उपाध्याय स्कूल हैं, एक कॉलेज होना चाहिए। संस्कृत विभाग में पूरे प्रदेश में काफी पद खाली हैं। संस्कृत के माननीय वह नहीं हैं लेकिन अध्यापकों के 2300, वरिष्ठ अध्यापकों के 1200, हैड-मास्टरों के 110, प्राध्यापकों के 456 और प्रिंसिपल्स के 111 पर खाली हैं। मेरे यहां पर चार, जिनकी संख्या 200 से ज्यादा, संस्कृत विद्यालय मिडल स्कूल हैं, जयसिंहपुरा, खेड़ा, आंतेला और बड़ नगर उनको प्रवेशिका बनाया जाए।

इसी प्रकार से नव-गठित पंचायतें जहां हैं, जहां पर सरकारी स्कूल भी नहीं हैं, 12वीं के और 10वीं के स्कूल भी वहां पर नहीं हैं। नई पंचायतें केरली, प्रेम नगर और वीर तेजाजी, इनकी क्रमोन्नति की जाए और इसी प्रकार से करोड़ी, पापड़ा और ढाणी गैसकान, यह दसवीं के विद्यालय हैं लेकिन प्राइवेट विद्यालय है, इनको 12वीं का किया जाए। ...(व्यवधान)... हां, बोल रहा हूं न। इसी प्रकार से जो सरकारी माध्यमिक विद्यालय हैं और जहां पर सरकारी विद्यालय है और बड़े गांव हैं, निश्चित तौर पर वहां गरीब लोग ज्यादा रहते हैं तो इस कारण से यह 40 का राइडर रहना नहीं चाहिए। अब तो थोड़े ही बचे हैं, लगभग एक हजार बचेंगे, उनको करना चाहिए। उनमें कुछ मिडल हैं और अगर उसकी आवश्यकता भी है तो 25 कर दें। राइडर की आवश्यकता है नहीं। वैसे हमारी मुख्य मंत्रीजी उदार हैं इस शिक्षा के मामले में। तीन हजार मिडल स्कूल, एक साथ सैकण्डरी स्कूल, भैरोंसिंहजी की 4600 स्कूल और अभी वसुन्धराजी ने 5 हजार स्कूलें, यह तो एक हजार स्कूलें हैं।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि यह राइडर खतम करके एक बार कर देना चाहिए। एक छलांग, यह कह सके, जब भारत सरकार कोई मीटिंग करे शिक्षा के बारे में, तो यह हमारे जैसे माननीय प्रभू लालजी ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में न बोलने वालों के लिए, चिकित्सा सुविधा होगी, ऐसे आप भी कह सकें कि हम सबके लिए यह शिक्षा, सैकण्डरी स्कूल होगी, ऐसा शान से कह सकें, इस प्रकार की आवश्यकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो-एक बातें और हैं, दो मिनट और लूंगा। इसी प्रकार से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय विराटनगर में नहीं है। माननीय, क्योंकि एस.बी.सी. बहुल मेरा इलाका है, इस कारण से इसकी आवश्यकता है। मॉडल स्कूल की आवश्यकता है।

एकीकरण से जो भवन खाली हुए हैं, उनके लिए प्री-प्राथमिक विद्यालय, जैसे गुजरात में है, दूसरी तक विद्यालय चलायें, एकल अध्यापक रहें, तो वह बिल्डिंग भी काम आएगी और जो छोटे बच्चे हैं, चार साल, पाँच साल, छह साल, सात साल के, वे दो साल तक पढ़कर फिर पास वाली एक-डेढ़ किलोमीटर की दूर जो स्कूलें हैं उनमें आ जाएंगे। इस कारण से यह प्री-प्राथमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए, जिससे उनका उपयोग होगा।

इसी प्रकार से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि बालिका शिक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए, सात हजार की आबादी पर जैसे भैरोंसिंहजी ने किया व तीन हजार की आबादी पर सैकण्डरी स्कूल, ऐसे ही सात हजार की आबादी पर लड़कियों के सैकण्डरी स्कूल खोल दिये जाएं तो महिला शिक्षा, जिस पर अभी भी हम 35वें नम्बर पर हैं, महिला शिक्षा में आखिरी पायदान पर है इसलिए उसको बढ़ाने का एक तरीका है कि सात हजार की आबादी वाले जितने भी गांव हैं, उनमें सबमें सैकण्डरी स्कूल खोल दी जाएं।

इसी प्रकार से विराटनगर और पावटा दो पंचायत समिति मेरे क्षेत्र में हैं लेकिन कॉलेज एक भी नहीं है। दोनों में खोला जाए। इस खंड में सरकारी आई.टी.आई. भी नहीं है सरकारी दोनों में, पावटा और विराटनगर में, वह भी खोलें।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

इसी प्रकार से चिमनपुरा कॉलेज है, जिसमें 35 साल से कृषि संकाय है। राजस्थान में पाँच सरकारी विश्वविद्यालय हैं। सरकारी कॉलेज नहीं है। उसमें पी.जी. कक्षाएं भी नहीं हैं लेकिन चिमनपुरा गांव में ही वहां कॉलेज के पास में 25 हैक्टेयर जमीन है, उसमें पी.जी. खोला जाए और कृषि महाविद्यालय अलग से खोला जाए। वहां पर पूरे शिक्षक हैं, केवल प्राचार्य को लगाना पड़ेगा।

इसी प्रकार से विधान सभा क्षेत्र में 335 पद खाली हैं तृतीय श्रेणी के, उनको भरा जाए और कक्षा-कक्षों की जो कमी है, उसको पूरा किया जाए।

मैं अंत में, इस वर्ष 11,651 करोड़ रुपये का जो बजट दिया गया है, लगभग सात परसेंट अब तक, पहले पाँच परसेंट था, साढ़े छह किया, सवा-छह, साढ़े-छह करके सात परसेंट किया। इसके लिए मैं, जो निरंतर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिस विचार से मैं आता हूं, उस विचार के लोग यह कहते हैं कि शिक्षा का बजट बढ़ना चाहिए। एक परसेंट के लगभग बढ़ा है दो साल में। इसका धन्यवाद देते हुए, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि यू.जी.सी. ने तीन साल पहले एक निर्देश भेजा था, जहां पर भी पाँच हजार विद्यार्थी रहते हैं। वहां विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन एक ही शर्त पूरी नहीं करता मेरा चिमनपुरा गांव। गांव है, वह चार शर्तें पूरी करता है, पूरी जमीन है विश्वविद्यालय के बराबर। चार फैकल्टी है, एग्रीकल्चर फैकल्टी है, बी.एड. है, कॉमर्स है, विज्ञान है और कला है, पाँच फैकल्टी हैं। वे तो चार फैकल्टी ही मानते हैं इसलिए चिमनपुरा को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, ऐसा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बाबू सिंह।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-24 में मैं अपने आपको शामिल कर रहा हूं।

शिक्षा किसी देश और प्रदेश की विकास की प्रगति की द्योतक है और मेरुदंड है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकरजी ने भी कहा था कि शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जो सभी समस्याओं का समाधान और निराकरण है। शिक्षा नीति ही संस्कारवान व अच्छे नागरिक बनाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी राजस्थान की सरकार ने और राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी

(श्री बाबू सिंह)

वसुन्धराजी ने और शिक्षा मंत्रीजी ने एक ऐसी शानदार टीम बनाई। टीम बनाकर, चाहे पानी हो, बिजली हो, सड़कें हो, चिकित्सा हो, उनमें कितना ही काम कर लें, लेकिन शिक्षा के बगैर हम अधूरे हैं और इस ओर काम करने का पहली बार बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके काम किया और आज जिस प्रकार से राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में इसकी प्रशंसा हो रही है और दूसरे प्रदेशों के लोग भी और सरकारें भी राजस्थान के मॉडल को देखना चाहती है कि राजस्थान में शिक्षा का मॉडल किस प्रकार से हो रहा है और उसको हमारे प्रदेशों में भी अपनाया जाए। ऐसी सोच विकसित हुई है।

हमारे सामने चुनौती है, देश की एकता, अखंडता और अस्मिता बनाये रखने की। लार्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली और लार्ड मैकाले ने यह कहा था कि जब मैं हिंदुस्तान गया और हिंदुस्तान में देखा कि हिंदुस्तान में धन-धान्य, वैभव, नैतिक मूल्य संस्कारित बहुत क्षमतावान लोग हैं और किसी देश की हस्ती को मिटाना हो तो उसकी विरासत में, जैसे हिंदुस्तान की विरासत में संस्कृति और सभ्यता, आध्यात्मिकता विरासत में मिली है, उसके इतिहास को मिटा दो तो वह देश आगे बढ़ने से रुकेगा, वह विकसित नहीं होगा। वास्तव में आज हम लोग देख रहे हैं कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली में हमारी संस्कृति थी, संस्कृति की शिक्षा थी। उस समय गुरुकुल हुआ करते थे, यज्ञोपवीत भी होते थे और बचपन के अंदर जो संस्कार मिलते थे। उन्हीं संस्कारों से चरित्र का निर्माण होता था, व्यक्ति का निर्माण होता था और वह जीवन में कामयाब होता था। आज जब पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव देखने को मिल रहा है और खास तौर से हम हमारे विश्वविद्यालयों को देखते हैं तो विश्वविद्यालयों के अंदर वास्तव में जहर उगल रहे हैं, लोग जहर पी रहे हैं। आप सब देख रहे होंगे कि दिल्ली के विश्वविद्यालय में, और भी कई विश्वविद्यालयों में ऐसे प्रकरण सामने आए कि वहां स्मैक हो रहा है, हेरोइन हो रही है, शराब हो रही है, चरस हो रही है, लोग नशे कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ऐसा वातावरण बन रहा है। यह इस कारण हो रहा है कि बचपन की जो प्रारंभिक शिक्षा है, वह शिक्षा उनको सही ढंग से नहीं मिलने के कारण यह हो रहा है। तो इन सबको रोकने की जरूरत है। हमारे देश के प्रधान

(श्री बाबू सिंह)

मंत्रीजी ने यह कहा कि अब शिक्षा मैन मैकिंग के साथ-साथ मनी मैकिंग भी बनायी जानी चाहिये और इस ओर काम करना चाहिये। शहरों में भी हम देख रहे हैं, अखबारों में भी पढ़ने को मिला है और कई बार ऐसे प्रकरण आये हैं, जो अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें हैं, वहां पर कोल्ड ड्रिंक के अंदर शराब मिलाकर ले जाते हैं और बच्चों को उसको चखाया जाता है।

इसके साथ-साथ, जहां पर विद्यालय हैं उनके पास में ऐसी नशे की दुकानें हैं, वहां शराब भी मिलती है, सिगरेट भी मिलती है, गुटखे भी मिलते हैं तो वह सारी चीजें क्यों मिलती हैं, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है और साथ ही उस ओर बच्चे भी आकर्षित नहीं हो। शहरों में भी इस प्रकार के प्रकरण बढ़े हैं। बच्चे जब अपने घर से साथ में मोबाइल लेकर जाते हैं तो मोबाइल के कुछ दुष्परिणाम सामने आये हैं तो स्कूलों के अंदर मोबाइल ले जाने पर रोक लगनी चाहिये। हम देख रहे हैं कि शहरों में बालवाहिनी है। बालवाहिनी घर के बाहर आती है और स्कूल के गेट के आगे ले-जाकर छोड़ती है जिससे बच्चों में शारीरिक विकास नहीं हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे शिक्षा मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को, खास तौर से अब शिक्षा पाठ्यक्रम में योगाभ्यास और सूर्य नमस्कार शामिल किये हैं, क्योंकि बचपन में हम विद्यालय में पढ़ते थे तो चार किलोमीटर पैदल चलकर जाते थे और कभी-कभी देरी होती थी तो दौड़कर जाते थे जिससे शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत रहता था और आजकल कहते हैं कि मोर्निंग वॉक, वह उस समय बच्चों में स्वत: हो जाती थी। आज इसका अभाव है। इसके लिये यह योगाभ्यास और सूर्य नमस्कार विद्यालयों में नितान्त आवश्यक है, जिसकी शुरूआत की है, इसके लिये मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

वास्तव में गांवों के अंदर प्रकृति की गोद में खेलकर कई प्रतिभाएं हैं जिनको आगे आना चाहिये। प्रारम्भिक शिक्षा में हमको सुधार करने की जरूरत है और प्रारम्भिक शिक्षा में गांवों में सुधार नहीं होने के कारण गांव के लोग पलायन करके शहर जाते हैं, शहर से दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और दूसरे प्रदेशों से विदेशों में पढ़ाई करने के लिये जाते हैं, तो ऐसी मजबूत शिक्षा प्रणाली लाई जाये और इस प्रकार का शिक्षा का वातावरण बने कि जो गांव छोड़कर विदेश गये, विदेश छोड़कर पुन: प्रदेश में आये हैं और प्रदेश से

(श्री बाबू सिंह)

शहर में आये हैं और शहर छोड़कर वापस गांव आ जाएं, इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली हमारे यहां होनी चाहिये और इस ओर काम हो रहा है।

वास्तव में यह पहली बार हुआ, हमारे पूर्व वक्ता जब कह रहे थे, यह सही बात है कि पहली बार राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री रहे आदरणीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने नई पंचायतें बनायीं और नई पंचायतें बनाकर, उन पंचायत मुख्यालयों पर भी और दूसरे जो पंचायत मुख्यालय वंचित थे, उन सारे मुख्यालयों पर आठवीं तक की स्कूलें पहली बार खोली। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी तो एक ही आदेश के अंदर आदरणीय वसुन्धरा जी ने 3, 108 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर माध्यमिक विद्यालय कर दीं। कुछ पंचायत मुख्यालयों पर माध्यमिक विद्यालय नहीं रहे तो पिछली कांग्रेस की सरकार में जरूर हुई, लेकिन इस बार जब फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी तो एक ही आदेश के अंदर बारहवीं तक की शिक्षा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मिले, इसलिये पांच हजार स्कूलें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हो गयी और पहली बार यह कहते हुए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि सभी पंचायत मुख्यालयों पर एक आदर्श विद्यालय बनेगा। मैं तो कह रहा हूं कि प्यासा कुए के पास जाता है, कुआ कभी प्यासे के पास नहीं आता। जहां गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी, निश्चित रूप से दूरदराज से भी बच्चे पढ़ने के लिये वहां जाएंगे, लेकिन जहां गुणवत्ता की शिक्षा नहीं होगी, वह नजदीक स्कूल होगा तो वहां पर भी पढ़ने नहीं जाएंगे। ऐसी शिक्षा के लिये पहली बार, जहां पर नामांकन कम था, उनको भी और जो नजदीक विद्यालय थे, उनका भी एकीकरण करके एक विद्यालय के अंदर नर्सरी से लगाकर बारहवीं तक की शिक्षा और वहां पर भौतिक सुविधाएं हों और सारे रिक्त पद भरकर वहां शानदार और गुणवत्ता की शिक्षा मिले, यह पहल की है और इस पहल के साथ-साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि वास्तव में पहली बार ये पंचायत मुख्यालयों पर काम हुए हैं। जब बारहवीं तक की स्कूल होगी और बारहवीं तक की स्कूल के साथ-साथ हमारे जो ब्लॉक है, जो हमारे पंचायत समिति मुख्यालय हैं, वहां पर शारदा छात्रावास पहली बार खोले गये हैं तो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पर शेखाला पंचायत समिति मुख्यालय है, वहां शारदा

(श्री बाबू सिंह)

छात्रावास नहीं है। वहां भी ऐसा शारदा छात्रावास बन जाएगा तो बारहवीं के बाद बच्चियां वहां शारदा छात्रावास में रहकर, जो दूसरे प्राइवेट विद्यालय हैं या राजकीय महाविद्यालय हैं, वहां शिक्षा अर्जन करेंगे। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास पंचायत मुख्यालय पर बने, वे भी शानदार चल रहे हैं।

इसके साथ-साथ स्वामी विवेकानन्द आदर्श मॉडल स्कूल बने हैं, वहां भी सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाई हो रही है और वे भी शानदार बने हैं। हम चाहेंगे कि इस प्रकार से आप बारहवीं तक और बारहवीं के बाद में छात्रावास खोलकर उनको शिक्षा दे रहे हैं तो पंचायत मुख्यालयों पर राजकीय महाविद्यालय जरूर बनायें।

अब कौशल विकास में आप सब जगह आई.टी.आई. दे रहे हैं तो हमारे यहां भी शेरगढ़ में और शेखाला में आई.टी.आई. पहली बार सैंक्शन हुआ है, इसके लिये मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं और पिछली बार जब सरकार थी, उस समय बालेसर में आई.टी.आई. बनाकर आपने शिलान्यास और उद्घाटन दोनों किये। इस प्रकार से आई.टी.आई. बनेंगे तो कौशल विकास भी होगा।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें और खेल के मैदान बनें। खेल मैदान में भी अब 50-50 लाख रुपये नरेगा में मिल रहे हैं। मैं शिक्षा मंत्रीजी से चाहूंगा, अपने स्कूलों के अंदर भूमि आबंटन के लिये नोर्म्स बने हुए हैं और नोर्म्स में जैसे बारहवीं स्कूल है तो उसको साढ़े 16 बीघा जमीन, दसवीं के लिये भी है, आठवीं के लिये भी है, पांचवीं के लिये भी है, लेकिन गांवों में आज भी स्कूलें ओरण, गोचर और आगोर में बनी हुई हैं। एक बीघे में बनी हुई है, दो बीघे में बनी हुई है तो क्यों नहीं आप पूरी सूचियां बनायें। हमारे स्कूल के नाम से, किन स्कूलों के नाम से पट्टे हैं या नहीं हैं या नोर्म्स के हिसाब से उनके पास भूमियां हैं कि नहीं हैं, तो वह भूमि आबंटन के लिये आपको विशेष निर्देश देने चाहिये कि नोर्म्स के अंदर जितनी भूमियां हैं, आज तो आपको भूमि मिल जाएगी, लेकिन आने वाले समय में भूमि का संकट आ जाएगा तो यह अभी अपने को व्यवस्था करने की जरूरत है, यह काम भी आप करें।

(श्री बाबू सिंह)

आप शहीदों के नाम से स्कूल भी बनाएं। आज कितना शानदार शिक्षा का वातावरण बना है। राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं से कितना शानदार वातावरण गांवों में देखने के लिये मिलता है। जब से यह बारहवीं की स्कूलें खुली हैं और सारे शिक्षकों के पद भरे गये हैं तो वहां पर साढ़े 17 लाख नामांकन बढ़े हैं और खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि हमारी बहन-बेटियां और ये जो बच्चियां हैं, उनका नामांकन सबसे ज्यादा है। कई स्कूलें ऐसी हैं जहां पर बच्चों से भी ज्यादा बच्चियों की संख्या बढ़ी हैं। वे स्कूटी लेकर, साइकिल लेकर और गीत गाते हुए अपने स्कूल पहुंचती हैं। इतना शानदार वातावरण है। साइकिल का पहली बार समय पर वितरण हो रहा है। लैपटॉप बंटे हैं, ट्रांसपोर्ट वाउचर हुए हैं और 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' यह अभियान हमारे आदरणीय प्रधान मंत्रीजी का है और मुख्य मंत्रीजी ने भी इस ओर विशेष ध्यान देते हुए 'मुख्य मंत्री हमारी बेटी योजना', 'आपकी बेटी योजना', 'मुख्य मंत्री राजश्री योजना', 'इंदिरा प्रियदर्शिनी प्रोत्साहन', 'गौरव सेनानी पुत्रियों को प्रोत्साहन', 'बालिका प्रोत्साहन योजना' इस प्रकार से योजना चलाकर इतना शानदार काम किया है।

आप दो योजनाएं और लेकर आये हैं। एक तो आदर्श विद्यालय, वह तो उच्च माध्यमिक विद्यालय होगा और उसके साथ-साथ आप एक पंचायत के अंदर एक आठवीं की स्कूल, वह उत्कृष्ट, ऐसे दो विद्यालय पंचायत मुख्यालय पर हो जाएंगे। एक मुख्यालय पर और एक मुख्यालय से अलग जगह पर, तो वहां पर सारे भौतिक संसाधन होंगे और अच्छी पढ़ाई होगी तो निश्चित रूप से कमजोर वर्ग के लोग, गरीब बच्चे वहां पढ़ सकेंगे और वह आगे बढ़ सकेंगे। यह पहली बार हुआ है,

अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपने क्या किया? वास्तव में आप देखिये कि यह पूरे हिन्दुस्तान में, इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतनी अधिक डी.पी.सी. कभी नहीं हुई। 87 हजार से अधिक पदोन्नति राजस्थान सरकार ने करके एक नया इतिहास बनाया है। मैं तो कह रहा हूं कि कई शिक्षकों को यह मन में ही नहीं था कि हमारी पदोन्नति होगी और लिस्ट में जब नाम आया तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा और मेरी पदोन्नति हुई है।

(श्री बाबू सिंह)

इसके अलावा 37 हजार 392 की सीधी भर्ती भी की है। यह पहली बार हुआ कि स्थानान्तरणों के लिये और पोस्टिंग लेने के लिये विधायकों के घरों पर भीड़ लगती थी और उसके लिये भी कई बार किसी का होता, किसी का नहीं होता तो यह भी हमें उलाहना सुनना पड़ता था, लेकिन पहली बार एक काउंसलिंग के माध्यम से स्कूलों के अंदर जो प्रमोशन किये, पदोन्नति की, उन सबको काउंसलिंग के माध्यम से, सामने बैठाकर बताया कि ये पोस्टें खाली हैं, आप इसमें से कहां जाना चाहते हैं? उन्होंने स्वेच्छा से कांउसलिंग ली और उनकी पोस्टिंग हो गयी। वे विधायक के पास नहीं आये। जिस प्रकार से आपने कांउसलिंग की है, जिस प्रकार से केन्द्र सरकार में स्थानान्तरण नीति है, गुजरात में भी स्थानान्तरण नीति है तो केन्द्र सरकार की स्थानान्तरण की नीति के अनुसार सभी विभागों में और खास तौर से शिक्षा विभाग में अगर काउंसलिंग की तरह ही शानदार स्थानान्तरण नीति आ जाए तो फिर विधायकों के पास कभी एक भी डिजायर लिखने की जरूरत नहीं रहेगी और शिक्षक को समय-समय पर ध्यान रहेगा कि हमें कहां जाना है और किस प्रकार से व्यवस्था करनी है। यह स्थानान्तरण नीति अपने को लाने की जरूरत है। इस ओर विशेष ध्यान देकर यह काम अपने को करने की जरूरत है।

साथ में ही हम चाहेंगे कि काम काफी हुए हैं और इनको और अच्छी मॉनिटरिंग करके काम करने की जरूरत है। जो काम करते हैं, उसी में कमियां निकालते हैं। जो विकास नहीं करते, काम नहीं करते, उनमें क्या कमियां निकालेंगे। व्यावसायिक शिक्षा दी है, कौशल विकास योजना लाये हैं, उपचारात्मक शिक्षा लाये है, लैपटॉप वितरण हो रहा है, साइकिल वितरण हो रही है, ट्रांसफर वाउचर योजना आयी है। अब तो हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वास्तव में शिक्षा में मैन मैकिंग के साथ मनी मैकिंग की एजुकेशन होनी चाहिये और इस ओर जो प्रधान मंत्रीजी की सोच है, राजस्थान सरकार ने उस ओर कदम बढ़ाये हैं। पहली बार हम देख रहे थे कि जब नामांकन होते थे, उस समय नामांकन बढ़ते थे। वह इसलिये बढ़ते थे कि फर्जी नामांकन होते थे और मिड-डे-मील का भ्रष्टाचार करने के लिये वे मिड-डे-मील में आते थे और ले जाते थे। जब

(श्री बाबू सिंह)

स्कूल की परीक्षा होती थी तब उसका मिलान होता था तो आधे बच्चे परीक्षा देने नहीं जाते थे। यह आंकड़ें कांग्रेस शासन के समय के हैं लेकिन पहली बार शाला दर्पण योजना लाये, शाला दर्शन योजना लाये और इन दोनों योजनाओं के माध्यम से अब बच्चों का रिकार्ड, शिक्षकों का रिकार्ड और स्कूल का रिकार्ड सारा ऑनलाइन है, सबके सामने है, जिससे यह कह सकते हैं कि पहले जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा होता था, उसके ऊपर अब रोक लगी है।

(15.00 बजे)

इसी के साथ-साथ राज ई-ज्ञान पोर्टल, छात्रवृत्ति पोर्टल, आर.टी.ई. पोर्टल, निजी स्कूल पोर्टल, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि अब आगे डिजिटल शिक्षा के लिए स्कूलों के अन्दर, जिस प्रकार से शहरों में स्कूलों के अन्दर है, वैसे ही गांवों में भी, जब हमारी प्रकृति में इतनी प्रतिभाएं हैं, उनको तराशने के लिए स्कूलों के अन्दर वाई-फाई दी जाए, ई-टीचिंग दी जाए, डिजिटल ऑनलाइन बोर्ड दिये जाएं, वीडियो कांफ्रेंस की जाए, डिजिटल पुस्तकालय दिया जाए, वहां इण्टरनेट की सुविधा दी जाए जिससे हमारे बच्चे भी गूगल पर सर्च कर सकें और सीधा इस प्रकार से डिजिटल से जुड़कर पूरे विश्व में क्या हो रहा है और किस प्रकार से हमको शिक्षित होना है, उस ऑनलाइन के माध्यम से उसको कुछ सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। यह भी काम हुआ है।

साथ-साथ में बालिकाओं का स्वयं सहायता प्रशिक्षण हो रहा है। अभी स्वच्छ भारत अभियान पर काफी चर्चा चली। स्कूलों में भी शौचालय हैं और साथ-साथ में सफाई की भी व्यवस्था की है। आपने प्रत्येक विद्यालय के अन्दर पांच हजार रुपये स्वच्छता अभियान में दिये हैं। अब यह राशि कम हैं। समय पर शौचालयों की अच्छी सफाई हो, अच्छे सुलभ कॉम्प्लेक्स बनें, इस राशि को बढ़ाकर भी स्वच्छता अभियान को ढंग से किया जाना चाहिए।

अब यह निर्माण कार्य, बार-बार शिक्षक आन्दोलन करते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि यह निर्माण कार्य शिक्षकों से हटाकर किसी स्वतंत्र कार्यकारी एजेंसी को दिया जाना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि रमसा के हैं या सर्वशिक्षा अभियान के कार्य हैं, हमारे सभी ब्लॉक के अन्दर पी.डब्ल्यू.डी. के

(श्री बाबू सिंह)

तीन ए.ईएन. हैं, उनके पास कम काम हैं। वो जो इंजीनियर हैं तो हम चाहेंगे कि पी.डब्ल्यू.डी. को दे दो या फिर कोई स्वयं सहायता संस्था या जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, उनको बिना टेण्डर के दस लाख रुपये के जो काम देते थे, उस योजना के अन्दर या कोई योजना बनाकर ये निर्माण कार्य जो शिक्षकों को दिया गया है, उसको नहीं दें। अब रमसा के अन्दर दो जिलों में एक ए.ईएन. है। अब पूरे विधान सभा क्षेत्र में, पूरे जिले के अन्दर तीन जे.ईएन. हैं तो वो कैसे गुणवत्ता का काम संभालेंगे। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

साथ ही आपने डिजिटल लिट्रेसी कार्यक्रम कराया है, लीडरशिप प्रशिक्षण कराया है, आई.सी.टी. लैब कार्यक्रम भी आप इसमें लेकर आये हैं तो यह सारा काम आपने किया है।

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक तो विद्यार्थी मित्रों की समस्या है। चुनाव से पहले विद्यार्थी मित्रों को कहा और उससे पहले भी जो हमारे पैराटीचर थे, उनको प्रबोधक बनाकर 40 हजार प्रबोधकों को नियमित किया था। विद्यार्थी मित्रों की भी समस्या है और विद्यार्थी मित्रों को नियमित करने के लिए हम एक अलग बना कर शिक्षा सहायक का लाये लेकिन कई बार याचिकाओं के माध्यम से, कोर्ट में अटकने की वजह से वो रुका हुआ है, तो उसको भी हम करेंगे और खास तौर से उसका निस्तारण हमको करना चाहिए।

अब दूर-दराज की ढाणियां हैं, उन ढाणियों के अन्दर हमारे स्कूल हैं। सबसे ज्यादा आंधियां चलती हैं, सबसे कम टैम्प्रेचर वहां रहता है, सबसे ज्यादा गर्मी का टैम्प्रेचर वहां रहता है तो ऐसी विषम परिस्थितियों में गांवों के अन्दर जो हमारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं चिकित्सा विभाग की तरह जो इन्सेन्टिव उनको दिया जाता है, हम भी गांवों के अन्दर शिक्षकों को, जो गांवों में पढ़ा रहे हैं उन शिक्षकों के लिए अलग से इन्सेन्टिव या ग्रामीण भत्ता अगर करेंगे तो वो बड़ी निष्ठा के साथ पढ़ाएंगे।

इसके साथ ही, अब उच्च शिक्षा में तो बहुत ध्यान दिया जा रहा है, उच्च माध्यमिक शिक्षा में भी अच्छा ध्यान दिया गया है लेकिन प्रारम्भिक शिक्षा में हालात और दयनीय हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि शेरगढ़ विधान सभा

(श्री बाबू सिंह)

क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि मेरे प्रारम्भिक शिक्षा में 1813 पद स्वीकृत हैं, उसमें 1144 कार्यरत हैं और 669 पद हमारे प्रारम्भिक शिक्षा में खाली हैं।

अब आगे भी आप देखेंगे, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि एकल अध्यापक वाले विद्यालय हैं। शेरगढ़ में 120 विद्यालय हैं जिनमें मात्र अकेले अध्यापक हैं। अब उनके घर में शादी हो या और कोई समारोह हो, अगर वो चले जाएं तो वो स्कूल बंद हो जाती है, ताला लग जाता है। ऐसी स्थिति में अभिभावक अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाने के लिए कैसे भेजेंगे? अपने बच्चों का भविष्य अंधकारमय कोई नहीं करना चाहता। उन विद्यालयों को संभालने की जरूरत है। कम से कम दो शिक्षक तो हर विद्यालय के अन्दर कम्पलसरी लगने चाहिए। एक शिक्षक वाले विद्यालय कम ही चलते हैं।

आप देखेंगे, हमारे यहां शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सत्य भारती की स्कूलें खुलीं। भारती फाउंडेशन ने खोली। जहां पर वो विद्यालय खुले, ऐसे 28 विद्यालय हैं और 28 विद्यालयों में 8 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं और वहां पर अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़ाया जा रहा है। जहां विद्यालय खुला, उसके अड़ौस-पड़ौस की जितनी अन्य स्कूलें थीं वो स्कूलें बंद हो गयीं और नामांकन वहां बढ़ गया। जहां गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी, निश्चित रूप से बच्चे वहां जायेंगे। इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।

इसके साथ आपने 75 विद्यालय बंद किये हैं मेरे यहां। वो बंद होने के कारण क्या रहे? या तो वहां ढंग से शिक्षक नहीं रहे और शिक्षक नहीं रहने के कारण वहां बच्चे नहीं गये या बच्चों का नामांकन नहीं होने के कारण से वो बंद हो गये। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, पहले भी हमारी सरकार ने यह कहा था कि शिक्षा के अन्दर पी.पी.पी. मॉडल लायेंगे। अब अगर यह पी.पी.पी. मॉडल आप इसमें लायें, हमारे यहां एस.टी.सी. के बच्चे हैं, बीएड के बच्चे हैं, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, अगर आप पी.पी.पी. मॉडल लाकर इसकी निविदा निकालेंगे कि इन विद्यालयों को कौन चलाएं, तो उस प्रकार से स्वयंसेवी संस्था बनाकर या इन बच्चों को अगर वो विद्यालय देंगे और वो मेहनत करेंगे तो आपको पता लग जायेगा कि वास्तव में जो स्कूल बंद हैं, ये बिलकुल अनुचित बंद

(श्री बाबू सिंह)

हुए हैं और अब जब इस मॉडल में दिया गया है, वो भी और मुझे बताएं कि पहले भी घोषणा हो चुकी है और आगे भी अपन शिक्षा के क्षेत्र में पी.पी.पी. मॉडल के माध्यम से गांवों में किस प्रकार से काम करेंगे।

साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि आर.टी.ई. के तहत 25 परसेंट तो गरीब बच्चों को मिलता है। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि जितने बी.पी.एल. और गरीब बच्चे हैं क्यों नहीं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को छात्रवृत्ति दे दें जिससे वो स्वैच्छिक तरीके से किसी प्राइवेट विद्यालय में या अच्छी स्कूल के अन्दर दाखिला लेकर अपना जीवन बना सके। इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।

साथ में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, जो प्रतिबंधित जिले हैं आठ जिले हैं, अब उनका ट्रांसफर एक जिले से दूसरे जिले में होता, हम आपसे मांग करेंगे, या तो प्रतिबंधित जिलों में ट्रांसफर किया जाए या फिर कोई स्वैच्छा से म्युचुअल ट्रांसफर कराना चाहे तो भी आपके कमी नहीं आयेगी और म्युचुअल ट्रांसफर में भी अगर छूट दे देंगे तो वर्षों से जो बाहर बैठे हैं, अब उनके वृद्ध माता-पिता हैं, पारिवारिक परेशानियां भी हैं तो उनको भी छूट मिल जायेगी तो कम से कम प्रतिबंधित जिलों में कोई म्युचुअल ट्रांसफर कराना चाहे या वो अगर आठ जिलों में ही ट्रांसफर कराना चाहे तो इनको भी विशेष तौर से छूट दें जिससे वो भी काम हो जाए।

एक, हम लोग देखते हैं कि शहरों के अन्दर प्राइवेट विद्यालय हैं, उन प्राइवेट विद्यालयों में अलग-अलग ड्रेस कोड है, अलग-अलग शानदार उनकी ड्रेसेज हैं लेकिन सरकारी विद्यालयों की ड्रेस तो लगता है कि ये राज रो स्कूल रो टाबर है, सरकारी स्कूल का बच्चा है। हम यह चाहेंगे कि यह प्राइवेट और सरकारी विद्यालय हैं। राजस्थान के अन्दर यह पहला उदाहरण हो कि सारी स्कूलों का ड्रेस कोड एक हो और पूरे राजस्थान में जहां बच्चा विद्यालय में पढ़ने जाए, उसकी ड्रेस एक जैसी हो जाए तो यह हीन भावना नहीं होगी और बच्चा अपने आपमें हीन भावना नहीं समझेगा।

इसके साथ ही आदर्श और उत्कर्ष विद्यालय बना रहे हैं, उनका रंग-रोगन एक जैसा हो जिससे गुजरने वालों की टकटकी और नजर वहां रुक जाए कि यह इस गांव का आदर्श विद्यालय है और यह उत्कर्ष विद्यालय है।

(श्री बाबू सिंह)

एक जैसा रंग-रोगन हो उसमें पेड़-पौधे हों। वास्तव में यह विद्या का मन्दिर स्वर्ग है और इसको स्वर्ग बनाने का काम आपका और हमारा है। इसको भी हम विशेष रूप से करने की कोशिश करेंगे।

साथ ही, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, एक तो मिड डे मील, यह भी शिक्षकों के माध्यम से नहीं कराके इसको भी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से और निर्माण कार्य भी आप उनके माध्यम से कराएं। मेरा यह भी निवेदन है।

साथ ही मुख्य मंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में इसका क्रेज बढ़ा है और कई भामाशाह आकर अच्छी क्वालिटी के निर्माण विद्यालयों में करा रहे हैं जिसमें 40 परसेंट तो भामाशाह की तरफ से और 60 परसेंट सरकार दे रही है। मैं यह चाहूंगा कि अब हमारी प्राथमिक शिक्षा में भी ऐसे लोग अगर गांव में कहते हैं कि यह योजना आप हमारी प्रारम्मिक शिक्षा में भी लागू करा दें तो इसमें हम कंट्रिब्यूशन दे सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें भी आप छूट दें। 60-40 का जो रेशो भामाशाह मुख्य मंत्री जन सहभागिता विकास योजना है, वह प्रारम्भिक शिक्षा में भी आपको लागू करना चाहिए। यह मेरा आपसे खास तौर से निवेदन रहेगा।

साथ में आपने पंचायत मुख्यालय पर यह घोषणा की है कि 40 बच्चे होने पर ही उस स्कूल को हम क्रमोन्नत करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और खास तौर से विधान सभा के माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्रीजी तक यह बात पहुंचाना चाहूंगा कि जो पुरानी पंचायतें हैं उन पुरानी पंचायतों में तो सभी जगह बारहवीं की, उच्च माध्यमिक की शिक्षा मिलनी चाहिए। जो प्राइवेट विद्यालय है। गांवों के अन्दर सभी गरीब बच्चे प्राइवेट विद्यालय से शिक्षा अफोर्ड नहीं कर सकते, एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम से कम उन सब जगह पर भी शिक्षा की व्यवस्था हो। मेरे यहां भी ऐसी 6 पंचायतें हैं, कनोड़िया पुरोहितान, सोलंकिया तला, खुड़ियाला, बेलवा, राणाजी, देवातू और दुग्गर। उसके साथ ही 28 नई पंचायतें हैं तो चरणबद्ध तरीके से पंचायत मुख्यालय जो नई बने हैं, उनमें पांचवीं है तो उनको आठवीं करिये, आठवीं है तो दसवीं करिये, दसवीं है तो बारहवीं करिये और चरणबद्ध तरीके

(श्री बाबू सिंह)

से करके सभी पंचायत मुख्यालय पर बारहवीं तक की शिक्षा मिले। यह मेरा आपसे खास तौर से निवेदन रहेगा।

इतना शानदार आपने काम किया है। पुन: मैं यही कहना चाहूंगा, अब वो समय आ गया, हिन्दुस्तान में यह शिक्षा विभाग एक रोल मॉडल बने, लोग इससे प्रेरणा लें। शानदार काम करके हमारे बच्चे तरक्की करें। अंत में यह कि "बालक वह नहीं जिसे भरा जाए, बालक चिराग हैं जिसे रोशन किया जाए"। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, आज शिक्षा, कला और संस्कृति जैसी महत्वपूर्ण मांग पर चर्चा हो रही है। मेरे से पहले भी माननीय सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण विचार रखे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या मौलिक परिवर्तन होने चाहिए और किस प्रकार की ज़रूरतें आज सुधार के लिए आवश्यक हैं।

सभापति महोदय, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम आज शिक्षा पर चर्चा कर रहे हैं तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री स्वयं एक शिक्षक हैं। हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में यह स्लोगन है कि "जहां-जहां भी लोकतंत्र है, शिक्षा उसका मूल मंत्र है"। दुनिया में जहां भी डेमोक्रेसी आई, वहां विकास की चाहत बढ़ी। दुनिया के तमाम देशों में विकास की चाहत बढ़ी तो शिक्षा उसका आधार बनी।

सभापति महोदय, हम सब यह मानते हैं कि शिक्षा जीवन जीने के लिए तो है ही, लेकिन मेरे जीवन के क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, उसकी समझ शिक्षा के बिना नहीं आ सकती है। यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक मुल्क की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। मौजूदा पीढ़ी चाहती है कि मेरी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुखद हो। वह संयमित और सृजनात्मक जीवन जीए। सुखद मानव कल्याण के विचार के साथ वह जीवन जीए।

सभापति महोदय, यह एक बहुत गंभीर विचार है कि कैसी शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा के महत्व को समझकर दुनिया के तमाम विकासशील देशों ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए अपने-अपने एजेंडे पर काम किया।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सभापति महोदय, अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जब भाषण कर रहे थे तो शिक्षा जैसे विषय पर राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल हो रहा था। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि आजादी के 70 सालों में जिस उच्च मानकों की शिक्षा हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। संविधान की भावना के अनुरूप शिक्षा के मूल अधिकार की प्राप्ति, समानता का अवसर देश के प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हो जाना चाहिए था, वह हम नहीं पहुंचा पाए।

सभापति महोदय, लेकिन हमें संतोष है कि हमारी मुल्क की पीढ़ी ने शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर दुनिया में परचम फहराया है। मैंने पिछली बार भी सदन में इस बात का जिक्र किया था कि अमेरिका के दो-दो राष्ट्रपतियों को यह कहना पड़ा कि 'अमेरिका के लोगों, सावधान हो जाओ, भारत का टैलेंट आ रहा है और समूचे अमेरिका की व्यवस्था पर कब्जा कर लेगा'। यह हमारे देश के नौजवान की प्रतिभा है जिसने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। सभापति महोदय, हमारे यहां शिक्षा के उन्नत संस्थान भी खुले हैं। मैं आज यह भी खुले मन से कहना चाहता हूं कि हमारे आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम विश्व मानकों में किसी दूसरे से कमजोर नहीं है।

सभापति महोदय, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ, उपनिवेशकाल से मुक्त हुआ तो एक विशेष प्रकार की शिक्षा थौपी गई। आजादी के बाद होना चाहिए था कि उस शिक्षा को उखाड़ फेंककर, एक मजबूत विकल्प तैयार करके, प्रचंड इच्छाशक्ति से नौकरशाहों को उस दिशा में कार्य योजना तैयार करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए था, लेकिन हमारी इच्छाशक्ति असफल हुई। शिक्षा का प्राइमरी ढांचा हम ठीक नहीं कर पाए। उसका परिणाम यह हुआ कि हम लगातार शिक्षा की नीतियां बनाते रहे, शिक्षा के बारे में चिंता करते रहे। लेकिन इस मुल्क की बेसिक शिक्षा क्या होनी चाहिए, इसके बारे में गंभीरतापूर्वक कभी प्रयास नहीं किया। हमने कभी इस मुल्क की परंपराओं के अतीत में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं की। आज उसका गंभीर परिणाम देश भुगत रहा है।

सभापति महोदय, पीड़ा होती है कि जब जेएनयू का एक विद्यार्थी,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जिसने उम्र के 18 साल पूरे नहीं किए हों, देश की व्यवस्था पर सवाल उठाता है। आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं? कौनसी एजुकेशन दे रहे हैं? आज हमने अखबारों में पढ़ा कि यूनिवर्सिटी में भूगोल के प्रोफेसर लड़ गए और चाकू जैसी धारदार चीज का इस्तेमाल हुआ।

सभापति महोदय, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे पास 600 ईसा पूर्व नालन्दा विश्वविद्यालय था। नालन्दा विश्वविद्यालय में उस समय 10 हजार विद्यार्थी थे। जब दुनिया की आबादी, भारत की आबादी से आधी नहीं होगी, उस समय भारत में उच्च शिक्षा पद्धति मौजूद थी, तत्व ज्ञान था, दर्शन शास्त्र था, सांख्यिकी थी, गणित थी, वेदों की शिक्षा थी। इन सबके बाद 11वीं शताब्दी में मुगलों के आक्रमण ने हमारे शिक्षा के मूल ढांचे को नष्ट कर दिया।

सभापति महोदय, जब आजाद हुए तो शिक्षा नीतियां तो बनाते रहे लेकिन कभी यह मौलिक चिंतन प्रारंभ नहीं किया कि हमें हमारी बेसिक शिक्षा की ओर जाना चाहिए। हमारे भावी वैज्ञानिकों को, इस देश के निर्माण की जिम्मेदारी लेने वाले लोगों को, इस मुल्क की शिक्षा नीति बनाने वाले लोगों को यह बात स्वीकार करने में शर्म आती रही। पश्चिमी देशों से सैकड़ों साल पहले भारत में एक सशक्त वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति थी। उसका पुनर्भरण होना चाहिए, उसका उदय होना चाहिए और मैं जब उसकी चर्चा कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय, तो आज हमारे सामने यह बात केवल चर्चा में रह गई। दुनिया में हम आर्यभट्ट के योगदान को नहीं भूल सकते। आर्यभट्ट की गणित को आज भी हिन्दुस्तान की बेसिक शिक्षा में पढ़ाया जाए तो वेदों में समाहित आर्यभट्ट की गणित के ज्ञान के सामने दुनिया का विज्ञान आज भी बौना साबित हो सकता है। यह हमारी परम्परा रही है और शिक्षा रही है। हम उससे दूर चले गए हैं और इतना दूर चले गए हैं माननीय सभापति महोदय, अगर लौटकर हमने उस परम्परा की तरफ मुड़ने का प्रयास किया तो फिर हमसे कह दिया गया कि ये पुरातनपंथी लोग हैं। यह धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर सवाल खड़ा करने वाले लोग हैं इसलिए धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर सवाल करने के तौर-तरीकों ने इस मुल्क की शिक्षा पद्धति को वहां ले जाकर खड़ा कर दिया, जहां पर स्वतंत्रता के नाम पर उद्दंडता हो रही है

(श्री प्रहलाद गुंजल)

और जहां पर स्वतंत्रता के नाम पर मौज-मस्ती हो रही है, जहां स्वतंत्रता के नाम पर शैक्षिक चरित्र समाप्त हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? मैं बहुत ईमानदारी के साथ आपको कहना चाह रहा हूं, यह केवल हमने अपने आप ही यह रास्ता नहीं चुना। आजादी के बाद हमारे जीवन पर पाश्चात्य जीवन का प्रभाव ही नहीं रहा, बल्कि पाश्चात्य सत्ताओं का भी प्रभाव रहा और प्रभाव इस स्तर पर तक रहा कि सारा देश जानता है।

माननीय सभापति महोदय, 1991-92 में ''रामायण'' एक सीरियल आया। पूरे मुल्क को, इस राष्ट्र की शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति से जोड़ने का उस सीरियल ने प्रयास किया। दुनिया के देश विचलित हो गए। वाल्मीकि रामायण, यह भारत का आधार स्तम्भ बन गया है। भारत की संस्कृति और सभ्यता का संक्रमण, भारत की मौजूदा शिक्षा पद्धतियों में रामायण को मानकर किया गया है तो भारत फिर से सनातन राष्ट्र के मौलिक स्वरूप में नहीं आ जाए और इसलिए साजिश के पूर्व माननीय सभापति महोदय, ''SHADOWS OF THE RAMAYANA'' नाम की एक किताब लिखी गई। लिखे, कोई आपत्ति नहीं। दुनिया के किसी राइटर को किसी विषय पर किताब लिखने का, विवादास्पद, गैर विवादास्पद लिखने का अधिकार है, लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि एक विदेशी द्वारा जो रामायण लिखी गई, Wendy Doniger द्वारा जिसमें सीताजी को, लक्ष्मणजी को, हनुमानजी को विकृत चरित्र स्वरूप का बता दिया और दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑनर्स पार्ट सैकंड में इस रामायण के अध्याय को जोड़ दिया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। दूसरे मुल्क के लोग तय करेंगे कि भारत का विद्यार्थी क्या पढ़ेगा? अमेरिका के लोग तय करेंगे कि भारत का विद्यार्थी क्या पढ़ेगा? इसलिए मैंने पिछली बार कहा था, जब मैं एजुकेशन पर बोल रहा था, लॉर्ड मैकाले ने हमारे यहां ऐसी शिक्षा पद्धति दी। एक ऐसी शिक्षा पद्धति जो भारत में उच्च स्तर के बाबुओं का निर्माण करेगी, जो रंग-वर्ण से भारतीय होंगे, लेकिन विचार और संस्कृति से पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में हों।

माननीय सभापति महोदय, आज मैं उस पर नहीं जाना चाहता। हमारे पास सत्तर सालों का अनुभव है, हम यह कहकर इस जिम्मेदारी से मुक्त

(श्री प्रहलाद गुंजल)

नहीं हो सकते कि लार्ड मैकाले ने हमारी शिक्षा पद्धति को दूषित कर दिया। सत्तर साल से जो व्यवस्था काम कर रही है लगातार निर्बाध रूप से, क्या उस व्यवस्था के अनुभव नहीं है कि सत्तर सालों तक जिस प्रकार से हमारी व्यवस्था पर सवाल उठता रहा है, लॉर्ड मैकाले की दुरभि संधि से भारत में जहां शिक्षा अमृतकर्ता थी विप्लवकारी बन गई? क्या सत्तर साल में हम इस अनुभव पर नहीं पहुंचे? इस अनुभव के बाद माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था को स्वयं बदलना चाहिए था। व्यवस्था ने बदलने का प्रयास भी किया लेकिन राजनीतिक बाधाएं बीच में आ गई। राजनीति की कुत्सित इच्छाशक्ति बीच में आ गई। मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा इतिहास का संवर्धन करती है, संस्कृति का संवर्धन करती है, संक्रमण करती है। वह शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए जिसमें जनतंत्र की इमारतों का सम्मान हो। इस देश की इमारतों और ऐतिहासिक इमारतों का सम्मान हो। जब-जब यह प्रयास हुए तो हमसे कहा गया कि यह साम्प्रदायिककरण है यह तुष्टिकरण है। पढ़ाया जाता रहा इस मुल्क में, लाल, बाल, पाल। वे इस देश के आतंकवादी हो गए? जिन लोगों ने इस देश के लिए अपना जीवन दे दिया, इस मुल्क की आजादी के लिए लड़े, इस देश की व्यवस्था में उन्हें आतंकवादी कहकर पढ़ाया जाता रहा।

मैं आज हमारे शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने आज अपना दायित्व निभाने का काम प्रारम्भ कर दिया। देर आए दुरुस्त आए। हम ऐसी शिक्षा देंगे जिसमें नैतिक संस्कार होगा, चरित्र होगा। हम ऐसी शिक्षा देंगे कि हमारे यहां से पढ़कर निकलने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय इमारतों का सम्मान करे, जनतंत्र का सम्मान करे, हमारे मुल्क की व्यवस्था करें। सुप्रीम कोर्ट और जो भी इस राष्ट्र का विषय है उन तमाम व्यवस्थाओं का सम्मान करें। इसलिए राष्ट्र गौरव का पाठ पढ़ाया गया, प्रारम्भ कर दिया गया, यह सिलसिला रुकना नहीं चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हम केवल इसी बहस में उलझे रहेंगे, हमारे राज में नरेगा के कितने पैसे लगे। मैं आज बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में शिक्षा व्यवस्था का अगर कचरा हुआ है तो पचास-पचपन साल तक इस मुल्क में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसके

(श्री प्रहलाद गुंजल)

ऊपर हमेशा पाश्चात्य कल्चर का प्रभाव रहा, जो दुनिया के दूसरे देशों के प्रभाव में काम करती रही, वह प्रभाव आज भी है। यूपीए की सरकार के समय भी कहा जाता था कि अमेरिका के फैसलों से भारत की नीतियां प्रभावित होती हैं। ...(व्यवधान)... उसका परिणाम कांग्रेस ने भुगत लिया लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में खड़े होकर आरोप लगाने वाले, मैं आज कांग्रेस के माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं। भैरोंसिंहजी शेखावत 1992 में राजस्थान के मुख्य मंत्री बने। मुझे याद है, उन्होंने कहा इस राजस्थान की एक-एक पंचायत पर मिडिल स्कूल होगा। मैं इसे उपलब्धि के रूप में जोर से बखान नहीं करना चाहता लेकिन मैं इसके पीछे की स्थितियों को शर्म के साथ बयान करना चाहता हूं कि 1947 की आजादी के बाद 1992 तक मेरे राजस्थान के गांव की पंचायतों को मिडिल स्कूल नसीब नहीं हुआ यह बड़ी लज्जा की बात है। राज किसका रहा लम्बे समय तक? आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राज्य की मुख्य मंत्रीजी को और राज्य के शिक्षा मंत्रीजी को, जिन्होंने पाँच हजार से ज्यादा उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले। राजस्थान की कोई पंचायत नहीं होगी, जहां पर उच्च माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के गरीब बच्चों को नहीं मिलेगी। राजस्थान में केवल 1300 के समथिंग पंचायतें बचेंगी और उनमें भी माननीय सभापति महोदय, 662 पंचायतें वे पंचायतें हैं जो नवगठित हैं। राजस्थान के शिक्षा के ढांचे को सुधारने के लिए जो समग्र विचार राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी का है, मैं आज उनको इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य आरटीई को लेकर सवाल उठा रहे थे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि यूपीए गवर्नमेंट आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर आयी। मैं सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाना चाहता, लेकिन मैं आरटीई के उन क्लॉजेज के बारे में कहना चाहता हूं। आखिर आप क्या परम्परा डालना चाहते थे, इस मुल्क को क्या संदेश देना चाहते थे? आपने बहुत जोरों से प्रचारित किया कि प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण होगा, उसका पुनर्भरण होगा। मैं अगर दूसरे शब्दों में कहना चाहूं, क्या यह निजीकरण को बढ़ावा देने की ओर कदम नहीं है? सरकारी शिक्षा की माली हालत को सुधारने के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

चिन्तन के बजाय हमने आत्मसमर्पण कर दिया दो-दो कमरों में चलने वाले प्राइवेट स्कूलों के सामने। ऐसा लगा जैसे कोई हम बहुत बड़े ऐतिहासिक रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं। गरीब का बच्चा हमारे खर्चे पर, सरकार के खर्चे पर प्राइवेट स्कूल, जिसमें डिस्क्वालिफाई, जो सरकारी स्कूल के अध्यापक की पात्रता भी नहीं रखते, ऐसे पढ़ाने वाले मास्टर होंगे। उस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे और एक ऐतिहासिक उपलब्धि कांग्रेस के खाते में दर्ज होगी। पर्दे के पीछे से निजीकरण को बढ़ावा देने की योजना। पर्दे के पीछे से अमेरिका की उन नीतियों को समर्थन करना। भारत के लोगों से सावधान हो जाओ।

आपने कह दिया आठवीं कक्षा का बोर्ड समाप्त होगा। पहली से पांचवीं, आठवीं कक्षा तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा, किताब का बोझ नहीं होगा। आज मैं इस पवित्र सदन में सवाल करना चाहता हूं क्या रेत की बुनियाद पर बहुमंजिला इमारत खड़ी की जा सकती है? इस मुल्क का निर्माण खोखला करना चाहते हैं? दुनिया के अगवा राष्ट्रों में ले जाने की कैसे चेष्टा की जा सकती है? भारत के भविष्य की नींव को खराब करने का काम अगर किसी ने किया तो आरटीई के माध्यम से इस मुल्क में यूपीए की सरकार ने किया। बच्चा पढ़ेगा नहीं और पास कर दिया जाएगा। बच्चा पढ़ेगा नहीं, बोर्ड नहीं देगा, परीक्षा नहीं देगा, पास कर दिया जाएगा। जिसकी नींव खराब हो जाएगी वो जीवन की चुनौतियों से लड़ने का रास्ता नहीं बना सकता। मैं राज्य के मुख्य मंत्री और शिक्षामंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान में फिर से एक नई परम्परा स्थापित करने की कोशिश की। क्या कहना चाहते हैं? माननीय उद्योग मंत्रीजी, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं। किस दिशा में इस मुल्क में ले जाना चाहते हैं? यह क्रेडिट लेना चाहती है कि हम गरीब को और अमीर को साथ बिठाकर पढ़ाएंगे। शायद ये परम्पराओं को भूल गये। इस मुल्क की सनातन सभ्यता में यह हिस्सा था कि कृष्ण और सुदामा साथ पढ़े थे। यह आज कौनसा नया संदेश देना चाहते हैं? ये तहजीब को मिटाना चाहते हैं, परम्परा को मिटाना चाहते हैं। कृष्ण-सुदामा साथ पढ़े। कृष्ण-सुदामा साथ लकड़ी चुनने के लिए जाते थे। हमारी गुरुकुल की परम्पराएं कहती थीं कि राजा का बेटा कृष्ण इसलिए लकड़ी चुनने जाएगा कि

(श्री प्रहलाद गुंजल)

आज सम्पन्नता अगर कल विपन्नता में बदल गयी तो चुनौतियों से लड़ने की हमारी शिक्षा उसको आधार दे सके। भगवान रामचन्द्रजी जब विश्वामित्र के आश्रम में गये थे। वे बोले, संन्यासी भेष में, नंगे पैर, नंगे बदन रहना पड़ेगा। जब सवाल उठाया राजपुत्रों ने तो बोला हमारी शिक्षा रोजगारपरक है। हमारी शिक्षा केवल पढ़ने और सीखने की शिक्षा नहीं है, हमारी शिक्षा चुनौतियों से लड़ने की शिक्षा है। अगर कभी राजा के बेटे को वन में जाना पड़े और संन्यास धारण करना पड़े तो वह जीवन फिर चुनौतियों से लड़ने का हमारी शिक्षा के माध्यम से रास्ता तैयार कर लिया। आप सत्यानाश करके क्रेडिट लेना चाहते थे। मैंने इस मुल्क में ऐसी लज्जाजनक परिस्थितियां नहीं देखीं जहां सत्यानाश करके उसका भी श्रेय लेने का प्रयास कोई करे तो यह आचरण अगर किसी का था तो यह कांग्रेस पार्टी की सरकार का था। सत्यानाश कर दिया।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कृष्ण-सुदामा तो साथ पढ़े। एकलव्य को नहीं पढ़ाया, उसके बारे में कहो आप। एकलव्य क्यों नहीं पढ़े?

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय विश्नोई साहब, एकलव्य को नहीं पढ़ाया, यह कहकर आप उस गुरु की महत्ता को समाप्त नहीं कर सकते जिसके प्रति श्रद्धा और ध्येय मात्र से एकलव्य इतिहास पुरुष बन गया। न कर्ण और अर्जुन की तरह महाभारत का युद्ध लड़ना पड़ा।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): वह उसकी मेहनत थी, उसकी लगन थी। साथ नहीं पढ़ाया उसको।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): यह आपके समझ के बाहर का विषय है। माननीय सभापति महोदय, यह हमारी शिक्षा का प्रभाव था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप टोकाटाकी न करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, एकलव्य का सवाल उठाया, मैं उस प्रसंग की चर्चा करना चाहता हूं। यह हमारी शिक्षा का प्रभाव था माननीय सुखराम जी, महान धनुर्धर कर्ण ने उस महाभारत के मैदान में तीनों लोक का भार वहन करने वाले रथ को एक-एक तीर में 100-100 गज पीछे धकेला। उस महान पराक्रमी योद्धा अर्जुन ने कर्ण से लेकर

(श्री प्रहलाद गुंजल)

गुरु द्रोण, भीष्म पितामह से लेकर न जाने कितने महान योद्धाओं को वीरगति प्रदान की। लेकिन यह हमारी शिक्षा, यह हमारी परम्परा केवल गुरु निष्ठा का उत्तम उदाहरण, गुरु दक्षिणा मांगी और अंगूठा काटकर दे दिया। इतिहास के पन्नों में अमरत्व प्राप्त कर गया कि अंगूठा नहीं कटा होता तो कर्ण और अर्जुन से बड़ा धनुर्धर होता। यह गुरु निष्ठा की हमारी परम्परा का उदाहरण है। गुरु निष्ठा का उत्तम उदाहरण पेश करने में हजारों साल बीत जाए, करोड़ों इतिहास बदल जाए लाखों सालों में, लेकिन इतिहास उस भ्रम को तोड़ नहीं सकता कि अंगूठा नहीं कटा होता तो एकलव्य दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर होता। यह किसी महाभारत के युद्ध के पराक्रम से उसको नहीं मिला। यह हमारी गुरु-शिष्य परम्पराएं जो इस मुल्क की थीं, गुरु के प्रति आस्था प्रकट करने से इतना बड़ा अमरत्व उसको प्राप्त हो गया। लेकिन आपने सत्यानाश कर दिया।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सदस्य, इनके इतनी बातें थोड़े ही समझ में आएंगी। क्या कर रहे हो, इतना ज्ञान क्या दे रहे हो? (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मैं बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूं, आज शिक्षा के जगत में भयानक स्थितियां हैं। मैं पिछली बार जब गवर्नर स्पीच पर बोल रहा था, शिक्षा के मंदिरों की तरफ राजनैतिक लोग झांकें। यह इतिहास है। नौजवानों की तरफ झांकें। यहां तो माननीय सभापति महोदय, आपके आसन के पीछे स्लोगन सच का लिखा है। लेकिन देश की सबसे बड़ी पंचायत में अगर आप जाएंगे तो अध्यक्ष के आसन के पीछे लिखा है "नसा सभा न सन्ति युवा नते ये वदन्ति सत्यम्" इस मुल्क में कोई सभा पूर्णत्व प्राप्त नहीं कर सकती जिसमें नौजवान का प्रतिनिधित्व नहीं हो और वो नौजवान, नौजवान नहीं हो सकता जिसमें सत्य का उद्घोष करने का साहस न हो। हमने इस कीमत को पहचाना। आजादी से पहले और आजादी के बाद, इस आजादी की लड़ाई में विश्वविद्यालयों की चौखटों पर लोग जाते हैं। देश में लोकतंत्र पर छींटा लगा। इमरजेंसी में लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय की चौखटों पर जाते है। इस मुल्क की बहबूदी के लिए, इस मुल्क में लोकतंत्र बचाने के लिए, इस मुल्क में समूची व्यवस्था को ध्वस्त करके एक नई व्यवस्था कायम करने के लिए विद्यार्थियों के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

योगदान को तमाम राजनैतिक दलों ने उपेक्षित किया है। लेकिन आपने क्या किया? आप कैसा चेहरा-मोहरा विश्वविद्यालयों का, शिक्षा का बनाना चाहते हैं? इस मुल्क के खिलाफ बोलने वाले लोगों को प्रश्रय देने के लिए आपकी पार्टी के युवराज जेएनयू के दरवाजे तक पहुंच गये। विश्वविद्यालय के दरवाजे पर पहुंच गये। आपने अपने काल में लगातार शिक्षा नीतियों का प्रयोग करते-करते, भारत की परम्पराओं का सत्यानाश करते-करते शिक्षा के मौलिक स्वरूप को उस विकृत स्थिति में ले जाकर खड़ा कर दिया और एक ऐसी भयावह स्थिति बना दी जहां पर शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के तीनों आत्मस्वरूप विमुख हो गये। कोई बचा ही नहीं। इसका प्रमुख कारण क्या रहा? धर्मनिरपेक्ष प्रशासन का अनर्थीकरण। धर्मनिरपेक्षता का वास्तविक अर्थ समझे बगैर आपने नीति और संस्कृति पर कुठाराघात किया। जिस देश में नीति और संस्कृति पर कुठाराघात होता हो वो देश कैसे एक बेहतर शिक्षा पद्धति दे सकता है। उसका परिणाम आज सारा मुल्क भुगत रहा है, उसके नुकसान को आज भी सारा मुल्क भुगत रहा है। जिस मुल्क की शिक्षा पद्धति में सनातन इबादतों के प्रति सम्मान न हो, जिस मुल्क की शिक्षा पद्धति में भारत के भविष्य की, जनतंत्र की इमारतों के प्रति सम्मान न हो, वो शिक्षा पद्धति किस तरीके से देश को आगे ले जा सकती है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर इतना कहना चाहता हूं कि हमें 70 साल के अनुभवों को लेना पड़ेगा। 70 साल के अनुभवों से एक व्यवस्था बनानी होगी। आरोपों-प्रत्यारोपों के आधार पर नहीं। मैकाले हमारी शिक्षा पद्धति में भाँग घोल गये, यह चर्चा अब बन्द हो जानी चाहिए। मैकाले का अध्याय भारतीय शिक्षा जगत की चर्चा से 70 साल के अनुभवों के बाद अब समाप्त हो जाना चाहिए। अब चर्चा होनी चाहिए। हम सनातन काल की शिक्षा पद्धति की ओर जाना चाहते हैं, जहां हमारी शिक्षा ने कृष्ण को सुदामा के साथ-साथ आत्मनिर्भरता के रास्ते पर ले जाने के लिए, राजा के बेटे को लकड़ी बीनने की शिक्षा दी। हम उस शिक्षा की ओर लौटना चाहते हैं, अगर इस सनातन मुल्क की आत्मा भगवान राम है तो राजा दशरथ के बेटे को संघर्ष का, एक संन्यासी का जीवन भी अगर विपदाओं में जीना पड़े तो भारत की शिक्षा विषमकाल में तुम्हारे साथ सहभागी बनकर खड़ी हो जाए,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

उन परम्पराओं की ओर लौटना पड़ेगा। लौटना पड़ेगा हमें उन परम्पराओं की तरफ और उन परम्पराओं में आज भी इतना ज्ञान निहित है माननीय सभापति महोदय, जो मौजूदा समय में नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं आर्यभट्ट की गणित के बारे में। पिछली बार इस सदन में सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य भाषण कर रहे थे। मुझे याद आ रहा है, जब मैं इस विधान सभा में पहले सत्र में आया था, आर्यभट्ट की गणित को लेकर, जब इसरो के वैज्ञानिकों ने अन्तरिक्ष में यान स्थापित किया तो दुनिया के लोगों ने सवाल खड़ा किया कि भारत ने बिना किसी से तकनीक उधार लिये यह चमत्कार कहां से कर दिया। तब उन्होंने कहा कि आर्यभट्ट की गणित का एक फार्मूला स्थापित किया और अन्तरिक्ष में उपग्रह स्थापित कर दिया। हम इतने सम्पन्न रहे हैं, हमारी शिक्षा पद्धतियां इतनी सम्पन्न रही हैं। नालन्दा में वो सब कुछ पढ़ाया जाता था और आज भारत के प्रधान मंत्रीजी रोजगारपरक शिक्षा, संकट में साथ देने वाली शिक्षा, विषम परिस्थितियों में साथ देने वाली शिक्षा, उन परम्पराओं की तरफ हम लौट रहे हैं, लौट रहा है राजस्थान। शिक्षा में कौशल होना चाहिए, शिक्षा में हुनर होना चाहिए और केवल विश्वविद्यालय खोलने के विधेयक नहीं लायें। प्रतिपक्ष के लोगों ने यहां खड़े होकर आरोप लगाये कि कितने सैकड़ों करोड़ रुपये आपने एप्रेंटिस एक्ट के तहत इण्डस्ट्री के मालिको को भुगतान कर दिया। एप्रेंटिस एक्ट में जो प्रावधान किये थे, उन प्रावधानों के तहत राजस्थान के शिक्षित व्यक्ति को, बेरोजगार को हाथ हुनर सिखाने के लिए, हमारी सनातन परम्पराओं, शिक्षा रोजगारपरक बने, शिक्षा जीवन की सहयोगी बने, हुनर सिखाया, प्रशिक्षित किया और इसीलिए आज भारत के प्रधान मंत्रीजी ने तय कर दिया कि इस मुल्क का कोई व्यक्ति शिक्षित होने के साथ-साथ हुनरबद्ध भी होगा। शिक्षा का स्वरूप आज मौलिक कुछ भी हो, हम उसको कौशल विकास कह दें, हम डिजिटल इण्डिया कहकर उसकी योग्यता को और आगे बढ़ाने की बात कर दें, लेकिन ये सारी चीजें हमारी उस मौलिक शिक्षा पद्धति में से निकली हुई हैं। मैंने दो उदाहरण राम और लक्ष्मण के दिये हैं कि राजा पर भी विपदा आ सकती है। लेकिन विपदा में शिक्षा ही साथ देगी, सिंहासन साथ नहीं देगा। ये हमारी शिक्षा के संस्कार थे। नालन्दा में जिस

(श्री प्रहलाद गुंजल)
प्रकार से गणित पढ़ाया जाता था, जिस प्रकार से तत्व ज्ञान पढ़ाया जाता था, आज के इस विज्ञान से हमारी शिक्षा का वो स्तर ऊँचा था।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, इस मुल्क के, राजस्थान के एक-एक व्यक्ति को शिक्षित करने के रास्ते पर चलें लेकिन, सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी विकृति आ गई। शिक्षा में एक वर्णभेद कायम हो गया। एक वो वर्ग जिसके सामने असमानता है, साधनों की कमी है और एक वो सीमित वर्ग जो साधन सम्पन्न, समृद्धि के वातावरण में पढ़ना चाहता है। इस वर्णभेद ने, इस वर्णपांत ने एक बहुत बड़ी गहरी खाई समाज में पैदा कर दी। इसको मिटाने के लिए कृष्ण-सुदामा की परम्पराओं पर जाना पड़ेगा। यह कह कर कि आर.टी.ई. में हम गरीब और अमीर को साथ बिठा देंगे, उन परम्पराओं पर नहीं जा सकते। उन परम्पराओं पर जाना है तो हमें हमारे सरकारी विद्यालयों को विश्वामित्र की पाठशाला के बराबर आदर्श बनाना पड़ेगा। हमें हमारी पाठशालाओं को कृष्ण-सुदामा की पाठशाला के बराबर आदर्श बनाना पड़ेगा जहां पर यह महसूस हो कि धनपति और गरीबपति साथ बैठकर उस वर्णभेद को समाप्त कर सकते हैं। उस गरीबी-अमीरी के कारण जो खाई बन गई है उसको समाप्त कर सकते हैं। इस दिशा में सार्थक प्रयास करने पड़ेंगे और हमारे सरकारी विद्यालयों को संसाधनयुक्त बनाना पड़ेगा।

आज स्थिति क्या है? माननीय सभापति महोदय, सरकारी स्कूलों में आज भी पर्याप्त कमरे नहीं, बिजली की व्यवस्था नहीं। हम इंटरनेट के युग में डिजिटल इण्डिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं पर सरकारी स्कूलों में बिजली की कमी है, फर्नीचर की कमी है। इन व्यवस्थाओं पर बहुत गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। हमारी सरकार लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। राजस्थान में आदर्श विद्यालय खोलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मैं उम्मीद करूंगा, निश्चित रूप से इस दिशा में सार्थक प्रयास होने चाहिए और जब तक इस दिशा में सार्थक प्रयास नहीं होंगे, इस खाई को पाटने का हम प्रयास नहीं करेंगे, सरकारी स्कूलों में ये संसाधन क्रियेट नहीं कर देंगे, प्राइवेट के मुकाबले संसाधनयुक्त, संसाधन सृजित कर हमारी सरकारी स्कूलों को जब तक हम खड़ा नहीं कर देंगे, कृष्ण-सुदामा की परम्परा पर नहीं लौट

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सकते। हम कानून बनाकर कृष्ण-सुदामा की मित्रता का इतिहास नहीं रख सकते। आर.टी.ई. में हम 25 प्रतिशत प्राइवेट स्कूल में देकर निजीकरण के हाथों में कोई इतिहास रच दें, हमारी परम्पराएं इससे डेस्ट्रॉय होंगी, परम्पराएं समाप्त होंगी। इसलिए सरकारी स्कूलों की माली स्थिति सुधारने में भी काम होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं उच्च शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। मुझे बहुत पीड़ा है। मैंने इस सदन में कई बार कहने का प्रयास किया कि आखिर किस तरीके से ड्राफ्ट करके ये मंत्रियों से और हमारे मुखियाओं से किस तरीके का बजट में बयान पढ़वा देते हैं। पिछले बजट में सर्वाधिक पीड़ा मुझे हुई, जब बजट भाषण में पढ़वा दिया गया कि कोटा के कॉलेज को हम विघटित कर देंगे। जहां राजस्थान में पांच हजार बच्चे थे उन कॉलेजों को संकाय के आधार पर टुकड़ों में कर देंगे। माननीय सभापति महोदय, आजादी के पहले का कोटा का हरबर्ट कॉलेज, जो उस हाड़ौती का सबसे बड़ा कॉलेज है, विश्वविद्यालय तो नहीं है, लेकिन किसी विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा से उसकी प्रतिष्ठा कम नहीं रही, पर अफसरों ने लिखकर दे दिया कि संकाय के आधार पर विघटित कर दो। जो यू.जी.सी. के नैक की प्रथम श्रेणी का जे.डी.बी. कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज है, विघटित कर दिया आपने। उसका स्वरूप बिगाड़ दिया और आज जब हम पढ़ते हैं कि वहां पर प्रिंसिपल लड़ रहे हैं कि मेरा कमरा कौनसा होगा, मेरी बिल्डिंग कौनसी होगी। वहां पर अलग-अलग तीन-तीन छात्र संघ लड़ रहे हैं कि मेरा सचिवालय कौनसा होगा। विद्या के मंदिरों को प्रयोगशालाएं बनाने की परम्परा अधिकारी बनाकर डाल देते हैं, हमें उस पर मॉनीटरिंग करनी पड़ेगी। इन परम्पराओं को बन्द करना पड़ेगा। मुझे बेहद प्रसन्नता होगी कि आज उच्च शिक्षा मंत्रीजी जब बजट पर जवाब देंगीं तो मेरे कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज, कोटा और जे.डी.बी. कॉलेज के मौलिक स्वरूप को बहाल करके करेंगे। आज 70 साल आजादी को हो गये। आजादी के समय 37 करोड़ का हिन्दुस्तान था, अब 137 करोड़ होने वाले हैं। आप नये संसाधनों से सृजित विद्यालय, विश्वविद्यालय खोलने की बात करो। संकाय के आधार पर पुराने महाविद्यालयों का विघटन करके यू.जी.सी. के नोर्म्स में भी उनका, अब मैं कुछ और कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा,

(श्री प्रहलाद गुंजल)
उनका स्तर गिराने का प्रयास मत करो। मुझे अच्छा लगेगा, आज उच्च शिक्षा मंत्री जी कहें कि इन कॉलेजों का विघटन समाप्त होना चाहिए।

इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रहे हैं और हर जिले में हमारी सरकार में लगभग इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं। हमने कांग्रेस की तरह प्रयोग नहीं किये। चुनाव आ गया 2013 का और 42 कॉलेजों की घोषणा कर दो, राजस्थान की आंखों में धूल झोंक दो, हम 42 कॉलेज खोलकर जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है, आजादी के 70 साल बाद शिक्षा का हम ऐसा मजाक उड़ायें कि इस राजस्थान की जनता को यथार्थ के धरातल पर खड़ा करके आगे बढ़ने के बजाय ऐसी हायर एजुकेशन की ओर, जहां न बिल्डिंग, न प्रिंसिपल, न बजट और कागजों में शुरू हो गया महाविद्यालय। हम कागजी राजस्थान का निर्माण नहीं करना चाहते, हम शक्तिशाली राजस्थान का निर्माण करना चाहते हैं जहां का एक-एक बच्चा शिक्षित हो और यह हमारा नारा है कि एक भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित रहा तो आजादी के 70 साल बाद यह संविधान और व्यवस्था का क्रूर मजाक उससे नहीं हो सकता जो आप 70 सालों से करते आये हैं। हम उस क्रूर मजाक को मिटाना चाहते हैं, उसको समाप्त करना चाहते हैं। यह बहुत हो गया राजस्थान के साथ क्रूर मजाक। मैं जब पहली बार एम.एल.ए. बनकर आया था और हम लगातार इस बात की चर्चाएं करते थे कि ठहराव की दर क्या है, एडमिशन की दर क्या है, ड्रोप आउट की दर क्या है। आखिर हम कहां जा रहे हैं? जब हिन्दुस्तान विकसित देशों की लड़ाई में शुमार हो रहा है, दुनिया की 5वीं महाशक्ति बनकर अब विश्व का नेतृत्व करने की ओर आगे बढ़ रहा है।

हम एक दशक पहले तक प्रवेश दर, ठहराव दर, ड्रोप आउट दर और साक्षरता के विषयों पर उलझते रहे। अब हमें सम्पूर्ण रूप से भारत को शिक्षा में और राजस्थान को पूरा शक्तिशाली प्रांत बनाने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार के गम्भीर प्रयास मैं समझता हूं, राजस्थान में प्रारम्भ कर दिये गये हायर एजुकेशन और माध्यमिक शिक्षा में और हमें इस वातावरण को ठीक करने के लिए सरकारी स्कूलों में संसाधन जुटाने पड़ेंगे। नई तकनीकी के कम्प्यूटर्स की प्रयोगशालाएं खोलनी पड़ेंगी।

हमने कल्पना की है 1986 की कोठारी आयोग की शिक्षा नीति में कि

(श्री प्रहलाद गुंजल)

हमारे उस समय विज्ञान होगा, भौतिकी होगी, रसायन होगी। मुझे पीड़ा है माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, कि आपने आज यहां कह दिया इस सदन में कि 40 बच्चे 10वीं में होंगे तो 11वीं खोलेंगे। मैं आज आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने के बाद भी यह कहना चाहता हूं, यह राइडर हटाओ, राजस्थान के विकास में ब्रेक मत लगाओ। जहां पर एक बच्चा भी पढ़ने वाला होगा तो, इस सरकार की जिम्मेदारी है, हम उस एक बच्चे को भी शिक्षा देंगे चाहे उसके किस तरीके के वैकल्पिक रास्ते ढूंढें। यह ढूंढने का काम सरकार का है। उसे टालने और रोकने का काम सरकारों का नहीं है। जब 1986 की कोठारी आयोग की नीति में रसायन, भौतिकी की शिक्षा अनिवार्य है तो आज इस राजस्थान के कितने पंचायत समिति के सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में हम भौतिकी पढ़ा रहे हैं, रसायन पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं? आज दुनिया के विकास का आधार कला और वाणिज्य से बढ़कर भौतिकी, रसायन विज्ञान, जिसमें दुनिया को तीव्र गति से विकास के आयाम प्रदान किये हैं। भारत का बच्चा, उसे पढ़ने से वंचित कर दिया कांग्रेस के लोगों ने। हमें उस कमी को पूरा करने के लिए ईमानदारी से आगे बढ़ना पड़ेगा और विज्ञान, भौतिकी, रसायन, गणित, अगर हम गांव के बच्चे को ठीक तरीके से पढ़ाने में वंचित रह गये तो इतिहास हमको भी अपराधी कहकर सम्बोधित करने से नहीं चूकेगा और इसीलिए आपके सार्थक प्रयासों में यह कड़ी जुड़नी चाहिए। हम भौतिकी पढ़ायेंगे, रसायन पढ़ायेंगे, गणित पढ़ायेंगे, एक-एक बच्चे को पढ़ायेंगे। 50 साल के उस क्रूर मजाक को समाप्त करेंगे जिसने शिक्षा के समता के अधिकार से भारत के गरीब बच्चे को वंचित रख दिया और झूठे कानूनों से कृष्ण-सुदामा की दोस्ती का नारा देकर झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास किया। हम इन नारों को मिटा देंगे। यथार्थ के धरातल पर इस राजस्थान के शैक्षणिक जगत का उन्नयन करते हुए, एक-एक बच्चे को पढ़ने का अवसर और समृद्ध संसाधनों वाले विद्यालय और आवश्यकताएं तैयार करके हम इस वातावरण को बहाल करेंगे, तब राजस्थान ठीक दिशा में आगे बढ़ेगा। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

श्री हीरालाल (निवाई): ये तो लाल मिर्च और हरी मिर्च का अंतर ही नहीं समझते, आपके भाषण का ये लोग क्या अंदाजा लगाएंगे।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आदरणीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर चर्चा हो रही है। यह एक ऐसा विषय है जो हमारा समाज ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश को एक नई दिशा की ओर ले जाने वाला है और शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय हम सबके लिए है कि राजनीति से ऊपर उठकर हमें इस पर विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि किस तरह से शिक्षा के स्तर को हम उठा सकें और वास्तव में किस प्रकार से सही शिक्षा हम दे सकें।

अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने लम्बा-चौड़ा प्रवचन दिया और जिस तरह से बातें कर रहे थे, जिस तरह से प्रवचन दे रहे थे और अंत में जाकर, लास्ट में यही कहा, स्कूल में कमरे नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं। स्कूल खुलनी चाहिए। 40 बच्चों का राइडर हटाना चाहिए। आखिर लास्ट में आकर इन बातों पर आ गये। इससे साफ जाहिर है, जब उस टाइम में आप इधर बैठे थे और तब हमेशा यही कहते थे कि कांग्रेस सरकार एक भर्ती कर नहीं सकी। स्कूलें खोल नहीं सकी। स्कूलों में शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया, वह कर दिया, यह कर दिया। लम्बी-चौड़ी बातें, बैठे-बैठे प्रवचन देते थे और आज तीन-साढ़े तीन साल हो गये और साढ़े तीन साल में जो कुछ हुआ, वह सब आपके सामने है। आपने एक साथ घोषणा की कि हम हर पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सैकण्डरी, 12वीं स्कूल खोल देंगे। वह आपने खोल नहीं दी बल्कि, आपने उसमें राइडर लगा दिया। उसमें आपने राइडर लगा दिया कि 40 बच्चे हों, दूसरा कोई प्राइवेट स्कूल वहां नहीं हो, यह राइडर आपने लगाया। यह राइडर क्यों लगा रहे हो? जब आपने घोषणा ही कर दी कि हम सभी पंचायतों में सीनियर सैकण्डरी करेंगे तो आपको एक ही आदेश में वह करना चाहिए था परन्तु आप यह नहीं कर रहे।

आज एकीकरण को लेकर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। पता नहीं, एकीकरण करके ऐसा कर दिया कि पूरा नक्शा ही अपने राजस्थान का बदल गया। बहुत अचम्भे की बात मैं कहना चाह रहा हूं। एकीकरण में हुआ क्या? अगर वास्तव में उस स्थिति पर कोई गया, उसमें कोई किसी ने देखा नहीं कि इस एकीकरण में जिस विद्यालय में, जहां एकीकरण हो रहा है, उस विद्यालय में कमरे हैं या नहीं, बैठने की उनकी व्यवस्था है या नहीं है, आसपास की जो स्कूलें बंद कर रहे हो, उनमें बच्चियों तक की जो स्कूलें हैं,

(श्री मेवाराम जैन)

उनको भी आपने बंद किया। इतना तक नहीं सोचा। कम से कम छात्राओं के लिए तो हम सोचें। वह भी आप भूल गये। स्कूल में कमरों का पता नहीं है और बच्चे बाहर बैठे हैं। आप बताओ, एकीकरण में इतनी स्कूलें आपने की हैं। मैं तो बाड़मेर की बात कर रहा हूं, एक भी स्कूल ऐसी माडल स्कूल बताओ जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। आप बड़ी-बड़ी, लम्बी-चौड़ी बातें कर रहे हो। आज आपने...

श्री हीरालाल (निवाई): एक-एक स्कूल में दो-दो बच्चे ही हैं तो एकीकरण तो करना ही था।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं उस पर भी आ रहा हूं। आज शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए होना तो यह चाहिए था कि हम सब मिलकर सार्थक प्रयास करते कि किस तरह से इसका हम स्तर बढ़ायें, किस तरह से अच्छी शिक्षा बच्चों को दे सके। कोई भी बच्चा निरक्षर नहीं रहे। 2013 में 7,000 शिक्षकों का चयन हुआ और पांच माह पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया, फिर भी आप उनको नियुक्ति नहीं दे रहे हो। क्या आपके पास अध्यापक ज्यादा हैं? स्कूलें तो खाली पड़ी हैं। आज रीट 2016 में थर्ड ग्रेड शिक्षकों का चयन हुए चार माह हुए, अभी तक आप उनको नियुक्ति नहीं दे पा रहे हो। क्या कारण है? मंत्रीजी, अभी बातें हो रही थी, इन पर कभी विचार किया क्या कि उनको आप क्यों नहीं लगा रहे हो?

(15.57 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

अभी कुछ रोज पहले शिक्षा विभाग में आपके अख़बार में ही पढ़ा, 6,120 पद आपने समाप्त किये। फाइनेंस ने भी उस पर अपनी मोहर लगा दी। अब उस विद्यालय में स्टाफिंग और एकीकरण पैटर्न के चलते आपने इन पदों को खतम कर दिया। क्या प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में खूब अध्यापक हैं? आपने उन पदों को खतम कर दिया। मौजूदा सरकार के गठन के बाद थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। पिछले साल 15,000 पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की, उसका क्या हुआ? ठंडे बस्ते में है।

(श्री मेवाराम जैन)

आज बात कर रहे हैं छात्रवृत्ति की अनुसूचित जाति, जनजाति मैट्रिक छात्राओं की आप तुलना कर लें कि उनको आप छात्रवृति क्या दे रहे हैं? 2014-15 में 2,34,486 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई, 2015-16 में 1,88,161 छात्रों को ही दी और 2016-17 में 1,57,600 को ही दी। आप देखो, लगातार उसको कम देते जा रहे हो।

इसी तरह घुमन्तू ओबीसी की जातियों को आपने छात्रवृत्ति के अंदर भी 2014-15 में 26,492 छात्रों को दी, 2015-16 में 25,923 और लास्ट 2016-17 में तो सिर्फ 10,595 पर आप अटक गये। यह आप कर रहे हो एससी के साथ। आज स्कूलों के हालात क्या हैं? आप शिक्षा का स्तर बढ़ाओगे किस तरह से? मेरे तो समझ में नहीं आ रही है कि हम शिक्षा को किस ओर ले जा रहे हैं?

(16.00 बजे)

मैं तो सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। बाड़मेर जिले की बात करके आपको बताऊंगा कि तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के 6,000 पद रिक्त हैं। अब अच्छी पढ़ाई कैसे होगी, आप ही सोच लो। मेरे से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी कह रहे थे कि पांचवीं में एक अध्यापक है। 8वीं कक्षा में भी दो हैं और कई तो ऐसी स्कूलें हैं जिनमें सिर्फ आठवीं कक्षा की स्कूलों में भी एक अध्यापक है। आप अब इस स्तर को सुधारोगे। कैसे सुधारोगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। आज कम से कम हम बालिकाओं की तो सोचें। बाड़मेर में 27 स्कूलें बंद कर दी जिनमें 21 मिडिल और 6 प्राइमरी बच्चियों की हैं। कम से कम बच्चियों पर तो तरस खाते। बच्चियों के लिए स्कूल अपन जितने ज्यादा से ज्यादा खोलें और उनको शिक्षा देने का प्रयास करें, परंतु आपने उसको भी नहीं छोड़ा और आज बाकी पदों की बात करो। सैकण्ड ग्रेड के 1300 में से 753 पद रिक्त और थर्ड ग्रेड के 14 हजार स्वीकृत हैं, उनमें भी 6 हजार रिक्त। पीटीआई 753 में से 562 पद रिक्त। प्रबोधक स्वीकृत हैं 2500 और उसमें 238 पद रिक्त हैं। प्रारंभिक शिक्षा में 1300 विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 75 पद स्वीकृत हैं उनमें भी 25 रिक्त हैं। अब कौन उन स्कूलों में सफाई करे? कौन, क्या व्यवस्था होगी? आप खुद ही इस शिक्षा के स्तर को देख लो।

अब आप मिडिल स्कूलों की बात करो तो आठवीं की स्कूलों में 392 प्रधानाचार्यों में से 200 पद रिक्त हैं। अब बताओ, स्तर बढ़ेगा?

(श्री मेवाराम जैन)

सैकण्डरी विद्यालय में एचएम के 178 पद हैं जिनमें 72 खाली हैं। व्याख्याताओं के 1700 पद हैं जिनमें 650 रिक्त। वरिष्ठ अध्यापक 3046 पद हैं उनमें 685 रिक्त। शारीरिक शिक्षक ग्रेड 4 हैं, 4 ही खाली। अब आप हिसाब लगाओ कि शिक्षा को हम कैसे ऊपर ले जाएंगे और किस तरह से बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे? आप खुद देख रहे हैं और तीन वर्षों में उत्कृष्ट और आदर्श विद्यालय के नाम पर बड़ी-बड़ी अपन बातें तो कर रहे हैं और सुविधाओं की बातें कर रहे हैं अब वो सुविधाएं अपन क्या दे रहे हैं? उन स्कूलों का हाल देखो। वहां विद्यालय में क्या हो रहा है। अभी तक बिजली के कनेक्शन नहीं, पानी का अता-पता नहीं और मैं तो यह कह रहा हूं कि टॉयलेट भी बने हुए हैं तो क्या हालत है उनकी? उनके अन्दर कोई जा नहीं सकता है, ये हालात हैं उन विद्यालयों की। आज एकीकरण के नाम से दो सौ विद्यालय बंद कर दिये सिर्फ बाड़मेर जिले के। अब वो बंद क्यों की?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अब आप इसमें देखें, एकीकरण के नाम से दो सौ स्कूलें सिर्फ बाड़मेर में बंद की और साढ़े सत्रह हजार पूरे राजस्थान में की और बीस हजार के करीब कुल बंद करने आप जा रहे हो। अब बंद आपने की, आपने पहले यह सोचा ही नहीं कि जिस विद्यालय में अध्यापक नहीं, तो बच्चे कहां से पढ़ेगे? आप अध्यापक लगाते और बच्चों को उसमें प्रवेश दिलाये, जितना एकीकरण में बंद करने का प्रयास किया, उतना बच्चों को उस स्कूल में प्रवेश का अगर प्रयास करते तो ये स्कूलें बंद नहीं करनी पड़ती और वे गरीब बच्चे पढ़ते, पढ़ाई से वंचित नहीं रहते। यह आपने राजस्थान की जनता के साथ भारी कुठाराघात किया है।

माननीय सभापति महोदय, आज नामांकन बढ़ने की बात कर रहे हैं कि हमारे इस एकीकरण से नामांकन बढ़े। एक साथ बढ़े होंगे, पर आपने पता किया क्या कि एक बाड़मेर जिले में वापस दस हजार नाम कम हो गये। प्राइवेट स्कूलों में चले गये। यह भी आप पता कर लो, पहले तो इसमें आपने नाम एड करा दिये और वापस वो प्राइवेट में चले गये। यह भी आप पता करके देख लो।

आज कंप्यूटर शिक्षा की बात करें अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने यह

(श्री मेवाराम जैन)

बात की कि कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए आप गरीब बच्चे से 960 रुपये ले रहे हो। एक विद्यालय में कम से कम ढाई-तीन लाख रुपये बनते हैं और वो एनजीओ को दे रहे हो। पूरे राजस्थान का ठेका एक एनजीओ को दे रखा है।

श्री सभापति: थोड़ा फास्ट करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): साहब, इतना वो बोले तो कम से कम थोड़ा मुझे भी तो बोलने दो। अब एनजीओ को, सिर्फ उन एनजीओ को लाभ पहुंचाने के लिए यह किया जा रहा है जबकि क्या अपने यहां पढ़े-लिखे नहीं हैं? उस कंप्यूटर शिक्षा में अगर वहीं का लोकल लग जाता तो एनजीओ को इतने पैसे नहीं देने पड़ते। अगर देने पड़ते हैं तो सरकार दे। अब पैसे तो उन बच्चों के गरीब माता-पिता से लेते हैं और फिर निहाल उनको कर रहे हैं। अब वो शिक्षा कैसी देंगे वो आपके सामने है।

अब वो एक नया किया कि एक पंचायत में प्रिसिपल को पूरे अधिकार दे दो। दे दो अधिकार। अब हालात क्या है? अब स्कूल में प्राइमरी हो, मिडिल हो, उनमें एक-एक, दो-दो अध्यापक और उसमें मिड-डे मील वो चलाये। ठेकेदारी का काम और करा दिया आपने। जितने कंस्ट्रक्शन हुए हैं वो भी काम आपने अध्यापकों को दे दिया। बीएलओ का काम भी ये करेंगे। डाक पहुंचाने का काम ये करेंगे। अब ये बताओ कि बच्चों को पढ़ाएगा कौन? ये तो इन कामों के लिए आने-जाने में ही लगा रहेगा, बच्चों की शिक्षा का स्तर कैसे आप बढ़ाओगे? इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हो, मनन नहीं कर रहे हो। सिर्फ कांग्रेस-बीजेपी की अभी बात कर रहे थे। छाती ठोक-ठोक कर बात कर रहे थे कि आपने बंटाधार किया। हमने किया पर आप तो सुधारो। ये जो बातें कह रहा हूं, उसमें कोई फर्क है तो बताओ कि ये हालात हैं। एक और दो अध्यापक हैं और उस एक के पास इतना काम दे रखा है वो पढ़ाई करायेगा कैसे। यह तो आप बताओ। ...(व्यवधान)...

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): चलो, यह तो स्वीकार कर लिया न आपने कि आपने बंटाधार किया।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अब मैं और भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज संस्कृत स्कूलों की भी यही हालत है। उनमें बिलकुल स्टाफ नहीं है और आपने ट्रांसफर पोस्टिंग में एकीकरण के नाम से, समानीकरण के नाम से

(श्री मेवाराम जैन)

जितनी चाही कर दी, कोई बात नहीं जबकि शिक्षा में होना तो यह चाहिए कि इसमें राजनीति नहीं हो।

अब मैं तो एक उदाहरण देना चाह रहा था। एक एससी का विरारा में अध्यापक था, वह कैन्सर से पीड़ित। अहमदाबाद में दो महीने से अस्पताल में इलाज करा रहा था। कीमोथैरेपी हो रही थी, उसकी ट्रांसफर कर दी बाड़मेर से डेढ़ सौ किलोमीटर दूर। अब ऐसे आदमी को तो कम से कम छोड़ना चाहिए। ये तो मंत्रीजी दया रखते। ऐसे कैन्सर पीड़ित पर तो कम से कम आप दया करते। बाकी तो आप भले ही कुछ करो। जो करना हो वो करो।

आज पंचायत समिति का पुनर्गठन हो गया और उस पुनर्गठन में ब्लॉक भी उसी पंचायत समिति का होना चाहिए। अभी भी उस ब्लॉक के 3-3,4-4 टुकड़े हैं। आज बाड़मेर ब्लॉक की मैं बात करूं तो पंचायत समिति का एरिया, एक तहसील एक, एसडीएम का एक, फिर भी अभी तक तीन भागों में बीईओ लग रहे हैं। जब ब्लॉक एक हो गया तो बीईओ एक को दो न, ताकि वो संभाल सके। आठ पंचायतें बायतू के पास, दस पंचायतें सिणधरी के पास। इस तरह से अलग-अलग ये हैं, आप दो साल में भी उस ब्लॉक को ठीक नहीं कर पाये। ये सारे अधिकार तो कम से कम एक जगह दो। अब मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा।

माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा की बात करूंगा। 207 प्राचार्य हैं, उनमें 56 पद रिक्त हैं। व्याख्याता 6086 में 2263 पद रिक्त हैं। अब इन हालात में किस तरह से शिक्षा का आप सोच सकते हो कि शिक्षा अच्छी हो सकती है। इस मौक़े पर मैं तो यही कहूंगा कि हम सबको सोचना होगा कि इसको कैसे हम ठीक करें।

कला और संस्कृति के बारे में मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि राजस्थान की कला और संस्कृति में ख्याति दिलाने वाले जो मंगणियार, लंगा आदि कास्ट हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपने भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व में अपनी छाप छोड़ी है। इनके लिए अपन उनको किस तरह से और आगे बढ़ायें, उनका शैक्षणिक विकास, कला संवर्द्धन आदि किस तरह से अपन करें, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको कैसे आगे बढ़ायें, इस बारे में भी हमें प्रयास प्रयास करने चाहिए और किस तरह से ये संस्कृति जीवित रहे और आगे बढ़े, ये प्रयास करने चाहिए।

श्री सभापति: कृपया पूरा करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था। जो हम यहां बातें कर रहे थे कि पार्टी से ऊपर उठकर हमें शिक्षा पर विचार करना चाहिये। सारे पद खाली पड़े हैं। इस तरह की शिक्षा है। विद्यार्थी मित्र की बात आप कर रहे थे, पैराटीचर्स हैं, प्रबोधक हैं, यह सारे जिनकी बात अपन कर रहे हैं, आपने खाली आश्वासन ही दिया। किया क्या? भर्ती एक की नहीं की।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ भाषणबाजी मत करो, प्रवचन मत दो, शिक्षा के लिये कुछ करो ताकि देश का भविष्य बन सके, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्या अलका सिंह जी। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि समय की मर्यादा को ध्यान में रखें। 22 सदस्य अभी बोलने वाले हैं, इसलिए आसन को घंटी बजाने के लिये मजबूर नहीं करें।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-24, शिक्षा कला व संस्कृति में आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत बहुत आभारी हूं। सभापति महोदय, शिक्षा व्यक्ति को समृद्ध करती है और स्वयं को और दूसरों को समझने में सहायक होती है। शिक्षा रचनात्मकता और उत्पादकता में वृद्धि करती है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय 8 परसेंट साक्षरता दर थी जो आज बढ़कर 66 परसेंट हो गई है। राजस्थान में पुरुषों में पूरे राष्ट्र का 27 परसेंट है और महिलाओं में 35वां स्थान है। मतलब शिक्षा की दृष्टि से हमारे राज्य की स्थिति बहुत ही सुधार करने लायक है। पूर्ववर्ती सरकार के समय शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं किया गया। न तो विद्यालयों की व्यवस्था सुधारने का काम किया, न शिक्षकों के लिये एप्रेजल या शिक्षकों को इस तरह का प्रोत्साहन दिया गया कि वह काम कर सके और शिक्षा दिला सके, ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। न ही स्कूलों के भवन सुधारने का काम किया गया। हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, जब हमारी सरकार आई उसके पश्चात् शिक्षा में गुणात्मक

(श्रीमती अलका सिंह)

सुधार करने के कदमों की शुरूआत की। आज एकीकरण किया गया, हमारे जो विपक्षी सदस्य हैं वे बार बार कहते हैं कि एकीकरण करके स्कूल बंद कर दिये गये। उनकी जानकारी के लिये बताना चाहूंगी कि स्कूल बंद नहीं हुए हैं, स्कूल मर्ज हुए हैं। जहां एक-एक, दो-दो विद्यार्थी थे और दो-दो शिक्षक थे, जहां हमारे काम करने की जरूरत थी, जहां विद्यार्थियों को अध्ययन की जरूरत थी, वहां आसपास के जो बडे स्कूल हैं, उनमें उनको मर्ज किया गया, एकीकरण किया गया ताकि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा विद्यार्थियों को उपलब्ध हो सके। इसके अलावा समानीकरण किया गया। हमारी सरकार की सबसे बडी उपलब्धि है कि प्रिंसिपल्स के प्रमोशंस किये गये। 15 साल से जो प्रमोशंस नहीं हुए थे और उसकी वजह से शिक्षा में रुकावट सी आ गई थी, उस रुकावट को दूर किया। प्रिंसिपल्स के प्रमोशंस हुए, भर्तियां हुईं। इसी का परिणाम है कि शिक्षकों की उपलब्धता कांग्रेस के समय में 49 परसेंट थी जो हमारे समय में बढकर 75 परसेंट हो गई है। पदोन्नति के फलस्वरूप प्रधानाचार्यों के रिक्त पद कांग्रेस के समय पर 52 परसेंट थे, जो आज सिर्फ 11 परसेंट रह गये हैं। माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद हैं, उनमें कांग्रेस के समय में 61 परसेंट रिक्तियां थीं, आज वहां 0 परसेंट रिक्तियां हैं। माननीय सभापति महोदय, यह विजन का फर्क है। हमारी सरकार, देश के भविष्य जो हमारे नौनिहाल हैं उनको गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिये कटिबद्ध है। यह हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी का विजन है और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस ने पूरे पाँच साल में 4435 विद्यालय क्रमोन्नत किये और हमने तीन साल में 9435 विद्यालयों को क्रमोन्नत कर दिया है।

सभापति महोदय, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के दो ही पैरामीटर्स होते हैं। अगर शिक्षा अच्छी है तो परिणाम बेहतर होंगे, स्कूल के रिजल्ट अच्छे आयेंगे। दूसरा है, नामांकन में वृद्धि। दोनों ही पक्षों में गुणवत्ता में सुधार के परिणामस्वरूप रिजल्ट में सुधार आया है। पहले 57 परसेंट था, आज 72 परसेंट है। विद्यार्थियों के नामांकन 2013-14 में 28.24लाख विद्यार्थी थे, आज 43.85 लाख है, करीब डेढ़ गुणा ज्यादा। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि पूरे देश में राजकीय विद्यालयों में जो नामांकन बढ़ा है वह बढ़ाने वाला अकेला राज्य राजस्थान है और देश के

(श्रीमती अलका सिंह)

किसी भी राज्य में राजकीय विद्यालयों में बच्चों का इतना नामांकन नहीं बढा है।

इसके अतिरिक्त स्टाफिंग पैटर्न लागू किया, बच्चों की संख्या के आधार पर टीचर्स की नियुक्ति की गई ताकि शिक्षा का स्तर सुधरे और जहां जरूरत है, वहां अध्यापक लगाये जाये। सभापति महोदय, हमारे यहां मैकाले की शिक्षा पद्धति चली आ रही थी और उसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि हम बाबू पैदा करते रहें। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा या रोजगारपरक शिक्षा बिलकुल भी नहीं दी जाती थी। हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी का यह विजन है, जो हमारे स्कूल हैं 670 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की है। 11 ट्रेड आरंभ किये हैं ताकि स्कूली शिक्षा के पश्चात् भी अगर बच्चा चाहे तो कोई भी रोजगार अपने स्तर पर कर सके। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस बजट में घोषणा की है कि 50 और विद्यालयों में इस तरह की व्यावसायिक शिक्षा आरंभ की जायेगी।

सभापति महोदय, अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य बच्चियों की शिक्षा के बारे में बोल रहे थे। बच्चियों की शिक्षा की जहां तक हम बात करें, बालिका विद्यालय के लिये पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा कुछ भी काम नहीं किया गया था। हमारी सरकार ने बच्चियों के लिये एजुकेशन फ्री की है। बहुत छोटी-सी बात बताना चाहूंगी। 9वीं की सारी बच्चियों को साइकिल दी जाती है। कांग्रेस के समय में 2500-2500 रुपये बांट दिये जाते थे। पहली बात तो 2500 रुपये में साइकिल नहीं आती। दूसरा, जब आप कैश देते हैं तो पैरेंट्स या भाई जो भी होते हैं, वह उस पैसे को ले जाते हैं। हमने शुरुआत की और आज 5.36 लाख साइकिल हम बच्चियों को बांट चुके हैं।

बालिका शिक्षा में इनकी गंभीरता का एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूंगी। हम बसंत पंचमी पर जो मैरिटोरियस बच्चियां होती हैं उनको गार्गी पुरस्कार दिया करते हैं। 2013 में कोटा में इन्होंने गार्गी पुरस्कार के चैक बांटे थे। उनमें से 365 चैक जो कि मैरिटोरियस बच्चियों को दिये गये थे, वे बाउंस हो गये थे। यह बालिका शिक्षा के बारे में पूर्ववर्ती सरकार की गंभीरता है। यह एक आइना है जो मैं इनको दिखाना चाह रही थी। इसके अतिरिक्त जो केन्द्र से पैसा आता था, उसका बजट भी आज तक पूर्ववर्ती सरकार खर्च

(श्रीमती अलका सिंह)

नहीं कर पाई कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में। यह उस सरकार की एक बहुत ही बड़ी कमजोरी है। हम तीन वर्षों में 89 हजार 339 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार से पुरस्कृत कर चुके हैं। ''आपकी बेटी योजना'' में प्रोत्साहन राशि हम 74 हजार 923 छात्राओं को दे चुके हैं। बालिकाओं के लिये मुख्य मंत्री राजश्री योजना चालू की है। उसमें बालिका के जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की होने तक एजुकेशन के हिसाब से 51 हजार रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। यह फर्क है शिक्षा में सुधार की उम्मीद का और हमारी मुख्य मंत्रीजी की सोच का।

डिजिटलाइजेशन की बात करें तो शिक्षा विभाग में पूर्णत: डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है। ''शाला पोर्टल'' में सारे विद्यालयों की ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध हो जाती है। इसके अतिरिक्त ''राजकीय ज्ञान पोर्टल'', पहली से 12वीं तक के बच्चों की, अगर वहां से बच्चे शिक्षण सामग्री देना चाहें तो पूरी शिक्षण सामग्री उस पोर्टल पर उपलब्ध है। ''शिक्षा समाधान पोर्टल'' जिसमें माननीय मंत्री महोदय से अगर किसी कर्मचारी को किसी तरह की कोई ग्रिवेन्स है तो सम्पर्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त आम जन अगर अपने कोई सुझाव शिक्षा के संबंध में देना चाहे तो उस पोर्टल के माध्यम से दे सकता है। इसके अतिरिक्त ''छात्रवृत्ति पोर्टल'', पूर्ववर्ती सरकार के समय जो बच्चों को स्कूलों में छात्रवृत्ति दी जाती थी, उसका कुछ पैसा काट लिया जाता था या वहां जो भी बाबू वगैरह होते थे, वे भ्रष्टाचार करते थे। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था की गई है कि ऑनलाइन आज पूरी डिटेल पोर्टल पर डाल दीजिए, बच्चे के एकांउट में पूरा पैसा पहुंच जाता है।

सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी अभी यहां नहीं है। मैं एक बात मिड-डे-मील के बारे में कहना चाहती हूं। जैसाकि हमारे शेरगढ़ से आने वाले विधायक ने भी कहा था, मिड-डे-मील में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। नामांकन के समय संख्या कुछ होती है और जब वह एग्जाम में एपीयर होते हैं, वह संख्या अलग होती है। यह जो बीच का गैप है, यह भ्रष्टाचार का सबसे जीता-जागता सबूत होता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह कहना चाहूंगी कि 10-15 परसेंट तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही गैप आ जाता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा गैप है तो उसकी जांच करवाई जाए और अगले

(श्रीमती अलका सिंह)

वर्ष जो फंड दिया जाता है या मिड-डे-मील की योजना के अंतर्गत जो व्यवस्था की जाती है, वह पैसा उसमें से काट कर दिया जाए।

सभापति महोदय, आज सबसे ज्यादा जरूरत नैतिक शिक्षा की है। हमारे गुरुकुल के समय शिक्षा के पहले दीक्षा दी जाती थी। दीक्षा का मतलब, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा इतिहास और हमारा जो देश है, उसकी वास्तविक जानकारी बच्चों को दी जाती थी, लेकिन मैकाले की शिक्षा पद्धति ने इस बात पर फोकस कर दिया कि "How to earn money?" सिर्फ पैसा पैदा करना और जिस वजह से आज नैतिक मूल्यों की गिरावट आई है, इंजीनियरिंग के बच्चे चोरी कर रहे हैं। आप मालवीय नगर की तरफ जाइये। कई केसेज आते हैं। मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज या आस-पास कॉलेजेज के बच्चे हैं, वे छोटी-मोटी लूट करते हैं। अभी तीन दिन पहले पेपर में पढ़ा था, बहुत सीनियर ऑफिसर्स भी वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। यह संस्कृति निश्चित रूप से हमारी नहीं है और न ही हिंदुस्तान के संस्कार हैं। यह हमारे एजुकेशनल सिस्टम की कमी है। मैं यह अपील करना चाहती हूं और यह सुझाव देना चाहती हूं कि जो गुरुकुल के समय किया जाता था, शिक्षा से पहले दीक्षा, उसका पालन किया जाए। विद्यार्थी के लिए एक नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम जरूर हो, जिसमें जो देश के वीर हैं, जो महापुरुष हैं, उनकी जीवनी हो। हमारे देश का वास्तविक इतिहास और हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम पढ़ाया जाए ताकि हमारे भारत के लिए जो स्वाभिमान माननीय मोदीजी ने पैदा किया है, वैसा ही हमारे बच्चे भी स्वाभिमान के साथ कह सकें कि भारत महान था ही नहीं, भारत महान है और रहेगा।

अब मैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगी। मेरे विधान सभा में एक नव गठित पंचायत खेड़ी है। उसमें एक स्कूल खेड़ा है, जो कि 1982 से है। उसको क्रमोन्नत किया जाए। पिछली बार जब सारे विद्यालय क्रमोन्नत हुए थे, उसमें एक विद्यालय टीचूपाड़ा खुर्द रह गया था, उसको भी क्रमोन्नत किया जाए। इसी तरह गुढ़ा कटला, पुंदरपाड़ा, भड़ियाल, बिवाई और आभानेरी क़स्बे हैं, वहां पर विज्ञान विषय के साथ-साथ कृषि विज्ञान विषय भी चालू किया जाए। एक चांदेरा पंचायत है, जहां जमीन अलॉट हो चुकी है, लेकिन विद्यालय भवन का पैसा अभी भी नहीं आया है। मैं तो माननीय

(श्रीमती अलका सिंह)

मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि जहां जमीन अलॉट हो चुकी है, वहां पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल के भवन की जल्दी ही स्वीकृति दे दी जाए, क्योंकि यह स्कूल टिन-शेड के अंदर चलता है। उसमें काफी बच्चे हैं और बच्चों को इस वजह से बहुत परेशानी होती है। इसके अतिरिक्त दौसा जिले की सभी विधान सभा क्षेत्रों में तीन विद्यालय, विवेकानंद मॉडल स्कूल के माडा योजना के अंतर्गत और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में इस तरह का एक भी विद्यालय नहीं है, तो वह विद्यालय भी वहां आरंभ किया जाए।

उच्च शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगी। मेरे पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। हमारी सरकार बालिका को शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध है और बालिका शिक्षा फ्री है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक महिला महाविद्यालय है, जो कि स्ववित्तपोषित है। उसके एकाउंट में 80 लाख रुपए हैं। भवन कम्पलीट है, संसाधन कम्पलीट हैं और उसके सरकारीकरण करने की मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदया से पुरज़ोर तरीके से मांग करना चाहूंगी ताकि कम पैसे में बालिकाओं को शिक्षा देने का जो हमने संकल्प किया है, वह पूरा हो सके और बालिकाओं को शिक्षा सुगम हो सके।

इसके अतिरिक्त मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक राजेश पायलट महाविद्यालय है, जहां पोस्ट ग्रेजुएशन में विज्ञान और हिन्दी विषय स्ववित्तपोषित स्कीम के अंतर्गत चलते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, काफी पिछड़े व गरीब घरों के बच्चे हैं। उनके लिए यह फीस बहुत ज्यादा हो जाती है। वहां विज्ञान का पूरा लैब है, टीचर्स पूरे हैं। सिर्फ सरकारीकरण की घोषणा कर दी जाए तो उनको फायदा जो जाएगा कि फीस में उनको रिबेट मिल जाएगी। मैं यही एक निवेदन करना चाहूंगी।

सभापति महोदय, सरकार कोई भी हो। कांग्रेस की हो चाहें, बीजेपी की हो। सरकारें शिक्षण संस्थाओं को सरकारी जमीन अलॉट करती हैं। जब जमीन अलॉट करती है तो उस समय एक क्लॉज जरूर होता है क्योंकि जब जमीन नॉमिनल कीमत पर दी जाती है, उसके पीछे यही उद्देश्य होता है कि जो शिक्षा है, वह आम गरीब बच्चे को उपलब्ध हो सके।

(श्रीमती अलका सिंह)

मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। ऐसी बहुत-सी संस्थाएं होंगी, मेरे पास सिर्फ एक उदाहरण है। एक गीतांजली कॉलेज है, जो किउदयपुर में है। जो लैंड की कीमत थी, उसके 35 परसेंट कीमत पर उनको जमीन अलॉट की गई और उस डीड में एक क्लॉज डाला गया कि जो एडमिशंस होंगे उनमें से आठ परसेंट एडमिशन राज्य सरकार और उदयपुर विकास न्यास की सिफारिश पर होंगे। उस कालेज को चलते हुए आठ-नौ वर्ष हो चुके हैं। एक भी बच्चा सरकार के द्वारा नोमिनेटेड वहां नहीं पहुंचा है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस पाँच मिनट लूंगी। मैं इसके बारे में यह कहना चाहूंगी। यह सारा सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। इसमें जो भी अधिकारी दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और इन आठ वर्षों में उस कॉलेज में जिन-जिन बच्चों से जितना पैसा मैनेजमेंट कोटे के नाम पर लेकर उनको एडमिशन दिया है, वह सारा पैसा वसूला जाए और राजस्थान की शिक्षा पर खर्च किया जाए।

माननीय शंकर जी यहां बैठे हैं। दौसा से विधायक हैं। इनकी भी एक सिफारिश है और मेरी सिफारिश साथ में हैं, क्योंकि मैं भी दौसा जिले से ही हूं। दौसा जिले के कॉलेज में विषय खोले जाएं क्योंकि वह जिले का एकमात्र बड़ा कॉलेज है, जहां पूरे जिले के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं।

अब मैं कला और संस्कृति के बारे में कहना चाहूंगी। मैं आभानेरी के बारे में बार-बार रिपीट करती हूं। आभानेरी मेरे विधान सभा क्षेत्र का यू.एस.पी. है। वहां बहुत पुरामहत्व की बावड़ियां हैं और यूनेस्को का प्रोटक्टेड मोन्यूमेंट है। यहां बैठे सभी माननीय सदस्य हवाई यात्राएं करते रहते हैं। जो इंडिगो की इन-फ्लाइट मैगजीन है, उसके अंदर आभानेरी की फोटो है और उसको राजस्थान का एक ट्यूरिस्ट अट्रेक्शन बताया जाता है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी और सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगी कि जैसे अभी एक ट्यूरिज्म का एक क्वेश्चन आया था। तब भी मुझे आश्वासन दिया था कि बांदीकुई में आभानेरी के लिए स्पेशल बसें चला दी जाएंगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि जयपुर-दिल्ली-आगरा एक ट्रेवल सर्किट है, उसके बीच में आभानेरी आता है। जब आभानेरी उत्सव होता है, उस समय स्पेशली दो-तीन बसें और चला दी जाएं।

(श्रीमती अलका सिंह)

इसके अतिरिक्त मेरे विधान सभा क्षेत्र में झाझीरामपुरा एक स्थान है, वहां भी बावड़ियां हैं और वहां पर गोमुख है, जिससे 365 दिन, 24 घंटे गरम पानी आता है। कहते हैं कि स्किन डिजीजेज वहां ठीक हो जाती हैं, तो उस क्षेत्र को भी विकसित किया जाए।

राणा सांगा के बारे में कहा जाता है कि उनकी मृत्यु बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र की बसवा तहसील में हुई है। वहां आम जन के सहयोग से राणा सांगा की स्टेच्यू लगाई गई है, जो कि महाराणा मेवाड़ की प्रोपर्टी है। लेकिन अगर सरकार उनसे बात करे तो उसको भी विकसित किया जा सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन पुरामहत्व की चीजों पर ध्यान दिया जाए ताकि रेवेन्यू बढ़े। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हरिसिंह जी रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, आज आपने मांग संख्या - 24 (शिक्षा, कला एवं संस्कृति) के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मुझे समय दिया। उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। सभापति महोदय, आज शिक्षा के संबंध में हमारे पक्ष और विपक्ष के वक्ताओं ने अपने-अपने विचार रखे और इस संबंध में मैं भी अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं।

किसी जमाने में कहते थे कि हमारा भारतवर्ष विश्वगुरु था। अगर इस 'विश्वगुरु था' को 'विश्वगुरु है' में परिवर्तन करना है तो हमें इस शिक्षा पद्धति में बहुत कुछ आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। कहते हैं “education is the gateway to the progress of our life” हमारी संस्कृति और हमारे इस युग को परिवर्तित करना है तो हमें शिक्षा को महत्व देना पड़ेगा और उसी दृष्टि से हमारी सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने पाँच साल तक शासन किया लेकिन उन्होंने ना कोई स्कूल खोली ना ही क्रमोन्नत की और ना ही शिक्षकों की कोई भर्ती की, जिसकी वजह से पाँच साल तक हम शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ गए।

मैं हमारी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने प्रथम वर्ष में ही शिक्षा को महत्व देने के लिए आमूलचूल परिवर्तन किया। पूर्व में हमारे कई विधायक, सांसद, जन प्रतिनिधि, गांवों से गाड़ियां भर-भर कर आते थे

(श्री हरिसिंह रावत)
कि हमारे यहां स्कूल खोलो। लेकिन हमारी मुख्य मंत्रीजी ने कभी किसी को परेशान नहीं किया। हर ग्राम पंचायत मुख्यालय में सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोली। मैं समझता हूं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए जहां शिक्षकों की कमी थी वहां शिक्षक लगाए। जहां पर प्राचार्य की कमी थी वहां प्राचार्य लगाए। जहां व्याख्याता की कमी थी वहां व्याख्याता लगाए। उसी के अनुसार हमारी सरकार ने शिक्षा की दृष्टि से कॉलेज खोले। कॉलेजों में जहां-जहां भी जो कमी थी वह पूरी की। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने शिक्षा की दृष्टि से कैसा बेडा गर्क किया और उन्होंने राइट टू एजुकेशन लगाया। राइट टू एजुकेशन कैसा कि हमारा बच्चा पढ़े या नहीं पढ़े उसको आठवीं में पास कर दो। शिक्षक भी मस्त, बच्चा भी मस्त। बच्चों को क्या पता कि मेरा भविष्य क्या है। लेकिन जब वह बच्चा आठवीं पास करके नवीं में जाता है। ना ही तो वह पढ़ा है ना ही लिखा है, वह सीधा फेल हो जाता है। अगर बच्चा फेल होगा तो क्या करेगा? वह स्कूल नहीं जाएगा। पास नहीं होगा तो वह आवारागर्दी करेगा। रोड पर उठा-पटक करेगा? कहीं चैन स्नेचिंग करेगा, कहीं मोटर साइकिल चोरी करेगा। कांग्रेस सरकार क्योंकि यही चाहती थी कि इस देश, इस राष्ट्र का नागरिक, गांव का रहने वाला अनपढ़ रहे, गंवार रहे ताकि फिर हम उसको गुलाम कर सकें और उस पर राज कर सकें। मैं हमारे देश और राष्ट्र की जनता को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने नरेन्द्र भाई मोदी को देश का प्रधान मंत्री बनाया। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं करें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): प्रधान मंत्री बनाने के बाद उन्होंने क्या परिवर्तन किए, वह जग जाहिर है। श्रवण जी आपको इसमें कहने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया जानती है, आपने अभी यूपी का रिजल्ट भी देख लिया और आने वाला रिजल्ट भी देख लेना।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पंजाब को याद क्यों नहीं कर रहे हो। पंजाब को भी याद करो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं करें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): आपको एक कटोरा क्या मिल गया, उसी को बजाए फिर रहे हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन को संबोधित करें।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): जिसकी जो मर्जी है वह याद करेगा।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): पंजाब क्या है, पंजाब कुछ भी नहीं है, छोटा सा है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन को संबोधित करें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): और पंजाब भी आया तो आपके भरोसे नहीं आया, यह भी ध्यान रखना। हमारे माननीया मुख्य मंत्रीजी की पहल पर राजस्थान में सबसे पहले विद्यालयों में शौचालयों की व्यवस्था कराई। राजस्थान के सभी विद्यालयों में बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था कराई। विद्यालयों की स्वच्छता एवं नियमित सफाई के लिए प्रति विद्यालय पांच हजार रुपये वार्षिक दिए जाने का प्रावधान भी किया। उसके पूर्व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 13वें पायदान पर था, आज राजस्थान प्रथम पायदान पर है, यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। शिक्षा नीति में तकनीकी क्षेत्र में देश में सबसे आगे हैं। राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि में आज अकेला हमारा राज्य है, यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है।

सभापति महोदय, हमारे सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ी है। और कैसे बढ़े इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि हमारे सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा-दीक्षा मिले, इसके लिए एक राइडर लगाना चाहिए। अधिकारी-कर्मचारी या जो भी हमें राय देता है इस पर राइडर लगे कि कोई भी अपना बच्चा, पोता-पोती प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाएगा। वह सरकारी स्कूल में पढ़ाए। जितने भी हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो इससे संबंध रखते हैं वह आटोमेटिक गुणवत्तापूर्ण कार्य करेंगे। हमारे सरकारी ग्रामीण स्कूल का अच्छा विकास हो सकेगा। हम तो बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाएं और बाकी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें।

मुझे एक बात याद आई। हाइवे पर एक ढ़ाबा था। उस ढाबे पर एक व्यक्ति गया, व्यक्ति ने कहा कि मुझे एक लस्सी पिला दो। उसने लस्सी पी, लस्सी पीते-पीते बोला, इधर आ, यह कैसी लस्सी बनाई है? सेठ को बुलाओ।

(श्री हरिसिंह रावत)

वह बोला, मेरा सेठ तो पड़ौस की दुकान पर लस्सी पी रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर ग्रामीण स्कूल गुणवत्तापूर्ण होंगी, हमारे अधिकारी-कर्मचारियों को बाडंड करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारी शिक्षा पद्धति में रातों-रात विकास होगा और हमारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी।

सभापति महोदय, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। इसमें ''मुख्य मंत्री राजश्री योजना'', इसके अन्तर्गत भी, हमारे पूर्व वक्ता ने बताया था, मैं भी इसमें प्रकाश डालना चाहता हूं। इस योजना के अन्तर्गत प्रथम जून के बाद जो बच्ची जन्म लेगी, उसको इसका लाभ मिलेगा। इसका लाभ कैसे मिलेगा। जून लास्ट के बाद जन्म लेने वाली बालिका का जन्म एवं उसकी वर्षगांठ पर 2500-2500 रुपये, राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर चार हजार रुपये, उसके बाद इसी योजनान्तर्गत बालिका शिक्षा को निरन्तर जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बालिका के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश करने पर पांच हजार रुपए और कक्षा 10 में 11 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसी योजना के अन्तर्गत राजकीय विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली बालिका को राज्य सरकार ओर से विभिन्न चरणों में 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। कितनी अच्छी हमारी सरकार की योजना है। नारी शिक्षा, हमारे-घर परिवार की एक बेटी पढ़ेगी। कहावत है न कि अगर एक बेटी पढ़ती है तो सात घर सुधरते हैं।

मेरा आपसे निवेदन है कि शिक्षा को महत्व देने के लिए हमारी सरकार की इस योजना का हम सभी को लाभ उठाना चाहिए। छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए गार्गी पुरस्कार द्वारा 92 हजार मेधावी बालिकाओं को लगभग 34 करोड़ रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई। गत वर्ष मेधावी विद्यार्थियों को लगभग 43 हजार लेपटाप एवं छात्राओं को 5 लाख 36 हजार साइकिल वितरित की गईं। वर्ष 2016-17 में लगभग तीन लाख छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल वितरण की जा रही है। 30 हजार बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही व्याख्याताओं एवं अन्य जो भी कर्मचारी हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जहां-जहां कमी है, जहां व्याख्याताओं का प्रमोशन है, वहां प्रमोशन दीजिए। जहां शिक्षकों की

(श्री हरिसिंह रावत)

कमी है वहां शिक्षकों की कमी पूर्ण कीजिए ताकि हमारी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ सके।

सभापति महोदय, हमारी सरकार में अंग्रेजी माध्यम को हमारे गांव के बच्चे कैसे पढ़े इसके लिए स्वामी विवेका नन्द मॉडल स्कूल खोली। इसमें प्रथम चरण में 66 मॉडल विद्यालय 2014-15 में, 5 मॉडल स्कूल 2015-16 में और 61 मॉडल स्कूल 2016-17 में। इस प्रकार हमारे क्षेत्र में ग्रामीण परिवेश के बच्चे-बच्चियों को इंग्लिश लेंग्वेज, कम्प्यूटर लेब के साथ यानी प्रोजेक्टर आदि शिक्षा भी इन स्कूलों में दी जा रही है।

सभापति महोदय, शिक्षा मित्रों की बहुत समस्या हो रही है। पूर्व में भी हमने कई कोशिश की लेकिन अभी हमारे शिक्षा मित्र वंचित रह रहे हैं। पंचायत समिति के माध्यम से लेने की हमारी सरकार ने घोषणा की है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विद्यार्थी मित्रों को प्राथमिकता से लें, ताकि जो ओवरएज हो चुके हैं, और दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, इन बच्चों को प्राथमिकता दी जाए।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं मेरे क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। मेरा क्षेत्र एक मगरा क्षेत्र है।

मगरा क्षेत्र में, विशेषकर मेरे भीम विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र, भीम विधान सभा क्षेत्र के लोग सेना में भर्ती होते हैं। सेना में जिला ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूं, उदयपुर सम्भाग में सबसे ज्यादा अगर सेना में भर्ती हैं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र से हैं। मैं चाहता हूं कि उन सैनिकों के बच्चों-बच्चियों की अच्छी एजुकेशन हो, उसके लिये हमारे भीम में सैनिक स्कूल की स्थापना होनी चाहिये। इसके लिये 30 बीघा जमीन हमने आलरेडी आबंटित कर रखी है। अगर सरकार सहयोग दे, केन्द्र सरकार के साथ मिलकर, अगर सैनिक स्कूल मेरे क्षेत्र में होगा तो हमारे बच्चे-बच्चियों का चहुंमुखी विकास होगा और वे सेना में जाने के लिये प्रोत्साहित होंगे।

इसके अलावा खेलकूद में प्रोत्साहन देने के लिये, जैसे झुंझुनूं में अभी बास्केट बाल की इन्होंने व्यवस्था की है। मैं समझता हूं कि हमारा देवगढ़ बास्केट बाल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जिला ही नहीं, राज्य ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय लेवल पर हमारे देवगढ़ के बच्चे-बच्चियां बास्केट बाल में अपने

(श्री हरिसिंह रावत)

खेल का प्रदर्शन कर चुके हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, बास्केट बाल को प्रोत्साहन देने के लिये प्रशिक्षण केन्द्र भी हमारे देवगढ़ में बनाया जाये ताकि हमारे बच्चे-बच्चियां खेलकूद में आगे बढ़ सकें।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ ही मैं मिड-डे मील की बात करूं। मिड-डे-मील में भी हमारे शिक्षकों को इस चीज से फ्री कर देना चाहिये। शिक्षक हमेशा आटा, दाल, लकड़ी, नमक, तेल के चक्कर में पड़े रहते हैं और बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, इसमें किसी एन.जी.ओ. के थ्रू यह मिड-डे-मील दिया जाये। जैसे अभी मिड-डे-मील बनाने के लिये जो महिला कार्यरत हैं, उनको हम एक हजार रुपये दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि उसका मानदेय बढ़ाया जाये ताकि जो महिलाएं हैं, जो कई तो विधवाएं होती हैं या परित्यकता होती हैं या एस.सी., एस.टी. की होती हैं, जिनको मैं समझता हूं हजार रुपये पर्याप्त नहीं हैं तो इसके लिये उनका मानदेय बढ़ाया जाये। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके अलावा कस्तूरबा गांधी विद्यालय की मैं बात करूं। सभापति महोदय, कस्तूरबा विद्यालय हमारा एक बहुत ही अच्छा विजन है। लेकिन इस कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियां कौन हैं। या तो अनाथ बच्चियां हैं या एस.सी., एस.टी. हैं या ओ.बी.सी. हैं, गरीब तबके की बच्चियां हैं। वे आठवीं तक तो पढ़ लेती हैं। लेकिन आठवीं के बाद वे वापस अपने घर चली जाती हैं, जिससे उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उन स्कूलों को आठवीं से लेकर बारहवीं तक क्रमोन्नत किया जाये। मैं समझता हूं कि इससे हमारी उन बच्चियों का भविष्य सुधरेगा और वे बच्चियां अपने पांवों पर खड़ी हो सकेंगी।

सभापति महोदय, मैं आगे न बढ़कर, सीधे मेरी कुछ स्कूलों के बारे में बात करना चाहूंगा। मेरा क्षेत्र एक मगरा क्षेत्र है और बिखरी हुई आबादी है। जो राइडर अभी हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने बताये कि 40 बच्चों पर हम एक स्कूल खोलेंगे। हमारी बिखरी हुई आबादी की वजह से, और चार-चार, पाँच-पाँच ग्रामों से मिलकर एक पंचायत बनती है, जिसकी दस-दस किलोमीटर की परिधि होती है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि यह राइडर खतम करके और जहां बच्चों की बहुलता है, वहां स्कूल खोले जाएं। प्राथमिक

(श्री हरिसिंह रावत)

विद्यालय या क्रमोन्नत करना है प्राथमिक को उच्च प्राथमिक में, उच्च प्राथमिक को माध्यमिक में, माध्यमिक से सीनियर सैकण्डरी में। जहां पर अभी हमारी नवीन ग्राम पंचायतें बनी हैं, वे हमारी दो, एक बिलियावास और एक डूंगाजी का गांव, उन पर भी हमारे सीनियर सैकण्डरी स्कूल की घोषणा करें क्योंकि वे लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, हमारे स्कूल कब बनेंगे। हमारी ग्राम पंचायत बन गयी लेकिन हमारे यहां पर स्कूल नहीं खुला है। इसका भी ध्यान रखें। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, अभी पाँच मिनट और दीजिये मेरे को।

मैं उच्च शिक्षा के मामले में कुछ बात करना चाहूंगा। प्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी मुख्य मंत्रीजी को कि मेरे भीम विधान सभा क्षेत्र में दो पंचायत समितियां हैं, दोनों में ही राजकीय महाविद्यालय खोल दिये। इसके लिये मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा और उच्च शिक्षा मंत्रीजी को भी। और उच्च शिक्षा मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे भीम राजकीय महाविद्यालय में साइंस और कॉमर्स फैकल्टी खोली जाये और...

श्री सभापति: कन्क्लूड करें माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, पाँच मिनट।

श्री सभापति: पाँच मिनट बहुत होते हैं।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): पी.जी. में क्रमोन्नत किया जाये। और दूसरा, हमारे यहां व्याख्याताओं की कमी है। आज व्याख्याताओं में खाली पद पड़े हैं। सात पदों में से केवल दो पद भरे हुए हैं और पाँच पद रिक्त हैं, उनको भरा जाये।

इसके अलावा राजसमंद जिले की बात करूं मेरे राजसमंद जिले में रेलमगरा और खमनोर, उच्च शिक्षा मंत्रीजी, आप भी उसी क्षेत्र से आती हैं, हमारे वहां राजसमंद में रेलमगरा और खमनोर में भी अगर राजकीय महाविद्यालय खुल जाये तो आपकी, हमारी सरकार की बड़ी महत्ती कृपा होगी। इसके साथ-साथ ही आमेट महाविद्यालय में भी व्याख्याताओं की कमी है।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सात स्वीकृत पदों में से केवल एक ही है, छह पद खाली हैं। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है, वहां भी जो पद रिक्त हैं, अगर उनको भर दिया जाये तो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा-दीक्षा मिलेगी। इसी के साथ, जय हिन्द, जय भारत, जय-जय राजस्थान।

श्री सभापति: धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पर पूरी बहस होकर और मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने एवं आज की मांगें स्वीकार होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

डा. मंजू बाघमार।

अनुदान की मांग

शिक्षा, कला एवं संस्कृति - मांग संख्या 24 पर विचार

डा. मंजू बाघमार (जायल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, माननीय मुख्य मंत्री महोदया और शिक्षा राज्य मंत्री महोदय को, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु आमूलचूल परिवर्तन किये और जो नवाचार किये, निश्चित रूप से वे शिक्षा क्षेत्र के अन्दर मील का पत्थर साबित होंगे।

माननीय सभापति महोदय, लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से शिक्षकों को उनके स्वयं के चुने हुए स्थान पर पदस्थापित किया गया। साथ ही साथ पिछले कई वर्षों से पदोन्नति को जो तरस रहे थे शिक्षक, उनको पदोन्नति का लाभ दिया गया। माननीय सभापति

(डा. मंजू बाघमार)

महोदय, हर दूसरे या तीसरे शिक्षक को इस पदोन्नति का लाभ दिया गया है। इसके लिये मैं माननीया मुख्य मंत्री महोदय का और शिक्षा मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी, मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल की ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय, दुग्स्वाओ, दुगौली, छापड़ा, सोमणा और लुणसरा, जिनमें नामांकन की संख्या करीब डेढ सौ से ज्यादा है, उनको माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की कृपा करें। कुछ विद्यालयों को प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय में और उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालयों में और कुछ में अतिरिक्त संकाय खुलवाने की स्वीकृति प्रदान करें। माननीय मंत्री महोदय, मैं उसकी सूची उपलब्ध करवा दूंगी।

इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, चावड़ा नगर में, जहां करीब डेढ सौ से ज्यादा विद्यार्थी हैं, वहां पर मैं उर्दू विषय खोलने की भी मांग रखती हूं। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगी, हमने हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक आदर्श विद्यालय खोला है। उसमें जो अनिवार्य विषय हैं अंग्रेजी और हिन्दी के, व्याख्याताओं के पद भी यदि उसमें सृजित किये जायेंगे तो, क्योंकि अभी तक वहां पर वरिष्ठ अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो इस विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक बेरोजगार युवाओं को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगी, मेरे विधान सभा क्षेत्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोध्यासी में लगभग 20 वर्षों से कला संकाय है। इस विद्यालय के अन्दर विज्ञान संकाय खोला जाये। नागौर से आने वाले हमारे विधायक महोदय ने भी एक डिमाण्ड रखी है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डिगोसी, नागौर की बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर अवस्था में हो रखी है और उसके प्रस्ताव भी माननीय मंत्री महोदय के पास भेजे जा चुके हैं। अत: बिल्डिंग निर्माण हेतु उसके लिये बजट आबंटन शीघ्र किया जाये।

(डा. मंजू बाघमार)

माननीय सभापति महोदय, मैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी, उच्च शिक्षा की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रणाली का विस्तार करना तो आवश्यक है लेकिन उसमें गुणवत्ता का सुधार किये बिना शिक्षा का विस्तार करने का लाभ हमें नहीं मिल पायेगा। हमें यह समझना चाहिये कि हमारे अधिकतर जो शिक्षण संस्थान हैं, वे अपेक्षित स्तर के नहीं हैं। उनमें से अधिकतर हाल के वर्षों में तेजी से हुए परिवर्तनों के अनुरूप बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। उनमें अभी भी ऐसे विषयों के स्नातक तैयार कर रहे हैं, जिनकी रोजगार बाजार में कोई भी मांग नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था और उसका एक गौरवपूर्ण अतीत रहा है। लेकिन विडंबना इस बात की है और यह गंभीर सोच का विषय है कि आज विश्व के 200 शीर्ष विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है, जो कि विश्व गुरु कहलाने के नाम पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है।

हमारे लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता सुधारना और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना तथा नकलों को रोकने के लिए एक गंभीर चुनौती है। हमारे कुलाधिपति महोदय इस दिशा में संकल्परत हैं और साथ ही साथ हमारी माननीया मुख्य मंत्री महोदया भी निरंतर इस दिशा में प्रयासरत है क्योंकि गुणवत्ता में सुधार लाए बिना शिक्षा के विस्तार को करने का कोई लाभ नहीं होगा।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीया मुख्य मंत्री महोदया को और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय को, जिन्होंने इस बजट सत्र में मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय जायल में विज्ञान संकाय खोला है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि उसमें गणित और जीव-विज्ञान दोनों विषयों को शामिल किया जाए। मैं यह भी बताना चाहूंगी कि मेरे राजकीय महाविद्यालय जायल के अंदर 375 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और कला संकाय भी उसमें है। लेकिन अभी वह केवल मात्र एक व्याख्याता के भरोसे चल रहा है। उसमें हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र के पद पूरे साल भर से रिक्त चले आ रहे हैं तो

(डा. मंजू बाघमार)

मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि इन पदों को शीघ्र ही भरा जाए।

साथ ही साथ, मेरा जो राजकीय महाविद्यालय जायल है वह 19 जनवरी को अपने नये भवन में शिफ्ट कर दिया गया है और हमारी सरकार ने इस विद्यालय के भवन निर्माण के लिए करीब तीन लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया था लेकिन अभी लाइब्रेरी, लैक्चर थियेटर और एक पूरी विंग का काम अधूरा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस कार्य हेतु दो करोड़ रुपये का और अतिरिक्त बजट आवंटित करने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगी, जिला मुख्यालय नागौर के ऊपर संचालित राजकीय माडीबाई मिर्धा महिला महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय के अंदर भामाशाहों द्वारा अपने प्रियजनों की स्मृति में प्रमुख प्रवेश द्वार एवं प्रवेश द्वार से कॉलेज तक सी.सी. सड़क निर्माण की सहमति प्रदान की गयी है। इस विषय में स्थानीय कॉलेज प्रशासन द्वारा कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय से भी स्वीकृति मांगी गयी है। अत: मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस कार्य को भामाशाह द्वारा निर्माण करवाये जाने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण करने हेतु शीघ्र ही एक नियामक आयोग का गठन किया जाए। अभी तक राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं क्योंकि इस बार, यदि एक बार इन निजी विश्वविद्यालयों का बिल यदि विधान सभा से पास हो जाए तो उसके बाद उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, कोई नियंत्रण नहीं रहता है, कोई प्रेशर नहीं रहता है जबकि जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, उनके ऊपर दुनिया भर के नियम-कायदे लागू कर रखे हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि स्टेट यूनिवर्सिटी की तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी बॉम, बोर्ड आफ मैनेजमेंट के अंदर दो-दो माननीय सदस्यों को और इसके अलावा दो-दो शिक्षाविदों को अपाइंट किया जाएं तथा साथ ही साथ इसमें गवर्नमेंट के अधिकारी भी नियुक्त किये जाएं ताकि इनकी गतिविधियों के ऊपर कंट्रोल किया जा सके।

(डा. मंजू बाघमार)

इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी, हायर एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की जा चुकी है, उसके सदस्यों की भी नियुक्ति की जा चुकी है लेकिन अभी तक वाइस चेयरमैन का पद खाली है। इस पद पर शीघ्र ही एक शिक्षाविद की नियुक्ति की जाए ताकि हायर एजुकेशन काउंसिल जो है, वह अपने कार्यों में गति ला सके। और सक्रिय हो सके। सभी विश्वविद्यालय की जो शिक्षा नीति है, वह इसके द्वारा निर्धारित हो क्योंकि अभी हर यूनिवर्सिटी अपने-अपने हिसाब से कार्य कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का भी इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता सुधारने के लिए और भाषा का ज्ञान करवाने के लिए, मैं इसे एक एग्जाम्प्ल द्वारा बताना चाहूंगी कि यदि कोई विद्यार्थी हिंदी में पीएच.डी. करता है तो वह हिंदी के अंदर ही अपनी थीसिस लिखता है। इंग्लिश में पीएच.डी. करता है तो वह इंग्लिश में अपनी थीसिस लिखता है लेकिन यदि कोई विद्यार्थी उर्दू के अंदर, संस्कृत और सिंधी के अंदर पीएच.डी. करता है तो भी वह अपनी थीसिस हिंदी में लिखता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी और साथ ही साथ यदि हम उसे एम.ए. की डिग्री भी देते हैं तो भी अपना प्रश्न-पत्र हिंदी में सोल्व करता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी, इस संबंध में उचित नियम बनाए जाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकारी विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि जिनकी संख्या 100 से भी कम हैं। माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि राज्य के समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों में, राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक एवं अधिकारी नियुक्ति एवं चयन अधिनियम, 1974 लागू है, जिसके अंतर्गत शिक्षक और अधिकारी वर्ग के पदों पर नियुक्ति समान रूप से सीधी भर्ती द्वारा की जाती है। इसमें शिक्षक वर्ग को तो कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत सभी समय पर पदोन्नति के प्रावधान किये गये हैं लेकिन जो अधिकारी वर्ग वहां पर कार्यरत है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, एग्जामिनेशन आफ कंट्रोलर उनमें सम्पूर्ण सेवा काल के अंदर एक भी पदोन्नति का प्रावधान नहीं किया गया है। निश्चित रूप से उनकी सेवा स्थिति जो है, वह दयनीय है और इस वर्ग के अधिकारियों के साथ भेद-भाव और अन्याय है।

(डा. मंजू बाघमार)

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि यू.जी.सी. के वेतनमान को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा विभाग को 31 दिसम्बर, 2008 को जारी परिपत्र में अन्य राज्य सरकारों की भांति राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव के माध्यम से एक परिपत्र जारी किया था। राज्य सरकार ने इसे विश्वविद्यालय के शिक्षकों, महाविद्यालय शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों और पुस्तकालयों पर तो लागू कर दिया लेकिन विश्वविद्यालयों के अधिकारियों पर लागू नहीं किया गया है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि राज्य के समस्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों को यू.जी.सी. वेतनमान और पदोन्नति का लाभ देकर इस वर्ग के साथ न्याय किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं तकनीकी शिक्षा की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। राज्य के सभी आठ सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसायटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत और सोसासटी द्वारा संचालित हैं। इन सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को उनके क्षेत्रानुसार राज्य के विश्वविद्यालयों का संघटक महाविद्यालय बना दिया जाना चाहिए क्योंकि राज्य के अनेक विश्वविद्यालय मानव संसाधन की कमियों के कारण सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहे हैं। वित्त को लेकर राज्य सरकार की अपनी अलग समस्याएं होती हैं। ऐसी स्थिति में इन राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय जोकि स्वायत्त-शासी संस्थान है, कई बार इन महाविद्यालयों को लेकर अनियमितताओं की भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और कई बार स्वायत्तता के नाम पर ये राज्य सरकार के नियमों की भी अवहेलना करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इन महाविद्यालयों का आधारभूत ढांचा, भूमि और भवन, प्रयोगशालाएं अच्छे स्तर की हैं और इनमें शैक्षणिक और अशैक्षणिक कार्मिकों की संख्या भी पर्याप्त मात्रा में हैं और दूसरी ओर हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, वे अधिकांश शैक्षणिक और अशैक्षणिक कार्मिकों की कमी की समस्या से त्रस्त हो रहे हैं तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि जिस प्रकार राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय कोटा को राजस्थान टैक्निकल यूनिवर्सिटी का संघटक महाविद्यालय बनाते ही राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय त्वरित रूप से स्थापित हो गया और

(डा. मंजू बाघमार)

विश्वविद्यालय में भी अपेक्षित कार्मिक जो हैं, वह सहज रूप से उपलब्ध हो गये। अत: मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है, ऐसे में राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय को उनके क्षेत्र के अनुसार राज्य के विश्वविद्यालयों का संघटक महाविद्यालय बना दिया जाए। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह भी निवेदन है कि यदि इसमें कोई टैक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए और उसमें एकैडमिशन की नियुक्ति जरूर की जाए।

एक, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगी। बी.ओ.जी. की एक कमेटी जो बनाई गयी है इन संस्थानों को गवर्न करने के लिए, उनकी मीटिंग डेढ़-डेढ़, दो-दो सालों तक नहीं हो पा रही है। उनकी रेगुलर बैठकें आयोजित करने के लिए किया जाए। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी कहना चाहूंगी, वर्तमान में बी.ओ.जी. का चेयरमैन है, एक प्राइवेट कॉलेज के व्यक्ति को उसमें बना रखा है तो उसके चेयरमैन को एक एकैडमिशन को या फिर आई.आई.टी. या एम.एन.आई.टी. के एक रिटायर्ड प्रोफेसर को उसका चेयरमैन बनाया जाए ताकि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिल सकें।

मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। बीकानेर में नए तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने की कवायद जोर-शोर से की जा रही है किंतु राज्य में संचालित एक मात्र तकनीकी विश्वविद्यालय, राजस्थान टैक्निकल यूनिवर्सिटी, कोटा में है। छात्रों की नामांकन संख्या जो कभी, पिछले कुछ वर्षों पहले 60 हजार के लगभग हुआ करती थी, वर्तमान में निरंतर घट रही है और अब वह संख्या घटकर 12 हजार, ओनली ट्वेंटी परसेंट, बारह हजार स्टूडेंट नामांकित हो रहे हैं। केवल 20 परसेंट रह गयी है। फिर एक नये तकनीकी विश्वविद्यालय को और खोले जाने का क्या औचित्य है? (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि विकास से वंचित नागौर क्षेत्र के अंदर यदि आप तकनीकी विश्वविद्यालय खोलेंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के व्यक्तियों और इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को इसका लाभ होगा।

(डा. मंजू बाघमार)

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और आपसे निवेदन करना चाहूंगी। राज्य में सरकारी क्षेत्र में एक मात्र अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर 2007 से संचालित है। यदि इसका नामकरण राजमाता विजयाराजे सिंधियाजी के नाम से किया जाता है, क्योंकि राजमाता विजयाराजे सिंधिया देश की महिलाओं की गौरव और सम्मान की प्रतीक हैं और यदि इसका नामकरण कर दिया जाता है तो यहां अध्ययनरत छात्राओं के गौरव को अनुभूति प्रदान करेगा और उन्हें आगे बढ़ने में भी सहयोग प्रदान करेगा।

(17.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, इस महाविद्यालय के अंदर कई गरीब और होनहार छात्राएं भी पढ़ती हैं जोकि अपनी फीस देने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि वह स्व-वित्त पोषित महाविद्यालय है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि यदि पूर्ण शुल्क नहीं तो कम से कम पचास प्रतिशत शुल्क छूट देकर उन छात्राओं का पुनर्भरण किया जाये ताकि वे भी तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर सके।

इसी श्रृंखला में तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय को और राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर के प्राचार्य श्री अजय सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूं। माननीय मंत्री महोदय के प्रयास और उनके दिशा-निर्देशन और प्रोत्साहन से राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर में एक वात्सल्य भवन की स्थापना की गयी है। माननीय सभापति महोदय, यह एक शिशु पालन गृह की भांति है। जिससे वहां की महिला टीचर्स और वहां पर पढ़ने वाली छात्राएं हैं, वे अपने मातृत्व की जिम्मेदारी के साथ-साथ पढ़ाई की राह को भी आसान बना सके।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि एक समान पालिसी के तहत प्रदेश के समस्त स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिशु पालना गृह की स्थापना की जाये। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं पोलीटैक्निक कॉलेज में हुई विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। तकनीकी शिक्षा विभाग में पोलीटैक्निक महाविद्यालय के अंदर वरिष्ठ प्रवक्ताओं को प्रवक्ताओं के पद पर लगाया गया है, जबकि नियमानुसार वरिष्ठ अधिकारियों को कनिष्ठ पदों

(डा. मंजू बाघमार)

पर नहीं लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, इन तकनीकी संस्थानों में प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता और विभागाध्यक्ष को अपने मूल विषय के स्थान पर अन्य विषयों के साथ और अन्य विभागों में ही पदस्थापित किया हुआ है, जिससे निश्चित रूप से तकनीकी शिक्षा के स्तर में भारी गिरावट आयी है। यह एक गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला है, जिसमें आडिट में भी आब्जेक्शन लगे हैं, अत: माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि छात्र हित में और राज्य हित में इसे रोका जाये और सुधारा जाये।

माननीय सभापति महोदय, कला और संस्कृति के विषय में मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। हमारे प्रदेश की भाषा, साहित्य और संस्कृति के उन्नयन और प्रोत्साहन हेतु संचालित राजस्थान सरकार का उपक्रम राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर की सभी गतिविधियां जैसे साहित्यिक-सांस्कृतिक आयोजन, पाण्डुलिपि प्रकाशन, साहित्य पुरस्कार अकादमी की मासिक पत्रिका 'जागती जोत' जिसमें साहित्यकारों के महत्वपूर्ण आलेख प्रकाशित होते हैं, जिसकी अपनी एक सामाजिक उपयोगिता है, आदि सब कार्य पिछले कई वर्षों से बंद पड़े हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय और सरकार से निवेदन है कि इस अकादमी में अध्यक्ष मनोनीत किया जाये और इस अकादमी के लिये जो निर्धारित बजट है, उसे आबंटित किया जाये ताकि अकादमी अपनी गतिविधियों का संचालन कर सके और साहित्यकारों को प्रोत्साहन मिल सके। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: कृपया अब समाप्त करें।

डा. मंजू बाघमार (जायल): माननीय सभापति महोदय, मैं एक बार पुन: आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री भँवरसिंहजी।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा, कला और संस्कृति पर विचार हो रहा है। सभापति महोदय, माननीय सदस्यों के द्वारा करीब 319 कटौती प्रस्ताव लगाये गये और उनमें अधिकांश माननीय सदस्यों के द्वारा अपने क्षेत्र में नये विद्यालय खोलने, विद्यालयों

(श्री भंवरसिंह)

को क्रमोन्नत करने, अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के अलावा मैं समझता हूं, कोई कटौती प्रस्ताव नहीं आये हैं। मैं अपने आपको इसमें शामिल करते हुए बात शुरू करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के हमारे माननीय सदस्य पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के बारे में बात कर रहे थे। सभापति महोदय, 1998 से लेकर 2003 के बीच में हमारी सरकार रही और उस समय राजस्थान के दूरदराज सुदूर के जो लोग ढाणियों में रहते हैं और जहां कई किलोमीटर तक, पाँच-दस-बीस किलोमीटर तक डैजर्ट एरिया में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां छितराई हुई आबादी थी और जहां किसान के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने से लम्बे समय से वंचित रह रहे थे, वहां 18 हजार राजीव गांधी पाठशालाएं खोली गयीं और वे राजीव गांधी पाठशालाएं बाद में आगे चलकर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय बनीं। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि फिर 2008 से लेकर 2013 तक हमारी सरकार रही। राजस्थान के विभिन्न ग्राम पंचायतों में और ग्राम पंचायत मुख्यालयों के अलावा भी जहां छात्रों की संख्या ज्यादा थी, जहां के क्षेत्र के लोगों की मांग थी, वहां हजारों की संख्या में नवीन प्राइमरी स्कूल खोले गये और अपर प्राइमरी स्कूल क्रमोन्नत किये गये। माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय भी क्रमोन्नत किये गये। इसके साथ-साथ राजकीय महाविद्यालय भी खोले गये, यूनिवर्सिटीज भी खोली गयी। मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा, पिछली सरकार के जो आंकड़े हैं, और 1998 से 2003, फिर 2008 से 2013 तक सरकार का जो कार्यकाल था, उस समय कितने विद्यालय खोले गये और कितने अध्यापकों की भर्तियां की गयीं, उस पर भी आपको ध्यान दे लेना चाहिये।

सभापति महोदय, 2014 में आपकी सरकार बनने के बाद सबसे पहले, जहां हमने 18 हजार नये प्राइमरी स्कूल खोले, द्वारा 17 हजार प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल एकीकरण के नाम पर बंद करने का एक प्रहार किया गया। राजस्थान में जो प्रारम्भिक शिक्षा है, हमारे सत्ता पक्ष के काफी विधायकों ने बताया कि इस प्रारम्भिक शिक्षा का ढांचा पिछले वर्षों में बहुत ज्यादा कमजोर हुआ है। सभापति महोदय, उसका एक सबसे बड़ा कारण यह रहा कि राजस्थान में 2014 में करीब 17 हजार प्रारम्भिक विद्यालयों को

(श्री भंवरसिंह)

एकीकरण के नाम पर बंद किया गया और उसके बाद 2016-17 का जब शैक्षणिक सत्र आया, तब भी वह क्रम रूका नहीं और करीब 4449 और प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल एकीकरण के नाम पर बंद किये गये। सभापति महोदय, उसमें 15 छात्र संख्या से कम नामांकन वाले विद्यालय बंद करवाये गये। छात्र संख्या को आधार माना गया और उसमें भी जुलाई से सितम्बर तक की जो छात्र संख्या है, उसको आधार माना गया।

सभापति महोदय, हमारे पश्चिमी राजस्थान में एक-फसली खेती होती है और जब जून-जुलाई में वर्षा होती है तो किसान गांव से खेत में चला जाता है और वह तीन महीने तक खेत में रहता है। उस दौरान किसान के बच्चों का एडमिशन नहीं होता और वह सितम्बर के बाद जब वह वापस आता है तो उनका नामांकन करवाया जाता है। जुलाई से सितम्बर तक का एडमिशन का जो आंकड़ा रखा गया, उसकी वजह से हमारे राजस्थान के करीब 23 हजार विद्यालयों को पिछले साढ़े तीन सालों में, माननीय मंत्री महोदय यहां विराजे हुए हैं, इनके गाइडेंस में और इनके आदेशों से बंद किया गया। यहां तक कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' यह हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी का और सरकार का नारा भी है, लेकिन राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में बालिकाओं के प्राइमरी और अपर प्राइमरी विद्यालय हैं वे बंद करने का काम किया गया। बीकानेर जिले में भी 20 से ज्यादा बालिका विद्यालय बंद किये गये।

सभापति महोदय, पिछले साढ़े तीन सालों में राजस्थान के एक भी गांव या ढाणी में नया प्राथमिक विद्यालय नहीं खोला गया, नया उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं खोला गया। इसकी वजह से भी और एकीकरण की वजह से करीब 45 हजार शिक्षकों के पद समाप्त कर दिये गये।

सभापति महोदय, आपके घोषणा पत्र की बात करें। आपने रोजगार देने का वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जो बातें लिखी गयी थीं, उसमें करीब 15 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की गयी थी लेकिन 4500 राजकीय विद्यालयों में लगे हुए कम्प्यूटर शिक्षकों को 2014 में हटा दिया गया। एक तरफ तो हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे राजस्थान के जो सैकण्डरी या सीनियर सैकण्डरी

(श्री भंवरसिंह)

विद्यालय हैं, वहां कम्प्यूटर लैब बनी हुई हैं लेकिन कम्प्यूटर सिखाने वाले जो अध्यापक थे, जो प्रशिक्षक थे, उनको हटाने के बाद उन कम्प्यूटर लैब के आज भी ताले लगे हुए हैं सभापति महोदय।

शिक्षाकर्मी में हमारे क्षेत्र की, सीमावर्ती क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सीमावर्ती जिलों में दूर-दराज के गांव, ढाणियों में पिछले करीब 25-30 सालों से विद्यालयों में ये शिक्षाकर्मी पढ़ाते हैं। इनको नाम मात्र का मानदेय दिया जाता है और करीब 25 से 30 साल की सर्विस होने के बावजूद ये सात-आठ हजार रुपये में अपना अध्यापक का दायित्व निभाते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, अधिकांश जीवन इन्होंने विद्यालयों में पढ़ाने में व्यतीत किया है और इनको नियमित किये जाने की लगातार मांग की जा रही है तो इन शिक्षाकर्मी, विद्यालयों में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, उनको नियमित किया जाए।

2007 में आपकी सरकार थी, उस समय विद्यार्थी मित्र लगाये गये लेकिन जब दुबरा 2014 में आपकी सरकार बनती है तो एक आदेश के तहत राजस्थान के 25 हजार विद्यार्थी मित्रों को पूरे राजस्थान में हटा दिया गया। ये विद्यार्थी मित्र सरकार के सामने लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं और सत्ता पक्ष और ना पक्ष के सभी माननीय सदस्यों के द्वारा भी बार-बार यह मांग की जाती रही है कि इन विद्यार्थी मित्रों का समायोजन किया जाए लेकिन सरकार ने इस विद्यार्थी मित्रों को एक तरह से फुटबॉल की तरह बना रखा है। कभी इन्हें कहा जाता है कि हम आपको विद्यालय सहायक लगायेंगे और जब विद्यालय सहायक की भर्ती निकाली जाती है तो उसमें टैक्निकली कमियों की वजह से वह कोर्ट में अटक जाती है।

पिछले दिनों इन्हीं विद्यार्थी मित्रों के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया गया कि आपको ग्राम पंचायत सहायक लगाया जायेगा और वह भी जो ग्राम पंचायत की एस.डी.एम.सी. है उसके माध्यम से इन विद्यार्थी मित्रों को लगाया जायेगा। लेकिन इस ग्राम पंचायत सहायकों की भर्ती में भी किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन तय नहीं की गयी, किसी प्रकार के नियम नहीं बनाये गये। माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थितियों

(श्री भंवरसिंह)

में यह भर्ती भी दुबारा कोर्ट में अटकने वाली है। सभापति महोदय, मैं पूरे सदन की तरफ से आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा, राजस्थान के ये जो 25 हजार विद्यार्थी मित्र हैं, इनमें से करीब 25-30 विद्यार्थी मित्रों ने आत्म हत्या कर ली है क्योंकि वे लगातार लम्बे समय से बेरोजगार थे तो इन विद्यार्थी मित्रों का समायोजन करने के लिए आज जब मंत्री महोदय अपना जवाब दें तो घोषणा करें।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ जो 2012-13 में 40 हजार शिक्षक लगाये गये थे उनका भी लम्बे समय से अभी तक कन्फर्मेशन नहीं किया गया है।

सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा में करीब 90 हजार पद खाली हैं। प्रारम्भिक शिक्षा में करीब 50 हजार शिक्षकों के पद रिक्त हैं। व्याख्याताओं के, वरिष्ठ अध्यापक के, प्रधानाचार्य के 50 प्रतिशत के करीब इस समय पद रिक्त चल रहे हैं।

सभापति महोदय, राजस्थान में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर दसवीं से बारहवीं स्कूलों को क्रमोन्नत करने के हमारे सत्ता पक्ष के भी माननीय सदस्य बार-बार कह रहे हैं लेकिन जो विद्यालय आठवीं से दसवीं हुआ या जो विद्यालय दसवीं से बारहवीं में क्रमोन्नत हुआ है, उस विद्यालय में तीन विषय स्वीकृत किये गये हैं। इन तीनों ही विषयों में व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं। सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में उस विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा किस प्रकार के परिणाम दे सकता है, आप स्वयं आइडिया लगा सकते हैं। दो मिनट का समय और लेना चाहूंगा।

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा, बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय हमारी सरकार ने खोला, आपने उसको निरस्त कर दिया। आपकी सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले बजट सत्र में तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर में खोले जाने की घोषणा की थी, वह आज तक नहीं खुला, यह बजट भी पेश हो गया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का और सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोलने के बिल लगातार लाते जा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा गवर्नमेंट का तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की

(श्री भंवरसिंह)

गयी है। इसी सत्र में, अभी सत्र चल रहा है इसमें बिल लाकर के जुलाई से जो शैक्षणिक सत्र शुरू होगा, उसमें बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय खोला जाए ताकि आपके द्वारा जो घोषणा की गयी है वह लागू हो सके और बीकानेर संभाग के लोगों को और आसपास के जिले के जो विद्यार्थी हैं, उनको तकनीकी शिक्षा मिल सके। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) एक-दो बातें मैं मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय, 2014, 2015, 2016 और 2017, यह चौथा बजट पेश किया गया। आपके घोषणा पत्र में भी है कि राजस्थान के हर उपखण्ड मुख्यालय पर हम कॉलेज खोलेंगे। हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय कालीचरणजी सराफ ने भी कहा था कि हम गुणावगुण के आधार पर और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कोलायत में जो राजकीय महाविद्यालय खोला गया था, उसको करेंगे लेकिन, सभापति महोदय, आज तक नहीं खोला गया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आप एक तरफ 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा दे रहे हैं, पूरे राजस्थान को एक साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हर बजट में माननीय सत्ता पक्ष के सदस्यों के विधान सभा क्षेत्रों में कॉलेज खोले जा रहे हैं। वहीं मेरा विधान सभा क्षेत्र 200 किलोमीटर लम्बा विधान सभा क्षेत्र है और बीकानेर संभाग व जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि बीकानेर सीमावर्ती क्षेत्र भी है, रेगिस्तानी क्षेत्र भी है और कोलायत विधान सभा क्षेत्र में आप दरियादिली रखते हुए और यदि आप सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक नजरिये से देखने की बात करते हैं तो कोलायत विधान सभा क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय को भी आप आपके माध्यम से या माननीय मुख्य मंत्रीजी के माध्यम से जब घोषणा हो, तो कोलायत में राजकीय महाविद्यालय खोला जाए सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मान सिंह जी।

श्री मान सिंह (गंगापुर): सभापति महोदय, मांग संख्या- 24 कला, शिक्षा, संस्कृति पर बहस चल रही है। सभापति महोदय, इस देश में आजादी

(श्री मान सिंह)

के बाद जैसे ही कांग्रेस नीत सरकार बनी, पंडित नेहरूजी ने वरनाकुलर एजुकेशन का बजट कम किया। उस चीज से पता लगता है क्योंकि वह व्यक्ति विदेश में पढ़कर केवल औद्योगीकरण की छलांग लगाना चाहता था। उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि हिन्दुस्तान का ढांचा क्या है। उनकी सोच थी कि हिन्दुस्तान का गरीब गरीब रहे, अमीर अमीर रहे और किस प्रकार की शासन व्यवस्था, जिस प्रकार के संस्कार उनको मिले थे, यह वहां ही से शुरू होती है। आज मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता।

मेरे प्रतिपक्ष के भाई कह रहे हैं। हमारे कोटा उत्तर से आने वाले माननीय प्रहलाद जी गुंजल साहब ने बहुत विस्तार से भारत की संस्कृति और भारत की संस्कृति के अनुरूप जो हमारी शिक्षा थी, जिस शिक्षा के दम पर आज भारत दुनिया में अपना संस्कृति का लोहा मनवाता है, उसका ज्यादा जिक्र नहीं करके, क्योंकि उन सब चीजों पर चर्चा हो चुकी, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि हमारी सरकार ने जिस प्रकार से शिक्षा के मामले में जो बजट का प्रावधान किया है, जिस प्रकार से आंकड़ों के हिसाब से जब आप देखते हैं तो इनके पांच साल के बजट को हमने तीन साल के बराबर करने का काम किया। हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने जिस प्रकार से अलग-अलग पैटर्न के माध्यम से, चाहे वो समानीकरण हो, चाहे विलयीकरण हो, चाहे स्टॉफीकरण हो, शिक्षा में इस प्रकार का सुधार करके आम व्यक्ति में एक विश्वास पैदा करने का काम किया कि राजस्थान की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना चाहती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इन सब चीजों से भी हटकर, एक मेरे मन की पीड़ा इस सदन में इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसको हमको राजनैतिक दलों की सीमाओं से उठ कर के भी इस पर चर्चा करनी चाहिए। आखिर हम इस भारत को, राजस्थान को किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी केवल यह है कि हम हमारी पार्टी की बात करके, सरकार की बात करके, क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रकार का भट्टा बैठाने का काम किया, अगर उसका गुणगान करेंगे तो वह तो लम्बी चर्चा हो जायेगी लेकिन सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि आज की जिस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है,

(श्री मान सिंह)

निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार ने व्यावसायिक केन्द्र खोलने का काम किया है। जो हमारे स्किल डवलपमेंट के 700 के लगभग सेण्टर चालू किये।

जो 11 ट्रेड हैं, वह एक बहुत ही दूरगामी कदम है। उससे शिक्षा के साथ-साथ हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। इस शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। जो हाई स्कूल लेवल की शिक्षा है, उसका वर्गीकरण हमको इस प्रकार से करना चाहिए कि जो बच्चा शुरू से ही किसी प्रकार की तकनीकी शिक्षा में जाना चाहता है तो उसको नोर्मल हाई स्कूल जोइन नहीं करना पड़े। शुरू से ही टैक्निकल और नोर्मल दो तरह के हाई स्कूल होने चाहिए।

सभापति महोदय, जैसे हमने 700 सेंटर खोले हैं, वह अभी हमारे सारे संभाग लेवल पर हैं। प्रत्येक उपखंड पर या पंचायत समिति लेवल पर नहीं पहुंच पाए हैं। अगर पहुंच भी गए तो जिस तरह से उनका केन्द्रीकरण का सिस्टम होना चाहिए, उस सिस्टम को बैठाने में टाइम लगेगा। मेरा यह कहना है कि इस मामले में सरकार द्वारा राजस्थान को देश में एक मॉडल बनाना चाहिए कि हम इसको किस प्रकार से अव्वल बनाना चाहते हैं।

राजस्थान में हमारा नौजवान है, उसको टैक्निकल और नोर्मल शिक्षा के हिसाब से शिक्षा देने का काम करेंगे तो हमें आईटीआई भी कम खोलनी पड़ेंगी। हमारे बच्चों को किसी प्रकार की इंजीनियरिंग में भी ट्रेनिंग के लिए कम जाना पड़ेगा। वह गरीब का बच्चा भी शुरू से ही वह काम कर सकेगा। अगर कोई कुम्हार के घर में पैदा हुआ है और उसके मन में यह बात है कि मैं पोट्री का काम करना चाहता हूं तो वह उसको उस टैक्निकल स्कूल में मिल जाएगा और वह बहुत बड़ा कारीगर बन सकेगा। इस प्रकार शिक्षा के अंदर हमें एक बहुत बड़ा विचार लेकर चलना पड़ेगा।

सभापति महोदय, कोलायत से आने वाले हमारे माननीय सदस्य राजीव गांधी केन्द्रों की बात कह रहे थे। किस तरह से राजनीतिकरण करके उनकी धज्जियां उड़ाई गईं। किस प्रकार से शिक्षा का राजनीतिकरण किया गया। मैं इन सब चीजों की चर्चा नहीं करना चाहता। जिस प्रकार से उन राजीव गांधी केन्द्रों को झेला है, जैसी व्यवस्था इन्होंने की थी, उन सब चीजों पर नहीं जाना चाहता।

(श्री मान सिंह)

सभापति महोदय, मैंने शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन किया था कि हमारे बोर्ड में परीक्षा चैकिंग का जो पैटर्न है, क्यों नहीं उसको आप केन्द्रीकृत करते? इस प्रकार से जो हमारे बोर्ड की कॉपियां जगह-जगह जाती हैं, उससे कई बार हमारे रिजल्ट पर प्रश्न चिन्ह लगता है। यह सब चीजें हम खुले मन से इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमें इस सारी व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमें पूरी तरह से आत्म विवेचन करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार ने जो कदम बढ़ाए हैं, उनके संबंध में मेरे कई साथियों ने चर्चा की है। आज अगर आप हमारे कॉलेज के स्टूडेंट से पूछेंगे जोकि थ्री ईयर डिग्री कोर्स कर रहा है कि हमारे महानरेगा का सिस्टम क्या है तो वह नहीं जानता है। क्यों नहीं हम उसकी इंटर्नशिप की व्यवस्था करते? क्यों नहीं महानरेगा के ऑफिस में उस कॉलेज के बच्चे के लिए 50 दिन की ट्रेनिंग करना कम्पलसरी करें? इन सब चीजों के लिए आपको कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। उसको कोई पैसे के लिए जाना पड़ेगा? कॉलेज की शिक्षा को महानरेगा से जोड़ने से जो भी बच्चा उस चीज को समझना चाहता है, उसको टैक्निकल रूप से समझने का मौका मिलेगा। वह इंटर्नशिप करने जाएगा तो सीखेगा कि मुझे क्या करना है। यह जब हम नहीं करेंगे तब तक हमारी शिक्षा है, उसमें सुधार नहीं होगा।

सभापति महोदय, जैसा हमारे बहुत से साथी चर्चा कर रहे थे कि यह मैकाले की शिक्षा बाबू पैदा कर सकती है। रोजगार के लिए जिस प्रकार की आवश्यकता है, जिस प्रकार का सृजन हमको शिक्षा के अंदर करना है, उसके लिए जरूरी है कि हम इसके साथ औद्योगीकरण को जोड़ें, व्यावसायिकरण को जोड़ें तभी यह रोजगार से जुड़ने का काम करेगा। इसके लिए कोई बहुत बड़े पैसे की आवश्यकता नहीं है। यह कम पैसे में हो जाएगा। यह नहीं कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं तो किस प्रकार से करेंगे। हमारे पास संसाधन होंगे तब करेंगे। इसमें कोई संसाधन की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय, आज हमारे बच्चे को अगर कहा जाए कि बैंक में आपको चार प्रकार के विदड्राल और आरटीजीएस करना है तो वह नहीं जानता है। उसको यह बताया नहीं गया है। जब आप इसी चीज को दूसरी

(श्री मान सिंह)

जगह देखते हो तो बैंकिंग का सिस्टम उसको सिखाया जा सकता है। हमारी जो छोटी-छोटी योजनाएं हैं उनको हमें सिखाना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा। आपने जिस प्रकार से हमारी सैकण्डरी एजुकेशन के अंदर बदलाव किया है और वापस विश्वास बहाली का काम किया है, वह अपने आपमें एक रिकार्ड है। जिस प्रकार से प्रमोशंस किए हैं, जिस प्रकार से ट्रांसफर्स हुए हैं, एक स्वतंत्र तरीके से वे सारे काम अपने आप हुए हैं। लेकिन इन सब चीजों के साथ में इसमें गुणवत्ता किस प्रकार से आए और यह लगातार किस प्रकार से बनी रहे, यह देखना है।

सभापति महोदय, हम संस्कृति की चर्चा कर रहे हैं। अगर स्कूल के समानीकरण में कोई ऐसी ढाणी है, जिसमें पांच बच्चे हैं और वे बच्चे अगर दूर हैं तो जिस प्रकार से आंगनबाड़ी केन्द्रों के बारे में सरकार कल्पना कर रही है कि संस्कार केन्द्र के रूप में डवलप करेंगे तो उसको अमलीजामा पहनाना चाहिए। वह आंगनबाड़ी केन्द्र इस प्रकार का संस्कार केन्द्र बने कि हमारा एक भी बच्चा चाहे वह किसी भी छोटी ढाणी में रहे, वह इससे जुड़े। इस काम को करना चाहिए। यह अच्छा कदम है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।

इसके साथ-साथ में, जहां हमसे गलतियां हुई हैं, अगर समानीकरण में हुई हैं तो उनके बारे में भी जिन साथियों ने चर्चा की है, वह सही करें। हमारे विभाग के अधिकारी यहां बैठे हैं। केवल लकीर का फकीर होने से काम नहीं चलेगा। शिक्षा देश की बुनियाद है। किसी भी देश की तरक्की का रास्ता बिना शिक्षा के नहीं हो सकता है। जब हम सदन में चर्चा करें तो हमारा अधिकारी वर्ग भी यह नोट करे कि कहां-कहां, किस प्रकार की गलतियां हुई हैं। उसके लिए आपके पास बाकायदा जवाब होना चाहिए कि हमने इस जगह के बारे में यह निर्णय किया है।

सभापति महोदय, हमारी उच्च शिक्षा मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहूंगा। आज हमारे सरकारी कॉलेजों को यूजीसी की ग्रांट कम मिलती है और हमारे प्राइवेट कॉलेजों को ग्रांट ज्यादा मिलती है। हमारे अधिकारी इस बात की चर्चा करें और इस बात का

(श्री मान सिंह)

पता लगाएं कि आखिर क्यों कम मिलती है? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण नहीं मिलती है? उनकी जो नोर्म्स हैं सेमीनार की, गोष्ठियों की उसके कारण से नहीं मिलती है? हमारे कॉलेज का जो सिस्टम है उसका करिकुलम पूरा नहीं करने के कारण नहीं मिलती है? सारे के सारे कॉलेजों में बड़ी ग्रांट मिल सकती है और वह नहीं मिल पाती है। इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। इस पर हमको ध्यान देना चाहिए कि हमारे सरकारी कॉलेजों को ग्रांट मिले।

सभापति महोदय, मैं उच्च शिक्षा मंत्री से एक और अनुरोध करना चाहूंगा। हमारे यहां कॉलेज लेवल पर, मैं हमारे गंगापुर, सवाई माधोपुर का ही आंकड़ा बताता हूं। मेरे यहां गवर्नमेंट कॉलेज, गंगापुर सिटी में 1532 बच्चियां रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड 3500 हैं यानी 5032 केवल गवर्नमेंट कॉलेज में हैं। अग्रवाल कॉलेज में 1800 और भगवती कॉलेज में 500 यानी कुल 7332 बच्चियां हमारे वहां हैं। ऐसी स्थिति में जहां 7,500 बच्चियां पढ़ती हों, वहां पर गर्ल्स कॉलेज की व्यवस्था हो, इसके लिए नोर्म्स बनाने चाहिंए। मैं यह नहीं कहता कि आप तुरंत ही बना दें लेकिन आखिर हम कब तक नहीं बनाएंगे? कब तक इस बात के लिए छोड़ देंगे कि जिसके पास व्यवस्था है, वह प्राइवेट कॉलेज में पढ़ ले। जिसके पास व्यवस्था नहीं है, वह नहीं पढ़ पाएगा।

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 12वीं तक के स्कूल कर दिए अन्यथा तो गांव की बच्ची 12वीं भी नहीं कर पाती। ये जो गरीब की बच्चियां हैं, जो 12वीं के बाद कॉलेज की एजुकेशन ले, इसके लिए भी व्यवस्था करें। हमारा यह जो सिस्टम है इसमें कोई बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस हायर एजुकेशन के बजट में मात्र एक परसेंट बढ़ा देते हैं तो 37 कॉलेज खुल सकते हैं। इन सारी चीजों पर हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमारे अधिकारियों को करनी चाहिए। किस प्रकार से राजस्थान में शिक्षा का स्तर ऊँचा उठ सके, इसकी कोशिश करनी चाहिए।

सभापति महोदय, पिछले पांच सालों में हमारी 5वीं तक और 8वीं तक की परीक्षा खतम कर दी गई और चाहे जिसको पास करना। यह सब स्टैप ठीक नहीं थे। मैं इस संबंध में विपक्ष के साथियों से भी कहना चाहूंगा कि

(श्री मान सिंह)

वह दिल पर हाथ रखकर के इस बारे में सोचें। हम अगर राजस्थान को मजबूत करना चाहते हैं तो बिना शिक्षा के यह संभव नहीं है। इस पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहूंगा। आपका जो बोर्ड ऑफ अजमेर है और उसकी जो गोपनीयता है परीक्षाओं के संबंध में, उसका भी एक सिस्टम तय करिए। राजस्थान के बोर्ड की जो विश्वसनीयता थी, उसमें और वृद्धि हो। इससे बच्चों के अंदर यह भाव होगा कि देश के अंदर सबसे अच्छा कोई बोर्ड है तो राजस्थान का बोर्ड है। आज भी हालांकि राजस्थान का बोर्ड कमजोर नहीं है। लेकिन अगर कहीं कोई कमी रही है तो इसको ठीक करें। मैं इसमें जाना नहीं चाहता कि किस प्रकार से लोगों को प्रमोशंस दिए गए हैं। वह एक जांच का विषय हो सकता है। माननीय मंत्रीजी, यह आपने नहीं किया, पिछली सरकार ने किया था लेकिन इसके बावजूद भी आज आपकी जिम्मेदारी है। राजस्थान में आप जिस प्रकार से कदम बढ़ा रहे हो, उन कदमों के माध्यम से राजस्थान शिक्षा के पायदान पर, आपने जिस प्रकार से उसका मतलब जो है हमने पन्द्रह में से प्रथम पायदान पहुंचाने का काम किया है उसमें हमें महत्ती भूमिका निभाने का काम करना है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत जल्दी और शोर्ट में कर रहा हूं, बहुत ज्यादा लम्बा नहीं करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ में मैं आपके माध्यम से हमारी शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा। शिक्षा मंत्रीजी, ग्राम पंचायत अहमदपुर, जो पंचायत हैडक्वाटर है। उसके और दूसरे स्कूल के बीच में रेलवे लाइन है, रेवेन्यू विलेज अलग-अलग है और अहमदपुर के प्राइमरी स्कूल को अलीगंज स्कूल में मिला दिया गया है। किसी भी तरीके से वह सही नहीं है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि ऐसे विषयों की जांच होनी चाहिए। जहां पंचायत हैडक्वाटर और रेवेन्यू विलेज अलग है, केवल बीच में रेलवे लाइन है उसको हम कैसे खतम कर सकते हैं? केवल इसलिए कि पहले दोनों गांव एक रेवेन्यू विलेज थे, आज नहीं है। नहीं है तो उस चीज को अपने को गणना करनी पड़ेगी। यह मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा।

(श्री मान सिंह)

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि राजस्थान में शिक्षा का वातावरण बना है। आज हायर एजुकेशन में हमारे कोटा का नाम है, आज हमारे गर्ल्स एजुकेशन में झुंझुनूं का नाम है, सैकण्डरी एजुकेशन में गंगापुर सिटी का नाम है। यह हम एजुकेशन के मामले को और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी से परमिशन लेकर राजस्थान के इतिहास में पहली बार अपने स्तर पर, राष्ट्रीय सेमीनार हम 13 और 14 मई को करने जा रहे हैं। देश के ख्यातिनाम विद्वानों को हम बुला रहे हैं। केवल मन में यह बात है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश से राजस्थान सरकार के चार विभागों को भी उसमें पार्टनर बना रहे हैं। पहली बार निजी स्तर पर इस प्रकार की सेमीनार गंगापुर में करने जा रहे हैं। उसके पीछे एक ही मकसद है कि राजस्थान हमारे शिक्षा के मामले में अव्वल नम्बर पर रहे। माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारी सरकार ने जिस प्रकार से कदम बढ़ाए हैं, उन कदमों के आधार पर राजस्थान नम्बर वन बने, यही हमारी मंशा है। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य मानसिंहजी किनसरिया।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति की चर्चा पर आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि शिक्षा सामाजिक जीवन का एक मुख्य पहलू है। शिक्षा में बात करें तो गुरुकुल शिक्षा से लेकर वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा के युग तक आज भी जहां ऑनलाइन शिक्षा हो रही है। सम्पूर्ण राष्ट्र की शिक्षा की व्यवस्था में हम देखें तो आज भी उसमें भारी कमी है। माननीय सभापति महोदय, आज भी हमारे राष्ट्र में शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए बच्चों के अभिभावकों को ही नहीं, बच्चों को भी कुछ व्यवस्थाओं में, उनको सुविधा देकर चाहे वह स्कूटी हो, चाहे वह साइकिल हो, चाहे पोषाहार हो, चाहे और उनको लाभ पहुंचाने की दृष्टि से जागरूकता की जा रही है जो कि एक विचारणीय पक्ष है। हमें चिंता करनी होगी कि आजादी के सत्तर साल बाद भी

(श्री मानसिंह किनसरिया)

हमारे देश में शिक्षा के लिए लोगों को समझाना पड़ रहा है, बच्चों को लालच देना पड़ रहा है। इन सब बातों पर हमें चिंता करने की बात है, विचार करने की बात है कि हम हमारे राष्ट्र में जो सत्तर साल हो गए तो सत्तर साल में आज तक व्यवस्था के द्वारा हम आम जनता में अपना विश्वास अर्जित नहीं कर पाए। इसके लिए हम चाहे पक्ष हों, चाहे विपक्ष हो, इसमें चिंता करनी होगी और इस व्यवस्था को सुधारना होगा।

माननीय सभापति महोदय, 1992 का एक किस्सा है। हमारे मुख्य मंत्री उस समय माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत थे। वे मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में दिल्ली गए और वहां राजस्थान में शिक्षा के बारे में उनको सुनना पड़ा कि आपका प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है, आपके प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है तो भैरोंसिंहजी को आत्मग्लानि हुई और उन्होंने राजस्थान आने के बाद में तुरंत शिक्षा मंत्रीजी से विचार विमर्श किया और पूरे प्रदेश भर में पंचायत हैडक्वार्टर पर आठवीं तक की शिक्षा लागू की। यह निर्णय भैरोंसिंहजी ने लिया लेकिन उससे पहले की जो व्यवस्थाएं थीं, वह नहीं ले पाई। उसके बाद में दसवीं तक की बात आई। भारतीय जनता पार्टी की दुबारा सरकार आई तथा माननीय वसुन्धराजी मुख्य मंत्री बनी, फिर वापस क्रमोन्नति का काम हुआ दसवीं तक। वह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय वसुन्धराजी ने किया।

माननीय सभापति महोदय, पुन: शिक्षा के काम को आगे बढ़ाने का समय आया। वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने सभी पंचायत मुख्यालयों पर बारहवीं तक स्कूलों को क्रमोन्नत किया।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता, विकास एवं व्यवस्थाओं में सुधार करने के काफी प्रयास किए जिससे हर साल शिक्षकों की कमी के कारण विद्यालयों में जहां तालाबंदी होती थी, अखबारों में हमें देखने को मिलता था कि आज इस विद्यालय में तालाबंदी हो गई, आज वहां हो गई। हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने बहुत प्रयास किए हैं जिसके कारण तालाबंदी की जो खबरें आती थीं, वे बंद हो गई हैं। आज अध्यापकों की भर्ती और प्रमोशन की प्रक्रिया के द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किया है। सांस्कृतिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास हमारी सरकार कर

(श्री मानसिंह किनसरिया)

रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदेश की माननीय मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी को, जिन्होंने पूरे प्रदेश के पंचायत मुख्यालयों पर शेष बचे सभी माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में इस बजट में क्रमोन्नत कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षकों की भर्ती कर शिक्षकों की कमी को भी पूर्ण करने का प्रयत्न किया है। विद्यार्थी मित्रों की एक बड़ी समस्या है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस समस्या का समाधान करें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार आई है तो हमने शिक्षा के प्रति जो मांगें थी उनको पूर्ण किया है। इस समस्या का भी ध्यान रखते हुए आप लोग कार्य करें।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में निजी व सरकारी जो विद्यालयों की व्यवस्था है, निश्चय ही हमारे सरकारी विद्यालयों में शिक्षा मंत्रीजी के प्रयासों से काफी सुधार हुआ है। उसमें नामांकन में बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में निजी विद्यालय भी चल रहे हैं। एक समानांतर व्यवस्था है, हमें उस व्यवस्था को भी ध्यान रखना होगा। उस व्यवस्था में कुछ जो निजी विद्यालय के प्रतिनिधि हमसे मिले, उन्होंने भूमि रूपांतरण की बात की कि ग्रामीण और शहरी में तीन बीघा व पाँच बीघा की जो बात है, उसमें प्राथमिक स्तर पर जो गांवों में स्कूलें खुलती हैं, छोटे शहरों में जो स्कूलें खुलती हैं उनमें थोड़ी सुविधा दी जाए, उसमें थोड़ी ढील दी जाए, जिससे कि निजी विद्यालय भी उसमें अच्छी शिक्षा दे पाएं। इसमें तीन लाख और पचास हजार के डीडी की जो एफडी और डीडी की व्यवस्था की गई है कि तीन लाख की एफडी और पचास हजार की बालिका फाउंडेशन के लिए डीडी। उसमें भी अगर कोई गरीब बीएड किया हुआ व्यक्ति विद्यालय खोलना चाहता है, प्राथमिक स्तर तक पढ़ाना चाहता है और उसके पास तीन लाख और पचास हजार की व्यवस्था नहीं हो तो उसमें भी उसको कुछ ढील दी जाए तो उसमें भी उसको कुछ फायदा हो सके।

एक इसमें दिया है कि किराये पर नहीं चला सकते। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि प्राइमरी स्तर पर किराये के भवन में भी यदि स्कूल चलाना चाहे तो वह भी उसमें सुविधा मिले।

(श्री मानसिंह किनसरिया)

एक राइट टू एजुकेशन में 25 प्रतिशत का प्रावधान रखा हुआ है। उसमें एससी एसटी के लिए प्रावधान रखा हुआ है। मेरा निवेदन है कि इसमें जो एपीएल के छात्र हैं, एपीएल के जो परिवार हैं, उनका भी निजी विद्यालयों में प्रावधान रखा जाए।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तीन साल में 28 महाविद्यालय खोले हैं। कॉलेज खोले हैं। वह आठ इस बजट में खोले हैं। टोटल 36 महाविद्यालय अपने इस चौथे साल तक के बजट में खोले हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और उच्च शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने शिक्षा के विस्तार के लिए 36 महाविद्यालय खोले हैं, जो वास्तव में एक ऐतिहासिक कार्य है। पहले कभी एक साथ इतने महाविद्यालय खुले नहीं हैं। मेरा उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि महाविद्यालयों में लैक्चरर्स के पदनाम, जैसे स्कूलों में पदनाम दिये गये हैं वैसे ही कॉलेजों में लैक्चरर्स को असिस्टेंट प्रोफेसर, रीडर, प्रोफेसर का पदनाम देकर सम्मानित किया जाए जिसकी घोषणा रुक्टा के राष्ट्रीय सम्मेलन में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की थी, उसकी पालना कराने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, बांसवाड़ा जैसे छोटे जिले में विश्वविद्यालय खोला गया है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि नागौर जिले में विश्वविद्यालय खोला जाए।

माननीय सभापति महोदय, कॉलेज लैक्चरर्स के करीब 1500 पदों की अभ्यर्थना सैद्धांतिक सहमति के द्वारा सरकार ने आरपीएससी को भेज दी जिसकी लिखित परीक्षा भी हो गयी है, लेकिन इनके साक्षात्कार अभी तक नहीं हुए हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वे साक्षात्कार जल्दी कराये जाएं।

माननीय सभापति महोदय, परबतसर, मकराना, नावां में पिछले बजट में महाविद्यालय खोला गया था जिसमें से एक सरकारी स्कूल के भवन में वह महाविद्यालय चल रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसकी भूमि का आवंटन किया जाए और उसकी राशि देकर उसका भवन बनाया जाए। साथ में वहां पर स्टाफ की भी पूरी व्यवस्था की जाए और कॉमर्स व विज्ञान के विषय भी वहां खोले जाए, यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

(श्री मानसिंह किनसरिया)

माननीय सभापति महोदय, मेरे परबतसर विधान सभा क्षेत्र में कुछ उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जो काफी दूरी में हैं जिनसे हाईस्कूल काफी दूर पड़ते हैं। वहां आठवीं तक के बच्चे उस स्थान तक जा नहीं सकते। 10 किलोमीटर है, मेगा हाइवे भी इसमें पड़ता है, वहां तक पहुंच नहीं पाते। मेरी कुछ ग्राम पंचायत हैं जिसमें ग्राम पंचायत खारड़िया की बवली के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए। ग्राम पंचायत पीपलाद के मेघ गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए। ग्राम पंचायत रूणीजा के धोकलिया के उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए। ग्राम पंचायत मीठड़ी की बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए, धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की डिमाण्ड संख्या 24 कला, शिक्षा (व्यवधान)

श्री सभापति: कौनसी डिमाण्ड पर?

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): 24 पर।

श्री सभापति: 34 पर, क्या करना चाहते हैं?

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): 24 बोल रही हूं साहब। आपकी अनुमति से मांग संख्या 24, शिक्षा, कला संस्कृति पर मैं अपने भाषण को टेबल करना चाहती हूं।

श्री सभापति: इजाजत है। माननीय सदस्य श्री भागीरथ चौधरी।

(माननीय सदस्या श्रीमती सोनादेवी द्वारा अपना लिखित वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, कोई कहते हैं शिक्षा के बगैर जीवन अधूरा है। मेरा मानना है कि शिक्षा के बिना जीवन शून्य है। आज इक्कीसवीं सदी है और इस इक्कीसवीं सदी में शिक्षा

(श्री भागीरथ चौधरी)

से कोई वंचित रह जाए इससे बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकरजी ने एक जगह कहा है कि मनुष्य के लिए भोजन अनिवार्य है। भोजन के बगैर मनुष्य को जीवित रहने में कठिनाई होती है, परन्तु बाबा साहब ने यह भी कहा कि भोजन से भी ज्यादा जरूरत है शिक्षा की। शायद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकरजी ने इस चीज को समझा होगा कि आज हमारा देश पिछड़ा हुआ है तो शिक्षा की कमी से पिछड़ा हुआ है।

सभापति महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश के शासक देश की आजादी के बाद जिन्होंने सत्ता संभाली, शायद उनका मन था कि यह देश की जनता अशिक्षित रहे, निर्धन रहे ताकि हमारे चंगुल में फंसे रहे और हम सत्ता का आनन्द लेते रहे। आज इस देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। कमी तो उसे तलाशने की है और तराशने की है, परन्तु बड़ी खुशी है चाहे केन्द्र में, चाहे राज्य में, जब-जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। केन्द्र में जब आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तब यह शिक्षा का अलख जगा था कि सबको शिक्षा मिले। मुझे पता है तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशीजी ने यह सर्वशिक्षा का अलख जगाया था। उसी का परिणाम है, प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्य कह रहे हैं ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, आज जो हर जगह सरकारी विद्यालय खुले हैं ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। बड़ी खुशी की बात है, मैंने कहा प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आज पूरी दुनिया में चाहे डॉक्टर्स हो या इंजीनियर्स हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, चाहे आस्ट्रेलिया हो, हर जगह हमारी प्रतिभा से पूरी दुनिया भयाक्रांत है। भारतवर्ष में प्रतिभा इतनी है, यदि इनको अच्छी शिक्षा मिल गयी तो पूरी दुनिया में ये छा जाएंगे। जिस पार्टी ने वर्षों तक केन्द्र व राज्य में सरकार दी है उन्होंने आम जनता को पीछे धकेलने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे खुशी है कि केन्द्र और राज्य सरकार में जब-जब भी भारतीय जनता पार्टी आयी है, वहां अटल बिहारी वाजपेयी जी, अब नरेन्द्र भाई मोदीजी और राजस्थान में भैरोंसिंह जी शेखावत की सरकार रही हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा

(श्री भागीरथ चौधरी)

राजे जी ने जब राजस्थान में सरकार संभाली, एक महिला होने के नाते उन्होंने इस राजस्थान में शिक्षा का अलख जगाया। उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से देश में आगे बढ़ा है। परन्तु दुर्भाग्य है जब 2008 में कांग्रेस की सरकार आयी, इन्होंने शिक्षा का भट्टा बिठा दिया। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि इन्होंने निर्णय लिया कि आठवीं तक बच्चे को फेल ही नहीं करना है। मुझे तो लग रहा है इनकी बाहर विदेशों से कोई सैटिंग हैं और ये चाहते हैं इस देश को कमजोर करें। हमारे इस देश की प्रतिभा को दबा दिया जाए ताकि यह देश आगे नहीं बढ़े। जब मकान की नींव कमजोर होगी तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि उसके ऊपर कोई इमारत खड़ी कर देंगे। मेरा मानना है एक बहुत बड़ी साजिश के तहत इन्होंने देखा बच्चे खुश हो जाएंगे, शिक्षक खुश हो जाएंगे, उनके अभिभावक खुश हो जाएंगे। उनको पता नहीं है, यह एक बहुत बड़ी विदेशी साजिश है। इसलिए इन्होंने इस प्रदेश में 2008 से 2013 तक शिक्षा के क्षेत्र में भट्टा बिठा दिया। बड़ी खुशी की बात है 2013 में हमारे इस प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने सत्ता संभाली और हर क्षेत्र में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, सबको शिक्षा मिले, इसके लिए उन्होंने एक अभिनव प्रयास किया। उसका प्रमाण है पांच हजार सीनियर सैकण्डरी स्कूलें एक झटके में प्रदेश में खोल दीं।

मुझे पता है कि जो सामने विपक्ष के माननीय सदस्य बैठे हैं तो इनकी सरकार में एक भी विद्‌यालय को क्रमोन्नत करते थे तो जनता का इतना एहसान लेते थे और यह भी कहते थे कि आप गांव वाले फिफ्टी परसेंट सहयोग करोगे तो ही आपकी स्कूल क्रमोन्नत होगी। परन्तु खुशी की बात है कि हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री और हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने इस प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है जिनमें स्कूल में समन्वय, दूसरा प्रमोशन, तीसरा नामांकन बढ़ाना है।

सभापति महोदय, इन तीन वर्षों में साढ़े 17 लाख बच्चों का नामांकन बढ़ा है, यह एक रिकार्ड है। इस प्रदेश में नहीं, इस देश में नम्बर वन पर रहे हैं और सरकारी व़िद्‌यालयों में साढ़े 17 लाख नामांकन तीन वर्ष में बढ़ा है और यह हम सबके लिए गौरव की बात है। आज मैं इस वर्ष की बात

(श्री भागीरथ चौधरी)

करूं तो इस वर्ष में 12 प्रतिशत नामांकन की वृद्धि सरकारी विद्यालयों में हुई है जबकि पिछली सरकार के तीन सत्रों में सरकारी विद्यालयों के नामांकन में भारी गिरावट आई थी और 12 लाख विद्यार्थियों का नामांकन कम हुआ था। अब आप यह तुलना कर लें हमारी सरकार की हमारी मुख्य मंत्रीजी और हमारे शिक्षा मंत्री जी से यह तुलना कर लें तो कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली वाला मामला है।

शिक्षा के क्षेत्र में देखिये, यह सच्चाई है, आपकी मजबूरी है और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड के चुनाव के बाद में तो आपको सोच लेना चाहिए। (व्यवधान) हम सच कह रहे हैं। अब मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखने से कोई फायदा नहीं है।

सभापति महोदय, हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदीजी ने जो सबका साथ-सबका विकास, हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे जी की छत्तीसों कौम को साथ लेकर चलने की जो प्रवृत्ति है वो आपको कहीं नहीं छोड़ेगी और कांग्रेस मुक्त भारत होगा। आप चिंता मत करो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, डिमाण्ड पर बोलें।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, मेरा यह कहना है, मैं एक बात बताऊं। "मुख्य मंत्री राजश्री योजना" है। उसमें जन्म के समय 2500 रुपये, प्रथम वर्षगांठ पर 2500 रुपये, विद्यालय में प्रवेश लेने पर 4000 रुपये, कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5000 रुपये, कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11 हजार रुपये, 12वीं उत्तीर्ण होने पर 25 हजार रुपये, कुल 50 हजार रुपये मुख्य मंत्री राजश्री योजना में दिये जा रहे हैं। और ऐसी कई अनगिनत योजनाएं हैं। "बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ" योजना है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि हमारी इस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी को और शिक्षा राज्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस देश में प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में नम्बर वन पर लाये हैं। इसके लिए मैं उच्च शिक्षा मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री, दोनों को बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहूंगा।

(श्री भागीरथ चौधरी)

सभापति महोदय, आज मैं एक बात कहना चाहूंगा। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि आज देश की आजादी के 70 वर्ष बाद भी अंग्रेजों की चलाई हुई कुछ नीतियां हैं वो आज भी चल रही हैं चाहे कांग्रेस की सरकार आई हो, चाहे इसमें हमारी सरकार आई हो। सभापति महोदय, आज यह हालत है, मैं शिक्षक भाई-बहन की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे कोई कर्मचारी हो, कोई अधिकारी हो यदि सम्भागीय मुख्यालय के ऊपर उसकी ड्यूटी है तो उसको हाउस भत्ता चौगुना मिलता है। वह जिला मुख्यालय या उपखण्ड कार्यालय पर हो तो उसका आधा मिलता है और गांवों के अन्दर चाहे शिक्षक भाई-बहन हो या दूसरे हो, यदि उनकी वहां ड्यूटी लगाई जाती है तो सभापति महोदय, उसको कोई सुविधा नहीं दी जाती है। हाउस रेंट उसको मिलता ही नहीं है और मिलता है तो न के बराबर मिलता है। जबकि मेरा कहना है कि यह उल्टा होना चाहिए। गांवों में शिक्षक भाई-बहनों को सम्भागीय मुख्यालय से चौगुना हाउस रेंट मिलना चाहिए और हम इस अंग्रेजों की नीति को अभी भी घसीट रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि इस स्थिति को बदलना चाहिए और कब तक इस ढर्रे को ऐसे ही धकेलते रहेंगे तो आखिर इस पर सोच-विचार करना पड़ेगा। आज सम्भागीय मुख्यालय, जिला मुख्यालय पर कोई कर्मचारी है या कोई शिक्षक भाई-बहन है तो उसको सारी सुविधाएं हैं, बच्चों को बढ़ाने के लिए अच्छे विद्यालय हैं....

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। समाप्त करें। समय जा रहा है जो मेरे हाथ में नहीं है।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, ऐसा मत करो। सभापति महोदय, मैंने मेरी बात तो अभी कही ही नहीं है। आपको तकलीफ नहीं हो रही है क्या? साथ हो न आप?

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने अच्छे काम किये हैं। सभापति महोदय, विद्यार्थी मित्रों की समस्या है। मैं मुख्य मंत्रीजी और मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। इन्होंने तो पाप कर दिया पर उन विद्यार्थी मित्रों को कहीं न कहीं समायोजित करें। इन्होंने तो ऐसा कर दिया कि अनपढ़ शिक्षक को लगा दिया और वह अनपढ़ शिक्षक क्या पढ़ाता? परन्तु वास्तव में विद्यार्थी मित्रों में जो टेलेंट है, जो योग्यता रखते हैं उनका कहीं न कहीं समावेश होना चाहिए।

(श्री भागीरथ चौधरी)

दूसरा, मेरा यह कहना है कि संस्कृत स्कूलें सीनियर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत तो हो गईं परन्तु आज वहां पद सृजित नहीं हैं। सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके पद सृजित होने चाहिए।

तीसरा, मेरा यह कहना है कि कई-कई पंचायत मुख्यालय हैं जहां सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं खुली हैं और इन्होंने कह दिया कि 40 का नामांकन होना चाहिए। सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में रियायत मिलनी चाहिए ताकि वहां सीनियर सैकण्डरी स्कूल खुल सके।

सभापति महोदय, सामने बैठने वाले तो राजनीति करते हैं परन्तु हमारी पार्टी नीति पर चलती है। आज मैं यह कह रहा हूं कि, कभी-कभी इस नीति से भी, हमारे जो समर्थक हैं, हमारे किसी के परिजन हैं, वे आज कई वर्षों से सीमावर्ती जिलों में हैं, जहां से ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। उन्होंने क्या गुनाह कर दिया कि वर्षों से वे उन जिलों में बैठे हुए हैं? सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सीमावर्ती जिलों में जो बैठे हैं और इन्होंने राजनीति करके चुन-चुनकर वहां भेज दिया जिससे वर्षों से वे बैठे हैं तो उनके बारे में भी कोई न कोई हल निकालना चाहिए।

सभापति महोदय, अब मैं मेरे क्षेत्र की बात पर पाँच मिनट लूंगा।

श्री सभापति: पाँच मिनट नहीं मिलेंगे। एक मिनट में अपनी बात पूरी करें।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री जो सुराज संकल्प यात्रा 2013 में अराई पधारी थीं तो उन्होंने अरांई में सरकारी महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी। इसलिए मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे अरांई के अन्दर, जहां सैकड़ों गांव लगते हैं और महाविद्यालय नहीं होने से या तो उनको मालपुरा जाना पड़ता है या किशनगढ़ (अजमेर) जाना पड़ता है इसलिए वहां कॉलेज की इसी बजट में घोषणा जरूर करें।

(श्री भागीरथ चौधरी)

सभापति महोदय, मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में नवीन राजकीय कृषि महाविद्यालय आगामी शिक्षण सत्र में खोलने की भी मैं मांग करता हूं और निवेदन करता हूं कि उसके ऊपर भी आप ध्यान दें।

तीसरा, मेरे यहां आर. के. पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किशनगढ़ में चित्रकला एवं रसायन शास्त्र के विषय नहीं हैं। वहां 1750 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदयजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां चित्रकला और रसायन शास्त्र खोले जाएं।

(18.00 बजे)

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, दो मिनट। मेरी मांगें तो अधूरी रह जाएंगी।

श्री सभापति: मांगें आप मंत्रीजी को बता देना। गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, मेरे वैसे ही, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, किशनगढ़...

श्री सभापति: आपके गले में गड़बड़ हो रही है। आप मंत्रीजी से...

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): हां, वही तो, इसीलिए तो। कृषि विज्ञान विषय की स्वीकृति प्रदान करें। मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा।

दूसरा, मेरे यहां राजकीय सार्दुल बालिका विद्यालय है। वहां नवीन शाला भवन में छह अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण हेतु मैं मंत्री महोदयजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इनको चालू कर दें।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय श्री घनश्यामजी मेहर।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): मेरे यहां प्राथमिक विद्यालय हाउसिंग बोर्ड में लूणचन्द बाहेती विद्यालय है। मैंने तो शहर की बात की है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-24 पर बोलने की मुझे जो अनुमति दी है...

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरा वक्तव्य सदन की पटल पर रखती हूं। आपकी सहमति चाहिए। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेरे करसूरा भांबोलाव केरिया कलां में मोहनपुरा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक में कमोन्नत करें। मंत्री महोदयजी, थोड़े उनके कारनामे बताने में मुझे टाइम लग गया।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरा लिखित वक्तव्य सदन की पटल पर रखना चाहती हूं।

श्री सभापति: आप विराजिये। भागीरथजी, विराजिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: आप बोलिये, क्या है आपका?

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरा लिखित वक्तव्य सदन के पटल पर रखना चाहती हूं। आपकी अनुमति चाहती हूं, आप हमें अनुमति दें। टेबल करना चाहती हूं।

श्री सभापति: कौनसी मांग पर? बोलो, कौनसी मांग पर?

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): मांग संख्या-24

श्री सभापति: इजाजत है।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): थैंक यू। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: मैं मांग संख्या-24 का मेरा भी टेबल करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय श्री घनश्यामजी मेहर। बोलिये बोलिये, शुरू करिये, आपका टाइम जा रहा है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या-24 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में पिछले तीन साल से शिक्षा का स्तर घटा है। इसमें सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापकों की वेतन विसंगति को लेकर लम्बे समय से चल रही हड़ताल के

(श्री घनश्याम)

लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। आज दिन तक उनकी समस्या का समाधान नहीं निकाल पाये हैं जिससे प्रदेश के अध्यापकों में भारी रोष व्याप्त है। इस संबंध में कई बार प्रदेश के अध्यापकों द्वारा आंदोलन किये गये हैं। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापकों के वेतन विसंगति के मामले में भारी अंतर कर रखा है जिससे कर्मचारियों की पे-स्केल में बढ़ोतरी की गई थी। फिर पे-स्केल को रिवाइज क्यों कर दिया गया? जब राजस्थान में वरिष्ठ शिक्षक संघ की अनुशंसा पर इस वेतन विसंगति को सरकार ने 60 दिवस कार्य योजना के तहत लिया था...

श्री सभापति: माननीय सदस्या, इधर से नहीं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): विभाग में उस विसंगति को पे-स्केल 5500-9000 पर स्पष्टीकरण के बजाय 4200 ग्रेड-पे पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, जबकि शिक्षा विभाग के सभी पदनामों पर ग्रेड-पे बढ़ाया गया था।

माननीय सभापति महोदय, वरिष्ठ अध्यापकों के सन्दर्भ में 5500-9000 पे-स्केल में 4200 की ग्रेड-पे की तुलना में केन्द्र में 4200 की ग्रेड-पे की गई थी जबकि केन्द्र में 4200 की ग्रेड-पे तृतीय श्रेणी अध्यापकों को देय है। वित्त विभाग द्वारा ग्रेड-पे के साथ-साथ समकक्ष पदनाम वरिष्ठ अध्यापकों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया जबकि केन्द्र में इस समकक्ष पदनाम पर पे-स्केल 7400-10500 का मूल वेतन, 17140 देय है। इसी संबंध में मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस वेतन विसंगति को समाप्त कर वरिष्ठ अध्यापकों को वांछित लाभ प्रदान करायें ताकि प्रदेश में अध्यापकों में व्याप्त असंतोष को समाप्त किया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी एक माड एरिया है। उसमें भी शिक्षा का स्तर बहुत घटा है। बहुत सारे स्कूलों को सरकार ने बंद किया है। 27,000 स्कूल बंद करने के नाम पर, जैसी सरकार ने कहा कि हम एकीकरण कर रहे हैं। एकीकरण नहीं किया, उनको बंद किया गया है और बंद करने की वजह से आज प्रदेश में गरीब, मजदूर, किसानों के बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, इसे जो भी पीएगा, चाहे गरीब हो, चाहे

(श्री घनश्याम)

दलित हो, वह शेर की तरह दहाड़ेगा। आज शिक्षा का स्तर सरकार कमजोर कर रही है, उसकी वजह यह नहीं है। उसकी वजह यह है कि गरीब और मजदूरों के बच्चे नहीं पढ़ें, किसानों के बच्चे शिक्षा का लाभ नहीं उठा सके। आज उद्योगपति, व्यापारी और बड़े वर्ग के लोग तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा लेते हैं, अच्छी शिक्षा कहीं भी ग्रहण करा लेते हैं पर जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो नरेगा में काम करते हैं, उनके बच्चे आज शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। यह सरकार उनके साथ बहुत कुठाराघात कर रही है। इसी तरह से अब हालात पैदा यों किये गये हैं कि ये लोग शिक्षा ग्रहण करके हमसे अधिकार की मांग करते हैं, नौकरी की मांग करते हैं तो वह सरकार को बुरे लगते हैं तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार इस तरह से गरीब, मजदूर, किसानों पर कुठाराघात नहीं करें। उनके खिलाफ इस तरह की सोच नहीं रखें।

माननीय सभापति महोदय, 10वीं और 12वीं की कक्षा में 80 प्रतिशत अंक पाने वाले बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने की सरकार ने घोषणा की थी। आज उसको लागू नहीं कर पाये हैं। अधिकांश बालिका विद्यालयों को बंद करने का काम भी सरकार ने किया है। यह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है।

राजनीति से प्रेरित होकर स्थानान्तरण प्रदेश में किये जा रहे हैं। आरएसएस का कोई भी कार्यकर्ता कहेगा तो उसका स्थानान्तरण हो जाएगा। एमएलए, एमपी और किसी भी राजनैतिक लोगों के कहने से स्थानान्तरण इस प्रदेश में नहीं हो रहे। यह भी अब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। (व्यवधान) यह पालिसी नहीं है। इसको पालिसी नहीं कह सकते आप।

श्री सभापति: आप आसन को सम्बोधित करें। आप अपना काम करें।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): इसी तरह व्याख्याताओं के 29,000 पद रिक्त हैं प्रदेश में। (व्यवधान)

(18.06 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सुनिये साहब, आप 15 लाख नौकरी देने की बात करते थे। अब 15 लाख नौकरी नहीं देकर, इस प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती कर देते। माननीय

(श्री घनश्याम)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि 15 लाख नौकरी नहीं देकर, आप शिक्षकों की भर्ती करें और शिक्षकों के जितने भी रिक्त पद पड़े हैं, उनको भरने का काम करें जिससे प्रदेश में अच्छी शिक्षा का स्तर बन सके और गरीब लोगों को शिक्षा का लाभ मिल सके। लगभग 11,000 विद्यालयों में एक-एक शिक्षक हैं आज की तारीख में। कैसे वह शिक्षा चल सकती है? कैसे वह स्कूल चल सकते हैं? ऐसे हालात पैदा आपने किये हैं पिछले तीन साल में।

मदरसों में कम्प्यूटरीकरण करने का वादा भी आप लोगों ने पूरा नहीं किया।

आज प्रदेश में छात्रवृत्ति की जो पोजिशन है, पिछले तीन साल से बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और वे दर-दर की ठोकरें खाते डोल रहे हैं। कई बार मंत्रीजी से हमने निवेदन किया कि क्या वजह है, आप इनको छात्रवृत्ति क्यों नहीं उपलब्ध करा रहे हैं?

इसी के साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में बहुत सारे विषयों के अध्यापक नहीं हैं। मेरे यहां एक सीनियर सैकण्डरी स्कूल में न गणित का अध्यापक है, न संस्कृत का अध्यापक है। गढ़मोरा एक बहुत बड़ा कस्बा है। वहां जब अध्यापक नहीं होंगे तो फिर इस शिक्षा का क्या स्तर होगा? आप यह पूरी तरह से जान सकते हैं।

इसी तरह विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के शौचालय हैं, उनकी हालत बहुत खराब हैं। अगर हमको शौचालय बनाने हैं तो छात्र और छात्राओं के पृथक्-पृथक् बनाने होंगे। उनकी दूरी निश्चित करनी होगी। उससे भी व्यवस्था हमारे विद्यालयों की खराब होती है।

इसी के साथ-साथ, कन्या महाविद्यालयों में महिला अध्यापक को ही लगाया जाये, जबकि ज्यादातर कन्या महाविद्यालयों में जेंट्स अध्यापक लगा रखे हैं। उससे भी शिक्षा की व्यवस्था खराब हो रही है।

इसी के साथ-साथ, स्कूलों में बच्चे मोबाइल लेकर साथ चले जाते हैं। इससे भी शिक्षा में व्यवधान पैदा होता है। इस पर भी प्रतिबंध लगाया जाये।

(श्री घनश्याम)

पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं विद्यालयों की, उनका जीर्णोद्धार करने के लिए भी सरकार ध्यान दें। हमारे क्षेत्र में कई विद्यालय ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग्स गिरने की नौबत आ रही है। उनको 'रमसा' से दुबारा ठीक कराया जाये।

राजकीय महाविद्यालयों में खेल के मैदान नहीं हैं। आज चारागाह भूमि पूरे प्रदेश में बहुत जगह उपलब्ध है। उन चारागाह भूमियों को सरकार बेचने का काम नहीं करें। स्कूलों के लिए, खेलने के ग्राउण्ड के लिए उनको अलाटमेंट करने का काम सरकार करें।

इसके साथ-साथ राजकीय महाविद्यालय, गढ़मोरा में भी आप इसको रमसा से ठीक कराने का काम करेंगे।

इसके साथ-साथ, मेरा आपसे निवेदन है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को आपने आदर्श विद्यालय बनाने की घोषणा की थी। ...(व्यवधान)... बिना सब्जेक्ट के लगा रखे हैं प्रदेश में। ऐसे हालात हैं। ये तो आप जानते हो। वर्तमान में कहीं भी आपने आदर्श विद्यालय नहीं खोले हैं। इनमें 1340 की जगह आपने 600 अध्यापक लगाये हैं। आप जान सकते हैं शिक्षा का क्या स्तर आप लोगों ने कर दिया है।

प्रदेश में जो हालात पिछले तीन साल में शिक्षा के पैदा हुए हैं। यह सब पूरे राजस्थान की जनता के सामने है। कई बार इस विषय को आपके सामने रखा गया है। हाउस में पिछले बजट में भी यह घोषणा आपने की थी कि हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे और शिक्षकों को लगायेंगे। आज उन स्कूलों को आपने बंद किया है और एकीकरण के नाम पर जो शिक्षक आपके पास बचे, उनको भी आपने एक-एक लगाकर जो प्रदेश में हालात पैदा किये हैं, उससे स्कूलों का शिक्षा का स्तर दिनोंदिन गिरता जा रहा है।

इसी तरह से, करौली में दो साल पहले आपने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है उसमें न तो कोई आपने बिल्डिंग बनाने का कार्य किया है और न उसको चालू करने का काम किया है। मेरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि इसको भी चालू करवाने की कृपा करेंगे।

शिक्षक सहायकों की भर्ती आपने की है और अभी वो भर्ती करने जा रहे हैं। तो ये शिक्षक सहायकों की भर्ती किस नियम के तहत की जा रही

(श्री घनश्याम)

है? इसमें आप लोग अपने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को भर रहे हैं। किसी तरह का इसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा। जब 27,000 आप भर रहे हैं तो इसमें 13,500 के आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। उस नियम को भी आप लोगों ने खतम कर दिया। मनमाने तरीके से, एक तानाशाह तरीके से आप इस सरकार को चला रहे हैं, यह बहुत निन्दनीय है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को चेताना चाहता हूं कि इस तरह तानाशाही और मनमाना रवैया नहीं चलायें, नहीं तो आने वाले चुनावों में जनता आप लोगों को सत्ता से बाहर कर देगी और वह हालात पैदा करेगी ...(व्यवधान)... नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं है मंत्रीजी, आपको क्षेत्र में और प्रदेश में जाकर देखना होगा कि प्रदेश में शिक्षा का क्या स्तर हो गया है। आज जो हालात शिक्षा के आपने पैदा किये हैं, ये पिछले सत्तर साल में कभी नहीं हुए। पचास घर की ढाणी थी तो कांग्रेस के राज में वहां भी स्कूल खोलने का हमने काम किया और आपने आज उन स्कूलों को बंद किया और बंद इसलिए किया क्योंकि आपको ईर्ष्या है। गरीब मजदूर किसानों के बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं करे। शिक्षा से वंचित रखना चाहते हो उन लोगों को आप। इसलिए इन स्कूलों को बंद किया है। बड़े लोगों के बच्चे तो अच्छे प्राइवेट स्कूलों-कॉलेजों में पढ़ते हैं पर आज हालात ये पैदा हो गये हैं कि जो स्कूल बंद किये, वे बच्चे या तो घर बैठ गये हैं या मजदूरी कर रहे हैं। होटलों पर काम कर रहे हैं। वे प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। तो जब प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तो वो इसी तरह से मजदूरी करेंगे, और जब वो पढ़ लेते तो अधिकार की मांग करते तो आपको बुरे लगते, वो नौकरी की मांग करते।

इसी तरह से एसबीसी के जो बच्चे थे साढ़े चार हजार उनको आपने पोस्टिंग तो दे दी, पर आज उनको नौकरी पर नहीं ले रहे हो। यह भी एक दुर्भाग्य का विषय है। जब सरकार ने विज्ञप्ति निकाली उन्होंने परीक्षा दी, पास हो गये। सलेक्शन हो गया और सलेक्शन होने के बाद आप उनको ले नहीं रहे हो। जगह-जगह प्रदेश में आंदोलन हो रहे हैं। सरकार उनसे बातचीत नहीं कर पा रही है। तो क्यों ऐसी क्या वजह है कि आप लोग उनसे बात भी नहीं कर सकते, उनकी पीड़ा को आप जान नहीं सकते? जब बात नहीं कर सकते तो आप समस्या को क्या दूर करोगे।

(श्री घनश्याम)

इसी तरह से प्रदेश में 10-15 जगह आंदोलन चल रहे हैं, उनसे सरकार को वार्ता करनी चाहिए। उनसे पूछना चाहिए पर आज सरकार पूरी तरह संवेदनहीन बनी हुई है। लोगों के प्रति ऐसा तानाशाह रवैया आप लोगों ने अपना रखा है कि अगर इसी तरह का रवैया चला तो प्रदेश किस स्तर पर जाएगा, यह आप जान सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से, मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में इसके अतिरिक्त मॉडल स्कूल स्कीम टोडाभीम गोपालपुरा, नांगल शेरपुर, नांगल लाट, मुखेपुरा, अभयपुरा आदि विद्यालयों में पीने का पानी नहीं है और वहां न कोई शौचालय की व्यवस्था है। इसके कारण भारी परेशानी का सामना वहां विद्यार्थी छात्र-छात्राओं को करना पड़ रहा है।

इसी के साथ-साथ आप स्कूल यूनिफार्म को चेंज कर रहे हैं। इसके क्या कारण हैं? पहले से जो चली आ रही है वो बढ़िया यूनिफार्म है। उसमें भी आप एक आरएसएस का वो लगाना चाहते हो और प्रदेश की यूनिफार्म को चेंज करके ...(व्यवधान)... यूनिफार्म को आप क्यों चेंज कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? आप भगवाकरण करना चाहते हो शिक्षा का भी। ...(व्यवधान)... आपके समझ में आना चाहिए। आपको जनता समझाएगी। हम तो क्या समझायेंगे, राजस्थान की जनता समझा देगी थोड़े दिन बाद। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, आप इधर-उधर की बातों पर ध्यान मत दो।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन है, मैंने जो सुझाव दिये हैं उनको आप पूरी तरह से मानें।

इसी तरह से यूनिवर्सिटी में परीक्षा कंट्रोलर के वेतन का मामला है, इस पर भी आप ध्यान दें।

एक तरफ आपने कहा था कि पूरे उपखंडों पर कॉलेज खोलने का काम सरकार करेगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में नादौती में उपखंड कार्यालय है और वहां एक भी कॉलेज, न प्राइवेट और न सरकारी है तो नादौती उपखंड पर भी आपकी कॉलेज खोलने की मंशा हो तो आप घोषणा करें। इसी के साथ,

(श्री घनश्याम)

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अंजू धानका।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको पधारने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं, विधान सभा क्षेत्र बस्सी जिला जयपुर में एक भी राजकीय बालिका महाविद्यालय न होने से छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित हो रही हैं। बस्सी में राजकीय बालिका महाविद्यालय नहीं होने के कारण बहुत-सी छात्राओं को अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ती है। हर साल तीन से चार हजार लड़कियां स्कूल पास-आउट करती हैं, ट्वेल्थ पास-आउट करती हैं, लेकिन उनको वहीं पर अपनी शिक्षा को विराम देना पड़ता है, क्योंकि वहां से जयपुर पच्चीस किलोमीटर और दौसा सैंतीस किलोमीटर पड़ता है और आजकल के माहौल के हिसाब से कोई भी मां-बाप अपने बच्चे को इतनी दूर भेजना नहीं चाहता। दूसरा यह है कि जैसे हम लोग हमेशा शिक्षा की बात करते हैं कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बढ़ाओ, लेकिन जब महाविद्यालय नहीं होगा तब तक आगे की पढ़ाई होना संभव नहीं है तो मैं आपसे मांग करती हूं कि बालिका महाविद्यालय खोला जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले आठ साल से छात्राओं के लिए बालिका महाविद्यालय की मांग कर रही हूं, परंतु हर बार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता न होने का हवाला दिया जाता है। बजट पर बहस के दौरान भी मैंने मेरा पूरा फोकस महिलाओं पर ही रखा और उसी बात को मैं दुबारा दोहराना चाहती हूं कि महिलाओं के प्रति सिर्फ बातें करने से नहीं होगा। माननीय मंत्रीजी महिला हैं तो बालिकाओं का विशेष ध्यान रखते हुए, इस बार कम से कम, जैसे आठ साल मुझे मांगते-मांगते हो गये, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, लेकिन बच्चियों के लिए आज तक किसी भी सरकार ने सुनवाई नहीं की है। मैं आपसे मांग करती हूं, हालांकि सभी की कांस्टीट्यएन्सी में यह प्रोब्लम है। सभी चाहते हैं और आपके घोषणा पत्र के हिसाब से आशावादी भी ज्यादा हो गये थे सभी कि

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

हां, सभी को उपखंड स्तर पर महाविद्यालय मिलेगा, लेकिन आपने उसमें कुछ पॉलिसीज लगा दीं कि नहीं, उसमें मिलेगा जिसमें निजी नहीं हैं, जो आपने क्लियर अपने घोषणा पत्र में नहीं किया था।

इसलिए शायद सबकी उम्मीदें हैं और मेरी उम्मीदें ज्यादा इसलिए है और मैं ज्यादा हक से इसलिए मांग करती हूं आपसे कि सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री, देवस्थान बोर्ड चेयरमेन और आपके प्रदेशाध्यक्ष ने, मैं फिर दोहराती हूं कि जून, 2016 में मुझसे वादा किया था कि आपको सौ प्रतिशत महाविद्यालय दिया जाएगा और बस्सी क्षेत्र के विकास का सब्जबाग दिखा करके मुझसे अपना सपोर्ट लिया। और उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी से पहले एक बार पहले भी मुझे झुंझुनूं भेजा गया अपने सपोर्ट में और फिर बाद में झुनझुना पकड़ा दिया कि बजाते रहो पाँच साल, हम कुछ नहीं करेंगे। पाँच साल तक विकास के नाम पर बार-बार जो मुझे ठगा जा रहा है, आज मैं सदन के माध्यम से कहना चाहती हूं कि कम से कम अब, जबकि समय बहुत कम रह गया है और हमारे क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी योजनाएं और बहुत सारी उपलब्धियां हैं कांग्रेस सरकार की पिछली बार की, जो 2009 से 2013 तक का कार्यकाल था उसकी, तो जिनके लिए मैं जब क्षेत्र में जाती है तो लोग पूछते हैं कि क्या किया। तो जितनी भी योजनाएं या स्कीम्स मैं उनको बताती हूं उपलब्धियां बताती हूं वो कांग्रेस सरकार के समय की हैं। मैं यह चाहती हूं कि आपके समय की अभी तक मेरे क्षेत्र में एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जो मैं गिनवा सकूं कि हां, बीजेपी सरकार आयी थी तो उन्होंने हमें यह दिया था।

मैं आपसे मांग करती हूं कि बालिका महाविद्यालय हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी मांग है। इस मांग को अगर आप पूरी कर देंगे तो पाँच साल में एक उपलब्धि आपकी भी हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि झुंझुनूं भेजकर जो झुनझुना पकड़ाया था, अबकी बार वह काम नहीं करेंगे।

दूसरी बात मैं समानीकरण की करना चाहती हूं। आपने समानीकरण किया वह बहुत अच्छा किया। समानीकरण करने से जो दो-चार बच्चे एक स्कूल में बैठे रहते थे जिसकी वजह से जो शिक्षक थे वह एक तरह से वेस्ट

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

होते थे, वह बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते थे। समानीकरण अच्छी योजना है लेकिन उसका जिस तरह से क्रियान्वयन हुआ है, वह बहुत अच्छा नहीं है। जहां मर्ज होकर बच्चे एक जगह हो गये हैं वहां पर बिल्डिंग नहीं है, वहां पर शौचालय नहीं है, पीने का पानी नहीं है। स्कूल मर्ज होने के बाद बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ रहे हैं। अभी मैंने अपने बजट से कई स्कूल में फर्नीचर दिये हैं लेकिन वह फर्नीचर पेड़ों के नीचे रखे हुए हैं। यह एक बहुत बड़ी दुविधा है कि समानीकरण अच्छा होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा तकलीफदेह हो रहा है। इस तकलीफ को आप कम कर सकते हैं। जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या ज्यादा हो गई है या स्कूल मर्ज कर दिये हैं, वहां पर ज्यादा बजट दें ताकि वहां पर बिल्डिंग, कमरों की व्यवस्था की जा सके और शौचालय बनाये जा सकें।

इसके अलावा मैं शिक्षा में प्राथमिक विद्यालय की बात करना चाहती हूं। मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि प्राथमिक विद्यालय पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये। सिर्फ सरकार ही नहीं, टीचर ही नहीं, खुद अभिभावक भी यह सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, छोटी क्लास में पढता है तो कोई फर्क नहीं पडता है। अगर वह फेल होता है तो उस पर खुद अभिभावक भी ध्यान नहीं देते हैं, टीचर्स भी ध्यान नहीं देते हैं। मिड-डे मील से बच्चे खुश होकर चले जाते हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी उनकी शिक्षा पर होनी चाहिये। उनको उचित और क्वालिटी की शिक्षा मिलनी चाहिये। शिक्षा में क्वालिटी होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर बेस मजबूत होगा तो ही वह ऊपर की शिक्षा अच्छे से ले पायेगा। इसलिए नींव मजबूत होना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहती हूं, हालांकि यह थोड़ा सा पर्सनल है, मेरी बेटी को फोर्थ में ग्रेस मार्क्स देकर फिफ्थ में भेजा गया था। मैंने खुद स्कूल जाकर उसको फेल करवाया। मैंने कहा, नहीं, आप इसको फोर्थ में रखो, आप इसको फिफ्थ में मत डालो क्योंकि अगर इसका बेस कमजोर हो गया तो यह जिंदगी में कुछ नहीं कर पायेगी। अभिभावक के तौर पर जो मैंने किया, तो इसके लिये हमें प्रेरित भी करना चाहिये, विज्ञापन के द्वारा या जैसे भी। सरकार के साथ-साथ अभिभावक भी बच्चों की जो पांचवीं तक की क्लासेज हैं उनको सीरियसली लें ताकि उनका बेस मजबूत हो सके।

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

मेरे क्षेत्र में नई का नाथ एक धार्मिक स्थल है, जिसकी बहुत मान्यता है। लगभग 20 लाख लोग हर साल वहां पर आते हैं, उसकी तरफ में आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी की ग्राम पंचायत बांसखों में नई का नाथ के महादेव का मंदिर धार्मिक स्थल है। उस मंदिर की अधिकतर भूमि वन विभाग के अधीन है। नई का नाथ महादेव मंदिर विधान सभा क्षेत्र बस्सी एवं अन्य लोगों की आस्था का प्रतीक है। प्रत्येक वर्ष लगभग 20 लाख लोग यहां आते हैं। नई का नाथ महादेव मंदिर पर प्रत्येक सोमवार सावन के महीने में, अमावस एवं पूर्णमासी से पूर्व के दिन बहुत संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं। लगभग 36 बीघा जमीन राज्य सरकार की है, परंतु वन विभाग से सीमा लगी होने के कारण वन विभाग के कर्मचारी धर्मशालाओं इत्यादि में किसी भी प्रकार के कार्य एवं पानी की व्यवस्था करने पर मना कर देते हैं एवं आर्थिक तरीके से परेशान करते हैं। वहां पर बहुत सारी धर्मशालाएं हैं और उन धर्मशालाओं में अक्सर गोठ, सवामणी वगैरह होते रहते हैं। एक दिन में वहां लगभग 25 गोठ होती हैं। वहां पानी की व्यवस्था इसलिए नहीं है कि वह क्षेत्र वन क्षेत्र वन विभाग में आता है और वन विभाग के कर्मचारी सुविधा शुल्क लेकर, जहां उनकी मर्जी होती है वहां पर इजाजत दे देते हैं। इस भ्रष्टाचार को रोकने का एक तरीका यह है कि इसको पर्यटन स्थल में कर दिया जाये। नई का नाथ महादेव मंदिर पर दर्शनों के लिये तीर्थ यात्री दूर-दराज से और आसपास से भी आते हैं। सावन में बहुत बड़ा मेला यहाँ लगता है। अरावली पर्वतमालाओं की पहाड़ियों की गोद में बसा नई का नाथ धाम प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम उपहार है। सरकार के थोड़े से प्रयासों से तीर्थ यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए पंचायत समिति बस्सी की ग्राम पंचायत बांसखों में स्थित नई का नाथ महादेव मंदिर को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है।

मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन समय बहुत कम है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आपको और मेरी मांग पूरी हो जाये, सरकार से ऐसी मैं उम्मीद करती हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: मास्टर मामन सिंह।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24 पर चर्चा करने के लिये आपसे अनुमति चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने तीन सालों में शिक्षा में ऐसे कीर्तिमान स्थापित किये हैं जो 60-70 साल में भी नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी की सरकार के 50-55 साल के लंबे शासन की वजह से, इनकी शिक्षा के प्रति गलत नीतियों की वजह से शिक्षा को पाश्चात्य सभ्यता की तरफ दौड़ा दिया। शिक्षा से हमारी युवा पीढ़ी भटक चुकी थी। हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी की सोच और उनके निर्देश पर माननीय मंत्री महोदय ने पुन: भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय मूल तत्व की तरफ शिक्षा को लाने का प्रयत्न किया है। शिक्षा संस्कार पूर्ण हो, विद्‌यालयों में प्रार्थना हो, विद्‌यालयों में सूर्य को प्रणाम हो, विद्‌यालय में वंदे मातरम् हो, विद्‌यालय में राष्ट्रीयता की नैतिक शिक्षा हो, यह कार्य करने की हमारे मंत्री महोदय ने शुरूआत की।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत-से उदाहरण आपको अवगत कराना चाहूंगा जिसके तहत कीर्तिमान स्थापित हुए। शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो। शिक्षा व्यावसायिक भी हो क्योंकि शिक्षा से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। शिक्षा में अगर गुणवत्ता नहीं होगी, शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई लापरवाही बरती जायेगी, तो देश, प्रदेश और गांव का विकास नहीं हो सकता। परिवार का विकास हो, हर क्षेत्र में शिक्षा की बहुत महत्ता है, इसलिए हर सरकार को यह चाहिये था कि हर बजट शिक्षा के प्रति समर्पित हो। हमारे मंत्री महोदय ने मुख्य मंत्रीजी के निर्देशानुसार शिक्षा के क्षेत्र में संस्कार पूर्ण शिक्षा देने का प्रयत्न किया। जिस पाठ्‌यक्रम में पूर्व सरकार ने सन् 1952 से ही जिन सम्राटों ने, जिन बादशाहों ने और जिन नवाबों ने हमारे देश को परतंत्र किया, अकबर महान्, किस बात का महान्? जिसने हमारे देश को गुलाम किया, उसको महान बनाने की पदवी बच्चों को किताब में पढाने का काम किया कि अकबर महान्। इससे सही शिक्षा नहीं मिल सकती। राष्ट्रीयता की भावना नहीं हो सकती। हमारे मंत्री महोदय ने इसको हटाकर बहुत ही कीर्तिमान स्थापित किया है, इसके लिये ये धन्यवाद के पात्र हैं। अकबर महान हटाकर, महाराणा प्रताप महान, पृथ्वीराज चौहान महान्, पंडित दीनदयालजी महान, इस तरह के महान् पुरुषों को पाठ्‌यक्रमों में जोडने का काम किया है, यह बहुत ही धन्यवाद का काम है।

(मास्टर मामन सिंह यादव)

इसी संदर्भ में हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बहुत से कीर्तिमान स्थापित किये हैं। प्रतिदिन विद्यालयों में नैतिक शिक्षा का काम हो रहा है जिससे बालक बालिकाओं में अच्छी सोच पैदा होगी और सही राष्ट्र का निर्माण होगा, अच्छे नागरिक होंगे। जब अच्छे नागरिक होंगे तो देश भी अच्छा होगा, विकास भी होगा और संसार में देश अग्रणी भूमिका में आयेगा। आज पूरे देश के नागरिक राष्ट्रवाद की तरफ जा रहे हैं। आज की युवा पीढी जाग चुकी है कि तुष्टिकरण खतम हो। भारतीयता, राष्ट्रीयता और वंदे मातरम् का गान हो। वह माननीया शिक्षा मंत्रीजी ने किया है। ये धन्यवाद के पात्र हैं। आदर्श अध्याय की पाठ्यपुस्तकें, जिनमें महर्षि दयानंद की पुस्तकें, महाभारत की पुस्तकें हैं। जो भारतीय संस्कृति को, राष्ट्रवाद की संस्कृति को छात्रों से व बालक-बालिकाओं से जोड़ती है, जिससे हिंदुस्तान का गौरव उनको मिलता है। इस तरह की पाठ्यपुस्तक और पुस्तकालयों में भी ऐसे ग्रन्थ और ऐसी पुस्तकें रखवाने का कार्य मंत्री महोदय ने किया है।

स्कूलों में योग शिक्षा हो ताकि बालकों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। विद्यार्थियों का स्वास्थ्य अच्छा हो और जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो दिमाग भी स्वस्थ होगा और अध्ययन भी सही होगा। यह काम किया है।

माननीय मंत्री महोदय ने मुख्य मंत्री के निर्देश पर, उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए ऐसे दस-पंद्रह काम किए हैं। समय का अभाव है, इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, जो कि प्रदेश में पहली बार हुए हैं। प्रदेश में नहीं, शायद देश में। एक साथ पाँच हजार आदर्श विद्यालय खोलना। 1952 से अब तक का इतिहास..। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य यह जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि यह रिकार्ड में रहता है। पाँच हजार विद्यालय (प्लस-टू) को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक ही कलम से खोलकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जो पहली बार हुआ है।

दूसरा, शिक्षकों की एक लाख पदोन्नतियां की, जो कि शिक्षकों ने सोचा भी नहीं था कि हम सैकेंड ग्रेड से प्रिसिंपल होकर रिटायर होंगे और अधिकारी बन जाएंगे। एक लाख के करीब पदोन्नतियां दी गई हैं। यह सत्तर साल में पहली बार हुआ है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा, यह भी पहली बार हुआ है। पहले स्कूलों

में क्या होता था कि चार अध्यापक लगा दिए। उनमें दो अंग्रेजी के हैं, लेकिन गणित नहीं। हमारे मंत्री महोदय ने सब्जेक्ट-वाइज अध्यापक लगाए हैं। एक अंग्रेजी का हो गया, दूसरा गणित का होगा, तीसरा विज्ञान का होगा, चौथा हिंदी का होगा ताकि सब्जेक्ट अध्यापक बालकों को सही रूप से शिक्षा दे। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी पहली बार हुआ है।

आज शिक्षा नीति पर विचार होना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि यह भी बनानी चाहिए। पदोन्नति होने पर हर शिक्षक को स्वयं अपना स्थान चयन करने का अधिकार दे दिया जाना चाहिए। कोई पार्टीबाजी नहीं कि वह कांग्रेस का है, वह बसपा का है, वह विरोधी है या वो किसी को गाली देने वाला है। लेकिन जिसका मेरिट में नंबर है, वह अपने स्थान का चयन कर सकता है कि यहां पर खाली है, मुझे यहां पर लगा दीजिए। यह बहुत ही कीर्तिमान का काम किया है, जिसकी सारे शिक्षा जगत में भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है।

विद्यालय दर्पण - हर विद्यालय का दर्पण अपडेट हो रहा है। पूरे विद्यालयों का डाटा आप बटन दबाकर देख सकते हो। कितने शिक्षक हैं? कितने अध्यापक हैं? कितने बालक-बालिकाएं हैं? पढ़ाई का क्या-क्या पैटर्न है? कितने कमरे हैं? यह पहली बार हुआ है।

सभी विद्यालयों में शौचालय - हमारे प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्रीजी का संकल्प है कि हर जगह शौचालय हो। आज राजस्थान के प्रत्येक विद्यालय में शौचालय और विद्युत का काम कर दिया गया है। यह भी पहली बार हुआ है।

बी.एड. स्टाफ इंटर्नशिप- बालक-बालिका बी.एड. करते थे। वे यूं ही करते थे, लेकिन अब पहली बार हर बी.एड. के विद्यार्थी को स्कूलों में चार महीनों के लिए भेजा गया है, जिससे उनको भी प्रशिक्षण मिल गया और वहां के बालकों को भी लाभ मिल गया। वे प्रशिक्षणार्थी वहां चले गए और वहां उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का काम किया है, जिससे बच्चों को फायदा मिला है। इस तरह के ऐसे बहुत से काम हैं, जो कि शिक्षा जगत में प्रदेश में पहली बार हुए हैं। इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय और हमारी मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आभार प्रकट करना चाहूंगा।

मेरी अपनी यह मान्यता है। वैसे आप सबकी भी होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री, शिक्षक हैं। माननीया मुख्य मंत्रीजी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री, शिक्षक को ही बनाया है। उन्हें शिक्षक होने के नाते शिक्षा के बारे में बारीकी से पता था। इन्होंने शिक्षक समाज का भी नाम किया है, गौरव प्रदान किया है। ऐसे शिक्षा मंत्री जिनकी हमेशा गौरवपूर्ण गाथा गाई जाएगी कि उस काल में शिक्षा मंत्री, शिक्षक थे, जिन्होंने शिक्षा का आमूलचूल परिवर्तन और पूरा ढांचा बदलकर अग्रणी.. यह सारा काम किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये तो हमारी सरकार की उपलब्धियां हो गईं। हमारी सरकार की इतनी उपलब्धियां हैं। खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी पूर्व सरकार भी इस तरह काम करती तो हमारा राजस्थान शिक्षा में पूरे देश में अग्रणी स्थान रखता। मैं मंत्री महोदय से थोड़ा सा.. क्योंकि समय कम है। मुझे पता है, उपाध्यक्ष महोदय फिर कहने लग जाएंगे कि समय हो गया तो मैं शोर्ट में करता हूं। वैसे तो और भी काफी है।

श्री उपाध्यक्ष: आप किस मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं? जो सिर्फ प्रोफेसर हैं, उसी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं या बाकी तीन का भी कर रहे हैं।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षक हूं। यह शिक्षा पर चर्चा है। तो पाँच मिनट का मुझे बोनस अंक मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: शिक्षा भी यहां दो तरह की हैं। यहां पर एक उच्च शिक्षा और है।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): उच्च शिक्षा पर बाद में।

श्री उपाध्यक्ष: उच्च शिक्षा पर बाद में आयेंगे तो ठीक है।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): : पहले इकाई नीचे से चलती है। सीढ़ी-दर-सीढ़ी चलती है।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। मैं तो समय को देख रहा था कि अभी तो आप प्राथमिक से माध्यमिक पर आए हैं और अभी तो उच्च शिक्षा बाकी है।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): मैं माननीय मंत्री महोदय को कुछ सुझाव देना चाहूंगा। आपने बहुत ही अच्छा काम किया। कीर्तिमान स्थापित किया। आप कृपया इन सुझावों पर गौर करें ताकि पूरे प्रदेश की शिक्षा में चार चाँद लग जाएं और प्रदेश के शिक्षा जगत में एक ऐसी मिसाल कायम हो। जैसे - शिक्षक वह है जो कि न तो कोई बेईमानी करता है, न कोई हेराफेरी करता है। सीधा-सादा आदमी है और अपने स्कूल में पढ़ता है। उसकी बिलकुल स्वच्छ छवि होती है। उन शिक्षकों के लिए कई समस्याएँ हैं। एक तो है प्रतिबंधित जिला। शिक्षक पंद्रह-पंद्रह साल से दूसरे ज़िलों में बैठे हुए हैं, वह भी छह सौ, आठ सौ और एक हजार किलोमीटर। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऐसी नीति बनाएं कि पाँच-सात साल बाद उसका तबादला अपने गृह जिले में हो जाए, जिससे वह अपने परिवार व रिश्तेदार के पास जा सके। यह बहुत आवश्यक है। वह वहां ऐसे रह रहा है, जैसे कोई अमरीका में जाकर बस गया है। न तो कोई समाज से संबंध रहा। पहले किसी सरकार ने नहीं किया। आप जब सारे कीर्तिमान के काम पहली बार कर रहे हो तो माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करके मई-जून में जब स्थानान्तरण होंगे तब यह प्रतिबंध खोलने का काम करें और यह तय कर दें कि पाँच या सात साल में हो जाएगा। इसी के अंदर, हैडमास्टर, प्रिसिंपल जो कि पदोन्नति में दूसरे जिलों में गए थे। दूर गए थे। उनको भी उनके निकट जिलों में लाने का काम करें। ऐसा मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है। मैंने पहले भी कहा था। कांग्रेस सरकार ने एक साथ दो हजार हैडमास्टरों की नियुक्ति की थी, जिसमें टोटल को दूर जिलों में भेज दिया। उनके लिए अब कुछ किया है। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं।

स्थानान्तरण नीति बनाई जाए ताकि शिक्षकों पर कोई राजनीति की, किसी तरह की द्वेष भावना नहीं हो। एक नीति बने, उसका काम शायद चल रहा है। वह भी मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है।

कम छात्र वाले विद्यालय, पिछली सरकार में या अब खुल गए गलती से। मेरे यहां तिजारा में ही ऐसे-ऐसे विद्यालय हैं जो आदर्श विद्यालय बन गए। पहले से ही बन रहे हैं। जिनमें 12वीं में एक छात्र है, 11वीं में 2 है, कहीं 5 है कहीं पर 4 है तो एक नीति बने। जो खुल गए और जहां पर 10 या 20 से कम छात्र है, वह आवश्यक नहीं है। उनको आवश्यकता से हटाकर,

(मास्टर मामन सिंह यादव)

जहां पर आवश्यक है, उसी विधान सभा में स्थानान्तरण कर दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय, अब इसको कन्क्लूड करें।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): हां जी।...

श्री उपाध्यक्ष: अब इसको समाप्त करने का प्रयास तो करो, देखें आप।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): मेरे यहां पर तिजारा में जूड़ पर जोडिया मेव, मिलखपुर, पालपुर, कारींडा और रूबाद 6 ऐसे विद्यालय है जिसमें अंदर 12वीं में पांच छात्र हैं, एक से पाँच तक, छठा भी नहीं है। रिकार्ड मंगा कर देख लीजिए। माननीय मंत्री महोदय तो बिराज नहीं रहे। बाकी वह तो रिकार्ड पर आएगा। इनके इसलिए बंद किए जाए कि ये गलत खुल गए। वहां पर बच्चे ही नहीं हैं। जहां बच्चे हैं जैसे खिजूरिवात, सलारपुर, सांथलका, आलमपुर, खलीरपुरी, साड़ोत, कारोली, मशीद ग्राम पुर, मुडाना, जोजाका, मिलकपुर, इनमें 25,30-35 या 40 बच्चे हैं दसवीं क्लास में, तो ऐसे में खोलने का विचार करें स्थानान्तरण करके।

अभी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बजट में घोषणा की कि 40 छात्र है वहां पर ही प्लस-टू का स्कूल खुलेगा। मेरा मंत्री महोदय से यह विनम्र निवेदन है, माननीय मुख्य मंत्रीजी से विशेष आग्रह करते हुए छात्रों की कुछ संख्या घटाए, क्योंकि 40 नहीं हो। लेकिन पंचायत मुख्यालय है और उस पंचायत में अगर एक भी प्लस-टू का स्कूल नहीं है तो वहां पर संख्या में ढील देते हुए उसमें भी खोलने का काम करेंगे। इस तरह की हमें आशा है माननीय मंत्री महोदय से। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसकी बजाय कम करें। यह तो प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा है। साहब, एक-दो मिनट। अब उच्च शिक्षा ....

श्री उपाध्यक्ष: आपको कहीं यह गलतफहमी तो नहीं हो गई, क्योंकि आप पृष्ठभूमि में अध्यापक रहे हैं कि स्कूल में तो घंटी बजती थी, कालेज में तो बजती ही नहीं है।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): उपाध्यक्ष महोदय, आपका आशीर्वाद है, आपकी इजाजत से ही बोल रहा हूं।

उच्च शिक्षा में ज्यादा नहीं है। उच्च शिक्षा में पहले तो माननीय मंत्री

(श्री उपाध्यक्ष)

महोदया को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जब ये जलदाय मंत्री थीं तो 80 करोड़ रुपये भिवाड़ी नगरपरिषद क्षेत्र में पानी के लिए दिए थे। वैसे तो 125 करोड़ है तिजारा और सब लगाकर। वह काम चल रहा है। क्यों दिए, क्योंकि भिवाड़ी में दो लाख की जनसंख्या है। एनरोल है दो लाख तो, बाकी ज्यादा है। वहां पर पानी की व्यवस्था की। दो लाख की जनसंख्या, जो राजस्थान की पहली औद्योगिक नगरी है, पूरे राजस्थान में नम्बर वन पर, औद्योगिक नगरी हरियाणा सीमा से लगती हुई, दिल्ली से लगती हुई है, उसके अंदर महाविद्यालय नहीं है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री से भी हर बार निवेदन किया है। उन्होंने थोड़ा गौर भी किया है। मंत्री महोदया से मेरा निवेदन है कि मेरी ओर से, अपनी ओर से और जनहित में भिवाड़ी जनता की ओर से माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करें। अब यह 29, 30 तारीख को जो घोषणाएं होगी, यह आज शाम को ही आप घोषणा कर दो।

एक बात है इसमें। मैं बताना चाहूंगा, आपका पैसा भी नहीं लगेगा। वहां पर भूतपूर्व सैनिकों ने, जिन्होंने देश के लिए सेवा की है, रक्षा की है, उन्होंने अपनी पेंशन का हिस्सा देकर, दस साल से ट्रस्ट चल रहा है बाबा मोहन राम महाविद्यालय। बिल्डिंग बनी हुई है, कालेज चल रहा है, 38 बीघा में चारदीवारी है, आपको केवल घोषणा करनी है, बाबा मोहनराम राजकीय महाविद्यालय भिवाड़ी। अब बताओ, इसमें क्या दिक्कत है?

श्री उपाध्यक्ष: चलिए अब बिराज जाइये।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): मंत्री महोदया घोषणा कर दें।

श्री उपाध्यक्ष: बिराज जाइये। आपको जो कहना था वह आपने आखिर में कह दिया। अब आप बिराज जाए।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): पंचायत मुख्यालय को, पहले वाले मंत्री महोदय, वह मेरे रह गए थे सारे। तो यह तो आप कर ही दो। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। भिवाड़ी का यह अहम् है, औद्योगिक नगरी है।

आपने बोलने का समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हीरालाल जी।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): साहब, मेरा एक सुझाव और रह

(श्री उपाध्यक्ष)

गया। एक सुझाव जो बहुत ही जरूरी है। प्रदेश लेवल का क्या, राष्ट्र लेवल का है। हमारे जो बच्चे पहली से बारहवीं तक पढ़ते हैं। पहली से पांचवीं तक और आठवीं तक के बच्चों को हम नीचे फर्श पर बिठाते हैं। अभी मानसिंह जी ने भी अभी यह फरमाया।

श्री उपाध्यक्ष: अब बिराज जाएं आप। आपने धन्यवाद दे दिया ना।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): नीचे बैठने से उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। टेबल-स्टूल .....

श्री उपाध्यक्ष: मैं आप सब सदस्यों से एक निवेदन करता हूं। आसन यह कोशिश करता है कि आप जब अपना वक्तव्य दे रहे हो तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो। अब आसन का भी आप कम से कम ख्याल तो रखिए। आप ही के सहयोगी है, आप ही के कलिग है जिनको आपके बाद बोलना है। अगर हम 25-25, 30-30 मिनट एक-एक सदस्य को दे देंगे ।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो पहले बोलते हैं उनको आधा-आधा घंटा, चालीस मिनट मिलती है और अंत में बोलते हैं उनको कम मिलती है। +++ यह हमारा निवेदन है। कृपया हमारी बात पर ध्यान दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: मुख्य सचेतक महोदय, अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैंने दोपहर में भी आपसे निवेदन किया था कि आपके सदस्यों को इस सदन की मर्यादा और नियमों का पालन करने की आदत ही नहीं है। धीरे-धीरे मेरे जेहन् में यह बात आ रही है कि इनको जानकारी भी है या नहीं है। मैं आपको यह हिदायत देता हूं आप आसन को फोर ग्रांटेड मत ले लो। इस प्रकार की अगर आपने बार-बार आसन की अवहेलना की तो आसन यह भी जानता है कि आपको कैसे मनवाना है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, +++ शब्द कहा है, उसको हटा दिया जाए, क्योंकि आसन के ऊपर कोई आक्षेप नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष: हटा दीजिए, अगर कहीं इसमें कांस्टीट्यूशनल रेलीवेंसी है तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माननीय गृह मंत्रीजी, सुबह बात हुई थी भरतपुर की, उस पर वक्तव्य देना चाहते थे।

श्री उपाध्यक्ष: वह तैयार हैं शायद। उन्होंने यह बात फरमाई भी थी कि जब आसन चाहे, कहे। एक बार पता करवा लेते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जी।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। अभी माननीय मामन सिंह जी ने बोलते समय यह कहा कि पहले वालों को बहुत टाइम दिया जाता है और +++ किया जाता है, +++ किया जाता है। जबकि मैं इनकी जानकारी के लिए और सदन की जानकारी के लिए बताता हूं....

श्री उपाध्यक्ष: +++ कौन करता है, पहले तो आप यह बताओ, उन्होंने +++ किसके लिए कहा।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): चाहे इन्होंने आसन के लिए कहा हो, चाहे हमारे लिए कहा हो।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, वह आपके लिए तो कह नहीं सकते। वह जो कुछ बात करते हैं आसन से करते हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): तो आसन के लिए भी कहा तो...

श्री उपाध्यक्ष: पहले तो उनसे क्षमा मंगवाइये।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): बिलकुल, मंगवाते हैं। क्षमा मांगो, मांगो।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): हां जी, मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा कि साहब, पहले ज्यादा समय मिल जाता है, बाद में समय के अभाव में समय कम मिलता है। कृपा करें, समान समय दो।

श्री उपाध्यक्ष: आप पूरी तरीके से समझकर बोलें।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): क्षमा प्रार्थी हूं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्य की गलत फहमी दूर हो जाए।

(श्री कालू लाल गुर्जर)

सबसे पहले फूलचंद जी भिण्ड़ा 27 मिनट बोले, बाबू सिंह जी 24 मिनट बोले, अलका सिंह 19 मिनट बोली, हरिसिंह रावत 16 मिनट बोले, मंजू बाघमार 17 मिनट, मानसिंह 15 मिनट, मानसिंह किनसरिया 10 मिनट, भागीरथ चौधरी 18 मिनट और यह मामन सिंह जी 24 मिनट बोले। अब इसके बाद भी अगर ये कहते हैं कि +++ और फर्क, पहले ज्यादा बोलने दिया, आप कैसी बात करते हो?

श्री उपाध्यक्ष: वैसे एक बात आप सब लोग कान खोलकर सुन लें, आसन आसन है। चाहे जिसको जितने समय तक बुलवा सकता है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपका अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अजीत सिंह।

श्री अजीत सिंह (टोंक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम मांग संख्या-24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर चर्चा कर रहे हैं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब से मानव सभ्यता का सूर्योदय हुआ है, तभी से भारत अपनी शिक्षा तथा दर्शन के लिये प्रसिद्ध रहा है। यह भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों का ही चमत्कार है कि भारतीय संस्कृति ने संसार का सदैव पथ-प्रदर्शन किया है। आज के वर्तमान युग में भी महान दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री इस बात का प्रयास कर रहे हैं। भारत के प्रत्येक युग की शिक्षा, उद्देश्य अलग-अलग रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत की संस्कृति कई चीजों को मिला-जुला कर बनी है, जिसमें भारत का लम्बा इतिहास, विलक्षण भूगोल और सिन्धु घाटी की सभ्यता के दौरान बनी और आगे चलकर वैदिक युग में विकसित हुई। बौद्ध धर्म एवं स्वर्ण युग की शुरूआत और अस्तगमन के साथ फली-फूली, अपनी खुद की प्राचीन विरासत शामिल है। इसके साथ ही पड़ौसी देशों के रिवाज, परम्पराओं से शताब्दियों से अधिक समय से भारत के रीति-रिवाज, भाषाएं, प्रथाएं, परम्पराएं इसके एक-दूसरे के परस्पर सम्बन्धों का मान, विविधताओं का एक अद्वितीय उदाहरण देती है।

उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय कला जहां एक ओर वैज्ञानिक, तकनीकी

(श्री अजीत सिंह)

आधार रखती है, वहीं दूसरी ओर भाव एवं रस का सदैव तारतम्य बना कर रखती है। भारतीय कला को जानने के लिये उपनिषद, वेद, शास्त्र, पुराण और पुरातत्व प्राचीन साहित्य का सहारा लेना पड़ता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने 13,500 किलोमीटर की सुराज संकल्प यात्रा में राजस्थान का दौरा किया। उन्होंने उस समय जिस तरह की राजस्थान की समस्याओं को अपनी आंखों से देखा, जिस तरह से प्रदेश के अन्दर शिक्षा के घटते स्तर को देखा। आपने देखा होगा कि जिस तरह के हालात राजस्थान के अन्दर शिक्षा को लेकर थे। उन्होंने एक ही आदेश किये थे सरकार के आने के बाद, एक साथ 5,000 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का काम किया, यह राजस्थान के लिये अपने-आप में एक बड़ी उपलब्धि है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार ने कार्यभार सम्भाला तो शिक्षा हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता थी, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कुप्रबन्धन किया था। उसको सुधारने के लिये हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने, शिक्षा मंत्रीजी ने अभूतपूर्व काम शिक्षा के क्षेत्र में किया। उसके लिये तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आजादी के बाद पहली बार हमारी सरकार ने शिक्षा के हित में जो कार्य किये हैं, उतने कांग्रेस ने 55 सालों के शासनकाल में नहीं किये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने आने के बाद 86,000 शिक्षकों को पहली बार डी.पी.सी. के माध्यम से प्रमोशन देने का काम किया है। यह अपने आपमें एक उपलब्धि है। 37,000 शिक्षकों की भर्ती करके बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का, विद्यालयों के नामांकन बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्रीजी का मैं आभार और अभिनन्दन करना चाहता हूं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं आभार और अभिनन्दन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर शिक्षा को लेकर जो हालात थे, जिस तरह से हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये, चाहे नि:शुल्क स्कूटी देने की बात हो, चाहे नवीं में आने के बाद बच्चियों को साइकिल देने

(श्री अजीत सिंह)

की बात हो, चाहे लेप-टॉप देने की बात हो, चाहे राजश्री योजना में ''बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ'' की बात हो, चाहे गरीब कन्या सहयोगिता विवाह की राशि देने की बात हो, हमारी सरकार ने आने के बाद अनेक काम किये हैं। चाहे माडल स्कूल खोलने की बात की हो, चाहे आदर्श स्कूल खोलने की बात की हो। आज विद्यालयों के अन्दर जिस तरह से चाहे शौचालय की बात है, हर विद्यालय के अन्दर शौचालय है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, वाकई जिस तरह से सरकारी विद्यालयों के हालात प्रदेश के अन्दर थे, वे बहुत दयनीय थे। दु:ख इस बात का है कि हम चाहे सत्तापक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, हमको इसके लिये कॉमन प्रोग्राम बनाना चाहिये कि हम अपने बच्चों के लिये, इन गरीब बच्चों को, किसान के बेटों को, मजदूर के बेटों को कैसे अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, गुणवत्तापूर्ण कैसे शिक्षा दे सकते हैं, उनको हम कैसे संसाधन उपलब्ध करवा सकते हैं, इसकी चिंता हमें करनी चाहिये।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के अन्दर, मैं आज भी जानता हूं कि विद्यालयों के अन्दर बैठने के लिये पूरे संसाधन नहीं हैं, हमने उच्च माध्यमिक विद्यालय बना तो दिये। उसके बावजूद भी आज हमने भामाशाहों के माध्यम से स्कूल में फर्नीचर देने की बात की है। हमने विद्यालयों के अन्दर आर.ओ. युक्त वाटर कूलर लगाने का प्रयास किया है, शौचालय हमने बनाये हैं। हमने हमारे कोष से कमरे बनाये, भामाशाहों के माध्यम से कमरे बनाने का भी हमने काम किया है। यह बात जरूर है कि संसाधन सीमित होने के बावजूद भी आज हमने विद्यालयों के स्तर को सुधारने का काम किया है, यह फिर भी उसकी अपेक्षा आज भी कम है। लेकिन यह दु:ख का विषय है कि 70 साल की आजादी के बाद भी शिक्षा के स्तर के ऊपर लोग चर्चा तो करते हैं लेकिन जितना परिणाम आना चाहिये, उतना नहीं आता है। मैं यशस्वी मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने तीन साल के कार्यकाल में शिक्षा के गिरते स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास किया। जिस तरह से आपने सारे सरकारी विद्यालयों के अन्दर पूरे टीचर्स देने की व्यवस्था की, आज मैं बताना चाहता हूं कि मेरे जिले के अन्दर जिस तरह से विद्यालयों के अन्दर नामांकन बढ़ा है, उससे हमारे

(श्री अजीत सिंह)

जिले का, मालपुरा के अन्दर एक बच्चा कला में मैरिट के अन्दर आया है। यह शिक्षा का स्तर उठ रहा है। आज विद्यालयों के अन्दर जिस तरह से रिजल्ट की परफोर्मेंस बनी है, यह आज शिक्षा के सुधार का नमूना मिला है। मुझे मालूम है कि आज प्राइवेट विद्यालयों के अन्दर घबराहट सी होने लगी है कि सरकारी विद्यालयों के अन्दर जिस तरह का सुधार आज आपको देखने को मिल रहा है। मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह का नवाचार करके, नये-नये कार्यक्रम करके, नये-नये क्षेत्र में आपने जिस तरह काम किया है, इससे आलोचना भले ही करें, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा काम राजस्थान के अन्दर शिक्षा में सुधार करने का किया है।

आज मुझे इससे भी ज्यादा आपको कहना पड़ेगा, मेरे क्षेत्र के अन्दर भी जिस तरह का आपने अभी, प्रदेश में कांग्रेस सरकार के समय जिन विद्यालयों के अन्दर जीरो नामांकन था, चार-चार, पाँच-पाँच अध्यापक कार्यरत थे, कई विद्यालयों में ऐसे थे जहां छात्रों के अनुपात में शिक्षक भी कम थे। हमारी सरकार ने इस विसंगति को दूर करने के लिये विद्यालयों का सेट-अप परिवर्तन कर, एकीकरण करने का काम किया है। यह ध्यान रखा है कि एक किलोमीटर पर प्राथमिक शिक्षा से कोई बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिये। आपने गरीब के बच्चे की, किसान के बच्चे की चिंता की है। इसके लिये तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा 'यू-डायस' डाटा के आधार पर, नवीन निर्माण कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। किन्तु पूर्ण जानकारी के अभाव में शिक्षकों के द्वारा 'यू-डायस' सही नहीं बनने की वजह से निर्माण कार्य, ज्यादा आवश्यक वाले विद्यालयों में स्वीकृत नहीं हो पाये हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे टोंक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोरण, हरचंदेड़ा, चन्दलाई, चिरोंज, गोपालपुरा, क्वाला बुर्ज आदि में विद्यार्थी खुले के अन्दर बैठकर अध्ययन करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि 25 प्रतिशत भी आप निर्माण कार्य के लिये विद्यालयों के अन्दर आप राशि स्वीकृत कर देंगे या कलेक्टर को अधिकृत कर देंगे तो इन बच्चों को बैठने के लिये, अच्छी

(श्री अजीत सिंह)

शिक्षा देने का जो संकल्प हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने लिया है, उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से मांग करता हूं कि टोंक जिला मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिटी नम्बर 12 है, जो छावनी क्षेत्र में स्थित है और 1981 से यह विद्यालय चल रहा है। इस विद्यालय में सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र अध्ययन कर रहे हैं। इस विद्यालय में कला एवं विज्ञान संकाय स्वीकृत है। पूर्ववर्ती सरकार के टाइम दुर्भाग्य रहा कि वहां पर, बहुत ही विचित्र बात है कि कांग्रेस सरकार ने इस विद्यालय में कला संकाय में ऐच्छिक विषय उर्दू, चित्रकला एवं भूगोल भी स्वीकृत किये हैं। इस कारण कला संकाय में उर्दू विषय के छात्र प्रवेश ले पाते हैं, लेकिन अन्य छात्रों को दूसरे विद्यालयों में प्रवेश के लिये जाना पड़ता है। माननीय मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में मैं कई बार पूर्व में भी निवेदन कर चुका हूं। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देकर इस विद्यालय में ऐच्छिक विषय हिन्दी एवं संस्कृत खोला जाना अति आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस गम्भीर विषय पर आज ही सदन के अन्दर घोषणा करेंगे तो मेरे क्षेत्र के बच्चों के लिये बहुत बड़े उपकार का काम भी करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि आज बहुत ज्यादा माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, लेकिन आपने मेरे क्षेत्र की समस्या के लिये मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये तो मैं आपका आभार और अभिनन्दन करता हूं। मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक में वर्ष 1995 से चल रहा है। इस ओर कभी भी कांग्रेस की सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। वर्तमान में इस कन्या महाविद्यालय में 550 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं। टोंक जिले का एक मात्र कन्या महाविद्यालय है, जिसमें विज्ञान संकाय नहीं होने के कारण छात्राओं को विज्ञान विषय के लिये अन्य जिलों में जाकर अध्ययन करना पड़ता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस इकलौते कन्या महाविद्यालय में विज्ञान विषय खोलने की और, इसे पी.जी. कॉलेज में क्रमोन्नत करने की घोषणा करेंगे।

(श्री अजीत सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टोंक में जीव विज्ञान एवं संस्कृत का ऐच्छिक विषय नहीं है। जिस कारण से छात्र-छात्राओं को अध्ययन के लिये अन्य दूसरे जिलों में जाना पड़ता है। अत: मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि छात्र-छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान एवं संस्कृत के ऐच्छिक विषय खोले जाने की घोषणा करें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत आभार और अभिनन्दन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पब्बारामजी।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-24 शिक्षा, कला और संस्कृति पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, आपका हार्दिक आभार। भारत में शुरू से ही, पुराने समय से ही शिक्षा के प्रति भारत में लगाव रहा और भारत की प्रगति का कारण भी यही रहा। प्राचीन काल में जिस समय में सम्पूर्ण विश्व में यूरोप और अफ्रीका के अंदर लोग वन मानुष का जीवन यापन करते थे, यहां पर सभ्यता फल-फूल रही थी और तक्षशिला और नालन्दा जैसे विश्वविद्यालय थे, यहां पर चाइना से ह्वेनसांग और फाह्यान जैसे शिक्षा हासिल करने वाले विद्वान पढ़ने आए, यह इतिहास की बात है।

सिंधु घाटी सभ्यता और नदी घाटी सभ्यता। नदी घाटी जो सभ्यता है, वह फल-फूल रही थी और जिसके अभी भी निशान आपको और हमको देखने को मिलते हैं तो यह शिक्षा के बल पर ही हुआ और जब कभी भी शिक्षा के अंदर पराभव हुआ, देश पुन: पराभव की तरफ गया। विदेशी आक्रांताओं ने वह शिक्षा का ढांचा तोड़-फोड़ दिया और उसके चलते पुन: भारत गुलामी के कगार पर गया और हमारी शिक्षा व्यवस्था चूर-चूर हो गयी और देश आजाद होने के बाद में सभी सरकारों ने अपने-अपने प्रयास किये और कोई न कोई ऐसा कार्य किया जिसके कारण शिक्षा में प्रसार बढ़े।

आज तक ट्रेजरी बेंच में बैठने वाले, तीन सवा तीन साल से विपक्ष के सदस्यों को और उनकी सरकार के बारे में कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया और वे कह रहे हैं कि आपने ढांचा बैठा दिया। मैं एक सकारात्मक

(श्री पब्बाराम)

और पहली बार कोई भी ट्रेजरी बेंच का एक व्यक्ति आपकी, एक अच्छे कार्य के लिए विपक्ष की प्रशंसा भी कर रहा है। आपने एक बहुत अच्छा कार्य किया और वह पिछली सरकार के दौरान में शिक्षा के प्रसार के अंदर जो कार्य आपने किया है शायद कोई दूसरी सरकार नहीं कर सकती थी। आपने मिडिल क्लास तक किसी को फेल न करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, उस निर्णय के आधार पर, चाहे वहां पर शिक्षक हो या न हो, यह चमत्कार आपकी सरकार के अलावा और तो कोई नहीं कर सकता। बगैर शिक्षक के ही बच्चा आठवीं पास हो जाए तो यह कार्य अगर किया है तो आपने किया है।

यही नहीं, मैं मेरे क्षेत्र का एक उदाहरण आपको देता हूं। मेरे वहां पर टीपू नाम का एक विद्यालय है। विज्ञान विषय वहां पर था और वहां पर सीनियर सैकण्डरी था। वहां पर मात्र एक शिक्षक है और वह भी शारीरिक शिक्षक था। वहां की सरपंच साहिबा हैं। वह वहां के विधायक की मुंह बोली बेटी थी। लगातार प्रयास करने पर भी एक से दूसरे शिक्षक का वहां पर अपाइंटमेंट नहीं हुआ और मुझे आज इस चीज की प्रसन्नता है और शिक्षा मंत्रीजी को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि जहां पर एक से दूसरे शिक्षक को तरसता वह विद्यालय था आज वहां पर 15 शिक्षक हैं और अच्छी तरह से पढ़ाई हो रही है। यह चमत्कार अगर आपने किया है, इसलिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हमेशा हमारे ऊपर आरोप लगते हैं कि शिक्षा के अंदर भगवाकरण कर रहे हैं और इस प्रकार से इतिहास लेखन में ऐसा कर रहे हैं और वैसा कर रहे हैं।

पाठ्यक्रम के अंदर बदलाव। जब कभी भी देश आजाद होता है, हर देश ने अपना इतिहास अपने नजरिये से लिखा है और आज भी हम अपना इतिहास अंग्रेजों के उस नजरिये से देख रहे हैं या कम्यूनिस्ट लेखकों ने जिस प्रकार से लिखा है, उसी के आधार पर उस इतिहास को पढ़ रहे हैं। यह इसको ठीक करने का अगर कार्य किया है तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने किया है। मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

आज तक हम लोग पढ़ते रहे कि अकबर महान था। हमने भी पढ़ा परंतु यह पहली बार हुआ है कि अकबर महान से, आपकी सोच और हमारी सोच में इतना अंतर है कि आपके लिए अकबर महान था, परंतु हम हमेशा

(श्री पब्बाराम)

जय महा राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की बोलने वाले, आज उन्होंने उस इतिहास लेखन के जरिए उन महापुरुषों को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। इसके लिए मैं बधाई और शुभकामना देता हूं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को। बीच में जिसमें यू.पी.ए. का शासन था, वहां पर उस समय एक बहुत बड़ा आंदोलन चला और आंदोलन इस बात को लेकर चला कि शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंदर भ्रामक प्रविष्टियां थीं। वहां पर भ्रामक पढ़ाई पढ़ाई जा रही थी और सी.बी.एस.ई. के पाठ्यक्रम में वैसा था और मैं आपको उस आंदोलन की तरफ ले जाता हूं और आपमें और हममें से बहुत से उसके साक्षी भी हैं। उस आंदोलन में हम लोगों ने भाग भी लिया है और पाठ्यक्रम के अंदर वह अंश हटाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों ने खड़ा किया था। उसके अंदर क्या लिखा था- रामायण और महाभारत, यह कम्यूनिस्टों के द्वारा लिखा गया पाठ हमें पढ़ाया जा रहा था, हमारे बालकों को पढ़ाया जा रहा था, सी.बी.एस.ई. के पाठ्यक्रम में कि रामायण और महाभारत कपोल-कल्पना है और यह गड़रियों के गीत है। यह उस समय में, यू.पी.ए. के शासनकाल में पढ़ाया जा रहा था। भगवान महावीर के बारे में टिप्पणी उस समय में शिक्षा के क्षेत्र में की गयी थी और पाठ्यक्रम में की गयी थी। उसमें कहा गया कि भगवान महावीर जो है, वह जंगल में भटक गया, फिरता रहा, घूमता रहा, फल, कंद-मूल-फल खाता रहा, उसके कपड़े फट गये और नग्न अवस्था में चला गया। इस सोच के साथ हमारे बालकों को जहर खिलाया जा रहा था, जहर पिलाया जा रहा था। शिवाजी और प्रताप को राजद्रोही के रूप में स्थापित किया जा रहा था उन पाठ्यक्रम की पुस्तकों में। इसी प्रकार से जिन जाट राजाओं ने, जाट लोगों ने भरतपुर के और धौलपुर के, इस दिल्ली दरबार की नाक में दम कर रखा था उनके लिए उनको लुटेरा लिखा गया था, उन पाठ्यक्रमों में और इसका बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ और आखिर में जाकर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसको डिलीट करवाया और उसके बाद में इस इतिहास को सही करवाने का काम किया। मैं उन सभी आंदोलनकारियों को हार्दिक बधाई और उनका आभार व्यक्त करता हूं।

आपकी सोच और हमारी सोच में दिन और रात का अंतर है। आपने राम सेतु को, आपके पाठ्यक्रमों में और आपके द्वारा यह कहा गया कि राम

(श्री पब्बाराम)

सेतु प्राकृतिक पहाड़ियां हैं बीच-बीच में और इसके चलते आप लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया कि यहां से हम लोग निकालेंगे और उसके चलते यह वहां से रास्ता निकालेंगे और यूरेनियम वहां से निकालेंगे और बड़ी-बड़ी मशीनें ले जाकर रखीं लेकिन वे मशीनें टूट गयीं वहां पर, परंतु वह नहीं टूटा और इस प्रकार से बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और पूरा भारतवर्ष का चक्का जाम हो गया। मैं, हम सब लोग उस समय में भी शामिल थे। हमारा सीना गर्व से फूल गया, जिस समय सम्पूर्ण भारत इस बात को लेकर, राम सेतु की बात को लेकर पूरा का पूरा ठप्प रहा और उसके बाद में तत्कालीन प्रधान मंत्रीजी को विवश होकर यह फैसला देना पड़ा कि हम वह रास्ता नहीं बनाएंगे।

मैं ज्यादा पृष्ठ भूमि में न जाकर सोच और सोच के अंदर अंतर है, वह स्पष्ट करना चाहता था। उसके बाद में अभी जो विद्यालय, इस नई सरकार के आने के बाद में जो इनोवेशन नए किये, नवाचार किये इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं स्वयं एक शिक्षक रहा हूं और मैंने कांग्रेस के शासन-काल के समय भी देखा और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में भी देखा। काम उन्होंने भी किया और हमने भी किया परंतु शिक्षा के साथ में, शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से द्रुत गति से विकास भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुआ, वैसा कभी भी नहीं हुआ।

विद्यालयों के एकीकरण के बारे में आप कह रहे हैं कि एकीकरण के माध्यम से विद्यालय बंद कर दिये गये। हम लोग, हम इस चीज के साक्षी हैं कि जो छोटे-छोटे विद्यालय थे और बिलकुल दो, चार, पाँच स्टूडेंट्स के माध्यम से चल रहे थे, उनको साथ में मिलाकर एक बड़ा विद्यालय चले और वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कायम किया जाए ताकि वहां के मानव संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जा सके। अगर बंद कर दिये तो आज 17 लाख स्टूडेंट्स फिर गवर्नमेंट की स्कूलों की तरफ किस प्रकार से आकर्षित हुए, यह बहुत बड़ा प्रश्न है, आप सब लोगों के लिए।

स्टाफिंग पैटर्न पर हमारे वहां पर, विशेषकर मैं तो आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर जो इन्टीरियर क्षेत्र है और सीमा से लगता हुआ है, वहां पर सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी

(श्री पब्बाराम)

स्कूल के अंदर कोई भी गजटेड आफिसर कहीं पर भी नहीं होता था। परन्तु अब कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं है जहां पर प्रिंसिपल और हैड मास्टर नहीं है। सब जगह एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कायम है और शिक्षा सही ढंग से चल रही है और यही कारण है कि प्राइवेट विद्यालय के लिये आपने षड्यन्त्र किया, लगातार बच्चों को पास करके इस प्रकार से एक षड्यन्त्र किया ताकि जनता अपने बच्चों को प्राइवेट की तरफ ले जाये और हमें कुछ करना ना पड़े। अपने आप लोग प्राइवेट की तरफ चले गये और हमने पुन: उस बहाव को बदला और राजकीय स्कूलों के अंदर किस प्रकार से गरीब का बेटा पढ़े, यह सारा कार्य आपने किया है। शिक्षा मंत्रीजी, आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

एक दृष्टि से यह ट्रांसफर उस समय एक उद्योग बन चुका था। हमें याद है और मेरे साथी किस प्रकार से ट्रांसफर करवाते थे। किस प्रकार अपना काम करवाते थे, मुझे पता है कि वह उद्योग का रूप ले चुका था। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसा इनोवेशन किया काउंसलिंग के माध्यम से कि जो व्यक्ति जहां पर जाना चाहता है, उसके सामने डिस्प्ले कर दिया जाये उस स्थान का नाम और वह स्थान का नाम लिखे और वह उस स्कूल में पढ़ाने के लिये चला जाये। यह बहुत बड़ी बात आपने की। आप यूं समझ लो कि हम तो बेरोजगार ही हो गये। कहीं पर कोई जाने-आने का नहीं, पहले तो इनके चारों तरफ घूमते थे।

विद्यालयों के क्रमोन्नयन की बात है। तीन समय में चाहे भैरोंसिंह जी की सरकार हो, चाहे वसुन्धराजी की सरकार हो, जब कभी भी ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में किसी ने सोचा था तो आपने सोचा है। चाहे हर पंचायत के ऊपर मिडिल बनाना हो, सैकण्डरी बनाना हो, सीनियर सैकण्डरी बनाना हो। सरकार आने के बाद में पहले वर्ष में जो निर्णय लिया गया, वह तो क्रान्तिकारी निर्णय था। इस देश के आजाद होने के बाद में कुल-मिलाकर 4400 विद्यालय थे और उसके बाद सीनियर सैकण्डरी और एक ही साथ पांच हजार से अधिक सीनियर सैकण्डरी स्कूल बनाकर उन बेटियों और बेटों को माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने और शिक्षा मंत्री ने तोहफा दिया है। हमें पता है कि कोई भी बेटी एक पंचायत से दूसरी पंचायत में सैकण्डरी और

(श्री पब्बाराम)

सीनियर सैकण्डरी पढ़ने के लिये नहीं जाती थी और वहां तो तहसील हैडक्वार्टर पर जाना पड़ता था। वहां पर नहीं जाती थी और वह शिक्षा से वंचित हो जाती थी। यह कार्य अगर किया है सीधा कालेज में जाने के लिये अपने ही गांव से, यह आपने किया, इसके लिये बहुत-बहुत आपका आभार।

इसी प्रकार से, शिक्षा मंत्रीजी से मेरा आग्रह है कि आपने एक नया आदेश निकाला। अभी पूरा सिनेरियो तो निकल गया। आपने पांच हजार से ऊपर विद्यालय तो सीनियर सैकण्डरी कर दिये और अपना संकल्प है कि हम अगले वर्ष चुनाव में जाएंगे, उससे पहले सभी पंचायतों में सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी करेंगे। प्राइमरी को नई पंचायत में अपग्रेड करके अपर-प्राइमरी कीजिये, अपर-प्राइमरी से सैकण्डरी कीजिये और सैकण्डरी से हायर सैकण्डरी कीजिये। इसमें यह जो 40 विद्यार्थियों का राइडर लगा रखा है, अब जब हजारों स्कूलें हो गयी हैं और 400-500 के अंदर आप इस प्रकार की कंजूसी ना बरतें। आप किसी प्रकार की कमी नहीं रखें। जब हम चुनावों में जायें तो हम यह डंके के साथ में कह सकें कि हमने सभी विद्यालयों के अंदर, सभी पंचायतों के विद्यालयों को क्रमोन्नत किया है। इस बात के साथ में हम डंके की चोट पर जायें। इस बात को सुनिश्चित करें माननीय शिक्षा मंत्री महोदय।

इन्फ्रास्ट्रक्चर को डवलप करने के लिये लगभग 200 करोड़ रुपये, चाहे वह कक्षा-कक्ष है, पुस्तकालय है, कम्प्यूटर कक्ष है, पेयजल है, प्रयोगशाला है या शौचालय हो, आदि के लिये 58 नवीन विद्यालयों के भवनों का निर्माण करवाया और 334 कक्षा-कक्षों का निर्माण कराया, यह भी बहुत बड़ा कदम है।

मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी का, कि आपने मेरे इन्टीरियर क्षेत्र, जो बिलकुल ही सीमा से लगा है और वहां पर इतना बड़ा सोलर हब है और इतनी बड़ी छितराई हुई आबादी है, तो उन बालकों को पढ़ने के लिये, हायर एजुकेशन के लिये कोई भी कॉलेज नहीं था। एक बहुत बड़ा तोहफा देकर माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने एक बहुत बड़ा उपकार मेरे क्षेत्र 'बाप' के ऊपर किया है, इसके लिये मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

(श्री पब्बाराम)

महोदय, मेरी एक-दो मांगें हैं जो माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा। उपखण्ड मुख्यालय हमारा फलौदी है। जोधपुर के अंदर दो-दो डी.ई.ओ. आफिस है और डी.ई.ओ. ग्रामीण क्षेत्र का है और इसके लिये मैंने कई बार आग्रह भी किया है कि प्रारम्भिक शिक्षा के डी.ई.ओ. और सैकण्डरी शिक्षा के डी.ई.ओ. का हैडक्वार्टर आप फलौदी में करें, क्योंकि मात्र शिक्षा के अलावा बहुत सारे जिला स्तर के कार्यालय वहां पर बन चुके हैं। वहां पर एक डी.ई.ओ. का कार्यालय खोल दिया जाये। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं सिर्फ दो-तीन मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

एक संस्कृत शिक्षा की हालत बहुत नाजुक है। मेरे यहां विद्यालय कल्याण सिंह की सिडकी सैकण्डरी विद्यालय है संस्कृत का। उस विद्यालय के अंदर मात्र दो शिक्षक हैं और यही परिस्थिति पूरे क्षेत्र में, जहां-जहां पर भी हमारे है, क्योंकि इंटीरियर में कोई जाता नहीं। हमारे वहां पर पानी भी जाता है तो बड़ी मुश्किल से लास्ट में पहुंचता है, बिजली भी लास्ट में पहुंचती है, शिक्षक भी बड़ी मुश्किल से पहुंचता है तो आपके लिये एक चैलेंज है माननीय शिक्षा मंत्रीजी, एक आदेश देकर स्टाफिंग पैटर्न किया जाए कि जितने छात्र हों, उसके अनुपात में शिक्षक लगायें। अगर यह कार्य कर सकें तो हमारे वहां के बच्चों का बड़ा भला होगा।

साथ ही हमारा एक कालेज है फलौदी के अंदर, वहां पर 2200 विद्यार्थी हैं। वह कालेज पोस्ट ग्रेजुएशन तक है, तीनों फैकल्टीज हैं। बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि वहां पर चार शिक्षक हैं और वहां पर प्रिंसिपल भी नहीं है। प्रतिवर्ष तीन-चार बार बच्चे सड़कों पर आते हैं और एजीटेशन करते हैं। कृपया अभी आप नये अपाइंटमेंट करने वाले हैं तो उसमें पहले-पहल मेरे कालेज को दें और इसमें भी स्टाफिंग पैटर्न करें। एक तो 600 छात्रों का विद्यालय है, वहां पर 20 शिक्षक लगा रखे हैं और एक 2200 छात्रों का महाविद्यालय है, वहां पर आपने केवल चार शिक्षक दे रखे हैं। इसको थोड़ा ठीक करने की आवश्यकता है।

एक-दो बातें और कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। सुराज संकल्प यात्रा के अंदर हमारा वादा था कि हम लोग कर्मचारियों को, हमारे शिक्षकों को, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनको ग्रामीण भत्ता देंगे। उन वादों

(श्री पब्बाराम)

को अब पूरा करने का समय आ गया है। यह अन्तिम सेशन ही मान लीजिये। हाउस रेंट के रूप में कर्मचारियों को शुरू में टोकन के रूप में दिया गया। हम लोगों को केवल पाँच रुपये दिये गये थे। धीरे-धीरे वह बढ़ता रहा। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि टोकन मनी के रूप में ही, एक सम्मान के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों को, कर्मचारियों को ग्रामीण भत्ते के रूप में भले थोड़ा ही दें, एक बार आप दे दें ताकि हमारा सुराज संकल्प यात्रा का वादा पूरा हो जाये।

शिक्षा मित्रों के समायोजन की बात सभी ने कही है और वह दर्द सभी के लिये है। आपसे मेरा निवेदन है कि इनका समायोजन किस प्रकार से करना है, कानून के अंदर रहते हुए कर लें।

इसी प्रकार से एक कार्य, विशेषकर मैं और मेरे समाज के लिये एक बड़ी खुशी का अवसर है कि आपने इस पोशाक को बदलकर बहुत बड़ा उपकार किया है।

विश्नोई समाज की यह लम्बे समय से मांग रही है कि यह आसमानी कलर के हम लोग कपड़े नहीं पहनते और यह हमारे धर्म में ही वर्जित है। मेरा ख्याल है सनातन धर्म में भी इस रंग से परहेज किया हुआ है और आपने इस रंग को बदल करके, मेरे साथी बंधु भगवाकरण का आरोप लगा रहे हैं तो इस भगवे से तो हम लोग प्रेरणा लेते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) आप भी जब भगवे के सामने जाते हैं तो साष्टांग प्रणाम करते हैं। पूरे के पूरे 80 लाख छात्र जब इस रंग के अन्दर जुलाई में दिखाई देंगे, सम्पूर्ण, पूरा राजस्थान प्रसन्न होगा, आह्लादित होगा। इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं।

आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-24 पर चर्चा हो रही है। शिक्षा, कला एवं संस्कृति, देश और प्रदेश के भविष्य के निर्माण जैसा एक गम्भीर विषय है और जहां शिक्षा की चर्चा हो और वहां मां सरस्वती को प्रणाम। आपसे भी गुजारिश है कि हम भी इस मन्दिर में, इस विद्यालय में पहली कक्षा में हैं। आपकी भी डांट का डंडा थोड़ा सा ना चले तो हमारे लिए बोलने में ठीक रहेगा।

(श्री मनोज कुमार)

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश में जहां हमारी शिक्षा की बात है, लम्बे अर्से से कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते आये हैं। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान प्रदेश शिक्षा के बारे में, उस मूलभूत शिक्षा का कैसे सुदृढ़ीकरण किया जा सकता है, हम सभी सदस्यों को इस पर विचार करने की जरूरत है।

सबसे पहले शिक्षा के मामले में माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने पिछले दो वर्ष से आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नति की घोषणा की थी। यह बड़ा सराहनीय कदम है इस प्रदेश के लिए, लेकिन आपने वो घोषणा करने के बाद पिछली बार तो एक राइडर आपने लगाया कि जहां प्राइवेट उच्च माध्यमिक विद्यालय है वहां नहीं खोलेंगे और अब की बार आपने एक छोटी सी बाधा और लगा दी कि जहां हमारे 40 छात्र से कम होंगे वहां क्रमोन्नत नहीं करेंगे। इनमें सबसे पहले आधारभूत व्यवस्था हो, जहां-जहां भी आपने आदर्श विद्यालय क्रमोन्नत किये हैं, वहां आपके विद्यालय में स्टॉफ पूरा हो, विद्यालय में बैठने के लिए फर्नीचर हो, भवन की व्यवस्था हो, इस बारे में भी हमें विचार करने की जरूरत है क्योंकि अकेले क्रमोन्नत करने से विद्यालय की प्रगति और शिक्षा का स्तर नहीं सुधर सकता। इसलिए हमें सबसे गम्भीर इन सब पर विचार करने की जरूरत है।

आज 772 विद्यालय आपने ऐसे बताये हैं जहां प्राइवेट विद्यालय हैं और उनमें 40 छात्र की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि 40 छात्र के राइडर को समाप्त करें। विशेषकर यह कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय, जिन-जिन विद्यालयों के आने वाले इस सत्र में आप राइडर समाप्त कर दें तो बहुत अच्छी बात है कि सभी विद्यालय क्रमोन्नत हो जाएं। नहीं तो जहां 40 छात्र हैं उन विद्यालयों की घोषणा तो कम से कम हो। आपने अपनी विभाग से रिपोर्ट मंगा ली होगी, जहां-जहां इस समय 40 छात्र हैं उनकी सभी की घोषणा आज कर दी जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे माध्यमिक विद्यालय हैं जो 1977 में माध्यमिक विद्यालय थे और आज भी माध्यमिक विद्यालय हैं। ऐसे विद्यालयों का मैं नाम बताना चाहूंगा। जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र में रामपुरा, जहां लोग लम्बे अर्से से आन्दोलन कर रहे हैं,

(श्री मनोज कुमार)

जसवंतपुरा, ख्याली, धानोटी छोटी, चैनपुरा, चुबकिया ऐसे गांव जहां विद्यालय के क्रमोन्नति की बात है, आप राइडर हटायें तो हम नहीं नाम लेकर लेकिन जहां 40 छात्र हैं वहां आप इनको जरूर करें।

दूसरा, आपने विद्यालयों का एकीकरण किया। इस एकीकरण में जहां छात्र कम थे, मान लिया, सही बात है लेकिन कुछ विद्यालयों की दूरी बहुत ज्यादा हो गयी। छात्र तो कम है लेकिन वहां तक जाना असंभव हो गया तो उन कम छात्रों को, गरीब छात्रों के हित में भी आप इस पर दुबारा विचार करने की कोशिश करें।

इन्हीं के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मित्रों के बारे में चर्चा चली, विद्यार्थी मित्रों की लम्बे अर्से से आप सब जानते हैं कि आपने बार बार उनके लिए योजना बनायी, कभी आपने उनको विद्यालय सहायक के रूप में, कभी शिक्षक के रूप में, कभी आप ग्राम सहायक सचिव के रूप में उनको लगाना चाह रहे थे लेकिन अब आपने यह भर्ती निकाली, उस भर्ती में भी यह संभव नहीं है कि आप उनको लगा पायेंगे, इसलिए उनके लिए भी आप सही व्यवस्था करते हुए इन बेरोजगारों को रोजगार दें।

दूसरा एक बहुत गम्भीर विषय है। लम्बे अर्से से कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी दोनों की सरकार आयीं लेकिन डार्क जोन में अध्यापक लम्बे अर्से से, 15-20 वर्षों से बैठे हैं, उनके लिए भी आप कोई न कोई व्यवस्था करें। आपका समय मई-जून में आने वाला है। जब स्थानान्तरण की चर्चा करेंगे उस समय इन डार्क जोन में बैठे उन अध्यापकों के प्रति भी चिंता करें क्योंकि वो इस राजस्थान के निवासी हैं। कहीं कोई पाकिस्तान, अमरीका से नहीं आये हुए हैं, लेकिन आपने अब तक इन पर विचार नहीं किया, इन पर गम्भीरता से विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा वेतन विसंगति है द्वितीय श्रेणी अध्यापकों की। खूब लम्बे अर्से से वो आन्दोलन करते आये हैं और आन्दोलन में भी बार बार कमेटी गठित कर ली, उप-समिति गठित हुई लेकिन मात्र उनके बेसिक-पे और पे-स्केल में जो भिन्नता रह गयी, उसमें ज्यादा कोई लम्बा विचार करने की जरूरत नहीं है। आप इनकी वेतन विसंगति को दूर करें।

(श्री मनोज कुमार)

अंग्रेजी के व्याख्याता पद सृजित नहीं किये। आपने आदर्श विद्‌यालय क्रमोन्नत किये, लेकिन आपने अंग्रेजी के व्याख्याता के पद सृजित नहीं किये, आपने वरिष्ठ अध्यापकों को ही वहां लगा दिया। जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है अंग्रेजी हमारे लिए, इस राजस्थान प्रदेश के लिए, उसके लिए व्याख्याता होने अति आवश्यक है लेकिन आपने 2004-05 के बाद आज तक डी.पी.सी. नहीं की और आपने इन आदर्श विद्‌यालयों में उनके पद सृजित नहीं किये तो आप उनके पद सृजित करें और उनकी डी.पी.सी. कर के उनको लाभान्वित करें।

इनमें आपके अधिकारियों ने एक राइडर लगा दिया कि जिन विद्‌यालयों में 80 से कम नामांकन हैं, वहां सिर्फ वरिष्ठ अध्यापक ही लगेंगे, वहां व्याख्याता नहीं, होंगे एक तरफ तो आप 40 वालों को क्रमोन्नत कर रहे हो, दूसरी तरफ वहां व्याख्याता लगाने के लिए आपने 80 का राइडर लगा दिया तो यह सरासर गलत है। माननीय मंत्री महोदय, इसमें भी सुधार करके एक नया आदेश जारी करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ साक्षरता प्रेरकों को नियमित करने की बात है। 2003 में साक्षरता प्रेरक लगाये थे और 80 रुपये में काम करना शुरू किया था और आज उनको वर्तमान में मात्र दो हजार रुपये दिये जा रहे हैं। 500 रुपये उनको महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय में लगा कर, पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट ने उनके साथ ऐसा गम्भीर अन्याय किया, सिर्फ 500 रुपये में काम करा रहे थे और मेरे सामने जानकारी में आया कि अब 31 मार्च को इसे समाप्त करने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं यह गरीब, जो लम्बे अर्से से, 2003 से लेकर 14 वर्ष से आपके काम कर रहे हैं, उनको भी नियमित किया जाए।

स्कूल व्याख्याता भर्ती, जो 16,10,2015 को विज्ञप्ति जारी हुई, 13,098 पद हैं जिनमें 19 विषयों की भर्ती हुई। आपका परिणाम सितम्बर, 2016 में जारी हो गया लेकिन आज तक आप उनको नियुक्ति नहीं दे पाये हैं। जो लगातार आपके माध्यमिक निदेशक कार्यालय के आगे धरना और आन्दोलन पर 83 दिन से बैठे हैं और बीकानेर में 10 फरवरी, 2017 को हाई कोर्ट से भी निर्णय हो गया। उसके बाद भी आपने सिर्फ एस.बी.सी. के

(श्री मनोज कुमार)

बहाने से कि एस.बी.सी. के कारण, मैं कहता हूं कि पांच प्रतिशत पद सुरक्षित रखते हुए शेष पदों में उनको नियुक्ति दे दी जाए।

इसी तरीके से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तृतीय श्रेणी और सैकिण्ड ग्रेड के पी.टी.आई. की जो भर्ती हुई, उनमें भी उनको एक वर्ष की छूट भर्ती में उम्र में दी गयी थी उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया लेकिन उनको आज तक नियुक्ति नहीं दी।

रीट परीक्षा इन्होंने करवा ली। 15 हजार शिक्षकों को इनको भर्ती करना था लेकिन आज तक उनके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे, कोई विचार नहीं किया जा रहा। आपकी एन.टी.टी. शिक्षक भर्ती अटकी पड़ी है। आप कह रहे हो कि हम सबको रोजगार देंगे, 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मिड-डे मील का भी गम्भीर विषय है। वहां हमारी महिलाएं खाना बनाने का काम करती हैं। सरकार उनको मात्र हजार रुपये दे रही है और एक हजार रुपये में अब की बार 200 रुपये की बढ़ोतरी की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, उनको कम से कम न्यूनतम मजदूरी तो दी जाए। छह हजार रुपये का भुगतान उनको किया जाए जो मिड-डे-मील में खाना बनाती हैं। छोटे-छोटे बच्चों को अपने घर छोड़ कर खाना बनाती हैं।

सैटअप परिवर्तन के नाम से शिक्षा में इन्होंने परिवर्तन कर दिया और स्टॉफिंग पैटर्न के नाम से इन्होंने जिन-जिनको माध्यमिक शिक्षा में ले लिया, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, माध्यमिक शिक्षा में जाने के बाद एक राइडर लगा दिया कि जहां 50 स्टूडेंट्स हैं वहां दो शिक्षक लगेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि पांचवीं क्लास में पांच क्लास हैं और शिक्षक आप दो लगाओगे तो क्या आप उनको पढ़ा पाओगे? आपकी धरातल की मूल शिक्षा प्राथमिक स्तर पर है, उनमें पांच कक्षा हैं, कम से कम पांच अध्यापक वहां लगायें। आप यह बच्चों का राइडर भी न लगायें क्योंकि अगर पांच बच्चे हैं तो शिक्षा कौन दूसरा देगा? इसलिए उनके साथ भी अन्याय हो रहा है।

शारीरिक शिक्षक, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले हम पढ़ते थे तो

(श्री मनोज कुमार)
शारीरिक शिक्षक का एक कालांश होता था और शारीरिक शिक्षक बच्चों को खेल खिलाने का काम करता था लेकिन वर्तमान में उस चीज का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खेल व्यवस्था, खेल सामग्री और खेल ग्राउंड की भी विद्यालयों में बहुत कमी है। आप इन सब पर गंभीरता से विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूं, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालयों में जहां-जहां विद्युतीकरण नहीं है वहां विद्युतीकरण का कार्य भी किया जाए।

माननीय प्रधान मंत्रीजी का स्वच्छता अभियान है, वह भी गंभीर इश्यू है। जिसके बारे में यहां चर्चा चल रही है कि आपने शौचालय बना दिए। लेकिन उन शौचालयों को साफ करने की आपकी क्या व्यवस्था है? कोई भी व्यवस्था नहीं है। वहां पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की जाए। जहां आपके प्राइमरी और उच्च प्राइमरी विद्यालय हैं, उनकी सुविधा के लिए आप मात्र 12 हजार रुपए देते हैं। इस राशि को भी माननीय मंत्री महोदय, बढ़ाया जाए। साल में बिजली का बिल, पानी का बिल और अन्य सारी व्यवस्थाएं उस 12 हजार रुपए में की जाती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी एक घोषणा ग्रीन बोर्ड की, की गई। आदेश भेज दिया लेकिन बजट का कोई प्रावधान नहीं किया। बजट के प्रावधान के बिना ग्रीन बोर्ड चलाया जाना भी मुश्किल हैं। इसके साथ ही आपने ऑनलाइन तो कर दिया सारे तंत्र को लेकिन कम्प्यूटर की व्यवस्था सारे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नहीं है। वहां पूरी व्यवस्था की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे सामने एक जानकारी आई कि बीईओ ऑफिस जो पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर होता है, उनको भी आप समाप्त कर रहे हैं। इससे हमारी उस व्यवस्था को, उस मैनेजमेंट को कौन देखेगा?

इसके साथ ही 2012 में जो तृतीय श्रेणी की भर्ती हुई, उसका संशोधित परिणाम आ गया, लेकिन उनकी भर्ती नहीं कर रहे हैं। 2013 में चयनित बेरोजगारों को पांच महीने हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए लेकिन उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, इनके सामने मैं एक विवरण प्रस्तुत करने जा रहा

(श्री मनोज कुमार)

हूं। प्राथमिक शिक्षा में राज्य का विवरण, एक सर्वे आया जिसमें नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग ने एलीमेंट्री एजुकेशन इंडिया, 2014-15 की रिपोर्ट जारी की। जिसमें सूचकांक राज्य अनुसार दिए गए। जिसमें 60 में से 15 सूचकांक में हमारी जो स्थिति है, वह आपकी अनुमति से बताना चाहूंगा। देश में सर्वाधिक प्राइमरी स्कूल में पश्चिमी बंगाल में 80 प्रतिशत ...

श्री उपाध्यक्ष: इसका साल बताओ। यह आपकी रिपोर्ट कब आई?

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 2014-15 में।

श्री उपाध्यक्ष: 2014-15 में रिपोर्ट आई यानी रिपोर्ट 2012-13 की है। अब बताएं आप इसको।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): क्लस्टर कॉर्डिनेटर द्वारा निरीक्षण, शीर्ष पर छत्तीसगढ़ है उसका 88.80 प्रतिशत है जबकि राजस्थान 39.2 प्रतिशत है। स्तर में सबसे नीचे है। स्वयं के स्कूल, सरकारी भवन में, इसमें अरूणाचल प्रदेश का आंकलन है 92 प्रतिशत और हमारा 62 प्रतिशत है। प्रति कक्षा छात्रों की औसत संख्या बिहार में 50 प्रतिशत है जबकि राज्य में केवल 20 प्रतिशत है।

मात्र एक टीचर वाले प्राइमरी स्कूल राज्य में 33.40 प्रतिशत प्राथमिक स्कूल हैं। राज्य में अभी भी छह प्रतिशत स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। राज्य के 49 प्रतिशत प्राइमरी स्कूलों में हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है। राज्य के 45 प्रतिशत प्राइमरी स्कूलों में बिजली के कनेक्शन नहीं हैं। राज्य में केवल 5.29 प्रतिशत प्राइमरी स्कूलों में कम्प्यूटर हैं। जिनमें भी केवल 23 प्रतिशत कार्यरत अवस्था में हैं। राज्य के 49 प्रतिशत विद्यालयों में खेल मैदान नहीं हैं जबकि पंजाब के 95 प्रतिशत स्कूलों में है। कक्षा 1 से 8 में बालक-बालिकाओं का अनुपात राज्य में 1:0.85 है। कुल शिक्षकों में महिलाओं का प्रतिशत भी प्राथमिक कक्षाओं में केवल 33.9 है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही माध्यमिक स्कूलों में व्याख्याताओं की स्थिति, राज्य में 33.12 प्रतिशत पद रिक्त हैं। वरिष्ठ अध्यापकों में 28.97 प्रतिशत पद रिक्त हैं। वरिष्ठ अध्यापक लेवल-2 के आठ हजार पद

(श्री मनोज कुमार)

रिक्त हैं। लेवल-1 के नौ हजार पद रिक्त हैं। पीटीआई प्रथम में 97 प्रतिशत पद रिक्त हैं। प्राचार्य के 12 प्रतिशत और प्रधानाध्यापक के 13 प्रतिशत पद रिक्त हैं। ऐसी गंभीर स्थिति इस राजस्थान प्रदेश की है। उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस प्रदेश की स्थिति को सुधारने के लिए सारे आधारभूत ढांचे को सुधारना है। इस प्रदेश में शिक्षा सही प्रकार से कैसे दी जा सकती है, इस पर विचार की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा के बारे में भी दो बातें कह दूं। वैसे तो मेरी चर्चा माननीय मंत्री महोदय से पहले हो चुकी है। हमारे राजकीय महाविद्यालय को तीन वर्ष हो गए लेकिन भूमि का आवंटन आज तक नहीं हुआ, भवन का निर्माण नहीं हुआ। लेक्चरर तीन हैं, बाकी सारे पद रिक्त पड़े हैं। भूमि आवंटन में आपकी क्या पारदर्शिता रही? माननीय मंत्री महोदय, उस चर्चा को 15-20 दिन हो गए। आपके पास कोई रिपोर्ट आई हो तो हमारे राजकीय महाविद्यालय की भूमि की चर्चा जरूर करें। रिक्त पदों के बारे में भी हमें बताएं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन करूंगा कि राजगढ़ तहसील में राजकीय महाविद्यालय की आप घोषणा करें। प्रदेश में प्रत्येक उपखंड कार्यालय में आपकी घोषणा की हुई है कि सरकारी आईटीआई कॉलेज हम खोलेंगे लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं है। इसकी भी आप घोषणा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, तकनीकी विश्वविद्यालय हमारे संभाग में खुलना था। उस तकनीकी विश्वविद्यालय की दुबारा चर्चा नहीं हुई। उसको खोलने की आपने वापस घोषणा की कि हम तकनीकी विश्वविद्यालय सुचारू रूप से चलाएंगे। एक मेरे वहां ओपीजीएस विश्वविद्यालय फर्जी रूप से चल रहा है। आपकी कमेटी गठित करने की बात हो गई थी। आप उसके बारे में भी बताएं कि कमेटी गठित करके उसकी जांच का स्तर कहां तक चल रहा है। ऐसे विश्वविद्यालयों को आप मान्यता दे रहे हैं, इन पर आप राइडर लगाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, विशेषकर मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक बात और कह दूं। मेरे यहां 197 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इनमें 978 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 350 पद रिक्त हैं। लगभग 40 प्रतिशत पद रिक्त हैं। इनकी भर्ती कराई जाकर मेरे राजगढ़ की जनता को लाभ दिया

(श्री मनोज कुमार)

जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार।

श्री हीरालाल (निवाई): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मेरे क्षेत्र की कुछ मांग रखना चाहता हूं। आप अनुमति दें तो?

श्री उपाध्यक्ष: बोलिए।

श्री हीरालाल (निवाई): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24, शिक्षा, कला और संस्कृति के संबंध में निवेदन है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में छह माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत नहीं किया गया है। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के लुहारा, सेदड़िया, सुनारा, बिड़ौली, ढाणी जुगलपुरा, नटवाड़ा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करावें। इसके साथ ही जो 40 बच्चों का राइडर रखा है, उसको कम किया जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, निवाई में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में केवल कला विषय है। यहां आसपास के बौंली, सवाई माधोपुर तक से बच्चे पढ़ने आते हैं। वहां पर भूगोल विषय भी खोला जाए। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, निवाई में गणित विषय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झिलाई, निवाई में विज्ञान विषय करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा। मेरे पीपलू उपखंड में राजकीय महाविद्यालय नहीं है। वहां पीपलू उपखंड पर राजकीय महाविद्यालय खोला जावे। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

व्यवस्था

मांगों पर चर्चा के समय लिखित वक्तव्य सदन पटल पर रखे जाने की अनुमति नहीं

श्री उपाध्यक्ष: मैं आप माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगा। मुख्य सचेतक महोदय और प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय नहीं हैं। मांग पर वाद-विवाद में कोई कागज, कोई आपका वक्तव्य टेबल नहीं हो सकता है। 15 मार्च, 2016 को भी इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया जा चुका है।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रतिपक्ष के सचेतक और मुख्य सचेतक इस बात पर आप निर्णय कर लें। आसन को कोई तकलीफ नहीं है कि आप जितने सदस्यों को बुलाना चाहें पूरी तरीके से बुलाइए। लेकिन कागज टेबल नहीं होगा।

श्री गोपाल कृष्ण।

अनुदान की मांग

शिक्षा, कला एवं संस्कृति - मांग संख्या 24 पर विचार

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या -24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर चर्चा करने के लिए बोलने का अवसर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आदमी को आदमी बनाती है और उसको ऐसी चीजें सिखाती है जो उसके जीवन में काम आती हैं। सुबह से मैं देख रहा हूं कि बहुत से विद्वानों ने अपने मत रखे हैं और बड़े-बड़े विद्वतापूर्ण प्रवचन इस संबंध में दिए हैं। अब उसी को बार-बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है कि पहले हम क्या थे और अब हम क्या हैं। हम कैसे बन गए, कितना बनना चाहते हैं। कांग्रेस ने क्या किया और हमने क्या किया। इसकी नहीं कह कर मैं कोट करना चाहूंगा, जैसे कंफ्यूशियस ने कहा कि शिक्षा तो नॉलेज है। नॉलेज से मनुष्य को अपने जीवन के अंदर सफलताओं की सीढ़ी चढ़कर जीवन यापन करना होता है तो उन्होंने कहा कि; “Essence of the knowledge is having it and applying it.” अगर नॉलेज है तो उसको एप्लाई कीजिए नहीं तो कोई काम का नहीं है। उसी ढंग से एक बेकन नाम के राइटर हैं वह कहते हैं; “Reading maketh a full man, writing an exact man and conference a ready man.” अगर आप पठन करते रहें, पठन करते रहें तो आप पूर्ण आदमी बन सकते हैं और जितना लिखते जाएंगे, उतनी एक्जैक्टनेस आपकी बनी रहेगी और जितनी आपस में बातचीत करेंगे तो उसमें आपको रेडीनेस आएगी। बात कहने की कला आपको आती है। डॉक्टर जॉनसन अठारहवीं जिनको शताब्दी में अंग्रेजी के डिक्टेटर कहा करते थे लोग, उनका कहना है कि; “knowledge is of two types. One that you

(श्री गोपाल कृष्ण)

have got the knowledge of this subject yourself." Second is that. you know from where this knowledge can be got." तो आपको सही आदमियों को पकड़ना पड़ेगा कि नॉलेज किससे क्या लेनी होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाकी बातों को रिपीट न करते हुए, मैं सबसे पहले तो अधिक जोर देना चाहूंगा कि प्राइमरी शिक्षा मनुष्य के लिए बहुत जरूरी होती है। प्राइमरी शिक्षा आपने यदि ठीक ढंग से नहीं ली है तो आगे की शिक्षा में आप हमेशा कच्चे रहेंगे, आप उसका वज़न नहीं उठा सकेंगे। आपकी नींव यदि पक्की नहीं है और आप बहुत बड़ी कोई स्कूल या कॉलेज में जाना चाहेंगे तो वह आपको भर्ती भी नहीं करेंगे। आठवीं तक आपने पास ऐसे ही कर दिया है तो बाद में नवीं के अंदर किसी अच्छी स्कूल वाले आपको भर्ती भी नहीं करेंगे। यह बात सही है कि जब कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है तो उसका वजन ऊपर तक नापा जाता है और नापने के बाद यह देखा जाता है कि उसकी नींव कैसे डाली जाए तो नींव पक्की होना बहुत जरूरी है। प्राइमरी शिक्षा को जब तक आप पक्की नहीं कर लेंगे, तब तक आप शिक्षा में सफल नहीं हो सकते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान जब बना था तो कुछ लिखित में ऐसे प्रावधान किए गए थे कि कैपिटल जयपुर रहेगा, हाई कोर्ट जोधपुर में रहेगा और शिक्षा का मुख्यालय बीकानेर रहेगा। लेकिन क्या देखते हैं कि बीकानेर को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पानी से भी पतला कर दिया। इतना पतला कर दिया कि वहां निदेशालय है, निदेशक खुद बैठते नहीं है ज्यादा और जितने भी ऑफिसर्स हैं, वे भी वहां पर कम बैठते हैं और दूसरे दफ्तर जो वहां क्रिएट होते हैं, वे सारे जयपुर में ट्रांसफर हो जाते हैं। बीकानेर को इस ढंग से कमजोर करने का कारण क्या है, यह मेरे को पता नहीं लगा। ऐसा बीकानेर ने क्या गुनाह कर दिया कि लगातार वहां से ऑफिसेज उठा-उठा कर जयपुर ले जाते हैं। या तो यह है कि अफसरों को पसंद नहीं है बीकानेर। बीकानेर में रहना नहीं चाहते या कुछ और बात है, वह मैं समझता नहीं हूं। चलो, फिर भी यह है कि मुझे इस बात का दु:ख है कि बीकानेर के उस समय पहले-पहल यह बना था तो इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, सभी कुछ वहीं पर था। सारी की सारी वहीं पर थी और आज अब

(श्री गोपाल कृष्ण)

कौनसी चीज वहां पर है या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। इसलिए अभी मंत्री महोदय से निवेदन है, पहले सिद्धांतत: आपने यह तय किया था कि शिक्षा निदेशालय में डिप्टी डाइरेक्टर एलीमेंट्री की पोस्ट बीकानेर कर दी जाएगी। मेरा ख्याल है कि साल भर हो गया उस बात को, अभी तक वह हुआ नहीं है। आप यहां विराजमान हैं, आप आज इसका जवाब देंगे, ऐसा मुझको लगता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने अच्छे काम भी किए हैं। समानीकरण, काउंसलिंग, लोगों को बुला बुलाकर कि यह जगह खाली है, कौनसी तुम्हें लेनी है और लोगों ने खुश होकर लिया भी है। अच्छे काम किए हैं, उसके लिए हम आपकी सराहना करते हैं। लेकिन एक दिक्कत यह होती है कि प्रिंटिंग डिफेक्ट के कारण से, स्पेलिंग डिफेक्ट के कारण से, किसी क्लर्क की मिस्टेक के कारण कोई जगह गलत लिख दी गयी है तो उसको आप ठीक करेंगे और आपके ऑफिसर ने साइन करके उस पेपर को निकाल दिया। उसकी यह हिम्मत नहीं है कि उसको ठीक कर दे। हालांकि गलती उस जगह पर हुई है लेकिन सही आप जब तक नहीं करेंगे तब तक यह नहीं होगी। यह भी वहां पर लोगों को कितनी दिक्कत होती है कि यहां पर आकर उसको ठीक कराया जाए। एनीवे, मैं आपसे यह निवेदन जरूर करूंगा कि डिप्टी डाइरेक्टर, एलीमेंट्री के पद का सृजन वहां जरूर कर दिया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उच्च शिक्षा के बारे में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि बीकानेर पश्चिम में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की नितांत आवश्यकता है क्योंकि कोई भी कन्या महाविद्यालय बीकानेर पश्चिम में एक भी नहीं है और जो है वह दूर है। वहां राजकीय कन्या महाविद्यालय नहीं है। प्राइवेट शिक्षा पर इतने पैसे खर्च होते हैं, वह अभिभावक वहन नहीं कर सकते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी-जल्दी अपनी बात को निपटा देता हूं, बहुत जल्दी-जल्दी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तकनीकी विश्वविद्यालय का प्रस्ताव था और पिछले बजट में इसको प्रस्तावित कर दिया गया लेकिन वह विधेयक नहीं लाए तो वह चालू नहीं हुआ तो इसको पूरा क्यों नहीं करते? जब अपना एक कमिटमेंट हो गया है बजट में। जब बजट में कमिटमेंट हो गया है तो

(श्री गोपाल कृष्ण)

उसको पूरा कर दें। मैं उच्च शिक्षा मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि इसको भी कम्पलीट करें और यह कन्या महाविद्यालय बीकानेर पश्चिम के अंदर, मैं बीकानेर पश्चिम की बात कर रहा हूं, उसको किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टेसीटोरी ग्रेवयार्ड वहां पर बना हुआ है। टेसीटोरी, एक इटालियन थे जो इटली से यहां आकर बीकानेर और जोधपुर में बसे। बीकानेर में उनका स्वर्गवास हो गया और बीकानेर में ही उनकी ग्रेवयार्ड बनी हुई है, उनकी समाधि बनी हुई है लेकिन वह इस तरह से जर्जर और ऐसी स्थिति में है कि वहां कोई पर्यटक जाए और देखना चाहे, चाहे इटली के आएं चाहे यूरोप से आएं, चाहे अपने देश से आएं, राजस्थानी में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। राजस्थानी में इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, राजस्थानी का इन्होंने अनुवाद भी किया है तो ऐसे व्यक्ति का जिसने राजस्थान के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन खपा दिया उसकी ग्रेवयार्ड तो कम से कम बहुत अच्छे ढंग से बननी चाहिए। लोग उसको देखें, आएं, तो बात ही कुछ और होगी।

राजस्थानी भाषा और संस्कृति अकादमी में काफी अर्से से अध्यक्ष नहीं है। आप मेरी बात पर थोड़ा ध्यान दें, वहां अध्यक्ष कई वर्षों से नहीं हैं और बिल्डिंग खाली पड़ी है, बिल्डिंग में कोई आदमी भी नहीं है। बिल्डिंग में चपरासी भी मुश्किल से है या नहीं है इसका भी पता नहीं है। वहां न तो स्टाफ है और न ही अध्यक्ष है। यह मुख्यालय है, यह सारा राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति अकादमी का मुख्यालय बीकानेर में होते हुए भी न तो अध्यक्ष है और न ही स्टाफ है। भाषा, साहित्य और संस्कृति अकादमी में स्थित हॉल, एक हॉल है उसको पुस्तकालय के रूप में खोला जा सकता है, काम में लिया जा सकता है। उसको भी नहीं लिया जा रहा है और खाली पड़ा है। वहां पर कोई आदमी जा नहीं रहा है तो आखिर यह भाषा, साहित्य और संस्कृति अकादमियां क्यों बनाई गई हैं? न वहां अध्यक्ष हैं, न वहां स्टाफ है, न वहां कोई और पुस्तकें वगैरह मिल जाएं ऐसी, बात नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लक्ष्मीनाथजी मंदिर में बीकाजी की छतरी का जीर्णोद्धार भी बहुत आवश्यक है। कला और संस्कृति विभाग को मैंने लिखकर भी दिया लेकिन नहीं हुआ। टेकरी के ऊपर जो पर्यटक लोग आते हैं,

(श्री गोपाल कृष्ण)

बीकाजी की टेकरी को देखने के लिए आते हैं कि बीकानेर की शुरूआत में बीकाजी ने यह बनाई थी तो वह कौनसी जगह है, वहां पर आते हैं तो वहां पर ताला लगा रहता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में और तो कुछ नहीं, अमेरिका में देखिए श्रीमानजी, भाषा और साहित्य की बात है, अमेरिका तो राजस्थानी को विश्व की प्रमुख भाषाओं में मान्यता देता है "major languages of the world" में राजस्थानी का नाम अमेरिका की डिक्शनरी में तो है लेकिन हम अभी तक उसको मान्यता नहीं दे रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि संविधान की आठवीं अनुसूची के अंदर इसको शामिल करवाने के लिए आप कोशिश करें और हमारी इस राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने की पूरी-पूरी कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में आज शिक्षा, कला व संस्कृति की अनुदान मांग संख्या 24 पर चर्चा हो रही है। शिक्षा के अंदर राजस्थान कैसे आगे आये, गुणवत्ता की शिक्षा राजस्थान में कैसे मिले, मुझसे पूर्व कई लोगों ने मंत्रीजी की शान के अंदर कशीदे पढ़े, कई लोगों ने विरोध किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगा, जब तक सरकारी स्कूलों के अंदर लोगों का रुझान नहीं बढ़ेगा, तब तक सारे दावे खोखले हैं। आज भी राजस्थान के अंदर, चाहे प्राथमिक स्कूल हो या माध्यमिक स्कूल हो, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, हर कोई पैरेंट चाहता है कि वह सरकारी स्कूल के अंदर अपने बच्चे का एडमिशन नहीं कराए क्योंकि ज्यादातर पद खाली हैं। कहीं तो 40 प्रतिशत पद खाली हैं, कहीं 50 प्रतिशत है और हमारे जो ढाणियों के इलाके हैं जैसे मेरी कांस्टीट्यूएंसी है या जैसलमेर, बाड़मेर है वहां तो बिलकुल हालात ही खराब हैं। कोई निरीक्षण नहीं होता। सरकारी स्कूल के अंदर राजस्थान की सरकार को चाहिए कि एक अनूठी पहल करे। आप नई-नई योजनाएं लाने में तो माहिर हो। नाम देने में स्किल, यह, वो, आप एक काम और करो। यहां से एक परिपत्र जारी करो

(श्री हनुमान बेनीवाल)
कि सरकारी स्कूल के अंदर एमएलए का बेटा भी पढ़ेगा, एमपी का बेटा भी पढ़ेगा, कलक्टर, एसडीएम का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो निश्चित रूप से वहां अध्यापक भी लगेगा। हम वास्तव में किसान का भला चाहते हैं, गांव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार देना चाहते हैं, जो अधिकार आप लाये हो कि हर व्यक्ति शिक्षित हो। यह आप कागजों के अंदर कर रहे हैं कि यह शिक्षा का अधिकार है। यह तभी कारगर होगा जब गांव के अंदर अंतिम छोर पर बैठे गरीब आदमी को भी शिक्षा का पूरा अधिकार मिले और लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को तभी पढ़ाएंगे जब पढ़ने की पूरी व्यवस्थाएं होंगी। सरकारी स्कूलों में फीस भी कम लगती है। प्राइवेट स्कूल के अंदर कितनी फीस लगती है। जयपुर के अंदर जो दो-तीन स्कूल हैं, हम तो फिर भी लड़-झगड़कर एडमिशन वहां पर कर लेते हैं, लेकिन आपके मंत्रीजी का तो वे स्कूल वाले फोन ही नहीं उठाते। मैंने देखा है। मैं खुद एक बार मिला था जब ये कह रहे थे कि आप अपना कराओ तो मेरा भी करा देना डांट-डपटकर। यह हालात है। फीस पर भी कंट्रोल हो। मनमर्जी से फीस ले लेते हैं, चाहे जितनी, कोई धणी-धोरी नहीं। पिछली बार इसी हाउस के अंदर मैं जब बोल रहा था तो मंत्रीजी ने जवाब दिया था कि हम फीस नियंत्रित करेंगे। हम कमेटी बना रहे हैं, आयोग बना रहे हैं, पैरेंट्स को भी रखेंगे, लेकिन अभी वह कागजों के अंदर ही है। कोई फीस नियंत्रण की कमेटी प्राइवेट स्कूल के अंदर नहीं बनी। प्राइवेट स्कूल के लोगों की दादागीरी राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा है। ये पहले तो आते हैं प्राइवेट स्कूल वाले दूसरे तरीके से। हाथ-पाँव जोड़ते हैं। सरकार के अधिकारियों से, दूसरों के मार्फत नेताओं से मिलते हैं और जब उनकी स्कूल चल पड़ती है तो फिर ये नेताओं और अधिकारियों के फोन उठाना बंद कर देते हैं। ये संबंधित जन-प्रतिनिधियों की भी बात नहीं सुनते। इन पर नियंत्रण होना चाहिए, सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। प्राइवेट के नाम पर सरकारी जमीन इनको दे दो, सहायता दे दो। अगर यही लुटाते रहेंगे तो हमारा सरकारी तंत्र खोखला हो जाएगा और यह प्राइवेट स्कूल माफिया इस राजस्थान के अंदर पनप जाएगा।

आज राजस्थान का जवान आत्महत्या कर रहा है। डिग्रियां तो बांट रहे

(श्री हनुमान बेनीवाल)
हो। अभी सरपंच के चुनाव हुए, कितनी फर्जी डिग्रियां राजस्थान के अंदर बंटी। शायद दौसा और नागौर दो ऐसे जिले थे जहां सबसे ज्यादा फर्जी डिग्री से सरपंच लोग बन गये। आठवीं के ले आये, दसवीं के ले आये। कोई उत्तरप्रदेश से अलीगढ़ से ले आया, कोई कहीं से ले आया। आपने कर तो दिया आनन-फानन के अंदर कि आठवीं या दसवीं पास होना चाहिए, लेकिन उसमें ध्यान नहीं दिया कि यह किस तरह का फर्जीवाड़े का खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर यूनिवर्सिटी का फर्जीवाड़े का घोटाला था और आज जिस तरह नकल की घटनाएं हो रही हैं चाहे आरपीएससी हो, विश्वविद्यालय हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, अख़बार का पहला पन्ना पलटते ही एक खबर जरूर आती है कि वहां नकल हुई। नकल कराते हुए शिक्षक या छात्र पकड़े। कैसी व्यवस्था है? उस व्यवस्था को कौन ठीक करेगा? 70 साल बीत गये। एक बार आप कहते हैं कि आपने यह किया और अगली बार फिर आते हैं कि आपने यह किया। इसके अलावा कोई भाषण शिक्षा पर, बजट पर या कभी राज्यपाल का अभिभाषण हो, अच्छी बहस नहीं हुई। हम सबको मिलकर यह देखना होगा कि इस राजस्थान के गरीब को कैसे अच्छी शिक्षा मिले। गरीब आदमी को शिक्षा के साथ रोजगार की व्यवस्था की गारंटी भी होनी चाहिए। एक लाख डिग्री बांटते हो और नौकरी 100 देते हो एक लाख पर। क्यों बाबूसिंह जी, सही है या गलत है? आप तो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हो।

उपाध्यक्ष महोदय, आज कोटा एजुकेशन का हब बन गया। जयपुर के अंदर भी सैकड़ों कोचिंग संस्थान खुल गये। हमारे पास छात्र आते हैं। गांव के गरीब किसान के बेटे यहां आते हैं और जिनकी कोचिंग संस्थाएं अच्छी चलती हैं, वे गुण्डागर्दी करते हैं, चाहे जैसे छात्र का नाम काट देते हैं, फीस बताते कुछ हैं और फीस उनको पूरी देनी पड़ती है। नहीं तो कह देते हैं कि आप तो जाइये, आपकी छुट्टी। इसमें भी जो कोचिंग संस्थाएं हैं इन पर नियंत्रण के लिए कारगर कदम राजस्थान की सरकार को उठाना चाहिए।

कोटा के अंदर हमारा छात्र आत्महत्या कर रहा है, जवान आत्महत्या कर रहा है। वह डिप्रेशन में क्यों जा रहा है? इस दिशा में भी सरकार को

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सोचना चाहिए। उसका कैरियर उसके सामने पड़ा है और वह ऐसी कौनसी पढ़ाई करता है और ऐसा कौनसा डिप्रेशन उसमें आ जाता है कि उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। सबसे ज्यादा आत्महत्याएं अगर कहीं हुई हैं तो साढ़े तीन साल के अंदर इस राजस्थान के अंदर कोटा, जयपुर और दूसरी जगह छात्र व जवानों ने की है।

उपाध्यक्ष महोदय, 15 लाख में मैं नहीं जाना चाहता, 15 लाख को रोजगार की बात कही थी। अच्छा तो यह होता कि राजस्थान में जितने भी स्कूल में खाली हैं, कॉलेज व विश्वविद्यालय के अंदर खाली हैं, आप प्रोफेसर का इंटरव्यू कराते, लेक्चरर्स की भर्ती करते, थर्ड ग्रेड, सैकण्ड ग्रेड अध्यापकों की भर्ती करते, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। अब चौथा साल है, कम से कम अब तो कर दो। खाली उत्तर प्रदेश के चुनाव से राज़ी होकर 2018 के अंदर राजस्थान के चुनाव में निकल मत जाना। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर फर्क है। वहां अलग बात है, यहां राजस्थान अलग है। आपको काम करके जाना होगा।

सुराज संकल्प यात्रा के दौरान आपकी पार्टी के नेता ने और आप लोगों ने जो वादे राजस्थान की जनता के सामने किये, किसान के सामने किये, जवान के सामने किये, उसको झुनझुना पकड़ाया। इसके अंदर सरकार को कारगर कदम उठाना चाहिए। मैं घनश्याम जी तिवाड़ी को धन्यवाद दूंगा। पहली बार, मैं कह रहा हूं, कांग्रेस की सरकार के अंदर मैं पिछली बार आपकी पार्टी से विधायक था। मैं देखता था कि भर्ती हो रही है, आरपीएससी से करा रहे हैं या कभी कहते थे जिला परिषद से करा रहे हैं, लेकिन भर्ती नहीं हुई। यदि गलती से आपने वैकेंसी निकाल भी दी और आपका एडवरटाइजमेंट आ गया तो हाईकोर्ट के अंदर अटक गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अटक गई। मैं घनश्यामजी को इस बात का धन्यवाद दूंगा। 1 लाख 18 हजार भर्ती इस राजस्थान के अंदर 20 साल के अंदर पहली बार की तो वह घनश्यामजी तिवाड़ी की सोच थी, आपकी सरकार की सोच नहीं थी। सर्वशिक्षा अभियान का पैसा था, वह वापस जाता, वह पैसा लैप्स हो जाता, कई तरह की बातें आयीं। कई लोग उस समय कहते थे कि संविदा पर ले लो। लेकिन इन्होंने कहा मैं आरपीएससी के माध्यम से एग्जाम कराऊंगा और पारदर्शिता

(श्री हनुमान बेनीवाल)

से एग्जाम कराऊंगा। वह पहली बार भर्ती राजस्थान के अंदर हुई। वह एक उपलब्धि आपकी 2003 से 2008 में रही। उसके वोट तो आपने 2008 में ले लिये थे। अब 2013 से 2018 की तरफ जाओगे। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं, अगर सही काम करते हैं तो उनको धन्यवाद भी देता हूं। मैं घनश्यामजी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान के अंदर अगर किसान के बेटे की सबसे ज्यादा नौकरियां कभी लगी तो घनश्यामजी तिवाड़ी जब मंत्री थे, तब इन्होंने 1 लाख 18 हजार भर्तियां कीं। इन्होंने कांग्रेस सरकार के समय 1998 के अंदर पैराटीचर आनन-फानन में लिये थे उन 24 हजार पैराटीचर को प्रबोधक बनाकर राजस्थान में उनके भविष्य को सुरक्षित किया। उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) पाँच-सात मिनट दो ना मुझे।

श्री उपाध्यक्ष: पाँच मिनट और बोल लें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ऐसा मत करो, दसेक मिनट तो देओ साहब। मैं तो कल भी नहीं बोला था।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे निर्दलियों का समस्त समय आप ले चुके हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आज तो मैं ही हूं, और कोई है ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: चलिए, पांच मिनट और बोल लीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): निर्दलीय और कांग्रेस में ज्यादा अंतर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: आप सुझाव दे दें। अच्छे-अच्छे सुझाव दे दें तो अच्छा होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में 14 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इससे जुड़े अधिनियम को 2009 में पूरे प्रदेश में लागू कर दिया, लेकिन इस अधिनियम की पालना कैसे होगी? कैसे वह ढाणी का बच्चा प्राथमिक शिक्षा हासिल करेगा? आपने स्कूल बंद कर दी। कक्षा 6 से 8 तक कंप्यूटर सीखने वाले प्रत्येक छात्र से 80 रुपये प्रति महीना ले रहे हैं। कक्षा 9 से 12 तक के

(श्री हनुमान बेनीवाल)

छात्रों से 1200 रुपये की राशि सालाना लेने का फरमान जारी किया। मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि एक तरफ तो आप 14 वर्ष तक नि:शुल्क शिक्षा के प्रावधान की बात करते हो और दूसरी तरफ ग्रामीण छात्रों से पैसे लेकर कंप्यूटर सिखाने की योजना बनायी। आज डिजीटल लिट्रेसी की बात करते हैं, डिजीटल इंडिया की हम बात करते हैं। जब बात आती है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में छात्रों को साक्षर कैसे बनाएं तो फिर आपने फीस लेने का प्रावधान कैसे किया? आपको पूरी फीस माफ करनी चाहिए। नि:शुल्क कम्प्यूटर की शिक्षा वहां मिले, ऐसी व्यवस्था राजस्थान की सरकार को करनी चाहिए।

(20.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात कही मगर इसमें भी बहुत बड़ी विसंगति है। निजी स्कूल संचालकों द्वारा इसमें भी बहुत बड़ी हेराफेरी की जा रही है तो इस दिशा में सरकार को सोचने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मिड-डे मील के अन्दर गुणवत्ता परखने हेतु सरकार को समय-समय पर सख्ती से ध्यान देने की आवश्यकता है। इस योजना में कार्यरत 1 लाख 11 हजार 684 कुक-कम-हैल्पर को जो वेतन दिया जा रहा है, उसमें 200 रुपये की बढ़ोतरी की है, तो इसको और ज्यादा करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा। तबादला नीति की बात भी आई लेकिन अभी तक राजस्थान में तबादला नीति नहीं बनी। चार साल से सत्ता पक्ष के लोग भी, टीचर भी, विपक्ष के लोग भी यह देख रहे हैं कि नई तबादला नीति बनेगी। बाड़मेर, जैसलमेर और जो प्रतिबंधित जिले हैं वहां लगा हुआ टीचर भी कह रहा है कि मुझे 10 से 15 साल हो गये, मैं मेरे गांव जाऊंगा। अभी सत्ता पक्ष के एक-दो माननीय विधायकों के सुझाव आये थे उपाध्यक्ष महोदय, उनका मैं स्वागत करता हूं और सरकार को प्रतिबंधित जिलों से टीचर्स को उनके मूल जिलों में लाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी को एक विशेष बात यह भी कहना

(श्री हनुमान बेनीवाल)

चाहूंगा। आप तो अजमेर में ही पूरा उलझ गये। अनिताजी और आप लड़ते रहते हो तो फिर राजस्थान के बच्चों के भविष्य के साथ इससे बड़ा क्या खिलवाड़ होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को अजमेर से बाहर निकलना चाहिए और राजस्थान के बच्चों के कैरियर की इनको चिंता करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन बातें मेरी जरूरी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर के अन्दर राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पीपल का कुआं में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक हरिप्रकाश गुप्ता ने प्रधानाध्यापिका श्रीमती अमिता तोषनीवाल से प्रताड़ित होकर दिनांक 09.03.2017 को आत्महत्या कर ली। उपाध्यक्ष महोदय, मृतक लिपिक ने अपने सुसाइड नोट में प्रधानाध्यापिका श्रीमती अमिता तोषनीवाल व अन्य पर इल्जाम लगाया जिसका उल्लेख थाना गंज पुलिस के अन्दर यह एफ.आई.आर. 71/17 दर्ज है। उस लिपिक की आत्महत्या के बाद सरकार ने अमिता तोषनीवाल को अजमेर शहर से ए.पी.ओ. कर दिया लेकिन अभी तक उसको सस्पैंड नहीं किया। जो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज है उसके अन्दर कार्यवाही नहीं की। मैं मंत्रीजी से इतना ही चाहता हूं कि मंत्रीजी, आप इसको संरक्षण नहीं दें, जिसकी वजह से वो आत्महत्या हुई है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट और दें। उपाध्यक्ष महोदय, जो बाजार में बात होती है वो ही कहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और थी कि शिक्षा मंत्री के निजी स्टाफ में +++ द्वारा लिपिक +++ के मार्फत स्थानान्तरण पर रुपये की मांग करने पर आत्महत्या की गई जिसकी जांच में लीपापोती कर दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह तो उस टाइम राजस्थान में सारी खबर आई थी और आंदोलन हुए थे। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और....

श्री उपाध्यक्ष: चलिये, अब धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट उपाध्यक्ष, महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप तो बाजार की बातों पर आ गये, बाजार की बातों का क्या, कभी इधर रख दे कोई, कभी उधर रख दे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय। जो बात राजस्थान के अन्दर चल रही है, उपाध्यक्ष महोदय, सबको बात कहने का अधिकार है, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं लेकिन

(श्री हनुमान बेनीवाल)

राजस्थान के अन्दर बात चलती है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास तो टीचर और ये लैक्चरर्स आते हैं। (व्यवधान) एक मिनट रुको। आप बता देना वापस।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, अपन कहां थे?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं सही ट्रेक पर ही हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अपन शिक्षा पर थे और चलते-चलते कहीं बाजार में आ गये तो अब वापस अपन वहां तो जाएं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): शिक्षा पर ही आ रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई मंत्रीजी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि आज बाजार के अन्दर यह बात चलती है कि प्रिंसिपल 3 लाख, लैक्चरर एक लाख.....

श्री उपाध्यक्ष: अब चलिये, बहुत हो गया। अब विराज जाएं आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सैकण्ड ग्रेड 75 हजार, थर्ड ग्रेड 50 हजार, मुकेश से मिल लो.....

श्री उपाध्यक्ष: अब विराजें आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उससे मिल लो। यह मैं नहीं कह रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: अब ये बातें शिक्षा विभाग से परे की हैं। गृह विभाग का जब आये तब आप बता दीजियेगा। अब विराज जाएं सम्माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ये टीचर, इनके जो कर्मचारी संगठन हैं वे हमको मिलते हैं उपाध्यक्ष महोदय और ये कहते हैं कि भारी भ्रष्टाचार इस तबादला नीति के अन्दर है इसलिए....

श्री उपाध्यक्ष: अब आसन पैरों पर है, सम्माननीय सदस्य, विराजो आप।

मैं सांगानेर से आने वाले सम्माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा। आपका पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन पर भरतपुर का जो भी है उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह सूचित करने के लिए मुझे कहा है कि गृह मंत्रीजी कल इसका वक्तव्य दिलायेंगे।

श्रीमती द्रोपती।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): टेबल कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: टेबल तो होगा नहीं सर। चलिये, उसको विदड्रा, उस पेपर को सस्पैंड कर दीजिये। श्री कैलाशजी भंसाली। मैं क्रम का निवेदन कर देता हूं। कैलाशजी भंसाली, तरूण राय कागा, संदीप शर्मा Followed by Shakuntla ji Rawat and concluded by Manik Chand ji Surana, that's it. सम्पूर्ण शिक्षा के सम्बन्ध में आज आप मांग पारित कर रहे हैं और शिक्षा के लिए देर रात तक आपने, जिसको कहते हैं कि तेल के दीये जलाये हैं इसलिए शिक्षाप्रद बात हो जाए, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आप विराज जाओ।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या -24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर बोलने का आपने अवसर दिया। माननीय शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी जी शिक्षाविद् हैं, कला के सेवक हैं एवं संस्कृति के रक्षक हैं। मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपने इस कार्यकाल में, माननीय मुख्य मंत्री महोदया के कार्यकाल में शिक्षा क्षेत्र में कई ऐतिहासिक कार्य किये हैं जिनकी सराहना पूरे प्रदेश के जन-जन के द्वारा की जा रही है। विशेषकर समानीकरण, नामांकन और पांच हजार आदर्श विद्यालय खोलने का जो आपने प्रयास किया है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरा जोधपुर शहर शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ शहर है, ऐसा आज तक माना जा रहा है और माना जायेगा। कारण यह है कि यहां पर कॉमर्स की शिक्षा का बहुत बड़ा केन्द्र है और आजकल टैक्निकल एजुकेशन और आई.आई.टी. खुलने के बाद में, फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट और केन्द्रीय सरकार के अनेक उद्यम यहां खुल गये हैं जिससे शिक्षा का बड़ा विस्तार हुआ है। परन्तु दयनीय स्थिति यह है कि यहां कई विद्यालय हैं जो 80-100 साल पुराने हैं, वे जर्जर हालत में हैं और कभी भी गिर सकते हैं। बारिश में एक-दो स्कूलें गिर भी गईं पर अच्छा हुआ कि बारिश उस समय हुई जब बच्चे स्कूल में नहीं थे नहीं तो अकाल मौत हो जाती।

आपने 37 हजार शिक्षकों की भर्ती की। 86 हजार शिक्षकों को पदोन्नति दी जो पहली बार इतनी पदोन्नति हुई है। उसमें काउंसलिंग के जरिये पूर्ण पारदर्शिता से पदस्थापन किया गया जिससे शिक्षकों में भी सरकार के प्रति

(श्री कैलाश भंसाली)

सद्भावना है। मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस नीति का, जितने भी शिक्षक संघ हैं उन सबके यहां मैं गया हूं तो सबने भूरि-भूरि प्रशंसा की है कि इस कारण से हमें बहुत लाभ हुआ है और जहां चाहते थे वहां पर हमारा पदस्थापन हो गया है तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। 13,900 प्राथमिक विद्यालयों के समीप 11,730 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वय, एकीकरण एवं 13263 एकीकृत विद्यालयों की स्थापना कर कार्यरत शिक्षकों का बेहतर उपयोग तथा विद्यालयों का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित किया है उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। इतनी मात्रा में पदोन्नतियां न कभी हुई और न कभी हो पायेंगी। यह राजस्थान के शिक्षा जगत में एक मिसाल बनेगी।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हेतु पांच हजार माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया है। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 11-12 में नामांकन में 32 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है, यह बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का सरकारी विद्यालयों में रूझान बढ़ा है। वर्ष 2012 में 53.4 प्रतिशत था जो बढ़कर 56 प्रतिशत हो गया है। यह बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। 2017-18 में 105 ग्राम पंचायतों में संचालित कक्षा 10 में 40 से अधिक नामांकन वाले एक-एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है।

मान्यवर, जोधपुर के कुछ स्थानों पर विद्यालयों की बहुत आवश्यकता है। जोधपुर झालामण्ड एरिया में दो लाख की जनसंख्या है। वहां सीनियर सैकण्डरी स्कूल है परन्तु उसमें विज्ञान, गृह विज्ञान एवं कॉमर्स के विषय नहीं होने से बच्चों को बड़ी असुविधा हो रही है। वैसे भी वहां कुम्हार समाज के लोग ज्यादा रहते हैं। वे बच्चियों को आगे पढ़ाने नहीं देते तो अगर यह विद्यालय वहां क्रमोन्नत हो जाएगा तो बच्चियां आगे पढ़ सकेंगी।

डाक्टर पदमचन्द विमल कंवर गांधी सीनियर सैकण्डरी स्कूल में विज्ञान एवं गृह विज्ञान विषय क्रमोन्नत कराया जाए। कृषि बस्ती में है, सारा समाज वहां इकट्ठा है और सरगरा समाज के बच्चे सभी सुविधाओं, कक्षा-कक्ष, लेबोरेट्री ट्रस्ट द्वारा देने की बात है और वेतन सरकार को देना होगा। आप इसको क्रमोन्नत करें। यह बहुत बड़ी मांग है।

(श्री कैलाश भंसाली)

वैसे मैंने मंत्रीजी से बात की थी तो उन्होंने कहा, सरकार का शहरों के लिए कोई निर्देश नहीं आया है। मैं मुख्य मंत्रीजी से इस सदन के माध्यम से निवेदन करूंगा कि शिक्षा गांव और शहर के लिए अलग-अलग नहीं होती है। बच्चे सबके बच्चे हैं। उनको पढ़ने के लिए पूरी सुविधा दी जाये। भगत की कोठी एरिया है। उसमें सीनियर सैकण्डरी स्कूल में विज्ञान, वाणिज्य एवं कला को क्रमोन्नत किया जाये। कक्षा-कक्ष तैयार हो गये हैं परन्तु विद्यालय की क्रमोन्नति नहीं हुई है। यह क्रमोन्नत होगा तो ही मामला बैठेगा। सरदारपुरा सीनियर सैकण्डरी स्कूल में कामर्स एवं गृह विज्ञान को क्रमोन्नत किया जाये। बाईजी तालाब सीनियर सैकण्डरी स्कूल में गृह विज्ञान एवं कम्प्यूटर की कक्षा भी प्रारम्भ की जाये। कम्प्यूटर लैब के लिए एनआरआई ने 24 कम्प्यूटर्स भेजे हैं। राजमहल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान विषय प्रारम्भ किया जाये। कामर्स और आर्ट्स तो है। फतेहपोल उच्च माध्यमिक विद्यालय को कक्षा 9 आर्ट्स के विषय के साथ में प्रारम्भ की जाये। कोतवाली विद्यालय को सैकण्डरी स्कूल बनाया जाये। खाण्डाबरसा सीनियर सैकण्डरी स्कूल में गृह विज्ञान का कम्प्लीट कोर्स का विषय चालू किया जाए। सिवांची गेट स्कूल को चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में शिफ्ट किया गया है, वहां अल्पसंख्यकों को शिक्षा दी जाती है। उसको अधिक सुविधाएं दी जाये। नामांकन वहां 100 परसेंट बढ़ा है। इसके लिए स्कूल के सारे टीचर्स बधाई के पात्र हैं।

जोधपुर की स्कूलों में टीचर्स की कमी नहीं हैं। टीचर्स सब जगह हैं परन्तु कई जगह बहुत ज्यादा टीचर्स हैं और कई जगह नहीं, तो इसको बिलकुल बैलेंसिंग किया जाये ताकि सब जगह शिक्षक समान रूप से मिले और विशेषकर विज्ञान के और मैथेमेटिक्स और फिजिक्स, बोटनी के शिक्षक बहुत कम हैं।

अब मैं उच्च शिक्षा के बारे में माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा। झालामण्ड क्षेत्र में कोई पीजी महाविद्यालय नहीं है। वह खोला जाये। वहां बहुत बड़ी जनसंख्या है। राजमहल पैलेस स्कूल में महाविद्यालय बनाया जाये। 125 साल पुरानी स्कूल है। जहां बहुत अच्छी-अच्छी महिलाओं ने, जो आगे जाकर आईएएस, आरजेएस और न्यायाधीश बनी हैं, वे सब यहां पढ़ी हुई हैं।

(श्री कैलाश भंसाली)

जयनारायण विश्वविद्यालय में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी 48 करोड़ रुपये पेंशन फण्ड के लिए राज्य सरकार ने अभी तक नहीं दिये हैं। मेरा निवेदन है विशेषकर क्योंकि मैं सीनेट का मेम्बर हूं, इसलिए आवश्यक रूप से यह राशि मुहैया कराई जाये। फाइनेंस सैक्रेटरी साहब के पास फाइल पड़ी हुई है। कृपया सरकार ध्यान दें और जयनारायण विश्वविद्यालय के नाले पर एसी मार्केट लीज पर देने की स्वीकृति प्रदान की जाये। निजी विश्वविद्यालयों को हर वर्ष रिन्युअल नहीं कराना पड़े, उसके लिए सरकार गाइडलाइन तय करे।

गत तीन वर्षों में 28 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले गये एवं पाँच राजकीय महाविद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया।

तकनीकी शिक्षा एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए आगामी वर्ष में 6,315 करोड़ 38 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2016-17 से संशोधित अनुमान से 8.21 प्रतिशत ज्यादा है। मेरा एक खास निवेदन है कि जोधपुर में शिक्षा का बहुत अच्छा माहौल है परन्तु यहां पर शिक्षकों की कमी है और सब्जैक्ट्स सब जगह नहीं है। सब जगह सब्जैक्ट्स खोलने चाहिए। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री तरुण राय कागा।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): शुक्रिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-24 शिक्षा, कला और संस्कृति के मौज़ूं पर बोलने का जो मौका फराहम किया, इजाजत दी, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

आज जिस मौज़ूं पर इस सदन में बहस-मुबाहिसा हुआ, तमाम माननीय सदस्यों ने अपने ख्यालात तासरात का इजहार किया और हमारी सूबाई हुकूमत वजीरे-तालीम मिस्टर देवनानी साहब ने इसी तलीम के शोबे में जो इन्कलाबी कदम उठाकर हमें नई राह अता की है, जिसके लिए मैं वजीरे-तालीम का शुक्रिया अदा करूंगा।

यह इस हमारे सूबे के आम-अवाम के लिए कई मुख्तलफ इन्होंने कदम उठाये हैं, जो एक मील के पत्थर साबित होंगे। मैं क्या कहूं, जब पिछली सरकारों ने आठवीं का बोर्ड भी खत्म करके, किसी को नापास नहीं करने का भी जो एक हुकम जारी किया था, उन्होंने इसको मुअत्तल करके जिस तरह से नई राह ईजाद की, वह एक काबिले तारीफ है।

(श्री तरुण राय कागा)

हालांकि यह हमारे हैं। मैं इनको यही कहूंगा कि आपने कई स्कूलों में नई-नई बातें, नई-नई कसमें, नये-नये करतब दिखाये हैं, लेकिन मैं यह कहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में, विधान सभा इलाके में 12 ऐसी पंचायतें हैं, जहां कोई सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। मेरा मुतालबा होगा कि इन 12 ग्राम पंचायतों में सीनियर सैकण्डरी स्कूल खुलें। मैं आपको यह गुजारिश करना चाहूंगा, आपने काफी इन्कलाबी कदम उठाये हैं जिसमें प्रमोशन से लेकर या आपने कौंसिलिंग से लेकर कदम उठाकर काफी कुछ हमारे लिए नायाब तोहफा अता किया है, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा वापस करूंगा।

आपने जिस तरह से माडल स्कूलों का हुक्म फरमाया कि हर उपखण्ड की माडल स्कूल होगी लेकिन मेरे इलाके में दो उपखण्ड हैं जिसमें एसडीएम आफिस चौहटन में खुला हुआ है, लेकिन हमारे सेड़वा उपखण्ड है उसमें माडल स्कूल, स्वामी विवेकानन्द की स्कूल की दरकार है। मैं आपसे यही मुतालबा करूंगा क्योंकि मेरा जो इलाका है, मेरा जो असेम्बली क्षेत्र है, वह एक अन्तरराष्ट्रीय बेनलकुआमी में सरहद पर है और वहां से आगे पाकिस्तान है और वहां इस साइड भी दूसरा सूबा है गुजरात और कच्छ का रण और यहां जालौर जिला है और यहां हमारा जो बाड़मेर है, ऐसा पश्मादा इलाका है और जाहिलियत का इलाका है। इस इलाके में स्कूल का, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप वहां स्कूलों का जाल बिछायेंगे तो अच्छा होगा। हमारी बच्चियां जो अब मुझे मालूम हुआ, पहले बच्चियां आठवीं पास करके, उसके बाद में कोई सैकण्डरी या सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं हुआ करती थी, तब वह पढ़ाई के बीच में रूखना पैदा हो जाता था, पढ़ाई छोड़ देती थीं, तालीम से महरूम हो जाती थीं। अभी जो रोशनी की थोड़ी किरण दिखाई दी, उससे हमारी उम्मीदें, आशाएं हैं। हमारे इस इलाके में कोई महाविद्यालय, जो कालेज कहा करते हैं, नहीं होने की सूरत में हमारी बच्चियों का भविष्य, हमारी बच्चियों का मुस्तकबल एक अंधेरे की ओर, अंधेरे की गर्त में जा रहा है। हमारे इलाके की, हमारे सब लोगों का मुतालबा है कि इस क्षेत्र में अगर हम कालेज नहीं दे पाये, तो वहां आगे दूसरी जगह हमारे 200 किलोमीटर के इर्द-गिर्द भी कोई इस तरह से नहीं है। मेरा चौहटन सूबा इस असेम्बली क्षेत्र

(श्री तरुण राय कागा)

में है। जिस तरह से भौगोलिक क्षेत्र है, जो एराजी है, वह भी आपको बताऊं कि 4,46,513 हैक्टेयर में फैला हुआ है। वहां की जनसंख्या 4 लाख 50 हजार 304 है। हमारे 486 गांव हैं और हमारी 95 ग्राम पंचायतें हैं मगर वहां ग्रामों में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। यह हमारे लिए एक दुखद बात है। मैं इस बारे में आपसे गुजारिश करना चाहूंगा आप हायर एजुकेशन के मंत्री भी मौजूद हैं और आप भी हैं और मैं हमारे सूबा-ए-वजीरे आला से भी गुजारिश माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत करूंगा कि हमारा इलाका इस प्रकार से जहालत में मुब्तला है तो उनको एक राहत देने के लिए एक अदद कॉलेज की बहुत अति जरूरत है।

हालांकि यह भी यों कह रहा हूं कि उसके अलावा, मैं मेरी तरफ से कुछ कहना चाहूंगा कि हमारे यहां जिस तरह आपने एकीकरण करके स्कूलों में, कुछ स्कूलों की बिल्डिंग किसी सुरक्षा व्यवस्था के बगैर, जो जर्जर हालात में पड़ी हैं, उनके लिए भी किसी सरकारी महकमों को वो दी जाए अन्यथा जो लाखों रुपये उन पर जाया किये गये हैं, वो नुकसानदायक होंगे।

मैं कहता हूं, हमारा एक नारा है 'सबका साथ सबका विकास' और हमारा 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का नारा भी है। मैं यह कहूंगा कि हमारी नन्ही-मुन्नी कलियां हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए जो स्कूल है, उनका अलग भवन बने और उन बच्चियों के लिए भी कुछ किया जाए।

मैं यह कहूंगा, हमारा क्षेत्र कला के लिए बहुत रिच है वहां 1971 के हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान हमारे जो लोग आये हैं वो अपने साथ एक कला लाये हैं कपड़े कशीदाकारी का और ऐसी कला जिसका माल विदेशों में लोग एक्सपोर्ट करते हैं। वो हमारे बनाने वाली महिलाओं को थोड़ा सा कम मेहनताना मिलता है, इसलिए मैं कहूंगा कि कला का या तो वहां पर केन्द्र खोल करके या छोटी बच्चियों की पढ़ाई के लिए उन बिल्डिंगों को ट्रांसफर किया जाए, ताकि उन बिल्डिंगों का भी उपयोग हो सकेगा।

इस तरह से मेरी यह भी गुजारिश है और मेरे वहां कस्तूरबा गांधी स्कूल, मेरे असेम्बली क्षेत्र में तीन पंचायत समितियां हैं चौहटन, धनाऊ और सेड़ुआ। सेड़ुआ पंचायत समिति में एक कस्तूरबा गांधी स्कूल है लेकिन चौहटन और धनाऊ में नहीं है। मेरी गुजारिश रहेगी कि आप इन दोनों

(श्री तरुण राय कागा)

पंचायत समितियों में कस्तूरबा गांधी स्कूल खोलने की भी मेहरबानी करें।

मैं यह कहना चाहूंगा कि आप हमारे सिंध इलाके से पैदाइशी सिंधी हैं तो मैं मेरी तरफ से आपकी शान में एक कशीदा पढ़ना चाहूंगा, 'माण्हु सब ने सुहिणा, पखी सब निहंज कैह कैह माण्हु मंझि अचे बू बाहर जी' हमारे शिक्षा मंत्रीजी, यह मैं आपकी शान में देना चाहूंगा कि हमारे पाक आईन के मुताबिक हमारी सिंधी जुबान, जो एक तस्लीमशुदा जुबान है। इस शिक्षा के इंकलाबी कदम उठा रहे हैं लेकिन हमारी मातृभाषा सिंधी के लिए आपने इसमें कुछ ऐसा रद्दोबदल या सब्जेक्ट नहीं किया है। मेरी गुजारिश रहेगी, चूंकि मेरा फर्ज बनता है मैंने पहले दो असेम्बली सेशन में अपना हलफ उठाया था, कसम ली थी, तब सिंधी जुबान में लिया था हमारे कई मित्रों ने, हमारे कई अजीज दोस्तों ने कहा था कि मैंने कसम उठाया तो यह क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन हमारा फर्ज बनता है हम जिस मिट्टी में पैदा हुए, जिस मां की कोख में पैदा हुए तो हमारे को उनके दूध को नहीं लजाना है इसलिए मैं आपसे कहूंगा, हालांकि हमारे...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ये वजीरे तालीम सिंधी जानते भी हैं कि नहीं, यह तो पूछ लो।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): जानते हैं साहब, जानते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि हमारे...

श्री उपाध्यक्ष: जब आपने इनको वजीरे तालीम ही कह दिया तो ये तो सिंधी क्या बहुत सी चीज जानते होंगे।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): जानते हैं साहब, कई भाषा जानते हैं। मैं इनको यह कहूंगा कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, हुकूमत-ए-राजस्थान, सूबाई हुकूमत ने हमारे सिंधी की भाषा, सिंधी जुबान की बहबूदी के लिए सिंधी भाषा एकेडमी भी बनाई हुई है, लेकिन मुझे बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि उस भाषा की एकेडमी का कहीं नामोनिशान नहीं है। कोई उसका चेयरमैन नहीं है, कोई उसका मैंबर नहीं है, न कोई उनको अख्तियारात हैं। यह मुझे बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको मजबूत बनाने के लिए, इस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको एक बहुत बड़ा सुझाव भी दूंगा और राय भी दूंगा

(श्री तरुण राय कागा)

कि इसके लिए कुछ न कुछ कदम उठाया जाए। मैं अब ज्यादा तो क्या कहूं। मैं कला के बारे में कह रहा था। हमारे लोग जो वो आये हैं कपड़े के कशीदाकारी या लकड़ी के, हमारे वहां एक इमारती लकड़ी पैदा होती है जिसको रोहिड़ा कहते हैं लेकिन हमारे यहां दूसरी जो कीमती लकड़ियां हैं...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): नहीं, साहब। थोड़ा सा मेरे को भी बोलने जरूर दें। उनको भी जो ये नक्काशी का काम होता है तो इन लोगों के लिए वहां खरीद-फरोख्त के लिए एक मरकज बनाया जाए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। इनको तो आधे घंटे और कम से कम समय दिया जाए। हमारा निवेदन है आज इस भाषा का जिस तरह से प्रचार-प्रसार करने का और ये तो इनको समझाना है जिनको, वो समझ रहे हैं। जिनको समझाना चाहते हैं वो समझ जाएंगे। समझाना चाहते हैं वो समझा रहे हैं और आधा घंटे तक बोलने दिया जाए साहब।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप शायद मंत्रमुग्ध होकर के सुन रहे हैं इसलिए इनको ज्यादा समय भी दिया है।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): हमारे जो यह कलाकारी है इसकी खरीद-फरोख्त के लिए, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए यहां एक मरकज बनाया जाए ताकि वहां हमारे लायक एक, मैंने पहले भी हमारी मीटिंग्स में कहा है। इस कार्य को जब हम बेरोजगारों को, श्रमिकों को, मजदूरों को, जो सौ दिन का रोजगार देने की गारंटी की बात करते हैं तो इस कला को, उस नरेगा से जोड़ करके, उन महिलाओं को घर बैठे रोजगार करके सरकार उनका माल बेचने की व्यवस्था करें तो यह एक बहुत बड़ी पहल हो सकती है। हमारे वहां इलाके में जो हमारी संस्कृति है वह संस्कृति हमारी मिली-जुली संस्कृति है। आप हमेशा पहले जिक्र कर रहे थे हमारी तालीम का, शिक्षा का बहुत बड़ा पुराना, हम विश्व गुरु रहे हैं, दुनिया के उस्ताद रहे हैं हमारे यहां बड़े-बड़े तालीम के मरकज रहे हैं। नालन्दा रहा है लेकिन मैं आपको याद दिलाऊंगा कि तक्षशिला एक ऐसा है जो हमारे सिंध में आज दिन तक महशूर बहुत बड़ा तालीम का मरकज रहा है।

(श्री तरुण राय कागा)

आपको मैं सिंधी संस्कृति, तहजीब के बारे जिक्र करना चाहूंगा तब आपको यह याद होगा, हमारे राजा जयद्रथ है और हमारे वहां के मोहनजोदड़ो कितनी एक हमारी तहजीबी, कितनी क़दीमी तहजीब वहां की है। यह तो हमारे स्टेट का मामला है। मैं तो सबको दावत दूंगा, हमारे सिंध की तहजीब व तक्षशिला व मोहनजोदड़ो देख कर के आप हैरतअंगेज हो जाएंगे कि वहां क्या-क्या है।

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय सदस्य, अब आप समाप्त कर दें।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): मैं तो समाप्त कर रहा हूं। मैं ज्यादा टाइम न लेकर लेकिन मेरे यहां के जो लोग हैं हम सत्ता में विराजे हैं, ये हमारे आदमी जो बैठे हैं हमारे मुखालिफ या हमारे विपक्षी पार्टी या ना लॉबी के लोग बैठे हैं। हम सब लोग इत्तफाक राय रखते हैं कि हमारे विद्यार्थी मित्र, वो हमारे परम मित्र रहे हैं। हमारे साथ में कदम से कदम मिला कर चले हैं, आज मुझे बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है। हमारे इन तीन सालों में कुछ ऐसे विद्यार्थी मित्र, वो आत्महत्या करके बीस-पच्चीस आदमी पितर हो गये हैं तो मैं उनको श्रद्धांजलि भी देता हुआ, मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी सबकी एक राय है और एक राय होकर उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए कोई न कोई एक माकूल कदम उठायें, यह मेरी आपसे गुजारिश है। मैं ज्यादा अब आपका समय न लेकर यही कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, अब टाइम तो आपने काफी ले लिया।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): नहीं लिया, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: चलिये, अब आप इसको कंक्लूड करिये।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): हमारे जो वजीरे-आला हैं और हमारे हायर एजुकेशन की मंत्री हैं उनकी भी शान में एक मैं अपना शेर कहूंगा।

'हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता चमन में दीदावर पैदा।'

इसके साथ मेरी एक मांग है कि मैं चार साल से हमारे यहां एक कालेज की मांग कर रहा हूं। यह मेरे लिये एक बड़ी सौगात होगी। उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद मेरे इलाके की हालत देखकर आये हैं। मैं आपको एक खुशखबरी बताऊं। मेरे विधान सभा क्षेत्र चौहटन में इस वर्ष 6 और पूरे विधान

(श्री तरुण राय कागा)

सभा क्षेत्र में 5 आरएएस अफसर निकले हैं। हमेशा कहा करते हैं कि सूरज पूर्व की तरफ से उगता है लेकिन अबकी बार यह पश्चिम की ओर से सूरज उगा है। मेहरबानी करके एक कालेज वहां खोलो ताकि हमारे क्षेत्र की तालीम जारी रहे। आपने मुझे मौका दिया उसके लिये उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दिल की गहराई से आपको शुक्राने का नजराना पेश करता हूं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में अनुदान संख्या-24 शिक्षा कला एवं संस्कृति के तहत आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का आशीर्वाद दिया, इसके लिये बहुत-बहुत आभार। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस राष्ट्र में शिक्षा उन्नतशील हो, गुणवत्तायुक्त हो, संस्कारों से जहां विद्यार्थियों को दीक्षित किया जाता हो, निश्चित रूप से उस देश का उत्थान अवश्यंभावी है। वह देश प्रगति के नये आयाम छूता है। आज से पूर्व यदि भारत विश्व गुरु बना तो उसके पीछे भारत की उच्चतर से उच्चतर ज्ञान की सीमाएं और संस्कारयुक्त ज्ञान के साथ-साथ राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम से समाहित समस्त ज्ञानों का कारण रहा है कि हम विश्व गुरु बन पाये।

मैं इस अवसर पर माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने राजस्थान को शिक्षा के व्यापक पहलू और शिक्षा के उच्चतम स्तर की गुणवत्ता व सार्थकता को बडे गंभीर रूप से लेते हुए, राजस्थान में प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतर से उच्चतर शिक्षा की ओर बहुत सार्थक प्रयास किये और यही वजह रही कि आज राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में नई प्रगति की ओर बढ़ रहा है। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने इन तीन वर्षों में ऐसे सकारात्मक निर्णय लिये जिससे शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार हुए, आज शिक्षाविद और शिक्षा से जुड़े सभी लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों का यदि हम विषय लें तो उनके सारे निर्णय अविवेकपूर्ण निर्णय थे। जिस प्रकार जहां विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं थी, जाति-पांति के नाम से विद्यालय खोल दिये गये। ऐसे महाविद्यालय, ऐसे विश्वविद्यालय खोल दिये गये जहां पर मात्र 30-40 विद्यार्थी एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिये करोड़ों रुपये के खर्चे के बाद बैठे नजर आते थे। गांवों में ऐसी जगह स्कूल

(श्री संदीप शर्मा)

खोले गये जहां विद्यालय में दो विद्यार्थी पढ़ने आते थे, छह शिक्षक उन्हें पढ़ाने आते थे फिर भी विद्यार्थी फेल हो जाते थे। ऐसी दयनीय स्थिति में कांग्रेस सरकार ने शिक्षा को मखौल के रूप में लिया था। परंतु आजादी के बाद पहली बार देश में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये व्यापक स्तर पर काम हुए हैं। जो बच्चे गरीबी और अज्ञानता के कारण विद्यालयों से वंचित रह गये थे उन्हें नामांकन अभियान के अंतर्गत विद्यालय में प्रविष्ट कराया गया और बहुत बड़ी संख्या में प्राथमिक स्तर पर बच्चों का नामांकन बढ़ा।

समय की उपलब्धता कम है। मेरा कोटा क्षेत्र जो कि शैक्षणिक नगरी है, मैं सीधे-सीधे अपने कोटा दक्षिण विधान सभा क्षेत्र के विषय में आपको बताना चाहूंगा। कोटा शहर की शैक्षणिक नगरी के रूप में पूरे देश में पहचान है। देश-विदेश से विद्यार्थी यहां पढ़ने आते हैं। इस देश के कई शहरों से विद्यार्थी साइंस और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिये कोटा क्षेत्र में आकर रहते हैं।

(20.35 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा के लिये विज्ञान संकाय बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहा है क्योंकि साइंस की पढ़ाई करने के लिये जो बाहर से विद्यार्थी आते हैं और कोटा शहर के भी जो विद्यार्थी हैं, उनके लिये पर्याप्त संख्या में विज्ञान संकाय हमारे विद्यालयों में उपलब्ध नहीं है। मेरे क्षेत्र के आर के पुरम, शिवनाथपुरम, विज्ञान नगर, संजय नगर, महावीर नगर, सुभाष नगर, ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जहां पर बहुत बड़ी आवश्यकता है कि विज्ञान संकाय इन विद्यालयों में खोले जाय। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, इन तीन वर्षों में मेरी विधान सभा में एक भी विद्यालय में विज्ञान का अथवा वाणिज्य का विषय नहीं खोला गया। मेरा आपसे निवेदन है कि वाणिज्य में भी यही स्थिति है। वाणिज्य भी कोटा क्षेत्र में अब छात्रों की चोइस बनता जा रहा है, इसलिए आवश्यक है। मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आपने कोटा शहर के लिये एक वाणिज्य और एक विज्ञान संकाय का विषय दिया है, लेकिन यह डिमांड के हिसाब से बहुत कम है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं, बड़ी आवश्यकता है इन संकायों की चाहे वह वाणिज्य का हो, चाहे विज्ञान का हो, पर्याप्त मात्रा में इन्हें खोलने की आवश्यकता है।

(श्री संदीप शर्मा)

माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने कोटा शहर में भूगर्भ शास्त्र देकर, चूंकि कोटा की भौगोलिक स्थिति भूगर्भ शास्त्र के अनुकूल थी, इसके माध्यम से कोटा शहर में कई सारे रोजगार से संबंधित युवाओं की आवश्यकता पूर्ण होगी। कोटा खनन और भू-संपदा के क्षेत्र में अग्रणी है, उन्हें रोजगार मिलेंगे। केन्द्र सरकार की बहुत बड़ी योजनाएं, जिसमें कोल मिथेन गैस जो पैट्रोल और गैस के बीच का एक ईंधन है, उस ईंधन की बहुत बड़ी संभावना कोटा शहर में है और भूगर्भ शास्त्र के माध्यम से अनुसंधान कर उस गैस की खोज कोटा शहर में कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा में नये कॉलेज खोले गये हैं, उन कॉलेज में स्टाफ की कमी है। कॉलेज में जो पहले व्याख्याता थे, कर्मचारी थे, उनको इन नये कॉलेजों में अध्यापन कराने के लिये शिफ्ट किया जा रहा है जिससे वह कॉलेज भी प्रभावित हो रहे हैं, साथ ही नये कॉलेजों में भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए इन कॉलेजों में जो व्याख्याताओं और कर्मचारियों के रिक्त पद हैं, उन्हें भरा जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। कोटा शहर में चार वर्ष पूर्व तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में ट्रिपल आई.टी. की घोषणा की गई थी, परंतु अभी तक इस क्षेत्र में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। न तो भवन का निर्माण हो पाया है, न ही और कोई कार्य इस ट्रिपल आई.टी. के क्षेत्र में हो पाया है जबकि ट्रिपल आई.टी. को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल गया है और कोटा जैसे क्षेत्र में, जिसे हम शैक्षणिक नगरी के रूप जानते हैं। वहां ट्रिपल आई.टी. का कार्य पूरी गंभीरता के साथ शीघ्र से शीघ्र चालू हो, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

हमारी मुख्य मंत्रीजी की मंशा रही है कि युवा और विद्यार्थी अपनी शिक्षा अध्ययन के साथ-साथ शारीरिक रूप से भी सक्षम रहें। मानसिक रूप से भी सक्षम रहें, इसलिए बड़े स्तर पर खेलों एवं खेल के मैदानों के लिए बहुत व्यापक रूप से कार्य चल रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी कई कार्य चल रहे हैं। मैं इस अवसर पर बताना चाहता हूं और माननीय मुख्य

(श्री संदीप शर्मा)
मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कोटा में छात्राओं के लिए फुटबाल एकेडमी खोली है। उससे छात्राओं की प्रतिभाएं फुटबाल के क्षेत्र में अग्रसर होंगी, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में मल्टी परपज स्कूल हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक, गुमानपुरा स्कूल। यह कोटा शहर के बिलकुल बीचोंबीच बसा हुआ स्कूल है और बहुत बड़ा भू-भाग इस स्कूल में हैं और बिना रखरखाव के इस स्कूल की बड़ी दुर्दशा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, आवश्यकता है कि इस विद्यालय में खेल संकुल, जिसका प्रस्ताव बनाकर शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार को दे रखा है और जिसको 21 करोड़ रुपए की लागत के साथ प्रस्तावित कर रखा है। यदि उस क्षेत्र में खेल संकुल खुल जाएगा तो वहां पर बहुत सारे ऐसे खेल, बॉस्केटबॉल, फुटबॉल स्विमिंगपुल के साथ-साथ सभी खेलों के ट्रेक वहां पर विकसित हो सकेंगे जिसमें आधुनिक खेल के उपकरणों को भी शामिल किया जाएगा। इनडोर गेम्स भी होंगे, स्विमिंग पूल भी होगा। ऐसा एक प्रस्ताव बनाकर भेज रखा है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो निश्चित रूप से कोटा शहर व पूरे हाड़ौती में खेलों को बहुत बढ़ावा मिलेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं। मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है, वहां कम-से-कम डेढ़ से दो लाख विद्याथी बाहर से पढ़ने आते हैं और वे विद्यार्थी साइंस और मेडिकल की पढ़ाई के चलते दबाव महसूस करते हुए कई बार अवसाद में आकर, कई बार ऐसी अप्रिय घटना कर देते हैं, जिससे पूरा शहर बदनाम होता है। सब लोग हतप्रभ रह जाते हैं, क्योंकि अभिभावकों को छोड़कर एक नितांत अकेले वातावरण में उसको रहना पड़ता है। इसलिए आवश्यकता है कि कोटा में एक ऐसा स्टूडेंट फैसेलिटी सेंटर बनाया जाए, जहां पर बच्चे को समय-समय पर मनोचिकित्सक जैसी काउंसलिंग के लिए अथवा उसकी परेशानी में उसे सहारा देने के लिए या उसके लिए एक ऐसी जगह हो, जहां वह उत्कृष्ट साहित्य वाचनालय या पुस्तकालय में पढ़ सकें। वह पढ़ाई के बोझ से, तनाव व दबाव से फ्री हो, इसके लिए स्वस्थ मनोरंजनात्मक चीजें हों। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो

(श्री संदीप शर्मा)

कोचिंग संस्थान हैं, वे भी अपनी सी.एस.आर. के तहत इस बात के लिए राज़ी हैं। उच्च शिक्षा मंत्रीजी, यदि कोटा शहर के जिलाधीश महोदय को कहेंगी तो निश्चित रूप से कोई एक अच्छी योजना बनाकर इस ओर कार्य किया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, आज स्किल डवलपमेंट के तहत पूरे भारतवर्ष में राजस्थान ने प्रथम आकर अपनी छाप छोड़ी है। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद कौशल दक्षता के तहत देना चाहता हूं, जिससे हमारा युवा दीक्षित होगा। उसे रोजगारपरक शिक्षा दी जाती है। आई.टी.आई. में अनुदेशकों के काफी सारे पद रिक्त चल रहे हैं, उन्हें भरा जाए। इसके साथ ही जिन्हें डिप्लोमा करने के बाद सरकारी भर्ती के लिए अस्वीकार कर दिया जाता है। पॉलिटेक्निक शिक्षा जो बच्चा लेता है, उसको बहुत सारी ऐसी, कनिष्ठ अभियंता की परीक्षा है, आर.पी.एस.सी. की परीक्षा है और अन्य विभागों की परीक्षा है, उनमें वे डिप्लोमा करने के बाद एपीयर नहीं हो पाते। अत: इन बाध्यताओं को समाप्त किया जाए। मेरा यही निवेदन है कि प्रदेश के आई.टी.आई. में तकनीकी शिक्षकों व अनुदेशकों के रिक्त पदों को भरा जाए और डिप्लोमाधारी पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों को भी सरकारी भर्तियों में प्राथमिकता दी जाए।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, अंत में, मैं सिर्फ कला के बारे में कहना चाहूंगा कि संस्कृति और भाषा एक दूसरे के पूरक हैं। बिना भाषा के किसी भी संस्कृति का अस्तित्व नहीं है। राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर मान्यता देने की मांग यहां के लोगों द्वारा लगभग चालीस साल से भी अधिक समय से की जा रही है। राजस्थानी भाषा प्रदेश के साथ, पूरे विश्व में लगभग ग्यारह करोड़ लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है जिसमें सात करोड़ लोग तो सिर्फ राजस्थान में रहने वाले हैं। एक करोड़ पाकिस्तान, सिंध और दूसरे राज्यों में और दो करोड़ शेष भारत में और एक करोड़ विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों द्वारा बोली व समझी जाती है। हजारों विद्यार्थियों ने राजस्थानी भाषा में एम.ए. कर लिया है। उनके लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था नहीं है।

(श्री संदीप शर्मा)

मान्यता नहीं होने से इसे सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ाया जा सकता। इस कारण समाज का शिक्षित वर्ग राजस्थानी भाषा का उपयोग छोड़ रहा है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस मामले में केंद्र सरकार से बात कर इसका समाधान किया जाए और राजस्थान की राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराकर मान्यता दी जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री भजनलाल जी। माननीय सदस्य संध्या अर्द्ध रात्रि की ओर ढल रही है। कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री भजन लाल जाटव (वैर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-24 पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर में कई स्कूल एकीकरण में बंद कर दिए गए। माननीय सभापति महोदय, आज के युग में शिक्षा के बगैर जीवन अधूरा है। शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक रहने की जरूरत है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकारी स्कूलों का स्तर दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है। उसको हम सब लोगों को मिलकर मजबूत करना है, जिससे उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ उन स्कूलों हो रहा है, वह खिलवाड़ न हो।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर में कई ऐसे स्कूल हैं, जो 1967, 1968, 1975, 1976 से भी पूर्व के हैं, वे प्राथमिक हैं, जिनकी नामांकन संख्या 40 से अधिक है, तो मैं उन प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर के विद्यालयों में से पिछले तीन वर्षों में एक भी विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं किया गया है। जबकि पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में करीब 20 हजार विद्यालयों को आपके द्वारा बंद कर दिया गया है जिससे गांव के गरीब किसान व मजदूर का बच्चा पढ़ाई हेतु दर-दर भटकर, दूरदराज में जाकर अध्ययन करने हेतु मजबूर हो रहा है। यह सरकार नहीं चाहती कि गरीब का बच्चा पढ़-लिखकर उन्नति करे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक मांग रखना चाहूंगा। सरकारी स्कूलों के बारे में बड़ी-बड़ी बातें बजट भाषण में कही गई

(श्री भजन लाल जाटव)

थी। गुणवत्ता की बात कही गई थी। मैं कहना चाहूंगा कि उन स्कूलों की गुणवत्ता ठीक थी तो वे बंद क्यों किए गए? निजी विद्यालयों का प्रचलन बढ़ रहा है और दिन-प्रतिदिन ये संस्थाएं ज्यादा जोर पकड़ रही हैं। प्राइवेट स्कूलों को दिन-प्रतिदिन मान्यता दी जा रही है। मैं कहना चाहूंगा कि गरीब किसान का बच्चा जब सरकारी स्कूल में पढ़ता है

और एक अमीर, नौकरशाह या राजनेता का बच्चा उस सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि उनमें हीन भावना पैदा होती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि उन सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में उनकी यूनिफार्म है वह एक जैसी होनी चाहिए। उनका सिलेबस है, वह भी एक जैसा ही होना चाहिए। नर्सरी से लेकर टैंथ तक उसका सिलेबस एक जैसा होना चाहिए जिससे उन बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा नहीं हो। हीन भावना पैदा होती है तो कई छात्र आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप लोगों ने बजट में कहा था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में हम लोग, उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करेंगे परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं कि वे आज तक क्रमोन्नत नहीं हुईं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर में करीब 68 विद्यालय प्राथमिक हैं जिनकी छात्र संख्या 40 से भी अधिक है। क्रमश: ग्राम रमासपुर, बल्लभगढ द्वितीय, माईदपुर, झालाटाला, नयागांव, दयापुर, खोरा, नहार की नेवाड़ा, गोविन्दपुरा, प्रेमनगर, नगलागोठरा, मोकरोली, दौलतपुरा, नयागांव माफी, नगला रहीमगढ़, नगला गढ़ीसाद आदि ऐसे प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करके गरीब जनता को, आम बच्चों को पढ़ने हेतु आप लोग लाभान्वित करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यही हाल महाविद्यालयों का है। मेरे यहां दो उपखण्ड है वैर और भुसावर, वहां पर एक भी महाविद्यालय नहीं है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनसे मैंने कई बार निवेदन भी किया है और इस सदन में हमेशा मैंने मांग उठाई है कि मेरे

(श्री भजन लाल जाटव)

विधान सभा क्षेत्र में या तो कालेज के लिए भरतपुर जाना पड़ता है या जयपुर आना पड़ता है। निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि आज महाविद्यालय की घोषणा माननीय मंत्री महोदया करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि भरतपुर संभाग में जब पदोन्नति का सिलसिला चालू था, सैटअप का हुआ उसमें पदस्थापन के लिए 900 शिक्षकों को भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर की वरिष्ठता सूची में अपग्रेडेशन की गडबडियां मिली क्योंकि उसमें वरीयता सूची में 2 से 15 शिक्षक के नाम गायब मिले। जिससे साफ होता है, विभाग की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगता है। भरतपुर संभाग में जो पात्र शिक्षक थे वे पदोन्नति से वंचित रह गए। जबकि रिक्त पद 1452 जारी किए गए थे। वरीयता सूची 1136 शिक्षकों की जारी हुई परन्तु पदोन्नति 921 की हुई, उनमें 215 पद गायब मिले। जो पदों की संख्या है, वह इस प्रकार है:- अंग्रेजी में 80 पद वरीयता सूची में हुए। उनकी डीपीसी 75 रही और अंतर आया 5 गणित में 64 और डीपीसी 49, अंतर रहा 15 का। एसएसटी में 133 और डीपीसी 116, अंतर 17 का। सामान्य में 58 और डीपीसी 50, अंतर 8 का। हिन्दी में 371 और डीपीसी हुई 333, अंतर आया 38। विज्ञान में 186, डीपीसी हुई 103, अंतर आया 83। ऐसे ही संस्कृत में 340 और 151, अंतर आया 49। ऐसे करके 215 पद रिक्त रह गए। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन पदों को शीघ्र भर्ती करने की कोशिश करें। कई बार आपको शिकायतें मिली पर आपने उस पर ध्यान देने की कोशिश नहीं की।

मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां कई स्कूलों में, जो शहरी स्कूल हैं जहां पर छात्र संख्या बहुत होती है। फिजिक्स केमेस्ट्री, मैथ्स के बच्चों के लिए वहां पर सब्जैक्ट बंद कर दिए गए हैं, इसलिए निवेदन करता हूं कि पुन: वहां पर बच्चों को फिजिक्स केमेस्ट्री, मैथ्स का सब्जैक्ट दिया जाए। वहां पर पूरी तरह व्याख्याता लगाए जाएं। वहां पर प्रेक्टिकल की व्यवस्था नहीं है। इस तरह से वे स्कूल बंद कर दिए गए। प्रयोगशाला नहीं थी। मैं कहना चाहूंगा कि जो गरीब बच्चे हैं, जो प्राइवेट स्कूल में शिक्षा नहीं ले पाते, उन गरीब बच्चों हेतु आप पुन: वहां पर संचालित करें। प्रयोगशाला के

(श्री भजन लाल जाटव)

लिए रमसा के द्वारा फर्नीचर के लिए और प्रेक्टिकल के लिए वहां पर राशि स्वीकृत होती है परन्तु स्कूलों में जब हम लोग देखते हैं तो उस राशि में कहीं न कहीं गड़बड़ी होती है और वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है और उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। प्रेक्टिकल का पूरा सामान है वह बच्चों को नहीं मिल पाता है। ना ही फर्नीचर उनको मिल पाता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसकी उच्चस्तरीय जांच कराकर आप लोग देंखे कि कहां-कहां उसमें कमियां रह गईं।

मैं कहना चाहूंगा कि एससी, एसटी छात्र हैं, उनकी छात्रवृति समय पर नहीं मिल रही है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शीघ्र ही आप लोग उनकी छात्रवृतियां दिलाने का काम करें।

जो प्रतिबंधित जिले हैं, प्रतिबंधित जिलों में ज्यादातर हमारे भरतपुर संभाग के शिक्षक हैं। भरतपुर संभाग के शिक्षक प्रतिबंधित जिलों में पड़े हैं, जिन्हें 20-20 साल, 25-25 साल हो गए हैं। उनके माता-पिता वृद्ध हैं। बीमारियां भी हैं, किसी की किडनी की खराब है, किसी को और परेशानी है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि 15 साल, 20-25 साल जिनके हो गए उनको किस तरह की सज़ा दी जा रही है। इसलिए जो प्रतिबंधित जिले हैं, उनको उन प्रतिबंधित जिलों से हटाकर उनका स्थानान्तरण किया जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। जो प्राइवेट स्कूल हैं, उन पर अंकुश लगाना चाहिए क्योंकि उनमें मनमानी फीस ली जाती है। हम सरकार के द्वारा रियायती दर पर जमीन लेते हैं, बहुत सारी सुविधाएं लेते हैं इसलिए उन प्राइवेट स्कूलों को बाध्य करके, गरीब बच्चों को वहां पर मुफ्त पढ़ाना चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्या शकुन्तला जी रावत। आप तो गागर में सागर भरने में माहिर हैं। कम शब्दों में अधिक बात कहने का प्रयास करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): साहब, आप ऐसे कहकर थोड़ा सा समय देते हैं। आज की मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति, सभापति महोदय, नारा दिया गया था ''सबका साथ सबका विकास''। हम सोच रहे थे

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

कि शायद यह नारा सच होगा। लेकिन तीन वर्ष बीत जाने के बाद, हम भी नये-नये विधायक बने। जैसे कई कह रहे हैं कि बोलने से क्या फायदा है, मैंने कहा फल मिले या नहीं मिले लेकिन पौधा तो लगाना ही चाहिए। जनता पौधा लगाना थोड़े ही छोड़ेगी। तो मांगे पूरी हो या नहीं हो लेकिन हम हमारी मांग तो रख सकते हैं।

श्री सभापति: पौधा लगाओ तो फल अवश्य मिलेगा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, सबका साथ सबका विकास नारा दिया लेकिन अब सार्थक होता यह दिखाई दे रहा है कि सब जनता का साथ, तो साथ किसी के नहीं विकास, यह नारा शायद ऐसा सार्थक हो रहा है। शिक्षा के बिना इंसान का जीवन अधूरा रहता है। बड़ी-बड़ी घोषणाएँ, नये-नये नवाचार कर दिए गए हैं लेकिन उन घोषणाओं का जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वह तीन वर्षो से, हम तो बार-बार उस चीज को विधान सभा के अंदर उठाते हैं लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है।

सभापति महोदय, हमारी उच्च शिक्षा मंत्री महिला हैं और राजस्थान की मुख्य मंत्री भी महिला हैं, तो मैं उम्मीद करती हूं कि औरों की मांग पूरी करें या नहीं करें लेकिन जो महिला सदस्य है उनकी मांग आप जरूर पूरी कर दें। उम्मीद तो रख ही रहे हैं। ...(व्यवधान)... मदनजी को तो कुछ ज्यादा वह होती है।

बानसूर विधान सभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा है। वहां किसान वर्ग ज्यादा निवास करता है। महाविद्यालय खोलने की मांग बार-बार उठाई जाती है लेकिन संसाधन नहीं होने का कारण बताकर उसको छोड़ दिया जाता है।

सभापति महोदय, बानसूर देवनारायण योजना के तहत भी आता है तो मैंने जिक्र भी किया कि अगर आप उसमें कॉलेज की घोषणा करें क्योंकि बानसूर के कॉलेज की मांग, बानसूर के युवा की मांग है, जनता की मांग है, उस युवा की मांग आप पूरी करें तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी।

प्रदेश में द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, वरिष्ठ अध्यापकों के साथ-साथ छठे वेतन आयोग की मांगों को ले करके कर्मचारीगण आक्रोशित भी हैं।

(21.00 बजे)

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

सभापति महोदय, मैं अपनी मांग रख रही हूं। मेरे बानसूर विधान सभा क्षेत्र में, चाहे पी.एस. स्कूल हों, यू.पी.एस. स्कूल हों, माध्यमिक हों, उच्च माध्यमिक हों, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, रमसा, सर्वशिक्षा अभियान में अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ है चाहे कमरे बनाना, चारदीवारी बनाना, इस तरीके का काम तीन वर्ष में नहीं हुआ तो आगे अभी इस चौथे वर्ष में उम्मीद करती हूं कि होंगे।

जिक्र किया गया है कि सभी ग्राम पंचायतों में सीनियर सैकण्डरी विद्यालय होंगे। सिर्फ नई पंचायतों में नहीं हुए हैं। अभी भी मेरे यहां पर देवसन, शाहपुर खेड़ा, सबलपुरा, बवेरा, बेराम का बास, रसनाली, ऊंचपुर, माझरा डाकोड़ा, नांगल हेड़ी, नाथूसरलोज, इसके साथ कई पंचायतें, जो सीनियर सैकण्डरी विद्यालय से वंचित रह रही हैं, आपके माध्यम से मैं यह अनुरोध करना चाहूंगी कि जिस विद्यालय में सौ, दो सौ, ढाई सौ, तीन सौ, चार सौ तक की संख्या छात्राओं की है, तो उन विद्यालयों को भी क्रमोन्नत करें क्योंकि बच्चियों को गांव से बाहर भेजने में परेशानी होती है। सरकार की कोई भी योजना के तहत, बहुत सारी योजनाएं हैं, जिनका बजट के अन्दर जिक्र किया गया है, टाडा, माडा, मेवात और अन्य योजनाओं का, तो किसी न किसी योजना के तहत आवासीय विद्यालय, अगर वहां क्रमोन्नत नहीं कर सकते हैं तो आवासीय विद्यालय दे करके उन बच्चियों को शिक्षित करने का काम करें।

एक 'टेट' तो हटा दिया, सभापति महोदय, लेकिन दूसरा नया 'रीट' लगा दिया। अब फर्स्ट, सैकण्ड, थर्ड ग्रेड की भर्तियां भी कर दीं, सारे काम कर दिये। सलेक्शन भी हो गया। लेकिन जब एन-टाइम आया उनका ज्वाइनिंग का, तो आरक्षण का बहाना लगा करके, कोर्ट का बहाना लगा करके उन अभ्यर्थियों को वंचित रखा जा रहा है। ऐसा युवाओं के साथ धोखा नहीं करना चाहिये। क्योंकि सरकार ने जब वादे किये हैं तो उनको पूरा करने की भी क्षमता होनी चाहिये।

साथ ही, मेरा अनुरोध है कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, एक अभियान चल रहा है युवा मतदाता महोत्सव, अच्छी बात है, चलना चाहिये, युवा को जोड़ना चाहिये। लेकिन जिन स्कूलों में बोर्ड की परीक्षा हो

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

रही है, वहां के प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। जबकि बोर्ड के समय पर, जब तक बोर्ड की परीक्षा सम्पन्न नहीं होती, नहीं जाना चाहिये। कोई नियम अगर ऐसा तब्दील हुआ है तो जानकारी में नहीं है। बाद में बोर्ड की परीक्षा खतम हो जाती तो जुड़वा लेते। लेकिन कोई नहीं जायेगा तो उसको नोटिस दिया जाता है। उसमें वैसे टीचर लगा करके बोर्ड को छोड़ दिया जाता है, तो इस तरीके की जो हरकतें हैं, यह क्या हैं। चाहे विद्यार्थी मित्र हों, कम्प्यूटर शिक्षक हों तो ये सारे जो बेरोजगार हो गये, इनको कब तक रोजगार देने की मंशा रखेंगे, मंत्री महोदय।

सभापति महोदय, जिन विद्यालयों में सर्वे तो बार-बार करा लिया जाता है कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, फर्नीचर नहीं है। हम लोग भी अपने कोटे से देते हैं, लेकिन इतने सारे विद्यालय वंचित हैं, जिनकी हम पूर्ति नहीं कर सकते। बिजली कनेक्शन अगर आप दिलाने का इसमें प्रावधान रखें तो पंखे, कूलर तो ग्रामीण सहयोग से, चाहे एम.एल.ए. फण्ड से, कहीं से भी करके हम लगवा सकते हैं। लेकिन इस सीजन में सभी विद्यालयों में बिजली कनेक्शन का प्रावधान होना चाहिये।

प्रदेश में बालिका महाविद्यालय हैं। उनमें अधिकतर, हम दो-चार विद्यालयों में गये थे, और भी जगह गये थे, तो भूगोल और गृह विज्ञान की बालिकाओं की मांग रहती है, तो वह भी मंत्री महोदय सर्वे करवाकर करें, तो ज्यादा सही रहेगा।

जो प्रतिबंधित जिले हैं, उनको भी किसी न किसी नियम के तहत ले करके, जो 25 से 30 वर्षों तक के वहां अध्यापक रह रहे हैं तो उनको भी अपने यहां लाने का कोई प्रावधान करें।

आज के युग में दिखा रहे हैं कि शिक्षा का इतना बड़ा नाम हो रहा है, लेकिन आज ये जो प्रोफेसर्स और जो बड़े उच्च शिक्षा में माने जाते हैं डाक्टर्स, जो युवा पीढ़ी को, उस उम्र की पीढ़ी को शिक्षा देते हैं सभापति महोदय, जहां उनकी जिन्दगी बनाई जाती है, वह खुद ही लड़ रहे हैं। यह कैसा अजूबा दिखाई दे रहा है, ऐसा कभी हुआ हो, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन इसमें भी हमारी मंत्री महोदय स्ट्रिक्टली उन पर कार्यवाही करें जिससे छात्र-छात्राओं पर गलत प्रभाव नहीं पड़े। कम से कम इन गुरुओं को ही आप

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

समझाओ, जिससे वे ऐसी हरकत आगे से नहीं करें। उनको सबक मिले कि किसी तरीके से भी ऐसे कॉलेज में इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिये।

निजीकरण, पी.पी.पी. मॉडल पर देना, वैसे तो कहा जाता है, अभी माननीय सदस्य ने भी बहुत कहा कि विद्या का मंदिर है। अच्छी बात है कि विद्या का मंदिर है, क्योंकि कहावत भी है कि जिस जगह इन्सान, अपने मन की शांति के लिये 36 कौम के व्यक्ति पूजा-पाठ करते हैं, उसे मंदिर कहते हैं और एक कतार में बैठ कर 36 कौम के बालक जहां ज्ञान ग्रहण करते हैं, उसे विद्यालय कहते हैं। उसी विद्यालय को आप पी.पी.पी. मॉडल पर देने की बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, एक तरफ क्या कर रहे हैं कि 25 प्रतिशत बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जायेगा। अभी तक कौन-कौनसे जिले में, कितने बच्चों को 25 प्रतिशत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिया गया, गरीब या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को, तो वह भी बता दें। आप जांच कराएं इन चीजों की कि कितने एडमिशन हुए या नहीं हुए? एक तरफ तो इधर कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्कूलों का निजीकरण कर रहे हैं। फिर क्या होगा, जो पी.एस. स्कूल थे वे भी बंद कर दिये गये। निजीकरण भी कर देंगे और फिर कहा जा रहा है कि हम सरकारी विद्यालयों को बढ़ावा देंगे। तो यह बढ़ावा देना है या उनके स्तर को नीचे गिराना है? सभापति महोदय, यह समझ में नहीं आ रहा है। जैसे शिक्षा की बाध्यता कर दी थी पंचायती राज में तो उसने भी एक भ्रष्टाचार को जन्म दिया। चाहे बी.ई.ओ. हो, डी.ई.ओ. हो, ऊपर आगे तक जो भी केस लड़े उसमें सारा भ्रष्टाचार हुआ है तो इस तरीके के काम करके, किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं।

सभापति महोदय, महिला शिक्षा तो आजादी से पहले भी चल रही थी। सावित्री बाई फुले ने आजादी से पहले ही महिला शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया था।

सभापति महोदय, अब यह संस्कृति और कला, ये ऐसी चीजें हैं जहां पर पुराने शिलालेख हैं। बानसूर विधान सभा क्षेत्र में भी हैं। जैसे बावड़ियां, छतरियां हैं, जो कि भारतीय संस्कृति और राजस्थान की कला और संस्कृति को दर्शाते हैं। ताल वृक्ष है, बानसूर का किला है, शीतलनाथ गर्वाजी, घूणी वाले हनुमानजी का मन्दिर, सुंदरी माता, ऐसी जो जगह हैं, पर्यटक स्थल,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

धरोहर हैं और इन पर लेख भी लिख रहे हैं। कई प्रोफेसर्स, डाक्टर्स हैं तो ऐसे लोगों को भी प्रोत्साहित करने के लिये पुरस्कृत करना चाहिये।

एक लाइन और है सभापति महोदय, आमेर के विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा बांदीकुई, दौसा की स्थिति पर चर्चा की गई थी पिछली बार भी, लेकिन आज दिन तक कहीं विकास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कितना हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहे, सभापति महोदय, अगर इनका भी उल्लेख कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

अभी बड़ी जोर-शोर से कर रहे थे कि हम महाराणा प्रताप को शामिल कर रहे हैं, वे महान थे। यह कौन कह रहा है कि वे महान नहीं थे। वे कब नहीं थे। कौनसी किताब में नहीं थे। जो पुराने सदस्य यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि 'अरे घास री रोटी ही, जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो' तो यह महाराणा प्रताप की कविता की लाइन नहीं है तो यह किसकी लाइन है? सभापति महोदय, ये तो पहले से ही महान हैं। किसको महान बताना चाहते हैं? सिर्फ आंकड़ों में महान बता करके, वह महान था, वह नहीं था, शिक्षा का तो भट्टा गोल करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये।

सभापति महोदय, आपके जरिये, एक मेरा केस है। मंत्रीजी के संज्ञान में मैं ला चुकी हूं। शायद सारे अधिकारीगण भी वहां बैठे थे। सभापति महोदय, क्या कहेंगे, मंत्रीजी ने आदेश कर दिया। महिला टीचर का कैंसर से पीड़ित पति, उसके ऐसा कैंसर कि ईश्वर किसी को नहीं करे। धीरे-धीरे मृत होता शरीर, नीचे से। अब वह मरने की स्थिति पर जा रहा है, तो वह महिला टीचर कैसे बाहर जायेगी। मैं मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगी कि इन्होंने तुरन्त आर्डर कर दिया। उसकी पोस्टिंग वहां करके, उसको उस दिन से वे तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। आर्डर को लेकर बी.ई.ओ. के पास गये तो कहते हैं आप कौन होते हैं। यहां सरकार हमारी है। हमारा आर्डर चलेगा यहां पर। किसी का नहीं चलेगा। वापस मैं जाती हूं, फिर फोन करवाती हूं। फिर फोन कर देते हैं लेकिन फिर भी नहीं होता है। अब उसके हस्बेंड की डेथ भी हो चुकी है। मेरा आपके जरिये अनुरोध है कि जितने भी ऐसे केस हैं, जिनके लाइलाज बीमारी है, जो गम्भीर केस हैं, उनको तो किसी भी तरीके से, मंत्री

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

महोदय, सरकार और जो भी अधिकारीगण हैं, उनके अन्दर क्या दिल नहीं है, क्या पत्थर हैं, उनके कलेजा नहीं है, उनके बहन-बेटी नहीं है क्या। उनको इतनी सी भी इंसानियत नहीं है कि वे जरा सी भी मानवता रखें। किसी पर दया और धर्म उनका खतम हो जाता है, बड़ी शर्म की बात है, माननीय सभापति महोदय, ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए और उस गरीब महिला को उनकी तनख्वाह मिलनी चाहिए। ऐसी जो महिलाएं हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है तो ये आम जो कर्मचारी हैं, उनके साथ क्या होता होगा, माननीय सभापति महोदय? मंत्री महोदय, आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट्ली इनको निर्देशित करें और ऐसे लोगों का, सभी का काम करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री मानिक चन्द जी सुराना। सभी सदस्य गंभीरता से सुने।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त कर दिये हैं। कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य का भाषण मैंने सुना। बानसूर से आने वाली हमारी माननीय सदस्या का भाषण अभी मैंने सुना।

माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से 2013 में जो स्थिति थी, उससे हम आगे गये हैं, बहुत आगे गये हैं। 2013 यानी, इस सरकार के आने के साल से पहले। 2013 में हमारा शिक्षा का बजट 15 हजार करोड़ था, मैं ऊपर 307, 207 नहीं बोल रहा हूं। 2014-15 में जब माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने बागडोर संभाली तो यह बजट 4 हजार करोड़ ऊपर चला गया, 15 से 19,000 हो गया। 2015-16 में यह वास्तविक खर्च दो हजार करोड़ ज्यादा हो गया। अनुमान तो तीन हजार करोड़ का था लेकिन दो हजार करोड़ ज्यादा हो गया और 2016-17 में यह चार हजार करोड़ ज्यादा हो गया जो साल अब खतम होने को है। और अगले साल के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने करीब-करीब 27 हजार करोड़ का बजट रखा है। निश्चित रूप से जब हम 15 से 26 हजार करोड़ पर आ गये, 27 हजार करोड़ पर आ गये, 12 हजार करोड़ रुपये में निश्चित रूप से माननीय सभापति महोदय, उपलब्धियां तो होनी ही हैं और उपलब्धियां हुई भी हैं। माननीय सदस्यों ने

(श्री मानिक चन्द सुराना)

जिक्र किया पाँच हजार स्कूलों का, कि जो उच्च माध्यमिक में कन्वर्ट हुए। सदन का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जब 2008 में थीं तो पहली बार सारे राजस्थान की पंचायतों में से आधी पंचायतों से ज्यादा आठवीं की स्कूलों को माध्यमिक किया गया यानी, उच्च प्राथमिक को माध्यमिक किया गया। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार का निश्चित रूप से श्रेय माननीय मुख्य मंत्री महोदया को जाएगा और उसमें कोई दो-राय नहीं हो सकती कि उससे पहले माध्यमिक शिक्षा तक भी बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, उच्च माध्यमिक तक भी नहीं पढ़ पाते थे।

माननीय सभापति महोदय, उपलब्धियां हुई हैं, नामांकन बढ़ा है। सदन के मेरे कुछ मित्र कहें भी कि नामांकन नहीं बढ़ा या कुछ कम हो गया पर नामांकन लाखों में बढ़ा है। 17 लाख का दावा है, 17 नहीं तो साढ़े सोलह बढ़ा होगा, 16 बढ़ा होगा। 16 लाख नामांकन बढ़ना भी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। काउंसलिंग की प्रक्रिया भी मैं समझता हूं कि जिनका कोई प्रमोशन हुआ है, काउंसलिंग से उनको ट्रांसफर करना, यह भी नवाचार है। माननीय सभापति महोदय, मैं इन सब नवाचारों के लिए माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी को तो बधाई देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने पिछले बजट में तकनीकी विश्वविद्यालय की घोषणा की थी और वह घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बीकानेर के जितने भी भाजपा के नेता थे, कार्यकर्ता थे और मेरे जैसा निर्दलीय विधायक था जो पहले भाजपा में था, उन सबसे भी सलाह-मशविरा किया गया और सबने एक मत से कहा कि बीकानेर के जन-मानस में तकनीकी विश्वविद्यालय, जो कांग्रेस के राज में खाली स्थापित हुआ था और हमारे राज में बजट पास करने के बाद भी जिसको बंद कर दिया गया था 2015-16 में और फिर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2016 के बजट में घोषणा कर दी थी।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उच्च शिक्षा मंत्रीजी, यह सदन अभी चल रहा है। सदन में शायद 30 मार्च के बाद 10 दिन का गैप है। कोटा

(श्री मानिक चन्द सुराना)

ओपन यूनिवर्सिटी का विधेयक, विधेयक नहीं बिल है। वह विधेयक बन चुका है। अधिनियम बन चुका है। आज माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी है तो वित्त विभाग भी सुने कान खोलकर और इस सदन के पूरे माननीय मंत्रीमंडल के सदस्य सुनें, माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा। जिसके लिए हम कहते हैं यशस्वी मुख्य मंत्री, निश्चित रूप से उच्च शिक्षा मंत्रीजी से मैं कहूंगा कि इसी सदन में, इस सदन की समाप्ति से पूर्व आप विधेयक लेकर आएं क्योंकि तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए अभी कोई बिल्डिंग बनानी जरूरी नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेजेज के पास बहुत साधन-संसाधन हैं। उनकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप तकनीकी विश्वविद्यालय को खोलने की नींव इसी सदन में विधेयक को अधिनियम में परिवर्तित करके कराएं।

माननीय सभापति महोदय, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थिति आज जो है, कुछ लोगों ने कहा कि साहब, क्या जरूरत है तकनीकी विश्वविद्यालय की? खैर, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उसकी जरूरत न बताते हुए, किसी ने कहा कि मेरे यहां पर खोल दो। कोई बात नहीं, कहीं खोल लो। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जो गिरता हुआ नामांकन है, सरकार को उसको भी गंभीरता से देखना चाहिए। हम जब कौशल विकास का विश्वविद्यालय बना चुके तो कौशल विकास का विश्वविद्यालय और तकनीकी विश्वविद्यालय, ये दोनों जुड़वा भाई की तरह हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो नामांकन हमारा कम हो रहा है, वह चिंता का विषय है। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि इंजीनियर्स को विभिन्न विभागों में जो उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर चुके उनको यदि रोजगार नहीं है तो फिर सिर्फ कौशल विकास वालों को रोजगार मिल जाएगा, ऐसी खुशफहमी भी न रहे। एक लाख 85 हजार लोगों को हम पूरी राज की ताकत लगाकर प्रशिक्षित कर पाए हैं। यह आंकड़ा श्रम मंत्रीजी ने दिया है और पहले, रिसर्जेंट राजस्थान में जो आंकड़ा सरकार ने छापा कि हमने कितने लोगों को प्रशिक्षित किया? रिसर्जेंट राजस्थान तक 92 हजार कुछ, दो-चार सौ, पाँच सौ ऊपर होंगे, 92 हजार लोगों को प्रशिक्षित किया गया और अभी लेटेस्ट आंकड़ा यह है कि एक लाख 85 हजार। मैं यह मान लेता हूं कि एक लाख को नौकरी, रोजगार, रोजगार

(श्री मानिक चन्द सुराना)

के अवसर मिल गये होंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज पर सरकार ध्यान दे। बीकानेर में एक तो बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज है और एक सी.ई.टी. कॉलेज फोर इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी, यह सब स्व-वित्त पोषित संस्थाएं हैं पर स्व-वित्त पोषित संस्थाएं होने से जो विद्यार्थियों पर भार पड़ रहा है, अभी तो मैं उसको बर्दाश्त करने को तैयार हूं पर यदि साल-दो साल में उनको करोड़, दो करोड़ रुपये की आवश्यकता हो और उनके शैक्षणिक स्तर को ऊँचा करने के लिए तो निश्चित रूप से जो स्व-वित्त पोषित संस्थाएं हैं, उनकी ओर भी सरकार को जो आपकी खुद की हैं, कॉलेज फोर इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी तो उनकी तरफ भी, जब माननीय घनश्यामजी शिक्षा मंत्री थे तो मुझे याद है। मैं उस वक्त सदन का सदस्य नहीं था लेकिन मैं वित्त आयोग का अध्यक्ष था और उन्होंने दो करोड़ रुपये की एड उस वक्त उस सी.ई.टी. को और बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेजों को प्रदान की थी।

मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि इंजीनियरिंग कॉलेज, कौशल महाविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय, ये सब रोजगार उत्पन्न करने के, रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के, हुनर उपलब्ध करवाने के, उच्च शिक्षा ज्ञान उपलब्ध करवाने के, विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में वह साधन हैं इसलिए इनकी तरफ भी पूरा तवज्जोह दिया जाए। यदि आप विधेयक नहीं लाती हैं तो हमारे लिये बड़ी तकलीफ की बात होगी, क्योंकि किनका विश्वास किया जाये? माननीय मुख्य मंत्रीजी की बात का तो विश्वास जनता ने कर लिया है। आपको देखना है कि करोड़-दो करोड़, तीन करोड़ रुपये उसकी स्थापना में लगते हैं तो वह कितना भारी है। हमारे बजट में 8,838 करोड़ का राजस्व घाटा 2016-17 में बर्दाश्त कर रह हैं तो चार-पाँच करोड़ और अब खर्च, वित्तीय प्रावधान नहीं है, इसकी तो बात न करिये माननीय मंत्रीजी। कर्ज लेने के अलावा हमारे पास विकल्प नहीं है। राजस्थान को आगे ले जाने के लिये कर्ज लेना जरूरी है और मैं मान गया हूं कि राजस्व प्राप्तियां तो 45 प्रतिशत ही हमारे राजस्व खर्च को मीट करती है तो वित्तीय संसाधनों की तो बात न कहिये। यह तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर में खुले।

दूसरी घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की थी एलीवेटेड रोड की। उसकी डी.पी.आर. बन गयी है, उसका काम भी जल्द होगा। हमारे यहां के

(श्री मानिक चन्द सुराना)

बीकानेर पश्चिम के विधायक बैठे हैं। मंत्रीजी ने कल ही घोषणा की है कि हम इनसे बात करके उस एलीवेटेड रोड को शुरू करेंगे।

सभापतिजी, संस्कृत शिक्षा आपके पास है, उच्च शिक्षा दूसरे मंत्रीजी के पास है। मुझे कहना नहीं चाहिये, इसमें राजस्थान भर में शिक्षकों की कमी है। इस कमी को आप बिलकुल आंक लीजिये और आंककर संस्कृत शिक्षा जो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल आधार है और सारे बड़े-बड़े ग्रन्थ संस्कृत साहित्य में है तो संस्कृत शिक्षा में जहां आपने विद्यालय खोल दिये हैं। मैंने आपको पत्र भी लिखा था। 5 सी.एच.डी. में वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय और 14 में से 3 आदमी अध्यापक, बामणवाली में दसवीं का विद्यालय संस्कृत का और मात्र दो अध्यापक। मैं अर्ज करना चाहता हूं आप बड़े पैमाने पर संस्कृत शिक्षकों की भर्ती करिये और संस्कृत शिक्षा में यह हमको शिकायत न होने दीजिये कि अध्यापक नहीं है, अध्यापक नहीं है। राजस्थान भर का आप बहुत कल्याण करेंगी और भारतीय संस्कृति की सही समझ भी संस्कृत शिक्षा के माध्यम से आप प्रदेश को देने का काम करेंगी।

सभापतिजी, कला और संस्कृति की बात करूं। बीकानेर में रवीन्द्र मंच बन गया। नाट्य होते रहें और नाट्य के माध्यम से नाट्य कला को आगे बढ़ाया जा सके, इसलिये करोड़-डेढ़ करोड़ रुपये सरकार ने खर्च कर दिये और उस रवीन्द्र मंच का लोकार्पण मुख्य मंत्रीजी ने कर दिया। उसकी बुकिंग के लिये कोई साधन नहीं है। कोई नाटक वहां खेला नहीं जा सकता, क्योंकि जो लाइटिंग करनी चाहिये थियेटर्स में, उस लाइटिंग का इन्तजाम नहीं है। चार-पाँच लाख रुपये लगेंगे ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: कृपया गंभीरता से सुनें। बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य आ रहा है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आप उसकी लाइटिंग की व्यवस्था कराइये। आखिर में आपने डेढ़ करोड़ रुपये खर्च कर दिये हैं। उसकी बुकिंग कराइये, आखिर वह नाट्य रवीन्द्र मंच है, नाटक वहीं खेले जायेंगे और मेरे बीकानेर शहर में, जहां से मैं भी विधायक हूं, वह हमारा जिला मुख्यालय है तो उसमें नाट्य के बड़े-बड़े कलाकार हैं और भास्कर के सम्पादक मधु आचार्य ने अनेक नाट्य ग्रन्थ लिखे हैं और खुद भी बहुत बड़े नाट्य के कलाकार हैं। पचासों लोग और हैं जोकि नाट्य में रूचि रखते हैं। मैं

(श्री मानिक चन्द सुराना)

चाहूंगा कि उच्च शिक्षा मंत्रीजी, रवीन्द्र मंच को शुरू करने के लिये दो महीने, ढाई महीने के अंदर सक्षम कदम उठायें और बीकानेर में रवीन्द्र मंच तो बन गया, लेकिन रवीन्द्र मंच के बनने के बाद जो कला में उत्थान आना चाहिये, उसका अनुभव कराने की कृपा करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, थोड़ा संक्षिप्त करें। रात्रि ढल रही है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मेरा नम्र निवेदन है कि 9.25 का समय हो रहा है, आज तो 11.30 तो बजने ही हैं तो पाँच-दस मिनट मुझे भी बर्दाश्त कर लें सभापतिजी।

श्री सभापति: काफी बर्दाश्त कर लिया।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उच्च शिक्षा मंत्रीजी, कॉलेज व्याख्याताओं का विज्ञापन हो गया सन् 2014 में, व्याख्याताओं की भर्ती होनी है। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि यू.जी.सी. ने व्याख्याताओं के मानदण्ड रखे हैं एम.ए. में 55 परसेंट और बी.ए. में भी कुछ योग्यता है। जो योग्यता यू.जी.सी. ने रखी, उसी योग्यता के सारे लोगों ने साक्षात्कार दिया है। अब आपने सरकारी विज्ञापन में यह लिख दिया कि दसवीं में भी 55 परसेंट, बारहवीं में 55 परसेंट। क्या लेना-देना दसवीं और बारहवीं का? लड़के ने एम.ए. कर लिया, 55 परसेंट मार्क्स आ गये। यू.जी.सी. के सारे मानक वह पूरे कर रहे हैं। अब राज्य सरकार ने विज्ञापन में डाल दिया कि दसवीं में भी 55 परसेंट और बारहवीं में भी 55 परसेंट, इस विज्ञापन को रिवाइज कराइये माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, जो यू.जी.सी. ने मानक तय किये हैं, उन मानकों के अनुसार हमारे राजस्थान के हजारों-हजारों लोगों को उसमें कालेज व्याख्याता बनने का अवसर मिल सके।

सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करता हूं। विश्वविद्यालय के अधिकारी को यू.जी.सी. ने जो छठा वेतनमान दिया, वह प्रोफेसर को मिल रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर को मिल रहा है, शारीरिक शिक्षक को मिल रहा है, पुस्तकालय वालों को मिल रहा है तो दूसरे अधिकारियों को, जिनके प्रमोशन के लिये कोई एवेन्यू नहीं है, जैसे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, इनके लिये कोई दूसरा पद नहीं है, जो अधिकारी वर्ग हैं यूनिवर्सिटी में, उन अधिकारी वर्ग को छठे

(श्री मानिक चन्द सुराना)

वेतनमान से राज्य सरकार ने क्यों महरूम किया? यह दलील कि धन नहीं है, वित्त नहीं है। आखिर कोई तो नीति-सिद्धान्त होगा। विश्वविद्यालय में हम दो टुकड़े क्यों करें, एक डिकोटोमी क्यों पैदा करें? एक वर्ग को छठा वेतनमान और दूसरे वर्ग को छठा वेतनमान नहीं। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

सभापतिजी, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं। आपने यह नियम बना रखा है कि जहां बारहवीं की स्कूल प्राइवेट सैक्टर में है, चाहे आपने बना रखा है, चाहे मुख्य मंत्रीजी ने बना रखा है, चाहे पूरे प्रशासन ने बना रखा है, वहां बारहवीं नहीं खुलेगी, वहां दसवीं ही रहेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी अनेक जगहों पर बारहवीं की क्लास खुलनी बाकी है। आपकी जो यह नीति-सिद्धान्त है कि यदि कहीं प्राइवेट की बारहवीं खुल गयी तो हजारों प्राइवेट स्कूलें राजस्थान के अनेक हिस्सों में खुल जायेगी और वह ग्रामीण जिसको सस्ती शिक्षा का अधिकार है, वह बिलकुल महरूम हो जाएगा। मैं निवेदन करता हूं कि चूंकि हमारा यह निर्णय दिखने में तो ठीक है कि हम सभी को उच्च माध्यमिक तक की शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं लेकिन यदि आप खोल देते हैं। तो मैं यह कह सकता हूं कि 70 प्रतिशत प्राइवेट स्कूल, जो उच्च माध्यमिक के हैं, वे बंद हो जाएंगे और जो सरकारी स्कूलें हैं, उसी को छात्र चूज करेंगे।

मेरे यहां कर्पूरीसर एक बहुत बड़ा गांव है, एक काकड़वाला बहुत बड़ा गांव है, और दोनों इसलिये सफर कर रहे हैं, क्योंकि वहां प्राइवेट स्कूल है और प्राइवेट स्कूल की फीस हमारे इस निर्णय के कारण मनमर्जी से बढ़ायी जा रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान की उन ग्राम पंचायतों के हित में, जहां अब तक बारहवीं नहीं है, आप कृपया इस निर्णय को, इस डाइरेक्शन को रिवाइज करने की कृपा करें ताकि राजकीय उच्च माध्यमिक खुलने से अपने आप 70 परसेंट प्राइवेट स्कूलें कम हो जायेंगी, बंद हो जायेंगी। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): पांच मिनट और। पांच मिनट।

श्री सभापति: अब पांच मिनट बहुत भारी पड़ेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): पांच मिनट में बात खतम करूंगा। मेरे क्षेत्र की बातों का तो मैं शिक्षा मंत्रीजी को पत्र भेज दूंगा पर शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान मैं शिक्षाकर्मियों की ओर आकर्षित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले राजस्थान में 1987 में शिक्षाकर्मी बोर्ड बना और यह सूचना आपके ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह विषय दिन भर आ चुका है। थोड़ा समय ज्यादा हो गया है, तीन मंत्रियों को जवाब देना है इसलिए कृपया समाप्त करें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): कहने तो दीजिए। बात तो कहने दीजिए।

माननीय सभापति महोदय, 1987 में यह शिक्षाकर्मी बोर्ड बना और शिक्षाकर्मियों के नियम बन गये। राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड, जयपुर, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी विनियम, 1994, सभापतिजी, यह नियम बन गये। उसके बाद 30.06.2005 को आपके डाइरेक्टर, एजुकेशन ने सरकार के आदेश के अनुसार यह निर्णय कर दिया कि इनकी जो सैलेरी वो फ्रीज की जाती है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: धन्यवाद। प्लीज, प्लीज, समाप्त करें। प्लीज, समाप्त करें अब।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): शिक्षाकर्मी पर बात करके मैं खतम ही करूंगा।

श्री सभापति: यह विषय काफी बार आ चुका है। मंत्री जी को ध्यान में है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आप मुझे नीतिगत बात कह लेने दें। आखिर पांच मिनट में कोई, आप कृपा करें।

श्री सभापति: ऐसे करते-करते साढ़े नौ से ऊपर हो गये हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मुझे यह बात खतम करने दें। मैं शिक्षाकर्मी की बात के बाद ही खतम करूंगा।

मैं कहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रबोधक नियम बना दिये 2008 में। प्रबोधक नियम मेरे पास हैं और प्रबोधक नियम के साथ में कौन-कौन उस प्रबोधक नियम में आयेंगे और किस-किसको पदोन्नति दी जायेगी,

(श्री मानिक चन्द सुराना)
मैं संक्षेप में आपसे कहता हूं। राजीव गांधी पाठशाला, शिक्षाकर्मी बोर्ड, लोक जुम्बिश परियोजना, सर्वशिक्षा अभियान, जितनी तरह की भी जो शिक्षक के अलावा संस्थाएं हैं, जो शिक्षण का काम करती हैं, वो इस प्रबोधक नियम में आ गयीं। मैं अर्ज करता हूं आप प्रबोधक भर्ती तो करें। आप प्रबोधक भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? 37 हजार की भर्ती आपने की है, 78 हजार की भर्ती बाकी है। यह आपके सरकारी आंकड़ों के अनुसार 78 हजार की भर्ती है ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप प्रबोधक भर्ती करें और प्रबोधक भर्ती करके इस समस्या का समाधान करें।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

उच्च शिक्षा मंत्री, श्रीमती किरणजी माहेश्वरी अपने विभाग के सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा दिये गये वाद-विवाद और वक्तव्यों का सारगर्भित शब्दों में उत्तर देंगी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं उन सभी सम्माननीय सदस्यों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं जिन्होंने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने अमूल्य सुझाव यहां पर दिये और आज की शिक्षा ही भविष्य का निर्माण कर सकेगी, इस पर बहुत अच्छी, लम्बी चर्चा, लगभग आठ घंटे की चर्चा यहां पर माननीय सदस्यों ने की। मैं यही कहूंगी, इस पंक्ति के साथ अपनी बात को शुरू करना चाहूंगी कि, 'कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान।'

माननीय सभापति महोदय, विभाग की मांग संख्या 24 के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा से सम्बन्धित 85 कटौती प्रस्ताव मुझे प्राप्त हुए और संसदीय प्रणाली में माननीय सदस्यों के द्वारा जो प्रस्ताव दिये गये हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनका जो जवाब है, उत्तर है वो ये घर पहुंचेंगे तब तक इनको प्राप्त हो जायेगा। माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से आपने कहा कि वास्तव में और माननीय सभी सदस्य ...

श्री सभापति: आज के दिन ही घर जायेंगे या कल?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): आज ही जायेंगे। आप जैसा चाहते हैं कि एकदम शॉर्ट में बोला जाए, क्योंकि आपने पहले ही कहा कि बहुत ही संक्षिप्त में ...

श्री सभापति: सारगर्भित शब्दों में।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): सारगर्भित। तो वैसा ही हम कोशिश करेंगे कि बिलकुल छोटा सा अपना वक्तव्य यहां पर प्रस्तुत करें लेकिन निश्चित रूप से डिपार्टमेंट की जो आज की परिस्थितियां हैं, जो वर्तमान परिदृश्य है, वो मैं आपके सामने, आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूंगी।

क्योंकि हम लोग शुरू करते हैं कि शिक्षा के सन्दर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा जब यहां पर माननीय सदस्यों ने की तो उस सारी चर्चा के अन्दर इस बात को हम लोग सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो उस समय हमारे यहां पर केवल सात महाविद्यालय थे और यह यात्रा 70 साल की यात्रा होते-होते अब लगभग 3000 महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं, शिक्षा की संस्थाएं संचालित हो रही हैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में।

यहां राजस्थान में हमारे राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय हैं वो 14 हैं, उनमें से सामान्य शिक्षा के 12, तकनीकी शिक्षा का एक और संस्कृत शिक्षा का एक। निजी विश्वविद्यालय 44 हैं। इसी तरीके से जो हमारे राजकीय महाविद्यालय हैं, वो सामान्य शिक्षा में 207, तकनीकी शिक्षा में 50 और संस्कृत शिक्षा में 29, ऐसे कुल 286 हमारे राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं। गैर राजकीय महाविद्यालय जो हैं वो टोटल 2662 हैं, जिसमें से सामान्य शिक्षा के 2336, तकनीकी शिक्षा के 263 और संस्कृत शिक्षा के 27. माननीय सभापति जी, इनके अतिरिक्त कृषि, चिकित्सा, पुलिस एवं खेल विभाग के 10 विश्वविद्यालय और 7 डीम्ड विश्वविद्यालय भी संचालित हैं तथा राज्य के राष्ट्रीय स्तर के 6 संस्थान हमारे राज्य में हैं जिनमें केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आई.आई.टी., आई.आई.एम., एम.एन.आई.टी., ट्रिपल आईटी और एम्स। ये सारे ही हमारे यहां पर संचालित हो रहे हैं।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

आज मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने गत तीन वर्षों में उच्च शिक्षा के लिए 3,490 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जबकि इसकी तुलना में, क्योंकि अभी हमारे विपक्ष के बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपनी बात यहां पर कही और कहा कि शिक्षा में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि तीन साल में हमने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जो दिया, वो 3490 करोड़ दिया और इनके जो तीन साल थे, उसमें इन्होंने मात्र 1482 करोड़ रुपये ही दिये थे। तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ढ़ाई गुणा अधिक राशि का प्रावधान हमारे इस तीन साल के कार्यकाल में हम लोगों ने किया है, इसलिए सरकार शिक्षा के प्रति बहुत ही कमिटेड है। इस बात का आपको विश्वास हो जाना चाहिए।

माननीय सभापतिजी, हमारी श्रद्धेय मुख्य मंत्री महोदया के शिक्षा के प्रति असीम अनुराग को देखते हुए उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के लिए इस साल हमारा जो यह बजट है, उसमें 11.01 प्रतिशत की वृद्धि की है और यह हम सबके लिए बड़ा अच्छा संकेत है कि हम शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं।

मैं आपके माध्यम से हमारे साथियों से यह कहना चाहूंगी कि जो कांग्रेस की सरकार थी पिछले कार्यकाल में, उसमें उन्होंने जो घोषणाएं की थीं, उनको अगर हम कम्पेरेटिवली देखें तो फर्स्ट फोर ईयर्स तक, चार साल तक आपने मात्र तीन महाविद्यालय खोले और लास्ट छह महीने, जब चुनाव आने लगा और इन्हें लगा कि अब हमें जाना है क्षेत्र के अन्दर, लोगों को क्या जवाब देंगे तो उस समय इन्होंने लगभग 42 महाविद्यालयों की घोषणा कर दी। छह महीने में 42 महाविद्यालय और पूरे चार साल के अन्दर मात्र तीन महाविद्यालय, तो इसको कम्पैरिजन कर लें। हमने आने के बाद उच्च शिक्षा के अन्दर जो आपके 42 महाविद्यालय थे, उनको चरणबद्ध तरीके से हमने स्टार्ट किया और हमने लगभग 34 महाविद्यालय, जो इनके घोषणा किये हुए थे उन महाविद्यालयों को लिया और अभी इस बजट के अन्दर दो महाविद्यालय उसमें से खोल दिये और अब केवल छह रहे हैं, जिनको भी चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

अपने यहां से 28 महाविद्यालय प्रारम्भ कर दिये तीन साल के अन्दर और इसके साथ ही अभी 2017-18 के बजट के अन्दर 8 महाविद्यालय खोलने के लिए भी घोषणा की गयी और इस घोषणा की पालना अगर देखें, यह करने के बाद टोटल अगर आता है तो यह आता है 72 महाविद्यालय अपने इस तीन साल के कार्यकाल में, जिसमें 36 उनके, 36 हमारे अपने यहां से घोषणा की। इस सरकार में माननीय मुख्य मंत्रीजी के आदेश पर, निर्देश पर यह कार्य हो रहा है। इस तरीके से उच्च शिक्षा को कितना बढ़ावा राजस्थान सरकार दे रही है, इसका यह अनुमान लगा सकते हैं कि उनके तीन साल में एक-एक यानी तीन और हमने 24, तो 1:24 का रेश्यों इसमें बैठ रहा है। हम जो कहते हैं वह करते हैं। इन्होंने बार-बार कहा कि आपने यह घोषणाएं की हैं। इनमें आगे क्या हुआ, मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगी कि 2007 में, जब पिछली बार हमारी सरकार थी तो 3 यूनिवर्सिटीज अलवर, भरतपुर और सीकर की घोषणा की थी। यह जो 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने की हमने घोषणा की, उसके बाद 2008 में चुनाव हुए और उसमें दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं बनी। कांग्रेस की सरकार बनी और उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया।

सभापति महोदय, 2013 में जब चुनाव का समय आ रहा था तो मात्र 6 महीने पहले इन्होंने विश्वविद्यालयों के कुलपति की घोषणा की। विश्वविद्यालय का क्या क्षेत्राधिकार होगा इसके बारे में कोई बात नहीं। विश्वविद्यालय में एक कुलपति लगेगा और वह कुलपति कौन होगा, इसकी घोषणा की।

जब हमारी सरकार का गठन हुआ, उसके पश्चात् इन विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार को हमने निश्चित किया। इसी के साथ में विश्वविद्यालय की चारदीवारी का कार्य पूर्ण कराया है। थोड़ा-बहुत कहीं चल भी रहा है। हमने विश्वविद्यालय से एफिलियेटेड कॉलेजेज के छात्र-छात्राओं की बहुत सफलतापूर्वक परीक्षाएं भी लीं। यही नहीं, इस 2017-18 के बजट के अंदर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 50 करोड़ की राशि एकमुश्त रखी है, जो साढ़े 12-12 करोड़ के हिसाब से हम करेंगे।

सभापति महोदय, आपने ट्राइबल यूनिवर्सिटी की घोषणा की, उसका भी

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

कुछ नहीं किया। उदयपुर में वह ट्राइबल यूनिवर्सिटी छोटे से कमरे के अंदर चल रही है। हमने आने के बाद में बांसवाड़ा के अंदर ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए जमीन आरक्षित करवाई। बहुत ही शीघ्र, इसी सत्र से इन चारों यूनिवर्सिटीज को हम संचालित कर देंगे। यह बात मैं आपके माध्यम से इनको कहना चाहती हूं।

सभापति महोदय, अभी चर्चा के दौरान कुछ चीजों का जवाब तो यहीं पर आ जाएगा। हमारे वरिष्ठ सदस्य, लूणकरणसर से आने वाले मानिक चन्द जी सुराना ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर के लिए इसी सत्र में विधेयक लेकर आएं। बीकानेर से आए सभी माननीय सदस्यों ने, जो इस तरफ भी बैठे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि यह जो घोषणा हुई है, इसका विधेयक जब तक नहीं आएगा, तब तक उसकी आगे प्रगति नहीं हो सकती। मैं इन सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहती हूं कि इसी बजट सत्र के अंदर ही हम बीकानेर विश्वविद्यालय का विधेयक यहां पर ले आएंगे। आप सबके समक्ष सदन में प्रस्तुत कर देंगे।

एक माननीय सदस्य: इच्छा रखते हैं?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): इच्छा रखते हैं, तभी तो कह रहे हैं कि पटल पर रखेंगे विधेयक। इसका अर्थ यही तो है। कुछ और तो मुझे नहीं लगता। ये सभी औपचारिकताएं पूर्ण करके शीघ्र ही यह विश्वविद्यालय भी हम प्रारंभ कर देंगे।

सभापति महोदय, इसी के साथ में, हमारे बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कहा कि कैसे कौशल विकास हो? कैसे इन लोगों को रोजगार मिले? जॉब कैसे क्रिएट हो? इन सबके लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि हम इनक्यूबेशन सेंटर लगाएंगे। उसमें भी हमारी प्रगति हो रही है। स्टार्ट अप ओएसिस, सीआईआई और आईआईएम अहमदाबाद, इन तीनों के सहयोग से हमने सभी संभाग मुख्यालयों पर इनक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित करना तय किया है। उसमें से जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, इन तीन संभाग मुख्यालयों पर इनक्यूबेशन सेंटर्स बनकर कम्पलीट हो गए हैं और उनका कार्य भी शुरू हो जाएगा। बाकी सभी में काम चल रहा है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि यह सिर्फ हमारी घोषणाएं हैं। इनके ऊपर काम भी चल रहा है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सभापति महोदय, इसी के साथ में मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि संस्कृत शिक्षा विभाग में टीचर्स ट्रेनिंग को सुदृढ़ एवं एकेडेमिक लीडरशिप उपलब्ध करवाने हेतु 2016-17 की बजट पालना में हमने स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, महापुरा में इसका कार्य प्रारंभ कर दिया है।

सभापति महोदय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना, जिसे हम रूसा कहते हैं, वह भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजना है। जिसमें 60:40 के रेश्यो में, 60 परसेंट केन्द्र का है और 40 परसेंट राज्य सरकार का है। इसके अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अभी यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि रूसा के अंदर थोड़ा पैसा बढ़ाना चाहिए। आपको यह जानकार खुशी होगी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने हमारे 96 गवर्नमेंट कॉलेजेज को 2-2 करोड़ रुपए इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करने, इनमें अच्छी तरह से व्यवस्थाएं हों, सुविधाएं हों, इसके लिए दिए हैं। इसी तरह से 4 संस्कृत कॉलेजेज को दिए। 20 करोड़ रुपए हमने हमारी 5 यूनिवर्सिटीज को दिए। इसी तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज, बारां को 26 करोड़ रुपए दिए हैं। कुल 326 करोड़ रुपए हम लोगों ने स्वीकृत किए, जिसके अंदर काम चल रहा है।

सभापति महोदय, यही नहीं, उच्च तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट एवं इनोवेशन के लिए और जो एसडीओ हैडक्वार्टर्स पर कॉलेज बनाने की हमारी योजना है, उन सबको लेते हुए हमने एक स्टेट हायर एजुकेशन प्लान 2016 से 2022 तक का बनाया है। उसके लिए रूसा से हमने 2,088.60 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाया है। हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें से कुछ पैसा इस वर्ष मिल जाएगा। यह पैसा 17 आधारभूत सुविधाओं के लिए लिया जाएगा। उसकी पूरी डिटेल यहां पर नहीं कहते हुए, बहुत ही संक्षेप में यह कहूंगी कि आधारभूत सुविधाओं में सेमीनार रूम, आईसीटी लैब, स्मार्ट लैब्स, सीसीटीवी, वाई फाई, पुस्तकों का डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन इत्यादि उपलब्ध कराया जाएगा।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

माननीय सभापति महोदय, मैं इस गरिमामय सदन को यह भी बताना चाहूंगी कि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम के अध्यापन के साथ सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यावसायिक, आर्थिक महत्व के क्षेत्रों में भी विमर्श, शोध एवं प्रकाशन हो सके, इस दृष्टि से हमने विश्वविद्यालयों में शोध पीठ स्थापित करने पर बहुत बल दिया है।

सभापति महोदय, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में मानव संसाधन मंत्रालय के सहयोग से डॉ. बी.आर. अम्बेडकर शोध पीठ, सिंधु शोध पीठ व पृथ्वीराज चौहान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शोध पीठ स्थापित की गईं। कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा में महारानी अवंतीबाई लोधी शोध पीठ और मीराबाई शोध पीठ स्थापित की हैं। यही नहीं, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर में पंडित मदन मोहन मालवीय शोध पीठ तथा कोटा विश्वविद्यालय में वंशावली लेखन शोध पीठ स्थापित करने की भी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अन्य विश्वविद्यालयों में भी हमने गुरु जम्बेश्वर, बाबा रामदेव, स्वामी विवेकानंद, इंटैलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स, आरबीआई आदि शोध पीठ हमारी संचालित हैं। हमारा विशेष ध्यान है कि हम रिसर्च पर ज्यादा से ज्यादा काम करें।

सभापति महोदय, संस्कृत विश्वविद्यालय के तहत भी आज मैं यह कह सकती हूं कि हमारी सरकार में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से बराबर प्रयास चल रहा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब संस्कृत विश्वविद्यालय की विजिट की थी तो उन्होंने 23 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। इसमें मंत्र प्रतिष्ठान का नवीन भवन विश्वविद्यालय परिसर के अंदर बनाने, ओपन थियेटर बनाने के लिए भी स्वीकृत किए थे जिसका काम अभी चल रहा है। आने वाले 6 महीनों में वे सारे काम कम्पलीट हो जाएंगे।

सभापति महोदय, कर्मचारी कल्याण के लिए भी, हमारी सरकार ने सदैव राज्य कर्मचारियों को हितों को ध्यान में रखा है। इनको मिलने वाले सभी लाभ समय-समय पर दिए जाते हैं। हमारे बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कर्मचारियों के संदर्भ में चीजों को उठाया है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि कई वर्षों के बाद जो डीपीसी हुई है, वह इन तीन सालों के अंदर की है। 1135 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति हमने की है। संस्कृत

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

शिक्षा विभाग में डीपीसी करवाकर 528 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हमने पदोन्नति का लाभ दिया है। राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत व्याख्याताओं की वरिष्ठता सूची भी लंबे समय से लंबित थी। वह प्रकाशित नहीं हुई थी। इसी महीने में हम इसे शीघ्र जारी कर देंगे। इसकी भी हमने तैयारी कर ली है।

तकनीकी शिक्षा विभाग में 2010 से लंबित राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियमों में छठे वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में संशोधन की कार्यवाही भी पूर्ण की जा चुकी है, जिसके बारे में हमारे बहुत सारे सदस्यों ने सवाल किया था। संस्कृत शिक्षा विभाग में स्कूल शिक्षा के नियम लागू किये जा चुके हैं। महाविद्यालय के लिए नियम प्रक्रियाधीन हैं।

सभापति महोदय, नई भर्तियों के बारे में बात आई। बहुत सारे हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि शिक्षक नहीं हैं, लैक्चरर नहीं हैं। कॉलेजों में लैक्चर्स नहीं हो पा रहे हैं। इतनी सारी वैकेंसी हैं। ये सारी बातें उन्होंने कहीं। उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि जो भर्ती हुई है हम लोगों के समय में जैसे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले कार्यकाल में, 2005-06 में 913 ऐसे लैक्चरर के पद स्वीकृत किए थे जिनमें से 440 पदों की नियुक्तियां उस समय हो गई और शेष 417 थे उनके लिए भी उन्होंने आरपीएससी को रिक्विजिशन भेज दी थी। सरकार बदली, 5 साल में एक भी लैक्चरर भर्ती करने की उन्होंने स्वीकृति नहीं दी। इसी का कारण है कि ये जो हम लोगों को इतनी डेफिसिट लग रही है कि हमारे यहां लैक्चरर नहीं है उसका मैन कारण यही है कि उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि लेक्चरर की भर्ती करनी है तो उसका प्रोसेस थोड़ा लम्बा है तो जब तक हम उसकी रिक्वीजिशन भेजते तो उसकी स्वीकृति ही नहीं करते तो आगे कुछ होता नहीं तो स्वीकृति तो हुई नहीं लेकिन सिर्फ जो 417 पद हमारे 2005-06 में स्वीकृत हुए थे, उन्हीं पदों की उन्होंने भर्ती की पूरे पाँच साल में। हमने आते ही यह तय किया कि हमारे कॉलेजेज के अंदर प्रोपर लैक्चरर हो जाएं इसके लिए हमने 1339 पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थना आरपीएससी को भेज दी। उसमें से 1248 पदों की परीक्षाएं हो गई, रिजल्ट आ गया, इन्टरव्यूज का काम शुरू हो गया।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह आश्वस्त करना चाहती हूं। हमारा पूरा प्रयास है कि अगले सत्र से पूर्व सारे लैक्चरर की भर्ती हो जाए और ये कॉलेजेज के अंदर लग जाएं, यह हम लोगों को पूरा प्रयास रहेगा ताकि उच्च शिक्षा के अंदर हम यह कमी महसूस कर रहे हैं, उस कमी को हम लोग पूरा कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, केवल 1248 ही, लेकिन हमने यह भी तय किया है कि दिसम्बर, 2018 तक जो भी संभावित ऐसी रिक्तियां होंगी, उनकी भी चयनके लिए हम लोग रिक्विजिशन आरपीएससी को भेज देंगे, यह भी हम लोगों ने तय किया हैं ताकि आने वाले समय में यह जो कंटीन्युअस प्रोसेस है वह चलता रहे और 2018 तक जो हमारी रिक्तियां हों...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ...(व्यवधान)... अर्ज किया है कि सैकडरी में 55 परसेंट की जो बार है, वह यूजीसी के नियमों और मानदंडों के खिलाफ है उसको हटाने के लिए भी आप कृपया कोई कार्यवाही कीजिए। ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, वैसे तो जवाब इसका दे सकती हूं लेकिन ये जो हमारे माननीय सदस्य हैं, वास्तव में बहुत देर हो गई है पर सिर्फ इनका छोटा सा रिप्लाई देना चाहती हूं कि आप स्वयं एक बहुत अच्छे सीनियर एडवोकेट हैं और इस बात को जानते हैं कि यह एकेडमिक रिकार्ड के संदर्भ में जो बात थी, यह पहले से ही चला आ रहा था और इसलिए उसको एज इट इज ही आरपीएससी के पास में रिक्विजिशन दी तो उसके साथ में जो नोर्म्स देते हैं कि किस आधार पर भर्ती करनी है तो वह दे चुके थे। आने वाले समय में इसके अंदर संशोधन करने का हम लोग प्रयास करेंगे और आपको जो डिटेल कोर्ट का आदेश है, बहुत सारे लोग कोर्ट में गए, वहां से भी खारिज हो गया उनका, इसलिए बता दूंगी तो आपके ध्यान में आ जाएगा। यह बहुत पुराना मामला है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा, राजकीय महाविद्यालय में लाइब्रेरियन और पीटीआई की भर्ती के लिए नियमों में जो आवश्यक परिवर्तन करना है, वह भी हमारी प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। बहुत शीघ्र ही हम लोग

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

उसमें जो परिवर्तन करना है, वह करके लाइब्रेरियन और पीटीआई की भर्ती के लिए भी हम भेजते हैं।

माननीय सभापति महोदय, तकनीकी शिक्षा महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में हमारी सरकार के गठन के बाद 329 लैक्चरर के चयन के लिए भी हम लोगों ने अर्थना आयोग को भिजवा दी और चयन के पश्चात् 103 लैक्चरर का पदस्थापन भी हमने कर दिया। बाकी शेष लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर उनका पदस्थापन कर दिया जाएगा।

यही नहीं, संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर भी एक बात आई थी कि टीचर्स नहीं हैं पढ़ाने के लिए तो उसके लिए भी हमारे माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगी कि यह भी हमारा प्रोसेस शुरू हो गया है और आपको जानकर खुशी होगी कि इस बार हमको 3266 पद संस्कृत शिक्षा के अंदर मिले हैं। इसमें तृतीय श्रेणी अध्यापक 2400 हैं, उनको हम रीट के माध्यम से भर्ती करेंगे। परीक्षा हो चुकी है, सलेक्शन करना है, बहुत शीघ्र हो जाएगा। आने वाले शैक्षणिक सत्र से हम सबको अपोइंट कर देंगे।

इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक, प्राध्यापक और प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका, 690, 134 और 42, ये तीनों ही आरपीएससी के माध्यम से होने है तो वह भी आरपीएससी को हमने अपनी तरफ से अर्थना भेज दी है।

विश्वविद्यालय में कुलपति चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में जो बात यहां पर आई, उसके सम्बन्ध में कहना चाहूंगी कि कुलपति चयन प्रक्रिया, योग्यता एवं अनुभव आदि के सम्बन्ध में गुणात्मक परिवर्तन किए जाने हैं, उसके लिए भी विधेयक वर्तमान सत्र के अंदर ही यहां पर हमने पुर:स्थापित कर दिया है उस पर चर्चा हो जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, राजकीय महाविद्यालयों में पदनाम के संदर्भ में भी बात आई थी कि हमारे जो लैक्चरर हैं उनके पदनाम नहीं बदले गए। यह भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हुआ, जो आज तक नहीं हुआ, इतने साल से कहना चाहिए कि 31 दिसम्बर, 2008 को हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा डाइरेक्शन जारी किए गए थे कि कॉलेजों में शिक्षकों का नाम असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

प्रोफेसर करेंगे। लेकिन विगत सरकार के पाँच साल होने पर भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया। हम लोगों ने आते ही इसके अंदर रुचि बनाई और राजकीय महाविद्यालयों में हमारे जो शिक्षक हैं, उनके पदनाम व्याख्याता के स्थान पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रूप में कर दिए।

माननीय सभापति महोदय, निजी विश्वविद्यालयों में अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में हमारे बहुत सारे माननीय सदस्यों ने, तीन-चार सदस्य हैं, जिनमें गोविन्द सिंहजी डोटासरा, मनोज कुमारजी सादुलपुर से आने वाले। इन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों में अनियमितताओं की जांच की जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि जितनी भी इनके विरुद्ध हमें शिकायत प्राप्त हुई हैं, उनको लेकर हमने सभी ऐसे नौ विश्वविद्यालय हैं, जिनकी हमें शिकायत प्राप्त हुई हैं, मैं उनके नाम अभी यहां पर कहना नहीं चाहती हूं क्योंकि मैंने प्रश्न की रिप्लाई में सभी नाम दिए थे। टाइम बचेगा, इसलिए ये जो सारे निजी विश्वविद्यालय हैं उनके लिए अलग-अलग कमेटीज का गठन कर दिया गया है और एक महीने के अंदर-अंदर उनकी जांच होकर हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, छात्रवृत्ति एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाएं, हमारी उच्च शिक्षण संस्थानों में वित्तीय वर्ष के अंदर मुख्य मंत्रीजी ने उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लगभग 53571 छात्रों को और 4147 ऐसी छात्राओं को स्कूटी दी है। वह भी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि राजस्थान में मेधावी छात्राओं का इतनी अच्छी तरह से ध्यान रखा गया और इनको स्कूटी दी गई।

माननीय सभापति महोदय, नैक एक्रिडिशन के लिए भी हम लोगों ने इस बार तय किया है कि गुणवत्ता सुधार करने के लिए हमारे जितने भी राजस्थान के विश्वविद्यालय हैं, उनके अंदर नैक एक्रिडिशन सभी का हो, इसके लिए हम लोगों ने निर्देश दिए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग को अगर देखें हम तो इसमें भी मुझे सदन को जानकारी देते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि राजस्थान के 14 संस्थान, जिसमें 7 विश्वविद्यालय, 3 डीम्ड विश्वविद्यालय, 3 अभियांत्रिकी संस्थान और एक प्रबंधन संस्थान को नेशनल

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग में फर्स्ट हण्ड्रेड में स्थान मिला है तो यह भी हमारे लिए बड़े गौरव की बात है।

माननीय सभापति महोदय, युवा विकास केन्द्र, जो हम लोग कहते हैं, हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी की मैं बहुत आभारी हूं कि युवाओं के लिए प्रधान मंत्री युवा योजना जो शुरू की है, स्टार्ट अप इंडिया, मैक इन इंडिया योजना। उसी की तर्ज के ऊपर उन्होंने प्रधान मंत्री युवा योजना के माध्यम से युवाओं के व्यक्तित्व विकास एवं उनके स्वावलम्बन एवं रोजगारोन्मुख बनाने के लिए यह योजना शुरू की है। इसका भी लाभ हमारे राज्य में मिलेगा। प्रदेश में 184 हमारे जो महाविद्यालय हैं ...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री सभापति: बिना अनुमति जो बोले हैं, उनको रिकार्ड नहीं करना है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापतिजी, 184 राजकीय महाविद्यालयों में युवा विकास केन्द्रों के माध्यम से युवाओं के व्यक्तित्व विकास और कौशल सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन इसके अंदर किया जाएगा। यह एन्टरप्रिन्योरशिप का काम करते हुए इसमें यह रहेगा कि कैम्पस प्लेसमेंट पर ज्यादा जोर देते हुए हम लोग इसको करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, बीएड के जो महाविद्यालय हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार के गठन के समय राज्य में नवीन बीएड कॉलेज खोलने पर रोक लगी हुई थी लेकिन टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उनके द्वारा जो 138 तहसील थे, जहां पर एक भी बीएड कॉलेज नहीं था तो उन्होंने कहा कि जिन तहसीलों में एक भी बीएड कॉलेज नहीं है, वहां बीएड कॉलेज खोला जाए। उसी क्रम में 83 हमारी तहसीलें थीं, जहां पर हमने बीएड कॉलेजेज खोल दिए हैं और बाकी भी सारे प्रक्रिया में है।

(22.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा कहने को बहुत चीजें हैं लेकिन हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने सवाल किए हैं, उनमें बहुत फास्ट में

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

आप लोगों को बता दूं कि मैक्सिमम जो सदस्यगण थे.... जिनमें लगभग 17 ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने यह कहा कि नवीन राजकीय महाविद्यालय हमारे यहां पर स्थापित करना है, महाविद्यालयों में नवीन विषय, संकाय एवं क्रमोन्नयन प्रारंभ करना है। ऐसे सदस्य हैं श्री फूलचन्द जी भिण्डा, जिन्होंने विराटनगर के लिए कहा। श्री बाबू सिंहजी शेरगढ़ के लिए, श्रीमती अलका सिंह जी बांदीकुई के लिए, श्री हरीसिंह जी रावत, श्री भंवरसिंह जी कोलायत, श्री मान सिंह जी गंगापुर, श्री मामनसिंह जी, श्रीमती मंजू बाघमार जी जायल से, भागीरथ जी चौधरी किशनगढ़, श्री घनश्यामजी टोडाभीम से, श्री अजीत सिंह जी टोंक, श्रीमती अंजू देवी धानका बस्सी से, श्री गोपाल कृष्ण जी बीकानेर पश्चिम, श्री कैलाश जी भंसाली जोधपुर, श्री तरुणराय जी कागा चौहटन और श्रीमती शकुन्तला रावत बानसूर। इन सभी माननीय सदस्यों ने जो अपना यहां पर दिया है तो मैं यही कह सकती हूं आप लोगों के लिए क्योंकि अभी लैक्चरर्स की बहुत कमी है। पहले एक बार लैक्चरर्स भर्ती हो जाए तो हम नये संकाय खोलना है, क्रमोन्नत करना है, नये महाविद्यालय खोलने हैं, इन सब पर गंभीरतापूर्वक हम लोग विचार करके उचित निर्णय लेंगे। यह मैं आप सबको आश्वस्त कर सकती हूं।

इसके अलावा हमारे कुछ माननीय सदस्य हैं, जैसे हमारे कोटा से आने वाले माननीय सदस्य प्रहलाद जी गुंजल हैं, उन्होंने एक विषय दिया कि हमारे राजकीय महाविद्यालय, कोटा एवं राजकीय जेडीबी कन्या महाविद्यालय, कोटा के अंदर नवीन पुनर्गठित राजकीय महाविद्यालय की घोषणा तो कर दी, उसके बाद उसमें जमीन नहीं है, पैसा नहीं है (व्यवधान)

श्री सभापति: आप आसन की तरफ देखकर जवाब दें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन किया है। बजट सत्र में मुख्य मंत्रीजी ने 5 हजार से ज्यादा संख्या वाले विद्यार्थियों के कॉलेजों को उस संकाय के आधार पर विघटित कर दिया। यह प्रयोग एकदम असफल रहा। जहां जोर से विरोध हो गया, वहां आपने उस विघटन को समाप्त कर दिया। कोटा में लगातार इसकी मांग हो रही है। यह विघटन समाप्त होना चाहिए। यूजीसी की ग्रांट्स मिलना बंद हो गया, कॉलेजों का स्तर गिर गया। रोज प्रिंसिपलों

(श्री प्रहलाद गुंजल)

के झगड़े हो रहे हैं, कॉलेज यूनियनों के झगड़े हो रहे हैं, शिक्षा का वातावरण ही खराब हो गया। इसलिए आपको नये कॉलेज खोलना है तो और खोलो, लेकिन कॉलेजों को विघटित कर दिया, उसको समाप्त करो।

(22.02 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात यहां पर कही है, उसको ध्यान में रखते हुए यह कहूं कि इनकी प्रोब्लम थी, वह यह थी कि जो पुनर्गठित राजकीय महाविद्यालय हुए हैं, उनको जमीन देना और उनके नये कॉलेजेज, नये कॉलेज की बिल्डिंग बन जाए, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस साल के अपने बजट के अंदर 48 करोड़ रुपये सेंक्शन किये हैं और 6-6 करोड़ रुपये इन सभी कॉलेजेज के अंदर, जितने भी ऐसे पुनर्गठित किये, उन सबको मिलेंगे। जो प्रोब्लम आपके मन में है कि वहां पर बैठने की जगह नहीं है या वहां एक ही कॉलेज के अंदर 3 कॉलेजेज हो गये तो कैसे संचालित होंगे, वह सारी प्रोब्लम्स दूर हो जाएंगी। यह हम आपको विश्वास दिला रहे हैं।

इसी तरीके से, नागौर में विश्वविद्यालय खोला जाए, ऐसा परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य मानसिंह जी ने कहा। नागौर जिले के अंदर 65 निजी महाविद्यालय हैं तथा 9 राजकीय महाविद्यालय हैं। इस तरह से कुल 74 महाविद्यालय हैं और विश्वविद्यालय की संबद्धता हेतु वह संख्या कम है, लेकिन फिर भी नागौर के लिए एक निजी विश्वविद्यालय की हमारे पास बात आयी है। स्थापना का प्रकरण हमारे यहां पर चल रहा है, विचाराधीन है, उस पर विचार करेंगे।

जायल से आने वाली माननीय सदस्य डॉ. मंजू बाघमार जी के बड़े इंपोर्टेंट सुझाव थे। वे खुद भी लेक्चरर रही हैं, उन्होंने काफी अच्छे सुझाव दिये। उन पर मैं यही कहूंगी, अधिकारियों की पदोन्नति के संदर्भ में मैं आलरेडी जवाब दे चुकी हूं। पोलीटेक्निक महाविद्यालय में वरिष्ठ प्रवक्ता को प्रवक्ता पद पर पदस्थापित करने के संदर्भ में आपने कहा। उसके लिए भी वरिष्ठ प्रवक्ता का पद प्रवक्ता वरिष्ठ वेतनमान के समान होने के कारण,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

वरिष्ठ प्रवक्ता को प्रवक्ता पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जा सकता है।

आपने स्टेट हायर एजुकेशन कौंसिल के गठन के संदर्भ में बात कही और वाइस चेयरमैन की नियुक्ति के संदर्भ में कहा। उसका भी प्रोसेस चल रहा है। कमेटी का गठन हो चुका है, और कमेटी ही तय करेगी।

इसके अलावा आठ अभियांत्रिकी महाविद्यालय हैं, उन्हें संघटक महाविद्यालय बनाये जाने के संदर्भ में आपने कहा। इसके संदर्भ में भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगी कि यह विषय और भी हमारे माननीय सदस्यों ने उठाया। संघटक महाविद्यालय बनाये जाने के संदर्भ में, हम लोगों ने आलरेडी इसके अंदर काम शुरू कर दिया है क्योंकि राज्य सरकार के सोसाइटी एक्ट में संचालित हैं ये आठ इंजीनियरिंग कॉलेजेज। लेकिन उनको कैसे संघटक महाविद्यालय करना है, उसके संदर्भ में प्रोसेस हमने शुरू किया है और शीघ्र ही इसके अंदर कोई न कोई अच्छा रिजल्ट आएगा। यह बताना चाहूंगी कि चार विश्वविद्यालय, जिसमें बांसवाड़ा है, अलवर है, भरतपुर है, सीकर है। इन चारों विश्वविद्यालयों के साथ में संघटक कॉलेजेज बना दिये हैं ताकि इसी वर्ष से ये सारी यूनिवर्सिटीज काम में आ जाएंगी।

जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य कैलाश भंसाली जी हैं, उन्होंने कहा कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के अंदर रिक्त पद भरे जाएं। रिक्त पद भरने के संदर्भ में आलरेडी हम लोगों ने कर दिया है, शैक्षणिक 98 पद, अशैक्षणिक 29 पद भरने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। यह प्रक्रिया विश्वविद्यालय के स्तर पर चल रही है।

लगभग मैंने सभी माननीय सदस्यों के, जो विद्वान सदस्य हैं, जिन्होंने नवीन एवं उपयोगी सुझाव दिये थे, वे सारे सुझाव स्वागत योग्य हैं, कुछ के जवाब आये हैं, कुछ के और आपको चाहिए, हमसे चर्चा कर लेना। मैं यही कहूंगी कि इन सभी विचारकों और प्रबुद्ध सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगी कि हम सब मिलकर आने वाले समय में अच्छा एक ऐसा वातावरण शिक्षा का बनाएं कि राजस्थान शिक्षा के अंदर अग्रणी प्रदेश के रूप में आगे आए और बहुत सारी घोषणाएं हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है इस वित्तीय बजट में, जो 11.01 परसेंट बढ़ा भी है। इन सब चीजों को

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

लेकर हम काम करना शुरू करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा। अंत में यही कहूंगी कि

"बुद्धिहीन को बुद्धि देती, अज्ञानी को ज्ञान,
शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान।"

श्री उपाध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह जी।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने आज अनुदान की मांग संख्या-24 शिक्षा, कला और संस्कृति के संबंध में अपने विचार प्रकट किये हैं और जो कटौती प्रस्ताव भेजे हैं उन कटौती प्रस्तावों का जवाब कल सुबह उनको भेज दिया जाएगा। उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने जो राय दी और जो उन्होंने अपने विचार प्रकट किये, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

जो खेल विभाग है, उसके अंदर हम इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो खेल और क्रीड़ा एक हैप्पीनेस इंडेक्स, एक अपनी अच्छी हैल्थ को जो प्रमोशन देती है। हमारी युवा पीढ़ी जो 35 साल से कम उम्र की है, 70 प्रतिशत हमारी जनसंख्या है वह युवा है। आज हमारा अच्छा फाउण्डेशन बन जाता है, स्कूल लेवल पर हमारे बच्चे खेल सकें। आज की तारीख के अंदर, चाहे प्राइवेट शिक्षा है, वहां पर खेलों को बिलकुल प्रमोट नहीं किया जा रहा है। आज हमारा देश विश्व का डाइबिटीज, हार्ट प्रोब्लम्स और कैंसर, भारत के अंदर दुनिया में ये सबसे ज्यादा हैल्थ हैजर्ड हैं। अच्छी हैल्थ, अच्छी नींव हमें मिल जाती है हमारे यंगस्टर्स के अंदर तो हमारी जो बॉडी है वह आगे जाकर 50-60 साल की उम्र के अंदर जब हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव अपने कार्य में होते हैं उस समय हमें मजबूत रखती है।

दूसरी तरफ हम क्रीड़ा को देखते हैं in the form of excellence, आज देश के अंदर जो यूनिटी होती है, एक नाम-निशान होता है, उसके अंदर कोई भी टूर्नामेंट हो, चाहे क्रिकेट का टी-20 हो, चाहे वन-डे इंटरनेशनल हो, वर्ल्ड कप हो, हमारी सबसे ज्यादा हमें यूनिटी दिखायी देती है। मेरा सोच है कि स्पोर्ट्स का जो एक्सीलेंस है, जिसके अन्दर हमारा देश बहुत पिछड़ गया है और हमने पिछले ओलम्पिक्स के अन्दर देखा कि हमें इतने कम मैडल्स मिले हैं।

(श्री गजेन्द्रसिंह)

सबसे पहले स्पोर्ट्स के अन्दर, जो एक तरह श्रृंखला बनी हुई है, आपके टेलेंट को ऊँचा उठाना, उसमें सबसे पहले तो फैसेलिटी होना जरूरी है उपाध्यक्ष महोदय। उसके बाद टेलेंट सर्च, उसके बाद अच्छी सामग्री, इक्विपमेंट, उसके बाद कोचिंग, सर्वश्रेष्ठ कोचिंग, उसके बाद हम हमारे उन बच्चों को स्कॉलरशिप दें, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कम्पीटिशन और उसके बाद जोब सिक्योरिटी। ये सब होने के बाद ही हम चैम्पियंस प्रोड्यूस कर सकेंगे। यह जो पूरी चेन बनी है, यह जो लिंक है यह चेन हमारे देश में मजबूत नहीं है।

सर्वप्रथम मैं इन्फ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आऊंगा उपाध्यक्ष महोदय। आज हमारे देश के अन्दर बहुत कमजोर इन्फ्रास्ट्रक्चर है। आज हमारे बच्चों को खेलों की जो सुविधाएं मिलती हैं, वो बहुत ही कम हैं। यहां पर हर शहर के अन्दर क्लब हैं, हम अपने बच्चों को खिलाना चाहें तो हमें मैम्बरशिप नहीं मिलती है। यदि मैम्बरशिप मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है तो सबसे पहले हमारे बच्चों को, हमारी युवा पीढ़ी को जब तक हम इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, खेलने की सुविधा नहीं देंगे, तब तक न तो हमारे देश के बच्चों की हैल्थ अच्छी हो सकेगी और न ही इंटरनेशनल लेवल के अन्दर हम परफोर्म कर पायेंगे।

राजस्थान में पहली बार माननीय मुख्य मंत्रीजी के चेयरमैनशिप के अन्दर हमने एक नये डायरेक्टिव्ज बहुत मेहनत करने के बाद तय किये। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर हमने कई मॉडल्स बनाये हैं और मॉडल्स बनाने का यही मतलब था, क्योंकि हमारे 33 जिले हैं, हमारे इतने स्टेडियम्स हैं, हमारे इतने स्कूल्स हैं कि हमें फण्डिंग बहुत भारी चाहिए अगर हमें स्पोर्ट्स को हर लेवल पर प्रमोट करना है। यह जो पीपीपी मोड हमने बनाया है इसके अन्दर चार मॉडल्स हैं उपाध्यक्ष महोदय। सबसे पहला मॉडल है, सरकारी जमीन, उसके ऊपर गवर्नमेंट अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे और इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद खुद ही उसका नियंत्रण करें, जैसा अभी तक एस.एम.एस. और कई स्टेडियम्स में होता आ रहा है। जो द्वितीय मॉडल है, उसके अन्दर सरकारी जमीन हो, गवर्नमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करे और आगे 20 साल, 30 साल के लिए प्राइवेट मैनेजमेंट को हम दे दें। तीसरा मॉडल

(श्री गजेन्द्रसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय जो है, सरकारी जमीन और प्राइवेट इन्फ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो डोनेशन से हो और सरकार उसको मैनेज करे। उपाध्यक्ष महोदय, चौथा मॉडल जो है, उसमें सरकार की जमीन, प्राइवेट इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट मैनेजमेंट। इसके अन्दर क्या है कि हमारे 200 विधान सभा क्षेत्र हैं। हर मैम्बर अगर प्रयास करे तो इस मॉडल को लेकर, क्योंकि हमारे जहां पर सरकारी जमीन है, अमूल्य है, हमारे जो स्टेडियम्स हैं उनकी बहुत हाई वैल्यू हैं। चाहें तो हम प्राइवेट संस्थाओं को, चाहे वो सी.एस.आर. मोड से हो, चाहे वो पीपीपी मोड से हो, चाहे वो लीजिंग से हो, चाहे वो जोइंट वेंचर हो या कोई दानदाता इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर अपना नाम उसको देना चाहे और सरकार को रन करने के लिए दे, ये सब हमारे पास मॉडल्स उपलब्ध हैं।

यदि हर एमएलए और एमपी अपने एरिया के अन्दर अगर वो चाहे तो जिले का हर स्टेडियम एकदम उभरकर 7-8 स्पोर्ट्स के अन्दर बहुत शानदार स्टेडियम बन सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान का जब मैंने दौरा करके सब स्टेडियम देखे थे तो एक मुझे सबसे बेस्ट मॉडल लगा था, वो था राजसमंद का मॉडल। हमारी सरकारी जमीन थी, वहां पर जे.के. ने क्रिकेट स्टेडियम कर दिया। वहां पर प्राइवेट संस्थाओं ने मिलकर एक क्लब बना लिया। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके अन्दर यह है कि प्राइवेट कम्पनी उसको रन करे, कोचिंग करे, चाहे कुछ भी करे। उसके अन्दर एक विण्डो होनी चाहिए जनता के लिए कि वो पे एण्ड प्ले कर सके। अगर स्विमिंग पूल है और चार महीनों के लिए आप अपने बच्चों को स्विमिंग कराना चाहते हैं तो आप चार महीने की मैम्बरशिप लेकर, चाहे वो महीने के 500 रुपये हो, 700 रुपये, जो भी हों, उनको एक्सेसिबिलिटी मिले।

मेरा यह सोचना है कि इन डायरेक्टिव्ज के बाद स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा मिली है और हम सब लोग मिलकर इसको चाहे सी.एस.आर. फण्ड्स के थ्रू हो, मुझे याद है जब मैं उद्योग मंत्री था तो हमने सब कलेक्टर्स को हर विधान सभा में कितने बिजनस हाउसेज हैं, हमने शायद करीब 10 लाख प्राइवेट एंटरप्राइजेज के हमने नाम दिये थे। बूंद-बूंद से सागर बनता है, हल्का-हल्का कंट्रीब्यूशन, चाहे एक कोर्ट कोई बना दे, एक क्रिकेट नेट कोई बना दे, तो अगर हम चाहें तो इस मॉडल को यूज कर स्पोर्ट्स को हम बहुत ही ऊंचे लेवल पर ले जा सकते हैं उपाध्यक्ष महोदय।

(श्री गजेन्द्रसिंह)

इसके बाद जो मैंने दूसरी कड़ी बोली, टेलेंट सर्च। टेलेंट सर्च के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, हमने 2016 में तीरंदाजी, बास्केटबॉल, घुड़सवारी, शूटिंग और हॉकी को लिया था। हमने 145 बच्चों को आइडेंटिफाई किया और 145 बच्चों को हम एक लाख रुपये प्रति साल, चाहे वो खेल की सामग्री ले, चाहे वो कोचिंग कराये, चाहे उनकी डाइट के लिए हो, चाहे उनकी फिजियोथेरेपी के लिए हो, फिजिकल फिटनेस के लिए हो, हम यह अनुदान उनको दे रहे हैं।

इसके अलावा खेलो इण्डिया के अन्दर इनका भी एक कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है जिसके अन्दर आठ खेल, एथेलेटिक्स, जूडो, तीरंदाजी, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीवॉल, फुटबाल और कबड्डी, ये स्पोर्ट्स आइडेंटिफाई करके इनका भी टेलेंट सर्च राजस्थान में अभी शुरू कर दिया है।

अगली कड़ी जो है, वो कोचिंग की है। कोचिंग के अन्दर 118 रेगुलर कोचेज हैं, 203 पार्ट टाइम कोचेज हैं। हमने सक्षम का जो प्रोग्राम किया था सेल्फ डिफेंस का, उसको करते हुए दो साल हो गये और उसके अन्दर बालिकाओं को स्कूल लेवल पर सेल्फ डिफेंस में कोर्सेज दिलाये, जिसको आगे शिक्षा विभाग संभाल रहा है। हमारे माउंट आबू में भी कोचिंग क्लिनिक्स होते हैं। इंटरनेशनल कोचेज, वर्ल्ड क्लास कोचेज क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबाल में लाये हैं और उन्होंने यहां पर प्रशिक्षण किया है। इसके अलावा जितना भी इक्विपमेंट जो जाता है हैडक्वार्टर्स को, पहली बार राजस्थान के अन्दर हमने रूल बनाया है कि जो नेशनल फेडरेशंस हैं, उनसे एप्रूव की हुई सामग्री के अलावा कोई सामग्री बिलकुल पुअर क्लास की नहीं दी जाए।

चैम्पियनशिप के लिए जो 200 रुपये डेली का डी.ए. था स्टेट लेवल का, उसको हमने 200 से 300 रुपये कर दिया है और नेशनल लेवल पर 300 से 500 रुपये डी.ए. पर डे किया है।

ग्रांट-इन-एड के अन्दर टूर्नामेंट्स की स्पॉन्सरशिप, उनके लिए पैसा, मैडल्स विजेता को पैसा और उनको अन्य बैनेफिट्स, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के लिए बिलकुल क्लियरकट रूल्स हमने बना दिये हैं जो इतने ट्रांसपेरेंट और क्लियरकट हैं कि उसके अन्दर मुझे भी अथोरिटी नहीं है कि मैं किसी को एक्स्ट्रा मदद करूं या किसी को मैं फेवर करूं। क्लियरकट रूल्स हैं।

(श्री गजेन्द्रसिंह)

इसके अन्दर जो टूर्नामेंट्स हम होल्ड करते हैं उनके रूल्स बनाये हुए हैं। स्कॉलरशिप्स जो देते हैं उनके रूल्स बनाये हुए हैं और जो ट्रेनिंग है, जो लोग चयनित किये जाते हैं उनको हमारे स्टेट के अन्दर लेते हैं तो 30 हजार रुपये और स्टेट से बाहर जाते हैं तो 75 हजार रुपये और विदेश में उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो 3 लाख रुपये का उनको अनुदान दिया जाता है।

अवार्ड्स जो होते हैं, सबसे पहली बार राजस्थान के अन्दर हमने दूसरे स्टेट्स के मॉडल पर कॉमनवैल्थ, ओलम्पिक, ये जितने भी गेम्स हैं, एशियन गेम्स के लिए हाई लेवल की नौकरी, जमीन प्लस राशि। कॉमनवैल्थ गेम्स के लिए जो पहली राशि है और निवास के लिए भी जयपुर में हमने जमीन दे दी है। अभी अवार्ड्स जो मिलते हैं, उनमें अगर इंटरनेशनल लेवल पर फर्स्ट प्राइज मिलता है तो हम पाँच लाख रुपये देते हैं, सैकण्ड मिलता है तो तीन लाख रुपये और थर्ड मिलता है तो ढाई लाख रुपये। नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपको दो लाख रुपये, सैकण्ड आते हैं तो डेढ़ लाख रुपये और थर्ड आते हैं तो सवा लाख रुपये और स्टेट लेवल पर फर्स्ट, सैकण्ड और थर्ड पर क्रमश: एक लाख, 50,000 और 30,000 रुपये है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2007 के बाद में हमारे महाराणा प्रताप अवार्ड हैं, जोकि अर्जुन अवार्ड है, उसके लाइन्स पर है, वह स्टेट का हाइएस्ट अवार्ड है और गुरु गोलवलकर अवार्ड है, वे 2007 के बाद नहीं दिये गये हैं। हमने फिर एक ऐसा पाइंट सिस्टम करके, ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम करके और अभी राजस्थान दिवस के दिनों में माननीया मुख्य मंत्रीजी के कर-कमलों के द्वारा हम 100 एथलीट्स को यह अवार्ड देंगे।

"खेलो इण्डिया" जो स्कीम है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पहले राजीव गांधी खेल अभियान स्कीम थी, उसके बाद में, उसके अंदर चेंजेज आये हैं और खेलो इण्डिया के अंदर अगेन इन्फ्रास्ट्रक्चर, टूर्नामेंट्स, स्कोलरशिप, कोचिंग के लिए नये रूल्स बने हैं और हमें आशा है कि खेलो इण्डिया के तहत भी प्रदेश को बहुत-बहुत फायदा मिलेगा।

पूरे स्पोर्ट्स का हमारा जो इश्यू है, इसको हमने खोल दिया है और माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर

(श्री गजेन्द्रसिंह)

स्टेडियम हैं, मैं आपको बैठकर बताऊंगा कि आर्थिक सहायता कैसे ली जाये और यह जो हमारे माडल्स हैं, अगर हम सब लोग इस सदन में मिलकर प्रयास करें तो राजस्थान के स्पोर्ट्स को और हमारी युवा पीढ़ी को एक नई दिशा मिलेगी। इसके साथ आपको मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे बोलने का समय दिया।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी। आप शिक्षा पर भी बोलेंगे, कला पर भी बोलेंगे और संस्कृति पर भी बोलेंगे।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रात:काल से सदन में मांग संख्या-24 शिक्षा, कला और संस्कृति पर चर्चा हो रही है। मुझे प्रसन्नता है कि सदन के माननीय सदस्यों ने शिक्षा संबंधी चर्चा में अपने सार्थक विचार रखें। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि आपके विचारों को, आपके सुझावों को शिक्षा में सकारात्मक सुधार के लिए शामिल किया जायेगा। लगभग 28 माननीय सदस्यों ने सदन में विचार प्रकट किये और लगभग 205 कटमोशन्स आये। इन सारे कटमोशन्स के जवाब कल सवेरे तक सबको प्राप्त हो जायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की नेता माननीया मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे के नेतृत्व में एवं हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के विश्व पटल पर राष्ट्रगौरव की पुनर्स्थापना के संकल्प से प्रेरित होकर हम प्रदेश में शिक्षा के ढांचे में सकारात्मक आमूलचूल परिवर्तन में जुटे हैं। इस वर्ष के बजट में शिक्षा विभाग की उन्नति एवं शैक्षिक सुविधाओं में वृद्धि किये जाने हेतु किये गये प्रावधानों के लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस वर्ष के बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले 1,720 करोड़ रुपये अधिक का प्रावधान किया गया है। अभी जैसा माननीय सुरानाजी ने कहा, पिछले तीन वर्षों में तो यह लगभग 15,000 से 27,000 करोड़ रुपये पहुंचा है। इसके लिए निश्चित रूप से मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का हृदय से आभारी हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन में खड़ा होकर जिस गर्व और आत्मसम्मान के साथ राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के यश और कीर्ति पर अपने विचार रख पा रहा हूं, उसका श्रेय

(श्री वासुदेव देवनानी)

माननीया मुख्य मंत्रीजी द्वारा सहृदयता से साधन-संसाधन एवं वित्तीय स्वीकृति दिये जाने और हमारा नेतृत्व किये जाने को देता हूं।

साथ में शिक्षा विभाग के अधिकारियों, संस्था प्रधानों, शिक्षकों एवं कार्मिकों के इस साढ़े चार लाख लोगों से अधिक के विशाल परिवार, जिसने राजस्थान में सुराज के लिए शिक्षा के मंत्र को अपना संकल्प बनाकर किये गये कार्यों के साथ ही, उन करोड़ों अभिभावकों का भी इस सदन में धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे इस बदलाव के संकल्प में साथ दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं है। शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। हमारे ऋषियों, मुनियों ने, हमारे धर्मशास्त्रों ने अनेक बार उच्चारित किया है कि शिक्षा व्यक्ति निर्माण का माध्यम है। स्वामी विवेकानन्द कहते थे, हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए जिससे व्यक्ति का चरित्र बने, बुद्धि का विकास हो, मानसिक तेज बढ़े और इन सबसे भी ऊपर अपने पैरों पर खड़ा हो सके।

प्राचीन भारत के आंकड़े मेरे पास हैं। उस भाषा में यदि बात करूं तो सन् 1850 के आंकड़े हैं, जो बताते हैं कि देश में 7,50,000 गांवों में 7,32,000 गुरुकुल थे और शिक्षा की यह व्यवस्था सरकार केन्द्रित नहीं थी, समाज केन्द्रित थी और इसलिए समाज की सहभागिता से शिक्षा और शिक्षा से व्यक्ति निर्माण और व्यक्ति निर्माण से समाज का सर्वांगीण विकास होता आया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा यही विचार हमें विश्वगुरु के सर्वोत्तम शिखर पर ले जाता था लेकिन कालखण्ड में विदेशी हमलों और समाज में आई निराशा ने इस भारत मां के विश्वगुरु के सम्मान को कमतर किया। इसलिए दो लाइनों में कविता में कहा भी जाता है,

"कालचक्र की गति से टूट गया सिंहासन,
मां बैठी थी जिस पर, करती थी जग का शासन"

यह इस प्रकार का दृश्य आ गया इस गुलामी के काल में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन साल पहले जब राजस्थान के सुराज के संकल्प के साथ माननीया मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की बागडोर संभाली तो शिक्षा के

(श्री वासुदेव देवनानी)

मामले में बड़ी भयावह स्थिति थी। मुझे शिक्षा विभाग की जब जिम्मेदारी दी गई, मैं स्वयं एक शिक्षक हूं। इसलिए उस पीड़ा को महसूस कर सकता हूं, उस समय के शिक्षकों के जो मन में थी, जिस शिक्षा का सम्मान इस समाज में बहुत गौरव की बात कहा जाता था, जिनके लिए कहा करते हैं,

"गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागूं पाय,
बलिहारी गुरु आपकी, गोविन्द दियो बताय"

वही गुरु, वही शिक्षक, समाज में पता नहीं क्यों उसके नकारात्मक रूप से प्रचारित किया गया। आज विद्यालयों के हालात यह थे कि कहीं विद्यार्थी नहीं थे और कहीं विद्यार्थी थे तो शिक्षक नहीं थे। शिक्षक थे तो विद्यार्थी नहीं थे। जहां भवन थे, वहां बिजली नहीं। जहां भवन भी थे, विद्यार्थी भी थे, शिक्षक भी थे, बिजली भी थी, वहां शौचालय नहीं। जहां शौचालय थे, वह उपयोगी नहीं थे। ऐसे में मुझे एक शेर याद आता है,

"डर मुझे भी लगा, फासला देखकर
पर मैं बढ़ता गया, रास्ता देखकर।
खुद-ब-खुद करीब आती गई
मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर।।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने सकारात्मक प्रयास किये, हमने नवाचार किये। हमने सबको साथ लेकर चलने के लिए कदम बढ़ाये। हर व्यक्ति से मिले सुझावों को सकारात्मक सोच के साथ शिक्षा के हित में जो कुछ कर सकते थे, उसका समावेश किया। आज सुखद अहसास होता है...

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मंत्री महोदय, आपके उस पर एक स्लोगन पढ़ रहा कि

"गुरु गोविन्द दोऊं खड़े, काके लागूं पाय,
बलिहारी गुरु आपकी, बारह दिये बजाय"

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैंने बारह किसी की आज तक न ही बजाई है, किसी की नहीं बजाऊंगा। घड़ी भले ही बजाती रहे। (व्यवधान)

(श्री वासुदेव देवनानी)

आज सुखद एहसास होता है कि वीरान से पड़े राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों की आवाजाही से रौनक लौटने लगी है। बच्चों के कलरव से जीवंत हुए विद्यालयों के कारण शिक्षकों के चेहरे पर भी एक मुस्कान नजर आती है। इस सकारात्मक माहौल में बच्चों ने नई उपलब्धियां, नये मुकाम हासिल किये हैं और इससे अभिभावकों के मन में भी एक संतुष्टि का भाव जगा है और यह संतुष्टि का भाव जो जगा है, इस संकल्प को पूरा करने के लिए, इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।

अभी चर्चा आई कि स्कूलों का आपने समन्वय किया। अभी इधर से विपक्ष के मेरे कुछ मित्रों ने भी इस मुद्दे को उठाया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्कूलों की स्थिति क्या थी, जरा उसकी तो चर्चा करायें। केवल स्कूल खोलते जाओ। गरीबों की और किसानों के बच्चों की भी चर्चा कुछ मेरे माननीय साथियों ने की, लेकिन हम स्कूल तो जरूर खोलते गये, अध्यापक उपलब्ध नहीं कराये। उनको क्या अनपढ़ तैयार करना था? कक्षा एक से आठ तक परीक्षा न करवाने का और तय किया। न विद्यार्थी आये और न अध्यापक आये और न अभिभावक भेजे। इस प्रकार का एक दृश्य जो खड़ा हुआ था, उस समय की स्थिति बता रहा हूं, जिस समय आया। 142 स्कूलों में जीरो नामांकन था, 4,164 विद्यालयों में जीरो से 15 थे, पांचवीं की कक्षा और आठवीं की कक्षा और 15 विद्यार्थी, यानी एक कक्षा में तीन, एक कक्षा में दो, यह दयनीय स्थिति थी और 28,013 स्कूल ऐसे थे जहां तीस से भी कम नामांकन था अर्थात् एक कक्षा में वही तीन और चार और पाँच का था।

हमारा स्वप्न था, माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी स्वप्न था कि बारहवीं तक की शिक्षा सबको उपलब्ध करायें। आज क्रमोन्नति का एक वातावरण बना है इस वातावरण को बनाने के लिए सबने सहयोग किया है, शैक्षिक वातावरण बना है नहीं तो क्या आपको किसने रोका था कि पूरे 68 साल के अन्दर केवल साढ़े चार हजार स्कूल ही आप बारहवीं के चलाते? उन बच्चों को कभी बारहवीं की शिक्षा देने का कभी सोचा था क्या? कभी सोचा नहीं। वो बेचारे कहां जाते थे, यह कभी सोचा नहीं और आज जब किया है, जब क्रमोन्नत की बात आई तो अच्छी है, यह जागरूकता है। एक साथ माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पाँच हजार स्कूलों को क्रमोन्नत करके इतिहास रचा है वो मैं समझता हूं कि इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।

(श्री वासुदेव देवनानी)

इसमें ये कहते हैं कि स्कूल बंद किये। एक भी स्कूल बंद नहीं किया। स्कूल को मर्ज किया है। क्या दो स्कूलों को मिलाना बंद करनी होता है? क्या दो परिवारों को मिलाना एक परिवार को समाप्त करना होता है? वह आपस में मिलाया है। आपस में मिलाने से एक उन्नति बनती है। हमने स्कूलों को बढ़ाया है यह सत्य है। कक्षा एक में बच्चा आये, बारहवीं करके एक ही स्कूल से निकले, इससे निश्चित रूप से मैं बताता हूं कि ड्रोप आउट्स में कमी हुई है। आज बारहवीं तक के जो पहले ड्रोप आउट होते थे वह आज की तारीख में आपको सुन कर आश्चर्य होगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि वह संख्या 2.16 केवल ड्रोप आउट्स की रही है, जो किसी जमाने में दहाई के आंकड़ों को क्रोस करती थी। इतने ड्रोप आउट्स कम हुए, कक्षा एक में आने के बाद वे तीन-तीन स्कूल बदलते हुए पढ़ते थे। टीसी ली, फिर पांचवीं के बाद छठी में गया, टीसी लेकर, फिर आठवीं के बाद टीसी लेकर के गया फिर कहीं नवीं में गया, फिर कहीं दसवीं तक का स्कूल मिल गया, फिर बारहवीं तक गया इस प्रकार की स्थिति को समाप्त करना आवश्यक था। इसीलिए हमने इन स्कूलों को क्रमोन्नत करके ...।

यह ठीक है आज बहुत रेशनलाइज हो गया है कि इस समय 64535 स्कूल चल रहे हैं एक बिलकुल रेशनलाइज हो गया और आपके जमाने में स्कूल तो थे, लेकिन न अध्यापक, न बिल्डिंग और बिजली की आज बात होने लगी तो कहने लगे कि बिल्डिंगों की कमी है। क्या हमने आकर बिल्डिंगें गिरा दी थी? बिल्डिंगें तो आपने इतने वर्षों में नहीं बनाई। आज ये कमी है, वो कमी है, कमी गिना सकते हैं आपका धर्म है हमारे ध्यान में लाना, लेकिन यह कमी एक दिन में डवलप नहीं हुई। यह लगातार पिछले कई वर्षों से शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिये जाने के कारण थी।

दूसरा मुद्दा यह आया कि आपके आध्यापकों की कमी है, अध्यापक नहीं है। मैं आपके माध्यम से सदन में यह बात कहना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आज प्रधानाचार्य, इनके समय स्कूल क्रमोन्नत होता था तो वर्षों तक नहीं बनते थे और आज स्कूल क्रमोन्नत होने के बाद केवल राजस्थान में केवल दस परसेंट प्रधानाचार्यों के पद खाली हैं। कुल 13525 स्कूलें हैं, उनमें केवल 1322 पद खाली हैं, उनको भी अप्रैल में 2017-18 की

(श्री वासुदेव देवनानी)

डीपीसी करके हम भर देंगे। एक भी स्कूल बिना उसके नहीं रखेंगे ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): थोड़ा सुनना सीखो।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): इसके साथ ही लैक्चरर्स की बात आई। लैक्चरर्स के पद माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 47,276 हैं...

श्री उपाध्यक्ष: आप ऐसे कैसे बात करते हैं? यहां भाषा का उपयोग होता है। आवाज करना अनिवार्य नहीं है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं तो धीरे ही बोल रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आपके ऊपर यह नहीं थी आपके सहयोगियों के लिए थी।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): हां, मैंने कहा कि मेरी आवाज तो माइक तेज कर रहा है, माइक को बंद कर दें। ...(व्यवधान)...

उसमें लैक्चरर्स में निश्चित रूप से 16,699 पद खाली हैं और इसके लिए भी लेक्चरर्स के 13,000 पद एक साथ विज्ञापित किये थे। हो गये, बैठे हैं कुछ कानूनी अड़चनों के कारण, लेकिन मुझे विश्वास है कि आगामी सत्र से पहले इनका भी हम पदस्थापन कर देंगे तो बाकी करीबन तीन हजार पद ही लेक्चरर्स के रहेंगे।

यह स्थिति सैकण्ड ग्रेड की भी है। सैकण्ड ग्रेड में माध्यमिक में केवल 15,408 पद खाली हैं। करीबन आठ हजार प्राइमरी में भी खाली होंगे तो कुल मिला करके लगभग इस साल 6,468 विज्ञापित हो चुके हैं एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है, मार्च के अंतिम सप्ताह और अप्रैल के पहले सप्ताह में उनकी परीक्षा हो रही है और बाकी 6,468 की वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी है जो एक अप्रैल के बाद हम आरपीएससी को भेजेंगे। इस तरह लगभग 13 हजार सैकण्ड ग्रेड के भी अध्यापक हमको मिल जाएंगे। इस कमी को भी हम दूर कर सकेंगे।

स्कूल बंद करने की बात पर मुझे एक बात याद आती है। यदि कभी

(श्री वासुदेव देवनानी)

स्कूल बंद होते हैं तो फिर नामांकन तो घटना चाहिए था। फिर नामांकन बढ़ा क्यों? इस गहराई में गये क्या आप? जब आप अकेले में मिलते हो तो कहते हो कि शिक्षा में बहुत काम हुआ। लेकिन यहां ठीक है, अपना विपक्ष का धर्म आपको निभाना होगा। आपने कोई चर्चा की, अच्छा हुआ, हमें भी कुछ बातें ध्यान में आई, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विद्यालयों का नामांकन निजी विद्यालयों की तुलना में बढ़ गया है। इस बार 82 लाख 3 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं जबकि निजी विद्यालयों में 78 लाख 15 हजार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। 4 लाख तो उनसे ज्यादा और कुल मिला करके तीन वर्षों में 15 लाख के आस-पास का नामांकन बढ़ा है। यह बढ़ता क्यों है? बढ़ा इसीलिए कि हमने अभिभावकों की विश्वसनीयता जीती। उनको लगा कि सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हो रहा है। वहां मेरे बच्चे को भेजूंगा तो अच्छी पढ़ाई हो रही है। वहां अध्यापक हैं। पहले क्यों नहीं भेज रहे थे? 2010-11, 2011-12, 2012-13 के जरा आंकड़े उठा कर देख लो। प्रतिवर्ष चार लाख, चार लाख, कुल बारह लाख का नामांकन कम हो गया। यह मैं नहीं, आंकड़े आपके सामने हैं तो कम क्यों हो रहे थे? आपकी स्थिति अच्छी थी, तो और बिगाड़ी तो फिर बढ़ क्यों रहे हैं? जरा इस पर विचार करो। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, आपके सहयोगियों को आप इजाजत दे रहे हो क्या कि इनसे पूछें क्यों बढ़े और क्यों घटे?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): नहीं, मेरा उत्तर मेरे पास है। आपकी अनुमति से कहूंगा मैं। यह सब इसलिए हुआ कि शुभ संकल्पों के कारण, ईमानदार प्रयासों के कारण, राजस्थान की आने वाली पीढ़ी के प्रति एक सकारात्मक सोच के कारण यह परिवर्तन राज्य सरकार के द्वारा किये गये। सारे प्रयोग सकारात्मक हैं और ये नामांकन भी बढ़ा मैंने जैसे कहा कि विश्वनीयता बढ़ी, उसका प्रमाण, प्रमाण हर व्यक्ति मांगता है क्योंकि साइंटिफिक युग है, कोई कहने से नहीं मानता कि आपने कहा कि अच्छा चल रहा है तो अच्छा मानेगा। इसलिए पिछले दिनों जो परीक्षा के परिणाम आये, इस वर्ष के तो अब आएंगे मई में तब शायद आप देखोगे तो इसमें कई गुना आपको वृद्धि मिलेगी। जो गत वर्ष मई में परीक्षा के परिणाम

(श्री वासुदेव देवनानी)

आये, उसमें मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता है कि बारहवीं के राजकीय विद्‌यालयों के परीक्षा परिणाम आये, बारहवीं की टोपर आठ में पहली, तीसरी और सातवीं मेरिट सरकारी स्कूल के बच्चों की रही और केवल बारहवीं नहीं, दसवीं की जो मेरिट निकली, 15 मेरिट घोषित होती हैं, उनमें से आठ मेरिट में सरकारी स्कूलों के बच्चे थे और यहां तक कि आजकल जिलास्तरीय मेरिट की भी घोषणा होती है, उसमें पाँच सौ से अधिक स्थानों पर जिलास्तरीय मेरिट में राजकीय विद्‌यालयों के विद्‌यार्थियों ने परचम फहराया है। ये तो मेरिट की बात रही।

मैं यदि परीक्षा के एवरेज परिणामों की बात करूं तो 2013-14 के अन्दर जो रिजल्ट आये उसमें दसवीं का रिजल्ट था 57 परसेंट और जो गत वर्ष 2016-17 में आया है वह 73 परसेंट है। 15 परसेंट परीक्षा परिणाम इम्प्रूव हुए हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ये आंकड़े समझ में भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कहीं समझ में ही नहीं आ रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको और सदन को जान कर प्रसन्नता होगी कि साक्षरता की परीक्षा होती है 2012 की जो साक्षरता की परीक्षा हुई, उसमें राजस्थान सत्रहवें नम्बर पर था। कौनसे नम्बर पर? सत्रहवें नम्बर पर और अभी जो 2016 के नम्बर आये हैं उसमें राजस्थान पहले स्थान पर है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा कर्म ही पूजा है। मैं बताना चाहता हूं कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे और संसदीय संस्था प्रथम द्‌वारा जारी किये गये, अभी जो एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट है जो 'असर' के नाम से अखबारों में भी आई है कि राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में हुए कार्यों और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रयासों को उन्होंने सराहा है। यूनिसेफ ने भी सराहा है और इसमें जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, वह राज्य सरकार के एसआरटी द्‌वारा दिया गया है, जो स्टेट लर्निंग अचीवमेंट सर्वे है, उसमें सामने आया है कि पिछले दो वर्षों में राजस्थान के विद्‌यार्थियों की दक्षता आठ से बीस परसेंट बढ़ी है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, सारे एनजीओज और नेशनल सर्वे कह रहे हैं।

(श्री वासुदेव देवनानी)

सतत और व्यापक मूल्यांकन में हमने इसको स्टेट लर्निंग अचीवमेंट के अन्तर्गत यह भी देखा कि लगभग अस्सी प्रतिशत शिक्षकों ने इसको सतत और व्यापक मूल्यांकन के सकारात्मकता की पुष्टि की है कि आज विद्यार्थियों का एक अच्छा बने और इसके दो-तीन कारण भी हैं। हमने वर्ष में दो बार शिक्षा सम्बलन का कार्यक्रम भी चलाया है। उसमें अध्यापक-अधिकारी वर्ग स्कूल में जाते हैं, दो दिन जाते हैं, वहां के बच्चों से बात करते हैं, सुविधाएं देखते हैं, फिर हमको कमियां बताते हैं उन कमियों को भी हम दूर करने का प्रयत्न करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजनीति अपनी जगह है और राजस्थान का भविष्य अपनी जगह है। राजस्थान की प्रगति में राजनीति न हो, राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को प्रदूषित न करे, यह हर राजस्थानी चाहता है। हम महाराणा प्रताप के ऋणी हैं, हम महाराजा सूरजमल के ऋणी हैं, हम पन्नाधाय के ऋणी हैं, हम पंडित दीन दयाल उपाध्याय के ऋणी हैं, हम गोविंद गुरु के ऋणी हैं, हम डाक्टर अंबेडकर के ऋणी हैं, हम भक्त रैदास के ऋणी हैं, हम भामाशाह के ऋणी हैं। पर हमने अपने बच्चों को क्या बताया, क्या पढ़ाया? तथ्य साबित करते हैं कि अकबर से युद्ध में महाराणा प्रताप जीते थे। मेरी स्पष्ट चुनौती है, यदि अकबर जीते होते तो उन्होंने छह बार हल्दीघाटी पर और मेवाड़ पर आक्रमण क्यों किया? जीता हुआ कभी भी आक्रमण नहीं करता, हारा हुआ करता है। इसका मतलब महाराणा प्रताप जीते, अकबर हारे। लेकिन हम बड़े गौरव के साथ बच्चों को पढाते थे अकबर महान। उससे क्या हमारे बच्चों में गर्व आयेगा? आज आप जापान जाइए, जर्मनी जाइए, इंग्लैण्ड़ जाइए। क्या इंग्लैण्ड़ में उपनिवेशवाद पढ़ाया जाता है? वहां पर वह पढाया जाता है जो बच्चों में देशभक्ति का ज्वार पैदा करे, उस प्रकार का पाठ्यक्रम, उस प्रकार का वातावरण वहां रहता है। मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि यहां पर केवल यह पढाया जाता है, महाराणा प्रताप की पराजय और अकबर के गौरव का गान करते रहते थे। तब जाकर यह स्थिति बनी कि राजस्थान में आकर अलाउद्दीन खिलजी के वहशीपन को प्रेम का रूप दे देता है और महारानी पद्मिनी के जौहर को कम आंकने की जरूरत करता है। इतनी हिम्मत हो गई कि रानी पद्मिनी के इतिहास को बदल दे। उसके

(श्री वासुदेव देवनानी)

जौहर को कोई कम नहीं कर सकता। राजस्थान में कोई भी आये, चाहे फिल्म बनाये या न बनाये, पर्यटन बढ़े या घटे, लेकिन देश के इतिहास के साथ इस प्रकार छेड़छाड़ को नहीं बर्दाश्त किया जा सकता।

हमने शिक्षा के मंदिरों को उन लोगों के हवाले कर दिया जिनकी जड़ें भारत में नहीं थीं। या तो मॉस से प्रेरित थे या उन अंग्रेजों से प्रेरित थे। मैकाले ने कहा था कि मैं यहां पर अंग्रेज तैयार करके जाऊंगा। उन्होंने पाठ्यक्रम बनाया, जहां भारत का गौरव गान नहीं, भारत की पराजय की गाथा लिखी गई। हमने इस बार पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया। उपाध्यक्ष महोदय, हमने पहले की तरह किसी महापुरुष के नाम पर कालिख नहीं पोती। हमने पाठ्यपुस्तकों में से पन्ने नहीं फड़वाये। हमने यह तेरा और मेरा महापुरुष नहीं किया। हमारी नजर में हर वह व्यक्ति जिसने इस देश और समाज के लिये अच्छा सोचा, अच्छा काम किया, उसे हमारे बच्चे जाने, उन्हें पहचाने, उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लें जिसके लिये पाठ्यक्रम में हमने उनको स्थान दिया। प्रताप महान, वीर दुर्गादास, महाराजा सूरजमल, पृथ्वीराज चौहान, गोविंद गुरु, डाक्टर अंबेडकर, वीर सावरकर, महात्मा गांधी, भगत सिंह, हेमू कालानी, भास्कराचार्य, पन्नाधाय, एपीजे अब्दुल कलाम, दीन दयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित दो सौ से अधिक वीर और वीरांगनाओं, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों के नाम हमने शामिल किये हैं पाठ्यक्रम में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही हमने सामाजिक सरोकारों के साथ अपने संबंध रखे। हमने पाठ्यक्रम में स्वच्छता, कौशल विकास, जल स्वावलंबन जैसे विषयों को भी समाविष्ट किया लेकिन मुझे लगा कि इनके साथ एक पाठ और जुड़ना चाहिये। कल सदन में एक बात चली कि मीसा बंदियों को लोकतंत्र सैनानी कहा जाये। लेकिन जो इमरजेंसी लगी, उस लोकतंत्र की जो हत्या हुई, उसका इतिहास मेरी नई पीढी जाने, इसके लिये पाठ्यक्रम में आपातकाल संबंधी एक पाठ को हमने जोड़ा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्यालयों की क्रमोन्नति से छात्र-छात्राओं का जैसा मैंने कहा ड्रोप आउट तो कम हुआ है और इसको सुनिश्चित करने के लिये भी मांग उठी। हमने पांच हजार स्कूल खोले। उसके बाद भी 1464

(श्री वासुदेव देवनानी)

पंचायत ऐसी हैं जिनमें 12वीं का सरकारी स्कूल नहीं है। उसमें 752 तो ऐसी थी जहां पर प्राइवेट स्कूल थे। जैसा चर्चा की और 692 ऐसी हैं जो नई गठित हुईं। जहां पर केवल प्राइमरी होंगी तो उसको अपर प्राइमरी बनायेंगे। जो अपर प्राइमरी होगी उसे पहले सैकण्डरी करेंगे और जहां सैकण्डरी होगी उसको सीनियर सैकण्डरी में ले जायेंगे, यह क्रम है। जो 752 हैं उनमें से अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट घोषणा में कहा है कि जहां 10वीं में 40 बच्चे होंगे, उसमें चाहे प्राइवेट हो तो भी हम उसको क्रमोन्नत करेंगे। जो नई पंचायतें हैं, दोनों में मिलाकर 282 स्कूलों को हम क्रमोन्नत करने जा रहे हैं। कइयों ने कहा कि 40 के बेरियर, यह मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आज सबकी अपेक्षा है, लेकिन मेरा आपसे एक आग्रह है, मैंने आपको कहा, अपन उनकी तरह अनपढ़ तैयार नहीं करेंगे। लैक्चरर्स की व्यवस्था करते जायेंगे, क्रमोन्नत करते जायेंगे, यह 40 का बेरियर इस साल खत्म नहीं हो रहा है। आप इस साल 40 लाइए और अगले साल इसको क्रमोन्नत करके ले जाइए, कहीं पैसे की कमी नहीं होगी। आपको चुनाव से पहले, हमारे सत्र से पहले ही आपको सारे स्कूल क्रमोन्नत मिलेंगे। आप भी मेहनत करके 10वीं में 40 बच्चे तो कर दीजिए। जब 40 बच्चे होंगे तो बोर्ड की परीक्षा में 30-32 पास होंगे, उसके बाद वह 11वीं में आयेंगे तो तीन लैक्चरर्स देने पडते हैं, तीन लैक्चरर्स का वेतन और सालभर का वर्क लोड, इसको भी देखना होता है। इसलिए कम से कम इतने विद्यार्थी आप लायेंगे तो मुझे सुविधा होगी।

कई कह रहे थे कि राजनीति से प्रेरित होता है। हमने तय किया क्या कि जहां कांग्रेस का एमएलए हैं वहां नहीं करेंगे? यह तो नहीं किया। 5 हजार एक साथ किये, जिन ग्राम पंचायतों में दोनों नहीं थे। आपकी विधान सभा की मेरे पास लिस्ट है, 282 में आपके क्षेत्र की भी कोई न कोई स्कूल क्रमोन्नत हुई है।

हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रकार की आपकी और मेरी राजनीति में नहीं जाती हैं। वह ''सबका साथ, सबका विकास'' जो कहती हैं, उसको व्यवहार में हमने करके बताया। स्कूल क्रमोन्नत भी हुए लेकिन स्कूल केवल स्कूल की तरह चले तो कौन पढ़ने के लिये आयेगा? अपन भी जाते हैं

(श्री वासुदेव देवनानी)

तो अपने बच्चे को वहीं भर्ती कराते हैं जहां पर अच्छी शिक्षा हो। हमने तय किया कि हम आदर्श विद्यालय बनायेंगे, हम उत्कृष्ट विद्यालय बनायेंगे। उसके तहत इन आदर्श विद्यालयों में हमने 1340 पहले चरण में बना लिये और इस वर्ष 3097 आदर्श विद्यालय की स्थिति में आ गये हैं और अगले वर्ष 5458 और विद्यालयों को भी आदर्श बनाने जा रहे हैं। यानी हर ग्राम पंचायत में एक आदर्श विद्यालय होगा। कक्षा एक से 12वीं के आदर्श विद्यालय तो बने, लेकिन एक स्थान और भी हैं जहां पर 8वीं तक की पढाई है। एक उत्कृष्ट विद्यालय और बनाया जाये तो पूरे 9894 आदर्श विद्यालय बनेंगे और 9894 उत्कृष्ट विद्यालय भी हम बनाने जा रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में एक आदर्श, एक उत्कृष्ट, इस तरह मिलाकर हम सारे विद्यालयों को श्रेष्ठ बनाने जा रहे हैं। जब आदर्श कहते हैं तो फिर आदर्श करने की कोशिश भी होती है। आप कह सकते हो, आदर्श पहले दिन नहीं बनते हैं। सामने लक्ष्य रखते हैं आदर्श का, उसकी व्यवस्थाएं करने में जुट गये हैं, हमारी नीयत साफ है। जब नीयत साफ हो तो फिर आदमी को कोई भी मंजिल पाने में देर नहीं होती। उस नीयत के साथ हम लोग आगे बढे हैं। मुझे लगता है कि हम सारे उत्कृष्ट विद्यालय बनायेंगे।

मेरा विद्यार्थी पीछे नहीं रहे, आधुनिक तकनीकी के साथ उसका ज्ञान बढे इसलिए हमने डिजिटलाइजेशन करना शुरू किया है। कुछ नवाचार किया। बीकानेर से आप भी हैं और दूसरे भी माननीय सदस्य हैं, उनको मेरे बीकानेर के डाइरेक्ट्रेट का ध्यान है कि सबका संधारण रजिस्टर में होता था। फिर उसका कहीं ट्रांसफर हो गया, कहीं प्रमोशन हो गया, पता ही नहीं। ढूंढने में मेहनत होती थी, गल्तियां होती थीं। उस रजिस्टर में इंद्राज नहीं किया जाता था, रिकार्ड सही नहीं था। इसके लिये माननीय प्रधान मंत्रीजी ने कहा कि डिजिटलाइजेशन करो। ''डिजिटल इंडिया'', ''डिजिटल राजस्थान'' जो माननीय मुख्य मंत्रीजी कहती हैं, हमने उसको ''शाला दर्पण'' और ''शाला दर्शन'' नाम के दो वेबपोर्टल बनाये। शाला दर्शन में जितना भी सैकण्डरी सैटअप है, उसमें सारे 43-44 लाख विद्यार्थियों के नाम, सारे प्राध्यापकों के नाम, स्कूल की सारी स्थिति है। आप चाहे तो क्लिक करके स्वयं पता कर सकते हैं कि वहां अध्यापक का कौनसा पद खाली है, किसको कहां करना है। धीरे-धीरे हम

(श्री वासुदेव देवनानी)

उसमें आधार नंबर भी भरने के लिये आगे बढे हैं। वह बनने के बाद मुझे लगता है कि श्रेष्ठ पोर्टल तैयार हो जायेंगे।

फिर आया कि कंप्यूटर की शिक्षा भी होनी चाहिये। आज सात हजार विद्‌यालयों में आईसीटी लैब है और 407 विद्‌यालयों में स्मार्ट क्लासरूम हैं और 363 में प्रक्रिया में हैं। आगामी वर्ष में हमारा लक्ष्य है कि हम धीरे-धीरे चरणबद्‌ध तरीके से बाकी छह हजार स्कूलों में आई.सी.टी. लैब बनाएंगे। कई जगह तो हम भामाशाह की योजना से या अन्य सहयोग से कर रहे हैं। इसमें आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हम आज दो हजार विद्‌यालयों में सैटेलाइट से अंग्रेजी, विज्ञान और गणित पढ़ा रहे हैं। हमारा सारा पाठ्‌यक्रम ई-ज्ञान पोर्टल पर उपलब्ध है। ऐसी तकनीक के साथ हमने बच्चों को और सिस्टम को डवलप किया है।

फिर हमारी डाइट्‌स भी हैं। डाइट्‌स में ई-लर्निंग के लिए वर्चुअल क्लासरूम प्रारंभ किए हैं और ये 11 स्थानों पर प्रारंभ भी हो गए हैं। फिर लगा कि हमें बार-बार लोगों को प्रशिक्षण के लिए बुलाना होता है, बार-बार अधिकारियों को बुलाना होता है इसलिए 12 जिलों में हमने डिजिटल लर्निंग सोल्युशन रूम की स्थापना की ताकि यहीं से बैठे-बैठे संस्था प्रधानों को हम प्रशिक्षण भी दे सकें, उनसे बात भी कर सकें और मेरा शिक्षक भी कम्प्यूटर जाने। उनके लिए भी हमने ट्रेनिंग चलाई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कहते हुए प्रसन्नता होती है कि डेढ़ लाख शिक्षकों ने कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और धीरे-धीरे हम औरों के लिए भी करेंगे। इसी डिजिटलाइजेशन में निजी विद्‌यालयों की मान्यता के लिए कई बार शिकायत रहती थी कि मान्यता के लिए बी.ई.ओ. के पास जाना पड़ता है, डी.ई.ओ. के पास जाना पड़ता है, डी.डी. के पास जाना पड़ता है। हमने कहा, नहीं। इन सब प्रकरणों की विचित्र स्थिति थी। लंबित होते थे। इससे निजात दिलाने के लिए हमने सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया।

फिर मेरा बालक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेगा, उत्कृष्ट आयेगा, संस्कार भी लेगा और प्रार्थना के समय उसको संस्कार मिले। शरीर से वह स्वस्थ हो। उसका एकाग्र मन बने। इसलिए आधे घंटे की प्रार्थना में उसके लिए योग, सूर्य नमस्कार, ध्यान, अनमोल वचन का समावेश किया है। योग

(श्री वासुदेव देवनानी)

तो सर्वोपरि है। योग पर किसी की कोई राजनीति नहीं। हालांकि, सूर्य नमस्कार पर कुछ मित्रों ने कहा। मैंने उस समय उनसे निवेदन किया। अरे भई, हम सब सूर्य की किरणों से रोशनी लेते हैं। कुछ लोग चंद्रमा के आधार पर अपना त्यौहार मनाते हैं। चंद्रमा से प्रेम करेंगे और सूर्य से घृणा करेंगे, यह कैसे चलेगा? इसलिए सूर्य भी हमारे लिए आराध्य देव है। सूर्य नमस्कार, केवल सूर्य को नमस्कार करना नहीं है। यह तो एक व्यायाम है। इस व्यायाम को बालक करके, पाँच मिनट ध्यान करके जब क्लास में जाता है तो उसका ध्यान भी क्लास में एकाग्र होता है। यहीं तक सीमित नहीं रहे। मेरा बालक जब स्कूल आए। स्कूल में उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखे। क्या वह सीरियस जाए? इसके लिए हैप्पीनेस इंडेक्स। उसके लिए माननीय प्रधान मंत्रीजी ने भी कहा था। माननीय मुख्य मंत्रीजी के माध्यम से भी कहलवाया और वैसे भी उन्होंने जानकारी भेजी कि हर स्कूल के पोर्च में एक बड़ा कांच लगे। बालक आए और अपने बाल देखे और उसकी जेब में कंघा हो तो देखे और हंसता हुआ अपनी क्लास में जाए। मुस्कुराता हुआ जाए और फिर उसे पता भी लगे कि मेरे यहां पर अध्यापक कौन-कौन हैं। कई बार ये शिकायतें आती हैं। उन सारे अध्यापकों के फोटो वहां पर लगे हुए हैं। यह हमने सारे स्कूलों में कर दिया है। इस प्रकार का एक प्रयोग किया है।

कुछ लोग कह रहे थे कि साहब कमरे नहीं बन रहे हैं और कहीं टॉयलेट्स नहीं हैं। कहीं कुछ नहीं है। मैं आज सदन के सामने विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आज राजस्थान देश का पहला राज्य है, जिसमें सारे स्कूलों के अंदर बच्चे और बच्चियों के टायलेट्स बन चुके हैं। उसकी सफाई की बात आई है। सफाई के लिए भी मेरे एस.एस.ए. ने हर स्कूल को पाँच सौ रुपए प्रति महीने से पाँच हजार रुपए की उसमें व्यवस्था की है और बाकी जगह सीनियर सैकण्डरी में छात्र कोष से वे व्यवस्था कर रहे हैं। यह ठीक है किपाँच सौ रुपए कम हैं, लेकिन धीरे-धीरे हम वहां की व्यवस्थाएं ठीक कर रहे हैं। शुरुआत तो की है। यहां तो शुरुआत ही नहीं थी। टायलेट्स ही नहीं थे, सफाई नहीं थी। बच्चियां नहीं आती हैं। इसलिए बच्चियों का नामांकन इस कारण बढ़ा है।

इसलिए जो गैप बताए, बिल्डिंगों के गैप। बड़े जोर-शोर से कह रहे थे

(श्री वासुदेव देवनानी)

कि साहब खुले में स्कूल चल रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल 0.78 परसेंट स्कूल खुले में चल रहे हैं। इसको स्वीकार करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 98.25 परसेंट के पास स्वयं के भवन हैं और 1.75 परसेंट के किराये के भवन हैं। केवल 0.78 परसेंट हैं। उनकी चिंता हैं, वे भी हमारे बच्चे हैं। उस गैप को ठीक करने का हम प्रयत्न करेंगे।

जहां तक इन टायलेट्स और सुविधाओं की बात है। टायलेट्स 100 परसेंट स्कूलों में हैं और जो ड्रिंकिंग वॉटर है, वह 2.48 परसेंट स्कूलों में नहीं है। वे दो स्कूल, चार स्कूल, पाँच स्कूल गिना सकते हैं। कमी है और यह कमी वर्षों से चल रही है। केवल हमने नहीं की कि वहां व्यवस्था थी और हमने हटा दी हो। यह काम धीरे-धीरे साफ नीयत से सब होते हैं। आप भी आइये, सहयोग कीजिए और आप और हम सब मिलकर करेंगे। बच्चे आपके या हमारे नहीं है, बच्चे किसी पार्टी के नहीं होते, बच्चे हम सबके हैं, उसकी व्यवस्था करें।

हां, बिजली में हम जरूर अभी पीछे हैं। उसके लिए भी इस साल 'दीनदयाल ज्योति योजना' के अंतर्गत हमने काम शुरू किया है। प्राइमरी में 4 हजार 35 स्कूलों में हम बिजली दे चुके हैं और बाकी की लगभग तीन हजार स्कूलों के लिए हमने पैसा भी सैंक्शन किया है। धीरे-धीरे हम उन स्कूलों में भी बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार इस सत्र तक हम उत्कृष्ट विद्यालय और आदर्श विद्यालय में सबमें बिजली की व्यवस्था कर देंगे।

जहां तक 'रमसा' की बात है। ठीक है, स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं, कमरे चाहिए। इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन आपके पाँच वर्षों में आपने केवल 98.57 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य कराए, जबकि हमारी सरकार ने इसके लगभग दस गुना 914.95 करोड़ रुपये का आधारभूत ढांचा खड़ा कर दिया। यह ठीक है कि और आवश्यकता है। इसको स्वीकार करने में हर्ज नहीं है। अभी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन दस गुना। फिर हम कहते हैं कि साहब कमरे नहीं हैं, बाहर बैठ रहे हैं। आलोचना करना सरल है। आलोचना की जा सकती है। अपना धर्म निभाने के लिए की जा सकती है। लेकिन जरा अपने सीने पर हाथ रखकर तय करो कि आखिर यह जो अवस्था है, वह किसी एक

(श्री वासुदेव देवनानी)

पार्टी द्वारा डवलप नहीं की गई। यह व्यवस्था है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। आप और हम सब मिलकर इन व्यवस्थाओं को सुधारेंगे।

बालकों को गुणवत्तापूर्ण और संस्कारी शिक्षा देना आपका और हमारा सबका संयुक्त काम है। इसलिए हमारे आगे कदम बढ़े और बालक स्कूल भी आ गया। पढ़ाई भी कर रहा है, लेकिन 12वीं के बाद क्या करेगा? जरा, उसकी व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो। कौशल विकास की आलोचना हो सकती है, लेकिन 670 विद्यालयों में हमने व्यावसायिक शिक्षा शुरू की है। उसमें 50 हजार 500 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। 9वीं से शुरू करते हैं। 12वीं तक इसमें 12 ट्रेड्स हैं, जिसमें उनको अलग-अलग व्यावसायिक शिक्षा दे रहे हैं और इस बजट घोषणा में माननीय मुख्य मंत्री ने और 50 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की है, जिसके कारण विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 78 हजार हो जाएगी।

एक मुद्दा बड़े जोर शोर से कहा गया।शिक्षकों की कमी के साथ ही जोड़ता हूं। जब यह दायित्व आया तो बेचारे शिक्षकों के मन में बड़ी पीड़ा थी। वर्षों से उनका प्रमोशन नहीं हुआ। अब जब प्रमोशन नहीं करोगे तो कैसे मन लगाकर पढ़ाएगा? हर शिक्षक का जो ड्यू है, वह उसे सही समय पर मिले। हर शिक्षक और शिक्षक संगठनों की हमेशा यह मांग रहती थी कि 'पदोन्नति दो, समय पर पदोन्नति हो' और मुझे भारतीय मजदूर संघ का एक ध्येय वाक्य भी याद आता है। वे कहते हैं - 'राष्ट्र हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम' मैं अपने शिक्षक साथियों को कहता हूं- 'शिक्षा हित में करो काम, पूरा प्राप्त करो सम्मान' यानी उसको पूरा सम्मान देंगे। उसके पूरे काम का सम्मान मिलेगा तो समाज उसके प्रति नतमस्तक होगा। काम के लिए वे पूरा दाम देंगे। यही इसलिए मैंने जोड़ा। 'शिक्षा हित में करो काम, काम का देंगे पूरा दाम, पूरा प्राप्त करो सम्मान। इस प्रकार से हमने यह आगे बढ़ाई है।

नई नियुक्तियों की बात चली है। जैसे कहा, हमारी मंशा साफ है। नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है। कहीं-न-कहीं कुछ कानूनी अड़चनों के कारण, मुझे लगता है कि आगामी एक-दो महीनों में हम इन अड़चनों को दूर करेंगे। 12 हजार 948 लैक्चरर के पद काउंसलिंग के लिए तैयार पड़े हैं। जैसे ही

(श्री वासुदेव देवनानी)

कानूनी अड़चन दूर हुई, अगले दिन हम उनकी नियुक्तियां कर देंगे। 228 सैकण्ड ग्रेड और 6 हजार 468 सैकण्ड ग्रेड की परीक्षा अभी आर.पी.एस.सी. ले रही है। 6 हजार 468 की अर्थना हम अभी और भेज रहे हैं।

1994 के बाद एक भी लाइब्रेरियन की नियुक्ति नहीं की है, इसलिए 562 लाइब्रेरियन की नियुक्ति और 1716 प्रयोगशाला सहायक हैं, इनमें भी 1997 के बाद एक भी नियुक्ति नहीं की। इनको आगे किया। इनकी परीक्षा हो चुकी है। परीक्षा के परिणाम अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा आने हैं। रीट के थर्ड ग्रेड के 15 हजार बैठे हैं, उसमें टी.एस.पी. एरिया या अन्य कुछ कारण से परेशानी है, जिसको हम हल कर रहे हैं। 2012 और 2013 की चर्चा हुई। 2012 के कोर्ट के सारे निर्णय आ गए हैं और उस निर्णय में दो हजार अध्यापक और मिलेंगे, लेकिन उसमें कानूनी अड़चन से सारी मेरिट नई बनी है, उससे कुछ अध्यापक बाहर भी जा रहे हैं। हमारी मंशा है कि काई बाहर नहीं जाए। इसके लिए हमने सारा कानून परीक्षण करवाने के लिए भेजा है, इसलिए देर हो रही है, बाकी हम देर नहीं कर रहे हैं। 2013 के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनी है। मुझे लगता है कि जल्दी वह निर्णय करेगी, उससे 8 हजार विद्यार्थियों को, जिन्होंने परीक्षा दी है, उनका भी पद स्थापन करेंगे। इस प्रकार 53 हजार नई नियुक्तियां पाइप लाइन में हैं, जिसको हम बहुत जल्दी पूरा करने जा रहे हैं।

(23.00 बजे)

प्रमोशन की बात चली। मैंने जैसा बताया, 2013 को याद करो कि डीईओ कितने थे। केवल 44 डीईओ थे और पद 142 थे। ये वर्षों से चल रहे थे, कभी उस ओर सोचा ही नहीं कि हमें डीईओज भी, कोई अधिकारी चाहिए। हमने आकर रिलैक्सेशन लेकर पूरे डीईओ के पद भरे। आज राजस्थान में एक भी डीईओ का पद खाली नहीं है।

डी डी के बारे में, मैं घोषणाओं के समय घोषणा करता हूं कि अगले वर्ष एक भी डी डी का पद खाली नहीं रहेगा। उनकी हम डीपीसी करने जा रहे हैं। ...(व्यवधान)... 232 अरब रुपये की मांग है। 232 अरब रुपये जितना जवाब भी तो....

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): जवाब इतना बढ़िया है। यह 22 तारीख से प्रारम्भ होकर 23 तारीख पर खतम होना चाहिए।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): प्रमोशन की बात आई। हमने कुल 87 हजार 27 पदोन्नतियां दी हैं। ये उपनिदेशक से लेकर वरिष्ठ लिपिक तक बताइये, कितनी पदोन्नतियां दीं?

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, उन्होंने जो फरमाया वह आपने सुना?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): क्या? नहीं, बताएं।

श्री उपाध्यक्ष: कि 22 से लगाकर 23, लेकिन आप भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, वह तो तारीख सूर्य उदय पर बदलेगी।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अगले साल के लिए भी रखो।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): अगले साल के लिए और नई मिलेगी आपको। यहां कमी नहीं है। जितने महीने, वर्तमान इसका काल है, हर महीने एक नया काम होगा।

पिछले तीन वर्षों में राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों ने अभूतपूर्व काम किया। हमेशा शिक्षकों के सम्मान में कहीं न कहीं यह कंजूसी रहती थी कि केवल राज्य स्तरीय शिक्षक का सम्मान जयपुर बुलाकर, सलेक्टेड शिक्षकों का करते थे। फिर हमने तय किया जिला स्तर पर भी सम्मान होगा, ब्लाक स्तर पर भी सम्मान होगा और स्कूल में भी शिक्षकों का सम्मान होगा। जिस गुरु का सम्मान होगा, विद्यार्थी अपने आप उस वातावरण में पढ़ने के लिए लगेंगे। शिक्षक का सम्मान कई बार इसलिए कम होता था कि या तो उसकी पदोन्नति नहीं हो या पोस्टिंग के लिए लोगों के चक्कर काटता था। हमने कहा कि उसका सम्मान बढ़े, किसी भी राजनेता या राजनीति के..

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): विधान सभा में भी गुरु का सम्मान होगा। ...(व्यवधान)...

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): हमने एक पारदर्शिता और शिक्षक के सम्मान के साथ जुड़े काउंसिल, पोस्टिंग का काउंसिल सिस्टम शुरू किया। ...(व्यवधान)... तय करो, कल से फिर आपके भी भाषण पढ़े हुए मान लिए जाएंगे। ऐसे मानने वाला नहीं हूं। उपाध्यक्ष महोदय जितनी अनुमति देंगे, उतना मैं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, आप बिलकुल विस्तार से बताइये। आपके पास पूरा समय है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने पदोन्नतियां दीं और पदस्थापन भी उनकी इच्छा के अनुसार किया। बिलकुल पारदर्शी सिस्टम। आप एक गेट से आइये, अपनी मैरिट के अनुसार आइये या सीनियोरिटी के अनुसार आइये, सारे स्थान वहां पर जितने हमने दिखाए, और खुद चयन करिए और चयन करने में यह नहीं कहा कि कहीं हो। जो बेचारे दिव्यांग हैं, सबसे पहले उनको, उसके बाद विधवा और परित्यक्ता को, उसके बाद महिलाओं को, उसके बाद पुरुषों को, इस प्रकार का काउंसिल सिस्टम किया। सारे भारतवर्ष में इसकी सराहना हुई है। केन्द्रीय एमएचआरडी मंत्री ने आकर कहा है बाकी राज्यों को भी, राजस्थान को फोलो करो। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा पारदर्शी कदम नहीं हो सकता, जो हमारी टीम ने उठाया है। पहले राजनीतिक भेदभाव से...(व्यवधान)... अभी आधा भी नहीं हुआ है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कितने पन्ने और हैं, पन्ने ले लो। ले लो, पास हैं, ले लो।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप चिंता मत करो, इतना कमजोर नहीं हूं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): 40 पेज और है, अभी चिंता मत करो। अभी 40 ही हुए हैं। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सबसे ज्यादा दु:खी तो सुखराम जी हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): जितना बोलोगे उतना और लेट चलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, कई बार इन सारी बातों को मैं अपने शिक्षक साथियों को हमेशा कहता हूं और आज सदन में इसको दोहरा रहा हूं।

"सारी धरा भी साथ दे तो और बात है।
तू जरा भी साथ दे और बात है।
चलने को चलते हैं लोग एक पाँव से भी,
दूसरा भी साथ दे तो और बात है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

मैं सदन में अपने मित्रों से राजस्थान की शिक्षा में सुधार के लिए किए गये कामों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हीं शब्दों के साथ आह्‌वान कर रहा हूं, ‘‘आओ साथ चलें, आओ साथ चलें’’।

स्टाफिंग पैटर्न, यह अभी बात चली कि आपने कैसे यह सारा तय किया, गुणवत्ता कैसे आई? उस गुणवत्ता को रखने के लिए हमने तय किया। पहले जैसा कहा कि शिक्षक या अध्यापक नहीं, विद्‌यार्थियों के हर स्कूल के लिए पद तय कर लिए। मुझ आश्चर्य है कि आज तक पता नहीं यह बात ध्यान क्यों नहीं आई कि प्राइमरी के अंदर भी विषय अध्यापक लगने चाहिए। थर्ड ग्रेड का टीचर सोशल साइंस का है, गणित पढ़ा रहा है। सोशल साइंस का है,अंग्रेजी पढ़ा रहा है। कई बार अखबारों में आता था और हम सब आपस में भी बात करते थे। मैं भी कहता था कि पांचवीं वाले को नाम लिखना भी नहीं आता। पांचवीं वाले को पहाड़ा भी नहीं आता। यह इसलिए था कि सब्जैक्ट टीचर नहीं थे। हमने तय किया कि हम सब्जैक्ट टीचर लगाएंगे। स्टाफिंग पैटर्न बनाया। उसके कारण से कई बार सैटअप परिवर्तन भी किया। पंचायती राज से वर्षों तक लोग शिक्षा विभाग में नहीं आए। हमने सैटअप चेंज करके, उसमें लेवल वन और लेवल टू तय किया। लेवल टू में बीएड वाले हैं, लेवल वन में पांचवीं एसटीसी के हैं, वे एक से पाँच में पढ़ाएंगे। इन सबको हमने तय किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जिस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है वह मानव संसाधन के मामले में सबसे बड़ा विभाग है। बजट आवंटन के मामले में सबसे बड़ा विभाग है। जिम्मेदारी के मामले में भी सबसे बड़ा विभाग है। कहा जाता है घर में किए गए पाप मंदिर में और मंदिर में किए गए पाप किसी तीर्थ स्थान पर धोए जा सकते हैं, पर शिक्षा के मंदिर में किया गया पाप किसी भी तीर्थ स्थान पर नहीं धुलता है और ना ही कम होता है। यह जिम्मेदारी हमारे शिक्षक बखूबी समझते हैं। इसलिए पूरी प्रतिबंद्‌धता, पूरी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा के साथ समाज को श्रेष्ठतम देने का काम कर रहे हैं।

हमारे कई माननीय सदस्य कहते हैं कि गांव के लोगों को आप आगे कैसे पढ़ाओंगे आप तो हिन्दी मीडियम में पढ़ा रहे हो। हमने कहा कि हम

(श्री वासुदेव देवनानी)

हर ब्लाक लेवल पर मॉडल स्कूल भी खोलेंगे जो सीबीएसई से संबंधित होगा, इंग्लिश मीडियम को होगा, इसके लिए माडल स्कूल योजना भारत सरकार के सहयोग से की। आज प्रदेश में, सारे माडल स्कूल पिछले तीन वर्षों में प्रारम्भ किए। योजना इनके समय आई, एक भी स्कूल नहीं खोल पाए। जो भी परिस्थितियां रहीं, मैं उनकी गहराई में नहीं जाना चाहता। लेकिन पिछले तीन वर्ष के अंदर 132 माडल स्कूल संचालित कर रहे हैं। इनमें 18 हजार 622 बालक और 17 हजार 385 बालिकाएं, कुल 36 हजार 13 विद्यार्थी नामांकित हैं। इनको स्वामी विवेकानंद माडल स्कूल का नाम दिया है। यहां सीबीएसई का पाठ्यक्रम लागू किया है। 01 अप्रैल, 2017 से अजमेर के श्रीनगर में और अलवर के कठूमर में हम माडल स्कूल प्रारम्भ करने जा रहे हैं। ...(व्यवधान)... बाकी जहां बन चुके और भी बनाएंगे। इस साल का मैंने अभी 132 का ही हवाला दिया।

बालक आधुनिक तकनीक के साथ जुड़े। बालक को तकनीकी ज्ञान हो, इंटेलिजेंट बालक है, गरीब है, कैसे जानेगा? तो हमने लेपटोप वितरण शुरू किया। लेपटोप वितरण में हर प्रतिभा को सम्मान मिले इस उद्देश्य से गत दो सत्रों में 43 हजार 204 मेधावी विद्यार्थियों को लेपटोप दिया है। इस बार 27 हजार 900 लेपटोप का वितरण शुरू हो गया है। इस तरह कुल मिलाकर 71 हजार इंटेलिजेंट बालकों को लेपटोप मिल रहा है। इंटेलिजेंट में भी हमने मेरा और आपका नहीं किया। हमने बोर्ड की मैरिट देखी। आठवीं की बोर्ड उसके पहले 6 हजार, दसवीं का बोर्ड उसके पहले 6 हजार, 12 वीं का बोर्ड उसके पहले 6 हजार, 18 हजार तो यह। जब इन 18 हजार पर विचार किया तो ध्यान आया कि कई ऐसे पिछड़े जिले हैं जिनका बालक शायद इन 6 हजार में नहीं आ सकें...

इसलिये कहा कि प्रत्येक जिले के भी सौ-सौ बालक, जो पहले मैरिट में आयेंगे, हम उनको भी देंगे। 33 जिले, इन 33 जिलों के 3300 आठवीं के, 3300 दसवीं के और 3300 बारहवीं के, इस तरह 9900 वे और 18000 ये, 27900 बालकों को हम लेपटोप देने के लिये जा रहे हैं। अब सारे बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों दसवीं के लिये तय किया कि जन प्रतिनिधि वही बनेगा, जो आठवीं और दसवीं पास होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मंत्रीजी। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह आप बार-बार पानी पी रहे हैं, पहले अशोकजी गहलोत तीन-चार बार गिलास से अलग-अलग पानी पीते थे। यह आप देख लेना, इस बात को सोचना आप, हां।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): उसकी चिंता आप मत करो। राजस्थान के अन्दर स्टेट ओपन स्कूल हैं। वह स्टेट ओपन स्कूल, वसुन्धराजी की पूर्ववर्ती सरकार में हमने प्रारम्भ की थी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो जन भावना जगी है पढ़ाई की, इन स्टेट ओपन स्कूल में नामांकन एक लाख से ऊपर हो गया है, भूतो न भविष्यति। आज तक कभी दस हजार, बीस हजार, पच्चीस हजार नामांकन रहता था, उसकी जगह एक लाख नामांकन हुआ।

फिर वे कागाजी कह रहे थे कि सिन्धी भाषा के लिये कुछ नहीं किया। तो दसवीं की जो ओपन स्कूल है, उसमें दसवीं में सिन्धी और बारहवीं के अन्दर संस्कृत विषय का भी हमने समावेश किया है। हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू पहले से ही है। उसमें ये दो भाषाएं हमने और उनके साथ जोड़ी हैं। उसमें जो टॉपर्स आते हैं, उनको एकलव्य पुरस्कार, और जो बच्ची फर्स्ट आती है, उसको मीरा पुरस्कार हम दे रहे हैं और यह जो भवन है, उसका नाम भी एकलव्य भवन रखा है। कारण, एकलव्य ने बिना गुरु के शिक्षा प्राप्त की थी। यह भी ओपन स्कूल, केवल पत्राचार पाठ्यक्रम में से पढ़ते हैं। इस भवन का नाम भी हमने एकलव्य रखा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपका गुरु कौन है?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मेरा समाज है और आप हो। बालिका सशक्तीकरण में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बेटियों के बारे में कहना चाहूंगा,

'ओस की एक बूंद-सी होती हैं बेटियां,
स्पर्श अगर खुरदरा हो, रोती हैं बेटियां,
रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को,
दो-दो कुलों की शान होती हैं बेटियां'

उपाध्यक्ष महोदय, स्वामी विवेकानन्दजी ने कहा था, कि अच्छी नारी

(श्री वासुदेव देवनानी)

शक्ति एक अच्छा राष्ट्र बना सकती है। इससे प्रेरित होकर हमने बालिका शिक्षा में अनेक नवाचार किये हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे यहां जो बालिका 75 प्रतिशत अंक लाती है, उसे गार्गी पुरस्कार देते हैं। आपने कहा, तीन वर्षों में, दो वर्षों में क्या परिवर्तन आया। 2014-15 के अन्दर टोटल 44 हजार बच्चियां ऐसी थीं, जिनके 75 प्रतिशत से अधिक अंक आये। 2015-16 के अन्दर जो बच्चियां आईं वे 68 हजार हुईं। इस वर्ष इन बच्चियों की संख्या बढ़कर 91 हजार हुई हैं। परिणाम आने पर ये शायद एक लाख को क्रॉस करेंगी। एक लाख बच्चियां 75 प्रतिशत से ऊपर मेरे इस राजस्थान में आयें, इससे ज्यादा और क्या परिवर्तन बच्चियों के लिये आ सकता है, आप जरा सोचिये।

फिर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 'हमारी बेटी योजना', जिसमें जो दो टोपर्स बेटियां दसवीं की हैं, मैरिट में आने वाली, उनको वित्तीय सहायता दी। माननीय मुख्य मंत्रीजी को लगा कि दो बेटियां तो हैं, लेकिन बी.पी.एल. परिवार की भी बेटी होनी चाहिये। तो हर जिले से तीन, इस तरह से 99 बेटियां, दो वर्षों में 198, और इस बार 99 और जुड़ करके इस योजना से वे लाभान्वित होंगी।

फिर आजकल कई बार बच्चियों के साथ घटनाएं होती हैं। हम भी कई बार उसकी चर्चा करते हैं। इसलिये उनको आत्म-सुरक्षा की ट्रेनिंग मिले, गत वर्ष तक 04 लाख 37 हजार बालिका लाभान्वित हुई थीं। आगामी वर्ष, अकेले इस वर्ष में 03 लाख 60 हजार छात्राओं को हम यह प्रशिक्षण देंगे ताकि आत्मविश्वास का भाव उनमें जग सके।

मुख्य मंत्री राजश्री योजना आ गई। जो कई सदस्यों ने कहा, इसलिये इसको रिपीट नहीं करूंगा कि जन्म लेने से बारहवीं तक पचास हजार रुपये उसके खाते में जाएं। कभी आपने कोई ऐसी योजना बनाई? यानी जन्म ले, ढाई हजार रुपये; पहली वर्षगांठ मनाये, ढाई हजार रुपये; पहली कक्षा में जाये, चार हजार रुपये; छठी कक्षा में जाये, पाँच हजार रुपये; दसवीं में जाये तो 11 हजार रुपये; बारहवीं तक जाये तो 25 हजार रुपये; पचास हजार उसके खाते में जमा, इतना सारा।

आगे फिर इन बच्चियों को पढ़ाने में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हमने

(श्री वासुदेव देवनानी)

लागू की। नवीं की हर बच्ची को हम साइकिल देते हैं। इस बार लगा कि हमारे माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे, पता नहीं उनको हर जगह कहीं न कहीं भगवाकरण या कोई बात याद आती है। साइकिलों का कलर या ड्रेस चेंज होती है तो महिलाओं से पूछो तो क्या उनको ओरेंज कलर पसन्द नहीं आता? सबसे ज्यादा उनकी पसंद वही है और काली साइकिल वह पसंद ही नहीं करती थी कि उसके भाई की है या उसके खुद की है। इस बार साइकिलों का कलर भी हमने ओरेंज और भगवा कर दिया है, तीन लाख साइकिलें आ गयी हैं। ड्रेस भी, ड्रेस के बारे में यह है कि सरकारी स्कूल का विद्यार्थी, नीली कमीज, खाकी निकर बीस साल से पहन रहा है। उसको पहनने में क्या, आपको रोज ड्रेस चेंज करना ध्यान में नहीं आता। नहीं, वही का वही सातों दिन पहन लिया जाये, एक महीने तक पहन लो। वह सारे मेरे बच्चे बीस साल से पहन रहे थे। यदि यह सोचा कि ड्रेस परिवर्तन हो और ड्रेस में कत्थई रंग की पेण्ट और हल्के भूरे रंग की शर्ट, अब इसमें कहां आर.एस.एस. आ गया, जो मेरे एक मित्र कह रहे थे। यह इसमें कहीं नहीं, प्राइवेट स्कूल के भाव से उनको लगेगा कि मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं भी किसी से कम नहीं हूं। यह आत्मविश्वास का भाव उसमें निश्चित रूप से जगेगा। इन बच्चियों के लिये ट्रांसपोर्ट वाउचर, साइकिलें भी पाँच लाख 36 हजार तो बांट चुके और इस बार तीन लाख का वितरण शुरू हो गया है।

अब ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम में कक्षा नौ से बारह में पढ़ने वाली बच्चियां, जो पाँच किलोमीटर दूर से आती हैं, कैसे आयें। कई बार स्कूल खोलने की बात आती है, कई बार गांव दूर है। इन सबको आने-जाने का किराया, जिसे ट्रांसपोर्ट वाउचर कहते हैं, इस समय 45453 छात्राएं, उससे लाभान्वित हो रही हैं। अब वे कैसे दें। यह नहीं कि वे अपने जेब में से खर्चा करें। एक महीना पहले उसके खाते में हम पैसा जमा करा देते हैं, पच्चीस दिन के हिसाब से। जितने दिन आयेंगी, वह कट करके बाकी अगले महीने की और जमा होगी। इस प्रकार से विवेकानन्द मॉडल स्कूल में तो इसको और रिलेक्स कर रखा है। दो से पाँच किलोमीटर से आने वाली छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर देते हैं। उसका भी लाभ 14534 ये बच्चियां ले रही हैं। बच्चियों के सशक्तीकरण के लिये शारदा छात्रावास चल रहे हैं। उसमें अभी

(श्री वासुदेव देवनानी)

9687 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। कस्तूरबा विद्यालय की बात चली, उसमें 19835 छात्राएं लाभ ले रही हैं। इन बालिकाओं को आपके समय भोजन के 835 रुपये मिलते थे और अब मिलते हैं 1500 रुपये। उनके छात्रावास में आर.ओ., कूलर, एल.ई.डी., टी.वी., गीजर, इन्वर्टर, डैजर्ट कूलर, बिस्तर, सब उपलब्ध हैं। अगर कहीं नहीं हों तो मुझे बता देना। कहीं कमी होगी तो उसे भी हम ठीक करेंगे, पूरा करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का गौरवशाली इतिहास और भविष्य सुन्दर हो, इसलिएं वर्तमान में धरातल पर खड़ा होकर हमें गौरवशाली अतीत और सुखद भविष्य का एक सेतु काम करना होगा। इसलिये मुझे लगता है कि राजस्थान के हर व्यक्ति के जीवट को परिलक्षित करते हैं, इसलिये 'काल के कपाल पर लिखता-मिटाता हूं, मैं गीत नये गाता हूं, मैं गीत नये गाता हूं'।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कल 11 बजे प्रश्नकाल तक चलने दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, साहब, इसमें? तैयारी है साहब, इनकी।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मेरा अभ्यास है। फिर, एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गुणवत्ता की जब बात चली। कक्षा एक से लेकर आठ तक फेल न होने की व्यवस्था, मैंने कहा, न बच्चा स्कूल जाता है, न अध्यापक की कोई रेस्पोंसिबिलिटी होती है, न अभिभावक को कोई चिंता होती है कि बालक स्कूल गया कि नहीं गया। राजस्थान पहला प्रदेश है जिसने कक्षा आठवीं और कक्षा पांचवीं की बोर्ड की परीक्षा की व्यवस्था की है।

दो वर्ष से हम आठवीं की परीक्षा करवा रहे हैं। इस साल पहली बार पांचवीं की बोर्ड की भी परीक्षा हो रही है। इससे निश्चित रूप से गुणवत्ता का स्तर होगा लेकिन इसमें ड्रोप आउट्स की कमी नहीं होगी। इसमें हमने व्यवस्था की है। पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षा होने पर, गुणवत्ता में सुधार आठवीं में आना तो शुरू हुआ है, पांचवीं के होने से और आयेगा। यदि सुझाव आया है तो तीसरी में भी लोकल लेवल पर अध्यापक उसकी परीक्षा लें। मूल्यांकन तो करें कि मेरे अध्यापक ने क्या पढ़ाया। उसमें यदि उसकी

(श्री वासुदेव देवनानी)

'डी' ग्रेड या 'सी' ग्रेड आयी तो अध्यापक से भी उसका एक्सप्लेनेशन कॉल निश्चित रूप से किया जा सकेगा। अध्यापक ने क्यों नहीं पढ़ाया, जब बालक स्कूल आ रहा है तो? इन सबकी व्यवस्था में जब चला तो लगा कि पंचायत में जो प्राइमरी स्कूल हैं, अपर प्राइमरी स्कूल हैं, उनकी मोनिटरिंग नहीं होती। यह बात सही है। मैं इसको स्वीकार करता हूं।

हमारी सदस्या ने बी.ई.ओ. के बारे में उठाया। बी.ई.ओ. के पद हम समाप्त नहीं करने जा रहे हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। हमने इस व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए पंचायत एजुकेशन आफिसर बनाये। जो भी 12वीं का स्कूल है क्योंकि एक डी.ई.ओ. के पास हजार स्कूल होते हैं, नौ सौ स्कूल होते हैं। उनकी वह मोनिटरिंग चाहे तो भी साल भर में नहीं कर पाता। उसके नीचे एक ढांचा होना चाहिए, इसके लिए आदर्श विद्यालय का प्रिंसिपल है या सीनियर स्कूल का प्रिंसिपल है, वह वहां पर पंचायत एजुकेशन आफिसर कहलाएगा और पी.ई.ओ. का काम होगा, वह अपनी ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी प्राइमरी स्कूल होंगे, जितनी भी मिडल स्कूल होंगे, उन सबकी मोनिटरिंग करेगा कि आज बराबर अध्यापक पहुंचता है या नहीं? पढ़ाई कैसे होती है? सबकी मोनिटरिंग करेगा और साथ में उन अध्यापकों की छुट्टियां भी सेंक्शन करने की पावर उसको होगी। उन अध्यापकों की सैलेरी भी वहां पर बनेगी ताकि वह अकाउंटेबल बने और यदि डी-सेंट्रलाइजेशन होगा तो निश्चित रूप से वहां की सुदृढ़ता होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक राजनीति में जिस विचार को अंगीकार मैंने किया है, मुझे गर्व है कि उसी विचार से निकला हुआ व्यक्ति आज देश के प्रधान मंत्री के पद पर पहुंच कर भी अपने आपको प्रधान सेवक के रूप में परिभाषित करता है। हमारा लक्ष्य राज करना नहीं है। हमारा लक्ष्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। मुझे खुशी है कि समाज में सकारात्मक बदलाव वाला विभाग शिक्षा विभाग है और माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस विभाग की महती जिम्मेदारी मुझे दी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सुदूर पूर्व ढाणियों से लेकर महानगर की रफ्तार में सबसे आगे हमारी राजधानी जयपुर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की चिंता करने का, उनके सुखद भविष्य की नींव गढ़ने का काम

(श्री वासुदेव देवनानी)

हमारे विभाग के पास है। मैंने निश्चित रूप से कहा कि मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, इसको मैं कोई छिपाता नहीं हूं। उस समय वहां शाखा में एक गीत बोला जाता है-

"पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना,
सब समाज को लिये साथ में, आगे है बढ़ते जाना"।

अब ये सारे आगे बढ़े, इसके लिए जन सहभागिता भी हो। सब काम सरकार, जैसा मैंने कहा कि समाज केंद्रित यहां पर शैक्षणिक व्यवस्था रही है। जब समाज केंद्रित शैक्षणिक व्यवस्था रही है तो समाज की सहभागिता भी रहे, इसीलिए भामाशाहों को प्रेरित करना और प्रेरकों को सम्मान करना यह 2014 में जहां केवल 13 करोड़ 68 लाख 79 हजार रुपये थी जबकि 2016 के अंदर 27 करोड़ 40 लाख 47 हजार रुपये विद्यालयों के विकास हेतु भामाशाहों ने दिये हैं। यह तो वह सूची है जिन्होंने 15 लाख से अधिक सहयोग किया है। नीचे पाँच लाख, दस लाख, दो लाख सहयोग करने वाले गिनेंगे तो 100 करोड़ से भी ज्यादा जन सहभागिता से लोगों ने सहयोग किया है। यह सब हमारे विश्वास का प्रतीक है और इसमें हमारी निगरानी रहे, यह खर्च तो हो रहा है लेकिन इस खर्च की निगरानी के लिए हमारे यहां पर व्यवस्था है। एस.एम.सी. एस.डी.एम.सी की और एस.एम.सी. और एस.डी.एम.सी. तो पहले भी बनी थी लेकिन इनकी बैठकें नहीं होती थीं या बैठकें होती थीं तो लोग नहीं पहुंचते थे। हमने तय किया कि अधिकांश ग्रामीण कब छुट्टी रखते हैं? अमावस्या को तो सारी एस.एम.सी. और एस.डी.एम.सी. की बैठकें अब अमावस्या को होने लगी हैं, किसी को कोई तारीख भी बताने की आवश्यकता नहीं।

और, इसके साथ हमने तय किया कि शैक्षणिक स्तर के बारे में यह जान सके। नवाचार कर सके, यह जो अभिभावकों को स्कूल से जोड़ना, प्राइवेट स्कूल में तो सुनते थे कि पेरेंट्स को बुलाते हैं, पेरेंट्स के साथ मीटिंग होती है। सरकारी स्कूल में कभी सोचा भी नहीं गया। हमने नया तय किया कि पेरेंट्स को भी बुलाएंगे। उन पेरेंट्स को बुलाने पर आपको जानकर आश्चर्य होगा या सुखद अनुभूति होगी कि अभी जो 16 जनवरी को पेरेंट्स-टीचर्स मीटिंग हुई थी, उसमें राजस्थान के स्कूलों में 38 लाख से ज्यादा

(श्री वासुदेव देवनानी)

अभिभावकों ने पार्टिसिपेट किया। जब अभिभावक जुड़ेंगे तो शैक्षणिक स्तर अपने आप ऊँचा उठेगा, बालक अपने आप पढ़ेगा और वह आगे आएगा इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक कवि की चंद लाइनें याद आ गयीं।

"चलो साथ तो चलो धूप भरी राह में,
सह लो धूप तो आओ साथ चले,
राह में है अंधियारा, बन सको विश्वास का पथ पर उजियाला,
आओ साथ चलो,
फूल कौन छोड़ता है राह में, तुम कांटे चुन सको तो,
आओ साथ चलो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब केवल विद्यार्थियों की बात नहीं रही। जैसा मैंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा में भी 1858 विद्यालयों में मेजर रिपेयरिंग का काम किया है। 2853 उत्कृष्ट विद्यालयों में गतिविधि आधारण के लिए कक्षा-कक्ष प्रारंभ किये हैं और माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान ने क्या किया। रमसा और एस.एस.ए. की बात आती है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि 40 परसेंट यदि जनरल देगा तो 60 परसेंट उस राशि में सरकार मिलायेगी। ऐसी जन सहभागिता से हमने कई कमरे बनवाये और मैं तो आप सबसे सहयोग चाहता हूं। आप सब इसमें सहयोग करें, भामाशाहों को लाएं, जन सहयोग लाएं, सरकार उसमें अपना कर्तव्य निभाएगी। विद्यार्थियों का केवल पढ़ाई के अंदर ही गुणगान नहीं हुआ। अभी हमारे सामाजिक अधिकारिता मंत्री मेरे साथ मैसूर स्काउट गाइड में चले। स्काउट गाइड में राजस्थान का 19 में से 17 प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान, सारे देश भर में उन्होंने प्राप्त किया। ऐसा है, मेरे राजस्थान का बालक जो अपने स्कूल में तो स्काउट का काम करता ही है लेकिन देश भर के अंदर उसने जिस प्रकार से अपना परचम फहराया है, मैं समझता हूं कि वह बहुत अलौकिक है।

और, इन सबके साथ आगामी वर्ष के अंदर हमने शिक्षक के परीक्षा परिणाम के भी कुछ मापदंड तय किये हैं। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम केवल पास होना नहीं माना जाएगा। उसमें 20 परसेंट सत्रांक भी जाते हैं। मैं टीचर्स को

(श्री वासुदेव देवनानी)

कहता हूं इसीलिए 80 प्रतिशत या उससे अधिक परीक्षा परिणाम होगा तो श्रेष्ठ परिणाम कहलाएगा और यदि 12वीं में 50 प्रतिशत और 10वीं में 40 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम होगा तो न्यून कहलाएगा और न्यून वाले के लिए फिर जिस प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं हैं, वह हम आगे करने वाले हैं और संस्था प्रधान के लिए भी आठवीं में यदि 50 प्रतिशत से अधिक डी-ग्रेड आता है, अध्यापक के लिए 60 प्रतिशत से अधिक डी-ग्रेड आता है तो इसको संतोषजनक नहीं माना जाएगा, उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही भी की जाएगी।

हम जहां सारी व्यवस्थाएं जुटा रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, अध्यापक को भी अकाउंटेबल बनाने की हमने योजना बनाई और उसके साथ श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को सक्षम स्तर से प्रशस्ति पत्र और न्यून परीक्षा परिणाम वाले शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने में भी हम पीछे नहीं रहेंगे।

फिर शिक्षकों की कमी, की बात आई। वास्तव में आपने यह कहा कि नहीं आ पाए। आपके समय भी नहीं आ पाए और अभी हमारे समय में भी कुछ रह रहे हैं तो एक नवाचार किया। इन दिनों बी.एड. और एस.टी.सी. विद्यार्थी करते हैं। उनको 20 सप्ताह, 16 सप्ताह की ट्रेनिंग लेनी होती है। वह ट्रेनिंग कहां पर लेता था, किसी को पता नहीं। सर्टिफिकेट लाकर कॉलेजों में सब्मिट कर देता था। हमने तय किया कि यह सारे बी.एड. वाले, सारे एस.टी.सी. वाले इस बार अपनी ट्रेनिंग सरकारी स्कूलों में लेंगे। जिसके कारण से एक लाख अध्यापक हमको चार महीने, पांच महीने के लिए मिलेंगे। इससे दोनों लाभ हुए। वह अध्यापक जो भविष्य में बनने वाला है, उसका स्कूल के साथ जुड़ाव हुआ। उसको सिस्टम भी ध्यान में आ गया और अध्यापकों की व्यवस्था हमारे यहां पर भी हो गयी। इस प्रकार से इन्टर्नशिप जो हमने की, उसमें यह पहली बार था, इसलिए कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां आईं, लेकिन वे आगे दूर होंगी।

अब एक नई योजना जिसमें मेरे बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा, जिसकी चर्चा अभी हुई, यहां पर हालांकि हमारे माननीय मंत्रीजी अजयजी किलक बैठे हैं, एक 'CLICK' योजना हमने तैयार की है। वह इनके नाम से नहीं है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

उसका नाम 'CLICK' है, Computer Literacy Initiative for Comprehensive Knowledge, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजकीय विद्यालय जो कक्षा 6 से 10 तक चलते हैं, उनमें यदि 200 विद्यार्थी हैं वहां पर हमने आर.के.सी.एल. के सहयोग से, प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्रों के सहयोग से एक स्वैच्छिक व स्व-वित्त पोषित 'CLICK' योजना लागू की है, जिसके आधार पर मेरे बच्चे कम्प्यूटर शिक्षा ले सकेंगे। हम राजकीय विद्यालयों में सबमें इंटरनेट की भी सुविधा प्रदान करने के लिए जा रहे हैं।

विद्युत की बात बहुत चली। हमारे जो सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं, उनमें कई सैकड़ों स्कूलों में बिजली नहीं थी और आज मैं बता रहा हूं कि केवल 48 स्कूल ऐसे बचे हैं जहां बिजली नहीं है, बाकी सारे स्कूलों में बिजली गयी। 48 में भी 36 अभी प्रक्रियाधीन है और 12 ऐसे हैं जो उस गांव में ही बिजली नहीं है तो वहां पर सोलर एनर्जी के सहयोग से हम बिजली की व्यवस्था करने के लिए जा रहे हैं।

नरेगा के माध्यम से खेल के मैदान की भी व्यवस्था की जा रही है। ....(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मंत्रीजी, रिपीट कर रहे हो। रिपीट कर रहे हो आप। रिपीट हो रहा है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): नहीं, रिपीट नहीं कर रहा हूं। रिपीट एक भी बात नहीं होगी। मनरेगा की नहीं आई। आंगनबाड़ी, पहले ये कहते थे कि एल.के.जी., हायर के.जी. शुरू करो। इस बार आंगनबाड़ियों को सरकारी स्कूलों के साथ जोड़ा है। जो भी 500 मीटर से नजदीक आंगनबाड़ी है, उसको सरकारी स्कूलों के अंदर एक कमरा और कमरा नहीं है तो कमरा बनाने के लिए हमने निर्णय ले लिया। वहां पर कमरा बनेगा और उसमें सारी चीजें व्यवस्थित होंगी और कक्षा एक से दस तक के एक हजार विद्यालयों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का समावेश किया जा चुका है और इन केन्द्रों की भी मोनिटरिंग अच्छे ढंग से हो सकेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर ने लिखा है 'जिन शिक्षकों के भीतर का बालमन सूखकर काठ हो गया है, वे बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के योग्य नहीं हैं' इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, हमने राज्य के

(श्री वासुदेव देवनानी)

सभी विद्यालयों में बाल केन्द्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण और सतत और व्यापक मूल्यांकन पद्धति लागू की है। कोई शिक्षक बन गया, फिर प्रिंसिपल भी बन गया, उसकी नेतृत्व क्षमता बढ़े, इसलिये उसकी लीडरशिप की ट्रेनिंग शुरू की है और जो सीनेट है, जयपुर में लीडरशिप एकेडमी की स्थापना की है और इस बार एस.आई.टी. के नेतृत्व में डाइट के माध्यम से हम प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं और यह नहीं कि स्कूलों की छुट्टी करके जायेंगे। गर्मी की या सर्दी की छुट्टियों में या दीवाली की छुट्टियों में सारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किये हैं।

स्वामी विवेकानन्द ने तो कहा है 'प्रधानाचार्य उस नाविक के समान है, जो जहाज को अपनी इच्छानुसार जहां चाहे वहां ले जा सकता है। इसके लिये प्रशिक्षण आवश्यक है' इसलिये डी.डी. और डी.ई.ओ. सबके प्रशिक्षण हम करवा रहे हैं। पिछले दिनों तो अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन बैंगलोर, हवाई जहाज में भेजकर इन सारे डी.ई.ओज. का हमने प्रशिक्षण करवाया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब कुछ घोषणाएं शुरू की जाएं और घोषणाओं के बाद कला एवं संस्कृति पर आऊंगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको घोषणा के साथ ही साथ कहना कि हम आठ सदस्य बैठे हैं, हमारे लिये भी कोई घोषणा करें। दो घंटे से इनको हम सुन रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, आज मंत्रीजी से पहले दोनों मंत्रियों ने जो भाषण दिया था, उनसे इनका भाषण अच्छा है। लेकिन मंत्रीजी पिछली बार से आधा घंटा कम है। पिछली बार से आधा घंटा कम दिया है तो यह तो पूरा करो कम से कम।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घोषणाओं में जैसा मैंने बताया, अब तक तो राजकीय विद्यालयों की बालिकाएं, कक्षा 6 में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल वाली छात्राओं को केवल ट्रांसपोर्ट वाउचर मिलता था। आगामी सत्र से जो आपको लगा कि बालक पाँच किलोमीटर दूर से कैसे जाएगा, स्कूल मर्ज हो गया। कक्षा एक से लेकर आठ तक के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं के लिए आर.टी.आई. मापदण्डों के आधार पर ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम हम

(श्री वासुदेव देवनानी)

लागू करने जा रहे हैं। कक्षा एक से लेकर पांचवीं तक का विद्यार्थी होगा और यदि वह एक किलोमीटर दूर से आयेगा तो उसको दस रुपये का और कक्षा छह से आठ तक की बालिका आयेगी तो उसको 15 रुपये के ट्रांसपोर्ट वाउचर की व्यवस्था सरकार करने जा रही है।

पहले एक बड़ी समस्या रहती थी। आप लोग भी कई बार चर्चा करते थे कि हमारे सर्वशिक्षा अभियान के अंदर जो शिक्षक काम करते हैं, उनको समय पर वेतन नहीं मिलता। कई बार 20-25 दिन बाद, कई बार कहते थे कि भारत सरकार से अभी आ रहा है तो इस प्रकार की कठिनाइयां खड़ी होती थीं। मैं घोषणा करता हूं कि इस आगामी वित्तीय वर्ष के अंदर आगे से उनके खातों में तय समय पर हस्तान्तरित होने को सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि सभी शिक्षकों का वेतन एक तारीख को, बाकी शिक्षकों की तरह उनके खाते में जमा हो जाये। यह व्यवस्था हम करने के लिये जा रहे हैं।

मोनिटरिंग की जब बात चली तो मैंने कहा डी.ई.ओ. के पद तो भरे, लेकिन डी.डी. के पद नहीं भरे, क्योंकि पहले डी.ई.ओ. के प्रमोशन ही नहीं हुए तो तीन साल के डी.ई.ओ. हमें उपलब्ध नहीं थे। डी.डी. बनायें तो किसको बनायें और बिना डी.डी. के, बिना ज्वाइंट डायरेक्टर के सारे पद खाली। इस बार हमने माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करके एक वर्ष का रिलेक्सेशन इनके अनुभव में लिया है और एक अप्रैल से हम इनकी डी.पी.सी. करने के लिये जा रहे हैं, जिसमें जो 36 डी.डी. के पद हैं, सभी हम भर देंगे। इस तरह से राजस्थान में एक भी डी.डी. का पद खाली नहीं रहेगा।

इसके साथ, जैसा मैंने कहा, डी.पी.सी. तो हम करते आ रहे हैं, लेकिन पहले दो-दो, तीन-तीन, पाँच-पाँच साल नहीं होती थी। अगले वर्ष 2017-18 की जो डी.पी.सी. है, वह भी हम एक अप्रैल से प्रारम्भ करने के लिये जा रहे हैं। मेरे हर उस शिक्षक को, जो उसका ड्यू है, वह सही समय पर मिले और उसकी पदोन्नति हो। बाकी की तो पदोन्नति कर रहे हैं, लेकिन बीच में मुझे एकाध सदस्यों ने याद दिलाया कि शारीरिक शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्षों की पदोन्नति काफी समय से नहीं हुई है। इनके नियमों में कुछ कमियां थीं, उन नियमों को भी हम ठीक करेंगे। बहुत जल्दी हम इन दोनों की पदोन्नति करने के लिये डी.पी.सी. करने जा रहे हैं।

(श्री वासुदेव देवनानी)

अभी प्रबोधकों के पद की बात आयी। उसके लिये भी हम विचार कर रहे हैं कि इन वरिष्ठ प्रबोधक के पद भी सृजित करके इनको भी कुछ लाभ दे सकें।

आदर्श विद्यालय की और उत्कृष्ट विद्यालयों की बात चली तो शहरी क्षेत्र से आने वाले माननीय विधायक महोदय भी मेरे साथी हैं। उनको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में ही आदर्श और उत्कृष्ट विद्यालय आप बनाने के लिये जा रहे हो। मैंने कहा नहीं, अगले सत्र से शहरों में भी आदर्श विद्यालय और उत्कृष्ट विद्यालय को विकसित करने की मैं घोषणा करता हूं।

विज्ञान संकाय की बात चली। उपाध्यक्ष महोदय, अब तक केवल साइंस फैकल्टी 978 विद्यालयों में थी। पिछले दो वर्ष के अंदर यह बढ़कर इससे दुगुनी हो गयी।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी की विद्वता पर अब किसी को शंका नहीं है। पूरा सदन बिलकुल इनकी बात से, इनके काम से संतुष्ट है। अत: मांग पारित करायी जाए।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): घोषणा तो पूरी करने दो। आप नींद ले लो भले। जिन विद्यालयों में कक्षा 10 में 100 से अधिक विद्यार्थी हैं और वहां एक ही कला संकाय है, ऐसे 112 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय आगामी सत्र से प्रारम्भ करने की घोषणा करता हूं। इसके अतिरिक्त जहां पर 120 बच्चे हैं, वहां पर दो-दो फैकल्टी भी हैं। ऐसे 26 स्कूल हैं जहां पर कला और वाणिज्य संकाय है, ऐसे 26 विद्यालयों में भी विज्ञान संकाय प्रारम्भ करने की घोषणा करता हूं।

साथ में, प्रदेश में 263 पंचायत समिति मुख्यालय हैं, जहां पर विज्ञान संकाय तो चलती है, लेकिन कहीं गणित, रसायन, भौतिक है, कहीं गणित, रयासन, जीव विज्ञान है, इन सारे 263 स्कूलों में पूरे पाँच विषय - भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, कृषि, जीव विज्ञान, गणित, ये पांचों विषय हम प्रारम्भ करेंगे ताकि कोई भी बालक वंचित न रहे। इस तरह से लगभग 190 स्कूलों के अंदर कृषि विषय शुरू हो जाएगा, जिसके आधार पर मैं सोचता हूं, कृषि की बहुत डिमांड भी है, यहां कृषि विषय खुलेगा तो निश्चित रूप से वह कालेज में आगे बी.एस.सी. भी करेगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी जा

(श्री वासुदेव देवनानी)

सकेगा। कई जगह कृषि न होने के कारण यह सबसे बड़ी दिक्कत थी।

फिर 13 हजार 527 हमारे माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। इन सबमें कम्प्यूटर, मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर और इंटरनेट की सुविधा देने के लिये 29 करोड़ 69 लाख रुपये आगामी वर्ष में खर्च करने की भी घोषणा करता हूं।

आगामी वर्ष में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 746 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, पुस्तकालय, कम्प्यूटर कक्ष आदि पर 74 करोड़ रुपये, 58 नवीन विद्यालय भवनों एवं एक हजार तीन विद्यालयों में 1 हजार 334 कक्षा-कक्षों के निर्माण के लिये 114 करोड़ 48 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

इसके साथ ही, अभी तक तो राज्यस्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा होती थी। यह केवल विज्ञान वाले विद्यार्थियों के लिये होती थी। इस बार आगामी वर्ष से कला और वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिये भी अलग से प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित कर मेधावी विद्यार्थियों को चिह्नित कर सम्मानित किया जाएगा।

अब पी.ई.ओ. तो बना लिये। लेकिन पी.ई.ओ. कार्यालयों को भी स्ट्रेन्थन करने की हमारी आगामी वर्ष में हम योजना बना रहे हैं। उनका सुदृढ़ीकरण करेंगे ताकि उनकी मोनिटरिंग हो सके। फिर प्राइवेट स्कूल वाले कहते थे साहब, आपने तो ऑनलाइन हमारी मान्यता के लिये कर दिया, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो एफिलिएशन है, वहां बहुत प्रॉब्लम आती है। आगामी वर्ष से बोर्ड की जो सम्बद्धता है, इसको भी ऑनलाइन करने की मैं घोषणा करता हूं।

महोदय, अभी हम 2 हजार स्कूलों में तो कम्प्यूटर से पढ़ा रहे हैं लेकिन हमको कई बार प्राइवेट स्टूडियो से सहयोग लेना होता है। आगामी वर्ष हमारे शिक्षा संकुल के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो कार्यालय है, जो भवन बना हुआ है, उस भवन में शिक्षा विभाग के एक स्टूडियो के निर्माण की मैं घोषणा करता हूं जिससे सारे राजस्थान के स्कूलों में हम व्यवस्था करके अच्छे माध्यम से पढ़ा सकें।

अब यह जो शिक्षा संबलन अभियान होता है, आगामी वर्ष से इसकी तिथियां भी घोषित की हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती 25 सितम्बर से

(श्री वासुदेव देवनानी)

महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक पहला चरण शिक्षा संबलन अभियान का होगा और दूसरा चरण स्वामी विवेकानन्द जयंती 12 जनवरी से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती 23 जनवरी के दो चरणों में शिक्षा संबलन अभियान चलाया जाएगा जिसके आधार पर आगे बढ़ सकें। ....(व्यवधान)...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ये नींद लेकर आये हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सुखरामजी, क्यों दु:खी हो रहे हो बार-बार खड़े होकर।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): हम कई बार अपने बच्चों को किसी स्कूल में भर्ती कराने जाते हैं तो कभी प्राइवेट स्कूल में भर्ती कराने जाते हैं तो अच्छा स्कूल चाहिये। हम बाहर किसी होटल में जाते हैं, तो थ्री स्टार चाहिये, फाइव स्टार चाहिये। हमारे स्कूलों के भी हमने मापदण्ड तय कर लिये। स्कूलों को भी हम सिंगल स्टार से फाइव स्टार तक ले जायेंग। उनके मापदण्ड तय किये। हर स्कूल में होड़ मचायेंगे, वो भी फाइव स्टार बने तब उसमें से एक श्रेष्ठ परीक्षा के परिणाम आ सकें।

विद्यालय में रिक्त पदों को भरने का, हम प्रायोरिटी से भरेंगे। एक घोषणा कर ही चुका कि हम 282 विद्यालयों को पंचायतों में, जहां 40 से अधिक बच्चे दसवीं में हैं उनको क्रमोन्नत करेंगे।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिसर में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए स्वामी विवेकानन्द विद्यार्थी सुविधा केन्द्र 6 करोड़ 14 लाख रुपये की लागत से बनाने के लिए जा रहे हैं।

इसके साथ ही, बोर्ड ने अभी 18 जिलों के अन्दर विद्यार्थी सहायता केन्द्र शुरू कर रखे हैं, सेवा केन्द्र। अगले सत्र से सारे 33 जिलों के अन्दर ये विद्यार्थी सेवा केन्द्र प्रारम्भ हो जायेंगे। किसी भी बालक को अजमेर आकर के किसी मार्कशीट या उसके लिए चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उपाध्याय परीक्षा में राज्य के पांच वनवासी बहुल क्षेत्रों, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ व सिरोही में से जनजातियों के जो छात्र-छात्राएं सर्वोच्च अंक प्राप्त करेंगे, उनमें से एक छात्र और छात्रा को 12 हजार रुपये की छात्रवृत्ति एक वर्ष के लिए दिये जाने की घोषणा करता हूं।

(श्री वासुदेव देवनानी)

छात्रावासों, शारदे और कस्तूरबा में भी अगले वर्ष तीन करोड़ रुपये व्यय करने की बालिका शिक्षा फाउंडेशन से घोषणा करता हूं।

राजकीय विद्यालयों की मरम्मत के लिए 6632 प्राइमरी, उच्च प्राइमरी विद्यालयों में 49 करोड़ रुपये प्रदान किये जायेंगे।

फिर पुस्तकालय। कई जगह पुस्तकालय तो हैं लेकिन ये एक आदर्श पुस्तकालय भी बने और जहां पुस्तकालय नहीं है वहां बने, तो राजकीय विद्यालयों में जहां पुस्तकालय नहीं हैं वहां पर ऐसे 8880 प्राथमिक विद्यालयों में प्रति विद्यालय 3 हजार और 751 अपर प्राइमरी हैं, प्रति विद्यालय 10 हजार रुपये प्रदान किये जायेंगे, इस मद में 3 करोड़ 41 लाख रुपये प्रदान किये जाने की घोषणा करता हूं।

हमारे शिक्षकों के प्रशिक्षण के साथ ही विद्यालय में विद्यार्थियों का विकास भी हो, इसमें हम सभी प्रमुख लोगों को भी बुलायेंगे और साथ में जो हमारे दूसरे विभाग हैं, उनसे भी सहयोग मिला है। जनजातीय विकास विभाग के द्वारा 44.79 करोड़ रुपये से 413 कक्षा-कक्षों का निर्माण करेंगे और बहु-क्षेत्रीय विकास योजना, एमएसडीपी के तहत 34.94 करोड़ से हम 216 कक्षा-कक्षों का और निर्माण करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि हम सारे क्षेत्रों के अन्दर ...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बहुत हो गया। खूब है अब तो। खूब है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): बस यह लास्ट में, घोषणा ही है दो-तीन। घोषणाएं तो पूरी कर लूं। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): घोषणा तो बहुत हो गयी। खूब है। अब दिल भर गया हमारा।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): देर से करोगे तो सुनने का मानस तो बनाना पड़ेगा।

राजस्थान के अन्दर एक केन्द्रीय, सात मण्डल और 33 जिला मुख्यालयों पर सार्वजनिक पुस्तकालय हैं, इस वर्ष उनको आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में विकसित करने की घोषणा करता हूं और केन्द्रीय पुस्तकालय हेतु एक करोड़ रुपये, मण्डल पुस्तकालय हेतु 50 लाख रुपये और

(श्री वासुदेव देवनानी)

जिला पुस्तकालय हेतु 25 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान किया जायेगा।

राजस्थान के अन्दर हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन दिये जाने के लिए हिन्दी साहित्य, पत्रकारिता, तकनीकी विज्ञान, विधि और कृषि सहित छह वर्गों में प्रत्येक क्षेत्र के लिए 50 हजार रुपये प्रति राजस्थानी लेखकों को प्रतिवर्ष पुरस्कार दिये जाने की घोषणा करता हूं।

साथ में हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन दिये जाने के लिए जिन विद्यालयों में दस या दस से अधिक विद्यार्थी शत-प्रतिशत अंक हिन्दी विषय में लायेंगे, उस विषय अध्यापक को भी सम्मानित करने की घोषणा करता हूं।

मैंने पिछले सत्र के अन्दर कहा था, शहीदों के नाम पर विद्यालयों के नामकरण की घोषणा की थी। सैनिक कल्याण विभाग से हमारे विभाग को आज तक प्राप्त 78 प्रकरणों को हमने निस्तारित कर दिया है। शहीदों के नाम पर हमने विद्यालय के नाम रख दिये हैं।

इसी प्रकार आठ भामाशाहों के नाम भी रखे। अब डूंगरपुर में गोविंद गुरु, संत भावजी महाराज के नाम पर और श्रीगंगानगर में पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री गुरूशरण जी छाबड़ा के नाम पर एक-एक विद्यालय के नामकरण की घोषणा करता हूं।

ये विद्यार्थी हैं, हमारी सारी शिक्षा तो प्राप्त करे लेकिन इनको केवल राजस्थान के साथ ही जोड़ा, ये ग्लोबली विश्व के साथ भी जुड़ें, इनको ग्लोबली एक्सपोजर मिले, इसके लिए इस वर्ष जयपुर के अन्दर जिस तरह "ग्राम" का आयोजन हुआ था उसी तरह फेस्टिवल ऑफ एजुकेशन का भी हम आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय आयेंगे, वर्कशॉप्स होंगे, सेमिनार्स होंगी। मेरे राजस्थान के विद्यार्थी को एक्सपोजर मिले ताकि बढ़कर वो अपने जीवन को संवार सके।

पैरेंट-टीचर्स मीटिंग की तो मैंने घोषणा की, लेकिन इस वर्ष एक नया प्रयोग कर रहे हैं। वह है पैरेंट-टीचर्स मीटिंग के साथ में मदर-टीचर मीटिंग। मतलब मदर स्कूल आये, इसका आग्रह होगा ताकि उसके कारण से विद्यालय के साथ उसका जुड़ाव भी होगा।

साथ में महीने के एक अंतिम शनिवार को एक कालांश को स्वैच्छिक

(श्री वासुदेव देवनानी)

श्रमदान की घोषणा करता हूं जिससे बालक के मन में स्वच्छता का भाव जगे और संस्कार सभाएं हर द्वितीय शनिवार को हों।

अब अंत में मैं अपनी बात को कहता हुआ पूरी करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बैठे हुए सभी सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि वे अपने विधायक कोष से भामाशाहों को प्रोत्साहित करने, राजकीय विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए अपना अधिकतम योगदान दें। मैं अब सभी शिक्षक साथियों की तरफ से आप सबसे यही कहना चाहता हूं, 'एक अकेला थक जायेगा मिल कर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना' और मुझे विश्वास है कि मेरे सामने विपक्ष के मित्र जो बैठे हैं, वे भी शिक्षा में उन्नयन के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी के सपनों के अनुसार अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सदन में यह जानकारी देते हुए बड़ा हर्ष और सुखद अनुभूति हो रही है कि सारे शैक्षिक परिवार के सामूहिक प्रयासों के आधार पर राजस्थान ने अपनी कीर्ति पताका पूरे शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में फहरायी है। इन नौ प्रकरणों में राजस्थान देश भर में प्रथम है, जिसकी सराहना हुई है। विद्यालयों का समन्वय जो हमने किया है उस समन्वय की देश भर में सराहना हुई है।

सरकारी विद्यालयों में बढ़ते नामांकन की बात हैं। मैं अभी दिल्ली में शिक्षा मंत्रियों की बैठक में गया। सारे शिक्षा मंत्रियों ने कहा कि हमारे यहां सरकारी स्कूलों में नामांकन कम हो रहा है। एक मात्र राजस्थान ऐसा प्रांत है जिसमें सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ रहा है। काउंसलिंग पद्धति की देश भर में सराहना हुई। पी.ई.ओ. के अधिकारी की नियुक्ति, एमएचआरडी मंत्री ने बाकी राज्यों को कहा है। पिछले दिनों, कुछ महीने पहले बिहार के शिक्षा मंत्री, जो हमारी पार्टी के नहीं हैं, वे भी जयपुर में आकर सारी जानकारी ले गये। अभी गत सप्ताह महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी यहां आकर सभी जानकारी ले गये।

पाठ्यक्रम को जो युगानुकूल, दिशा अनुकूल बनाया है, उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। इसके साथ ही रिटेंशन, आठवीं और पांचवीं की परीक्षा, बीएड और एस.टी.सी. इन्टर्नशिप, स्काउट-गाइड में प्रदेश के पहले स्तर पर पहुंचने

(श्री वासुदेव देवनानी)
के लिए देश में एक बहुत ही पहले स्थान का एक वातावरण बना है। हमारी सब जगह सराहना हुई है।

अंत में, मैं एक गीत की दो लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। ...(व्यवधान)... अभी वह है न संस्कृति।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): एक डिपार्टमेंट और है साहब।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): एक डिपार्टमेंट और है अभी। चिंता मत करो। मैं कर रहा हूं भाई साहब, है न अभी।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कला, संस्कृति बाकी पड़ा है अभी।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): अभी कला, संस्कृति बाकी है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हां, कला और संस्कृति।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): 'कोई चलता पद चिह्नों पर, कोई पद चिह्न बनाता है, है वही सूरमा इस जग में, जो अपनी राह बनाता है' और मुझे विश्वास है कि हमारे शिक्षा परिवार का हर व्यक्ति सूरमा है। एक व्यक्ति नहीं, शिक्षा परिवार का हर व्यक्ति सूरमा है और जिस राह पर हम चल पड़े हैं, वह राह मंजिल की ओर जा रही है और हमारी मंजिल प्राप्त करने के लिए हम एक ऐसा राजस्थान बनाने जा रहे हैं, जहां है सुराज का प्रकाश, जहां है विश्वास की रोशनी, जहां है अपने राजस्थान का गौरव, जहां है अपनी माटी का स्वाभिमान। भारत माता की जय। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय जय राजस्थान।

अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे पास ...(व्यवधान)...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): भिण्डा साहब ले गये पीछे, भिण्डा साहब।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मांग आधी थोड़े ही पारित कराओगे। कला, संस्कृति बाकी है अभी। आधा ही किया है। ...(व्यवधान)... साहब, यह तो अन्याय हो रहा है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, अब संक्षेप में। जो आप लोगों के कट-मोशन मिले थे, उनमें 83 प्रस्ताव तो विद्यालय

(श्री वासुदेव देवनानी)

क्रमोन्नत के थे, दो एकीकरण के सम्बन्ध में थे, छठे वेतनमान में द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के वेतन विसंगति का एक था, अलवर शहर के पटरीपार क्षेत्र में विद्यालय का एक था और अतिरिक्त विषय संकाय खोलने के लिए 29 थे और एक मुख्यालय था और साधारण मरम्मत के 66 थे, इन सारे प्रस्तावों के उत्तर हमने आपको भिजवा दिये हैं। जब तक आप घर पहुंचेंगे या सवेरे उठेंगे तो आपको घर पर मिल जायेंगे।

अब वैर के माननीय विधायक ने एक प्रश्न उठाया था कि भरतपुर जोन में डी.पी.सी. में गड़बड़ हुई है। अब वे हैं नहीं। समय-समय पर जांच तो हमारे यहां करते हैं, फिर भी इसकी जांच कराऊंगा। कोई दोषी पाया जायेगा तो हम काम करेंगे।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, व्याख्याता, अंग्रेजी की डीपीसी की बात थी। जो कि 2004-05 के बाद नहीं हुई है। उसके बारे में क्या कहना है?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): वह 13 हजार में देख लेना कि अंग्रेजी के कितने हैं? फिर मेरे पास आ जाना।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके निर्देशानुसार कला और संस्कृति विभाग के आज जो कटमोशन थे, उनके भी उत्तर हम भेज रहे हैं। राजस्थान विविधताओं से भरा प्रदेश है। यहां भौगोलिक और जलवायु संबंधी विषमताएं तो हैं लेकिन यहां सभी लोग मिलकर मुस्कुराहट के साथ रहते हैं। उसके कारण हैं यहां के सुरीले गीत, लोक नृत्य और वर्ष भर आयोजित होने वाले मेले और त्यौहार लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग हैं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वह जो शहीद का नाम गलत हो गया, उसके शुद्धिकरण के लिए क्या कर रहे हो?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): उसका भी करेंगे। सब करेंगे। कुछ आज करेंगे, कुछ कल करेंगे।

इन सारी चीजों से ना केवल हमारा जन-जीवन सरस होता है बल्कि लोक कलाकारों, चित्रकारों एवं साहित्यकारों को प्रोत्साहन एवं सहायता भी मिलती है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग राज्य के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कलात्मक और साहित्यिक धरोहर के संरक्षण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राजस्थान का इतिहास विश्व में गौरवपूर्ण है। प्रदेश में स्थित किले, बावड़ियां, स्मारक, हवेलियां आदि इस धरा के शूरवीरों, दानवीरों, वीरांगनाओं एवं बलिदानियों की अमर गाथा के साक्षी हैं।

मीरा के भक्तिपूर्ण गीत, दादू के पद आदि आज भी जन-जीवन के पथ प्रदर्शक हैं। प्रदेश में फैली इस विशाल सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग और भाषा अकादमियां निरंतर अपना काम कर रही हैं।

पुरातत्व संग्रहालय विभाग का गठन 1950 में हुआ। वर्तमान में 342 पुरास्मारक व 43 पुरास्थल संरक्षित घोषित हैं। मैं इसमें बीच-बीच में से ही पढ़कर पूरा कर रहा हूं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अब हो गया।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): हां, हो गया। मांगें भी तो पारित करवानी हैं।

राणा सांगा पेनोरमा, वैर किला, चौबुर्जा किला और ये सारे, इन पर चालू वित्तीय वर्ष में 640 लाख रुपये व्यय हुए हैं। पर्यटन विभाग, राजस्थान के द्वारा भी इसी प्रकार निधि से सांभर, गागरोन किला, डीग किला इन सबके विकास, संरक्षण के लिए 1038.51 लाख रुपए व्यय हुए हैं।

विभाग द्वारा वर्तमान में संरक्षित पुरास्थल जूनाखेड़ा नोडल जिला पाली में उत्खनन कार्य प्रगति पर हैं। मैं जानकारी दे रहा हूं। इस सबमें विश्व प्रसिद्ध वेधशाला जंतर मंजर, जयपुर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। इसके साथ ही छह और किलों को यूनेस्को ने अपनी उस धरोहर सूची में शामिल किया है। उसमें आमेर महल, चित्तौड़ का दुर्ग, गागरोन का किला (झालावाड़), कुम्भलगढ़ दुर्ग (राजसमंद), जैसलमेर दुर्ग और रणथम्भौर दुर्ग (सवाई माधोपुर) हैं।

इसके साथ इनके संरक्षण के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी के

(श्री वासुदेव देवनानी)
निर्देशानुसार राजस्थान स्मारक पुरावेश स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम के अंतर्गत चल रहा है। दो हमारे प्राधिकरण राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण तथा आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है जो 2014-15 से आवश्यक काम कर रहे हैं। इसमें कई प्रकार के पेनोरमा बन रहे हैं। भरतपुर में और बाकी कई स्थानों में बन रहे हैं।

2016-17 के लिए निम्न पेनोरमा के कार्य प्रगति पर हैं:- संत रैदास, चित्तौड़गढ़, पाबूजी, कोलू (जोधपुर), नागरीदास जी, (किशनगढ़ जिला अजमेर), काली बाई (मांडवा डूंगरपुर), पन्ना धाय (कमेरी जिला राजसमंद), हसन खां (मेवाती अलवर), बप्पा रावल मठाठा (जिला उदयपुर), महाकवि माघ व गणितज्ञ ब्रहमगुप्त, भीनमाल, (जालोर), महाराणा राजसिंह (राजसमंद), धन्ना भगत, धवां (टोंक), राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय, मानगढ़, बांसवाड़ा। इसके साथ ही टोंक में मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान है, इसके विकास की भी सरकार ने योजना बनाई है।

जवाहर कला केन्द्र की गतिविधियों में भी नियमित आने वाले रसिकों एवं पर्यटकों का एक विशेष वर्ग तैयार किया है जिनकी वजह से वह सांस्कृतिक धड़कन के रूप में स्थापित हो गया है। केन्द्र में अतिथि कलाकारों की सुविधा के लिए एक सुविधा संपन्न अतिथि गृह भी है। इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाने के लिए यहां आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की गुणवत्ता कायम रखकर कलाओं को बहुआयामी स्तर पर लाया गया है। यहां जो आठ अकादमियां हैं, वे भी अपना काम कर रही हैं।

अंत में हमारा कला, संस्कृति विभाग प्रदेश की कला संस्थाओं, कलाकारों, भारत सरकार एवं अन्य संस्थाओं के बीच में समन्वय स्थापित करने का भी कार्य करता है। विभाग द्वारा मूर्धन्य साहित्यकार, विशिष्ट कलाकार आदि को पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने हेतु भारत सरकार को समय-समय पर अभिशंसा भी की जाती है। अकादमियों के स्तर पर भी कई योजनाओं का पुरस्कार मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब 2-3 जो घोषणाएं हैं। 2017-18 के प्रथम चरण में 10 संग्रहालय यथा अजमेर, भरतपुर, चित्तौड़, कोटा, झालावाड़, जोधपुर, पाली, बीकानेर, सीकर, जैसलमेर में 37 करोड़ 53 लाख रुपए के कार्य

(श्री वासुदेव देवनानी)

स्वीकृत किए हैं। 2017-18 में आठ संग्रहालय यथा शाहपुरा (भीलवाड़ा), चन्द्रावती (सिरोही), मंडोर (जोधपुर), विराटनगर (जयपुर), आहड़ (उदयपुर), अलवर, डूंगरपुर एवं अल्बर्ट हॉल (जयपुर) में स्वीकृत किए हैं। अजमेर और भरतपुर में 2-2, नागौर एवं कोटा में एक-एक पुरातत्व स्थल के संरक्षण का कार्य 6 करोड़ 46 लाख रुपये से होगा।

स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों से जुड़े हुए खेतड़ी के फतेह विलास महल के शेष रहे जीर्णोद्धार और संरक्षण के कार्य भी आगामी वर्ष में पूरे किए जाएंगे। साथ में धानक्या जो दीनदयाल जी का गांव है, उस स्थान में भी इस वर्ष हम एक संग्रहालय बनाकर तैयार कर रहे हैं। इसी प्रकार राज्य में महत्वपूर्ण दरगाहों इत्यादि के विकास की भी योजना सरकार ने की है।

इस विभाग के लिए आगामी वर्ष में 156 करोड़ 83 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तुत किया है। जो कि गत वर्ष से 49.42 प्रतिशत अधिक है। यह बजट घोषणा 62 के क्रम में की हैं। इसके तहत कार्य हेतु 6 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इनके कटमोशन बहुत हैं लेकिन आप कह रहे हैं इसलिए इसको समाप्त करता हूं।

एक माननीय सदस्य: चार मिनट रह गये हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): चार मिनट, अभी घोषणा करेंगी ना, अभी किरणजी की घोषणा बाकी हैं। मैं कह रहा हूं कि किरणजी कुछ घोषणा करेंगी।

श्री उपाध्यक्ष: आपने अपना वक्तव्य पूरा कर लिया?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): हां। आप कहें तो और भी है। हालांकि सब लोग कह रहे हैं ..

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, पीछे के सब माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए कहा है। आपकी आज्ञा हो तो मैं भावना प्रकट कर दूं। आपकी आज्ञा हो तो?

श्री उपाध्यक्ष: आज सब अपनी-अपनी भावनाएं प्रकट कर दीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): इन्होंने

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

कहा है, गुलाबजी भाई साहब भी कह रहे हैं। हमने किया कौनसा पाप, जो रात के बारह बजाई, नहीं कोई सुनना चाहता, भले ही करो बड़ाई।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): दो लाइन मैं भी पढ़ दूं। उपाध्यक्ष महोदय, सदस्यों की भावनाएं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: चलिए, आप भी पढ़िए अपनी दो लाइनें। लेकिन आप सभ्यता के दायरे में रहकर कहें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, सभ्यता के दायरे में ही और वह माननीय मुख्य सचेतक महोदय को समर्पित करके कह रहा हूं। 'गुरु गोविन्द दोऊं खड़े काके लागूं पाय, बलिहारी गुरु आपने बारह दीनी बजाय। बारह दीनी बजाय, नहीं की खाने की व्यवस्था, चुपचाप सुन वक्तव्य, घर का पकड़ो रस्ता। घर का पकड़ो रस्ता, आओ साथ चलें'।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपकी हालत हो रही खस्ता।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, आप अपना प्रस्ताव करिए।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 24 को पारित कराने के लिए प्रार्थना करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, आपकी कुछ घोषणाएं करनी शेष रह गई थी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय इतना ज्यादा हो गया है कि आप कहें तो यह सब मैं टेबल कर दूं। कर सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष: टेबल आप नहीं कर सकती। आपको श्रीमुख से ही करनी पड़ेगी।

(00.00 बजे)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी घोषणाएं हैं उच्च शिक्षा विभाग की और संस्कृत शिक्षा के संबंध में, इसमें जो नवाचार हमने किया है, वह बहुत ही संक्षेप में सदन के सामने रखना चाहती हूं।

विश्वविद्यालय और महाविद्यालय ऊर्जा के अक्षय स्रोतों का उपयोग कर

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनें, इस कल्पना के साथ हमने कोटा विश्वविद्यालय और राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद में सौर ऊर्जा के तहत रूफ टोप सोलर पावर प्लांट लगाए थे। इन दोनों संस्थानों में परियोजना के सफल क्रियान्वयन के पश्चात् राज्य सरकार ने तय किया है कि सोलर नीति को आगे बढ़ाते हुए हमारे जितने भी महाविद्यालय हैं, जितने भी राज्य वित्त-पोषित विश्वविद्यालय हैं, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय और पॉलीटेक्निक महाविद्यालय हैं, उनमें रूफ टोप ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की मैं घोषणा करती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजकीय विधि महाविद्यालय हैं, उनका बीसीआई के साथ एफिलिएशन होता है। हमेशा एक साल का एफिलिएशन होता है लेकिन इस बार हम लोगों ने उनसे बातचीत करके, अब यह व्यवस्था कर दी है कि तीन साल का एफिलिएशन बीसीआई के साथ में होगा ताकि बार-बार सत्रों के अंदर एफिलिएशन के अभाव में छात्रों को परेशानी आती है विधि महाविद्यालयों की, उनकी सारी परेशानी दूर होगी।

इसी के साथ में National Law University है, उसमें प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए किसी भी तरीके का कोई आरक्षण नहीं है और सारे प्रदेशों के अंदर हम जाते हैं तो वहां पर ऐसी National Law University होती है, जहां स्टेट के सहयोग से वह बनती है तो उन्हें कहीं न कहीं वहां के स्टूडेंट के लिए मैरिट में एक पार्ट दिया जाता है, थोड़ा आरक्षण दिया जाता है। टैन परसेंट, ट्वेंटी परसेंट और कहीं-कहीं थर्टी परसेंट तक दिया जाता है तो राजस्थान में National Law University, Jodhpur में विद्यार्थियों के लिए सीटों को आरक्षित करने की प्रक्रिया हमने चालू कर दी है।

शोध कार्य को वेबसाइट पर अपलोड करना भी हमने शुरू किया है। जितने भी शोध कार्य हैं, एमफिल और पीएचडी की डिग्री होगी, वह भी उन्हें सारा अपलोड करना होगा वेबसाइट पर, इसको कम्प्लसरी कर दिया है।

राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस जो जीमेंस की मैरिट के आधार पर प्रवेश किया जाना है, उसमें भी रीप, राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस में जो कुछ कमियां थीं, पिछली बार वह सारी सुधार कर

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

इस बार राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा को अधिकृत किया है रीप को लेने के लिए।

इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन सेल की हम लोगों ने स्थापना की है। हमारे पोलीटेक्निक कॉलेजेज में जिसमें आठ पोलीटेक्निक कॉलेजेज में हम कर चुके हैं 42 हमारी पोलीटेक्निक कॉलेजेज हैं उनमें हम इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन सेल स्थापित करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डिजिटल इंडिया की माननीय प्रधान मंत्रीजी की जो संकल्पना है वह राज्य की उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार के रूप में हमने कुछ चीजें प्रारम्भ की है। ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है, वन टाइम एडमिशन प्रोसेस होगा जो सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है और संस्कृत शिक्षा के भी महाविद्यालयों में एक ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा।

हायर एजुकेशन पोर्टल हमारा बन रहा है जो ''शाला दर्पण'' शिक्षा विभाग का है, उसी ''शाला दर्पण'' के साथ ही लिंक कर दिया है, वह हायर एजुकेशन का तो एन टू एन फर्स्ट हंड्रेड से लेकर अप-टू उनको रोजगार मिले, तब तक के लिए यह कम्पलीट पोर्टल, हायर एजुकेशन का पोर्टल बन रहा है जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ इन्फोर्मेशन एण्ड टेक्नोलॉजी एण्ड कम्युनिकेशन की सहायता से हम यह कार्य कर रहे हैं।

ई-क्लासरूम योजना, हमारे प्रथम चरण में 34 कॉलेजों में हमने लिया है जो डायनामिक ई-क्लासरूम हम स्थापित करने जा रहे हैं वहां पर। वाई-फाई की सुविधा प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के राजकीय संस्थानों में उपलब्ध कराई जाएगी, यह भी हमने तय किया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि एनओसी की प्रक्रिया है, जो प्राइवेट महाविद्यालय हैं उसकी एनओसी की प्रक्रिया को बड़ा लंबा खींचा जाता है तो उसमें भी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और एक टाइम बाउंड करने की दृष्टि से हमने इसको भी ऑनलाइन कर दिया है। इसकी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, इसकी पूरी प्रक्रिया अप-टू उनको एनओसी देना, तब तक सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएगी ताकि ऑफिसों के अंदर उनको भटकना नहीं पड़े।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

तकनीकी शिक्षा के अंदर भी राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेज में ई-जर्नल्स एवं ई-बुक्स की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिस पर एक करोड़ साठ लाख रुपए दिए जाने की घोषणा करती हूं। राजकीय खेतान पोलीटेक्निक कॉलेज, जयपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक नई ब्रांच खोली जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खेल मैदान और जिम का निर्माण करने का भी हमने सोचा है कि जितने भी हमारे उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनकी चारदीवारी तथा खेल मैदान विकास सम्बन्धी तथा स्थानीय सहयोग से हम लोग वहां पर ओपन जिम का निर्माण कराएंगे। गर्ल्स कॉलेजेज में सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इसी तरह राजकीय महाविद्यालयों में छात्र निधि कोष है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेज में बॉयज फंड होता है, उस बॉयज फंड की एक्सपेंडिचर लिमिट थी वह बहुत कम थी। एक लाख रुपये हमारे यूजी कॉलेजेज की और डेढ़ लाख रुपये पीजी की, आयुक्तालय को तीन लाख रुपये की थी, उसको बढ़ाकर हमने दस लाख, पन्द्रह लाख रुपये और तीस लाख तक कर दिया है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं के शिक्षा स्तर की गुणवत्तापूर्ण उन्नयन के लिए 44 राजकीय कन्या महाविद्यालय हैं, उनमें सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा जिसमें आईटी एनेबल्ड एजुकेशन प्रदान करने के लिए इन महाविद्यालयों में चरणबद्ध रूप से वाईफाई व डिजिटल वर्चुअल क्लास रूम उपलब्ध कराने की भी हम व्यवस्था करेंगे।

हमारा हायर एजुकेशन पोर्टल है उसमें प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों द्वारा जारी की जाने वाली डिग्रियां, मार्क्स शीट हैं उनके सम्बन्ध में इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी कि वे सारी हमारे हायर एजुकेशन पोर्टल पर आ जाएं ताकि फर्जी डिग्री और ये जो सारी शिकायतें आ रही हैं, उन पर कहीं न कहीं रोक लगेगी और ऐसा पाए जाने पर कठोर कार्यवाही भी की जा सकेगी।

ये कुछ घोषणाएं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने की हैं। एक लेटेस्ट अभी 17 मार्च, 2017 को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फोर इंफोर्मेशन एण्ड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला है, वह भी मैं आपके माध्यम से सदन में रखना चाहूंगी कि फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

पुणे के माध्यम से यहां पर एक कोर्स शुरू किया जा रहा है हमारे बांदर सिंदरी, जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है वहां पर, स्किलिंग इंडिया इन फिल्म एण्ड टेलीविजन नाम का कोर्स यहां प्रारम्भ किया जाएगा और इसको राजस्थान की यूनिवर्सिटी के अंदर, एक और यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें हम इसको लेंगे, यह भी मैं आज घोषणा करती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी जो बांदीकुई से आने वाली माननीय सदस्या, ...(व्यवधान)... निकल गई, तो ठीक है। मुझे कहा था माननीय सदस्य अलका सिंहजी ने, गीतांजलि कॉलेज को जिन शर्तों पर जमीन आबंटन हुई थी उन शर्तों की पालना नहीं हो रही है तो वह भी हम लोग एक समिति गठित करके जांच करवाएंगे। यही मेरी संक्षिप्त में कुछ घोषणाएं थीं, धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

शिक्षा, कला एवं संस्कृति - मांग संख्या 24 का पारण

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24 - शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 232,72,20,77,000 (दो सौ बत्तीस अरब बहत्तर करोड़ बीस लाख सत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक गुरुवार दिनांक 23 मार्च, 2017 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 00:08 बजे गुरुवार, दिनांक 23 मार्च 2017 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

प्रश्न संख्या 272

(स्थगित)

सवाई माधोपुर के दुब्बी बनास औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना

273. राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर)**:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सवाई माधोपुर में दुब्बी बनास औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए 247 हैक्टेयर भूमि का आवंटन रीको को किया गया है? यदि हां, तो रीको द्वारा उक्त औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिये क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अविकसित भूमि में से तत्काल उद्योग लगाने के लिए भू-खण्ड आवंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सवाई माधोपुर में दुब्बी बनास नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु 247.98 हैक्टेयर राजकीय भूमि का आवंटन राजस्थान सरकार द्वारा रीको के पक्ष में दिनांक 03.02.2016 किया जा चुका है।

इस क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं अभिन्यास योजना (layout Plan) तैयार कर नियमानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जाएगी, जिसके पश्चात उक्त औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किए जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) जी नहीं। सुनियोजित औद्योगिक विकास के लिए पर्यावरण स्वीकृति उपरान्त विकसित औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगाने हेतु भू-खण्ड आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।

नगर में महाविद्‌यालय की स्थापना

274. श्रीमती अनीता (नगर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नगर में उच्च शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में महाविद्‌यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र नगर में उच्च शिक्षा के लिए निजी क्षेत्र में 06 महाविद्‌यालय संचालित हैं।

(2) निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर नगर में राजकीय महाविद्‌यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

रामगंजमण्डी में सरकारी भूमियों पर से अतिक्रमण हटाने की योजना

275. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में हजारों बीघा सिवाय चक, चारागाह व सरकारी भूमि पर भू-माफियाओं अतिक्रमण है? यदि हां, तो कहां-कहां पर कितनी-कितनी भूमि पर कब-कब से?

(2) क्या सरकार उक्त भूमियों पर से अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) जी नहीं। रामगंजमंडी विधान सभा क्षेत्र में सिवाय चक, चारागाह व सरकारी भूमि पर भू-माफियाओं का अतिक्रमण नहीं है। वर्तमान में 707 काश्तकारों द्‌वारा 439 है. सिवायचक एवं 492 काश्तकारों द्‌वारा 160 है. चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है।

(राज्य मंत्री, राजस्व)

(2) बिन्दु सं. (1) के अनुसार उक्त भूमियों पर भू-माफियाओं का अतिक्रमण नहीं है। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों ने सिवाय चक व चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है उनके विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 91 के तहत बेदखली की कार्यवाही की जाती है।

प्रदेश में रमसा व सर्व शिक्षा अभियान के तहत क्रय की गई सामग्री

276. श्री कैलाश चौधरी (बायतू): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में रमसा एवं सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों को उपलब्ध करवाई जाने वाली सामग्री क्रय करने के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है? यदि हां, तो निविदा में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या रमसा और सर्व शिक्षा अभियान के तहत सामग्री क्रय करने से पूर्व अनुमोदन कराया जाता है? यदि हां, तो किस स्तर से?

(3) गत तीन वर्षों में रमसा और सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों को उपलब्ध करवाई गई सामग्री का क्रय किस प्रकार किया गया तथा कौन-कौन से विद्यालयों में क्या-क्या सामग्री कौनसी एजेंसी के द्वारा कब-कब उपलब्ध करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों को उपलब्ध करवाई जाने वाली सामग्री क्रय करने के लिए खुली, सीमित, दो चरण, सिग्गल सोर्, इलेक्ट्रोनिक रिवर्स ऑप्शन, रिक्वेस्ट फॉर कॉटेशन, स्पोट पर्चेज, कम्पेटेटिव नेगोशेशन्स, रेट कॉन्ट्रेक्ट तथा दूसरी अन्य प्रक्रिया जो राजस्थान सरकार द्धारा निर्धारित की जाती हैं। स्वीस चेलेन्ज मैथड भी अपनाया जाता हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में मुख्य रूप से सीमित एवं खुली निविदा आमन्त्रित की जाती है।

(निविदा के लिए प्रक्रिया राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपनाई जाती है) परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामग्री क्रय के संबंध में आवश्यकतानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन कराया जाता है। सक्षम स्तर के लिये निविदा पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 40 (2) के अनुसार सक्षम स्तर तय है जो कि परिशिष्ट "ख" पर संलग्न हैं। निविदा प्रक्रिया में टाइम फ्रेम हेतु नियम परिशिष्ट "ग" पर संलग्न हैं।

(3) गत तीन वर्षों में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा विद्यालयों को उपलब्ध करवाई गई सामग्री का क्रय राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा 2013 में निर्धारित उपापन प्रक्रिया अनुसार किया गया है। विद्यालयवार क्रय की गई सामग्री का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर द्वारा विगत तीन वर्षों में विभिन्न प्रभागों में बिन्दु संख्या 03 के अनुसार कार्यवाही की गईः-

1. आईसीटी - सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान केवल संलग्न परिशिष्ट-2 के अनुसार ही क्रय हुआ है।
2. व्यावसायिक शिक्षा- सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में व्यावसायिक विषयों की पाठयपुस्तकें जिला स्तर Spiral Binding करवाकर विद्यालयों को उपलब्ध करवायी गई।

   सत्र 2015-16 एवं 2016-17 में व्यावसायिक विषयों की पाठ्यपुस्तकें राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर द्वारा मुद्रित करवाकर जिलों को प्रेषित कर विद्यालयों को उपलब्ध करवायी गई। पुस्तकों की संख्या परिशिष्ट "3" पर उपलब्ध है।

3- आईईडीएसएस योजना के अन्तर्गत -

- सत्र 2014-15 में कोई सामग्री क्रय नही की गई सत्र 2015-16 61 दृष्टिहीन विद्यार्थियों को ब्रेललिपि की पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई, जिनका मुद्रण एवं वितरण राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

जयपुर द्वारा किया गया। कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट "4" पर संलग्न है।

विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को संबलन प्रदान करने हेतु राज्य के 249 ब्लॉक में रिसोर्स केन्द्रों की स्थापना की गई है, जिनमें प्रति रिसोर्स रूम 70000/ रुपये के उपकरण क्रय किये गये,जिनके स्पेशिफिकेशन राज्य स्तर पर निर्धारित कर जिला स्तर पर निविदाएं आमंत्रित की गई, जिसमें विभिन्न फर्मो द्वारा उपकरणों की आपूर्ति की गई। 249 रिसोर्स केन्द्रों की सूची परिशिष्ट "5" पर संलग्न है।

- भारत सरकार से अनुमोदित उपक्रम कृत्रिम अंग उपकरण निर्माण निगम लि. एलिमको कानपुर के सहयोग से जिला स्तर पर मेडिकल कम फंक्शनल असेसमेन्ट केम्प का आयोजन करवाकर चिन्हित 868 CWSN को अंग उपकरण प्रदान किये गये। जिलेवार सूची परिशिष्ट "6" पर संलग्न है।
- वर्ष 2016-17
- 195 दृष्टिहीन विद्यार्थियों को ब्रेललिपि पुस्तके उपलब्ध करवाई गई, जिनका मुद्रण एवं वितरण राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संद्य जयपुर द्वारा किया गया। कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट "7" पर संलग्न है।
- 46 ब्लॉक में रिसोर्ट केन्द्रों की स्थापना कर प्रति केन्द्र 70000 रुपये के उपकरण क्रय किये जाने हेतु जिला स्तर पर निविदा प्रकिया जारी है। 46 रिसोर्स केन्द्रों की सूची परिशिष्ट "8" पर संलग्न है।

  भारत सरकार से अनुमोदित उपक्रम कृत्रिम अंग उपकरण निर्माण निगम लि. एलिमको कानपुर के सहयोग से जिला स्तर पर मेडिकल क्रम फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प का आयोजन करवाकर चिन्हित 773 CWSN को अंग उपकरण प्रदान किये गये। जिलेवार सूची परिशिष्ट 9 पर संलग्न है।

4. एसएजी - सत्र 2014-15 में रमसा के तहत निम्नानुसार सामग्री क्रय की गई:-

   सत्र 2014-15 में राज्य में प्रारम्भ किये गये 66 मॉडल स्कूलों (66 मॉडल स्कूलो की सूची संलग्न है) में DGS&D फर्मो के माध्यम से

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

सामग्री रामाशिप जयपुर द्वारा निम्नानुसार संलग्न कार्यादेश परिशिष्ट "10" जारी कर क्रय की गई थी:-

1. Godrej & Boyce Mfg Co Ltd Gaurav Tower, Malviya Nagar, Jaipur द्वारा डबल डस्कं स्टूडेन्ट टेबल 120, ऑफिस विजिटर चेयर कुर्सी 6, प्रिसिपल टेबल 1, ऑफिस टेबल 1, प्रिन्टर आफिस चेयर 1 सत्र 2014-15 में संबंधित स्कूलों को आपूति की गई परिशिष्ट "11" संलग्न है।

2. एस.आर के माड्यूलर कम्पनी जयपुर द्वारा 60 ब्लॉक्स में सूची संलग्न है कम्प्यूटर टेबल 12 (Contilever type) कम्प्यूटर चेयर एंडस्टैबल 7 स्टील ऑफिस चेयर 5 माड्यूलर टेबल (एम.डी.एफ.बोर्ड) संबंधित स्कूलों को आपूर्ति की गई परिशिष्ट "13" पर संलग्न है।

3. मैसर्स सुरभि इलेक्ट्रानेट प्रा.लि. जयपुर द्वारा 10 कम्प्यूटर DGS&D दरों पर सत्र 2014-15 में संबंधित 66 स्कूलों को आपूर्ति की गई, परिशिष्ट "11" में सम्मिलित है।

4. मैसर्स प्रोमार्क टेक्नो सोल्यूशन प्रा.लि. मोहाली (पंजाब) द्वारा 66 मॉडल स्कूलों में 1200x1800mm साइज के प्रत्येक विद्यालय में 6 ग्रीन बोर्ड उपलब्ध करवाये गये हैं, परिशिष्ट "11" में सम्मिलित है।

सत्र 2016-17 में रमसा के तहत 71 मॉडल स्कूलों में स्टाफ की बॉयोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स डाटा मिनी टैक्नोलाजी मुम्बई से DGS&D दरों पर बॉयोमेट्रिक मशीन का क्रय कर विद्याथियों को आपूर्ति करवाई गई, परिशिष्ट "13" पर संलग्न है।

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

गत तीन वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में बजट प्रावधान नहीं होने के कारण विद्यालयों में कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यूपीएस क्रय नहीं किये गये।

वर्ष 2015-16 में 544 विद्यालयों में डीजीएस एण्ड डी की दरों के द्वारा कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यूपीएस क्रय करके उपलब्ध करवाये गये थे। जिसकी विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-14 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के सरकारी होटलों एवं मिडवे को विक्रय करने की योजना

277. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश की सरकारी होटलों व मिडवे को विक्रय करने की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में राजस्थान पर्यटन विकास निगम व होटल कॉरपोरेशन के कितने होटल और मिडवे कहां-कहां पर संचालित हैं एवं उनमें से कौन-कौन से होटल और मिडवे कब से एवं कितनी राशि के घाटे में चल रहे हैं? इकाईवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार प्रदेश की होटलों एवं मिडवे को निजी हाथों में सौंपने पर आमादा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पर्यटन विकास निगम को घाटे से उबारने/आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ किये जाने हेतु निगम के अध्याधीन परिसम्पत्तियों का श्रेणीवार निस्तारण किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है और इस हेतु वर्तमान में इनका श्रेणीकरण व मूल्यांकन करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राजस्थान राज्य होटल निगम ने निगम की अंसतोषजनक वित्तीय स्थिति पर विचार कर उसके होटलों के संबंध में उपयुक्त पीपीपी मॉडल सुझाने और राज्य सरकार के निर्णयोपरान्त अनुमोदित मॉडल को क्रियान्वित करने हेतु एक ट्रांजेक्शन एडवाइजर नियुक्त करने का निर्णय लिया है, जिसकी नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित होटलों व मिडवे की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। राजस्थान राज्य होटल निगम के दो होटल, होटल खासाकोठी, जयपुर व होटल आनन्द भवन, उदयपुर संचालित हैं।

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित होटलों एवं मिडवे का गत वर्षों का लाभ/हानि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

राजस्थान राज्य होटल निगम के घाटे में चल रहे होटल खासाकोठी, जयपुर एवं होटल आनन्द भवन, उदयपुर का गत वर्षों का लाभ/हानि का विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(3) होटल व्यवसाय करना सरकार के मुख्य दायित्वों में शामिल नहीं हैं। इस व्यवसाय को निजी क्षेत्र द्वारा बेहतर तरीके से संपादित किया जा सकता है। होटल व्यवसाय में निरन्तर बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के चलते सरकारी सैक्टर में होटलों का संचालन घाटे का सौदा बन गया है। ऐसी स्थिति में, राजस्थान पर्यटन विकास निगम और राजस्थान राज्य होटल निगम की इकाइयों (होटल/मिडवे आदि) में विनिवेश (डिस्इन्वेस्टमेन्ट) करना अथवा उनके संचालन में पी.पी.पी. मॉडल पर निजी क्षेत्र की सहभागिता प्राप्त करना प्रस्तावित है। परन्तु यह समस्त कार्यवाही विद्यमान नियमों के अनुसार तथा पूर्ण पारदर्शिता रखते हुए खुली निविदा अथवा नीलामी द्वारा सम्पन्न की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर में राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेन्ट ट्रिब्यूनल की स्थाई बैंच की स्थापना

278. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जोधपुर में राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेन्ट ट्रिब्यूनल की स्थाई बैंच स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने उक्त संबंध में निर्देश भी जारी किए हैं? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 30.10.1996 के

(कार्मिक मंत्री)

द्वारा जोधपुर में अधिकरण की चलपीठ प्रत्येक माह मे दो दिवस एवं आदेश दिनांक 06.04.2010 के द्वारा प्रत्येक माह में पांच दिवस के लिए बैठक आयोजित करने की स्वीकृति जारी की गई है। जोधपुर में वर्तमान में केवल 1213 प्रकरण ही लम्बित है। प्रकरणों की संख्या को देखते हुए स्थाई बैंच की आवश्यकता नहीं है।

(2) जी हां। मा. उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6935/2009 श्री राम सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य में चलपीठ, जोधपुर की कार्यशैली के बारे में आदेश दिनांक 05.10.2009 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे। आदेश की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट "क")

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के पुलिस थानों के बीट अधिकारियों का वाहन भत्ता बढ़ाने की योजना

279. श्री अशोक (हिण्डौली): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में पुलिस थानों में कार्यरत कानिस्टेबल जो बीट अधिकारी भी होता है को बीट क्षेत्र में आवागमन हेतु किस वाहन का कितना मासिक किराया एवं भत्ता दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बीट अधिकारियों को उक्त वाहन भत्ता किस वर्ष से दिया जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्तमान में बीट अधिकारी को दिया जा रहा वाहन भत्ता/किराया अपर्याप्त है?

(4) बून्दी जिले के प्रति पुलिस थाने की प्रति बीट में कितने ग्राम सम्मिलित है एवं प्रति गांव की थाने से दूरी कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार बीट अधिकारियों को नये वाहन उपलब्ध करवाने एवं वाहन किराया भत्ता बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पुलिस मुख्यालय द्वारा विभिन्न जिला/यूनिटों को वाहन उपलब्ध

(गृह मंत्री)

कराए जाते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा वाहन थाना/चौकी स्तर तक उपलब्ध कराए जाते है जो वहां के अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा आवश्यकतानुसार उपयोग में लिए जाते हैं।

वर्तमान में पुलिस थानों मे कार्यरत कांस्टेबल जो बीट अधिकारी भी होता है, को बीट क्षेत्र में आवागमन हेतु साइकिल भत्ता 50 रुपये मासिक दिया जा रहा है।

(2) बीट अधिकारियों को साइकिल भत्ता दिनांक 01.01.1995 से दिया जा रहा है।

(3) चूंकि वाहन उपलब्ध कराये जा रहे हैं इसलिये वाहन भत्तों में फिलहाल परिवर्तन की आवश्यकता नही है।

(4) बून्दी जिले के प्रत्येक पुलिस थाने की प्रत्येक बीट में सम्मिलित ग्राम एवं ग्राम की थाने से दूरी की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(5) इस प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बस्सी एवं चाकसू पंचायत समिति में कराये गये विकास कार्य

280. श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू जयपुर को एस.एफ.सी., टी.एफ.सी., निर्बन्ध राशि एवं अन्य योजनाओं में जनवरी, 2015 से जनवरी, 2017 तक कितना-कितना बजट कब-कब और किस-किस मद में आवंटित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंचायत समितियों द्वारा कितना-कितना बजट ग्राम पंचायतों को दिया गया? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में उपरोक्त पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों द्वारा कहां-कहां, क्या-क्या कार्य करवाये गये एवं कितनी-कितनी राशि के कार्य कब स्वीकृत किये? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू की ग्राम पंचायतों में करवाये

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

गये विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत समिति बस्सी व चाकसू को एस.एफ.सी., टी.एफ.सी., निर्बन्ध राशि एवं स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) योजनाओं में जनवरी 2015 से जनवरी 2017 तक आवंटित की गयी राशि का तिथिवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू द्वारा ग्राम पंचायतों को दिये गये बजट का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) उक्त अवधि में पंचायत समिति बस्सी व चाकसू की ग्राम पंचायतों द्वारा करवाये गये कार्य एवं राशि तथा कार्य कब स्वीकृत किये गये का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(4) पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू की ग्राम पंचायतों में करवाये गये विकास कार्यों की स्थिति का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झुन्झुनूं में भवन रहित स्वास्थ्य केन्द्र

281. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) झुंझुनूं विधान सभा क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अस्पताल कहां-कहां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौन-कौनसे स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां राजकीय भवनों में संचालित हो रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से कौन-कौनसे स्वास्थ्य केन्द्र भवन रहित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि कई जगहों पर भूमि के अभाव में भवन का निर्माण नहीं हो सका है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

(5) क्या यह सही है कि कई स्थानों पर अन्य राजकीय विभागों की सरप्लस भूमि एवं भवन उपलब्ध है? क्या सरकार उनको स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु आवंटित करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सालय, सिटी डिस्पेन्सरी, क्षय निवारण केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त में से राजकीय भवनो में संचालित हो रहे चिकित्सा संस्थानो की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानो में से भवन रहित चिकित्सा संस्थानो की सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं के अन्तर्गत भूमि के अभाव में भवन निर्माण न होने वाले चिकित्सा संस्थानों की सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(5) भवन रहित चिकित्सा संस्थानों हेतु जिले में उपलब्ध रिक्त सरकारी भवनों का आवंटन करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर संभाग में स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

282. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा अजमेर संभाग में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में एन. जी. ओ. एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण योजनाएं प्रारंभ की गई है? यदि हां, तो जिलेवार किस-किस एन. जी. ओ. एवं शैक्षणिक संस्थाओं को योजनाएं संचालित करने हेतु अधिकृत किया गया है?

(2) उक्त को अधिकृत करने में क्या-क्या विभागीय प्रक्रियाएं अपनाई

(श्री भागीरथ चौधरी)

गई? उक्त संस्थाएं कितने-कितने प्रशिक्षणार्थियों को किस-किस अनुमानित दर पर प्रशिक्षण प्रदान कर रही है? वर्षवार, जिलेवार उक्त संस्थाओं के पते एवं प्रशिक्षण स्थल सहित लाभान्वितों का संख्या विवरण मय व्यय सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के तहत अब तक अजमेर संभाग में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार से जोड़ा जा चुका है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा अजमेर संभाग में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में विभिन्न प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। जिलेवार अधिकृत प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा सभी योजनाओं में प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के चयन हेतु EOI प्रकाशित की जाती है। इन EOI में पात्रता मानदंडों की योजनानुसार विस्तृत जानकारी दी जाती है। प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों का पात्रता मानदंडों के अंतर्गत निगम द्वारा डैस्क मूल्यांकन किया जाता है। इसके उपरांत योग्य पाये गये संस्थानों से निगम कार्यालय में प्रजेंटेशन कराया जाता है। निगम की समिति की अनुशंसा पर सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को स्वीकृति आदेश व लक्ष्य जारी करते हुए अनुमोदित प्रशिक्षण प्रदाता के साथ सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया जाता है।

निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अनुमानित दरें निम्नानुसार है:-

1. रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP): निगम मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य के बेरोजगार पात्र युवाओं हेतु उत्पादन क्षेत्र से संबंधित आर्थिक क्षेत्रों के पाठ्यक्रमों के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी दर 23 रुपये प्रति घण्टा निर्धारित है। सेवा क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी दर 20 रुपये प्रति घण्टा निर्धारित है। आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी दर 120/- रुपये प्रतिदिन निर्धारित है।

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

2. पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY): भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल/गरीब ग्रामीण बेरोजगार युवाओं हेतु इस योजनान्तर्गत तीन महीने के कोर्स हेतु रुपये 13696/- प्रति प्रशिक्षणार्थी, इसके अतिरिक्त रुपये 17000/- प्रति प्रशिक्षणार्थी आने जाने का किराया, मुफ्त आवास, यूनिफोर्म, पदस्थापन इत्यादि के मद में निर्धारित है।

3. नियमित कौशल प्रशिक्षण योजना (RSTP): इस योजना के अन्तर्गत सभी वर्ग के बेरोजगार युवाओं/युवतियों हेतु 14/- रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति घन्टा एवं 30/- रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति घन्टा विशेष योग्यजन हेतु निर्धारित है। आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी दर 120/- रुपये प्रतिदिन निर्धारित है।

प्रशिक्षण की वर्षवार, जिलेवार प्रशिक्षणार्थियों की संख्या, संस्थाओं के पते व प्रशिक्षण स्थल एवं लाभान्वितों का संख्यात्मक पूर्ण विवरण मय व्यय परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(3) अजमेर संभाग में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में उक्त सभी योजनाओं में कुल 16191 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। इन प्रशिक्षित युवाओं में से प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं से प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक 4785 युवाओं को रोजगार/आजीविका संवर्धन के अवसर प्रदान किये गये हैं। योजनाओं में लाभान्वितों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में सी.एस.आर. के तहत व्यय राशि

283. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में सरकार द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) की राशि व्यय करने के लिए क्या प्रावधान तय किये गये है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दिनांक 01-01-2012 से 31-01-2017 तक प्रदेश में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के तहत किस-किस कंपनी द्वारा कितनी-कितनी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

राशि किस-किस प्रकार व्यय की गई? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समयावधि में पब्लिक सैक्टर व प्राइवेट सैक्टर की कंपनियों द्वारा कंपनी एक्ट 2013 के अन्तर्गत प्रदेश में तीन प्रतिशत की दर से कितनी राशि बनती थी तथा उनमें से कितनी राशि किस-किस संस्थाओं के माध्यम से व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों व अधिसूचनाओं के अनुसार प्रत्येक कम्पनी, जो सीएसआर के दायरे में आती है, उन्हें अपने विगत तीन वर्षों के शुद्ध लाभ की औसत राशि का दो प्रतिशत सीएसआर फण्ड कम्पनी में गठित सीएसआर समिति के निर्णयानुसार उपयोग व्यय किये जाने का प्रावधान है।

(2) खण्ड-1 में वर्णित कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार कम्पनी द्वारा व्यय किये जाने वाले सीएसआर फण्ड की मोनेटरिंग करने का राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त नहीं है। तद्नुसार इस प्रकार की सूचना का संधारण नहीं किया जाता है।

(3) खण्ड-2 के प्रत्युत्तर अनुसार इस प्रकार की सूचना का संधारण नहीं किया जाता है।

श्री राजेश पायलट राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, दौसा में नवीन संकायों की स्थापना

284. श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) श्री राजेश पायलट राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय दौसा में वर्तमान में कौन-कौन से संकाय संचालित हैं एवं इनमें कितनी सीटें हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त महाविद्यालय में नए विषय सिविल, इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल शाखा संचालित किए जाने की स्वीकृति दी गई थी? यदि हां, तो उसके पश्चात् कौन-कौन से नवीन संकाय इस महाविद्यालय में स्वीकृत किए

(श्री शंकर लाल शर्मा)

गए है? यदि नहीं, तो क्या सरकार क्षेत्रीय मांग एवं आवश्यकता के अनुसार उक्त महाविद्यालय में नवीन विषय स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्री राजेश पायलट राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, दौसा में वर्तमान में इलेक्ट्रोनिक्स एवं कम्प्यूटर संकाय 60-60 प्रवेश स्थानों के साथ संचालित है।

(2) उक्त महाविद्यालय में सत्र 2017-18 में नये विषय के रूप में मैकेनिकल संकाय संचालित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्त संकाय के अतिरिक्त क्षेत्रीय मांग एवं आवश्यकता के अनुसार वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर गुणावगुणों के आधार पर नए विषय स्वीकृत करवाये जाने बाबत विचार किया जा सकेगा।

मावली में भूमि आवंटन के लम्बित प्रकरण

285. श्री दलीचन्द डांगी (मावली): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली के उपखण्ड मावली, गिर्वा व बडगाव में वर्ष 2003 से 2013 तक किन-किन किसानों, संस्थाओं, व्यक्तियों को जमीन का आवंटन किया गया है? क्षेत्रफल सहित किसानों, संस्थाओं व व्यक्तियों की नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि तक जिला कलक्टर के समक्ष भूमि आवंटन के कितने प्रकरण विचाराधीन है एवं उनमें से कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विचाराधीन प्रकरणों में से कितने प्रकरण सरकार के पास आवटंन हेतु प्रेषित किये गये एवं कितने प्रकरण किन कारणों से लंबित हैं? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार किसानों को राहत देने के लिये उक्त लम्बित प्रकरणों के निस्तारण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली के उपखण्ड मावली, गिर्वा एवं बडगाव में वर्ष 2003 से 2013 तक किसानों, संस्थाओं, व्यक्तियों को भूमि आवंटन का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	उपखण्ड	आवंटित प्रकरण संख्या	रकबा
1	मावली	228	652.06 बीघा
2	गिर्वा	150	68.5600 है.
3	बडगांव	0	0

सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष भूमि आवंटन के कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। अत: सूचना शून्य है।

(3) बिन्दु संख्या 2 में वर्णित सूचनानुसार सूचना शून्य है।

(4) राजकीय कृषि भूमि का आवंटन राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत भूमिहीन काश्तकारों को कृषि प्रयोजनार्थ तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 व राजस्थान भू-राजस्व आवंटन नियम 1963 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन बने अन्य नियमों के तहत संस्थाओं आदि को विभिन्न प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित किये जाने के प्रावधान है।

कृषि भूमि का आवंटन उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन नियम 1970 के तहत तथा अन्य प्रयोजनार्थ व्यक्तियों व संस्थाओं को भूमि का आवंटन गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार के स्तर से किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डूंगरपुर जिले की पंचायतों के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

286. श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति बिछीवाड़ा एवं डूंगरपुर में किन-किन पंचायतों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं किन-किन पंचायतों

(श्री देवेन्द्र कटारा)

में माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं? उक्त विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिन ग्राम पंचायतों में माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं, उन पंचायतों के विद्यालय क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति बिछीवाडा एवं डूंगरपुर में संचालित राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा इनमें अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का विवरण निम्नानुसार है:-

पंचायत समिति - बिछीवाडा

क्र.सं.	**राजकीय उच्च मा. विद्यालय/मा. विद्यालय कुल संख्या**	**छात्र**	**छात्रा**	**कुल**
1	27 (उच्च माध्यमिक)	7119	7259	14378
2	09 (माध्यमिक)	1098	1352	2450

पंचायत समिति - डूंगरपुर

क्र.सं.	**राजकीय उच्च मा. विद्यालय/मा. विद्यालय कुल संख्या**	**छात्र**	**छात्रा**	**कुल**
1	26 (उच्च माध्यमिक)	7259	7902	15161
2	14 (माध्यमिक)	2298	2341	4639

विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्ष 2015-16 से बजट सत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में गैर राजकीय/ राजकीय उच्च माध्यमिक स्तर का विद्यालय नहीं होने पर माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का लक्ष्य निर्धारित था, जिसकी पालना में 114 एवं 126 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जा चुके

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

हैं। चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2020 तक विद्यालय क्रमोन्नत किये जा सकेंगे, जिसमें मुख्यालय अथवा मुख्यालय के राजस्व ग्राम के विद्यालय भी हो सकते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में प्राचीन गुफाओं के संरक्षण के कार्य

287. श्री घनश्याम (टोड़ाभीम): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर, दौसा, अलवर, करौली जिलों में उत्सुक खोजी प्रवृत्ति के व्यक्तियों ने असंख्य गुफाओं को खोज निकाला है? यदि हां, तो उक्त जिलों में खोजी गई गुफाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पुरानी संस्कृति और इतिहास की खोज के लिए देश ही नहीं अपितु दुनिया भर में कई जगह गुफाओं पर शोध कार्य हो रहा है? यदि हां, तो प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रकार की खोज नहीं करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त गुफा क्षेत्रों में सरकार द्वारा खनन लीज जारी करने से उक्त पुरामहत्व महत्व की गुफाओं को नुकसान हो रहा है?

(4) क्या सरकार ढूँढाड के पहाड़ों, जयपुर, दौसा व अलवर के पहाडों में मौजूद गुफाओं को खोजकर उन्हें मूलस्वरूप में लौटाकर तथा उक्त गुफाओं के आस-पास जारी खनन लीज एवं अवैध खनन को बन्द कराकर पर्यटन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। पुरातत्व विभाग के पास इस प्रकार के किसी व्यक्ति की कोई सूचना नहीं है ।

(2) राज्य सरकार द्वारा कृष्णदेव पयहारी की गुफा, गलता (जयपुर) तथा आलनिया की गुफा (कोटा) को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है।

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री)

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं। वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

किशनगंज-शाहाबाद क्षेत्र में नवीन जी.एस.एस. की स्थापना

288. श्री ललित कुमार (किशनगंज): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या बारां जिले के किशनगंज-शाहाबाद क्षेत्र में विद्युत लोड ज्यादा होने के कारण राजपुर, रामपुर बिची, छत्रगंज व निवाड़ी गांव में सर्वे करवाकर नये 33 के.वी. जी.एस.एस. निर्माण हेतु प्रस्ताव भिजवाये गये हैं? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नये 33 के.वी. जी.एस.एस. बनवाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त जिले के किशनगंज क्षेत्र में विद्युत लोड ज्यादा होने के कारण नाहरगढ़ क्षेत्र का सर्वे करवाकर 132 के.वी. जी.एस.एस. निर्माण हेतु प्रस्ताव भिजवाये गये हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार नाहरगढ़ में उक्त जी.एस.एस. बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले के किशनगंज-शाहाबाद क्षेत्र में बढ़ते हुए विद्युत भार के मद्देनजर राजपुर एवं रामपुर बिची में 33/11 केवी सब स्टेशन स्वीकृत किये जा चुके हैं। साथ ही छत्रगंज व निवाड़ी गांव में 33/11 केवी सब स्टेशन निर्माण को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में सम्मिलित किया गया है। इन सभी सब स्टेशनों का निर्माण कार्य आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता व प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

(2) बारां जिले के नाहरगढ़ में 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन बनाये जाने के प्रस्ताव का अध्ययन करने पर वर्तमान में आर्थिक दृष्टि से साध्य नहीं पाया गया। भविष्य में विद्युत भार के बढ़ने पर प्रस्ताव का पुन: आंकलन किया जावेगा तथा प्रस्ताव के तकनीकी व आर्थिक रूप से साध्य पाये जाने

(ऊर्जा मंत्री)

पर, संसाधनों की उपलब्धता एवं विभिन्न योजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

प्रदेश में साइबर क्राइम रोकने हेतु थानों का गठन

289. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा साइबर क्राइम को रोकने हेतु आधुनिक संसाधनों और विशेषज्ञों की नियुक्ति एवं थानों का गठन किया गया है? यदि हां, तो जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा कैशलेस ट्रांजेक्शन में होने वाली साइबर ठगी को रोकने हेतु कोई कदम उठाये गये हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा साइबर क्राइम को रोकने हेतु राज्य स्तर पर जयपुर में दिनांक 15.09.2013 से साइबर थाना कार्यरत है ।

राजस्थान पुलिस अकादमी एवं केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों से साइबर अपराधों में अनुसंधान के विषय में 210 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाया जा चुका है। इसी प्रकार प्रत्येक जिले में साइबर क्राइम संबंधी अपराधों का अनुसंधान करने हेतु अनुसंधान अधिकारियों की टीम तैयार करने के लिए 10-10 पुलिस निरीक्षक/उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को "साइबर क्राइम इन्वेस्टीगेशन प्रशिक्षण" योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 288 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाया जा चुका है।

साइबर अपराधों सें संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों द्वारा ही अति महत्वपूर्ण साइबर अपराधों का अनुसंधान करवाया जाता है। पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर सलग्न है।

साइबर थाना को उपलब्ध करवाये गये आधुनिक संसाधनों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) कैशलेस ट्रांजेक्शन में होने वाली साइबर ठगी को रोकने के लिए निम्न कदम उठाये गये है:-

(गृह मंत्री)

1. साइबर थाने का गठन किया गया है।
2. राजस्थान पुलिस अकादमी एवं केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों से साइबर अपराधों में अनुसंधान के विषय में 210 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाया जा चुका है। इसी प्रकार प्रत्येक जिले में साइबर क्राइम संबंधी अपराधों का अनुसंधान करने हेतु अनुसंधान अधिकारियों की टीम तैयार करने के लिए 10-10 पुलिस निरीक्षक/उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को "साइबर क्राइम इन्वेस्टीगेशन प्रशिक्षण" योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 288 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाया जा चुका है। साइबर अपराधों सें संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों द्वारा ही अति महत्वपूर्ण साइबर अपराधों का अनुसंधान करवाया जाता है।
3. साइबर थाने को आधुनिक संसाधन/उपकरण उपलब्ध कराये गये है।
4. Cyber Crime Investigation and Forensic Training Facility (CCIFTF) एवं प्रत्येक रेंज में एक साइबर क्राइम पुलिस यूनिट का गठन प्रक्रियाधीन है।
5. आम जनता में जागरूकता हेतु समय-समय पर पोस्टर, पम्पलैट, दूरदर्शन, सेमीनार आदि के माध्यम से साइबर अपराधों से बचाव हेतु अभियानों का आयोजन किया जाता है।

   कैशलेस ट्रांजेक्शन के संबंध में साइबर थाने पर कोई प्रकरण दर्ज नही हुआ है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सहाड़ा में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण

290. डॉ. बालू राम चौधरी (सहाड़ा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किस-किस ग्राम पंचायत में कितने शौचालयों का निर्माण कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या शौचालय निर्माण में सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान लाभान्वितों को पूर्ण रूप से स्थानांतरित हो गया है? यदि हां, तो किस ग्राम

(डॉ. बालू राम चौधरी)

पंचायत के किस व्यक्ति के खाते में कितना अनुदान स्थानांतरित हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण के अनुदान को लाभान्वितों के खाते में स्थानांतरित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो कौन-कौनसी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त कठिनाइयों को दूर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में स्वच्छ भारत अभियान के तहत कुल 10902 शौचालयों का निर्माण हुआ है। ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) स्वच्छ भारत मिशन के तहत सहाड़ा पंचायत समिति में शौचालय निर्माण उपरान्त कुल 7994 लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है। ग्राम पंचायतवार व्यक्तिगत खाते में अनुदान स्थानान्तरण की सूची परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है। शेष लाभार्थियों को भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जायेगा।

(3) जी नहीं। शौचालय की प्रोत्साहन राशि के भुगतान लाभार्थियों के खाते में करने में किसी भी प्रकार कठिनाई नहीं हो रही है।

(4) कोई कठिनाई नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बांदीकुई व बसवा में चिकित्सकों के रिक्त पद

291. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बांदीकुई व बसवा में चिकित्सकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? उनमें से कितने पद किस दिनांक से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अलका सिंह)

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांदीकुई एवं बसवा में चिकित्सकों के कुल 18 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 4 पद रिक्त है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। चिकित्सकों के पदोन्नति के रिक्त पदों को डी.ए.सी.पी. के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से पीजी/सर्टिफिकेट कोर्स फॉर स्पेशिलाइजेशन कोर्स पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथा संभव लगाने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु 684 चिकित्सा अधिकारियों के पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बड़ी सादड़ी में श्रमिक कार्डों से लाभान्वित श्रमिक

292. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में कुल कितने श्रमिक कार्ड बनाये गये? नाम व ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त श्रमिक कार्डों से अब तक कितने कार्डधारियों को क्या-क्या लाभ मिला? नामवार व गांववार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में कुल 10119 श्रमिक कार्ड बनाए गए। नाम व ग्रामवार विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) उक्त श्रमिक कार्डों से अब तक 276 कार्डधारियों (हिताधिकारियों) को लाभान्वित किया गया। कार्डधारियों (हिताधिकारियों) को योजनावार दिए गए लाभ का नामवार व गांववार विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वल्लभनगर में सी.एस.आर. फण्ड के तहत कराये गये विकास कार्य

293. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

गत पांच वर्षों में सी.एस.आर. फण्ड के तहत हिन्दुस्तान जिंक द्वारा वल्लभनगर तहसील के कितने गांवों में विकास के क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार कम्पनी द्वारा व्यय किये जाने वाले सीएसआर फण्ड की मोनिटरिंग करने का राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त नहीं है, तदनुसार इस प्रकार की सूचना का संधारण नहीं किया जाता है।

सिकराय में महिला महाविद्यालय की स्थापना

294. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सिकराय में महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) महिला महाविद्यालय खोलने के क्या मानदंड निर्धारित है? क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र महाविद्यालय खोलने के मानदंडों में नहीं आता है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र सिकराय में सहशिक्षा का राजकीय महाविद्यालय, सिकराय वर्ष 2013-14 से संचालित है, जिसमें छात्रों एवं छात्राओं को पर्याप्त अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही विधान सभा क्षेत्र सिकराय में निजी क्षेत्र में भी तीन महाविद्यालय संचालित हैं।

(2) महाविद्यालय खोले जाने के मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

जी हां। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र सिकराय में सहशिक्षा का राजकीय महाविद्‌यालय, सिकराय वर्ष 2013-14 से संचालित है, जिसमें छात्रों एवं छात्राओं को पर्याप्त अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही विधान सभा क्षेत्र सिकराय में निजी क्षेत्र में भी तीन महाविद्‌यालय संचालित हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर ग्रामीण में पटवारियों के रिक्त पद

295. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर ग्रामीण विधान सभा में पटवार सर्किल बने हुये हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी पंचायत में? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त पटवार सर्किलों में पटवारियों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में 32 पटवार सर्किल स्थित है। पटवार मण्डलों की पंचायतवार सूची निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	पटवार मण्डल का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	कलडवास	कलडवास
2	सवीना खेडा	सवीना खेडा
3	तितरडी	तितरडी
4	डाकनकोटडा	डाकनकोटडा
5	नाई	नाई
6	उन्दरी	उन्दरी
7	अलसीगढ़	अलसीगढ़
8	पई	पई

(राज्य मंत्री, राजस्व)

क्र.सं.	पटवार मण्डल का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
9	सीसारमा	सीसारमा
10	डोडावली	डोडावली
11	बूझडा	बूझडा
12	बछार	बछार
13	बारापाल	बारापाल
14	काया	काया
15	टीडी	टीडी
16	पडूणा	पडूणा
17	जावर	जावर
18	चणावदा	चणावदा
19	सरू	सरू
20	मटून	मटून
21	भोईयों की पंचोली	भोईयों की पंचोली
22	कानपुर	कानपुर
23	उमरडा	कानपुर
24	चांसदा	चांसदा
25	झामरकोटडा	झामरकोटडा
26	गोवर्धन विलास	बलीचा
27	वरडा	वरडा
28	बडी	बडी
29	भुवाना	भुवाना
30	शोभागपुरा	शोभागपुरा
31	ढिकली	ढिकली
32	धार	धार

(2) उक्त पटवार सर्किलों में से वर्तमान में निम्न चार पटवार सर्किलों में पटवारियों के पद रिक्त है:-

1 सरू

2 चांसदा

(राज्य मंत्री, राजस्व)

3 पई

4 सवीना

(3) राज्य में पटवारियों के 4400 रिक्त पदों को भरे जाने हेतु सीधी भर्ती राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर में प्रक्रियाधीन है। चयन बोर्ड से सफल अभ्यर्थियों की सूची राजस्व मण्डल, अजमेर को प्राप्त होने पर रिक्त पदों को भरा जाएगा।

शिक्षकों का प्रतिबन्धित जिलों से गृह जिलों में स्थानान्तरण

296. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में किस-किस श्रेणी के शिक्षकों के स्थानान्तरण के लिये कौन-कौनसे जिलों को प्रतिबंधित घोषित कर रखा है? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शिक्षकों को ठहराव के आधार पर उनके गृह जिले में स्थानान्तरण की नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े निम्नांकित 10 जिलों को स्थानान्तरण हेतु प्रतिबन्धित घोषित किया हुआ है:-

1. जैसलमेर 2. बाड़मेर 3. डूंगरपुर 4. बांसवाड़ा 5. जालौर 6. झालावाड़ 7. सिरोही 8. बीकानेर 9. बारां 10. प्रतापगढ। संबंधित आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-"क" पर संलग्न हैं।

(2) जी नहीं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की स्थानानतरण हेतु प्रस्तावित स्थानान्तरण नीति में गृह जिले में स्थानान्तरण का प्रावधान नहीं है, अपितु शिक्षक के प्रार्थना पत्र में वांछित जिले हेतु पात्रता में आने पर स्थानान्तरण का प्रावधान किया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में नियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति अधिकारी जिला स्तर, मण्डल स्तर एवं राज्य स्तर पर होते हैं। एक जिले से अन्य जिले अथवा एक मण्डल से अन्य मण्डल में स्थानान्तरण होने से उस शिक्षक की पुराने जिले अथवा मण्डल की

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

वरिष्ठता का विलोपन होता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बयाना का पर्यटन की दृष्टि से विकास

297. श्री बच्चू सिंह (बयाना): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र बयाना में पर्यटन एवं पुरातत्व क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं कराये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वाणासुर नगरी बयाना एवं शाही तालाब रूपवास का पर्यटन की दृष्टि से विकास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बयाना में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य कराये गये हैं:-

- वर्ष 2007-08 में कालेखां के मकबरे का संरक्षण कार्य।
- वर्ष 2012-13 में 12 खम्भों की छतरी का संरक्षण कार्य।

पर्यटन विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बयाना में कोई विकास कार्य नहीं करवाये गये हैं।

(2) वाणासुर नगरी बयाना एवं शाही तालाब रूपवास को पुरातत्व से पर्यटन में जोड़ने के संबंध में वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं हैं।

विभाग में उपलब्ध बजट प्रावधानों एवं प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन विकास कार्य करवाये जाते हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

रानी (पाली) में नवीन न्यायालय की स्थापना

293. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सिविल न्यायालय (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायालय खोलने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त करना आवश्यक होता है? यदि हां, तो क्या रानी (पाली) में नवीन न्यायालय खोलने का प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त स्थान पर सिविल न्यायालय (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। रानी जिला पाली में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना हेतु माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/ स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रकरण वित्तीय संसाधन की उपलब्धता हेतु राज्य सरकार के वित्त विभाग को प्रेषित किया गया।

(2) उक्त न्यायालय की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर रानी जिला पाली में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

प्रदेश में अनुसूचित जाति/ जनजाति के कार्मिकों को पदोन्नति के लिये अनुभव में छूट

294. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सभी राजकीय विभागों/ बोर्डो/उपक्रमों की सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति/ जनजाति के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण देने के प्रावधान हैं? यदि हां, तो संबंधित नियमों/परिपत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में सभी राजकीय विभागों में पदोन्नति हेतु पात्र व्यक्तियों को कार्यानुभव नहीं होने की दशा में अनुभव में शिथिलता देने का प्रावधान है? यदि हां, तो कब से? संबंधित नियमों/परिपत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में सभी राजकीय सेवाओं में पदोन्नति हेतु पात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों को कार्यानुभव नहीं होने की स्थिति में अनुभव में शिथिलता नहीं दी जाती है? यदि हां, तो क्यों एवं किस नियम के तहत? नियम/परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में सभी राजकीय सेवाओं में पदोन्नति हेतु पात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों को उच्च पद पर अनुसूचित जाति/जनजाति का पूरा कोटा होने एवं सामान्य श्रेणी का पद रिक्त होने की स्थिति में अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों को वरिष्ठता सूची में पहले स्थान पर होने पर भी सामान्य श्रेणी के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है? यदि हां, तो कब से एवं किस नियम के अंतर्गत व नहीं, तो क्यों? संबंधित नियमों/परिपत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2008, अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 एवं परिपत्रादेश दिनांक 20.11.1997 की प्रति क्रमश: परिशिष्ट - "क", "ख" एवं "ग" पर संलग्न है।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.02.1998 की प्रति परिशिष्ट - "घ" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 की प्रति परिशिष्ट -"ख" पर संलग्न है।

उक्त अधिसूचना में विहित प्रावधान के अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के निर्धारित अभ्यांश में आधिक्य किये जाने के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लिया जाकर निम्न अभिमत व्यक्त किया जा रहा है:-

(कार्मिक मंत्री)

यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई योग्य एवं पात्र अभ्यर्थी अपनी स्वयं की वरीयता (Own Merit) अर्थात् सेवा में प्रवेश के समय की वरीयता के आधार पर बिना आरक्षण का लाभ लिये वरिष्ठ होता है और उससे कनिष्ठ अनारक्षित वर्ग का राजसेवक पदोन्नत हो जाता है तो उसे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति हेतु निर्धारित अभ्यांश यथा 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत अथवा रोस्टर बिन्दु से पद भरा होने पर भी पदोन्नति से वंचित नहीं किया जायेगा, अपितु आधिक्य हुआ निर्धारित अभ्यांश भविष्य में समायोजित किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में कनिष्ठ लेखाकारों को पदोन्नति के लिये अनुभव में शिथिलता

295. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी प्रथम एवं सहायक लेखाधिकारी द्वितीय के कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सीकर एवं जयपुर जिले के किन-किन कार्यालयों में सहायक लेखाधिकारी द्वितीय के कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं? विभागवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कनिष्ठ लेखाकार से सहायक लेखाधिकारी द्वितीय के पद हेतु पदोन्नति में कितने वर्ष के अनुभव का प्रावधान है? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पदोन्नति हेतु अनुभव में शिथिलता प्रदान की जाती है? यदि हां, तो कितनी और गत पांच वर्षों में वित्त विभाग द्वारा किन-किन पदों पर पदोन्नति हेतु कब-कब और कितनी-कितनी शिथिलता प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार कार्यरत कनिष्ठ लेखाकारों को अनुभव में शिथिलता देकर उनकी पदोन्नति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में लेखाधिकारी के 812 पद, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम के 2107 एवं सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय के 3502 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से क्रमशः 495, 691 एवं 1617 पद रिक्त हैं। जिलेवार सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "अ" "ब" एवं "स")

(2) सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय के जयपुर जिले में 211 एवं सीकर में 13 पद रिक्त हैं, जिनकी जिलेवार सूची (परिशिष्ट "द") पर संलग्न है।

(3) कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 01.10.2014 के अनुसार (छाया प्रति संलग्न है) कनिष्ठ लेखाकार से सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय के पद पर पदोन्नति हेतु पांच वर्ष के अनुभव का प्रावधान है (परिशिष्ट "य")।

(4) कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2(1) कार्मिक/क-2/अ.प्र./91 दिनांक 04.06.08 के बिन्दु संख्या 15 में पदोन्नति हेतु अनुभव में शिथिलता दिये जाने का प्रावधान है, जिसके अनुसार अनुभव में एक तिहाई कालावधि की सीमा तक शिथिलता दी जा सकती है। विगत पांच वर्षों में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय (लेखाकार) से सहायक लेखाधिकारी-प्रथम पद पर वर्ष 2013-14 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति देने हेतु 2008-09 की रिक्तियों के प्रति लेखाकार पद पर चयनित राजसेवकों को पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में एक वर्ष की शिथिलता प्रदान करते हुए छह माह अथवा नियमित चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक में से, जो भी पहले हो, तब तक के लिये नियमानुसार आवश्यक अस्थायी आधार पर पदोन्नति किये जाने हेतु कार्मिक विभाग की सहमति के अनुसरण में वित्त विभाग के पत्र क्रमांक प.1(11) वित्त/राजस्व/96पार्ट/ दिनांक 18.09.2013 के द्वारा शिथिलता प्रदान की गई है। (परिशिष्ट "र")।

(5) जी नहीं। वर्तमान में पदस्थापित कनिष्ठ लेखाकारों द्वारा वर्ष 2012 एवं वर्ष 2013 में कार्यग्रहण किया था। इन्होंने पदोन्नति हेतु न्यूनतम अनुभव पूर्ण नहीं किया है। ऐसी स्थिति में शिथिलता प्रदान कर पदोन्नति दिये जाने का विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में मंत्रालयिक कर्मचारियों की समयबद्ध पदोन्नति की कार्ययोजना

296. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मंत्रालयिक कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति दिये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में सरकार द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों हेतु 30 संस्थापन अधिकारी के एवं 169 प्रशासनिक अधिकारी के पद प्रथम बार स्वीकृत किये जाकर वर्ष 2015-16 में पद भरने हेतु निर्धारित अनुभव में एक बारीय 100 प्रतिशत पूर्ण छूट प्रदान की गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि संस्थापन अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम 5 वर्ष का निचले पद का अनुभव आवश्यक है, क्या सरकार वर्ष 2016-17 में विभिन्न विभागों में रिक्त चल रहे संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी के पदों को भरने हेतु अनुभव में 80 प्रतिशत (4 वर्षों की) छूट दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि पदोन्नति हेतु निर्धारित सेवा अनुभव में वर्ष 2016-17 के लिए कार्मिक विभाग द्वारा कई अन्य विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों को पदोन्नति देने के लिए अनुभव में छूट (शिथिलता) प्रदान की गई है? यदि हां, तो किस-किस विभाग के किस-किस पद के अधिकारियों/ कार्मिकों को किस-किस पद पर पदोन्नति देने हेतु कितने वर्षों की शिथिलता प्रदान की गई है?

(4) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग में वर्तमान में मंत्रालयिक कार्मिकों के काफी पद रिक्त हैं लेकिन निर्धारित अनुभव प्राप्त कार्मिक उपलब्ध नहीं होने के कारण पद भरे नहीं जा रहे हैं एवं वर्ष 2016-17 में पद भरने हेतु निर्धारित अनुभव में छूट (शिथिलता) प्रदान किये जाने हेतु कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भिजवायें गये हैं? यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों पर कब तक शिथिलता प्रदान कर दी जावेगी?

(5) क्या यह सही है कि रिक्त होते ही मंत्रालयिक कर्मचारियों को तुरन्त ही तदर्थ पदोन्नति दिये जाने की स्वीकृति प्रक्रियाधीन रखकर

(श्री मनोज कुमार)

पदोन्नति समय पर नहीं दिये जाने के उद्देश्य से विलम्ब किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्या उक्त आदेश वर्ष 2016-17 की समाप्ति से पूर्व जारी कर उक्त रिक्त पद भर दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। अधिसूचना दिनांक 6.5.15 एवं परिपत्र दिनांक 8.5.15 की प्रति (परिशिष्ट- क एवं ख) संलग्न है।

(2) जी हां। संस्थापन अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव आवश्यक है। नियमों में पदोन्नति हेतु अनुभव में 1/3 अवधि की छूट का प्रावधान है। वर्ष 2016-17 में इन पदों को भरने हेतु निर्धारित अनुभव में छूट का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी हां। कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों को वर्ष 2016-17 में पदोन्नति देने हेतु निर्धारित अनुभव में प्रदान की गई छूट का विवरण (परिशिष्ट-ग) संलग्न है।

(4) जी हां। पुलिस विभाग में वर्ष 2016-2017 में मंत्रालयिक कार्मिकों के पद भरने हेतु निर्धारित अनुभव में छूट चाहे जाने के संबंध में प्रशासनिक विभाग (गृह विभाग) के माध्यम से कोई प्रस्ताव कार्मिक विभाग में प्राप्त नहीं हुए।

(5) जी नहीं। अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम में तदर्थ पदोन्नति का प्रावधान किये जाने हेतु कार्यवाही प्रकियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सोजत में संचालित अवैध शराब की दुकानों के विरुद्ध कार्यवाही

297. श्रीमती संजना आगरी (सोजत): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में वर्ष 2013-14 से जनवरी 2017 तक शराब की दुकानों के कितने लाइसेंस, किस-किस जगह, किसको-किसको जारी किये गये? नामवार, ग्रामवार, स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में अवैध रूप से

(श्रीमती संजना आगरी)

शराब की दुकानें संचालित की जा रही है? यदि हां, तो कहां-कहां? क्या सरकार अवैध रूप से संचालित दुकानों का सर्वे कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में वर्ष 2013-14 से जनवरी, 2017 तक भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर एवं देशी मदिरा की स्वीकृत एवं संचालित दुकानों की सूचना परिशिष्ट -1 व 2 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विभाग में उपलब्ध जानकारी के आधार पर शराब की कोई अवैध दुकान संचालित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में यौन हिंसा के दर्ज प्रकरण

298. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गत तीन वर्षों में नाबालिग बच्चियों के साथ होने वाली यौन हिंसा के कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों में कितनों के चालान पेश किये जा चुके हैं व कितने प्रकरण अब तक अनुसंधान में कितने समय से चल रहे है? जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा जिन प्रकरणों में अब तक भी चालान पेश नहीं किये जा सके हैं, उनके जांच अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में विगत तीन वर्षों में कुल 5995 (वर्ष 2014 में 2026 वर्ष 2015 में 1936 व वर्ष 2016 में 2033) प्रकरण नाबालिग बच्चियों के विरुद्ध होने वाली यौन हिंसा के दर्ज किये गये हैं, जिनका वर्षवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(2) प्रदेश में विगत तीन वर्षों में नाबालिग बच्चियों के विरुद्ध होने वाली यौन हिंसा के कुल दर्ज मामलों में से 4946 प्रकरणों में चालान न्यायालय में पेश किये जा चुके हैं। गत तीन वर्षों के चालान प्रस्तुत किये गये एवं जो मामले अनुसंधान में चल रहे हैं, उनका जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(3) नाबालिग बच्चियों के विरुद्ध होने वाली यौन हिंसा के जिन मामलों में अभी तक न्यायालय में चालान पेश नहीं किये जा सके हैं, उनमें किसी जांच अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रकरणों के लम्बित रहने के कारणों का विस्तृत विवरण जिलेवार तथा वर्षवार परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सुजानगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर कारागृह की स्थापना

299. श्री खेमाराम (सुजानगढ़): क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार सुजानगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर उप जिला कारागृह/जिला कारागृह खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में जिला चूरू में जिला मुख्यालय पर जिला कारागृह के अतिरिक्त राजगढ़ व रतनगढ़ में उप कारागृह संचालित हैं।

वैर के थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति के दर्ज मुकदमे

300. श्री भजन लाल जाटव (वैर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र वैर के विभिन्न थानों में गत दो वर्षों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने मुकदमे दर्ज हुए तथा उक्त मुकदमे किन-किनके द्वारा किस-किस प्रकरण में व किस-किस थाने में दर्ज कराये गये व कितनों में चालान पेश हुआ तथा कितनों में क्या-क्या कार्यवाही की गयी? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र वैर के विभिन्न थानों में गत दो वर्षों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कुल 123 मुकदमें दर्ज हुए। उक्त मुकदमों का थानेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शिव के थानों में पदस्थापित कार्मिक

301. श्री मानवेन्द्रसिंह (शिव): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में पुलिस कार्मिकों के एक स्थान पर कितने समय तक पदस्थापित रहने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बाड़मेर जिले में ऐसे कितने थाने व कार्यालय हैं, जिनमें तीन वर्षों से अधिक समय से पुलिस कार्मिक पदस्थापित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विधान सभा क्षेत्र शिव के अधीन आने वाले थानों में तीन वर्षों से अधिक समय से पदस्थापित कार्मिकों को सरकार हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कार्मिकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति के अनुसार कानि/हैड कानि को दोनों रेंको में कुल मिलाकर एक थाने में 5 वर्ष एवं सउनि. स्तर के अधिकारी का एक थाने पर कुल 4 वर्ष व उप.नि. 5 वर्ष और निरीक्षक 2 वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं किया जा सकता हैं। पुलिसकर्मियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन्न की नीति का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर अंकित है।

(2) जिला बाडमेर के पुलिस थानों में आसूचना अधिकारी के अतिरिक्त कोई भी कर्मी तीन वर्ष से अधिक अवधि से पदस्थापित नहीं हैं। एस.पी.ऑफिस बाड़मेर में 08, वृत कार्यालय बाड़मेर में 01, वृत कार्यालय चौहटन में 01 एवं वृत कार्यालय गुढामालनी में 01 मुलाजमान के वर्तमान

(गृह मंत्री)

पदस्थापन पर तीन वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली है, जिन्हें स्थानान्तरण नीति के अनुसार वर्तमान पद पर पांच वर्ष तक पदस्थापन रहने के कारण स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र शिव के पुलिस थाना शिव, गिराब, गडरा रोड में आसूचना अधिकारी के अलावा कोई भी कर्मी तीन वर्ष से अधिक अवधि से पदस्थापित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के पुलिस थानों के सीमांकन हेतु गठित समिति

302. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के सभी थानों का सीमांकन किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पुलिस थानों के सीमांकन हेतु गठित समिति द्वारा क्या-क्या प्रस्ताव सरकार को दिये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बाड़मेर जिले में पुलिस थानों का सीमांकन किस प्रकार निर्धारित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2014-15 के बजट में यह घोषणा की गई थी कि एक उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से राज्य की विभिन्न प्रशासनिक यूनिट्स यथा पटवारी-ग्राम सचिव, तहसीलदार-बीडीओ एवं पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार को co-terminus किया जाएगा । समिति का गठन किया जा चुका है एवं इसकी अनुशंसा के अनुसार पुलिस थानों की सीमाओं का पुनर्गठन/सृजन किया जाएगा ।

(2) जी नहीं। उच्च स्तरीय समिति की समग्र अनुशंसा रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(3) उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित ग्राम पंचायत घुमणा में कराये गये कार्य

303. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना क्या है? उक्त योजना में सरकार द्वारा कौन-कौनसे कार्य करवाए जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र सिकराय की चयनित ग्राम पंचायत घुमणा में वर्ष 2015-16 में कौन-कौनसे कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा पूर्व में आदर्श ग्राम पंचायतों में कोई राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो उक्त राशि से कौन-कौनसे कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में ग्राम पंचायत का समग्र विकास किया जाता है जिसमें मुख्यत: निम्न कार्यकलाप शामिल हैं:-

(1) बुनियादी सुविधाए

(2) मानव विकास

(3) आजीविका

(4) सामाजिक समरसता (सामाजिक विकास)

(5) सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने के सुधार (सुशासन)

(2) विधान सभा क्षेत्र सिकराय के चयनित ग्राम पंचायत घुमणा में वर्ष 2015-16 में कराये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट - 1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। आदर्श ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों के लिये परिसम्पत्ति निर्माण निधि के तहत महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत रुपये 59.05 लाख स्वीकृत किये गये थे, जिसमें रुपये 33.62 लाख के करवाये गये कायों की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति छबड़ा व छीपाबड़ौद द्वारा कराये गये विकास कार्य

304. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बारां जिले की पंचायत समिति छबड़ा व छीपाबड़ौद में 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक ग्राम पंचायतों द्वारा विकास कार्य करवाये गये हैं? यदि हां, तो पंचायत समिति छबड़ा एवं छीपाबड़ौद में ग्राम पंचायतों द्वारा किस-किस योजना के तहत क्या-क्या कार्य करवाये गये हैं? योजना का नाम, कार्य का नाम, व्यय की गई राशि सहित ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति छबड़ा एवं छीपाबड़ौद में ग्राम पंचायतों द्वारा करवाये गये कार्यों का निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन किया गया है? यदि हां, तो कब-कब एवं किस-किस अधिकारी द्वारा? ग्राम पंचायतवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बारां जिले की पंचायत समिति छबड़ा व छीपाबड़ौद में 1 जनवरी 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक ग्राम पंचायतों द्वारा विकास कार्य करवाये गये है।

पंचायत समिति छबड़ा एंव छीपाबड़ौद में ग्राम पंचायतों द्वारा करवाये गये कार्यों का योजनावार, नामवार एवं व्यय की गई राशि का कार्यवार विवरण परिशिष्ट-1 पर अंकित है।

(2) पंचायत समिति छबड़ा एवं छीपाबड़ौद में ग्राम पंचायतों द्वारा करवाये गये कार्यों के किये गये निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन का तिथिवार, अधिकारीवार विवरण परिशिष्ट-1 के कॉलम संख्या 13 से 15 पर अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सांसद व विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष के मानदण्ड

305. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री भवानी सिंह राजावत)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष से विभिन्न समाजों की भूमि पर सामुदायिक उपयोग के निर्माण हेतु अनुशंसा की जाती थी जिसे बाद में गैर अनुमत कर दिया गया है? यदि हां, तो गैर अनुमत कब किया गया व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कोष द्वारा विभिन्न समाजों की भूमि पर सामुदायिक उपयोग के निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की जा सकती है, यदि हां, तो विधायक एवं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास में इस अंतर का कारण क्या है? क्या सरकार उपरोक्त कार्य पर लगाई रोक हटाने पर विचार करेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष से विभिन्न समाजों की भूमि पर सामुदायिक उपयोग के निर्माण हेतु अनुशंसा का प्रावधान नही है, अपितु योजना प्रारंभ से ही परिशिष्ट-1 पर संलग्न दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत संस्था/ट्रस्ट के लिए कतिपय शर्तों के साथ योजनावधि में राशि 10.00 लाख रुपये. तक की टिकाऊ प्रवृति की परिसम्पत्तियों का सृजन किये जाने का प्रावधान है।

(2) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कोष द्वारा विभिन्न समाजों की भूमि पर सामुदायिक उपयोग के निर्माण हेतु राशि स्वीकृति के सम्बन्ध में किसी सोसायटी/न्यास को एमपीलेड निधियों से परिशिष्ट-2 पर संलग्न दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार योजनावधि में राशि 50.00 लाख तक टिकाऊ प्रवृति की परिसम्पत्तियों का सृजन किये जाने का प्रावधान है।

इस प्रकार सांसद एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के वार्षिक आवंटन के अनुसार पंजीकृत संस्था/ट्रस्ट के लिए टिकाऊ प्रवृत्ति की परिसम्पत्ति निर्माण का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भरतपुर में बी.पी.एल. में चयनित परिवार

306. श्री विजय बंसल 'पप्पू बन्डा' (भरतपुर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री विजय बंसल 'पप्पू बन्डा')

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बी.पी.एल. सर्वे का कार्य काफी लम्बे समय से नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में बी.पी.एल. सर्वे कराने पर विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में गत तीन वर्षों में बी.पी.एल. में चयन करने हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये व उनमें से कितने परिवारों का चयन किया गया? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीपीएल सेन्सस- 2002 में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार 13 आर्थिक एवं सामाजिक सूचकों के आधार पर सर्वे करवाकर 52 अंकों में से अंक प्रदान किये गये थे। सर्वे से प्राप्त अंकों के आधार पर आरोही क्रम में सूचियां तैयार कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक आने वाले परिवारों को एकल कट ऑफ स्कोर के आधार पर 12 अंक प्राप्त करने वाले समस्त एवं 13 अंक प्राप्त करने वाले आंशिक परिवारों को बीपीएल सूची 2002 (ग्रामीण) में चयन किया गया था।

निर्धारित प्रक्रियानुसार भारत सरकार द्वारा बीपीएल सर्वे करवाया जाता है। इसी क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 में राज्य के समस्त परिवारों का सर्वे किया गया।

भारत सरकार के निर्देशानुसार सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 में तीन स्तरीय प्रकिया द्वारा रैंक प्रदान की गई है।

1. परिवारों का एक समूह जो गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की सूची में स्वत: अलग हो जाएगा।
2. परिवारों का एक समूह जो गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की सूची में स्वत: शामिल हो जाएगा।
3. शेष बचे परिवारों को सात वंचन सूचकांको का प्रयोग करते हुए रैंक दिया गया है। सबसे अधिक वंचन स्कोर वाले परिवारों को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) भरतपुर विधान सभा क्षेत्र में गत तीन वर्षों में बीपीएल में चयन हेतु प्राप्त आवेदन एवं उनका निस्तारण निम्नानुसार है:-

(ग्रामीण विकास मंत्री)

क्र.सं.	**वर्ष**	**बीपीएल सूची में चयन हेतु प्राप्त आवेदन एवं उनके निस्तारण की स्थिति**		
		प्राप्त आवेदन	निस्तारित प्रकरण	बीपीएल सूची 2002 में जोड़े गये परिवारों की संख्या
1.	2013-14	10	10	8
2.	2014-15	11	11	10
3.	2015-16	225	225	92
कुल योग		246	246	110

नाम सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण/प्रजनन दर में कमी लाने पर व्यय राशि

307. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के कई जिलों में प्रजनन दर 4 प्रतिशत से अधिक है? यदि हां, तो कौन-कौनसे जिलों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त जिलों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत 3 वर्षों में सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण व प्रजनन दर में कमी लाने के लिए कितनी राशि व्यय की गई है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ए.एच.एस. 2012-13 के अनुसार प्रदेश के केवल बाड़मेर जिले में प्रजनन दर 4.4 प्रतिशत है। राजस्थान एवं जिलों की प्रजनन दर परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) बाड़मेर जिले में जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु किये जा रहे प्रयासों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विगत तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण, प्रजनन दर में कमी लाने के लिए की गई व्यय राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

आई.ई.सी. ब्यूरो द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं जनसंख्या नियंत्रण हेतु विज्ञापन एवं मुद्रण कार्यों के लिए मुख्यालय स्तर पर विगत तीन वर्षों में व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के चिकित्सकों को डी.ए.सी.पी. का लाभ

308. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के चिकित्सकों को डी.ए.सी.पी. का लाभ दिया गया है? यदि हां, तो कितने चिकित्सकों को कब से एवं कितने चिकित्सक वर्तमान में उक्त लाभ से वंचित हैं व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि डी.ए.सी.पी. का लाभ मिलने के बाद कई कनिष्ठ चिकित्सक अपने वरिष्ठ चिकित्सकों से अधिक वेतन आहरित कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि 1992 में आर.पी.एस.सी. से चयनित चिकित्सा अधिकारियों को डी.ए.सी.पी. का लाभ देने के बाद भी वे अपने कनिष्ठ चिकित्सकों से बहुत कम वेतन आहरित कर रहे हैं? यदि हां, तो इस विसंगति के क्या कारण हैं व सरकार द्वारा इसे दूर करने हेतु क्या प्रयास किये गये यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। 6237 चिकित्सकों को दिनांक 11.07.2011 से फरवरी 2017 तक डी.ए.सी.पी. का लाभ दिया जा चुका है।

183 चिकित्सक जिनकी नियमित नियुक्ति पश्चात् 12 वर्ष या इससे

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

अधिक की राज्य सेवा पूर्ण हो चुकी थी एवं जिनको विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2010-11 में कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था किन्तु पदोन्नति के पश्चात् दिनांक 11.07.2011 को डी.ए.सी.पी. के वर्तमान नियमों के अनुसार पदोन्नत पद पर छह वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण नही करने के कारण, डी.ए.सी.पी. के अन्तर्गत पदोन्नति के लाभ से वंचित है।

(2) जी हां। दिनांक 11.07.2011 को 12 वर्ष एवं अधिक की नियमित राज्य सेवा पूर्ण करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को डीएसीपी स्कीम के अन्तर्गत दिनांक 11.07.2011 से ग्रेड पे 6600/- में प्रथम पदोन्नति पश्चात् 2 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 01.04.2014 से ग्रेड पे 7600/- में द्वितीय पदोन्नति प्रदान की गई है, किन्तु चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति पश्चात्, 12 वर्ष एवं अधिक की राज्य सेवा पूर्ण करने वाले चिकित्सक जिनको विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था किन्तु पदोन्नति के पश्चात् दिनांक 11.07.2011 को डी.ए.सी.पी. के वर्तमान नियमों के अनुसार पदोन्नत पद पर दो वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण नही करने के कारण, उक्त चिकित्सक डी.ए.सी.पी. के अन्तर्गत पदोन्नति के लाभ से वंचित रह गये। इस कारण उपरोक्त विसंगति उत्पन्न हुई है।

(3) वर्ष 1992 में राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सा अधिकारी जिनकी वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति हुई है, वे डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत वरिष्ठ विशेषज्ञ एवं उप निदेशक के पद पर पदोन्नत चिकित्सकों से कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं। इन चिकित्सकों को डी.ए.सी.पी. के वर्तमान नियमों के अन्तर्गत 11.07.2011 को पदोन्न्त पद पर 6 वर्ष की सेवा पूर्ण नही करने के कारण कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 08.02.2013 के अनुसार डी.ए.सी.पी. के अन्तर्गत द्वितीय पदोन्नति डी.पी.सी. से पदोन्नत पद पर 6 वर्ष की सेवा के पश्चात दी गई है, जबकि ऐसे चिकित्सक जिनकी 11.07.2011 को राजकीय सेवा में

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

12 वर्ष अथवा अधिक अवधि पूर्ण हो चुकी थी, किन्तु एक भी पदोन्नति डी.पी.सी. के अन्तर्गत नहीं की गई थी, को उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार दिनांक 11.07.2011 को प्रथम एवं तत्पश्चात् 01.04.2014 को डी.ए.सी.पी. के अन्तर्गत द्वितीय पदोन्नति प्रदान की गई है।

उक्त विसंगति को दूर करने के लिए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 में संशोधन हेतु प्रस्ताव भिजवाये गये हैं, जिन पर वित्त विभाग से सहमति प्राप्त हो चुकी है। उक्त प्रस्तावों पर कार्मिक विभाग एवं विधि विभाग से सहमति लिये जाने के उपरान्त सेवा नियमों में संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण कर उक्त विसंगति को दूर करने का प्रयास किया जायेगा।

प्रदेश में निःशुल्क दवा योजनान्तर्गत वितरित की जाने वाली दवाइयों की जांच

309. श्री रमेश (सपोटरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नि:शुल्क दवा योजनान्तर्गत वितरित की जाने वाली दवाइयों की जांच की क्या व्यवस्था है?

(2) क्या सरकार द्वारा सभी दवाओं की जांच की जाती है? यदि नहीं, तो क्यों एवं जांच का क्या आधार है?

(3) क्या यह सही है कि केवल शिकायत/आशंका होने पर ही दवाओं के सैम्पल लेने का आदेश जारी किया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार सभी दवाओं की जांच अनिवार्य करने एवं तत्पश्चात् ही वितरित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार मिलावटी/ निम्न दर्जे की दवा आपूर्ति करने वाली कम्पनी पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने का नियम बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में नि:शुल्क दवा योजनान्तर्गत वितरित की जाने वाली दवाइयों की जांच हेतु राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम के जिला औषधि भण्डार स्तर पर सप्लायर्स से प्राप्त दवाओं को जिला औषधि भण्डारों के

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

क्वारेन्टाइन एरिया में रखा जाता है। दवा के प्रत्येक बैच से सैम्पल लिये जाते है तथा टैस्टिंग हेतु निगम के मुख्यालय स्थित क्वालिटी कन्ट्रोल सेल में भेजे जाते हैं।

मुख्यालय स्थित क्वालिटी कन्ट्रोल सेल द्वारा राज्य के विभिन्न जिला औषधि भण्डारों से प्राप्त नमूनों को बैच अनुसार अलग-अलग किया जाता है। यदि एक ही बैच की दवा का नमूना कई वेयर हाउस से प्राप्त होता है, तो उसकी पूलिंग की जाती है। फिर उस नमूने पर से कम्पनी का नाम, बैच नम्बर, ड्रग लाइसेंस नम्बर इत्यादि मिटाकर उसे एक सीक्रेट कोड नम्बर दिया जाता है जिसे कोडिंग कहते है। इसके बाद उन नमूनों को टैस्टिंग हेतु इम्पेनल्ड लैबोरेट्रीज में भेजा जाता है।

इम्पेनल्ड लैबोरेट्रीज से दवा की स्टैण्डर्ड क्वालिटी की टैस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही ई-औषधि सिस्टम के माध्यम से चिकित्सा संस्थाओं को इश्यू किये जाने हेतु दवा के सम्बन्धित बैच को एक्टिव किया जाता है। इसके बाद ही जिला औषधि भण्डारों में क्वारेन्टाइन एरिया से दवाइयां भण्डारण एरिया में शिफ्ट की जाती है एवं संस्थाओं की मांग के अनुसार उन्हें इश्यू किया जाता है। यदि क्वालिटी कंट्रोल (गुणवत्ता नियंत्रण) रिपोर्ट के अनुसार कोई दवा मानकों पर खरी नहीं उतरती है, तो उस दवा को क्वारेन्टाइन एरिया से रिजेक्ट ड्रग एरिया में शिफ्ट किया जाता हैं तथा उन्हें वापस सम्बन्धित दवा कम्पनी को लौटा दिया जाता है।

(2) जी हां। नि:शुल्क दवा योजनान्तर्गत वितरित की जाने वाली सभी दवाइयों की जांच राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम द्वारा पंजीकृत एवं सरकारी प्रयोगशालाओं के द्वारा करवायी जाती है।

निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रयोगशालाओं के द्वारा दवा की जांच की जाती है। दवाइयां स्टैण्डर्डस ड्रग एक्ट के शिड्यूल के अनुसार होती है, जिनमें फार्माकोपिया दवाइयों की बुक ऑफ स्टैण्डर्डस हैं जिनके संक्षिप्त नाम आई.पी., बी.पी., ई.यू.पी., यू.एस.पी. इत्यादि है एवं इसमें दवा के मोनोग्राफ होते हैं जिनमें दवा के समस्त मानकों का एवं जांच प्रक्रिया का विवरण होता है। उसी के अनुसार निर्धारित प्रोसेस के अनुसार अत्याधुनिक मशीनों व

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

उपकरणों जैसे एचपीएलसी, जीसी, जीसी-एमएस, एफटीआईआर, यूवी, आईसीपी-एमएस इत्यादि से ही अनुमोदित कुशल केमिस्टों द्वारा दवा की जांच की जाती है। दवाइयों की क्वालिटी टैस्टिंग के स्टैण्डर्डस में उसकी आईडेन्टिटी, प्यूरिटी एवं स्ट्रैन्थ इत्यादि मानक शामिल हैं।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है कि केवल शिकायत/आशंका होने पर ही दवाओं के सैम्पल लेने का आदेश जारी किया जाता है।

दवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निगम द्वारा डबल क्वालिटी कन्ट्रोल चैक सिस्टम के तहत् चिकित्सा संस्थानों को रिलीज करने के पूर्व अपने स्तर पर पुन: इन दवाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। खरीदी गयी दवाइयों को लैबोरेटरी जांच की टैस्ट रिपोर्ट में स्टैण्डर्ड क्वालिटी की आने के बाद ही दवा को चिकित्सा संस्थानों में इश्यू किया जाता है।

शिकायत/आशंका होने पर इश्यू की गई औषधियों की पुन: जांच कराई जाती है।

(4) गुणवत्ता नीति अनुसार दवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निगम द्वारा डबल क्वालिटी कन्ट्रोल चेक सिस्टम के तहत् चिकित्सा संस्थानों को रिलीज करने के पूर्व अपने स्तर पर पुन: इन दवाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। खरीदी गयी दवाइयों को लैबोरेटरी जांच की टैस्ट रिपोर्ट में स्टैण्डर्ड क्वालिटी की आने के बाद ही चिकित्सा संस्थानों को इश्यू किया जाता है।

(5) औषधि के नमूने की जांच में मिलावटी/निम्न दर्जे की दवा पाये जाने पर दवा आपूर्ति करने वाली कम्पनी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के उद्देश्य से औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा वैधानिक नमूना लिया जाता है। तदुपरान्त राजकीय विश्लेषक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा अवमानक घोषित किये जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है एवं अधिनियम की गाइडलाइन्स के अनुसार सक्षम न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दर्ज करावाये जाते हैं।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय में लिटरेट अटेन्डेंट की पदोन्नति

310. श्रीमती रानी सिलौटिया (बसेड़ी): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत पाँच वर्षों में सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय में कितने लिटरेट अटेन्डेंट की पदोन्नति लैब अटैन्डेन्ट/लैब टैक्निशियन के पद पर हो चुकी है? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालय में लिटरेट अटैन्डेंट से लैब अटैण्डेंट/ लैब टैक्निशियन के लिए किस प्रमोशन पॉलिसी को आधार माना गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि महाविद्यालय में लिटरेट अटैण्डेंट से लेब अटैण्डेंट/लेब टैक्निशियन के पद पर पदोन्नति के लिए टाईम बाउण्ड पॉलिसी है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय में 19 लिटरेट अटैन्डेंट की पदोन्नति लैब अटैण्डेन्ट/लैब टैक्निशियन के पद पर चुकी है। नाम सहित सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) कार्मिक (क-2) विभाग, राज. जयपुर की अधिसूचना संख्या एफ.2(2) डीओपी/ए-II/97 दिनांक 18.06.2012 (छाया प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है) की अनुपालना में लैब टैक्नीशियन के पद पर पदोन्नितयां की गई हैं।

(3) जी नहीं। यह सही है कि सवाई मानसिंह महाविद्यालय में लिटरेट अटैण्डेंट से लैब टैक्निशियन के पद पर पदोन्नति के लिए टाइम बाउण्ड पॉलिसी नहीं है। किसी भी अधीनस्थ सेवा में टाइम बाउण्ड पॉलिसी की व्यवस्था नही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर जिले में उद्योग लगाने के लिये प्राप्त आवेदन

311. श्री गोरधन (धोद): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सीकर जिले में जनवरी, 2014 से जनवरी, 2017 तक उद्योग लगाने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए व उनमें से कितने लोगों को ऋण स्वीकृत

(श्री गोरधन)

करवाकर उद्योग लगवाये गए व शेष आवेदनों पर कब तक स्वीकृति जारी कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सीकर जिले में जनवरी 2014 से जनवरी 2017 तक बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान कर स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु निम्नानुसार आवेदन प्राप्त कर ऋण स्वीकृत एवं वितरण कर उद्यम स्थापित किये गये-

क्र. सं.	योजना का नाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृति संस्या	निरस्त आवेदनों की संख्या	ऋण वितरण संख्या
1.	मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना 2013 (योजना दिनांक 31.3.2014 तक प्रभावी)	14	0	14	0
2.	भामाशाह रोजगार सृजन योजना (योजना माह दिसम्बर 2015 से प्रभावी)	680	76	99	65
3.	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	302	83	189	82
	योग	996	159	302	147

शेष आवेदनों में ऋण स्वीकृति/वितरण प्रक्रियाधीन है।

नसीराबाद में औद्योगिक क्षेत्र का विकास

312. श्री रामनारायण (नसीराबाद): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार नसीराबाद में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास व विस्तार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस हेतु सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार की नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र के लिये क्या नवीनतम योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रीको द्वारा नसीराबाद के ग्राम बेवन्जा में कुल 25.74 है. भूमि पर औदयोगिक क्षेत्र स्थापित किया हुआ है। इस औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

(2) स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार किये जाने हेतु 51.99 है. निजी भूमि की अवाप्ति की जाकर दिनांक 18.03.2015 को उक्त भूमि का अवार्ड जारी किया जा चुका है तथा दिनांक 30.03.2016 तक उक्त अवाप्त भूमि में से 46.52 है. भूमि का कब्जा रीको द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। 13.38 है. राजकीय भूमि का अवांटन भी निगम के पक्ष में किया जाकर उक्त भूमि का कब्जा दिनांक 22.09.2016 को प्राप्त कर लिया गया है। नियमानुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् उक्त औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार एवं विकास किया जाना संभव हो पायेगा।

(3) नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र के ग्राम श्रीनगर में कुल 32.89 है. भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र में भू-खण्डों का नियोजन किया जाकर औद्योगिक भू-खण्डों का आवंटन शुरू कर दिया गया है।

प्रदेश में स्थानान्तरित व्याख्याताओं को योगकाल व यात्रा भत्ता देने की कार्यवाही

313. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विभाग के आदेश क्रमांक प.3 (1) शिक्षा ग्रुप-3/2012 दिनांक 31.5.2012 के द्वारा भूगोल विषय के व्याख्याताओं का स्थानान्तरण स्वयं की प्रार्थना पर व कितने व्याख्याताओं की स्थानान्तरण बिना उनकी प्रार्थना के किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आदेश में जिन व्याख्याताओं के नाम के सम्मुख स्वयं की प्रार्थना अंकित नहीं है उन सभी को योगकाल व यात्रा भत्ता दिया गया है? यदि हां, तो कितना-कितना व नहीं, तो योगकाल व यात्रा भत्ता नहीं देने के क्या कारण रहे? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विभाग में योगकाल व यात्रा भत्ता देने के लिये संदर्भित आदेश को संशोधित करने के लिये कितने आवेदन पत्र कब से लम्बित हैं व उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कैलाश भंसाली)

(4) क्या सरकार उक्त आदेश के द्वारा जिन व्याख्याताओं का स्थानान्तरण स्वयं की प्रार्थना पर नहीं किया गया है, को यात्रा भत्ता व योगकाल देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भूगोल विषय के व्याख्याताओं के स्थानान्तरण आदेश क्रंमाक प.3(1) शिक्षा/ ग्रुप-3/2012 दिनांक 31.05.2012 में स्वयं की प्रार्थना अथवा बिना उनकी प्रार्थना बाबत, अभियुक्ति आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित है। संबंधित आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) दिनांक 31.05.2012 को जारी आदेशों में भूगोल विषय के व्याख्याताओं के नाम सम्मुख स्वयं की प्रार्थना अंकित नहीं है उन सभी को योगकाल एवं यात्रा भत्ता दिये जाने संबंधी विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। तत्संबधी यात्रा भत्ता नियम की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) विभाग में योगकाल एवं यात्रा भत्ता देने के लिए उक्त संदर्भित आदेश के क्रम में एक आवेदन पत्र दिनांक 01.03.2016 को प्राप्त हुआ है। मूल आदेश में यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय नहीं होने के कारण यात्रा भत्ता एवं योगकाल नहीं दिया गया है।

(4) नियमानुसार प्रकरण का परीक्षण कर अपेक्षित कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय महाविद्यालय, हिण्डौन में विज्ञान संकाय खोलने की योजना

314. श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि हिण्डौन के राजकीय महाविद्यालय में काफी लम्बे समय से विज्ञान संकाय खोलने की मांग की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। बजट भाषण वर्ष 2017-18 में राजकीय महाविद्यालय, हिण्डौन सिटी में विज्ञान संकाय प्रारम्भ करने की घोषणा की गई है, (प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न) जिसकी अनुपालना में शैक्षणिक सत्र 2017-18 से राजकीय महाविद्यालय, हिण्डौन सिटी में विज्ञान संकाय प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर जिले के संनिर्माण श्रमिकों के लम्बित प्रकरण

315. श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के संनिर्माण श्रमिकों के लाभ के लिये कोई योजना बनाई गई हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? योजनाओं के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सीकर जिले में उक्त योजनाओं के द्वारा गत पांच वर्षों में किन-किन संनिर्माण श्रमिकों को क्या-क्या लाभ दिया गया? विधान सभा वार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनाओं में सीकर जिले के संनिर्माण श्रमिकों के कितने प्रकरण लंबित हैं? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त लंबित प्रकरणों के लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? यदि हां, तो कौन-कौन व उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त लंबित प्रकरणों का अब कब तक निस्तारण कर श्रमिकों को लाभ दे दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राजस्थान द्वारा संनिर्माण पंजीकृत हिताधिकारियों के लिए योजनाऐं बनाई गई हैं। वर्तमान में संचालित योजनाओं का नाम सहित विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

(2) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राजस्थान द्वारा लाभान्वित हिताधिकारियों का विवरण विधान सभावार संधारित नहीं किया जाकर जिलेवार संधारित किया जाता है। सीकर जिले में गत पांच वर्षों में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दिए गए हितलाभ का योजनावार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट '2' पर तथा नामवार विवरण परिशिष्ट '3' पर संलग्न है।

(3) सीकर जिले में दिनांक 15.3.2017 तक निर्माण श्रमिकों द्वारा किए गए आवेदनों में से 16783 आवेदन विचाराधीन हैं। विचाराधीन आवेदनों की नामवार सूची परिशिष्ट '4' पर संलग्न है।

(4) सीकर जिले में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या प्रदेश में सर्वाधिक है। इसी प्रकार योजनाओं के आवेदन भी बहुतायत में प्राप्त हुए हैं। विभाग में काफी पद रिक्त होने से अतिरिक्त कार्य भार देकर काम कराया जा रहा है। प्रगति की उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा की जाती है। लम्बित प्रकरणों के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(5) विचाराधीन आवेदनों के निस्तारण की नियमानुसार निरन्तर प्रक्रिया जारी है एवं विशेष प्रयास किए जाकर शीघ्र निस्तारण की कार्यवाही कर दी जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

न्यायालय सहायक कलेक्ट्रेट कार्यालय, जमवारामगढ़ का भवन निर्माण

316. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में न्यायालय सहायक कलेक्टर कार्यालय जमवारामगढ़ का भवन नहीं है तथा उक्त कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ के कार्यालय में ही संचालित किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों कार्यालय एक ही भवन में संचालित होने से 2 बजे तक एस.डी.एम. कोर्ट एवं 2 बजे बाद ए.सी.एम. कोर्ट का कार्य संचालित किया जाता है? यदि हां, तो कब से एवं क्या बार

(श्री जगदीश नारायण)

एसोसिएशन जमवारामगढ़ द्वारा भी उक्त व्यवस्था का विरोध किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के न्यायालय सहायक अधिकारी कार्यालय हेतु उपखण्ड अधिकारी कार्यालय जमवारामगढ़ के समीप ही एक न्यायालय हॉल तथा अधिकारी चैम्बर बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। सहायक कलेक्टर कार्यालय पुरानी तहसील भवन में संचालित किया जा रहा है।

नायब तहसील सायरा (उदयपुर) का तहसील में क्रमोन्नयन

317. श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नई तहसील खोलने के क्या नियम हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नायब तहसील सायरा (उदयपुर) को तहसील बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 15 सन, 1956) की धारा 15 एवं 16 के अन्तर्गत तहसील गठन/पुनर्गठन के संबंध में शक्तियां राज्य सरकार में निहित हैं।

प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2014-2015 में की गई बजट घोषणा संख्या 196 के अनुसार राज्य में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों को सह सीमान्त क्षेत्राधिकार कर प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार पुनर्गठन/सृजन किये जाने संबंधी प्रकरण उच्च स्तरीय समिति में विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 318

(स्थगित)

निवाई के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण का कार्य

319. श्री हीरालाल (निवाई): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई शहर में नरूका राजाओं के प्राचीन महल रक्तांचल पर्वत की तलहटी में स्थित ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहरों को नुकसान पहुंचाने के कारण इन ऐतिहासिक स्मारकों के विलुप्त होने का खतरा है? यदि हां, तो क्या सरकार गत 5 वर्षों में उक्त ऐतिहासिक स्मारकों के साथ तोड़फोड व छेड़छाड़ करने वाले व्यक्तियों को दण्डित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण व संवर्द्धन हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई शहर में नरूका राजाओं के प्राचीन महल रक्तांचल पर्वत की तलहटी में स्थित स्मारक/स्थल पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित घोषित नहीं हैं।

पुरातत्व विभाग द्वारा केवल संरक्षित स्मारकों व स्थलों के संबंध में ही विभागीय अधिनियमों/नियमों के तहत कार्यवाही की जाती है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में इन स्मारकों/ स्थलों के संरक्षण व संवर्द्धन का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं हैं।

बसवा (बांदीकुई) की डाइट शिक्षण संस्था की मान्यता समाप्त करने का प्रकरण

320. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के बसवा में डाइट

(श्रीमती अलका सिंह)

शिक्षण संस्था की मान्यता कुछ समय पूर्व समाप्त कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त संबंध में सरकार के स्तर पर कोई प्रयास किये गये हैं? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बसवा डाइट में अध्ययनरत छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, जयपुर द्धारा पत्रांक एनआरसी/ एनसीटीई/ राज-266/ 208वीं मीटिंग/ 2012/ 37405-407 दिनांक 04.02.2013 के द्धारा डाईट, बसवा, दौसा की मान्यता के संबंध में 2000 वर्गफीट का मल्टी परपज हॉल नहीं होने के कारण अस्वीकृति आदेश (Refusal Order) जारी किया गया।

(2) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) दौसा के मान्यता प्रकरण के संबंध में विभाग स्तर पर किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

विभाग स्तर पर डाइट, बसवा (दौसा) को आगामी सत्र में एनसीटीई से मान्यता प्रदान करने हेतु प्रयास जारी है एनसीटीई द्धारा लगाये गये आक्षेपों की पूति हेतु 2000 वर्गफीट के मल्टीपरपज हॉल के निर्माण हेतु भवन निर्माण मद में 108.00 लाख रुपये बजट प्रावधान करवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें से वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमानों में 21.28 लाख रुपये की राशि प्रावधिक हो चुकी है तथा आगामी सत्र में एनसीटीई से मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(3) डाइट बसवा (दौसा) में अध्ययनरत छात्रों का उनके इच्छित अन्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त सीटों के अनुसार स्थानान्तरण कर दिया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य अंश में उपलब्ध कराई गई राशि

321. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के दायित्वों के कार्यान्वयन हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच राशि के वितरण के लिये क्या नये प्रावधान किये गये हैं तथा राज्यों को धनराशि जारी करने हेतु क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या तेरहवें वित्त आयोग ने देश में सर्व शिक्षा अभियान सहित प्रारंभिक शिक्षा के वित्त पोषण की आवश्यकता का आंकलन किया था? यदि हां, तो वित्त आयोग द्वारा इस संबंध में किये गये आवंटन का ब्योरा क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या केन्द्र सरकार का शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु राज्यों का वित्तीय बोझ कम करने का कोई प्रस्ताव है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में राज्य को किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि उपलब्ध करवायी गई? राज्य सरकार ने राज्य अंश के रूप में कितनी-कितनी राशि उपलब्ध करायी तथा राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई? वर्षवार व मदवार उपलब्ध राशि व व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के दायित्वों के कार्यान्वयन हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार और राज्य सरकारो के बीच वित्तीय पोषण (Funding Patten) हेतु निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:-

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

वर्ष	वित्तीय पोषण (Funding भारत सरकार: राज्य सरकार
2014-15	65:35
2015-16	60:40
2016-17	60:40

भारत सरकार द्वारा राशि राज्य सरकार के संचित निधि खाते में जारी की जाती है। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त राशि एवं अपने हिस्से की राशि सर्व शिक्षा अभियान के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित की जाती है।

(2) तेरहवें वित्त आयोग के तहत सर्व शिक्षा अभियान सहित प्रारम्भिक शिक्षा के वित पोषण का आंकलन करते हुए निम्नानुसार राशि आंवटित की गई थी:-

लाखों में

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	प्राप्त राशि
1	2010-11	28700.00
2	2011-12	32000.00
3	2012-13	35600.00
4	2013-14	39400.00
5	2014-15	40900.00

(3) यह बिन्दु केन्द्र सरकार से संबंधित है। राज्य सरकार को इस तरह का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा राशि मदवार उपलब्ध नही कराई जाकर एकमुश्त उपलब्ध कराई जाती है। विगत तीन वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा वर्षवार निम्नानुसार राशि उपलब्ध कराई गई है:-

लाखों में

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	प्राप्त राशि	
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार
1	2013-14	242488.70	112899.97
2	2014-15	248041.55	123023.59
3	2015-16	193462.09	213209.12

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

सर्व शिक्षा अभियान द्‌वारा विगत तीन वर्षों में निम्नानुसार राशि व्यय गई है:-

S.No.	Name of Activities	2013-14	2014-15	2015-16
1	Teacher Salary	323200.09	366905.79	371302.94
2	Free Text Book for UPS SC/ST	19.67	1157.97	1135.40
3	Civil Work	12345.50	22658.99	12546.11
4	Maintenance Grant	0.00	3264.68	3523.31
5	School Grant	5981.08	6182.70	5875.62
6	Teachers Training	856.96	832.87	1348.07
7	Training for Community Leaders SMC PRIS	216.20	443.24	506.91
8	Provision for Disabled Children	1106.04	835.33	1062.27
9	Research Evaluation Supervision and Monitoring	72.65	253.01	205.42
10	Management Cost	8512.20	8371.10	7630.63
11	Innovation Activits	395.57	29.69	735.54
12	LEP	0.00	71.49	276.36
13	Community Mobilization (0.04%)	0.00	7149	276.36
14	Block Resource Center	5067.76	7574.38	7202.09
15	Cluster Resource Center	256.55	239.71	339075
16	Interventions for Out of School Children (Special Training- Res Non. Res. Migratory Hostels)	814.11	121.28	184.82
17	Residential School for Speciaol Category of Childern	252.05	259.44	348.54

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

S.No.	Name of Activities	2013-14	2014-15	2015-16
18	Residential Hostels of School for Special Category of Children	9.64	34.34	
19	Transport Escort Facility	11.17	0.00	0.00
20	25% Reembursement of Fee Under RTI:	0.00	0.00	4171.21
21	KGBV	4968.32	6355.00	6552.27
22	NPEGEL	14.84	0.00	0.00
	Total	364100.39	425638.41	425635.44

कोटा जिले के विद्‌यालयों में मध्याह्‌न भोजन उपलब्ध कराने की योजना

322. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत् संस्थानों के द्‌वारा विद्‌यालयों में मध्याहन भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है? यदि हां, तो जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कोटा जिले में उक्त योजना में किन-किन संस्थानों के द्‌वारा कितने बच्चों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य था तथा वर्तमान में इससे कितने बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं? गत तीन वर्षों का माहवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्‌वारा जिले के उक्त संस्थानों को गत तीन वर्षों में कितनी-कितनी राशि तथा अनाज उपलब्ध करवाया गया? माहवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में मिड-डे-मील योजनान्तर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे संस्थानो द्‌धारा विद्‌यालयों में मध्यान्ह्‌ भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) पिछले तीन वर्षो से कोटा जिले में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे कोई भी संस्थान योजनान्तर्गत भोजन वितरण का कार्य नहीं कर रहे हैं।

(3) बिन्दु संख्या 02 के अनुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट

मांग संख्या 24 - शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-24 मुख्य शीर्षक **शिक्षा, कला एवं संस्कृति** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/ करेंगी कि:-

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, शेरगढ़ को शास्त्री महाविद्यालय स्तर पर क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के पंचायत मुख्यालय कनोड़िया पुरोहितान, खुडियाला, बेलवा, राणाजी, सोलंकिया तला सहित नव सृजित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
3. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के राजकीय महाविद्यालय बालेसर में व्याख्याताओं के रिक्त पद भरने, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग एवं एन.सी.सी. स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

4. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन ग्राम पंचायतों में रा.उ.मा.विद्यालय स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
5. प्रदेश में तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की नई भर्ती नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
6. प्रदेश में अनार्थिक एवं एकीकरण के अन्तर्गत बंद हुए स्कूलों को पुन: चालू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।
7. प्रदेश के द्वितीय श्रेणी के वरिष्ठ अध्यापकों के छठे वेतनमान आयोग में दिये गये वेतनमान की विसंगति को दूर नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर):

8. विधान सभा क्षेत्र अलवर में शहर के पटरीपार क्षेत्र में राजकीय सीनियर सैकेण्डरी बालिका विद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

9. उपखण्ड मुख्यालय शेरगढ़ में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर):

10. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के ब्यावर शहर में महिला कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

11. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में रा.उ.प्रा.वि. शरोफोबाला, रूपनगर अरनाली, कालिंजर, बिच्छुचौड़ा, सरूपा, रामपुरादुदा, मालीपुरा, मेड़तातान, गणेशपुरा, गोविन्दपुरा, रावली, फतेहपुर प्रथम, सेन्दड़ा रोड ब्यावर एवं हाउसिंग बोर्ड ब्यावर को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय दूधालेया, ब्यावरखास, बाघमाल, खोड़माल, अनाकर को राजकीय उ.मा.वि. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भजनलाल जाटव (वैर):

13. विधान सभा क्षेत्र वैर के प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय को उ.मा.वि. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

मास्टर मामनसिंह यादव (तिजारा):

14. विधान सभा क्षेत्र तिजारा के भिवाड़ी में महाविद्यालय आजादी के समय से बनी उप तहसील टपूकड़ा में कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना):

15. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के उपखण्ड मुख्यालय सिणधरी एवं तहसील मुख्यालय समदड़ी पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

(श्री हमीरसिंह भायल)

16. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की सीनियर विद्यालय-सिवाना में कृषि विज्ञान विषय एवं सिणधरी (छात्र) में विज्ञान संकाय, सिणधरी (बालिका) में भूगोल विषय प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के भवन विहीन रा.उ.मा.वि. के नये भवन रमसा के तहत बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सैकण्डरी/ सीनियर सैकण्डरी विहीन ग्राम पंचायतों में विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पंचायत मुख्यालय को छोड़कर प्राथमिक से उच्च प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर):

20. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में झालामण्ड विद्यालय में विज्ञान, गृह विज्ञान एवं जीव विज्ञान की कक्षाएं प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. फतेहपोल, जोधपुर के उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान एवं गृह विज्ञान विषय प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में झालामण्ड एरिया में खेल स्टेडियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम):

23. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की सभी ग्राम पंचायतों के विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के विद्यालय भवनों के नवीन कक्षा कक्ष बनाये जाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली):

26. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के समस्त विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में संस्कृत महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

28. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की प्रत्येक ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में नाट्य एवं संगीत के सरकारी स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. राज्य में कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

31. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में उपखण्ड मुख्यालय फलौदी पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा-द्वितीय जोधपुर को स्थानान्तरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में उपखण्ड मुख्यालय फलौदी पर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-द्वितीय जोधपुर को स्थानान्तरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में जयनारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय फलौदी में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में जयनारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय फलौदी में विभिन्न संकायों में सीटों में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फलौदी में अंग्रेजी साहित्य विषय शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर):

36. विधान सभा क्षेत्र आहौर में रा.मा.वि. गोदन, आईपुरा, बांकली व सिवणा को रा.उ.मा.वि. में एवं रा.उ.प्रा.वि. देलदरी को रा.मा.वि. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. विधान सभा क्षेत्र आहौर में रा.उ.मा.वि. ऊण, शंखवाली में वाणिज्य संकाय एवं रा.उ.मा.वि. पादरली में विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. विधान सभा क्षेत्र आहौर के राजकीय महाविद्यालय, आहौर में वाणिज्य संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री रतन लाल जलधारी (सीकर):</u>

39. विधान सभा क्षेत्र सीकर में राजकीय कन्या महाविद्यालय को राजकीय श्री कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भवन में स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. विधान सभा क्षेत्र सीकर के श्री कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विज्ञान संकाय को सबलपुरा स्थित कन्या महाविद्यालय के नये भवन में स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. विधान सभा क्षेत्र सीकर स्थित चारण का बास व कटराथल राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):</u>

42. रा.उ.मा.वि. किशनगढ़ (अजमेर) में कृषि विज्ञान विषय प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. रा. शाईन बालिका मा.वि. कृष्णापुरी मदनगंज किशनगढ़ (अजमेर) के नवीन शाला भवन परिसर में छह अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. सुराज संकल्प यात्रा 2013 के दौरान पं.स. एवं तहसील मुख्यालय अरांई (अजमेर) कस्बे में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की समुचित क्रियान्विति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

45. आर.के. पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ (अजमेर) में स्नातकोत्तर स्तर पर चित्रकला एवं रसायन शास्त्र विषय में अध्ययन की सक्षम स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):</u>

46. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन विद्यालयों में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नये संकाय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

49. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित राजकीय महाविद्यालय रामगंजमण्डी में रिक्त व्याख्याताओं सहित अन्य पदों की नियुक्ति एवं महाविद्यालय में नये संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर):

50. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 75 आर बी रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर) के मर्ज होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

51. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 90 जी बी पं.स. अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर) में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह "आक्या" (चित्तौड़गढ़) :

52. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के राजकीय कन्या महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

53. एम.पी.पी.जी. कॉलेज चित्तौड़गढ़ में एम.एससी. रसायन शास्त्र की सीटें बढ़ाने एवं एम.एससी. वनस्पति शास्त्र की नवीन कक्षाएं प्रारम्भ किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

54. एम.पी.पी.जी. कॉलेज चित्तौड़गढ़ में स्ववित्त पोषित विषय भूगोल की कक्षाएं राजकीय खर्च पर संचालन कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अजीत सिंह (टोंक):

55. विधान सभा क्षेत्र टोंक में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

56. राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

57. रा.उ.मा.वि. सिटी नं. 12, टोंक में ऐच्छिक विषय हिन्दी एवं संस्कृत खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

58. राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

59. राजकीय महाविद्यालय, टोंक में स्नातकोत्तर कक्षाओं में जीव विज्ञान एवं संस्कृत विषय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर):

60. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में विद्यालयवार पोषाहार हेतु किचन शेड एवं गैस

(श्री अमृतलाल)

कनेक्शन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में विद्यालयवार शिक्षक एवं छात्रों की संख्या के संबंध में चर्चा के लिये ।

62. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कला एवं संस्कृति को बढ़ाने हेतु किये जा रहे कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

63. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

64. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के विद्यालयों में बालक-बालिकाओं के शौचालय निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

डॉ. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर):

65. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के विद्यालयों में पीने के पानी, विद्युत, किचन शेड़, टॉयलेट एवं शौचालयों की उपलब्धता के संबंध में चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में संचालित विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण एवं क्षतिग्रस्त भवन एवं कक्षा-कक्षों की मरम्मत कराने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में स्थित मनसा माता शक्ति पीठ के विकास के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर):

70. प्रदेश में तृतीय श्रेणी के शिक्षकों को नियमित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

71. प्रदेश में प्राइवेट उच्च माध्यमिक स्कूलों के गांव में विद्यमान होने की स्थिति में राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

72. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के ग्राम धीरेरा, सहजरासर, कालू, बामणवाली एवं सहनीकलां के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों को रमसा कार्यक्रम में बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय, ग्राम महाजन को राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74. बीकानेर में मुख्य मंत्री महोदया द्वारा गत बजट सत्र में तकनीकी विश्वविद्यालय की घोषणा के बावजूद उसकी स्थापना हेतु इस सत्र में विधेयक न लाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद):

75. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के शिवालय पौराणिक एवं ऐतिहासिक मन्दिर चारचौमा तहसील दीगोद को पर्यटन सर्किट से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय अध्यापकों एवं व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल, शौचालय एवं फर्नीचर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के सुखराय मन्दिर दूनपुर तहसील सांगोद के जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (कपासन):

79. विधान सभा क्षेत्र कपासन के सभी विद्यालयों में रिक्त शैक्षणिक पदों पर पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर):

80. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में राजकीय महिला महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

81. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के प्रत्येक प्रा.वि., उ.प्रा.वि., मा.वि., उ.मा.वि. में खेल सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री मनोज कुमार)

82. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में द्वितीय श्रेणी अध्यापकों की वेतन विसंगति दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानान्तरण के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री मानसिंह किनसरिया (परबरतस)</u>:

84. विधान सभा क्षेत्र परबतसर की ग्राम पंचायत खारड़िया के बेवली ग्राम में माध्यमिक विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा)</u>:

85. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में बंद रा.प्रा.वि. भीलवाड़ा (असारीवाड़ा), वेणदरी (खेड़ाघाटी), निचलीडेरी, उपलाकला विद्यालय को पुन: प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा में प्रथम वर्ष में कला वर्ग में सीटें बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

87. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में ऋषभदेव को केसरियाजी मंदिर, सालण बावजी, करकेला भैरव को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में राजकीय महाविद्यालय ऋषभदेव में उपखण्ड मुख्यालय पर कॉलेज खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

89. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के ग्रामीण जनजाति बहुल क्षेत्र के संस्कृति पहनावा, आभूषण एवं गहनों को संग्रहालय में रखने एवं एम.बी.सी. संग्रहालय, खैरवाड़ा का विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डॉ. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़)</u>:

90. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में प्रारंभिक व माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

91. राज्य की विभिन्न साहित्य, कला व संस्कृति अकादमियों को पर्याप्त अनुदान नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

92. राजकीय महाविद्यालय, नवलगढ़ में रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

93. सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षा के प्रति बरते जा रहे भेदभाव व उपेक्षा के कारण संस्कृत शिक्षा पर पड़ रहे प्रतिकूल असर के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

94. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के विद्‌यालयों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

95. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के रा.उ.प्रा.वि. झीड़ा, कानपुरा, दम्बाकाबास, रामसिंह का बास, सबलपुरा, गौरी का बास, चारण बास (आलीसर) को माध्यमिक विद्‌यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

96. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम पंचायत अणतपुरा-चिमनपुरा, कुशलपुरा, नांगल-गोविन्द, धोबलाई, गुडलिया, यक्तिकपुर, डोला का बास, सान्डसर, जयसिंहपुरा में रा.सी.बा.स्कूल खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

97. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में संचालित विद्‌यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

98. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के रा.उ.मा.वि.धोसा में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास):

99. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के रा.उ.मा.वि. बुढीबावल में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

100. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के रा.उ.मा.वि. कोटकासिम में विज्ञान संकाय में गणित विषय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

101. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास रा.मा.वि. आकोली बिलाहेड़ी, उजौली,गुणसार मोठूका, दौगड़ा एवं जिलौता को रा.उ.मा.वि. में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

102. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के रा.उ.प्रा.वि. अहीर बासना, खरौला, जखोपुर, दादरहेड़ा, गूजरीवास, आड़का व शेरपुर को रा.मा.वि. में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

103. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के ग्राम पंचायत मुख्यालय लाड़पुर में राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्‌यालय को राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्‌यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर):

104. विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में स्थित राजकीय विद्‌यालयों में नवीन संकाय खोलने एवं क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जयराम जाटव (अलवर):

105. अलवर जिले में राजकीय महाराजा भर्तृहरी स्थल पर संस्कृति को जीवंत रखने हेतु पुरातत्व विभाग द्वारा कारगर उपाय करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

106. राजकीय कन्या महाविद्यालय, बाड़मेर को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

107. राजस्थान की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाली मांगवियार जाति के शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास के संबंध में चर्चा के लिए।

108. बाड़मेर की बहुआयामी होलीपाट कला को सहेजने के संबंध में चर्चा के लिए।

109. बाड़मेर में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में ग्राम पंचायत बाड़मेर मगरा, बाड़मेर ग्रामीण एवं जूना पतरासर में माध्यमिक विद्यालय खोलने एवं जिन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं, वहां पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोरधन (धोद):

111. विधान सभा क्षेत्र धोद में माध्यमिक विद्यालय सिंगरावट, शाहपुरा, सखड़ी, गोढडाते गलान, श्यामपुरा को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुखराम विश्नाई (साचौर):

112. सांचौर में स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय को प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में बंद की गई राजीव पाठशाला को पुन: प्रारंभ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

114. प्रदेश में राजकीय पाठशालाओं में विद्यार्थियों की स्कूल यूनीफोर्म को नीले रंग में बदलने के संबंध में चर्चा के लिए।

115. सांचौर में पश्चिमी संस्कृति को बचाये रखने के लिए कला एवं संस्कृति केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116. सांचौर के राजकीय स्कूलों में पानी, बिजली की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा)</u>:

117. सन्त सुन्दरदास राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दौसा में स्नातक स्तर पर अंग्रेजी, भूगोल, संस्कृत, लोक प्रशासन एवं स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीति विज्ञान विषय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

118. पं. नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दौसा में विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, गणित एवं कला महाविद्यालय, दौसा में स्नातक स्तर पर संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, लोक प्रशासन तथा स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल एवं हिन्दी विषय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

119. पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, दौसा में नवीन विषय सिविल, मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल शाखा खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

120. ग्राम पंचायत सिण्डोली, खान भांकरी एवं हिंगोटिया में तथा ग्राम ठिकरिया में संचालित माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

121. राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, दौसा को शास्त्री से आचार्य स्तर पर क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा)</u>:

122. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में ग्राम पंचायत मुख्यालयों काकेलाव, रावर की ढाणी, खातियासनी, जालेली दईकड़ा, लवारी एवं सिंधीनगर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उ.मा.वि. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के रा.उ.प्रा.वि. आदर्श मगरी बिलोड़ा, वार्ड नं. 10 उचियार्डा बेरापीपाड़ शहर, बीनावास, बीरावास, बिरड़ावास, सोवणिया, हर्ष एवं जालखा को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय खारिया मीतापुर, खेजड़ला, रणसीगांव, बीसलपुर, डांगियावास, फिटकासिनी एवं जालेली अंहिचा को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125. राजकीय महाविद्यालय, बिलाड़ा में विज्ञान संकाय एवं राजकीय महिला

(श्री अर्जुन लाल)

महाविद्यालय, पीपाड़ शहर में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में राजकीय महिला विद्यालय एवं पीपाड़ शहर में राजकीय महाविद्यालय (सह शिक्षा) की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन)</u>:

127. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के राजकीय उच्च मध्यमिक विद्यालय, खिवाड़ा में विज्ञान के साथ गणित विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

128. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, डुठारिया को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

129. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में पंचायत हैडक्वार्टर राणावास, मलसावावड़ी, गुडारामसिंह, जाड़ण एवं वरकाणा के माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

130. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की ग्राम पंचायत चौकदिया के ग्राम बोगला के माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हरिसिंह रावत (भीम)</u>:

131. विधान सभा क्षेत्र भीम के समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यकतानुसार वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

132. विधान सभा क्षेत्र भीम में समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मंत्रालयिक एवं शिक्षक, व्याख्याताओं व प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र भीम के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

134. राजकीय महाविद्यालय, भीम को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री हरिसिंह रावत)

135. राजकीय महाविद्यालय, भीम में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री छोटू सिंह (जैसलमेर)</u>:

136. बालिका स्कूल जैसलमेर को क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

137. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

138. जैसलमेर जिले के पहाड़ी क्षेत्र में स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

139. जैसलमेर की कला एवं संस्कृति को बनाये रखने के लिए ठोस उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140. जैसलमेर जिले में प्राचीन सांस्कृति को बढ़ावा देने के लिये प्रदर्शनी लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं)</u>:

141. विधान सभा क्षेत्र बेगू में गंगरार (महादेव) के पौराणिक महत्व को ध्यान में रखते हुए पर्यटन के रूप में(सारणेश्वर महादेव) विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण)</u>:

142. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर (ग्रामीण) में वनवासी परिवारों को लकड़ी के खिलौने को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिए।

143. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर (ग्रामीण) में मेवाड़ संभाग के गवरी नृत्य को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिए।

144. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की ग्राम पंचायत नाई की उ.मा.वि. में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

145. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में ग्राम पंचायत कलडवांस की एकलिंगपुरा और ग्राम पंचायत बलीचा के ग्राम नया खेड़ा के सेंकण्ड्री स्कूल को हायर सेंकण्ड्री स्कूल में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री खेमाराम (सुजानगढ़):</u>

146. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के ग्राम गिरवरसर, उडवाडा, नोरंगसर, मून्दड़ा,

(श्री खेमाराम)

ऊंटालड, जागलसर, बोखासर, गुडावणी, अमरसर एवं नोहडिया के माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

148. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के बीदासर (चूरू) में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

149. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ (चूरू) में कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भँवरसिंह (कोलायत):

150. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक व अन्य रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

151. कपिल सरोवर कोलायत को धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित करने तथा कोलायत पर्यटन मेले का बजट 10 लाख करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. कोलायत में राजकीय महाविद्यालय खोलने तथा बीकानेर मे तकनीकी विश्वविद्यालय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153. विधान सभा क्षेत्र कोलायत की मढ़, नेणिया, माधोगढ़, गंगापुर, अंगणेऊ, लाखासर आदि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी):

155. विधान सभा क्षेत्र लूणी की रा.उ.मा.वि. शाहपुरा (कुड़ी) मोगड़ाकलां, दुन्दाड़ा, सांगरिया, बोरानाड़ा में विज्ञान संकाय खोलने एवं रा.उ.मा.वि. डोली में भूगोल एवं अंग्रेजी साहित्य का अतिरिक्त विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. विधान सभा क्षेत्र लूणी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पीपरली, लूणावास, खारा,

(श्री जोगाराम पटेल)

मोडी जोगियान, झालामण्ड, पाल, कालीजाल, चौखा, इन्द्रोका, जोलियाली बड़ली, माणकलाव, चावण्डा, नान्दड़ा कलां में स्थित रा.मा.वि. को रा.उ.मा.विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. विधान सभा क्षेत्र लूणी की रा.उ.प्रा.वि. मेलबा, दूदिंया, बम्बोर पुरोहितान, मध्य पूर्व गंगाणा, कटाहरडा बासनी झूठा को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158. विधान सभा क्षेत्र लूणी के उपखण्ड मुख्यालय लूणी में महिला महाविद्यालय/ महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):

159. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कराये गये कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

160. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने एवं स्टॉफिंग पैटर्न के अन्तर्गत समाप्त किये गये पदों के संबंध में चर्चा के लिए।

161. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के विद्यालयों में संकाय परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

162. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, इटावा के पद को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामपाल (बारां-अटरू):

163. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के अटरू उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

164. अटरू में स्थित गड़गच मंदिर का पुनरुद्धार करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़):

165. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में सीनियर सैकण्डरी स्कूल विहीन पंचायतो में सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

166. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के दूर-दराज टिब्बा क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल को मिडल स्कूल में एवं मिडल स्कूल को हाई स्कूल में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

167. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्तियां करने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

168. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के विद्यालय भवनों में बिजली-पानी एवं छात्रों को बैठने के लिये भी फर्नीचर की उचित व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर):

169. विधान सभा क्षेत्र आमेर के सभी ग्राम पंचायतों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुन्झुनूं):

170. राज्य में प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं के जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय महाविद्यालयों में नवीन विषय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा):

172. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

173. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में रा.उ.मा.विद्यालयों में विषय व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

174. विधान सभा क्षेत्र मसूदा की ग्राम पंचायत अन्धेरी देवरी में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

175. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी):

176. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में रा.उ.मा.वि. एवं रा.मा.वि. में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

177. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के रा.उ.मा.वि. बोहेड़ा में गणित विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी):

178. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के ग्राम पंचायत मुख्यालय जहाज व पापड़ा के माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री शुभकरण चौधरी)

179. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में रा.उ.प्रा.वि. न्यू उदयपुरवाटी को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

180. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में राजकीय महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

181. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के गुढ़ा गौड़जी की पहाड़ी पर ऐतिहासिक शिव मंदिर व धरोहर का जीर्णोद्धार कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

182. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में पुरानी जीर्ण-शीर्ण बावड़ियों एवं प्राचीन छतरियों का संरक्षण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

183. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के नारायणपुर में आवासीय विद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

184. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के नारायणपुर में कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

185. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में सरकारी नवीन महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल (निवाई):

186. विधान सभा क्षेत्र निवाई-पीपलू के पीपलू उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय व निवाई उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

187. विधान सभा क्षेत्र निवाई-पीपलू के निवाई तहसील की छह पंचायत मुख्यालयों पर रा.मा.विद्यालयों को रा.उ.माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र निवाई-पीपलू की तहसील निवाई के राजकीय उ.मा. विद्यालय, निवाई में भूगोल, रा.बा.उ.मा. विद्यालय, निवाई में गणित व रा.उ.मा.विद्यालय, झिलाय में विज्ञान विषय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

189. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के विद्यालयों में पर्याप्त स्टाफ लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू):

190. रा.उ.मा.वि. बायतू, बाड़मेर में कृषि विज्ञान विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
191. प्रदेश भर में प्राथमिक विद्यालयों के समायोजन उपरान्त खाली भवनों की उपयोगिता के संबंध में चर्चा के लिए।
192. विधान सभा क्षेत्र बायतु, बाड़मेर के ऐतिहासिक संगमरमर के कुंए का जीर्णोद्धार करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
193. बाड़मेर जिले के संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा):

194. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में उच्च माध्यमिक विद्यालय से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों में विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
195. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में रमसा के अन्तर्गत निर्माण कार्यों को करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।
196. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में रमसा अन्तर्गत हुए घटिया निर्माण कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रमेश (सपोटरा):

197. जिला करौली में नवीन आदर्श विद्यालयों की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।
198. जिला करौली में नवीन राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी):

199. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में राजकीय बालिका महाविद्यालय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।
200. तहसील बस्सी के नई का नाथ धाम को पर्यटन स्थल का दर्जा दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम):

201. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में कन्या महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर):

202. आर.डी. गर्ल्स कॉलेज, भरतपुर में स्नातक स्तर पर भूगोल विषय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।
203. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की ग्राम पंचायत मुख्यालय मुरवारा के सैकण्डरी स्कूल को हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।
204. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की ग्राम पंचायत रूंध इकरन के ग्राम बझेरा के सैकण्डरी स्कूल को हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।
205. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की ग्राम पंचायत मडरपुर के ग्राम बाराकुर के मिडल स्कूल को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।
206. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की ग्राम पंचायत बिलोठी के ग्राम नंगला बिलोठी के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

207. बाड़ी महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
208. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में जिन पंचायत मुख्यालयों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है उनमें उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
209. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार अध्यापकों एवं लिपिकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
210. बाड़ी महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

211. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में नयी एवं पुरानी ग्राम पंचायत में सीनियर स्कूल क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में 12 मिडिल स्कूलों को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
113. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ को उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

214. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में नौगांवा के माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय प्रारंभ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू):

215. विधान सभा क्षेत्र चाकसू के वार्ड नं. 1 में स्थित संस्कृत विद्यालय को प्रवेशिका से उपाध्याय स्तर में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

216. विधान सभा क्षेत्र चाकसू के ग्राम चितौड़ा, झाड़ला, पहाड़िया, बल्लूपुरा, काठावाला में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़):

217. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ नगर पालिका में स्थित क्षतिग्रस्त दुर्ग (किले) का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

218. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में व्याख्याताओं एवं अन्य संवर्गों के रिक्त पड़े पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

219. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

220. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के घड़साना ब्लॉक में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू):

221. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में आदिवासी गरासिया समाज के बच्चों के लिये स्कूल खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

222. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा के रा.मा.वि. आमथला, बसंतगढ़, ठण्डीवेरी को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार (किशनगंज):

223. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहाबाद क्षेत्र में प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

224. बारां जिला मुख्यालय से 16 किमी. दूर किशनगंज कस्बे में होली के पावन पर्व पर लगभग 131 वर्षों से लगातार स्थानीय लोगों के सहयोग से आयोजित फूल डोल लोकोत्सव में कला एवं संस्कृति की सजीव झांकियां प्रदर्शित होती हैं।

(श्री ललित कुमार)

उक्त कार्यक्रम को और अधिक भव्य बनाने हेतु सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने एवं पर्यटन विभाग के कलैण्डर में सम्मिलित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर):</u>

225. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में दसवीं को क्रमोन्नत करने हेतु 40 बच्चों की अनिवार्यता हटाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल):</u>

226. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में पंचायत केन्द्र पर माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती संजना आगरी (सोजत):</u>

227. विधान सभा क्षेत्र सोजत के रायपुर उपखण्ड पर महाविद्यालय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

228. विधान सभा क्षेत्र सोजत के देवली कलां ग्राम पंचायत में रा.बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

229. सोजत शहर राजकीय महाविद्यालय में पेयजल की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़):</u>

230. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के वुहाणा में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

231. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में ग्राम ठाठोत में रा.उ.मा.वि. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री दलीचन्द डांगी (मावली):</u>

232. विधान सभा क्षेत्र मावली में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

233. विधान सभा क्षेत्र मावली में राप्रावि, राउप्रावि, रामावि, राउमावि में पीने का पानी, विद्युत, खेल मैदान एवं प्रार्थना स्थल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

234. विधान सभा क्षेत्र मावली के रामावि, राउमावि में भूगोल विज्ञान, विषयाध्यापक एवं लैब-इन्स्ट्रूमेंट्स, प्रायोगिक आइटम्स उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री दलीचन्द डांगी)

235. विधान सभा क्षेत्र मावली में राप्रावि को राउप्रावि में, राउप्रावि को रामावि में क्रमोन्नत करने एवं वंचित पंचायत मुख्यालयों पर राउमावि खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

236. विधान सभा क्षेत्र मावली में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा):</u>

237. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में रा.मा.वि. धन्धुरी, महतसर एवं कंकड़ेऊ कलां में राउमावि में क्रमोन्नत करने एवं नवीन महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल):</u>

238. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में विद्यार्थी मित्रों को स्थायी करने की आवश्यकता पर चर्चा लिए।

239. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में नये विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

240. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में नवोदय विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

241. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के विद्यालयों में आधारभूत सुविधाए उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

242. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के विद्यालयों में अध्यापकों को व अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर):</u>

243. विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर (सीकर) में उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन ग्राम पंचायत मुख्यालयों के माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

244. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीमाधोपुर (सीकर) में विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान विषय और खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

245. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीमाधोपुर (सीकर) में कृषि विज्ञान संकाय के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

246. विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर (सीकर) में राजकीय माध्यमिक विद्यालय को

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

247. प्रदेश के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों जिनमें कक्षा दस में सौ से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उन विद्यालयों में वर्तमान एकल संकाय के अध्ययन की सुविधा को बढ़ने हेतु अतिरिक्त संकाय के अध्ययन स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

248. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में राउमावि विज्ञान नगर व श्रीनाथपुरम में विज्ञान संकाय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।
249. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में हाड़ौती पर्यटन सर्किट को विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।
250. प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में शिक्षा सुधारने हेतु विद्यालयों में स्कूली बच्चों के लिये ड्रेस, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):

251. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में एकीकरण के नाम पर बन्द की गई स्कूलों को पुन: शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिए।
252. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में तीन या तीन वर्ष से अधिक पुरानी बालिका उच्च प्राथमिक व बालिका माध्यमिक स्कूलों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।
253. विधान सभा क्षेत्र खींवसर व नागौर के ग्राम पंचायत मुख्यालयों में स्कूलों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।
254. प्रदेश में समस्त निजी सीबीएसई बोर्ड से संचालित व मिशनरी स्कूलों को आरटीई व आरटीआई दायरे में लाने के संबंध में चर्चा के लिए।
255. विधान सभा क्षेत्र खींवसर राजकीय विद्यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत कराने हेतु स्वीकृति दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर):

256. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर की राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सिहागावाली को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्रीमती कामिनी जिन्दल)

257. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के ग्राम पंचायत मुख्यालय 4 एलएल (ढींगावाली) के राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई):

258. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में स्थित राजेश पायलट कॉलेज के स्नातकोत्तर में विज्ञान व हिन्दी विषय का सरकारीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

259. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के नव सृजित ग्राम पंचायत खेड़ी के ग्राम खेड़ा में स्थित माध्यमिक विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

260. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में झाझीरामपुरा व आभानेरी-पर्यटन व पुरातत्व स्थलों पर पब्लिक टॉयलेट व पीने का पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

261. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में विवेकानन्द आवासीय मॉडल स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर):

262. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के विद्यालयों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

263. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा):

264. विधान सभा क्षेत्र भादरा के ग्राम पंचायत डोमी एवं भखाना में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राउमा विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

265. विधान सभा क्षेत्र भादरा की भादरा पंचायत समिति क्षेत्र में आई.टी.आई खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

266. विधान सभा क्षेत्र भादरा भादरा उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

267. विधान सभा क्षेत्र भादरा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीबड़ी (जिला हनुमानगढ़) में वाणिज्य एवं कृषि संकाय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री संजीव कुमार)

268. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रासलाना (जिला हनुमानगढ़) में विज्ञान संकाय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम):

269. टैस्सीटोरी ग्रेवयार्ड बीकानेर को पर्यटन की दृष्टि से विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

270. राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर में स्टाफ की समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

271. राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर की गतिविधियां शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा):

272. सागवाड़ा मुख्यालय पर बालिका महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

273. ग्राम पंचायत ओड के राउप्रावि गामडा चारणीया को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

274. सागवाड़ा पंचायत समिति में ब्लॉक शिक्षा कार्यालय की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर):

275. विधान सभा क्षेत्र नागौर में प्रा.स्कूल फागली एवं केमखानियों की ढाणिंया-अमरपुरा को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

276. नागौर क्षेत्र की राउमा विद्यालय झुझण्डा मूण्डवा नागौर में कला विषय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

277. विधान सभा क्षेत्र नागौर की राउमा विद्यालय मूण्डवा में साइस का विषय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

278. विधान सभा क्षेत्र नागौर की उच्च प्रा. विद्यालय बू-कपोसोला-हनुमान नगर व नागौर शहर की बड़ली नागौर को सैकडरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

279. नागौर की बालिका सैकडरी विद्यालय बासनी व अलाय को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर):</u>

280. विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर के पी.जी. महाविद्यालय में स्नातकोत्तर में रसायन विज्ञान विषय प्रारंभ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

281. विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में विद्यालय क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर):</u>

282. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में राजकीय बालिका महाविद्यालय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

283. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के संस्थापक और सांगानेर के आराध्य देव सांगा बाबा की सांगानेर में मूर्ति लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डॉ. मंजू बाघमार (जायल):</u>

284. राजकीय महाविद्यालय जायल (नागौर) में लाइब्रेरी व लैक्चर थियेटर की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

285. विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) में राजकीय मा. विद्यालय, सोमणा, दुगस्वाउ, दुगौली, लुणसरा (जायल) को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

286. राजकीय महाविद्यालय जायल (नागौर) में नवीन विज्ञान संकाय में गणित और जीव विज्ञान विषय प्रारंभ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

287. विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) में राजकीय उ.प्रा. विद्यालयों (चावड़ा नगर) (बसेल) में उर्दू विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

288. विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) में राउप्रावि को राउमा विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):</u>

289. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के जहाजपुर व कोटड़ी तहसील के विद्यालयों में अंग्रेजी, विज्ञान व गणित विषय अध्यापकों का पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

290. जहाजपुर व कोटड़ी उपखण्ड मुख्यालयों पर खेल विद्यालयों की स्थापना एवं स्टेडियम निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

291. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय को प्रारंभ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री धीरज गुर्जर)

292. उपखण्ड मुख्यालय कोटड़ी पर नवीन आई.टी.आई खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

293. उपखण्ड मुख्यालय कोटड़ी पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर):</u>

294. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में सभी पंचायत मुख्यालयों पर उ.मा.वि., मा. विद्यालय तथा UPS क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

295. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में जिला मुख्यालय पर गणित, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के उच्चतर शिक्षण व्यवस्था स्थापित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

296. बिछीवाड़ा उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

297. रा.उ.मा.वि. मेवाड़ा में गणित-विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

298. राजकीय महारावल सी.उ.मा.विद्यालय, डूंगरपुर की भूमि पर अतिक्रमण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़):</u>

299. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

300. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में विभिन्न राजकीय विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर):</u>

301. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में संचालित सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों, वरिष्ठ अध्यापकों व अन्य रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

302. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में फतेहपुर उपखण्ड पर दानदाता द्वारा जमीन देने व भवन बनाकर देने के बावजूद भी सरकारी कॉलेज की घोषणा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

303. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में एक ही ग्राम पंचायत में अलग-अलग गांवों में विद्यार्थियों की संख्या अत्यधिक होते हुए भी वहां पर स्कूलों को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

304. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में उच्च माध्यमिक विद्यालय से वंचित ग्राम पंचायतों में उच्च मा.विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

305. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में स्थित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय, बिजली सफाई की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

306. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की 6 ग्राम पंचायत मुख्यालयों के उच्च माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

307. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

308. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के मुख्यालय पर महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

309. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में श्री सुंधा माता मंदिर राजपुरा, जसवंतपुरा के संबंध में चर्चा के लिए।

310. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में प्राचीन संस्कृति के प्रतीक देवालय सेवाड़ा दांतवाड़ा सहित प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

311. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की ग्राम पंचायत आकोड़ा एवं मलिकपुरा के सैकण्डरी स्कूलों को सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

312. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

313. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की विभिन्न स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री निर्मल कुमावत)

314. प्रदेश के विद्यालयों में लिपिकों के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

315. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विद्यालयों में शुद्ध पेयजल एवं शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी):

316. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के राजकीय विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

317. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के शहीद बजरंग लाल रा.मा.विद्यालय लालगढ़ को उ.मा. विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

318. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में रा.उ.मा. विद्यालय खां में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

319. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खातियों की ढ़ाणी (खोंह) ग्राम पंचायत मणकसास में कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षकों को चयनित वेतनमान नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।